ISSN : 2278-4632

JUNI KHYAT
जूनी ख्यात

जुलाई–दिसम्बर, 2024 (Vol-II)

(सामाजिक विज्ञान, कला एवं संस्कृति की शोध पत्रिका)

A Peer-Reviewed and Listed in UGC Care List

'जूनी ख्यात' सम्पादक मण्डल

प्रो. हरबंस मुखिया	इतिहास	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
प्रो. वसन्त शिंदे	पुरातत्त्व एवं प्राचीन इतिहास	पूर्व कुलपति दक्कन कॉलेज, पूना
प्रो. राजीव गुप्ता	समाज शास्त्र	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर
प्रो. दिलबाग सिंह	राजस्थान इतिहास	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
प्रो. जी.एस.एल. देवड़ा	मध्यकालीन इतिहास	पूर्व कुलपति, वर्धमान महावीर खुला विवि., कोटा (राज.)
प्रो. एल.एस. निगम	प्राचीन इतिहास	पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
प्रो. सीताराम दुबे	प्राचीन इतिहास	बी.एच.यू., वाराणसी
प्रो. चन्द्रपाल सिंह चौहान	शिक्षा	अलीगढ़ मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ (उ.प्र.)
नर्मदा प्रसाद उपाध्याय	कला इतिहास विशेषज्ञ	इन्दोर, (म.प्र.)
कर्नल प्रो. एस.एस. सारंगदेवोत	कुलपति	जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ (वि.वि.), उदयपुर (राज.)
डॉ. दिनेश जुनेजा	डायरेक्टर	खुशालदास विश्वविद्यालय हनुमानगढ़
प्रो. सूरजभान	मध्यकालीन इतिहास	दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली
प्रो. किशोरकुमार अग्रवाल	क्षेत्रीय इतिहास	पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर
प्रो. रामेश्वरप्रसाद बहुगुणा	मध्यकालीन भक्ति आन्दोलन	जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
प्रो. जीवनसिंह खरकवाल	प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्त्व	साहित्य संस्थान जे.आर.एन, विद्यापीठ, उदयपुर

JUNI KHYAT
जूनी ख्यात

(सामाजिक विज्ञान, कला एवं संस्कृति की शोध पत्रिका)

वर्ष : 14 ● अंक 1 | जुलाई-दिसम्बर 2024 VOL. II

A Peer-Reviewed and Listed in UGC Care List

ISSN 2278-4632

संपादक

डॉ. बी. एल. भादानी

प्रोफेसर

❑

प्रबंध संपादक

श्याम महर्षि

सह संपादक

डॉ. रीतेश व्यास ❑ **रवि पुरोहित**

मरुभूमि शोध संस्थान

संस्कृति भवन, एन.एच. 11

श्रीडूँगरगढ़ (बीकानेर) राज. 331803

सदस्यता

10 वर्ष के लिए शुल्क - 5000 रुपये

संस्थागत सदस्यता-700 रुपये वार्षिक।

इस अंक का मूल्य : 500 रुपये

Punjab National Bank
Marubhumi Shodh Sansthan,
Sri Dungargarh (Bikaner)
Account No. 3604000100174114
IFSC: PUNB0360400

❑

प्रकाशकीय एवं विज्ञापन कार्यालय :

मरुभूमि शोध संस्थान

(राष्ट्रभाषा हिन्दी प्रचार समिति)
संस्कृति भवन, एन.एच. 11
श्रीडूँगरगढ़ (बीकानेर) राज. 331803
फोन : 01565-222670
www.rbhpsdungargarh.com

❑

लेजर टाईप सेटिंग : जुगल किशोर सेवग

मुद्रक : महर्षि प्रिण्टर्स, श्रीडूंगरगढ़

आवरण :
शेषशायी विष्णु 10वीं शताब्दी
हर्ष पर्वत, सीकर

❑

सम्पादकीय कार्यालय :

प्रोफेसर (डॉ.) बी.एल. भादानी

रांगड़ी चौक, बीकानेर 334001 (राज.) मो. 9950678920

bbhadani.amu@gmail.com • junikhyat.mss@gmail.com

सावधान

जूनी ख्यात (अर्द्ध वार्षिक) दिसम्बर 1994 ई. से नियमित Print Form में प्रकाशित हो रही है। जून 2019 में 'UGC Care List' (S.N. 220) में सामाजिक-विज्ञान की श्रेणी में सम्मिलित करली गई है। हमारी पत्रिका Online प्रकाशित नहीं होती है।

जूनी ख्यात नाम से ही एक फर्जी पत्रिका (Cloned Journal) ऑन लाइन निकाली जा रही है जो हमारे ही ISSN एवं यू.जी.सी. केयर लिस्ट की संख्या को उपयोग में ले रही है। इस सम्बन्ध में **यू.जी.सी.** ने 23-7-2020 को 'Cloned Journal' की एक सूची जारी की है उसमें अन्य पत्रिकाओं के साथ **जूनी ख्यात** का भी नाम है। यह पत्रिका निम्न वेबसाइट पर प्रत्येक विषय के शोध पत्र आमंत्रित करती है।

Juni khyat Journal

Language	:	English & Hindi
Publisher		NA
ISSNo.		2278-4632
URL http	:	www.junikhyat.com

हमारी पत्रिका **मरुभूमि शोध संस्थान, श्रीडूँगरगढ़** द्वारा प्रकाशित की जाती है। अब 'नकली पत्रिका' बी.एल. भादानी, संपादक के नाम का भी उपयोग कर रही है जो एक आपराधिक कृत्य है।

इसमें तथाकथित रूप से प्रकाशित आलेख का कोई महत्त्व भी नहीं है। इसलिए शोधार्थियों से सावधान रहने की अपील की जाती है।

बी.एल. भादानी
संपादक

Sl.No.	Journal No.	Title	Publisher	ISSN
220		JUNI KHYAT		2278-4632

UGC Journal Details

Name of the Journal **: JUNI KHYAT (Print Form)**
ISSN Number : 2278-4632
e-ISSN Number : NA
Source : **UGC**
Discipline : **Social Science**
Subject : **Social Sciences (all)**
Focus Subject : Cultural Studies
Publisher : Marubhumi Shodh Sansthan, Sri Dungargarh (Bikaner)

Membership Fees

A half- yearly research journal named Juni Khyat is being regularly published by the Marubhumi Shodh Sansthan Shri Dungargarh (Bikaner), which is featured in the Social Sciences category of the UGC Care List. Its membership fees for ten Years is Rs 5000/-. This increase is applicable from the July- December 2022 issue.

Members Life will get the journal for ten years and no fee will be charged from the members on the publication of research articles approved by the subject experts. Please deposit the membership amount in the following account number of our organization and send us information about the same.

E-mail:marubhoomisansthan@gmail.com

Membership Fee Account Details:-

Punjab National Bank

Marubhumi Shodh Sansthan,

Sri Dungargarh (Bikaner)

Account No. 3604000100174114

IFSE. PUNB0360400

Regarding publishing articles in the Journal and life time (TEN YEARS) membership fees and charges. Please contact following Persons

01. **Shri Shyam Maharshi** (Managing Editor) 9414416274

02. **Dr. Ritesh Kumar Vyas** (Associate Editor) 9828777455

Send research articles to the following

email: bbhadani.amu@gmail.com ● drrkvyas1977@gmail.com

शोध आलेखकों से निवेदन है कि वे अपने आलेख अंग्रेजी में 3000 से 3200 एवं हिन्दी में 3400 से 3500 शब्दों से अधिक न भेजें। इससे अधिक शब्द होने पर आलेख स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

पत्रिका का सदस्यता शुल्क

मरुभूमि शोध संस्थान, श्रीडूँगरगढ़ (बीकानेर) द्वारा **जूनी ख्यात** नामक अर्द्धवार्षिक शोध पत्रिका नियमित प्रकाशित की जा रही है जो UGC Carelist की सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में दर्शाई गई है। इसकी सदस्यता शुल्क रुपये 5000/- है। आशा करते हैं कि आप हमारी विवशता को समझ कर हमारा सहयोग करेंगे।

पत्रिका के सदस्यों को दस वर्षों तक पत्रिका मिलेगी एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा स्वीकृत शोध आलेखों के प्रकाशन पर सदस्यों से किसी प्रकार की फीस नहीं ली जायेगी। सदस्यता हमारी संस्था के निम्न अकाउण्ट (खाता) में जमा करवा कर हमें उसका स्क्रीनशाट भिजवाने का कष्ट करें।

Membership fees should be transferred directly to the A/c of Institution and send us screenshot
to
E-mail:marubhoomisansthan@gmail.com

सदस्यता शुल्क संस्था के निम्न खाते में सीधा ट्रांसफर करके हमें बताने की कृपा करें।

Marubhumi Shodh Sansthan, Sri Dungargarh

Bank : Punjab National Bank
Branch : Sri Dungargarh
A/c No. : 3604000100174114
IFSC : PUNB0360400

पुनश्च : सदस्यता एवं पत्रिका से संबंधित अन्य प्रकार की जानकारियों हेतु प्रबंध संपादक **श्री श्याम महर्षि** मो. नं. 9414416274 एवं **डॉ. रीतेश व्यास** मो. नं. 982877455 से संपर्क करने का कष्ट करें।

शोध आलेख संपादक की ईमेल पर भेजें : आलेख के साथ अपना ई मेल पता डाक का पूर्ण पता एवं मोबाइल नंबर का उल्लेख आवश्यक रूप से करें।

bbhadani.amu@gmail.com ● drrkvyas1977@gmail.com

महाराजा मानसिंह द्वितीय कालीन नवीन ज्ञात शिलालेख, निवाई (टोंक)

परिचय : यह शिलालेख निवाई (टोंक) में जमात स्थित बाहरलें कुण्ड पर लगा मिला है। इस सफेद संगमरमर के पत्थर पर उत्कीर्ण लेख में ऊपर सूरज-चाँद व नीचे भगवान शिव की मूर्ति बनी है। शिव ललितासन मुद्रा में बैठे है तथा इनको चार हाथों युक्त दिखाया है।

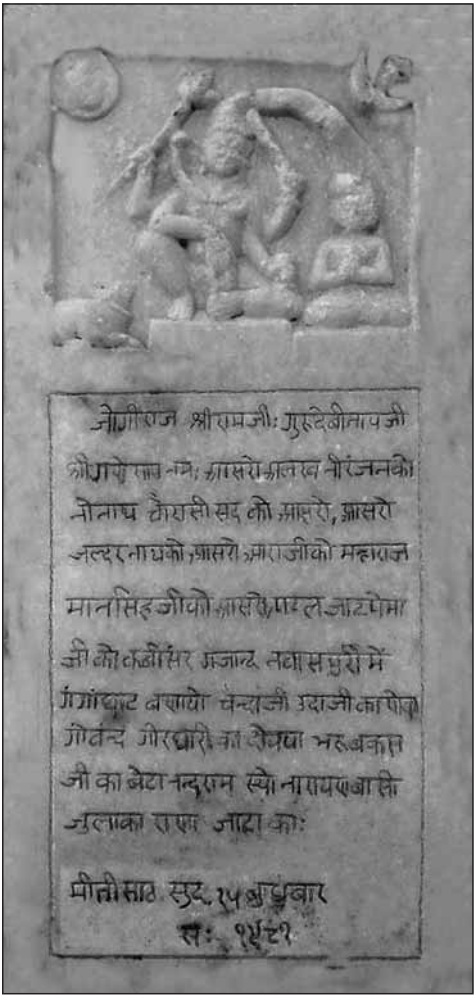

 ISSN 2278-4632 जुलाई-दिसम्बर 2024 VoL. II

इनकी जटा से गंगा निकल रही है जो नीचे एक भगत पर गिर रही है। इनके बगल में नंदी ऊपर मुख किये आसीन है। इनके नीचे एक 12 पंक्तियों का लेख उत्कीर्ण है। इस लेख में निवाई का नाम 'नवासपुरी' मिलता है।

स्थान : जमात, निवाई
तिथि : वि.सं. 1981 (1924 ई.)
मिति आषाढ़ सुदी 15 बुधवार
लिपि : देवनागरी
भाषा : देशज
शिलालेख का मूलपाठ
जोगीराज श्री राम जी : गुरुदेबी जाप जी
श्री गणेशाय नम : आसरो अलख निरंजन को
नो नाथ चौरासी सद को आसरो, आसरो
जल्दर नाथ को आसरो आरा जी को महाराज
मानसिंह जी को आसरो, पटल जाट पेमा
जी को कबींसर गजानन्द नवासपुरी में
गंगाघाट बणायों चन्दाजी उदाजी का पोता
गोविन्द गीरधारी का दोयथा भरू बकस
जी का बेटा नन्दराम स्यो नारायण बासी
जुला का राणा जाटा का :
मीती साठ सुद 15 बुधवार,
सं. 1981

सारांश : विक्रम संवत 1981 (1924 ई.) मिति आषाढ़ सुदी 15 बुधवार, महाराजा मानसिंह जी के समय जाटों के राणा गजानन्द जी जो जौला के निवासी थे, ने नवासपुरी (निवाई) में गंगा घाट बनाया। इसमें गजानन्द के परिवार की वंशावली दी गयी है।

मनोज मीना
पैलियोग्राफी, एपिग्राफी एण्ड न्युमिसमैटिक्स, विभाग
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ हैरिटेज, **नोएडा**

संपादकीय

जुलाई-दिसम्बर 2024 VOL. II के लिए सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों के विद्वानों एवं शोधार्थियों के अगणित आलेख प्रकाशन हेतु प्राप्त हुए, जिनको विशेष-विशेषज्ञों के पास उनकी राय जानने हेतु भेजे गए। इसके अतिरिक्त हमारी संपादकीय टीम ने उन आलेखों की गहन जांच के पश्चात प्रकाशन हेतु उनका चयन किया। आलेखों की संख्या इतनी अधिक थी कि उनको एक अंक में प्रकाशित करना असम्भव था। प्रेस के लिए भी यह अव्यवहारिक था। इसलिए हमारी संपादकीय टीम को इस अंक को दो भागों में प्रकाशित करने का निर्णय लेना पड़ा। इस कारण से अंक का विलंब से प्रकाशित होना स्वाभाविक था। प्रथम भाग प्रकाशित होकर सदस्यों के पास पहुँच चुका है। द्वितीय भाग भी आपके हाथ में है।

इस अंक में अनेक महत्त्वपूर्ण शोध आलेखों को सम्मिलित किया गया है। इनमें ओड़िसा की काली एवं अन्य लोकदेवियों की प्रचलित पूजा, भगवद् गीता-प्राचीन प्रज्ञा एवं आधुनिक मनोविज्ञान के मध्य सेतु, उदयगिरि की गुफाओं की कलात्मकता, ढूंढ़ाड़ की लोक-संस्कृति के अतिरिक्त महात्मा गांधी एवं अम्बेडकर के अल्पसंख्यकों के बारे में विचार, साईबर क्राईम को प्रभावी रूप से लागू करने में कानूनी कठिनाइयां, शिक्षा के क्षेत्र में सोशियल मीडिया की भूमिका जैसे शिक्षा शास्त्र एवं कानून एवं भूगोल विषय से सम्बन्धित अनेक शोधपूर्ण आलेखों को इस अंक में स्थान दिया गया है। इनके अतिरिक्त क्षेत्रीय इतिहास पर केन्द्रित कई नवीन विषयों पर शोधार्थियों के आलेख भी इसमें संकलित हैं। यह अंक सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों पर शोध करने वालों के लिए अत्यंत उपयोगी होगा।

इस अंक के विषय-विशेषज्ञ जिन्होंने आलेखों पर अपनी महत्त्वपूर्ण राय समय पर प्रेषित कर जो अकादमिक सहयोग किया, उसके लिए पत्रिका परिवार उन विद्वानों का आभार व्यक्त करता है। ये विद्वान हैं, प्रोफेसर चन्द्रपालसिंह चौहान (अलीगढ़), प्रोफेसर राजीव गुप्ता (जयपुर), प्रोफेसर के. के. अग्रवाल (रायपुर), प्रोफेसर जीवनसिंह खरकवाल (उदयपुर) एवं प्रोफेसर सूरजभान आदि।

पत्रिका की टाईप सेटिंग का कार्य श्री जुगल किशोर सेवग ने किया। जिन्होंने अत्यंत लगन के साथ समय पर कार्य निष्पादन किया, इस हेतु उनका आभार।

सम्पादक

— डॉ. बी. एल. भादानी

अनुक्रम

- The Worship of Goddess Kali and Other Folk Deities In Danda Nata of Western Odisha 13
  Dibya Ranjan Tripathy • Dr. Santosh Kumar Mallik
- Emotional Regulation and Psychological Insights from the Bhagavad Gita : Bridging Ancient Wisdom and Modern Psychology 27
  Bini T V • Dr. Seema Menon K P.
- The Role of Geography in Shaping the Economic Structure of the Meo Community in Nuh District, Haryana 34
  Avadhesh Kumar Meena • Anju Jangid • Dr. Harpreet Singh • Prof. Anand Kumar Chaudhary
- Ambedkar's Thoughts on Minorities and Rights of Minorities in the Indian Constitution 46
  • Dr. Prerna Malhotra
- Poverty Deprivation Among Social Groups in Thellur Village : A Case Study 57
  Dr Shivanand Panwer • Dr Lakshmana G
  Dr. Mahantagouda Patil • Dr. Ahalatha R
- Assessing the connection between Self-esteem and Academic chievement 76
  Ekta Kansal • Rajive Kumar
- A Study on Teacher Effectiveness of Government Secondary School Teachers In Uttarakhand State 86
  Devraj Singh Rana • Dr. Malvika Kandpal
- Cyber Terrorism: Tackling Legal Challenges for Effective Enforcement 98
  Dr. Subhradipta Sarkar • Md. Minhajuddin
- Role of Social Media Networks on Political Socialization of the Youth of Gwalior 110
  • Mohd Tariq Mir
- Legal Protection of Endangered Languages in India with Special Reference to A.Tong, A Dialect of Garo Language in Meghalaya 121
  Dr. Ranjit Sil • Mrs. Puja Khetawat

- Rule of Law: A Fundamental Pillar of Democracy 132
  • Dr. Ashok Kumar Karnani
- Laws On Bail in India: A Comparative and Analytical Study with Special Reference to New Criminal Laws 145
  Rekha Acharya • Dr. Malika Parvin
- Navigating engendered human security in a conflict zone: Insights from Kashmir through cinema in the 21st century 160
  Dr. Vaishali Raghuvanshi • Arti Devi
- Reforming Labour Codes and Promoting Gender Equity : India's Feminist Diplomatic Efforts in South Asia 175
  Surbhi Sharma • Prof. (Dr.) Nagalaxmi M. Raman
  • Dr. Amit Kumar Mishra
- UNESCO's Happy Schools Project: Promoting Well-being in Higher Education 190
  Dr. Bhavya. R • Dr. Jagannath K. Dange
- Cost-Return Analysis of Tobacco Cultivation in Karnataka : A Case Study of Mysore District 200
  CMA Dr. Trinesha. T. R. • Dr.Ramesha M.C.
- Literacy and Socio-Economic Development of Rural Muslims in Nagpur District 211
  • Dr. Sangita R.Chandrakar
- From Smart Cities to Smart Governance: Role of ICCC's in Achieving Vikshit Bharat@2047 222
  Dr. Arun Pandya • Mr. Navinkumar Rohit
- Classification of an Urban Centers and Urban Tehsil Places into Different Hierarchical Orders in the Ahilyanagar..... 235
  • Dr. Pandurang Yadavrao Thombare
- Blended Learning: Overviewing its Significance & Challenges 244
  Vanessa Vera Khriam • Dr. Rihunlang Rymbai
- Assessment of channel shifting, bank erosion and deposition of Gangadhar river..... 255
  Hasne Toufiki • B.S. Mipun • Sourabh Dutta
- Parenting, Peer Bond, Identity Formation and Non-Suicidal Self Injury 275
  Dr. Vandana Gupta • Dr. Pratima Gond • Dr. Divya Singh

- Gender Equality And Women Empowerment In Contemporary India 288
  Prof. Sanjay Kumar • Nikhilesh Rai
- Interventions for Dyslexia : Emerging Approaches.... 294
  Mr. Harit Dobaria • Dr. Bhavik M. Sha
- Animal Cruelty Through The Lens of Religion and Law..... 308
  • Shreya Sharma
- Domestic Violence and The Condition of Affected Women..... 318
  • Dr. Jaidave Prasad Sharema
- बस्तर की जनजातियों की धरोहर : कुटीर उद्योग 326
  मनहरण कुमार लहरे • प्रो. आभा रुपेन्द पाल
- भारत में वैवाहिक बलात्कार का महिलाओं के मानवाधिकारों के उल्लंघन के रूप में अध्ययन 343
  • विजय लक्ष्मी जोशी
- इतिहास लेखन में राष्ट्रवाद' : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन 353
  • रामदेव जाट
- सर सैयद अहमद खान एवं पश्चिमी आधुनिकता : विज्ञान के प्रति दृष्टिकोण और सामाजिक शैक्षणिक सुधारों में उसकी प्रधानता 367
  डॉ. तालीम अख्तर • डॉ. मुख्त्यार अली
- राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की वर्तमान परिप्रेक्ष में प्रासंगिकता 378
  • सलीम सोलंकी
- कर्मचारियों के मानवाधिकार : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन 385
  • डॉ. रितु चौधरी
- बालकों में अपराधों का बदलता स्वरूप एवं इनका समाधान 399
  • नीलम श्रीवास्तव • डॉ. नीलिमा कुँवर
- वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बी. एड. छात्राध्यापकों के लिए आवश्यक मृदु कौशल (Soft Skills) : एक समीक्षात्मक अध्ययन 406
  • दीपक कुमार
- पैकेज्ड मसालों के टेडमार्क के प्रति घरेलू महिलाओं की जागरूकता पर विस्तृत अध्ययन 413
  • भाग्य श्री बाला

- पोषण वाटिका एवं पोषण सुरक्षा : एक अध्ययन 417
  • डॉ. प्रगति
- शिक्षा में-AI के प्रयोजन से मूल्यों के हस्तांतरण की दिशा में भविष्य 430
  डॉ. नरेन्द्र कुमार पाल • डॉ. चित्रा पाल • दीपक कुमार जाँगिड़
- घेरण्ड संहिता में उल्लेखित पारंपरिक प्राणायाम विधियों द्वारा.... 443
  • मयंक उनियाल • डॉ. गजानन्द वानखेड़े
- राष्ट्रीय कार्यसूची ''विकसित भारत @2047'' की कार्यसिद्धी... 453
  डॉ. नरेन्द्र कुमार • डॉ. ऐश्वर्य राणा
- उत्कृष्ट कला एवं स्थापत्य का उदाहरण : उदयगिरि की गुफायें 461
  • डॉ. मोना जैन
- भारतीय ज्ञान परम्परा व राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 466
  राजेन्द्र गुप्ता • डॉ. कीर्ति सिंह
- छत्तीसगढ़ राज्य के राजनैतिक इतिहास में कंवर जनजाति..... 476
  हरवंश सिंह मिरी • प्रो. आभा रूपेन्द पाल
- महात्मा गांधी : परिवार में संवाद और सामंजस्य के प्रोत्साहक 488
  • पूर्वा भारद्वाज
- आधुनिक जीवन दर्शन और जम्भ वाणी 500
  • डॉ. श्यामा पुरोहित
- ढूंढाड़ की लोक-संस्कृति 510
  • डॉ. महेश कुमार मीना
- मारवाड़ के दशनाम मठों के अभिलेखों व ताम्रपत्रों का सर्वेक्षण : एक अध्ययन 519
  डॉ. दिनेश राठी • हुमा गोस्वामी
- दशरथ लाल चौबे : एक क्रांतिकारी एवं पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम संस्थागत प्रयास के जनक 536
  • ज्ञानेश शुक्ला
- प्रधानाचार्यों की विद्यालय प्रशासन की समस्याओं का अध्ययन 548
  नीलम गोपीलाल परिहार • डॉ. विनीता एस. आडवाणी

The Worship of Goddess Kali and Other Folk Deities In Danda Nata of Western Odisha

• Dibya Ranjan Tripathy
• Dr. Santosh Kumar Mallik

Danda Nata is an annual festival celebrated in Western Odisha, spanning 13 to 21 days from March to April, culminating on MahaVishubaSankranti. This festival is a profound amalgamation of folk, tantric, and mainstream Hindu traditions, reflecting the region's rich cultural heritage. Central to DandaNata is the worship of Goddess Kali, alongside various local deities such as Khambeswari, Kshetrapala, Bauti, and Naraghanta, each embodying distinct aspects of agrarian life and community well-being. The festival is characterized by intense rituals, including blood sacrifices and fire-walking, emphasizing the community's dedication and spiritual fervor. The Danduas, the festival's practitioners, play a vital role in its execution, supported by the Ghasi community, whose drumming provides the rhythmic backdrop for the rituals. Furthermore, the incorporation of tantric practices, including specific mantras and rituals, highlights the spiritual depth of the worship. The historical, mythological, and puranic origins of DandaNata are rooted in ancient narratives that enhance its significance. This paper examines the complex interplay of religious practices, community dynamics, and cultural identity in DandaNata, illustrating its vital role in sustaining traditional values while adapting to contemporary realities.

Keywords : *Danda Nata, Goddess Kali, Western Odisha, Tantric Practices, Community Participation, Folk Deities, Agrarian Traditions.*

Introduction

A major annual celebration, DandaNata takes place in Western

Odisha and lasts for 13 or 21 days, mainly from March to April, ending on the auspicious day of MahaVishubaSankranti. This colorful celebration illustrates the region's rich spiritual legacy by combining folk, tantric, and mainstream Hindu practices. The festival's rigorous rituals, vibrant community involvement, and devotion to a variety of deities that represent the area's agrarian way of life are what make it unique. The 10 districts that make up Western Odisha are: Boudh, Kandhamal, Sonepur, Bolangir, Kalahandi, Nuapada, Jharsuguda, Sambalpur, Baragarh, Demogarh. In these areas, where it is widely observed by a variety of people, including both tribal and non-tribal groups, DandaNata is an integral part of the districts' cultural and religious character. The core of DandaNata is the worship of Goddess Kali, who is honored for both her strong protective personality and her vital role in guaranteeing the success of agriculture. In addition to Kali, many other local deities, each symbolizing a distinct facet of rural life and agricultural concerns, are also highly revered, including Khambeswari, Kshetrapala, Bauti, Naraghanta, and others. DandaNata entails complex rituals that showcase the community's commitment and cultural identity, such as fire-walking, blood sacrifices, and other extreme physical actions. The Danduas, the festival's practitioners and performers who receive support from numerous local communities, are the main adherents of DandaNata. The Ghasi community is particularly crucial because they provide lively music and rhythmic drumming that elevate the festival's lively ambiance. Further adding complexity to the worship activities and reflecting the region's long-standing spiritual traditions is the integration of tantric practices, such as the recitation of particular mantras and ceremonies intended to evoke divine forces. DandaNata's mythical and puranic roots, which stem from tales of deities like Mura and Daruna as well as Shiva's cosmic dance, enhance the festival's cultural background. The purpose of this essay is to examine the various dimensions of DandaNata, with particular attention to the worship of Goddess Kali and other regional deities in the context of Western Odisha's larger socioreligious system. We hope to shed light on the festival's significance as a fundamental manifestation of the local community's cultural and religious identity by investigating its historical, mythical, and spiritual aspects. We shall demonstrate the lasting influence of DandaNata in modern society through this investigation, illustrating how age-old customs persevere in the face of contemporary difficulties.

Literature Review

The extant scholarly works concerning DandaNata and the veneration of deities during the celebration provide a thorough comprehension of the religious, cultural, and ethnological importance of this occasion in Western Odisha.

Cultural And Anthropological Perspectives

In Cults and Religious Movements in Odisha, Mishra and K.C. (1971) examines the interaction between mainstream Hindu practices and tribal customs, emphasizing the syncretism inherent in DandaNata. As an example of how cultural traditions in rural Odisha can adapt, he points out that the event provides a venue for the confluence of different belief systems, with local deities worshipped alongside well-known Hindu goddesses [1].

Mahapatra and L.K. (1980) examines the social dynamics of the tribal and caste populations in the area in Social Anthropology of Odisha: An Ethnographic Research of Tribes and Castes, ethnographic research. His research clarifies how religious celebrations such as DandaNata foster communal identity and solidarity amongst disparate communities by promoting social cohesion [2]. Panda and R.N.'s (2004) book Religious Syncretism in Odisha: A Study of Village Deities and Folk Traditions explore the phenomenon of religious syncretism in the region. He highlights the importance of village deities in the local religious life, such as Kali. According to his research, these deities are essential to the socio-religious environment because they represent the community's agricultural worries and spiritual goals [3]. Roy Basu et al. (2019) examine how Hindu and tribal customs are combined during the DandaNata celebration, highlighting how indigenous deities are combined with popular Hindu goddesses such as Kali. His work emphasizes the coexistence of various rites and spiritual beliefs, emphasizing how this syncretism preserves unique cultural identities while fortifying communal ties. According to Sarkar, this kind of syncretism is essential to the survival of local cultures against the influence of larger religions [4].

Tantric Practices And Rituals

Scholarly interest has been focused on the function of tantra in DandaNata deity worship. Kinsley and D. (1997) examine the

theological foundations of Shakta worship, which includes Kali, in Tantric Visions of the Divine Feminine: The Ten Mahavidyas. He goes into detail about the transformative power of rituals and the essential role tantric practices play in calling out heavenly forces. grasp the intricate interplay between spirituality and physicality in DandaNata ceremonies requires a grasp of Kinsley's study [5].

In his article Rituals of Odisha: From Tribal to Hindu Practices, Dash and J.N. (1997) explore how rituals moved from their tribal roots to Hindu customs. His study demonstrates how the DandaNata celebration embraces Hindu customs while holding on to some of its tribal heritage. Das contends that the festival's adaptability keeps it meaningful in modern religious contexts [6].

In "Folk Tantra in Eastern India," Samdarshi and Pranshu(2019) delve into the role of tantric elements in folk traditions, specifically focusing on Odisha's festivals like DandaNata. Roy points out that tantric rituals, such as the recitation of specific mantras and offerings to deities like Kali, reinforce the esoteric aspect of the festival. He argues that these rituals serve as a means to invoke divine power and protect the community, thereby linking spiritual practices with everyday concerns such as agriculture and protection [7].

Gender And Identity In Worship

Research has also surfaced on the complexities of gender throughout various religious rituals. In Folklore of Odisha: Myth, Ritual and Reality, Satapathy and S. (1994) explore the role of women in the worship of goddesses such as Gramadevati and Kali. She draws attention to how women's engagement in rituals reflects their agency and social standing in the community. Her research suggests that DandaNata functions as a forum for women to demonstrate their commitment and have an impact on the welfare of the community [8].

Folk Beliefs And Community Engagement

Bailey and F. G. (1957) delves deeper into the anthropological features of DandaNata in Caste and the Economic Frontier: A Village in South India, offering insights into how religious practices are influenced by agricultural cycles. Even though he focuses on South India, the similarities to DandaNata highlight how similar patterns of community participation in rural religious observances exist,

underscoring the significance of the agricultural setting [9]. Majhi, Laxman. (2024) explores DandaNata is portrayed in the literature as a complex celebration that encompasses the syncretic character of spirituality in Western Odisha, as well as the complex network of customs, agriculture, and local beliefs. DandaNata's research adds to wider conversations on religious rituals, cultural identity, and communal cohesion in rural India by placing Goddess Kali and other regional deities into this framework[10].

Methodology

To complete this study, a review of prior research on the DandaNata event as well as fieldwork and participant observation are combined. Interviews with participants, priests, and community leaders involved in the DandaNata rites were used to gather primary data. During the festival's several phases, such as DhuliDanda, PaniDanda, and Agni Danda, when certain deities are called, observations were made. In addition, secondary sources are used to analyze how local and mainstream religious rituals converge at this festival, as well as to provide historical and mythical context.

Nomenclature Of Danda Nata

The phrase "DandaNata" comes from the Sanskrit words "Danda," which means austerity or penance, and "Nata," which means performance or dance. Penance rites are performed during this festival, which include physical endurance exercises like walking barefoot on hot coals and self-smacking as a symbol of commitment and purity. Danduas, the participants, go through these ordeals to please the gods and obtain their benefits.[11]

Historical And Mythological Origins Of Danda Nata

The religious environment of the Boudh-Sonepur region of Western Odisha was formed by the Bhanja and Somavamsi dynasties, which provided support for the development of DandaNata in the 8th and 9th centuries. Agrarian societies' dependence on natural cycles is reflected in the festival's historical focus on fertility and agricultural prosperity. Through common rituals, it promoted a sense of community and shared identity. Legends like those of Mura and Daruna, which highlight heavenly protection against evil, and the sage Tarani, which stands for ritual observance and spiritual dedication, are connected to DandaNata mythology. The Shiva

Tandava, a dance that symbolizes life's dualities and metamorphosis by combining elements of creation and destruction, is another highlight of the event. DandaNata is a cultural work that reflects the rural culture of Western Odisha, the local god worship, and the larger Hindu cosmology by fusing historical, mythical, and cultural themes.[12]

Goddess Kali Worship In Danda Nata

The DandaNata celebration is centeredaround Goddess Kali, who is invoked through intense rituals such as fire-walking, blood sacrifices, and martial performances during the Agni Danda and BanaDanda stages, symbolizing her powerful and protective character. The farming villages of Western Odisha rely on Kali's blessings for protection and agricultural prosperity, and these ceremonies emphasize her dual function as a nurturer of life and a destroyer of evil. The main focus of Kali's worship is the parabha, a bamboo shrine, and the celebration includes special mantras and yantras to harness her energy. The rites embody both high and folk spirituality, combining the traditions of Sabarikatantra and Vedic medicine. Animal offerings represent devotion and a request for heavenly favor, and they represent the wishes of the farming community for a bountiful harvest. DandaNata worship of Kali combines spirituality, communal identity, and farming methods to strengthen cultural beliefs, unity, and the life-death-rebirth cycle.[13]

Khambeswari Or Sthambeswari Worship

The deity Khambeswari, also known as Sthambeswari, is the focal point of the DandaNata festival and represents the axis mundi, or the link between heaven and earth. She is revered as a stambha, or wooden or stone pillar, signifying a connection between the spiritual and material worlds that upholds cosmic order. Offerings of rice, flowers, and blood sacrifices are part of the rituals associated with Khambeswari, which express thanks and a request for protection. Her worship is associated with fertility rites, in which women ask for blessings for successful reproduction and farming. Chanting mantras like "Om NamahSthambeswari Devi Namah" invokes her presence and fosters a meditative mood. Offerings such as fruits, pana, milk, and curd represent the community's rich agricultural history and cultural legacy. To ensure the continuation of this cultural

and religious practice, dehuris—who operate as a bridge between the community and Khambeswari—conduct ceremonies, preserve customs, and impart information. DandaNatahonors community identity, fertility, and safety through the worship of Khambeswari, who plays both a nurturing and a protecting function.[14]

Bauti Worship

The rural lifestyle of Western Odisha is reliant on water and fertility, which are attributes of the local deity Bauti. Her devotion at the DandaNata festival is intended to ensure rains, which is necessary for abundant crops and food security. Processions to bodies of water—rivers, ponds, and wells—are part of the rites since they are seen to be hallowed conduits for Bauti's blessings. Traditional music, dances, and group prayers are performed during these processions, which express the desire for a plentiful crop.

Offerings of ukhuda, milk, fruits, and sugarcane are made by devotees as a sign of appreciation and agricultural wealth. Animals including buffaloes, sheep, and goats are also ritually sacrificed as a sign of surrender and a request for safety. These rites are facilitated by the dehuris, who are the Suda caste's traditional guardians of Bauti's devotion, maintaining spiritual traditions and directing the community. The worship of Bauti emphasizes the community's dependence on natural resources and the interdependent nature of humans and the environment. They demonstrate their stewardship of the land and their desire for peace and prosperity by divine favor by paying respect to Bauti.[15]

Naraghanta Worship

Naraghanta, a lesser-known deity in Western Odisha, serves as a protective guardian of village boundaries, safeguarding against spiritual and material threats. His worship, central to the DandaNata festival, involves the ritualistic clanging of bells (ghanta), believed to ward off evil and create a sacred, protective atmosphere. This act symbolizes the community’s collective plea for protection and blessings.Naraghanta is revered as both a defender against supernatural forces and a destroyer of enemies, embodying the community’s aspirations for safety, harmony, and prosperity. His worship blends Sabarika tantric practices with local folk traditions, including specific mantras that enhance his protective energies.

Offerings during DandaNata include milk, curd, sugarcane, pana, mahuli (a local alcoholic drink), and buffalo sacrifices. These sacrifices, seen as a powerful gesture of surrender, emphasize the community's deep faith and devotion, reinforcing Naraghanta's role as a vital guardian deity. The rituals highlight the community's commitment to ensuring his ongoing protection, symbolizing their hopes for security and prosperity.[16]

Kshetrapala Worship

DandaNata is an important event for populations that depend on farming, especially for Kshetrapala, the guardian deity of agricultural fields in Western Odisha. In keeping with the agricultural cycle, his devotion shields crops from pests, natural catastrophes, and other hazards. To symbolize his defending presence, rituals are performed at the boundaries of fields. Fruits, grains, and customary dishes are offered to thank God for rainy, productive fields and ask for his blessing.Invoking Kshetrapala's potency, tantric practices emphasize themes of fertility and abundance through the use of protective symbols like kolams and special mantras. The community's connection to the land is strengthened by these customs, which also underline his spiritual value. By encouraging ecological balance and environmental responsibility, Kshetrapala exemplifies sustainable agricultural methods. The cosmology of the area, which views the natural world as sacred and links the spiritual well-being of the land to its health, encouraging harmony with the natural world, is reflected in his devotion.[17]

Pitabali Worship

Pitabali, a revered folk deity in Western Odisha, embodies fertility, protection, and the well-being of the agricultural community. Depicted as a fierce mother figure, she represents nurturing and safeguarding aspects essential for fertility and life cycles. Her worship during DandaNata is crucial for ensuring abundant harvests and village prosperity.The rituals are intense, involving animal sacrifices (goats or chickens) as acts of faith to appease Pitabali, seeking her blessings for the fields. Offerings of rice, grains, and produce symbolize abundance and are accompanied by traditional songs and chants, fostering a communal atmosphere. Cultural expressions like dance and music narrate Pitabali's protective

strength, passing her teachings across generations.Pitabali's worship underscores the interconnectedness of the community and nature, emphasizing sustainable agricultural practices and the belief that land health aligns with spiritual well-being. As a fierce motherly protector, she symbolizes empowerment, guiding the community in balancing nurturing and safeguarding the land.[18]

Kandenbudhi Worship

In particular, the Kandha people of Boudh and Kandhamal districts hold great reverence for Kandenbudhi, a fertility deity in Western Odisha. She has a particular position among women and families pursuing individual and societal prosperity since she represents both childbirth and agricultural fertility. During DandaNata, she is worshipped through ceremonies focused on the community that emphasize her function as a nurturer in life cycles. Women are heavily involved in these ceremonies, taking part in chants, dances, and songs that honorKandenbudhi's defender spirit and promote unity. The communal prayers for safe childbirth and abundant harvests, along with the emphasis on individual and agricultural fertility, represent the concept that fertility is a shared responsibility.

A local alcoholic beverage called mahuli is one among the offerings, along with goat and cock sacrifices that stand for prosperity and fertility. A Jani, who represents the community's hopes, oversees the ceremonies and makes sure that the right sacrifices and prayers are made. The worship of Kandenbudhi highlights the connection between agricultural and personal fertility, which is necessary for prosperity in general. The Kandha people's close devotion of Kandenbudhi celebrates women's role in life sustenance and affirms the community's legacy and shared goals, fostering a sense of cultural identity and belonging. [19]

Maheswari Worship

A key figure in Western Odisha'sDandaNata celebration, Maheswari is a formidable embodiment of the divine feminine who is called upon as a protection during fire rites and martial arts displays. The furious force of Maheswari, the consort of Lord Shiva, is thought to bestow courage and strength upon the Danduas, those who execute ceremonial dances and athletic

exploits.Offerings of incense, flowers, and turmeric are made in her worship; these represent health, purity, and divine favors. Though modest in the larger scheme of the celebration, Maheswari's rites, predominantly performed by the Dumala caste in the regions of Boudh and Kandhamal, indicate a profound cultural devotion for the divine feminine. Through group prayers and hymns, they uphold cultural heritage, foster communal cohesion, and transmit traditions. Maheswari's contribution at DandaNata is less than that of other goddesses, but her presence enhances the spiritual and cultural aspects of the celebration by highlighting the delicate balance between compassion and strength that is essential to the divine feminine.[20]

Bhairabi Worship

In Purunakata, Boudh district, particularly, Bhairabi, one of the ten Mahavidyas, is a significant deity during DandaNata in Western Odisha. She stands for both annihilation and rebirth and encompasses ferocious and protective attributes. Her devotion is based in tantric customs, and ceremonies held during the celebration are intended to ask for her blessings in order to overcome obstacles in life and to be protected from bad forces.

Offerings of red flowers, such as hibiscus, are made as part of complex and passionate rites that represent vigor, passion, and sacrifice. To respect Bhairabi's fiery character and to call on her protection, blood sacrifices of goats or chickens are also offered. An important symbol of purification, metamorphosis, and communion with the goddess is represented by fire sacrifices. Invoking her presence and aligning followers with her energies involves chanting the mantra "Om BhairabyaiNamah." By preserving ethnic identity and customs, Bhairabi's worship promotes community cohesion. Danduas and worshipers are inspired to confront life's obstacles with fortitude by her dual nature, which emphasizes creation and destruction. By being in the community, Bhairabi serves as a reminder of the guiding and shielding forces around them.[21]

Gramadevati Worship

The worship of the Gramadevati, the village goddess, is central to the social and spiritual life of rural Odisha. She is revered as the village guardian, symbolizing the collective identity and aspirations

of the community. During the DandaNata festival, elaborate rituals and offerings—like flowers, rice, and fruits—are conducted to honor her, reflecting community spirit and gratitude. Her worship is closely linked to agriculture, with prayers for protection, good harvests, and overall well-being.The rituals involve Sabarika mantras and tantra, blending folk traditions with ancient tantric practices. Mantras are chanted to invoke the goddess's protective powers, while yantras are used as focal points for devotion. These practices enhance the spiritual connection between the community and the goddess. Celebrations often conclude with communal feasts, dances, and songs, reinforcing social bonds, collective identity, and a sense of belonging among villagers.[22]

Tantra And Mantra In Danda Nata

Tantric rituals, which are an integral part of DandaNata in Western Odisha, are a blend of Sabarika and Brahmanical traditions that emphasize the spiritual diversity of the area. Using certain mantras that harness their nurturing and protecting powers, one can conjure powerful goddesses like Kali and Bhairabi, as well as regional deities like Kshetrapala, Naraghanta, Khambeswari, Bauti, Pitabali, Kamdenbudhi, and Maheswari. Rituals frequently include symbolic offerings like flowers, rice, and milk along with extreme activities like firewalking, blood sacrifices, and martial demonstrations. The fertility and protection that these deities represent highlights the festival's link to the cycles of agriculture, communal well-being, and spiritual resilience. The worship of the gods, which is symbolized by customs like bell-ringing, chanting, and the use of yantras, promotes social cohesion and preserves the local way of life.[23]

Findings And Conclusion

This study examines the complex interactions between mainstream Hindu, tantric, and folk traditions during the DandaNata celebration, emphasizing the festival's significance for Western Odisha's spiritual and cultural life. The worship of local deities like Kshetrapala, Bauti, Naraghanta, and Khambeswari, together with Goddess Kali, indicates a close relationship between religious customs, agricultural cycles, and community life in the area. Every god stands for a certain aspect of life, such as protection and fertility or agricultural success, bringing spiritual beliefs into line with

everyday life. DandaNata's religious environment is enhanced by the incorporation of tantric traditions, which employ mantras and fire- and blood-sacrificing ceremonies to call upon the powers of the deities. Reciting holy words such as "Om KrimKalikayeNamah" gives them a sense of empowerment and a shared mission. These customs show the syncretic character of the area, where native beliefs peacefully coexist with mainstream Hinduism to create a rich tapestry of spiritual expression that is specific to this area. The DandaNata festival is an important cultural occasion that strengthens the social and religious bonds of rural communities by serving as a bridge to maintain long-standing customs while adjusting to modern circumstances. By participating in common rituals, community members strengthen their ties to one another and their culture, guaranteeing that the spirit of their history is preserved for future generations. According to this research, Danda Nata is more than just a festival rather; it is a live example of the adaptation and resiliency of rural communities in Western Odisha. It illustrates how firmly held-ideas continue to influence communal life in a world that is always changing. It captures the harmony between spirituality, agriculture, and social cohesiveness.

References

1. Mishra, K. C. (1971). Cults and Religious Movements in Odisha. Bhubaneswar, India: Orissa State Museum.
2. Mahapatra, L. K. (1980). Social Anthropology of Odisha: An Ethnographic Study of Tribes and Castes. Calcutta, India: Anthropological Survey of India.
3. Panda, R. N. (2004). Religious Syncretism in Odisha: A Study of Village Deities and Folk Traditions. Delhi, India: Concept Publishing Company.
4. Roy Basu, A., Bharat, G., Chakraborty, P., &Sarkar, S. K. (2019). Adaptive co-management model for the East Kolkata wetlands: A sustainable solution to manage the rapid ecological transformation of a peri-urban landscape. Science of The Total Environment, 698, 134203. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.134203
5. Kinsley, D. (1997). Tantric Visions of the Divine Feminine: The Ten Mahavidyas. Delhi, India: MotilalBanarsidass.
6. Dash, J. N. (1997). Rituals of Odisha: From Tribal to Hindu Practices. Bhubaneswar, India: Orissa Review.

7. Samdarshi, P. (2019). The Historiographical Issues of Buddhist Tantra. Journal of Religious Studies and History, 5(3), 214-225.
8. Satapathy, S. (1994). Folklore of Odisha: Myth, Ritual and Reality. New Delhi, India: National Book Trust.
9. Bailey, F. G. (1957). Caste and the Economic Frontier: A Village in South India. Manchester, UK: Manchester University Press.
10. Majhi, L. (2024). Daṇḍanāṭa Tradition in Odishan Culture. Journal of Cultural Heritage Studies, 3(1), 109-118. https://doi.org/10.5281/zenodo.10825674.
11. Satapathy S K.(1999).DandaNata: Prabidhi O Prayoga(Odia). Bhubaneswar, Mrs SaibaliniRath, p-2.
12. Mohanty, R. (2022). Rituals and performances in the Boudh-Sonepur region: The case of DandaNata. Journal of South Asian Folklore, 16(2), 45-63.
13. Mahapatra, P. (2010). The cultural roots of DandaNata: Folklore and tradition in Odisha. Bhubaneswar: Odisha Folklore Research Academy.
14. Dash, N. (2019). DandaNata: A ritual and performance tradition of Western Odisha. New Delhi: National Publishing House.
15. Sahu, A. (2015). DandaNata and the legacy of the Somavamsis in Odisha. Odisha Historical Review, 22(3), 101-118.
16. Panda, M. K. (2016). Shiva and Shaiva practices in Western Odisha: A historical and cultural survey. Indian Journal of Cultural Studies, 9(1), 78-89.
17. Roy, S. (2021). Myth, community, and identity in DandaNata: An ethnographic study. Cultural Heritage Journal, 15(4), 89-104.
18. Bhowmik, S. (2018). Agrarian festivals and folk performances in Odisha. Journal of Rural Studies, 13(2), 31-47.
19. Patel, A. (2020). Fertility rites and agrarian deities in Odisha: A study of the Kandha community. Journal of Tribal Studies, 8(3), 55-72.
20. Mohanty, R. (2022). The feminine divine in Odisha's folk traditions: An analysis of DandaNata and associated deities. Odisha Cultural Studies Journal, 7(1), 95-108.
21. Sahu, A. (2015). Bhairabi and the tantric traditions of Odisha: A study of her role in DandaNata rituals. Journal of Indian Religious Studies, 12(2), 47-61.

22. Dash, S. (2019). The Gramadevati and rural spirituality in Odisha: A study of DandaNata rituals and community worship. Journal of South Asian Folklore and Religion, 14(3), 129-142.

23. Roy, P. (2021). Tantric traditions and spiritual diversity in DandaNata: Exploring the synthesis of Sabarika and Brahmanical practices in Western Odisha. International Journal of Tantric Studies, 22(1), 48-62.

Dibya Ranjan Tripathy,
PhD Research Scholar
School of History
Gangadhar Meher University, Sambalpur, Odisha, India
Email: Tripathydibya090@gmail.com

Dr. Santosh Kumar Mallik
Assistant Professor
School of History
GangadharMeher University, Sambalpur, Odisha, India

❑ ❑ ❑

Emotional Regulation and Psychological Insights From The Bhagavad Gita : Bridging Ancient Wisdom and Modern Psychology

Bini T V • Dr. Seema Menon K P

The Bhagavad Gita incorporates ancient wisdom and modern psychology through its teachings on emotional regulation, mindfulness, mental well-being and so much more. This paper demonstrates the relevance of Gita in contemporary life by discussing ethics and emotions along with the cognitive functions. Furthermore, Gita advocates for mental stability, which is the goal of contemporary psychotherapeutic techniques, through the control of emotions. The focus is shifted from stressors to healthy attitudes and emotions, warping the stress management technique into a more wholistic one. Gita provides great value when looking for harmony on a personal and social level because of his deep principles and ideals on social values and emotional maturity.

As with much of contemporary theories on positive psychology and Cognitive Behavioral Therapy (CBT), many of the concepts presented in the Bhagavad Gita are similar. There is a combination of karma yoga, bhakti yoga, and gyan yoga, which offers an approach towards the behavioral, emotional, and intellectual aspect of a human.

The Gita is and has been very helpful in achieving the positive impact for a person's emotional and mental development. It enables one to regulate negative emotions and manage stress which provides invaluable tools towards both personal and professional life. The Gita still remains a guide for those trying to achieve inner emotional fulfillment and balance.

Keywords : *Bhagavad Gita, Emotional Regulation, and Mindfulness.*

Emotional Regulation in the Bhagavad Gita

The ancient Hindu scripture, the Bhagavad Gita, remarkable offers timeless wisdom as well as an approach towards dealing with modern challenges through the use of mindfulness practices. It has been studied in the context of contemporary psychology and stress management, amongst several other issues. The Bhagavad Gita views emotional regulation alongside wisdom as pivotal. The ability to control the emotions is assumed to be a highly desired trait, along with knowledge of life, control over desires, and being self-contented. These aspects can and should be cultivated, which by all means makes intervention approaches focused on improving personal well-being relevant1. The text proposes a method of regulating emotions with the help of yoga practices, which, together with meditation, serves as a means of attaining mental control and emotional stability5.

Typically, understanding and internalizing the Bhagavad Gita has also been aimed at fostering more favorable emotions such as appreciation and forgiving, who are negatively correlated with stress. An intervention study determined that the Gita can be helpful in reducing the stress among participants by nurturing emotions like appreciation and positive thinking.

Gita's readers are found to be more emotionally mature and value driven than people who do not read the Gita. A study which was conducted with college students revealed that students that read the Gita are emotionally more developed, socially well-adjusted and integrated with more personality. This implies that the Gita's teachings can help in the improvement of emotional maturity as well as social and religious values3.

The teachings of Gita about human nature and practice of yoga helps in the management of stress and improving one's quality of life. The movement from tamas (inertia) to sattva (purity) or inner calm and tranquility is beneficial. The principles of the Gita are applicable in a broad variety of settings, including stress management within corporate environments, which illustrates its value in daily life4 8.

The positive impact of the Gita on emotional and mental development has been and continues to be extremely beneficial. Its positive focus on emotional maturity able to regulate negative emotions and manage stress provides invaluable tools towards both

personal and professional life. The Gita remains a guide for those trying to achieve inner emotional fulfillment and balance.

Psychological Concepts in the Bhagavad Gita

The Bagavad Gita, besides being a philosophical and spiritual piece of literature, is one of the most important Hindu scriptures and possesses a wealth of psychological knowledge. The psyche is covered in its self-care and self-identity teachings and duty offering elderly timeless advice which is relevant to many aspects in psychology today. The Gita contains the components of karma yoga (action) and bhakti yoga (devotion) and gyan yoga (knowledge) and provides and an integrated approach to psychological wellbeing.

The Bhagavad Gita is one of the most remarkable documents that has distinct importance concerning the broader contemplation of Indian culture. It works on addressing some of the deepest fundamental psychological dilemmas of mankind irrespective of the time period or the geography. Happiness, appreciation, satisfaction and looking at the positive aspects of life is what the Gita appreciates the most. It trains an individual on how to cope with the grim realities of life by effectively using techniques employed in contemporary stress management9.

The Gita's teachings align closely with the principles of positive psychology, emphasizing the cultivation of positive emotions such as joy, gratitude, and contentment. It encourages leveraging personal strengths and mental resilience to cope with life's challenges, similar to modern stress management techniques10. The Gita also highlights the importance of mind management, duty, and self-management, which are crucial for mental health and personal development 6.

The Gita principles are reflected in modern psychotherapy practices such as Cognitive Behavioral Therapy (CBT). This include self-reflection, contentment, and internal problem solving which are the common goals present in modern day psychotherapy. In a broader view, the philosophy of the Gita which includes self-reflection, boosting self-esteem, and having positive outlook towards oneself aids in a person’s self-actualization and mental well-being11 12.

The fundamental concepts in the Gita can be parallel with concepts in self-actualization in western psychology and mindfulness in eastern philosophy which touches on the pursuit of spiritual

paths. The Gita teaches that focusing one's consciousness offers enlightenment and depth of self-awareness which enables personal growth 1314.

The Gita is considered a wealth of Psychological Capital because it offers hope, self-efficacy, resilience, and optimism. The Associated Press emphasizes accomplishment in life regardless of the obstacles one faces. This tenet can be applied to modify psychological systems and improve mental endurance15.

The Gita is so powerful and helpful that it can be applied in modern and previous times. It's ideas on self-regulation, as well as positive thinking, and even psychotherapeutic dealing to a great extent help in resolving issues around mental health, and self-improvement. By applying these teachings, people are better placed to cope with stress and challenges to their life which is a problem across the world and throughout all cultures.

Mindfulness in the Bhagavad Gita

From the fairest book of Gita Kriti, it is clearly stated that mindfulness must be practiced as a spiritual and ethical virtue. This means in parts of the Baghavat Gita, it explains that Ghandi's concepts are about focusing overfocusing more over hisatan and gading control over one's mind. The Gita seeks to tame the mind and body of one to reach self-satisfaction and overcome moral issues. This is evident in Arjuna's mental battle which Krishna solves by guiding him over the issue. This idea is like that of a sithaprajna, which is a stable mind found in Buddhism16.

The Gita advocates for the self-actualization of the user through meditation spectacles in a yoga. These practices are identified as means of fighting mental disorders The Gita links mental health to mindfulness, advocating for mental control through practices like meditation and yoga. These practices are seen as pathways to self-actualization and mental harmony 5 6 17. This ideal is further elaborated upon in the book where mindfulness is described as selflessness (Nishkama Karma) and a blend of knowledge, action, and devotion. It promotes the welfare of both the individual and the community. In the context of the Gita, consciousness is taught with an accent on attention and more importantly, the development of these skills. This particular attention emphasises the form of

consciousness differ people have, yogi versus the ordinary individual and the morality and social responsibility of mindfulness 14.

Also, the Bhagavad Gita teaches mindfulness in a way that leads to clarity of thought, harmony within the society, and ethical development. The Gita offers a multidimensional approach to development and wellbeing by promoting the awareness and control over the mind which leads to self-empowerment that is in harmony with Eastern and Western psychology.

Conclusion

The text effectively illustrates how the Gita serves as a blend of ancient traditions and current concepts in psychology. It emphasizes the importance of incorporating emotional and cognitive processes to tackle mindfulness, emotional management, and one's mental wellbeing. The Gita, just like modern psychotherapy, seeks to enhance emotional regulation for the sake of mental stability.

It provides a fuller method to alleviating stress by redirecting attention from the stressors themselves to the positivity an individual's attitude and emotion. Gita's ideas and principles on social values and emotional maturity were set in a time period which now serves as the foundation for many issues pertaining to personal and social harmony.

As with the many sociological shifts within the branch of Positive Psychology and in CBT (Cognitive Behavior Therapy), it is evident that there is much that is explicitly discussed in the Gita. It is a combination of karma yoga, bhakti yoga or devotion, gyan yoga or intellectual yoga which the self-realization and mindfulness that the Gita places emphasis on is directed at. All these, in turn, are addressed to the emotional and behavioral as well as to the cognitive aspects of a human being.

The Gita perceives self-control and ethical living through the lens of mindfulness as a technique which is why it is greatly recommended. It is a religious scripture. The Gita emphasizes the idea of mastering and having command over one's mind as a way to attain mental balance and deepen one's spirituality, which in itself describes an advanced phase of integration of ancient practices into contemporary psychology. The teaching of Gita at its most basic level helps balance the emotions, fosters mindfulness and provides

psychological vedic insight that aids everyone who seeks for self and career development. Gita does this by balancing the mind and emotions which is so very vital in this modern world, hence proving to be an important guide.

References

1. Jeste, D., & Vahia, I. (2008). Comparison of the Conceptualization of Wisdom in Ancient Indian Literature with Modern Views: Focus on the Bhagavad Gita. Psychiatry, 71, 197 - 209. https://doi.org/10.1521/psyc.2008.71.3.197.
2. Priyanka, T., & Seema, S. (2021). Enhancing Positive Emotions Through Bhagvaad Gita: A Path To Reduce Occupational Stress.
3. Balodi, G., & Raina, D. (2015). A Comparative Study of Emotional Maturity and Values in Bhagavad Gita Readers and Non-Readers. Indian journal of positive psychology. https://doi.org/10.15614/IJPP.V5I4.1222.
4. Sharma, R., & Batra, R. (2018). Bhagvad Gita Approach to Stress Mitigation and Holistic Well-Being. Managing by the Bhagavad Gītā. https://doi.org/10.1007/978-3-319-99611-0_7.
5. Tewari, R., & Shukla, A. (2024). The Science of Yoga and Bhagavad Gita. Mind and Society. https://doi.org/10.56011/mind-mri-132-20247.
6. Pattabhiram, B., &BalajiDeekshitulu, P (2017). Mental health in Bhagavad Gita. .https://doi.org/10.28933/IJNR-2017-04-0801.
7. Krishnan, R. (2022). The Bhagavad Gita as the Epitome of Indian Psychology vis-à-vis Modern psychology. Mind and Society. https://doi.org/10.56011/mind-mri-111-20228.
8. Ganguly, S., & Gope, M. (2020). A Study on the Influence of the Bhagavat Gita on Modern Day Corporate Stress Management. https://doi.org/10.34257/gjmbravol20is15pg53.
9. Dhakad, M. (2018). Critical Analysis of Psychological Concepts in the Bhagavad Gita.
10. Das, A., & Rai, P. (2024). Understanding Positive Psychology Through The Lens Of Indian Knowledge System: Insights From Shrimad Bhagavad Gita. EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR). https://doi.org/10.36713/epra16776.
11. Phogat, P., Sharma, R., Grewal, S., & Malik, A. (2020). The

overlapping principles of Bhagavat Gita and contemporary psychotherapies.8. https://doi.org/10.25215/0803.197.

12. Bhatia, S., Madabushi, J., Kolli, V., Bhatia, S., & Madaan, V. (2013). The Bhagavad Gita and contemporary psychotherapies. Indian Journal of Psychiatry, 55, S315 - S321. https://doi.org/10.4103/0019-5545.105557.
13. Ramani, P. (2024). A Comparative Analysis of Self-Realisation in the Bhagavad Gita with Psychology and Philosophy and its Educational Implications. Shanlax International Journal of Arts, Science and Humanities. https://doi.org/10.34293/sijash.v11i3.6910.
14. Maitra, K. (2022). Consciousness and Attention in the Bhagavad Gita. Journal of the American Philosophical Association, 8, 191 - 207. https://doi.org/10.1017/apa.2020.23.
15. Akartuna, D., & Menon, P. (2017). Bhagavad Gita - A Storehouse of Psychological Capital. International Education and Research Journal, 3.
16. Nirban, G. (2018). Mindfulness as an Ethical Ideal in the Bhagavadgītā. Mindfulness, 9, 151-160. https://doi.org/10.1007/S12671-017-0755-5.
17. Keshavan, M., Gangadhar, B., &Pandurangi, A. (2021). Hinduism. Spirituality and Mental Health Across Cultures. https://doi.org/10.1093/med/9780198846833.003.0013.
18. Kumar, N., & Bhardwaj, R. (2023). Community Wellbeing : The Message from Shrimad Bhagavad Gita. Journal of Psychosocial Well-being. https://doi.org/10.55242/jpsw.2023.4108.

Bini T V1,
Research Scholar
NCERT Doctoral Fellow,
Department of Education,
NSS Training College Ottapalam, Kerala.

Dr. Seema Menon K P
Professor,
Department of Education,
NSS Training College Ottapalam, Kerala.

❑ ❑ ❑

The Role of Geography in Shaping the Economic Structure of the Meo Community in Nuh District, Haryana

Avadhesh Kumar Meena • Anju Jangid • Dr. Harpreet Singh • Prof. Anand Kumar Chaudhary

This study examines the influence of geography on the economic structure of the Meo community in Nuh District, Haryana. The Meo community, predominantly involved in agriculture and livestock farming, is affected by various geographical factors, including land fertility, water availability, infrastructure, and proximity to urban centers. These factors significantly shape the community's economic activities, income levels, and overall livelihoods. The research utilizes both primary data, collected through surveys and interviews with community members, and secondary data from government reports, census records etc.to analyze the spatial distribution of economic activities. Quantitative methods such as descriptive statistics, correlation, and regression analysis are employed to assess the relationship between geographic variables and economic outcomes. The findings reveal that geographic proximity to resources like water sources and markets, as well as access to transportation networks, plays a crucial role in determining the economic prosperity of the Meo community. The study concludes that enhancing infrastructure and resource accessibility could improve economic opportunities and livelihoods for the Meo community in Nuh District. This research offers valuable insights for policymakers and development agencies focused on rural economic development and highlight the need for geographically informed strategies to address socio-economic disparities in rural India.

Keywords : *Geography; Economic structure; Meo community; Nuh (Haryana)*

Introduction

A geographic approach to modeling regional growth views the evolving economic landscape as a dynamic system with intricate interdependencies among its agents and structures (Plummer & Sheppard, 2006). Location impacts economic activities, with countries near the equator often being poorer than those in temperate zones, and notable regional inequalities existing within countries (Krugman, 1999). Location and climate significantly influence income levels and growth by impacting transport costs, disease prevalence, and agricultural productivity, among other factors (Gallup et al., 1999). The primary mechanisms involve geography's influence on agricultural productivity and the disease environment. Warm climates are susceptible to tropical diseases and extreme weather conditions such as heavy rainfall or drought, which negatively impact health and agricultural development (Constantine & Khemraj, 2019).

Geography plays a crucial role in shaping the economic structure of communities, particularly in regions where environmental factors significantly influence livelihoods(Ottaviano, 2008). Geography has historically played a crucial role in shaping economic development, impacting the distribution of resources, the establishment of trade routes, climatic conditions, and the spatial arrangement of economic activities(Montgomery, 2024). Physical features like mountains, deserts, and restricted access to navigable waterways can significantly obstruct economic activities. Poor infrastructure and geographic isolation markedly increase transportation costs, which in turn hinder trade and limit economic integration(Limão & Venables, 2001). The geographic determinants of economic activity's spatial distribution can result in agglomeration effects, which may either concentrate wealth or amplify regional disparities.

Cultural and social elements, influenced by geographical conditions, contribute to economic development. Geographic isolation can facilitate the preservation of traditional customs and norms, which may impact the adoption of innovative technologies or economic frameworks. In many regions, the interplay between geographic features and human economic activities is evident in the adaptation of communities to their environment. The suitability of land for agriculture, the presence of mineral resources, and the proximity to trade routes and markets are key geographic determinants that have historically shaped economic systems. Additionally, geographic constraints such as aridity, remoteness,

or natural hazards can pose challenges, influencing the strategies communities adopt for economic sustainability (Saha, 2013).

This study aims to understand how the region's topography, climate, natural resources, and environmental conditions have shaped the economic activities and livelihoods of the Meo people. By analyzing the relationship between geography and economic practices, the research seeks to provide insights into sustainable development strategies that align with the community's geographic and cultural context, thereby contributing to more effective economic planning and policy formulation for similar semi-arid regions. The relationship between geography and economic structures has been a subject of extensive research, emphasizing how geographical factors shape the livelihoods and economic strategies of communities. Regions with advantageous geographic attributes, such as fertile soil and access to navigable waterways, have a higher propensity to develop intricate economic systems capable of supporting sustained long-term growth (Koyama & Rubin, 2022). Regions with strategic geographic positions demonstrated a more robust recovery, indicating that inherent geographic advantages play a significant role in economic resilience and sustainability (Davis & Weinstein, 2002).

Objectives of the paper

1. To examine the influence of geographical features in Nuh District on the economic activities of the Meo community
2. To investigate the role of geography in the socio-economic mobility and occupational diversification within the Meo community in study area.

Study Area

Nuh district, located in the Indian state of Haryana, was previously recognized as Mewat district. According to the 2011 Census, the district covers an area of 1,507 square kilometers (582 square miles). The population of Nuh District is approximately 1.1 million, with a significant proportion belonging to the Meo Muslim community. The Meo, also called Mev or Mewati Muslim, self-identify as a distinct socio-cultural ethnic community. The majority of the population in the district is composed of Meo people, who primarily follow agriculture as their occupation and practice Islam. Agriculture, along with related and agro-based activities, constitutes the main livelihood. The agricultural practices are largely dependent

on rainfall, with the exception of certain areas where irrigation is facilitated through a canal system(Kukreja, 2020).Nuh district is regarded as one of the most socio-economically backward districts in India(India, 2018).

The socio-economic status of the Meo community, particularly Meo women, is influenced by inequalities in wealth, limited access to educational resources, and the cultural norms that dominate within the community(Sikand, 2016). The geographical features of Nuh district are characterized by semi-arid conditions, comprising a blend of plains and low-lying hills. The district is chiefly populated by the Meo community, who are primarily engaged in agriculture and livestock(NIC, 2024).

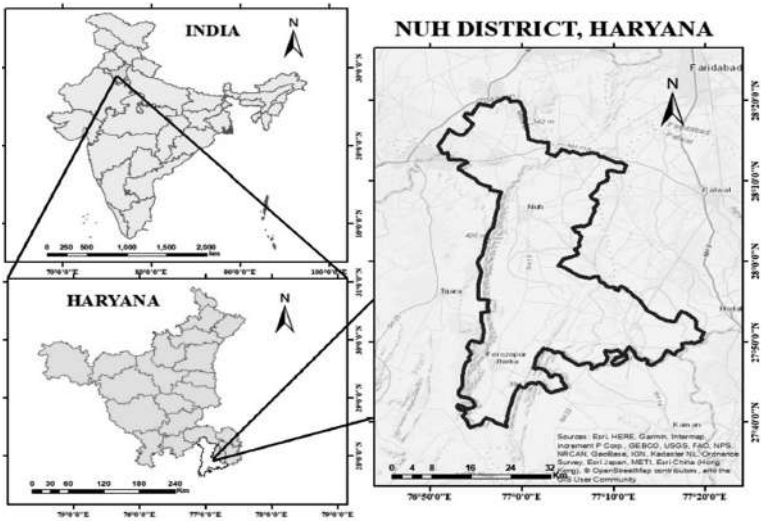

Figure 1: Study area map

Data and Methods

This research will adopt a quantitative approach to examine the role of geography in shaping the economic structure of the Meo community in study area. A primary survey will be conducted using quantitative methods, with data collection through semi-structured questionnaires and interviews. Non-probability sampling techniques, including purposive and snowball sampling, will be employed to identify and select 130 participants from the Meo community. The purpose of using these sampling methods is to target individuals

who are most knowledgeable about the community's economic and geographical conditions. Descriptive statistics will be utilized to analyze demographic characteristics, providing insights into the socio-economic profile of the participants. Additionally, regression analysis will be conducted to assess the relationship between geographical factors and the economic structure of the Meo community, offering a deeper understanding of the influence of geography on their economic activities.

Results and discussion

Table 1 : Demographic characteristics of the participants

Demographic characteristics	n= 130 Frequency(n)	Percentage (%)
Gender		
Male	77	64.1%
Female	53	40.7%
Age		
15-25	15	11.5%
26-36	39	30%
36-45	28	21.53%
46-55	27	20.76%
Above 55	21	16.15%
Married status		
Married	87	66.92%
Single	19	14.61%
Widow	14	10.76%
Separated/ Divorced	10	7.69%
Level of education		
No formal education	89	68.46%
Primary education	22	16.92%
Secondary education	11	8.46%
Territory education	8	6.15%

Source: Primary survey by the authors, 2024

The table 1 provides a detailed breakdown of the demographic characteristics of a sample of 130 individuals, encompassing gender, age, marital status, and educational attainment.The data reveals that the sample is predominantly male, with 77 participants, representing 64.1% of the total, while females constitute 40.7% with 53 participants. This indicates a gender imbalance in the sample, which could influence the generalizability of the study findings, depending on the research context. The participants' ages are segmented into five groups. The largest group, comprising 39 individuals or 30%, falls within the 26-36 age range, suggesting that the sample skews towards young adults. The next largest groups are the 36-45 years category, with 28 participants (21.53%), and the 46-55 years category, with 27 participants (20.76%). The above 55 age group includes 21 participants (16.15%), while the youngest age group, 15-25 years, comprises 15 participants (11.5%). This age distribution highlights a relatively even spread across most adult age groups, though younger adults are slightly more represented.

A significant majority of the participants are married, with 87 individuals (66.92%). Single participants represent 14.61% of the sample, with 19 individuals. Widows account for 10.76% (14 participants), and those who are separated or divorced make up 7.69% (10 participants). The high proportion of married individuals could suggest that marital status is a notable characteristic within this sample, potentially affecting other variables under study. The educational attainment of participants shows a substantial proportion without formal education, with 89 individuals (68.46%). Those with primary education make up 16.92% (22 participants), while secondary education holders constitute 8.46% (11 participants). Participants with tertiary education are the least represented, at 6.15% (8 participants). This distribution suggests a generally low level of formal education within the sample, which may have implications for interpreting study results, particularly in contexts where education level influences outcomes.

The community's occupational structure is predominantly agricultural, with 40.76% engaged in farming activities (see fig 1). This significant dependence on agriculture highlights a rural, agrarian lifestyle where land and farming practices are central to economic sustainability. The second most prevalent occupation is livestock farming, comprising 28.46% indicating some level of

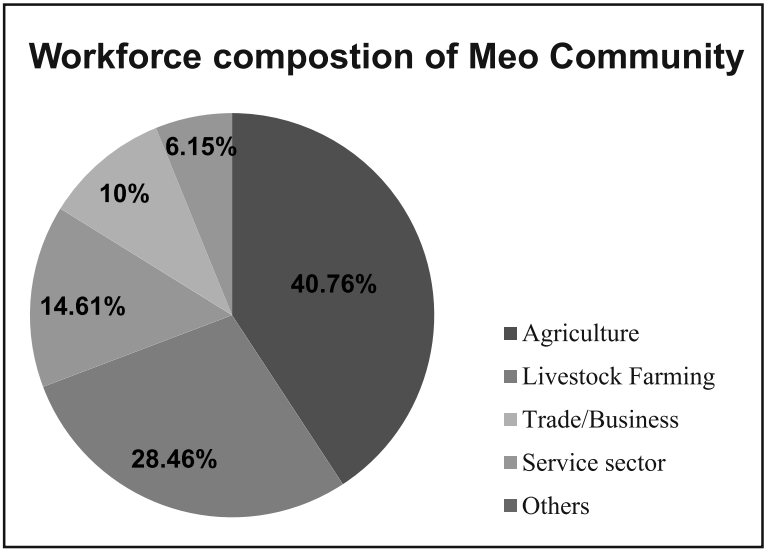

Figure 2 : Occupational structure of Meo community

economic diversification as community members explore alternative income sources trade/business accounts for 14.61% whereas service sector is minimal, representing only 10%, which suggests limited integration into stable, formal sector occupations. Additionally, 6.15% are employed in various other sectors, underscoring the economic constraints and limited occupational diversification within the community. The income distribution within the community reveals a diverse economic landscape (see fig 2). A minority, constituting 5.38%, earns below 10,000, suggesting a segment facing significant financial constraints. The income bracket of 10,001 to 20,000 encompasses 14.61% of the population, indicating a slightly broader group experiencing modest earnings. A considerable portion of the community, 23.84%, falls within the 20,001 to 30,000 income range, which might represent a middle-income segment. The largest share of the population, 36.15%, earns between 30,001 and 40,000, reflecting a substantial portion with relatively higher incomes. Additionally, 20% of the community earns above 40,001, indicating a notable upper-income group. This distribution suggests a reasonably broad economic spectrum, with a significant proportion of individuals in middle to higher income brackets, while a smaller percentage remains in lower-income categories.

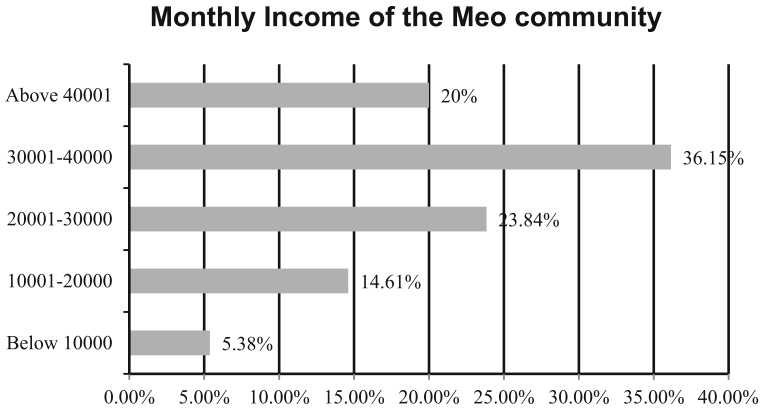

Figure 3 : Monthly income distribution of Meo community

Influence of Geography on the Economic Structure of the Meo Community

To investigate how geography influences the economic structure of the Meo community in Nuh District, Haryana, this study utilizes a multiple linear regression model. The analysis focuses on the relationship between economic activity (the dependent variable) and a set of geographical factors (independent variables). These geographical factors, including the proximity to markets, soil fertility, access to water resources, climate variability, and the level of education, are expected to impact the community's economic performance.

Table 2 : Regression Analysis of Economic Structure and Geographic Factors

Variable	Coefficient (β)	Standard Error	t-Statistic	p-Value
Intercept (β_0)	5.32	2.15	2.48	0.014
Distance to Market (β_1)	0.78	0.12	6.50	0.000
Soil Quality (β_2)	0.45	0.18	2.50	0.013
Water Availability (β_3)	1.20	0.30	4.00	0.000

Climate Variability (β_4)	-0.30	0.20	-1.50	0.135
Education Level (β_5)	0.55	0.15	3.67	0.001
R square: 0.82 F statistics: 45.23				

Source: Computed by authors

This regression analysis results provide a detailed understanding of the relationship between various geographical factors and the economic activity of the Meo community in study area.The intercept term (β_0 = 5.32, p = 0.014) indicates the baseline level of economic activity when all the independent variables are set to zero. This suggests that the inherent economic activity, absent any of the geographical influences, is 5.32 units, and this value is statistically significant given the p-value of 0.014, which is less than the standard significance threshold of 0.05.The variable distance to market (β_1 = 0.78, p = 0.000) has a positive coefficient, indicating that as the distance to market increases, economic activity also increases, with each additional unit of distance contributing 0.78 units to economic activity. This relationship is highly significant, as evidenced by the p-value of 0.000, which suggests a strong and statistically reliable connection between market proximity and economic outcomes. The result underscores the importance of market access in influencing economic activity in the Meo community.

Soil quality (β_2 = 0.45, p = 0.013) also demonstrates a positive relationship with economic activity. A unit improvement in soil quality corresponds to an increase of 0.45 units in economic activity, and this relationship is statistically significant with a p-value of 0.013. This highlights the crucial role of agricultural land quality in fostering economic development, as better soil quality can lead to increased agricultural productivity and, by extension, greater economic engagement in agricultural activities. The coefficient for water availability (β_3 = 1.20, p = 0.000) is notably positive and highly significant, with a p-value of 0.000. This suggests that the availability of water resources is strongly associated with economic activity, with each additional unit of water availability contributing an increase of 1.20 units to economic activity. The statistical significance of this result further underscores the centrality of water

access in shaping economic outcomes, particularly for agricultural and other water-dependent activities.

The effect of climate variability (β_4 = -0.30, p = 0.135) is negative, suggesting that increased climate variability is associated with a decrease in economic activity. However, the p-value of 0.135 indicates that this relationship is not statistically significant at the 5% significance level. This result implies that while climate variability may have some effect on economic outcomes, its impact is not robust enough to be considered statistically significant in this model, suggesting that other factors may play a more substantial role in shaping economic activity. Education Level (β_5 = 0.55, p = 0.001) shows a positive and statistically significant relationship with economic activity. The coefficient indicates that for each unit increase in education level, economic activity increases by 0.55 units. The p-value of 0.001 confirms that this relationship is highly significant, emphasizing the importance of education in fostering economic growth and development. Higher education levels may equip individuals with better skills, improve productivity, and facilitate participation in more diverse economic activities.

The R-squared value of 0.82 suggests that the model explains 82% of the variation in economic activity, which indicates a strong fit and demonstrates that the selected geographical factors account for a substantial portion of the variation in economic outcomes. Additionally, the F-statistic of 45.23, with a p-value less than 0.001, indicates that the overall model is statistically significant. This suggests that the independent variables collectively provide a strong explanation for the variation in economic activity in the Meo community, affirming the relevance of these factors in shaping economic outcomes. The results of the regression analysis reveal that distance to market, soil quality, water availability, and education level all significantly contribute to explaining the variation in economic activity in the Meo community in study area. Notably, water availability and market access have the most substantial positive effects on economic outcomes. While climate variability does not show a statistically significant effect, the high explanatory power of the model, as evidenced by the R-squared and F-statistic, confirms that geographical and socio-economic factors play a vital role in determining economic activity in the region. These findings highlight the importance of strategic investments in infrastructure, education, and natural resource management to promote economic development in rural communities.

Conclusions

The geographical landscape of the Nuh district in Haryana plays a pivotal role in shaping the economic structure of the Meo community. The region's topography, climate, soil fertility, and accessibility to natural resources have significantly influenced the occupational choices and economic activities of the community. Predominantly an agrarian society, the Meo community's reliance on agriculture and allied sectors reflects the suitability of the land for cultivation and livestock rearing. Additionally, geographical isolation and limited infrastructure development have impacted the diversification of economic opportunities, constraining the community to traditional livelihoods.

The study highlights the interconnection between geographic factors and economic behavior, emphasizing how environmental constraints and opportunities shape the socio-economic fabric of the Meo community. The findings underscore the need for targeted development policies that address geographical challenges while leveraging local resources to promote sustainable economic growth and diversification in the region. By improving infrastructure, enhancing educational opportunities, and fostering non-agricultural employment, the economic resilience of the Meo community can be strengthened, paving the way for holistic regional development.

References

Centre, N. I., & Ministry of Electronics & Information Technology, G. of I. (2024). Nuh District, Government of Haryana. https://nuh.gov.in/

Constantine, C., & Khemraj, T. (2019). Geography, economic structures and institutions: A synthesis. Structural Change and Economic Dynamics, 51, 371–379.

Davis, D. R., & Weinstein, D. E. (2002). Bones, Bombs, and Break Points: The Geography of Economic Activity. American Economic Review, 92(5), 1269–1289.

Gallup, J. L., Sachs, J. D., & Mellinger, A. D. (1999). Geography and Economic Development. International Regional Science Review, 22(2), 179–232.

India, G. of. (2018). Aspirational Districts Baseline. In Niti Aayog.

Koyama, M., & Rubin, J. (2022). How the World Became Rich: The Historical Origins of Economic Growth. Polity Press. Polity

Krugman, P. (1999). The Role of Geography in Development. International Regional Science Review, 22, 178(August), 142–161. https://doi.org/10.1093/ajae/aau104

Kukreja, B. R. (2020). Meo Muslim , Mev , Mewati Muslim. July, 1–38.

Limão, N., & Venables, A. J. (2001). Infrastructure, Geographical Disadvantage, Transport Costs, and Trade. The World Bank Economic Review, 15(3), 451–479. https://doi.org/10.1093/wber/15.3.451

Montgomery, R. M. (2024). The Role of Geography in Economic Development : Insights from Historical and Modern Perspectives The Role of Geography in Economic Development : Insights from Historical and Modern Perspectives. Preprints.Org. https://doi.org/10.20944/preprints202410.0006.v1

North, D. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University press.

Ottaviano, G. I. P. (2008). Infrastructure and economic geography: An overview of theory and evidence. EIB Papers, 13(2), 8–35. http://hdl.handle.net/10419/44891

Plummer, P., & Sheppard, E. (2006). Geography matters: Agency, structures and dynamics at the intersection of economics and geography. Journal of Economic Geography, 6(5), 619–637. https://doi.org/10.1093/jeg/lbl005

Saha, B. (2013). Institutions or geography: Which matters most for economic development? Journal of Interdisciplinary Economics, 25(1–2), 69–89. https://doi.org/10.1177/0260107914524668

Sikand, Y. (2016). Meonis of Mewat. Economic and Political Weekly, 30(10), 490–492.

Avadhesh Kumar Meena
Research Scholar,
Department of Geography,
Institute of Science,
Banaras Hindu University
Varanasi, Uttar Pradesh
email: avgeographer@bhu.ac.in

Dr. Harpreet Singh
Assistant Professor,
Department of Geography,
Institute of Science,
Banaras Hindu University,
Varanasi, Uttar Pradesh
email: harpreetsingh@bhu.ac.in

Anju Jangid
Research Scholar,
Department of Rasa Shastra and
Bhaishjya Kalpana,
Faculty of Ayurveda,
Institute of Medical Science,
Banaras Hindu University,
Varanasi, Uttar Pradesh
email: anjuvns99@bhu.ac.in

Prof Anand Kumar Chaudhary
Department of Rasa Shastra and
Bhaishjya Kalpana
Faculty of Ayurveda
Institute of Medical Science
Banaras Hindu University
Varanasi, Uttar Pradesh
email; Anandayubhu@gmail.com

❑ ❑ ❑

Ambedkar's Thoughts on Minorities and Rights of Minorities in the Indian Constitution

• Dr. Prerna Malhotra

Dr. Bhim Rao Ambedkar's significance and continuing legacy have been examined within the context of the emancipation of marginalised sections of society. In this context, his concern for religious and linguistic minorities forms an integral part of his philosophical thoughts of equality, justice, and human rights which envision an inclusive and democratic India. Whether it is his 'State and Minorities' or his 'Pakistan or the Partition of India', constant support for the protection of the rights of minorities has been the central theme of these works. In 'State and Minorities', his support for linguistic recognition of states was based on his strong belief that unlike Abrahamic identities which are alien to India, regional and linguistic fault lines are not fundamental to the extent that they can divide a nation, as long as these fault lines are not encouraged. Further, in 'Pakistan or the Partition of India', he reflects on the 'Muslim Question' and why Muslims were not simply one among many of India's minorities. This argument gets validated when we notice the rampant violations of basic human rights of religious and ethnic minorities in our neighbouring countries. This paper while presenting a close reading of Ambedkar's position on religious and linguistic minorities also points out the present rights position of minorities in the Indian constitution and polity.

Introduction

Dr. B. R. Ambedkar famously known for his prominent role in drafting the Indian Constitution was at the forefront of ensuring the rights and protections of marginalised sections of the society namely untouchables, women, and minorities. His contribution to

building an inclusive and democratic India is unparalleled. For Ambedkar, religious pluralism, political democratisation, social and economic egalitarianism formed the foundations of an inclusive Indian nation. Also, it is worth noting that Ambedkar's pursuit of a 'caste-free society' was in sync with his ideas of building a modern Indian nation. He rightly described the idea of an Indian nation that does not include 'the people of India' as delusional. His concerns of an equal and inclusive India which is free from social evils like untouchability and entails the emancipation of Schedule Castes, women, and minorities were also shared by Veer Savarkar.

On the lines of inclusive India, Ambedkar was a strong proponent of democratisation of Indian society and polity. He believed that to protect the interests of the downtrodden and minorities, democracy could be the best form of socio-political ideology. It is in this context that the concept of the 'tyranny of the majority' was opposed by him due to the potential harm it could cause to democracy and also, he held the view that any form of power concentration was detrimental to the democratic ideals. Further, for Ambedkar, democracy was not just a form of government but it is also a mode of associated living and thus he rightly pointed out that political democracy would be incomplete without economic and social democracy.

Thus, for Ambedkar, a society and a country based on values of liberty, equality, and fraternity constituted the 'Ideal society' and 'Ideal Country'. It thus invariably involved the emancipation of not only untouchables but religious and linguistic minorities as well.

This paper while studying his often-overlooked works like 'States and Minorities' and 'Pakistan or the Partition of India' attempts to provide a detailed descriptive analysis of his thoughts on religious and linguistic minorities. It also entails the rights position of minorities in the Indian constitution and polity.

Ambedkar's Thoughts on Minorities

For Ambedkar, a democratic and inclusive India entails the protection of the rights of religious, linguistic, and ethnic minorities. He was of the view that considering the 'tyranny of the majority' in a liberal representative democratic state, the rights of marginalised sections including minorities can be best protected by way of constitutional safeguards for them. In this context, in his work titled

‘States and Minorities’, he provides a comprehensive examination of the concept of minority, including its definition, the principles that support minority representation, the electoral process for selecting minority representatives, and safeguards to protect against potential discriminatory actions by the legislative majority. Though the central theme of this work revolves around recognising Schedule Caste as a minority yet his support for constitutional mechanisms for the protection of the rights of religious and linguistic minorities is worth noticing (Ambedkar, 1947/2014e: 383-384).

Further, his second such work dealing with minorities is ‘Pakistan or the Partition of India’, where he reflects on the ‘Muslim Question’ and why Muslims were not simply one among many of India’s minorities. This work also deals with the issue of Kashmir and overall presents an insightful critique of the Nehruvian foreign policy.

In light of these two major works, a detailed analysis of Ambedkar’s thoughts on religious and linguistic minorities follows here.

A. On Religious Minorities

India has many religious groups, of which Hindus are a majority, and Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, and Jains are minorities. Ambedkar’s thoughts regarding religious minorities can be primarily found in his work on Pakistan. Ambedkar believed that all individuals, regardless of their caste, religion, or minority status, have the right to live in India with full dignity. It is worth noting that he also advocated for equal rights, liberties, and equitable political representation for India’s largest minority group namely Muslims.

However, his critical analysis and the ‘Muslim Question’ and ‘Pakistan Case’ is often overlooked in the academic discourse. The Muslim League demanded a separate state for Muslims namely Pakistan as part of their ‘Lahore Resolution’. On this issue, Ambedkar came up with his monumental work ‘Pakistan or the Partition of India’, where he reflects how India’s largest minority group namely Muslims was not simply one among many of India’s minorities and endorsed the idea of a separate state for Indian Muslims.

Ambedkar’s support for the idea of partition was based on several arguments. Firstly, he believed that Mahatma Gandhi's

efforts to appease the Muslim League and other Muslim groups were unsuccessful, as Muslim demands remained unending. Secondly, Ambedkar argued that Hinduism and Islam were not just different sects or castes, but distinct nations with irreconcilable destinies. Thirdly, he believed that the significant presence of Muslims in the pre-partition armed forces made it difficult to trust them to defend a Hindu-majority India from Muslim countries' aggression post-independence. Lastly, Ambedkar expressed concerns about the safety, security, and progress of an independent India without the British as a disinterested third party overseeing the governance of Hindus and Muslims.

Though he expressed his unhappiness withthe partition, he stated clearly, "I was glad that India was separated from Pakistan. I advocated partition because I felt that it was only by partition that Hindus would not only be independent but free. If India and Pakistan had remained united in one state Hindus though independent would have been at the mercy of Muslims. A merely independent India would not have been a free India from the point of view of the Hindus. It would have a government of one country by two nations and the Muslims without question would have been the ruling race notwithstanding Hindu Mahasabha and Jana Sangh." (Ambedkar, 2014: 356-360). Thus, his endorsement of the idea of Pakistan was grounded in practical considerations and reflected his perspective on achieving a workable political entity for the Indian state.

Also, Ambedkar had an underlying suspicion of Jinnah. In his book 'Pakistan or The Partition of India' he criticised Jinnah for the tabulation of his 14 points including his demands like Discarding the song- 'Vande Mataram', Freedom for Muslims to perform Cow slaughter, or making changes to the 'Tri-colour'. Further, he was of the opinion that Muslims are exploiting Hindus and using their outrageous demands to force the Hindus into the negotiation tables. In this context, he rightly states that "the second thing that is noticeable among the Muslims is the spirit of exploiting the weaknesses of the Hindus. If the Hindus object to anything, the Muslim policy seems to be to insist upon it and give it up only when the Hindus show themselves ready to offer a price for it by giving the Muslims some other concessions" (Ambedkar, 2014: 456-460).

Further, dwelling deep in his work 'Pakistan or The Partition

of India', we find that Ambedkar's thoughts on religions are grounded in practical considerations and he made a clear distinction between Indic and Abrahamic faiths. In this context, talking about Islam as an Abrahamic identity's alien nature to India, Ambedkar viewed it as a "closed corporation" which is a brotherhood not of all humanity but of Muslims only. He finds the Islamic governance system incompatible with the democratic ideals which India strives to achieve and thus viewed Indian Muslims as not just another minority group but a different nation within India altogether. Thus, it was in the interests and safety of India and Hindus, if Pakistan were to be acceded to Muslims who wanted it at any cost. Also, he advocated the idea of total population transfer in case partition was to happen on religious lines. Apart from this, Ambedkar also emphasised discriminatory provisions prevalent in Muslim personal laws and advocated for equal rights for Muslim women. He says, "The Muslim woman is the most helpless person in the world" (Ambedkar, 2014: 471-480).

Similarly, tracing the non-Indic identity of Christianity, Ambedkar was of the view that Christianity as a religion was irrelevant to affect any social movement. From his interactions with the Christians of the Madras Presidency, he concluded that missionaries think of conversions in the name of equality and but inequalities in race, language, and caste continue to exist for untouchables despite conversion. In this context of religious conversions to non-Indic faiths, Ambedkar rightly believed that "if Dalits converted to non-Indic religions, they become denationalized. If converted to Christianity, they strengthen the hold of Britain on the country" (Choudhary, 2021). Further, he also called out the Christian conversions via deceitful means unethical, and against rational reasoning.

Though Ambedkar emphasised the positive role of religion in the making of an inclusive India at the same time his critical observations on social evils present in the religious doctrines led to socio-religious reforms,particularly in Hindu Dharma. Though Ambedkar may have criticised Hinduism he didn't hate the history of the land, he hated the superstitious culture that was prevailing in his era and the gross inequality of the caste. Also, he believed in the potential of Hinduism to purge itself of these evils. As he clearly points out, "Hindus have their social evils. But there is this relieving

feature about them-namely, that some of them are conscious of their existence and a few of them are actively agitating for their removal" (Debnath, 2022: 136-145). Ambedkar's embracing of Buddhism can be seen in this context. As Keer (1971) rightly points out, "He chose Buddhism because it is a part and parcel of Bharatiya culture and his conversion will not harm the tradition of the culture and history of this land" (Keer, 1971: 498).

Ambedkar's constant search for egalitarianism in religious philosophy and practices forms the basis of his position on a Uniform Civil Code as well. In this regard, his statement in the Constituent Assembly debate on the Uniform Civil Code is worth noting. He said, "I personally do not understand why religion should be given this vast, expansive jurisdiction, so as to cover the whole of life and to prevent the legislature from encroaching upon that field. After all, what are we having this liberty for? We are having this liberty in order to reform our social system, which is so full of inequities, discriminations, and other things, which conflict with our fundamental rights" (Constitution of India, 2023). Thus, for Ambedkar, an ideal democratic and inclusive India entails equality of laws and equal protection of the rights of all Indian citizens including religious and linguistic minorities.

B. On Linguistic Minorities

Ambedkar's thoughts regarding linguistic minorities have been majorly entrusted in his work namely 'State and Minorities'. The major concern of this book is to make a case for 'Schedule Caste' as a minority. However, this work also entails his overall concern for all the marginalised sections of society including women and linguistic minorities. This work while advocating for the fundamental rights of minority groups and ScheduledCastes in India also stipulates recommendations for their constitutional safeguards in the country.

In this context, Ambedkar's proposition for the establishment of linguistically homogenous stems from his overall concern aboutthe rights protection of linguistic minorities. His support for linguistic recognition of states was guided by his democratic principles and recognition of the significance of political and cultural representation for regions (Ambedkar, 2014: 137-201). Further, his definition of a linguistic state strengthened his case for linguistic states which according to him entailed, "It can mean that all people

speaking one language must be brought under the jurisdiction of one state. It can also mean that people speaking one language may be grouped under many states provided each state has under its jurisdiction people who are speaking one language" (Sharma, 2015). Thus, he advocated for the adoption of a single language in each state to ensure the development, justice, equality, and freedom of marginalised sections of society including linguistic minorities.

Ambedkar's thoughts on the linguistic formation of states and the duly recognition of regional languages transcended the narrow politically motivated linguistic chauvinism of the present time. This gets reflected in his thoughts on 'Nationalism' which according to him entails the inclusiveness of all Indians and the importance of being 'Indian first' and 'India first'. As he rightly says, "I do not want that our loyalty as Indians should be in the slightest way affected by any competitive loyalty whether that loyalty arises out of our religion, out of our culture or out of our language. I want all people to be Indians first, Indian last, and nothing else but Indians" (Ambedkar, 2014g: 309). Also, his support for linguistic recognition of states was based on his strong belief that, unlike Abrahamic identities which are alien to India, regional and linguistic fault lines are not fundamental to the extent that they can divide a nation, as long as these fault lines are not encouraged politically. Further, his support for the creation of small states to reduce regional economic disparities bodes well for achieving social and economic equality across different regions and classes.

Minorities in the Indian Constitution

"No democracy can long survive which does not accept as fundamental to its very existence the recognition of the rights of minorities". This statement by Franklin D. Roosevelt clearly portrays the importance of protecting the rights of minorities in a democracy. India, being the largest democracy, has a significant population consisting of individuals from diverse religious, linguistic, and cultural backgrounds. The religious minority groups, namely Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, Jains, and Zoroastrians make up about 20 percent of the total population.

The term 'Minority' is not defined explicitly in the Indian Constitution; instead, it only references 'Minorities' and specifies them based on religion or language. However, the Constitution

provides a comprehensive account of the rights of minorities. Though through the 42nd Amendment, the State is declared as 'Secular' in the Preamble of the Constitution, the Indian Constitution explicitly ensures the right to religious freedom through articles 25-28, which also elucidate the protection of minority rights under various fundamental provisions. Additionally, articles 29 and 30 of the Constitution safeguard the interests of minorities. Article 29 guarantees the entitlement of any group of citizens to preserve their unique language, script, or culture. On the other hand, Article 30 grants minorities the privilege to establish and manage educational institutions according to their preferences (Constitution of India, 2023).

Similarly, for linguistic minorities too, many such constitutional provisions exist. Article 347 of the Constitution allows for the President to issue directives to acknowledge languages spoken by a significant portion of a state's population or its specific regions for specific purposes outlined by the President. Article 350 grants individuals the right to present grievances to any authority of the Union or a State using any of the languages employed by the Union or the respective States. Additionally, article 350A mandates the provision of primary education instruction in the mother tongue for children belonging to linguistic minority groups (Constitution of India, 2023).

Aside from the constitutional protections, India has established numerous statutory and non-statutory bodies and enacted special acts over time to uphold the rights of minorities. Among these, the National Commission for Minorities (NCM) holds a significant role, established under Article 338-A of the Constitution, with the specific responsibility of safeguarding the constitutional rights of minorities and redressing their grievances. Similarly, Commissioner for Linguistic Minorities under article 350-A takes up all matters relating to safeguards for linguistic minorities brought to their notice by linguistic minorities-individuals/groups/associations/ organizations, etc.

Moreover, a notable stride towards minority empowerment was taken in 2006 with the establishment of the Ministry of Minority Affairs, tasked with formulating and implementing policies aimed at the welfare of minorities. Its different schemes have led to the

betterment of the socio-economic and educational status of minority communities. Many commissions and committees were established to suggest measures for the social, educational, and economic empowerment of Minorities. In this context, the Sachar Committee report and Ranganath Mishra Commission are important whose recommendations have been incorporated by the governments for the welfare and empowerment of minorities.

Thus,theIndian Constitution is known for its comprehensive rights protections for its religious and linguistic minorities. These arrays of constitutional provisions and institutional bodies ensure the preservation of cultural identity and the provision of education in alignment with the values and beliefs of minority communities.

Conclusion

Today, Dr. Ambedkar is a synonym for human rights, equality, and justice everywhere. His preoccupation with these concerns established him not only as a national icon but a global figure as well. Ambedkar believed that the foundations of an inclusive and democratic India rest on the premise of religious pluralism, political democratisation, social and economic egalitarianism, and emancipation of marginalised sections of society including religious and linguistic minorities.

Ambedkar's thoughts on the 'Muslim Question' and the 'Pakistan Case' reminds us of the sharp distinctions that Ambedkar made between Indic and non-Indic faiths. Further, today, when we see the civilizational tragedy in the form of rampant violations of basic human rights of women, and religious and linguistic minorities by state and non-state actors in our neighbouring countries Pakistan and Bangladesh which were partitioned of undivided India, we get reminded of Ambedkar's case for Pakistan and the issue of total population transfer.

India is a civilisational country, and its traditions, culture, and constitution entail comprehensive rights for religious and linguistic minorities. These rights' protections have added to the prosperity and dignity of minority communities in India. In continuation of the same, whether it is the outlawing the practice of Triple Talaq or the Prime Minister's New 15 Point Programme for the welfare of Minority Communities, the Indian political dispensationsare

committed to Ambedkar's vision of inclusive India in the spirit of the slogan of 'New India' that is 'Sab ka Saath, Sab ka Vikas, Sab ka Vishwas'.

References

1. Ambedkar, B. R. (2014a). Dr. Babasaheb Ambedkar:Writings and speeches, Vol. 1, pp. 23-96. Dr. Ambedkar Foundation,Ministry of Social Justice and Empowerment, New Delhi.
2. Ambedkar, B. R. (2014e). "States and minorities",Dr. Babasaheb Ambedkar:Writings and speeches, Vol. 1, pp. 381-449. Dr. Ambedkar Foundation,Ministry of Social Justice and Empowerment, New Delhi.
3. Ambedkar, B. R. (2014g). "The triumph of Brahmanism: Regicide or the birth of counter-revolution",Dr. Babasaheb Ambedkar:Writings and speeches, Vol. 3, pp. 266-331. Dr. Ambedkar Foundation,Ministry of Social Justice and Empowerment, New Delhi.
4. Ambedkar, B. R. (1979). "Thoughts on the Linguistic States",Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches, Vol. 1, pp. 137-201. Dr. Ambedkar Foundation, Ministry of Social Justice and Empowerment, New Delhi.
5. Ambedkar, B. R (2014). "Pakistan or the Partition of India." Dr. Babasaheb Ambedkar:Writings and Speeches, Vol. 8, pp. 1-480.Dr. Ambedkar Foundation, Ministry of Social Justice and Empowerment, New Delhi.
6. Centre for Democracy, Pluralism and Human Rights (CDPHR) (2023). Available at: https://www.cdphr.org/Pakistan%20report.pdf. Dated. 2-04-2023.
7. Choudhary, V. K. (2021). The idea of religious minorities and social cohesion in India's constitution: Reflections on the Indian experience. Religions, 12(11), 910. Accessed Via:doi:https://doi.org/10.3390/rel12110910. Dated. 5-04-2023.
8. Debnath, K. (2022). Reappraising BR Ambedkar's Thoughts of Inclusive Indian Nation. Contemporary Voice of Dalit, 14(2), 136-145.
9. Government of India (2023). Constitution of India.Available at: https://legislative.gov.in/constitution-of-india/. Dated. 3-04-2023.

10. Keer, D. (1971). Dr. Ambedkar: life and mission. Popular Prakashan.
11. Ministry of Minority Affairs (2023).Government of India. Accessed Via: https://www.minorityaffairs.gov.in/index.php. Dated. 4-04-2023.
12. National Commission for Minorities (2023). Government of India. Accessed Via: https://www.minorityaffairs.gov.in/index.php. Dated. 1-04-2023.
13. National Minorities Development & Finance Corporation (NMDFC) (2023). Available at: https://www.nmdfc.org/. Dated. 1-04-2023.
14. The Hindu Desk, May 20, 2022. Accessed Via:https://www.thehindu.com/news/national/bjp-considers-all-indian-languages-soul-of-bharatiyata-says-pm-modi/article65439065.ece. Dated: 2-04-2023.
15. Sharma, M. (2015). Ambedkar'sStruggle for Empowerment of Downtrodden. International Journal of Research in Economics and Social Sciences, 5(6).

Dr. Prerna Malhotra
Associate Prof.,
Dept. of English, Univ. of Delhi

❑ ❑ ❑

Poverty Deprivation Among Social Groups in Thellur Village : A Case Study

Dr. Shivanand Pawar • Dr. Lakshmana G
Dr. Mahantagouda Patil • Dr. Ahalatha R

The present study attempts to describe and compare the poverty among various social groups in Thellur village, Kalaburagi District, Karnataka, India. For the study, 145 households (complete enumeration) were chosen and interviewed with the help of an interview guide. The outcome indicated that the village has 104 General Category (GC), 32 Schedule Caste (SC), and nine Other Backward Classes (OBC) settlements. Results show that 32% of GC, 36% of SCs and 44% of OBC families had poverty status. Comparatively, it was found that the SCs and OBCs had high poverty and low living standard. It was observed that most households from these two groups are farmers and labourers. The overall poverty index of the entire Thellur village was 26% deprivation, which is similar to the other developing countries.

Keywords : *Poverty, Deprivation, Global Multidimensional Poverty Index*

Introduction

Poverty is generally classified as absolute poverty and relative poverty (Prabhavathi & Naveena, 2014). Absolute poverty, equable to destitute, exists when people cannot acquire satisfactory resources (measured by calories or nutrition) to support a minimum level of their physical health and it is often referred to as the deprivation of fundamental human needs, which include food, water, sanitation, clothing, shelter, healthcare, and education. "Relative poverty is defined contextually as economic inequality in the location/ society in which people live. It occurs when people do not enjoy

a certain minimum level of living standard (as enjoyed by the bulk of the population) and determined by a government) that varies from country to country, sometimes within the same country" (Prabhavathi & Naveena, 2014). Blackwood & Lynch (1994) reported that "Poverty is being unable to meet 'basic needs' such as physical (food, health care, education, shelter etc.) and non-physical (participation, identity, etc.) requirements for a meaningful life". According to the United Nations, (1998) "Fundamentally, poverty is a denial of choices and opportunities, a violation of human dignity". It means a lack of basic capacity to participate effectively in society. It means not having enough to feed and clothe a family, not having a school or clinic to go to; not having the land on which to grow one's food or a job to earn one's living, and not having access to credit. It means insecurity, powerlessness, and exclusion of individuals, households, and communities. It means being susceptible to violence and living in marginal or fragile environments, without access to clean water or sanitation". In Indian society, social groups have been historically classified as Schedule Cast (SC), Scheduled Tribe (ST), Other Backward Class (OBC), and General Category (GC).

Poverty is not limited to one or two countries of the globe or one or the other part of the world. This is a global phenomenon which creates a dilemma for the overall growth of the world. The World Bank (2015) reported that globally, extreme poverty has declined drastically. World Bank (2011) reported that 1 billion people i.e., 14.5 % of the world's population could be classified as extremely poor, down from 1.25 billion or 18.6% of the world's population in 2008. Yet less than half of the population in developing countries lives on a dollar or less a day which is absolutely below the numerical measurement of the poverty line (World Bank, 2015). Among the Asian countries, 450 million of the poor still exist in India, 225 million in China, and 55 million in Southeast Asia (UNDP, 2006-07) (Baikady, Pulla, & Channaveer, 2017).

Defining Deprivation:

"Deprivation is a state of observed and demonstrable disadvantage relative to the local community or the entire society or nation to which an individual, family or group belongs" (Townsend, 1987).

Global Multidimensional Poverty Index Report (2018) noted that around 1.3 billion of the population lived in multidirectional poverty in the 105 world's developing countries, which represents nearly 23 per cent of the world population and these were being left behind in several ways. They were deprived of components such as health, education, and living standards, lacking in such basic things as clean drinking water, clean sanitation, and adequate nutrition. In India, it was reported that 364 million people were living in multidimensional poverty in the country (Poverty& Human Development Initiative, 2018).

As per the Karnataka Economic Survey Report (2009-10) from 1973 to 2010 rural poverty in Karnataka state declined by 39 per cent which is higher by 5% as compared to the decline at the national level. The total number of rural poor declined over some time. The State urban deprivation (28%) declined but at a lesser level than rural (30%). The decline in the poverty rate was not sufficient to address the growth in the state's urban population. Hence, the total number of urban poor had gone up both in the state and the nation as a whole between 1973-74 and 2004-05. The growth of the urban poor was higher in the state than that of the whole nation year on year. The poverty deprivation within Karnataka was 31%; when comes to rural it was 18% and urban it was 26%. At the country level, the deprivation rate was 32%, with rural 37% and urban 20% (Prabhavathi & Naveena, 2014).

Borooah et al. (2014) reported that households from the scheduled caste were more likely to be in a low probability of expenditure and more probability of being poor, compared to high-caste Hindu households in the county. Motiram & Naraparaju (2015) reveal that absolute and relative poverty and deprivation were more in scheduled caste and scheduled tribes than other social groups because marginal farmers and wage labourers belong to these two groups. Ngwane et al. (2002) highlighted that more than half of the rural households did not have access to safe drinking water, or electricity, and lacked sanitation facilities. Hence more households become deprived and poor in rural Africa. Nasri & Belhadj (2017) reported that the poverty rate at the rural level had

gone beyond the national poverty rate, and therefore policymakers have to look to enhance the living standards of poor households. Gang et, al (2008) observe that in Indian society social groups are historically classified as Schedule Cast (SC), Scheduled Tribe (ST), Other Backward Class (OBC), and General Category (GC). Poverty among Scheduled Castes and Scheduled Tribe stood at 21%. This was because Scheduled Caste and Scheduled Tribe households were more dependent on agriculture and self-employment. Hence these two groups have more poverty and deprivation than other groups in India. Tikhonova and Slobodeniuk (2015) note that household incomes may be higher than sufficient, but their real situation in life may put households in a deprivation position.

Problem Statement:

Though studies described poverty and deprivation from a larger perspective, there are no research studies which describe poverty and deprivation of different social groups from the rural perspective. This study would help to understand the main causes and factors that contribute to poverty and deprivation at the rural level. The significance of this study is that it looks at the poverty deprivation phenomena and has put together a report which would help in framing the policy and help prepare an action plan at the Gram Panchayat level. There is a need to take up micro-level studies to understand poverty deprivation among rural people.

The objectives of the study are to analyze the poverty status among the various social groups and assess the living standard of different social groups within the community.

Methods

The researcher followed a descriptive survey design to describe the phenomenon of poverty and deprivation at the community level. Thellur village was selected, and all households were included in the study (complete enumeration). Primary data was collected from 145 households using the interview method, while secondary data was obtained from the Gram Panchayat, for analyzing the poverty and deprivation status of the village.

Study area: Thellur community is one of the backward communities in Aland taluka of Kalaburagi district in Karnataka, as per the 2011 India census, The community consists of 145 houses with a population of 1005 comprising 511 males and 494 females.

The major occupation of the community is agriculture with Brown gram, sunflower, groundnut, jawar, and cotton being the major crops.

The following **tools were used for the study**

Analysis

To test the study objective used The Global Multidimensional Poverty Index (MPI) tool was co-designed and launched in 2010 by the United Nations Development Program (UNDP) and Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI). The tool uses different factors to determine poverty beyond income-based lists. The MPI assesses poverty at the individual level (The Global Multidimensional Poverty Index (MPI) 2018). MPI uses ten indicators and 3 dimensions to determine poverty. The same tool is used in this study (Table 1).

Table 1: **Multidimensional Poverty Index (MPI)**

Dimension & Weight	Indicators
Health (1/6)	• Child mortality
	• Nutrition
Education (1/6)	• Years of schooling
	• School attendance
Living standard (1/18)	• Cooking fuel
	• Toilet
	• Water
	• Electricity
	• Floor
	• Assets

Sources : (Alkire, S., Jindra, C., Robles, G., & Vaz, A. (2016). Multidimensional Poverty Index 2016: Brief methodological note and results. OPHI briefing, 42, 2.)

Calculating the Village Multidirectional Poverty Index

The Village Multidimensional Poverty Index was calculated using the formula MPI= H x A Where

H: Percentage of people who are MPI poor (incidence of poverty)

A: Average intensity of MPI poverty across the poor (%)

As per the guidelines, a person or household is considered poor if they are deprived in at least a third of the weighted indicators. The intensity of poverty denotes the proportion of indicators which they are denied.

The data was analyzed manually as per the tool guidelines (See Annexure 1)

Results

Descriptive Statistic

Table 2 describes the socio-demographic information of the village. The total population of the village was 1005, comprising 145 households. Among those, three houses are permanently locked. The village has different caste and religions, and they live harmoniously.

Table 2: Socio- demographic Data

Variables	Value label	Number
Population	Men	511
	Women	494
	Total	1005
Caste (Houses)	GC	104
	SC	32
	ST	0
	OBC	9
	Total	145
Religions (Houses)	Hindu	140
	Muslim	5
	Total	145
Type of Families (Houses)	Below Poverty Line (BPL)	117
	Antyodaya	24
	Above Poverty Line (APL)	3
	Don't have	1
	Total	145

(Source: Field Survey)

Poverty Index of General Category (GC) families

Table 3 describes the MPI of GC families in Thellur village (Appendices 1).

Table 3 : Poverty indexes of GC social groups

Factors	Values
Factor H for GC Families of Thellur village H= 54/104	0.5192
Factor A for GC Families of Thellur village A=3343.81/54	0.6192
MPI=H x A	0.3214

(Source: Field Survey)

Poverty Index of Other Backward Classes (OBC) families

Table 4 : describes the MPI of OBC families in Thellur village (Appendices 2).

Factors	Values
Factor H for OBC Families of Thellur village H=7/9	0.7777
Factor A for OBC Families of Thellur village A=394.40/7	0.5634
MPI =H x A	0.4381

(Source: Field Survey)

Poverty Index of Scheduled Caste (SC) families

Table 5 : Poverty index of SC social groups

Factors	Values
Factor H for SC Family of Thellur village H=23/32	0.7187
Factor A for SC Family of Thellur village A=1161.00/23	0.5047
MPI =H x A	0.3627

(Source: Field Survey)

Table 5 describes the MPI of SC families in Thellur village (Appendices 3). Here H factor explains the percentage of poverty in SC families as 0.7187. A factor explains the intensity rate of SC families as 0.5047 and the MPI of SC families in Thellur village as 36.27%. This is the poverty level across the poor SC families in the village.

Overall poverty index of the Thellur village

Table 6 : Multidimensional Poverty Indexes (MPI) across social groups of Thellur Village

Factors	GC	OBC	SC	Total Values of village
H factor explains the percentage of people who become MPI poor; (occurrence of poverty) rate.	0.5192	0.7777	0.7187	0.5793
A factor explains the average extent of MPI poverty across the poor (%) rate.	0.6192	0.5634	0.5047	0.4536
Multi-Dimensional Poverty Index	0.3214	0.4381	0.3627	0.2627

(Source : Field Survey)

The overall poverty index was calculated by using ten indicators of the Multidimensional Poverty Index and their weighted scores. Table 6 explains the poverty deprivation rate across social groups of families as well as that of the entire Thellur village. MPI H factor explains the percentage of people who have become MPI poor; (occurrence of poverty) the rate shown is 0.5793. MPI. A factor explains the average extent of MPI poverty as 0.4536 across the poor. The overall poverty and deprivation index of their community was 26.27%. The GC families' poverty status was 32.14%, SC families' poverty status was 36.27%, and OBC families' poverty status was 43.81% Compared to all social groups, OBC Social group poverty,

and deprivation status are very high, and living standard status was very low.

Discussion

Poverty in a developing society tends to be generally more widespread and is evident in most developing countries. India is one of the developing countries and, as per the 2011 census, 69% of the population lives in villages and 54% population depends on agriculture (Ministry of Agriculture & Farmer Welfare, 2017). Villages are the backbone of India and all the successive governments have tried to eradicate poverty and improve the quality of life of its rural population. In the present study, an attempt was made to study poverty deprivation among social groups in a village. For the study purpose, the researcher visited the village multiple times and established rapport. Poverty deprivation of the various social groups shows that GC families have low poverty status, whereas SC families have medium poverty status and OBC families have very high poverty status in the community. Therefore, GC families have a higher living standard, SC families have medium, and OBC families have very low living standards in the community. Overall, the poverty status of the community (26.28%) has high poverty and low living standard in the district. As per the 68th National Sample Survey Report, there was 37.06% of SC, 27.75% of OBC, and 21.62 GC and the overall poverty deprivation in Kalaburagi district was 38.09% (Niranjan & Shivakumar, 2018). Panagariya & Mukim, 2014) reported that Karnataka State had 23.8% poverty whereas looking at other social group-wise poverty rates stood at SC 34%, ST 24%, OBC 24%, and GC 16.7%. This study found 26.28% poverty- deprivation in Thellur village which is below the district average. It also observed that OBC families had high poverty depravation in the village, behind the SC families. This is due to high child mortality, malnutrition, low years of schooling and school attendance, no proper cooking fuels, no proper toilet, no clean water, and no proper housing and electricity at the community and district level.

Kerstenetzky, C. L., & Santos, L. (2009) study which was conducted in Rio de Janeiro shows that poverty deprivation was 0.67, whereas the present study reported 0.26 in the Thellur Village.

This study shows that even the poverty rate in the small village of Karnataka state is quite similar to the poverty rates found among other underdeveloped countries.

Implications for Social Work Practice

There is a need to study the phenomena of child mortality, malnutrition, under-nutrition, number s of schooling years, school attendance, clean water housing and electricity status of the village. Based on this report respective Gram Panchayaths and local governments may frame policy, prepare locally adoptable plans and take action to address these issues. Social Work is practice-based and has the responsibility of taking up locally adaptable interventions. This study demonstrates that social workers can take up poverty assessment in the community, and prepare plans applicable. Working in collaboration with the local governments and linking with government policies and programs for the development of the community would help. India has many schools which are three tiers, two-tier and rural-based. These institutions can use this study for their fieldwork practice, training students in assessing the villages and preparing an action plan for community development and empowerment.

Limitations

The limitation of the study was focused only on the rural families In Thellur Village of Kalaburagi District of Karnataka State and other villages of the same region were excluded in the study. The village was heterogeneous and it covered all the GC, OBC, and SC households in the village. The researcher followed a survey method to collect the research data. The result of the study can generalize to every rural village of Kalaburagi District of Karnataka State.

Conclusion

In this paper, the researchers examined poverty and deprivation in the rural community of Karnataka state in India. However, Poverty and deprivation are closely related; where poverty is present deprivation exists. The crisis of poverty is a vicious circle - a small level of investment is the result of low-level production; a low level of production is the result of a low level of saving. After analyzing the data, it was found that poverty, deprivation, unemployment, low saving and purchasing power were the problems faced by social

groups in the village. Therefore, GC families had low poverty status and high living standard (32%), SC families had medium poverty status and medium living standard (36%) than GC families and OBC families had higher poverty and low living standard (45%). Comparison among the three groups shows that (32%) of SC and (45%) of OBC had higher poverty and deprivation because most of the houses from these two groups belong to farmers and wage laborer in the community. The village as a whole has 26.28% of poverty and deprivation, which is similar to the other developing countries.

References :

1. Alkire, S., Jindra, C., Robles, G., & Vaz, A. (2016). Multidimensional Poverty Index 2016: Brief methodological note and results. OPHI briefing, 42, 2.
2. Alkire, S., Kanagaratnam, U., & Suppa, N. (2018). The global multidimensional poverty index (MPI): 2018 revision. OPHI MPI methodological notes, 46.
3. Alkire, S., Roche, J., Santos, M., & Seth, S. (2011). Multidimensional poverty index 2011: brief methodological note.
4. Baikady, R., Pulla, V., & Channaveer, R. M. (2017). Rural Poverty and Social Work: Three Models. International Journal of Social Work and Human Services Practice, 5(1), 25-28.
5. Blackwood, D. L., & Lynch, R. G. (1994). The measurement of inequality and poverty: A policy maker's guide to the literature. World development, 22(4), 567-578. https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)90112-0
6. Borooah, V. K., Diwakar, D., Mishra, V. K., Naik, A. K., & Sabharwal, N. S. (2014). Caste, inequality, and poverty in India: A re-assessment. Development Studies Research. An Open Access Journal, 1(1), 279-294. https://doi.org/10.1080/21665095.2014.967877
7. Gang, I. N., Sen, K., & Yun, M. S. (2008). Poverty in rural India: caste and tribe. Review of Income and Wealth, 54(1), 50-70.
8. Kerstenetzky, C. L., & Santos, L. (2009). Poverty as deprivation of freedom: The case of Vidigal Shantytown in Rio de Janeiro. Journal of Human Development and Capabilities, 10(2), 189-211. https://doi.org/10.1080/19452820902940893

9. Motiram, S., & Naraparaju, K. (2015). Growth and deprivation in India: What does recent evidence suggest on "Inclusiveness"? Oxford Development Studies, 43(2), 145-164. https://doi.org/10.1080/13600818.2014.988693

10. Nasri, K., & Belhadj, B. (2017). Multidimensional poverty measurement in Tunisia: distribution of deprivations across regions. The Journal of North African Studies, 22(5), 841-859. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/83318/

11. Ngwane, A. K., Yadavalli, V. S., & Steffens, F. E. (2002). Poverty: Deprivations in terms of basic needs. Development Southern Africa, 19(4), 545-560. https://doi.org/10.1080/0376835022000019400

12. Niranjan, R. and Shivakumar. (2018). Poverty across socio religious groups in Karnataka by using NSSO data. International Journal of Creative Research Thoughts, 6(1), 479-498.

13. Panagariya, A., & Mukim, M. (2014). A comprehensive analysis of poverty in India. Asian Development Review, 31(1), 1-52.

14. Ministry of Agriculture & Farmers Welfare. (2017). Pocket Book of Agricultural Statistics. Government of India Ministry of Agriculture & Farmers Welfare New Delhi, 27-32.

15. Poverty, O., & Human Development Initiative. (2018). Global Multidimensional Poverty Index 2018: The most detailed picture to date of the world's poorest people. University of Oxford, UK.

16. Prabhavathi, P.O. and Naveena, N. (2014). An analysis of poverty in Karnataka: A study. Journal of Humanities and Social Science, 19(3), 27-31.

17. Tikhonova, N. E., & Slobodeniuk, E. D. (2015). The heterogeneous character of Russian poverty through the prism of the "deprivation" and the "absolute" approaches. Sociological Research, 54(1), 20-40. http://dx.doi.org/10.1080/10610154.2015.1068605

18. Townsend, P. (1987). Deprivation. Journal of social policy, 16(2), 125-146. https://doi.org/10.1017/S0047279400020341

19. United Nations. (1998). Statement of commitment for action to eradicate poverty adopted by administrative committee on coordination. In Meetings coverage and press releases, ECOSOC/5759. New York City.

20. World Bank. (2011). World bank sees progress against extreme poverty, but flags vulnerabilities. Press Release.

21. World Bank. (2015). Global monitoring report 2014/2015: ending poverty and sharing prosperity. The World Bank. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0336-9

Annexures

Annexure 1: Fictional Analyses

Village X consists of family A, B, and C. The following table shows the deprivation on each of the 10 indicators for family A, B, and C. "0%" indicates no deprivation in that indicator, while "100%" indicates deprivation in that indicator.

Indicator	Weight	Family A	Family B	Family C
1	1/6	0%	0%	0%
2	1/6	0%	0%	0%
3	1/6	100%	100%	0%
4	1/6	0%	100%	0%
5	1/18	0%	100%	100%
6	1/18	0%	100%	100%
7	1/18	0%	0%	100%
8	1/18	100%	100%	100%
9	1/18	100%	0%	100%
10	1/18	100%	0%	0%
Weighted score		33.33%	50.00%	27.78%
Status		MPI poor (≥ 33%)	MPI poor (≥ 33%)	Not MPI poor (< 33%)

Factor H for Village X is : $\frac{1+1+0}{03} = 0.667$

Factor A for Village X is : $\frac{33.33\%+50.00}{02} = 0.417$

Thus MPI for Village X is 0.667 X 0.417 = 0.287

Sources : (Alkire, S., Roche, J. M., Santos, M. E., & Seth, S. (2011). Multidimensional poverty index 2011: brief methodological note).

Annexure 2 : Poverty Indexes of GC Social Groups

Indicators and Weight

Household number	Child Mortality (1/6)	Nutrition (1/6)	Years of Schooling (1/6)	School Attendance (1/6)	Pacca House (Floor) (1/18)	Drinking Water (1/18)	Toilet (1/18)	Electricity (1/18)	Cooking Fuel (1/18)	Assets (1/18)	Weighted score
H1	0	0	0	0	100	0	100	0	100	**100**	22.22%
H2	0	0	100	100	100	0	0	0	0	0	38.88%
H3	0	0	100	100	100	0	100	0	100	0	50%
H4	0	0	0	100	0	0	100	0	0	0	22%
H5	0	0	100	100	0	0	100	0	0	0	38.88%
H8	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	5.55%
H10	0	0	100	100	0	0	100	0	0	0	38.88%
H11	0	100	100	100	0	0	100	0	0	100	61.11%
H12	0	0	100	100	100	0	100	0	100	0	50%
H13	0	0	100	100	100	0	100	0	100	0	50%
H14	0	0	100	100	0	0	100	0	0	0	38.88%
H15	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	55.55%
H16	0	0	100	100	100	0	100	0	100	100	55.55%
H19	0	0	100	100	0	0	100	0	100	100	50%
H20	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	11.11%
H26	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	22.22%
H28	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	33.33%
H29	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	16.66%
H31	0	0	100	0	100	0	100	0		100	33.33%
H32	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	11.11%
H33	0	100	100	0	100	0	100	0	100	100	55.55%
H34	0	0	100	0	100	0	100	0	100	100	38.88%
H35	0	0	100	100	100	0	100	0	100	0	50.00%
H36	0	0	0	0	100	0	100	0	0	100	16.66%

H37	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	33.33%
H38	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	16.66%
H39	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	11.11%
H40	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100	22.22%
H43	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	11.11%
H44	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	16.66%
H45	0	100	100	100	100	0	100	0	100	0	66.66%
H46	0	0	100	100	100	0	100	0	100	100	55.55%
H47	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	33.33%
H48	0	0	0	0	100	0	100	0	100	100	22.22%
H49	0	0	0	100	100	0	100	0	100	100	38.88%
H52	0	0	100	100	0	0	100	0	0	100	44.44%
H53	0	0	100	100	100	0	100	0	100	100	55.55%
H54	0	0	0	0	100	0	100	0	100	100	22.22%
H55	0	0	0	100	100	0	100	0	100	100	38.88%
H58	0	0	0	0	0	100	100	0	100	0	16.66%
H60	0	0	0	0	100	0	100	0	100	100	22.22%
H61	0	0	0	0	0	100	100	0	100	100	22.22%
H62	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	16.66%
H63	100	0	0	0	0	0	100	0	100	100	33.33%
H65	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	16.66%
H66	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	11.11%
H67	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	11.11%
H68	100	0	100	100	0	0	100	0	100	100	66.66%
H70	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	11.11%
H71	0	100	0	0	0	0	100	0	0	100	27.77%
H72	100	0	0	0	100	0	100	0	100	0	33.33%
H73	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	5.55%
H74	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	16.66%
H75	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	11.11%
H76	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	5.55%
H77	0	0	0	0	0	100	100	0	100	0	16.66%
H78	0	0	0	100	100	0	100	0	0	0	27.77%
H80	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	16.66%
H83	0	0	100	0	0	0	100	100	0	100	33.33%
H85	0	0	100	0	0	100	100	0	0	100	33.33%

H86	0	0	100	0	100	0	100	0	0	0	27.77%
H87	0	0	100	0	100	0	100	0	0	0	27.77%
H88	0	0	100	0	100	100	100	0	0	0	33.33%
H89	0	0	100	0	0	0	100	0	0	100	27.77%
H94	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	11.11%
H95	0	0	100	100	100	0	100	0	0	0	44.44%
H96	0	0	100	100	0	0	0	0	100	0	38.88%
H97	0	0	100	100	0	0	100	0	0	100	44.44%
H98	0	100	100	100	0	0	100	0	0	100	61.11%
H99	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	22.22%
H105	0	0	0	0	100	0	100	0	0	100	16.66%
H106	100	0	100	0	100	0	100	0	0	100	50%
H107	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	11.11%
H109	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	33.33%
H110	0	0	100	0	0	0	100	0	0	100	27.77%
H111	100	0	100	0	100	0	100	0	0	0	44.44%
H112	0	0	100	0	100	100	100	0	100	100	44.44%
H113	0	0	100	0	0	100	100	0	0	0	27.77%
H114	0	100	100	100	0	0	100	0	0	100	61.11%
H115	0	100	100	100	0	0	100	0	0	100	61.11%
H116	0	0	100	100	0	0	100	0	0	100	44.44%
H117	0	0	100	100	0	0	100	0	0	0	38.88%
H118	0	0	100	0	0	0	100	0	100	100	33.33%
H119	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	11.11%
H120	0	0	100	100	0	100	100	0	0	100	50%
H121	0	0	100	0	0	100	100	0	0	100	33.33%
H122	0	100	100	100	0	0	100	0	100	0	61.11%
H123	0	100	100	100	0	0	100	0	0	100	61.11%
H124	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	50%
H125	0	0	100	0	0	0	100	0	0	100	27.77%
H126	0	0	0	0	0	0	100		0	100	11.11%
H127	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	11.11%
H128	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	11.11%
H133	0	0	0	0	100	100	100	0	100	0	22.22%
H134	0	100	100	100	0	0	100	0	0	100	61.11%
H135	0	0	100	100	0	0	0	0	0	100	33.33%

H136	0	0	100	0	0	0	100	0	0	100	27.77%
H138	0	0	100	100	0	0	100	0	100	0	44.44%
H139	0	0	100	100	100	0	100	0	100	0	50%
H140	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	33.33%
H141	0	100	0	0	100	0	100	0	100	0	33.33%
H142	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	11.11%
H144	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	11.11%
H 145	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	44.44%

Annexure 3 : Poverty Indexes of OBC Social Groups

Indicators and Weight

Household number	Child Mortality (1/6)	Nutrition (1/6)	Years of Schooling (1/6)	School Attendance (1/6)	Pacca House (Floor) (1/18)	Drinking Water (1/18)	Toilet (1/18)	Electricity (1/18)	Cooking Fuel (1/18)	Assets (1/18)	Weighted score
H 9	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	66.66%
H 21	0	0	100	100	100	0	100	0	100	100	55.55%
H 22	0	0	100	100	100	0	100	0	100	100	55.55%
H 23	0	0	100	100	100	0	100	0	100	100	55.55%
H 30	0	0	100	0	100	0	100	0	100	100	38.88%
H 64	0	0	0	0	100	0	100	0	100	100	22.22%
H 69	0	0	0	0	100	0	100	0	100	100	22.22%
H 90	0	0	100	100	0	0	100	0	0	100	44.44%
H 137	0	100	0	0	100	0	100	0	100	0	33.33%

Annexure 4: Poverty Indexes of SC Social Groups : Indicators and Weight

Household number	Child Mortality (1/6)	Nutrition (1/6)	Years of Schooling (1/6)	School Attendance (1/6)	Pacca House (Floor) (1/18)	Drinking Water (1/18)	Toilet (1/18)	Electricity (1/18)	Cooking Fuel (1/18)	Assets (1/18)	Weighted score
H6	100	0	100	100	100	0	100	0	100	0	66.66%
H7	0	0	100	100	100	0	100	0	100	0	50%
H17	0	0	100	0	100	0	100	0	100	100	33.33%
H18	0	0	100	100	0	0	100	0	100	0	44.44%
H24	0	0	100	0	100	100	100	0	100	0	38.88%
H25	0	0	100	0	0	0	100	0	100	100	33.33%
H27	0	0	100	0	100	0	100	0	100	100	38.88%
H41	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	33.33%
H42	0	0	100	100	100	0	100	0	100	0	50.00%
H50	0	0	100	100	100	0	100	0	100	0	50%
H51	0	0	100	0	0	0	100	0	100	100	33.33%
H56	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	11.11%
H57	0	0	0	0	100	0	100	0	0	100	16.66%
H59	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	5.55%
H79	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	5.55%
H81	0	0	100	100	0	100	100	0	0	100	50%
H82	0	0	100	0	0	0	100	0	0	100	27.77%
H84	0	100	100	0	0	0	100	0	100	100	50%
H91		0	100	100	0	0	100	0	100	0	44.44%
H92	0	0	100	100	100	0	100	0	100	0	50%
H93	0	0	100	100	0	0	100	0	100	0	44.44%
H100	100	0	100	0	100	0	100	0	0	0	44.44%

H101	0	0	100	0	100	0	100	0	0	100	33.33%
H102	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	50%
H103	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	50%
H104	100	0	100	0	0	0	100	100	100	100	55.55%
H108	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	11.11%
H129	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	33.33%
H130	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	22.22%
H131	0	0	100	100	0	0	100	0	0	100	44.44%
H132	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	16.66%
H133	0	0	0	0	100	100	100	0	100	0	22.22%

Dr. Shivanand Pawar
Assistant Professor,
Department of Social Work, Jain University, Bengaluru-560078
email: shivupawar898@gmail.com.
Orcid id: orcid.org/0000-0002-5667-4632

Dr. Lakshmana G
Associate Professor
Department of Social Work
Central University of Karnataka, Kalaburagi-585367
email: lakshmanagsagar@gmail.com Orcid id: orcid.org/0000-0002-1324-5387 (Corresponding author)

Dr. Mahantagouda Patil
Assistant Professor of Kannada
Devanampriya Ashoka,
Government First Grade College, Raichur Maski-585124.

Dr. Ahalatha R,
Guest Faculty,
Sri Sathya Sai University of Human Excellence Karnataka
email: ashalatha.dsce@gmail.com

❑ ❑ ❑

Assessing the Connection Between Self-Esteem and Academic Achievement

Ekta Kansal • Rajive Kumar

In today's rapidly evolving world, education stands as a cornerstone for shaping the future. Accessible and quality education for all is our shared responsibility, empowering generations to create a brighter tomorrow. Secondary education is particularly crucial, fostering personal development and laying the groundwork for success. It offers students diverse subjects to explore their interests, nurturing critical thinking and problem-solving skills essential for navigating modern complexities. Academic achievement serves as a measure of progress and potential, motivating students to excel and boosting self-esteem. The research involved 540 CBSE secondary school students selected through random sampling. Employing a survey method research design,the data were examined through the use of average values, variability measures, and Pearson's Product moment correlation.The research paper under study clearly indicates a significant and strong relationship among self worth and academic performance scores among school learners,with confidence observed at the 0.05 level. The findings revealed that a student with higher self-esteem scores exhibits higher academic achievement scores and vice versa.It seems pertinent here to mention that self worth has a crucial impact on influencing students' academic success. This relationship holds true for the overall student population as well as for male students specifically, but it is not significant for female students. This implies that gender significantly influences the connection between self - worth and academic performance in school students.

Keywords : *School Students, Self - Esteem And Academic Achievement*

Introduction

In a rapidly changing world, the importance of education cannot be overstated. It forms the foundation for a person's future and is vital for secondary school students, who use this period to develop their identity and self-awareness. Secondary education provides a diverse range of subjects, fostering intellectual curiosity, critical thinking, and problem-solving skills essential for navigating modern complexities. Academic achievement reflects students' progress and potential, helping educators and parents pinpoint strengths and areas for improvement. Recognizing achievements encourages students to pursue knowledge and strive for excellence. Success in academics can also boost self-esteem, while repeated failures can lower it, potentially affecting academic performance.When people express their sense of value, they refer to their self-esteem. During adolescence, self-esteem becomes extremely important. As Carl Rogers stated,the self-concept is divided into three parts. And one of the parts is self-esteem. When people respond positively, individuals are more likely to develop positive self-esteem. Self-esteem can be negatively affected when individuals compare themselves to others and find themselves lacking[4]. A student's academic performance is typically evaluated through testing and assessments. Academic success is important for secondary school students because it affects their readiness for college and the workforce, aids in the development of critical academic skills, determines their educational pathway, opens doors to scholarships and financial aid, promotes confidence and personal growth, influences college admissions, and lays a solid foundation for future learning. It gives pupils the resources and chances to succeed in school and beyond. Academic achievement is defined as the percentage of students at a school who meet or exceed the level of their grade. Therefore, fostering academic achievement should be a priority in secondary education to empower students and prepare them for a fulfilling future. Research on African American students revealed no distinctions in self-worth or academic identity between the experimental and control groups, even though pretest and posttest assessments were utilized (Ed Bell ,2009) [2]. The study found similar self-esteem levels in rural and urban adolescents, but urban students scored higher academically. Additionally, boys had higher self-esteem, while girls achieved higher academically (Shobhna Joshi and

Rekha Srivastava ,2009) [7].A research conducted at the Federal Polytechnic in Nigeria examined the influence of examination-related anxiety and self-worth on scholastic achievement. The findings indicated that elevated self-confidence was positively associated with improved educational outcomes, while learners with reduced exam anxiety exhibited higher grade point averages compared to those experiencing heightened anxiety(Akinleke,2012)[1]An investigation at G.C. University Faisalabad discovered a significant link between self-worth and scholastic achievement.It also revealed female students outperformed male students academically, while male students had higher self-esteem compared to their female counterparts(Mohammed Arshad ,2015)[3].

Objectives:

The research sought to evaluate the self-esteem as well as academic achievement of school learners,examining their overall status in both areas. Additionally, it investigated the relationship between research variables , with a specific focus on this relationship for both genders of school students.

Hypotheses:

The study found no substantial relationship between research variables among secondary school students overall. This lack of correlation was consistent across both genders.

Sample selected for the study

540 students studying in the Xth standard of secondary schools are the sample randomly selected for the study.

Tools

1. Self-Esteem Scale - developed by Rosenberg Self-Esteem Scale (1965)[6].
2. Academic Achievement Scores- The scores obtained by the students in the 9th class collected from school records were used as academic achievement.

Data Analysis

The gathered data was processed through appropriate

descriptive as well as inferential statistical techniques.The average, standard deviation, and coefficient of correlation were employed to link the scores of students on the research variables.

Result With Discussion

Table 1 : Classification, in terms of low, average and high Self-Esteem based on their Self - Esteem scores through NPC distribution

Number of Students	Mean (M)	Standard Deviation (SD)	Above+1 S.D score [m+s.d]	Below-1 S.D score [m-s.d]	Number (%) of students with low self-esteem (Below Mean-SD)	Number (%) of students with average self-esteem	Number (%) of students with high self-esteem (Above Mean+SD)
540	19.07	3.51	22.58	15.56	77 (14.26)	371 (68.70)	92 (17.04)

Table 1 provides information about self-esteem levels among secondary school students, based on their scores. The mean score is 19.07, with a standard deviation of 3.51. Students are classified into three groups based on their scores. Those with scores below 15.56 (mean minus one standard deviation) are considered to have low self esteem, making up 14.26% of the students (77 students). The majority 68.70% (371 students) fall into the average self-esteem range, with scores between 15.56 and 22.58 (within one standard deviation of the mean). Finally, students with scores above 22.58 (mean plus one standard deviation) are classified as having high self-esteem, accounting for 17.04% (92 students). This shows most students experience average levels of self-esteem; however, a fair number either face extremely low or high levels of self-esteem. It means data is normally distributed.

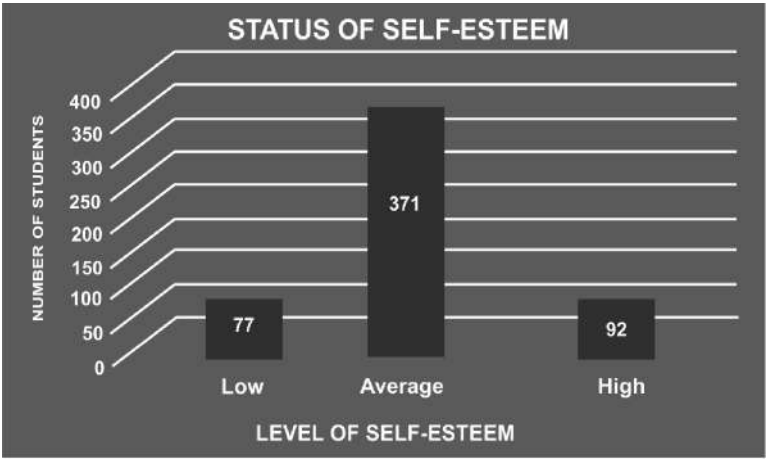

Fig 1:Graphical representation of status

Table 2 : Classification, in terms of low, average and high Academic Achievement based on their Academic Achievement scores through NPC distribution

Number of Students	Mean (M)	Standard Deviation (SD)	Above+1 S.D score [m+s.d]	Below-1 S.D score [m-s.d]	Number (%) of students with low self-esteem (Below Mean-SD)	Number (%) of students with average academic achievement	Number (%) of students with high academic achievement (Above Mean+SD)
540	72.69	12.36	85.05	60.33	101 (18.70)	369 (68.33)	70 (12.96)

Table 2 provides information about academic achievement levels among secondary school students, based on their scores. The mean score is 72.69, with a standard deviation of 12.36. Students are classified into three groups based on their scores. Those with scores below 60.33(mean minus one standard deviation) are considered to have low academic achievement, making up 18.70% of the students (101 students). The majority 68.33% (369 students) fall

into the average achievement range, with scores between 60.33 and 85.05 (within one standard deviation of the mean). Finally, students with scores above 85.05 (mean plus one standard deviation) are classified as having high academic achievement, accounting for 12.96% (70 students). This shows most students experience average levels of academic achievement; however, a fair number either face extremely low or high levels of achievement. It means data is normally distributed.

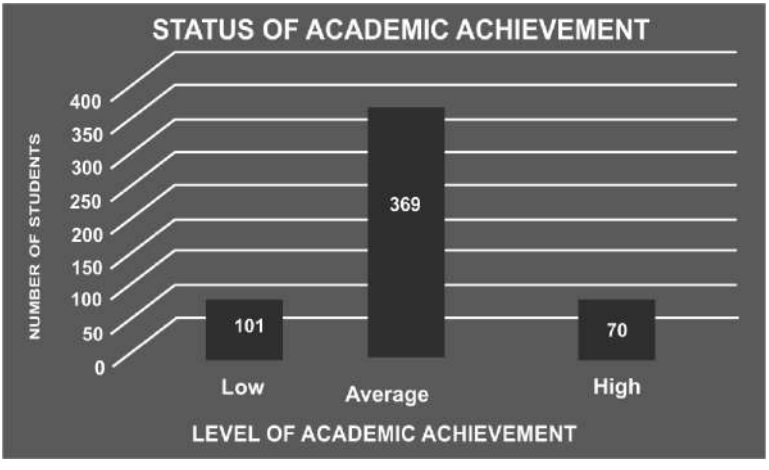

Fig 2 : Graphical representation of status

So above mentioned Table 1 and Table 2 show the NPC distribution of both variable scores of the students. Therefore data fulfils the conditions of using the correlation between research variables.

Table 3 pearson's correlation of students

Variables	EX	EY	EX2	EY2	EXY	N	r	Level of Signi-ficance
Self-esteem	19.07		6652.18		2405.77	540	0.102	P>0.05 Signi-ficant
Academic achievement		72.69		82343.79				

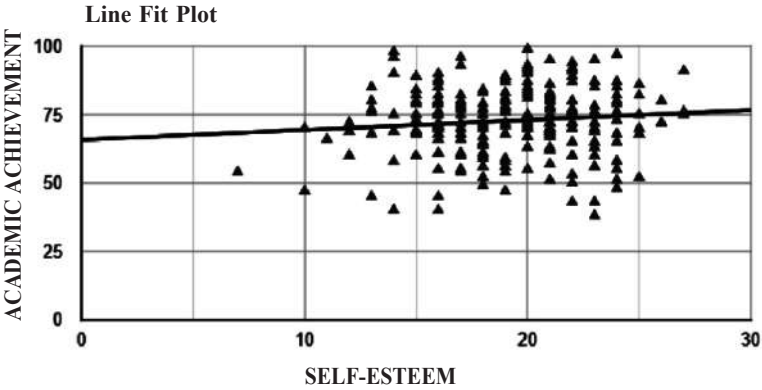

Graphical Representation of Coefficient of Correlation of Students

Table 3 clearly shows that the variable scores of students are significantly and positively correlated with one another. The table values for the significance of correlation are 0.088 and 0.115 at 0.05 level and 0.01 level of significance respectively. The correlation coefficient 0.102 obtained in this study exceeds the minimum significant correlation value at the 0.05 level of significance. Therefore, it is clarified that higher self-esteem scores of students predict higher academic achievement of students. More precisely, it can be said that a student with higher self-esteem scores exhibits higher academic achievement scores and vice versa. Hence, the formulated null hypothesis, ‘‘There will be no significant relation between academic achievement and self-esteem of students’’ is rejected at 0.05 level of significance.

Table 4 pearson’s correlation of female students

Variables	EX	EY	EX2	EY2	EXY	N	r	Level of Signi-ficance
Self-esteem	19.82		3481		59.259	278	0.0051	Not Signi-fican
Academic achievement		74.02		38790.82				

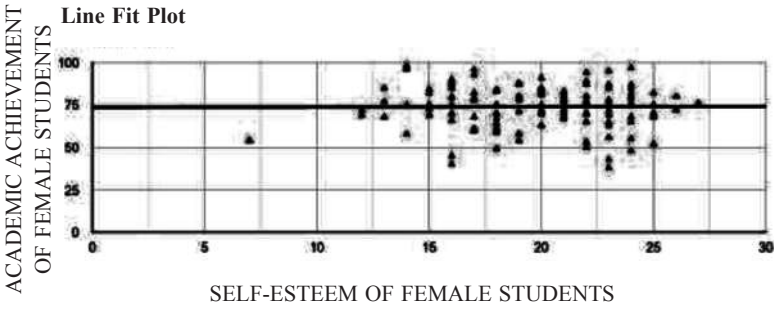

Graphical Representation of Coefficient of Correlation of Female Students

Table 4 clearly shows that the variable scores of female students are not correlated with one another. The table values for the significance of correlation are 0.113 and 0.148 at 0.05 level and 0.01 level of significance respectively. The correlation coefficient 0.005 obtained in this study lesser than the minimum significant correlation value at the 0.05 level of significance.Therefore, it is clarified that academic achievement is not correlated with self-esteem among female students.More precisely, it can be said that a female student with higher self-esteem scores does not affect academic achievement scores. Thus, the proposed null Suppose, ‘‘There is no significant relationship between academic achievement and self-esteem of female secondary school students’’ is accepted.

Table 5 pearson’s correlation of male students

Variables	EX	EY	EX2	EY2	EXY	N	r	Level of Signi-ficance
Self-esteem	18.27		2850.66		1777.82	262	0.161	P>0.01 Signi-ficant
Academic achievement		71.29		42543.95				

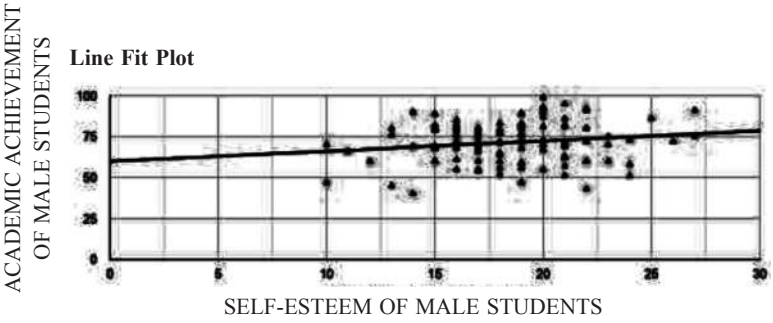

Graphical Representation of Coefficient of Correlationof Male Students

Table 5 clearly shows that the variable scores of male students are positively correlated with one another. The table values for the significance of correlation are 0.113 and 0.148 at 0.05 level and 0.01 level of significance respectively.The correlation coefficient 0.161 obtained in this study exceeds the minimum significant correlation value at the 0.01 level of significance.Therefore, it is clarified that academic achievement is positively correlated with self-esteem among male students.More precisely, it can be said that a student with higher self-esteem scores exhibits higher academic achievement scores and vice versa.Thus, the proposed null Suppose,"There is no significant relationship between academic achievement and self-esteem of male secondary school students" is rejected.

Conclusion

Self-esteem is the way we perceive and value ourselves. It can be high or low, and having healthy self-esteem is crucial for confidence, resilience, positive relationships, mental and emotional well-being and achievement. The findings revealed that a student with higher self-esteem scores exhibits higher academic achievement scores and vice versa. This relationship holds true for the overall student population as well as for male students specifically, but it is not significant for female students. This suggests that gender plays a crucial role in shaping the connection between both variables of learners.

Reference

1. Akinleke, 0.W. [2012]. An Investigation of the Relationship between Test Anxiety, self-esteem and Academic Performance among Polytechnic Students in Nigeria. International Journal of Computer Applications 51(1): 47-50
2. Ed Bell,2009, Impact of Self-Esteem and Identification with Academics on the Academic Achievement of African American Students, A Dissertation, Doctor of Education, Liberty University.
3. Mohammed Arshad, Journal of Education and Practice ISSN 2222-1775 (Paper) ISSN 2222-288X (Online) Vol. 6, No. 1, 2015
4. Rogers, Carl R. "A Theory of Therapy, Personality, and Interpersonal Relationships as Developed in The Client-Centred Framework." Psychology: A Story of a Science, Vol. 3, edited by Sigmund Koch, McGraw-Hill, 1959, pp. 184-256.
5. Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image. Princeton, NJ: Princeton University Press. online pdf here: https://www.docdroid.net/Vt9xpBg/society-and-the-adolescent-self-image-morris-rosenberg-1965.pdf
6. "Rosenberg self-esteem scale" (PDF). callhelpline.org.uk, by The Betsi Cadwaladr University Health Board. Retrieved January 31, 2017.
7. Shobhna Joshi & Rekha Srivastava,2009, Self-esteem and Academic Achievement of Adolescents, Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, vol. 35, pp. 33-39.

Ekta Kansal
Research Scholar,
Department of Education,
N.A.S. College, Meerut,Uttar Pradesh, India
email:ektakansal1234@gmail.com
Mob.No. 7983071634

Rajive Kumar
Professor
Department of Education
N.A.S. College, Meerut,Uttar Pradesh, India
email id-drrajive@gmail.com
Mob. No. 9897126782

❑ ❑ ❑

A Study on Teacher Effectiveness of Government Secondary School Teachersin Uttarakhand State

Devraj Singh Rana • Dr. Malvika Kandpal

The purpose of this research studyis to assess the teachereffectiveness of government secondary school teachers by employing a descriptive survey methodology. Teacher effectiveness refers to the influence of high-quality teaching on student learning, measured in terms of academic achievement. It involves the dynamic and interactive process of creating, adjusting, and dealing with learning environments that support all students. The data was gathered using standardized tool "Teacher Effectiveness Scale (TES)" developed by P. Kumar and D.N. Mutha. By the use of a stratified purposive sampling technique, 482 government secondary school teachers were selected as sample for the study. The gathered data was examined using statistical techniques such as the mean, standard deviation, and 't' test. Research study indicates that variables like gender, location (rural or urban) and mode of recruitment (direct or promoted) do not significantly affect the effectiveness of teachers in government secondary schools. The results show that these demographic traits had no effect on teachereffectiveness with in the selected sample.

Keywords : *Teacher Effectiveness, Secondary School, Promoted Teachers, Directly Recruited Teachers.*

Introduction

The progress and development of a nation mainly depends on its teachersas they havegreat and extensive contribution in nation building. The quality of teachers largely depends on the quality of teaching. Learning lies at the core of being a teacher, unless the teacher is willing to learn. This is best expressed by Rabindra Nath

Tagore in these words, "A teacher can never truly teach unless he is still learning himself. A Lamp can never light another lamp unless it continues to burn its own flame". A school may have excellent physical resources, equipment, building, library and other facilities as well as a curriculum suitable to the needs of the community, but if the teachers are not effective and efficient and they are inappropriate, disengaged and indifferent to their responsibilities, the entire program is likely to be ineffective and ruined. Education Commission (1964-66) noted that "of all the different factors which influence the quality of education and its contribution to the national development, the quality, the effectiveness and character of teachers are undoubtedly the most significant". Teachers have to adapt themselves to the noble profession and mission cherished by the country. To do this, teachers have to be efficient and effective. Medley (1982) observed, "Teacher Effectiveness must be defined, and can only the assessed, in terms of behaviors and learning of students, not behavior of teachers". It is the duty of the teacher to mold the behavior of the students in the desired direction. To perform his role effectively, the teacher should be psychologically, philosophically, methodologically, technologically and above all physically well equipped. An effective teacher may be understood as one who helps in the development of basic skills, understanding, proper habits, and desirable attitude, value judgment and adequate personal adjustment of the student (Barr, 1952).

Actually, it is absolutely true that there is a significant relationship between teacher's factors and student's achievement (Olatoye, 2006; Adekola, 2006 &Kiadese,2011). There are so many factors which influence student's academic achievement. According to Postlethwaite (2007) student's academic achievement is dependent on Teacher-related Variables, Environment or Family-related Variables and School-related Variables. Among these variables, one of the most important Teacher-related Variables or factors that contribute immensely to enhance student's academic achievement is "Teaching Effectiveness".

Rationale Of The Study

Teacher effectiveness is an important factor in delivering high-quality education and enhancing students' academic performance. In the context of Uttarakhand's government secondary schools, understanding

the factors that influence teacher effectiveness is particularly important, given the unique geographic, socioeconomic, and institutional challenges the region faces. These factors may uniquely shape the teaching environment and affect the quality of education.

Although much research has been conducted on teacher effectiveness globally, there is an obvious lack of studies focused on the Uttarakhand region. The challenges faced by schools here, including resource constraints and varied recruitment practices, may influence the effectiveness of teachers in ways that are not fully understood. The aim of the present study is to bridge that gap by examining whether factors such as gender, location (urban or rural), and recruitment mode (direct or promoted) influence the effectiveness of teachers.

The present research study will offer major insights that can guide educational policy decisions in Uttarakhand state by analyzing these factors. The results of the present research study will be beneficial in determining the approach for the recruitment process, professional development, and ongoing support systems for teachers. Additionally, the research study will impart important region-specific data to the larger discourse on teacher effectiveness, addressing a gap in the ongoing literature on this subject.

Review of Related Literature

Vijaya Lakshmi (2005) conducted a research study on "Teacher Effectiveness and Job Satisfaction of Women Teachers" to uncover the effect of locality, management and teaching subject on teacher effectiveness and job satisfaction. The findings of the study revealed that the locality of school and subject of teaching have no significant effect on teacher effectiveness.

Sharadha and Paremeswaram (2008) in their study on "Teacher Characteristics and Learning in the Classroom", tries to examine the role of some behavioral variation among teachers and their possible implications for effective classroom teaching and learning. The findings of the research study indicate that the gender and locality have significant impact on the behavior variation in the level of their Teaching Effectiveness.

Malik and Sharma (2013) conducted a research study on "Teaching Effectiveness of Secondary School Teachers in Relation

to their Professional commitment". This study revealed that gender of teachers does not bear any relationship with their teaching effectiveness. It also revealed that locality of schools does not influence the teaching effectiveness of teachers.

Tyagi (2013) conducted research on "Teaching Effectiveness of Secondary School Teachers in Relation to their Demographic Characteristics," examining secondary school teacher's perceptions of teaching effectiveness concerning various demographic factors. The research study found that factors such as qualification, stream, teaching experience, and locality of the school significantly influenced the teaching effectiveness of secondary school teachers

Pachaiyappan and Ushalaya Raj (2014) conducted a study on "Evaluating the Teacher Effectiveness of Secondary and Higher Secondary School Teachers". The findings of the study reveals that the male and female school teachers did not differ significantly in their teacher effectiveness. The research results also signify that there was a significant difference in teacher effectiveness among the school teachers with respect to location, stream, teaching level (secondary versus higher secondary level), teaching experience and school management type.

Chowdhury (2014) conducted a study on "Effectiveness of Secondary School Teachers in relation to their Gender, Age, Experience and Qualification". The study revealed that majority of the teachers both male and female had average level of effectiveness in their teaching-learning process. The study demonstrates that there was no significant difference in the effectiveness of secondary school teachers in terms of their gender, age, experience and qualification.

Kothawade (2014) conducted a study on "Correlative Study of Teaching Effectiveness & Job Satisfaction of Higher Secondary School Teachers". The results of the study reveal that Teaching Effectiveness of higher secondary school teachers of Dhulia district is 44.04 %. The significant difference found in teaching effectiveness in male & female teachers of higher secondary schools of Dhulia district. Furthermore, no significant difference found in teaching effectiveness of Arts & Science faculty's teachers of higher secondary schools of Dhulia district.

Dash& Barman (2016) in their investigation titled "Teaching Effectiveness of Secondary School Teachers in the District of

Purba Medinipur, West Bengal" uncovered that the overall level of teaching effectiveness of secondary school teachers in the district of Purba Medinipur is good. The study also found that while there were no significant differences among secondary school teachers in terms of teaching effectiveness based on gender, qualification, stream, and training status, there was a significant difference in teaching effectiveness based on the location of the school.

Biswas (2017) conducted a study titled "A study of teacher effectiveness of secondary school teachers in relation to gender, location, and academic stream." The research findings indicate that there is no significant difference in teacher effectiveness between male and female teachers. Additionally, the study shows significant difference in teacher effectiveness based on factors such as the level of classes taught (secondary and higher secondary), locale, and academic streams (arts and science) among secondary school teachers.

Sadhukhan (2018) conducted a study titled "A Study of Teaching Effectiveness of Secondary School Teachers," findings indicated that there was no significant difference in teaching effectiveness based on gender or subject stream. Nonetheless, the study highlighted that teaching experience and the geographical location of the school did influence teaching effectiveness.

Haldar & Chel (2020) conducted a research study on “A Comparative Study of Teaching Effectiveness of In-Service Teacher with Pre-Service Teacher at Secondary Level”. The study reveals that no significant difference was found of teaching effectiveness between In-service and pre-service secondary school teachers.

The existing literature lacks research study pertaining to the educational landscape of Uttarakhand state. Hence, the present study aims to fill this gap by examining the effectiveness of government secondary school teachers within Uttarakhand. This investigation seeks to shed light on the teaching practices and their effect on student learning outcomes in this particular regional context.

Objectives Of The Study

1. To study the teacher effectiveness of male and female government secondary school teachers.
2. To study the teacher effectiveness of rural and urban government secondary school teachers.

3. To study the teacher effectiveness of promoted and directly recruited government secondary school teachers.

Hypotheses Of The Study

1. There is no significant difference in the teacher effectiveness between male and female government secondary school teachers.
2. There is no significant difference in the teacher effectiveness between rural and urban governmentsecondary school teachers.
3. There is no significant difference in the teacher effectiveness betweenpromoted and directly recruited government secondary school teachers.

Methodology:

Method and Procedure of the study:

The current study employs the descriptive survey method within the scope of its research design. It is undeniably true that the descriptive method stands out as the most favored and extensively utilized research approach in the field of education.

Population and Sample of the study:

In the present study, teachers of government secondary schools of Uttarakhand have been taken as the population of this study. A sample of 482 government secondary school teachers from Garhwal educational division of Uttarakhand state was selected through stratified purposive sampling technique. Theallocationof the sample is given below-

Types of teachers		Gender		Locality	
Promoted	Directly Recruited	Male	Female	Urban	Rural
121	361	239	243	238	244

Tool for data collection:

Teacher Effectiveness Scale (TES) developed by P.Kumar and D.N. Mutha (1985) was used.

Statistical Techniques Used:

For analyzing the data Mean, Standard Deviation (SD) and t-test havebeen computed.

Data Analysis, Interpretation And Findings

Hypothesis 1: "There is no significant difference in the teacher effectiveness of male and female government secondary school teachers."

Table 1

Mean scores of teacher effectiveness differential between male and female government secondary school teachers.

Teacher Effectiveness	N	Mean	S.D.	t-value	p-value	Level of significance
Male	239	315.9707	24.73496	1.180539	0.238371	.05
Female	243	312.8230	33.12582			

The Table 1 indicates that the mean teacher effectiveness score for male teachers (315.9707) is a little higher compared to female teachers (312.8230). However, the t-value with the p-value (0.238371) is 1.180539. In hypothesis testing, a p-value less than 0.05 is measured statistically significant. In this case, the p-value is greater than 0.05, indicating that the observed difference between male and female teacher effectiveness scores is not statistically significant. Thus, the null hypothesis i.e. there is no significant difference in teacher effectiveness of male and female government secondary school teachers is accepted. The result shows that teacher effectiveness of male and female government secondary school teachers is equal.

Hypothesis 2 : "There is no significant difference in teacher effectiveness of urban and ruralgovernment secondary school teachers."

Table 2

Mean scores of teacher effectiveness differential between Urban and Rural government secondary school teachers

Teacher Effectiveness	N	Mean	S.D.	t-value	p-value	Level of significance
Urban	238	314.0210	28.04659	-0.268418	0.788493	.05
Rural	244	314.7377	30.48775			

The Table 2 demonstrates that the mean teacher effectiveness scores for urban and rural teachers are 314.0210 and 314.7377, respectively. The t-value is -0.268418, and the p-value is 0.788493. The p-value is greater than 0.05, indicating that the observed difference in mean scores between urban and rural teacher effectiveness is not statistically significant. Thus, the null hypothesis i.e. there is no significant difference between teacher effectiveness of urban and rural government secondary school teachers is accepted. The teacher effectiveness of urban government secondary and rural government secondary teachers is not different.

Hypothesis 3 : ‘‘There is no significant difference in teacher effectiveness of promoted and directly recruited government secondary school teachers.’’

Table 3

Mean scores of teacher effectiveness differential between promoted and directly recruited government secondary school teachers.

Teacher Effectiveness	N	Mean	S.D.	t-value	p-value	Level of significance
Promoted	121	314.4463	27.07704	0.027088	0.978401	.05
Directly Recruited	361	314.3629	30.01747			

The Table 3 demonstrates that the mean teacher effectiveness scores for promoted and directly recruited teachers are 314.4463 and 314.3629, respectively. The t-value is 0.027088, and the p-value is 0.978401. The p-value is greater than 0.05, indicating that the observed difference in mean scores between promoted and directly recruited teacher effectiveness is not statistically significant. Thus, the null hypothesis i.e. there is no significant difference in teacher effectiveness of promoted and directly recruited government secondary school teachers is accepted. The effectiveness of the promoted government secondary school teachers and the directly recruited government secondary school teachers is not different.

Findings of The Study

1. The result of research study shows that there is no statistically significant difference in teacher effectiveness between male and female teachers in government secondary schools. This demonstrates that gender does not influence the level of the teacher effectiveness in these schools.
2. Likewise, the study shows that there is no significant difference in the effectiveness of teachers working in rural and urban areasin government secondary schools. This suggests that location of the school does not influence effectivenessof teachers.
3. The research study also reveals no significant difference in teacher effectiveness between those who are promoted and those who are directly recruited teachers in government secondary schools. This finding indicates that their effectiveness is not impacted by the type of recruitment.

Conclusions

1. Findings of the research study explore that within government secondary schools the teacher effectiveness of male and female teachers does not differ significantly. While the difference in mean scores observed is not substantial enough to be considered statistically significant, the p-value suggests that any observed differences may be the result of random variability rather than inherent variations in the teacher effectiveness.
2. The study also shows in government secondary schools the

teachereffectiveness does not significantly differ between urban and rural region. The minimal difference in mean scores is not considered statistically significant, the p-value advise that any variations may be the result of random chance rather than a true difference in the effectiveness. Thus, there is noevidence to support the thought that teacher effectiveness varies significantly based on school location.

3. Additionally, the study's results indicate no significant difference in mean scores between teachers who are promoted and directly recruited in government secondary schools. The p-value suggests that any observed difference may be the outcome of random variability rather than a true difference in the teacher effectiveness. Therefore, there is no evidence to support the idea that the mode of recruitment has an impact on the teacher effectiveness.

Educational Implications

From teaching practice in secondary level of education, it is clear that the research implications emphasize the importance of effective teaching practices. Teachers play a major role in the academic performance of their students as well as in the future standing of their students and even the future of many educational institutions. This signifies the ability to use strategic pedagogies of teaching and learning activities needed to bring learners from passive and dormant enterprise with their own insights in depth. Concentrating on such behaviors can enhance student learning and retention, uplift academic achievement, and have a broad impact on educational objective.

References

Adekola, B.O. (2006). Influence of Teachers‟ Qualification, Age, and Gender on Effective Teaching of English Language. Journal of Educational Focus, 6, 97-99.

Barr, A.S. (1952). The Measurement of Teacher Characteristics and Prediction of Teacher Efficiency, Review of Educational Research. 22,169-174.

Biswas, M. (2017). A study of teacher effectiveness of secondary school teachers in relation to gender, location and academic stream, International Education and Research Journal,3(9), 47-48.

Chowdhury, S. R. (2014). Effectiveness of Secondary School Teachers in relation to their Gender, Age, Experience and Qualification. The Clarion-International Multidisciplinary Journal, Volume: 3, Issue: 1, 141-148.

Dash, U. & Barman, P. (2016). Teaching Effectiveness of Secondary School Teachers in the District of Purba Medinipur, West Bengal. IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Volume 21, Issue 7, 50-63

Haldar P. P. & Chel M. M. (2020). A Comparative Study of Teaching Effectiveness of In-Service Teacher with Pre-Service Teacher at Secondary Level. International Journal of Research, Vol 6, No.3, 106-112

Kiadese, A. L. (2011). An Assessment of the Teaching Effectiveness of Prevocational Subjects Teachers in Ogun State, Nigeria. International Journal of Vocational and Technical Education, Vol. 3(1), 5-8.

Kothawade, P. L. (2014). Correlative Study of Teaching Effectiveness & Job Satisfaction of Higher Secondary School Teachers. Indian Journal of Applied Research, Vol. 4(7), 116-118.

Malik, U., & Sharma, D. K. (2013). Teaching Effectiveness of Secondary School Teachers in Relation to their Professional commitment. International Educational E-Journal, (Quarterly), Volume-II, Issue-IV, 148-154.

Medley, D.M. (1982). Teacher Effectiveness in H.E. Mitzel (Ed.) Encyclopedia of Educational Research, 5/e. New York: The Free Press.

Olatoye R.A. (2006). Science Teacher Effectiveness as a Predict Students Performance in the Senior Secondary School Certificate Examination. Journal of Educational Studies, 6, 104-110.

Pachaiyappan, P., &Ushalaya Raj, D. (2014). Evaluating the Teacher Effectiveness of Secondary and Higher Secondary School Teachers. IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSR-JRME), Volume 4, Issue 1, Ver. V, 52-56.

Postlethwaite, T. N. (2007). Evaluating Teacher Competence through the Use of Performance Assessment Task: An Overview. Journal of Personnel Evaluation in Education, 5(1), 121-132.

Report of the Kothari Education Commission (1964-66). Ministry of Education, Government of India. New Delhi.

Sadhukhan, M. (2018). A study of teaching effectiveness of secondary school teachers, International Journal of Creative Research Thoughts, 9(1), 18-193.

Sharadha, D.G., and Parameswaram, E.G. (2008). Teacher Characteristics and Learning in the Classroom, Edutracks, Vol.11, No.3, p.18.

Singh, A.K. (2009). Tests, Measurements and Research Methods in Behavioural Sciences. Bharati Bhawan, New Delhi.

Tyagi, S. (2013). Teaching Effectiveness of Secondary School Teachers in Relation to their Demographic Characteristics. International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT), Volume 3, Issue 1, 288-295.

Vijaya Lakshmi, A. (2005). Teacher Effectiveness and Job Satisfaction of Women Teachers. Edutracks, Vol.4, No.7, 7-9.

Devraj Singh Rana
Research Scholar, Department of Education,SGRR University, Dehradun, Uttarakhand/ Lecturer, Department of Curriculum Studies and Development, SCERT Uttarakhand
Mob. No. – 9412145887, Email – dsrana1001@gmail.com

Dr. Malvika Kandpal
Professor, Department of Education, SGRR University, Dehradun,Uttarakhand
Mob. No.– 9897988674, Email –mskandpal1234@gmail.com

❑ ❑ ❑

Cyber Terrorism : Tackling Legal Challenges for Effective Enforcement

Dr. Subhradipta Sarkar • Md. Minhajuddin

It is undeniable that the cyber security threat to India has grown tremendously. In the post-Covid-19 world, our online activities and threat perception have increased significantly. In these circumstances, cyber terrorism may well serve as a method of destabilizing India. It can originate from any location in the world, as it is a global crime. Yet India is not a party to the Budapest Convention. Additionally, our current anti-terrorism, criminal, and IT laws have been considerably challenged by the anonymity of the perpetrators, attribution issues, jurisdictional complexities, and admissibility of evidence. As a result, convictions in these types of cases are rare. Despite the recent criminal law reform and an IT legislation proposal, skepticism continues to prevail. This article endeavours to assess the legal process to identify the challenges during the investigation and prosecution of the case and propose potential solutions.

Keywords *: Cyber Terrorism, Information Technology, Hacking, Privacy, Budapest Convention, Electronic Evidence, Judiciary, Intermediary*

I. Introduction

India ranks second internationally behind China with 59.5 percent of the population using the internet – approximately 83 crore people. India's worldwide cybercrime victim rating is alarming. Based on data gathered between 2017 and 2021, the Federal Bureau of Investigation (FBI), USA, ranked India fourth in cybercrime. Covid-19 has only exacerbated the situation. As our online activity has increased immensely, so have cybercrimes. Digital attacks

on Indian government entities quadrupled in 2022, with the most intrusions on Indian government websites.

The 2018 Aadhaar data leak affected 1.1 billion people. Hackers posted Aadhaar Card numbers, bank accounts, IFSC codes, and personal information on forums for everyone to see. The whole cyber security procedure collapsed as vendors illegally shared information with anybody by charging charges. On November 23, 2022, All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) New Delhi's entire server was blocked. Millions of medical records, including sensitive information about important personalities, were stolen. According to authorities, the assault likely began from China with hackers demanding ₹ 200 crore in cryptocurrencies. Indian cybersecurity agenciestermed the incident as 'cyber terrorism'.

Terrorism frightens individuals about their state's inadequacy to protect them from harm and wrecks their psychological and social life. Conventional terrorism sought to disturb a nation's peace and tolerance. With changing generational tendencies, terrorism has evolved with current times. Cyber terrorism has added several features to conventional terrorism that distinguish it. Global technology has fueled cyber terrorism. This is computer- and internet-aided terrorism. Modern computer-savvy terrorists can cause significant economic damage without breaching establishments' physical security.

Cyber-terrorist attacks have threatened the country's law and law enforcement despite their rapid expansion and ferocity. We currently have only one legal provision for cyber terrorism under the Information Technology Act, 2000 ('IT Act'), but we have expanded the mandate of the National Investigation Agency to investigate such cases and established separate special courts for prosecution. The conviction rate remains pitiful. Even when cybercrime involves many states within India, jurisdiction is problematic. Limited regulation and jurisdictional blame games sometimes have serious effects for the nation. Thus, the authors analyze the challenges and address its legal issues. Finally, they propose law and policy measures to combat cyber terrorism.

II. Understanding Cyber Terrorism

Recently, computer scientist Barry C. Collin coined the term 'cyber terrorism'. Cyber terrorism aims to destroy lives and property like conventional terrorism. This terrorism uses computers and modern technologies to terrorize in people. National Infrastructure

Protection Centre defines cyberterrorism as the use of computers and telecommunications to cause violence, destruction, and/or disruption of services to instill fear and conformity to a political, social, or ideological agent. It has certain universal traits: First, it is done to send a destructive or disruptive message to the government(s), such as by stopping services, sending threatening emails, defacing government websites, hacking governmental systems, or disrupting civil amenities by destroying digital information systems. Second, religious, social, or political ideas may drive the conduct. It is a technologically transmitted crime that destroys or affects politically, morally, or ideologically undesirable information and creates fear to prevent its future perpetuation.

Cyber terrorism is sometimes mistaken for hacking, although it takes up a far larger role. Cyberterrorists might compromise data storage algorithms. Their superior technology makes them aware of the malevolent concept of hacking without exposing it. Cyber terrorism may take many forms, although some are simple to identify:

(a) Privacy violation: In Justice K.S. Puttaswamy v. Union of India, the Supreme Court of India has recognized the right to privacy as a fundamental right. It is protected by civil and criminal penalties. Privacy violations include unauthorized access to personal or organizational data or the disclosure of personal data by an agent. Cyberterrorism violates privacy. Cybercrime and cyber terrorism threaten personal data and activity. It may include phishing, account hacking, malware spreading, etc.

(b) Data misappropriation: Cyber terrorism tries to steal and misuse secret information from people, governments, and other institutions. Such information may be essential to a nation's security and defence. Source data may be changed to get access to an item while denying the owner. This disables security mechanisms and seizes data.

(c) E-Governance Base Destroyed: In today's world, e-governance is the primary means of state-citizen contact. The government holds residents' personal and public activity data. Most of this information is in hard copy, but the digital version is vulnerable to cyberattacks. A successful attack might destroy this e-governance basis.

(d) Distributed Denial of Service Attack (DDoS): Multiple infected

computers or servers attack another, causing the afflicted computer/server to 'deny' service to the user. An attack like this disrupts communication and costs money. A national DDoS may slow down systems and impair government management while threatening national security and integrity.

III. Law and Policy Framework dealing with Cyber Terrorism

(a) National Framework

India has several anti-terrorism legal provisions. Previously, the Indian Penal Code, 1860 (IPC) did not encompass terrorism. Section 113 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, (BNS) makes terrorism a crime. The BNS broadly defines activities that harm India's security, sovereignty, unity, public order and economic stability. These include riots, mob violence, and armed revolt. Explosives, dynamite, guns, combustible materials, poisonous gasses, and other weapons may be used in the process to injure, kill, or destroy property. The Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (UAPA) continues in effect even though the BNS classifies terrorism as a distinct crime. This might cause an anomaly if the BNS and UAPA cover the same act.

The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, (BNSS) and the BharatiyaSakshyaAdiniyam, 2023, (BSA) which replace the Code of Criminal Procedure, 1973 and the Indian Evidence Act, 1872, respectively, do not offer a distinct criminal procedure for these offences. The anti-terror laws differ from general criminal procedures in various ways. They abolish bail requirements and do away with non-admissibility of confession by an accused person before police. Under the National Investigation Agency Act, 2008, (NIA) Special Courts try UAPA (including cyber terrorism) and SAARC Convention (Suppression of Terrorism) Act, 1993cases. Terrorism cases would be tried in sessions courts under the BNSS. This would result in varying investigation and trial methods for comparable crimes.

The IT Act governs Indian cyberlaw. Section 66F of the Act may be the sole cyber terrorism law. Section 66F states that whoever threatens the unity, integrity, security, or sovereignty of the country or strikes a sense of terror in the people using electronic media and causes death or instils a fear of its causation and/or accesses restricted information, which is against India's interest that includes security, friendly relations with foreign states, public order, decency, or morality. Cyber-terrorism

is broadly covered in the section. Defamation and contempt of court seem ambiguous. It doesn't relate them to criminality. It overlooks most other cyberterrorism aspects discussed above. Furthermore, decency and morality are vague and hard to relate.

In compliance with the Section 70B IT Act, specialized agencies like Computer Emergency Response Team India (CERT-In) under Ministry of Communication and Information Technology (MeitY)to notify of cyber security threats and provide emergency response procedures.

However, the digital revolution and new technology have rendered India's IT law obsolete. So, the GoI is contemplating to replace the IT Act with a future-ready Digital India Act (DIA). The DIA's framework will prioritize online safety, trust, accountability, an open internet, and artificial intelligence and blockchain regulation. It will also assess the 'safe harbour' concept, which protects Facebook, Telegram, etc. from liability regarding user-generated content.

The National Cyber Security Policy2013 was India's first network security policy. The cyber security policy aimed to defend cyberspace from outside threats. Protecting Indian cyberspace from cyber terrorists was another key aspect of this cyber security policy. The National Cyber Coordination Centre was established under this policy. IB, R&AW, and CBI and other intelligence agencies coordinate with this metadata-scanning centre.

(b) Budapest Convention on Cyber Crime

Being a global crime, jurisdictional issues regarding cyber terrorism is complicated, and therefore, maintaining international relations is going to be the order of the day. Sir Malcolm Evans aptly noted that international law jurisdictional principles "are truly principles, and not rules". There are no set guidelines for its use, unlike for the seas and air. Development of international law needs gradual advances, and the Budapest Convention is crucial to fighting cyber terrorism.The Council of Europe created it in 2001, and 68 states have adopted it until 2023. The treaty aims to improve research, international cooperation, and national legislation of any willing State. India has not joined the Convention yet.

IV. Judicial Response to Cyber Terrorism

Cyber terrorism is a major danger, yet prosecutions for 66F

of the IT Act offences are rare. Recently, Anees Ansari and Nishant Agrawal, computer engineers, were convicted of cyber terrorism and sentenced to life in prison in October 2022 and June 2024. Both cases are under appeal.

The sessions court in Mumbai found Ansari guilty under section 66F of the IT Act for communicating with a foreigner and sending offensive ISIS messages and ideologies to threaten India's unity and sovereignty or terrorize people by unauthorizedly using his company's computer. He shared the data with the foreigner to conspire to bomb an American school to kill foreign children and incite panic.

BrahMos Aerospace senior systems engineer Agrawal worked on missiles. The Anti-Terrorism Squad, UP, and Military Intelligence apprehended him near Nagpur in 2018 for leaking confidential project information to Pakistan. Agrawal's laptop included confidential and restricted material, citing the charge sheet. Software was also detected that sent classified laptop data to other nations and anti-social components. Besides section 66F of the IT Act, the Nagpur Additional Sessions Court held him guilty under the Official Secrets Act, 1923.

There are a couple of other cases before the Kerala High Court. In Hakkamv. State of Kerala, the Sub Inspector of Ernakulam Town North Police Station got a text message from the accused threatening to bomb Kerala in 28 hours. IT Act Section 66F and IPC Section 506 were used to file the complaint. The petitioner's letter is cyber terrorism that incites public fear. The Court ordered the petitioner to provide ₹ 1 lakh with two solvent sureties, report to the Investigating Office periodically until the case is finalized.

In Niyas Kuttassery v. State of Kerala, the accused had allegedly conducted illegal fraudulent activities to acquire unlawful gain by installing parallel illegal telephone exchanges at different locations and converted international phone calls and other phone calls to local calls, with the help of illegal call routing gateway devices. Thus, they compromised the telecommunication network and breached the internal security and sovereignty of the nation, threatened the privacy of the citizens and caused huge financial loss to the Indian government. The accused were subject to IT Act 66F(1)(B). Considering the severity of the offence, the Court denied them bail.

V. Challenges in cases of Cyberterrorism

The legal war against cyberterrorism has been difficult, therefore cyberterrorism convictions are rare. Offenders remain anonymous, and even if their identity is revealed throughtechnology, attribution issues remain. Investigating and prosecuting such offenders also presents jurisdictional issues, admissibility of evidence, and ambiguous law and policy. Some of the major challenges are explained herein below:

(a) The first stage in investigating a cyberterrorist case is identifying the source of the attack, such as the perpetrator's Internet Protocol Address (IP address) or location. Virtual Private Network (VPN), Tor browser, and proxy servers can hide this IP address, which is personal information under the IT (Reasonable Security Practices And Procedures And Sensitive Personal Data Or Information) Rules, 2011 and Digital Personal Data Protection Act, 2023 ('DPDP Act'). Further, Section 75 IT Act, which applies to offences committed outside India, along with Mutual Legal Assistance Treaties (MLATs), and 'security cooperation' Memorandum of Understanding (MoUs) with that country, are attracted. These collaborations only operate when both countries adopt the same case-by-case privacy regulations.

(b) If the IP address and Internet Service Provider (ISP) name are identified after anonymity and attribution, the ISP may still deny client information due to privacy rights. In a US terror case, 'Apple' refused FBI assistance. 'WhatsApp' has disputed the 'traceability clause' of IT (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 and does not divulge communication originators. The accused cannot be forced to divulge seized device passwords, which may violate his right to self-incrimination under Article 20(3) of the Indian Constitution.

(c) Even if the assault is domestic, investigations are complex. Most states like Telangana, Jharkhand, and Kerala have cyber investigation manuals that outline how to seize, gather, pack, transport, and maintain electronic evidence as 'law and order' is a state issue. Section 14 of IT Act mandates hashing/ digital signature to provide 'secure electronic evidence' for

BSA Section 86 presumption of authenticity. The legislation regarding digital device seizure and evidence collection is ambiguous. Investigating officer discretion rules.

(d) Indian guidelines for managing digital evidence follow Scientific Working Group on Digital Evidence (SWGDE) and National Institute of Standards and Technology (NIST) standards and best practices. Are our police educated to grasp all technological problems, do we have enough cyber professionals to investigate, and do we have the equipment and laboratories under Section 79A of the IT Act to review and preserve records? Without real backing, our norms are just theory.

(e) Electronic evidence admissibility was questioned at trial, requiring a contemporaneous certificate under Section 63 BSA. The original laptop, CD, and other devices of a terror suspect confiscated will be used as primary evidence without a certificate. Can police/courts order the accused to provide the Section 63 certificate? Who submits and validates the certificate using WhatsApp, Facebook, and other social media platforms and website material is also unclear. No standard legislation governs electronic evidence.

VI. Conclusion: The Way Forward

The Indian government recognizes the magnitude of cyberthreats. It now allocates cybersecurity funding separately. The 2023 budget allocates around ₹ 600 crores on cybersecurity.

A chapter in the IT Act or DIS-like statute is needed to address cyber terrorism. Cyber terrorism is a serious crime that requires special treatment. NIA cannot combat all cyber terrorism threats. The centre and each state may establish special investigation units or cyber police like NDRF (National Disaster Response Force) to exercise its authority over 'information and communications technology', and such police may be attached to the general police force for complex cases. A legal provision requiring intermediaries and aggregators to assist the investigative authorities is required. Electronic evidence law from the time of occurrence to trial must be rationalized, including Section 63 BSA certificate requirements. Clear legal provisions must resolve self-incrimination.

Technically, IP address tracking is possible. Skill improvement and capacity growth of technical professionals may help cyber forensic experts trace the criminal by analyzing 'logs'. Regular cyber security audits and public-private cooperation for security audit and threat analysis centres may enhance results.

Police forces require frequent practical training to upskill. Varied police cadres demand varied curricula and course structures. Central and state governments must recruit additional cyber specialists due to the high number of cases and potential threats. Aseparate cyber security budget fund must be revised annually to expand lab infrastructure.

Cyber terrorism is a global crime. Although Section 75 of the IT Act allows its extra-territorial operation, cooperation with other countries is essential for prosecuting the suspected cyber terrorist in India. Therefore, India must accede to the Budapest Convention.

Without such measures, cyber terrorism would remain beyond the clutches of law and law enforcement agencies, leading to easy acquittals in courts.

1. Telecom Regulatory Authority of India, "The Indian Telecom Services Performance Indicators: April – June 2022" 34 (November 23, 2022). https://trai.gov.in/sites/default/files/QPIR_23112022.pdf.
2. Divyanjali Rathore and Anmol Kuldeep Tyagi, "A Holistic Overview of Cyber Laws Pertaining in India" 3(2) Jus Corpus Law Journal 892 – 893 (2023).
3. Samprity Halder, "Cyber Terrorism: A Threat to Human Society"3(1) Jus Corpus Law Journal282 (2022).
4. Vijaita Singh "AIIMS attack: Investigators asking E&Y about its Audit of Hospital's cyber system" The Hindu, December 3, 2022. https://www.thehindu.com/news/national/aiims-cyber-attack-investigators-asking-ey-about-its-audit-of-hospitals-cyber-systems/article66218762.ece.
5. Sanjay Gupta, "The Changing Dimensions of International Terrorism and the role of the United States: A Comprehensive and Multilateral Approach to Combat Global Terrorism" 65(4) Indian Journal of Political Science557 – 559 (2004).
6. *Id*. at 569.
7. Press Information Bureau, MHA, Government of India (GoI),

"Functioning of NIA", August 3, 2022. https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1847869.

8. Mohammad Iqbal, "Defining Cyber terrorism" 22 John Marshal Journal of Computer & Information Law 397 – 408 (2004).
9. Aditya Goyal, "Cyber Terrorism: An Analysis with an Indian Perspective" 4 *Communication, Media, Entertainment and Technology Journal* 69 (2017).
10. P. Madhava Soma Sundaram and Syed Umarhathab (eds.), Cybercrime and Digital Disorder 75 – 90 (Manonmanian Sundaramar University, Tirunelveli Tamil Nadu, 2011).
11. *Supra* note 9, at 70.
12. *Supra* note 3, at 278.
13. *Supra* note 9, at 71 – 72.
14. AIR 2017 SC 4161.
15. Shrushti Taori and Tatva Damania,"Balancing Free Speech and National Security: A Critical Analysis of Section 152 of The Bhartiya Nyaya Sanhita and Section 124-A Of The IPC", Live Law, June 2, 2024. https://www.livelaw.in/lawschool/articles/balancing-free-speech-national-security-critical-analysis-section-152-bhartiya-nyaya-sanhita-section-124-a-ipc-259465.
16. PRS Legislative Research, "The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023", PRSIndia.Org. https://prsindia.org/billtrack/the-bharatiya-nyaya-sanhita-2023.
17. NIA Act, Sec. 6 & 22.
18. Shikha Pandey, "Anti-Terrorism courts & Procedural (In) Justice: The case of the National Investigation Agency(NIA) Special Courts in South Chhattisgarh, India" 16(1) Socio Legal Review 109 – 139 (2020).
19. Anant Chhabra, "Cyberterrorism: An Analysis" 3(1) Jus Corpus Law Journal337 (2022).
20. Sidrah Jami, "A Synopsis on cyber terrorism dark side of cyber space" 2 International Journal of Legal Science and Innovation 458 – 459 (2020).
21. Sanhita Chauriha, "Explained: The Digital India Act 2023", Vidhi Centre for Legal Policy, August 8, 2023.https://vidhilegalpolicy.in/blog/explained-the-digital-india-act-2023/.
22. MeitY, GoI, "Proposed Digital India Act, 2023" Presentation,

March 9, 2023. https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/DIA_Presentation%2009.03.2023%20Final.pdf.

23. MeitY, GoI, "National Cyber Security Policy – 2013". https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/downloads/National_cyber_security_policy-2013%281%29.pdf.
24. B. Venkatraman and Karun Gupta, "Cybersecurity: Its Effects on National Security and International Relations" 3(2) Indian Journal of Law and Public Policy80 (2017).
25. Chia Chen Wei, "Sketching the Margins of a Borderless World" 30 Singapore Academy of Law Journal 870 (2018).
26. *Supra* note 5, at 572.
27. Cybercrime Division, DGI, Council of Europe, "Joining the Convention on Cybercrime: Benefits" July 5, 2024. https://rm.coe.int/cyber-buda-benefits-2024-july-2789-5929-5498-v-1/1680b0d659.
28. Rebecca Samervel, "American school plot in BKC: Engineer given life for cyber terror", The Times of India, October 22, 2022. https://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/american-school-plot-in-bkc-engineer-given-life-for-cyber-terror/articleshow/95021561.cms.
29. Amisha Shrivastava, "Nagpur Court Convicts and Awards Life Sentence To Ex BrahMos Engineer On Cyber Terrorism Charges", Live Law, June 3, 2024. https://www.livelaw.in/news-updates/nagpur-sessions-court-sentences-ex-brahmos-engineer-nishant-agrawal-pakistan-espionage-case-259585.
30. Bail Appl. No.2553 of 2021.
31. Punishment for criminal intimidation.
32. 2023 SCC OnLine Ker. 2245.
33. Arindrajit Basu, "India's engagement with global trade regimes on cross-border data flows", Centre for Law & Policy Research. https://publications.clpr.org.in/the-philosophy-and-law-of-information-regulation-in-india/chapter/indias-engagement-with-global-trade-regimes-on-cross-border-data-flows/.
34. Lauren Feinee, "Apple refuses government's request to unlock Pensacola shooting suspect's iphone",CNBC, January 14, 2020. https://www.cnbc.com/2020/01/14/apple-refuses-barr-request-to-unlock-pensacola-shooters-iphones.html.
35. Nupur Thapliyal "Traceability Rule Will Break End-To-End Encryption; Can Put Privacy of Journalists, Activists, Politicians

at Risk: WhatsApp Tells Delhi High Court",Live Law, May 26, 2021. https://www.livelaw.in/news-updates/whatsapp-delhi-high-court-traceability-end-to-end-encryption-privacy-risk-174743.

36. Gyanvi Khanna "Cooperating with Investigation Doesn't Mean Accused Is Expected to Make Self-Incriminating Statements: Supreme Court", LiveLaw, March 8, 2024. https://www.livelaw.in/top-stories/cooperating-with-investigation-doesnt-mean-accused-is-expected-to-make-self-incriminating-statements-supreme-court-251604.
37. Anurag Mishra and Satyam Singh, "Understanding E-Evidence Under Bhartiya Sakshya Adhiniyam 2023: Key Provisions and Implications", Live Law, July 15, 2024. https://www.livelaw.in/know-the-law/understanding-e-evidence-under-bhartiya-sakshya-adhiniyam-2023-key-provisions-and-implications-263448.
38. Bureau of Indian Standards, "Information Technology – Security Techniques – Guidelines for Identification,Collection,Acquisition and Preservation of Digital Evidence: ISO/IEC/27037:2012 (Reviewed in 2024)". https://www.services.bis.gov.in/php/BIS_2.0/bisconnect/standard_review/Standard_review/Isdetails?ID=MjMxMzg%3D.
39. Devesh K. Pandey "Cyber terrorism cases: NIA needs additional infra and domain specialists, says experts" The Hindu,September 18, 2021. https://www.thehindu.com/news/national/cyber-terrorism-cases-nia-needs-additional-infra-and-domain-specialists-say-experts/article36536277.ece.
40. Pihu Yadav, "Budget 2023/India allocates over Rs 600 crore to improve cybersecurity infra", CNBCTV18, February 2, 2023. https://www.cnbctv18.com/technology/budget-2023-govt-allocates-over-rs-600-crores-to-improve-indias-cybersecurity-infrastructure-15791831.htm.

Dr. Subhradipta Sarkar

Associate Professor at the Faculty of Law,
Jamia Millia Islamia (JMI), New Delhi.
ssarkar@jmi.ac.in.

Md.Minhajuddin

He is a Ph.D. Research Scholar at the Faculty of Law,
JMI, New Delhi. He may be reached at mdminhajalig@gmail.com.

❑ ❑ ❑

Role of Social Media Networks on Political Socialization of the Youth of Gwalior

• Dr. Mohd. Tariq Mir

Politicians and political parties have begun to use social media networks to campaign, attract young people and promote their ideas among them in the modern period. On the other side, some social media users used it for political purposes.In the ancient era, there were limited facilities available for the people to get any type of information whether it was political information or information related to the general public. Only print media and a few government or private broadcast television channels were available in India to educate and inform the public. The world has completely changed since then. The major goal of this research is to determine the effect of social media networks on the political socialization of Gwalior's youth. The research is conducted by keeping in mind certain objectives: study the level of awareness among respondents of different social media networks; know the level of trust in information obtained from social media networks and study the impact of social media networks on political socialization and political participation of the youth. A well-planned survey method is selected to get the required data. A questionnaire is used to collect data from the 120 study samples. The young generation of Gwalior (India) from the age of 18 to 32 years including both males and females is a sample of the study. A purposive sampling technique is used by the researcher for data collection. The study's findings demonstrate that social media networks have a significant impact on the political participation and political socialization of Gwalior's youth.

Keywords : *Social Media Networks, Youth, Political Socialization. Political Participation.*

Introduction

In India, we have seen a rapid internet penetration rate over the past decade. India had about 600 million internet users in 2020, which is excessively rapid in comparison to the time and it reached around 900 million internet users by 2025, according to the IAMAI-Kantar ICUBE report 2020. India has about 600 million internet users and it overtakes the US as now the second-largest internet base in the world.

The impact of social media is increasingly apparent in India, where Indians are among the world's most active users of these platforms. Social media networks are helping people of India almost in all aspects of their lives such as on political socialisation of youth, political participation, communication, education, entertainment and development etc. Now, after transforming many facets of Indian life, social media networks have found new users and are emerging as a tool for political strategists and leaders from all political parties. The use of the internet by the people of India helps them to connect with the politics, learn about their political parties and their leaders, as the country's internet penetration and its users grow rapidly. In India, the Internet has given everyone access to politics. Almost all major Indian political parties have websites, Facebook pages, Twitter and WhatsApp accounts, as well as Instagram accounts.

Each of the social media networks provides a platform for its users to receive political information. The effect of one network member is greatly dependent on the members of the other and these networks have a significant influence on voters. It also boosts electoral involvement, as we witnessed in the 2008 presidential election campaign in the United States.This is now happening in India, where political parties are attempting to use the Internet to recruit new members, for votes and support, build larger volunteer bases, and for solicit donations. Eg. The AAP's official website solicits nominations, suggestions, and donations for the upcoming 2014 general elections. After realising the impact of social media networks,every political party is always adding content to its websites and creating fresh ideas and tactics to maximize the use of the Internet for political gain.

Previously, only print media and a few government or private broadcast television channels were available in India to educate and

inform the public. The world has completely changed since then. The modern era is defined by digital communication technologies. The internet and social media networks have altered the communication and information landscape. The spread of social media networks in India is on par with that of the rest of the world. It now has a significant impact on the political socialisation of India's youth.India's citizens use social media networks to obtain political information and to spread their political beliefs. Many political parties and activists have personal accounts and official pages to entice young people to support them and keep in touch with their networks.

Significance of the Study

The introduction of social media networks altered the environment of communication and information. Millions of individuals throughout the world have been interested in the rapidly increasing social media networks. People, particularly young people, are becoming increasingly active in the use of social media networks. Social media networks are becoming increasingly popular in India, as in many other nations. It has piqued the interest of people of all ages and professions, particularly young people. Its impacts are visible and measurable in all aspects of life. So, with the popularity, the quantity of involvement, and the effects of social media networks in mind, the researcher chose the issue to assess the impact of social media networks on the political socialisation of youths. It is because social media networks are playing a big part in bringing about revolutions and political transformations all over the world. For political campaigns and communication, it has emerged as a significant tool.

Objectives of the study

1. Study the level of awareness among respondents of different social media networks.
2. To know the level of trust in information obtained from social media networks.
3. Study the impact of social media networks on political socialization and political participation of the youth.

Research Questions

1. What is the awareness among youth regarding social media networks?

2. What is the popular social media network among youth to get political information?
3. How often do young people rely on information from social media networks?
4. What is the purpose behind social media network use?
5. Does the use of social media networks help in the political socialization of the youth?
6. Do social media networks impact youth political participation?
7. Do social media networks have an equal impact on male and female political socialization?
8. Do social media networks impact Indian politics?

Review of Literature

Political socialisation is defined as the process through which attitudes regarding the political system progress from one epoch to the next. These orientations include political knowledge, perspectives on specific political issues, values, beliefs and attitudes, and voting behaviour. All of these orientations contribute to the formation of a person, regardless of whether it occurs in India, the United States, or South Africa (German 2014). Social media is a vital tool for rapidly disseminating mass communication. Social media, in addition to serving as a networking medium, played an important role in mobilising people as activists and eliciting citizen reactions to political activity. The Delhi Assembly election 2014 is the best example of that (Katkar 2014). Social media is an important instrument utilised by all political parties to encourage young people to come, vote, and join any political party of their choice. Males as well as females participate in political debates and discussions and express their opinions on social media platforms like Facebook, WhatsApp, and Twitter. People are more likely to support a party that is active on social media (Biswas 2014).

Social media have grown in popularity in recent years. The Obama campaigns in 2008 and 2012 piqued the public's curiosity about how social media affects those who participate in civic and political life (Boulianne 2015). Political knowledge is growing among the general public, particularly among young people. Political campaigns using new media assist in attracting more

citizens to political engagement moulding it as a meaningful future of politics (Rahul 2016). With the introduction of different social media platforms political campaigning has undergone significant changes and a new trend was seen in India during the Lok Sabha election in 2014 (Narasimhamurthy 2014) when social media played an active role and predicted which party would win the most seats. The Internet today allows people in India to actively participate in all political activities, which has strengthened and expanded democracy (Saikia 2019).

Methodology

Explanatory research methodology is selected for this study, and data are collected from each sample through the survey research method.

A well-planned survey method is selected to get the required data. A questionnaire is used to collect data from the 120 study samples. The young generation of Gwalior (India) from the age of 18 to 32 years including both males and femalesisa sample of the study. A purposive sampling technique is used by the researcher for data collection.

Major Findings

Table 1 reveals that 60 respondents are male and 60 are female included in this research. The majority of the 45 percent are from the age group of 23 to 27 years of age, 32 percent belong to the age group of 18 to 22 years of age and the rest of 23 percent belong to the age group of 28 to 32 years of age (Table 2).

Table 3 shows that 93 percent of the respondents say that they are well aware of social media networks like WhatsApp, Twitter, Facebook etc., and only 7 percent say that they have no awareness about that.

According to Table 4, 43 percent of the respondents spend 3 to 4 hours on social media networks per day. 28 percent of the respondents use social media networks between 5 to 6 hours, 16 percent spend more than 6 hours and only 13 percent of the respondents spend 1 to 2 hours on social media networks in a day.

Table-1. Sex Composition. (N=120)

Gender	Frequency	Percentage
Male	60	50%
Female	60	50%
Total	120	100

Table-2. Age of the respondents. (N=120)

Age	Frequency	Percentage
18-22	38	32%
23-27	54	45%
28-32	28	23%
Total	120	100

Table-3. Awareness about social media networks. (N=120)

Awareness	Frequency	Percentage
Yes	112	93%
No	8	7%
Total	120	100
Total	120	100

Table-4. Time Spend on Social Media Networks. (N=120)

Time Spend	Frequency	Percentage
1-2 hours	15	13%
3-4 hours	52	43%
5-6 hours	34	28%
More than 6 hours	19	16%
Total	120	100

As per Table 5, Facebook is the most popular network among all the social media networks and 37 percent of respondents have

used it and get political information, 31 percent say that they prefer WhatsApp, 23 percent Instagram and 9 percent of the respondents are used Twitter to acquire political information.

The data represented in Table-6 shows that 85 percent of the respondents rely on the information getting through social media networks to a great extent, 9 percent rely on it to some extent and the rest of 6 percent of the respondents say that they are not at all rely on the information acquired through the social media networks.

Table 7 shows that 51 percent of the respondents use social media networks to get updated news about their surroundings, whether it is political news or news about any other issues. 25 percent used it for entertainment, 19 percent of the respondents used it for making new friends and 5 percent used it for other purposes.

Table-5. Preferred social media networks to get political information. (N=120)

Preferred networks	Frequency	Percentage
Facebook	44	37%
WhatsApp	37	31%
Instagram	28	23%
Twitter	11	9%
Total	120	100

Table-6. Rely on information from social media networks. (N=120)

Time Spent	Frequency	Percentage
To some extent	11	9%
To great extent	102	85%
Not at all	7	6%
Total	120	100
Total	120	100

Table-7. Purpose behind social media network use. (N=120)

Purpose	Frequency	Percentage
Entertainment	30	25%
To Get Updated News	61	51%
Making New Friends	23	19%
Others	6	5%
Total	120	100

Table 8 explains that 74 percent of the respondents are in favour of social media networks having a great impact on the political socialisation of the youth, and 20 percent say that to some extent it impacts the youth. 6 percent of the respondents believe that social media networks do not at all impact youth's political socialization.

Data represented in Table 9 reveals that the use of different social media networks has a great impact on the political socialization of the young generation, 64 percent of the respondents are in favour of it, and 25 percent say that to some extent it impacts youth political participation and 11 percent of the respondents don't agree with the question that social media networks impact on youth's political participation.

Table-8. Social media networks & political socialization of the youth. (N=120)

Political Socialization	Frequency	Percentage
To Some extent	24	20%
To a great extent	89	74%
Not at all	7	6%
Total	120	100

Table-9. Social media networks impact youth political participation. (N=120)

Political Participation	Frequency	Percentage
To some extent	30	25%
To a great extent	77	64%
Not at all	13	11%
Total	120	100

Data represented in Table-10 shows that out of 120 respondents 73 percent believe that social media networks have a great impact on both male and female political socialization, 17 percent believe that to some extent it impacts young male and female political socialization, whereas 10 percent believe that they don't have any impact on their political socialization.

The represented data in Table 11 shows that 81 percent of the respondents are in favour of social media networks having a great impact on Indian politics whereas 19 percent say that it has no impact on Indian politics.

Table-10. Social media networks impact on male and female political socialization. (N=120)

Impact on male & female	Frequency	Percentage
To some extent	20	17%
To a great extent	88	73%
Not at all	12	10%
Total	120	100

Table-11. Social media networks impact Indian politics. (N=120)

Indian Politics	Frequency	Percentage
Yes	97	81%
No	23	19%
Total	120	100

Discussion and Conclusion

The term "political socialization" refers to the process by which a society's political culture is passed down from one generation to the next, or from one generation of citizens to the next. It is a process in which the younger generation acquires deliberate, formal and informal social attitudes and personality traits that are relevant to politics. Political socialisation is the process of socialisation that takes place in a political context.The main aim of this research is to know how social media networks influence political socialization, political participation and political knowledge among the youth of Gwalior.

The findings of the study show that most of the respondents are well aware of social media networks like WhatsApp, Facebook Twitter Instagram etc., and the majority of them spend 3 to 4 hours a day on different social media networks. Among all the social media networks Facebook is the most popular network among the youth of Gwalior to get political information, 37 percent of the youth use Facebook followed by WhatsApp with 31 percent, 23 percenton Instagram and 9 percentuseTwitter to get political information (Table-5).Respondents also agreed that they rely on social media networks to a great extent to get political information and most of them use it to get updated news about their surroundings whether it is political information or information about any other issues (Table 7).

It also proved that social media networks have a great impact on the political socialization of the youth of Gwalior whether they are male or female. It provides all types of information to the people, influences their political behaviour and also attracts them to participate actively in politics. In the modern era, people use different social media networks to express their feelings and also reveal the truth which is not broadcast by the traditional media. Through this platform, people connect with all around the globe and learn a lot from the friends of other countries. Social media networks also have a great impact on Indian politics. It has changed the whole trend and old campaigning process of Indian politics. Nowadays, it become the main weapon for any political partyin India to attract youth. Social media networks also provide unlimited knowledge, information and entertainment to the youth.

References

1. Biswas, A. Ingle, N.& Roy, M. (2014). Influence of social media on voting behaviour. Journal of power, politics and governance. Vol-02, No-02, PP-127,155. ISSN-2372-4919.

2. Boulianne, S. et al (2015). Social Media use and participation: A meta-analysis of current research. Taylor and Francis Group in information, communication and society. https://dx.doi.org/10.1080/1369118X.2015.1008542
3. German, D.B. (2014). Political Socialization Defined: Setting the Context. Published in PL Academic Research. PP. 19-26, Vol. 32, e-ISBN 978-3-653-01971-1.
4. Katkar, S.A. (2014). Impact of Social Media on Indian Politics. Indian Institute of Management Kozhikkode. A Business Research Management Proposal. Pp. 1-14. Pgt/17/130/2014.
5. Mahmood, S. & Awan, A.G. (2019). Role of social media inactivation of youth in politics: A case study of district Khanewal. Global journal of management, social sciences and Humanities. Vol-05. PP-718-742. ISSN- 2520-7113.
6. Narasimhamurthy, N. (2014). Use of social media as election campaign medium in India. International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies. Vol-01. No- 08. PP- 202-209. ISSN-2348-0343.
7. Neelamalar, M. & Chitra, P. (2009). News media and society: A study on the impact of social networking sites on Indian youth. Estudos em comunicacao. No- 06, PP-125,145.
8. Punia, S.K. (2016). Social media: political campaigns and elections. MP. Journal of Social Sciences. Vol-21. No- 02. PP-65, 74. ISSN- 0973-855X.
9. Rahul, K. (2016). Use of new media in the Indian political campaigning system. Journal of political sciences and political affairs. Vol-04. Issue-02. ISSN- 2332-0761.
10. Saikia, B. (2019). Interactive computer-mediated Technology: social media and politics. IJITEE. Vol- 08. Issue- 11. ISSN-2278, 3075.
11. Zuniga, H.G.D. Molyneux, L. &Zheng, L. (2014). Social media, political participation: Panel analysis of lagged and concurrent relationship. Journal of communication. ISSN-0021-9916.

Dr. Mohd. Tariq Mir
Lecturer of Sociology
Govt. of J & K, Dept. of Higher Education
emal:tariq.mir50@gmail.com

❑ ❑ ❑

Legal Protection of Endangered Languages in India with Special Reference to A.Tong, A Dialect of Garo Language in Meghalaya

Dr. RanjitSil • Mrs. Puja Khetawat

A.tong which is regarded as critically endangered by United Nations Education, Scientific and Cultural Organization (UNESCO),A.tong is spoken by 4600 people in India which is only 0.15% of total population of Meghalaya and 10,000 speakers worldwide where it is a sharp decline since of use of this language as in 1920 there were 15000 A.tong speakers in India. The reason for which this language in on the verge of extinction is most of the speakers are themselves not comfortable to speak their own language and are bilingual in today's date as Garo being the standard language of Garo Hills, hence as this language is oral having no script of their own therefore it is difficult to preserve the same.A.tong can be categorized as an "unclassified language" as no sufficient data is available on this language in Government offices.The United Nations General Assembly imposes liability on the state to promote and protect the linguistic identity of minorities. It also says that state parties should make legislation in their own state and adopt other measures to promote and protect linguistic minorities.The 2030 Agenda for Sustainable Development adopted by the General Assembly in 2015 aims to ensure equal access for the indigenous people to all level of education and vocational training under the Sustainable Development Goals target 4.5.The Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage (CSICH), 2003: lays emphasizes that the state parties are supposed to take necessary measures to ensure the safeguarding if the intangible cultural heritage present in its territory such as adoption of appropriate policies and promotion of education and so on.There is no special legislation in India

to protect endangered languages.The Right to Education Act, 2009 unquestionably states that the "medium of instructions shall, as far as practicable, be in child's mother tongue." The knowledge transformation in regional languages has enabled students to understand the subject matter better and improve their overall learning experience. The National Education Policy 2020 advocates that "wherever possible, the medium of education will be the mother tongue/local language/regional language until at least Grade 5, but preferably until Grade 8 and beyond," both in public and private schools.Hence the medium of instruction in A.tong language must be encouraged and also the available materials on this language must be included in their syllabus such as grammar and vocabulary. Essentially more research work has to be carried out by Scholars especially through empirical study by visiting South Garo Hills of Meghalaya in order to understand deep-rooted cause of declining factor of A.tong language

Keywords : *Indigenous Languages, Critically Endangered Language, Unclassified Language, A. tong, Linguistic Minorities, Oral Traditions,Intangible Cultural Heritage,Sustainable Development,Open Educational Resources,language data,The National Education Policy 2020, Indigenous and Tribal People Convention (ITPC), 1989*

I. Introduction

Meghalaya is one of the State in India where English is an official language whereas Khasi and Garo are two associated languages as per The Meghalaya State Language Act,2005. Out of the total population of the state which is approximately 29.67 lakhs, Garo is spoken by 31.60% which is 937572 as per 2011 census. Garo is a Sino-Tibetan language which has its twelve dialects out of which this paper mainly focus on one of its dialect namely A.tong which is regarded as criticallyendangered by United Nations Education, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), Ethnologue and People's Linguistic Survey of India(PLSI). A.tong is spoken by 4600 people in India which is only 0.15% of total population of Meghalaya and 10,000 speakers worldwide where it is a sharp decline since of use of this language as in 1920 there were 15000 A.tong speakers in India. The reason for which this language in on the verge of extinction is most of the speakers are themselves not comfortable to speak their own language and are bilingual in today's date as Garo being the standard language of Garo Hills,

hence as this language is oral having no script of their own therefore it is difficult to preserve the same. Therefore, apart from International Organizations, there are several measures available at National level itself to safeguard the linguistic minorities such as several articles of the Constitution of India which specifically protects linguistic minorities and their cultures, documentation schemes, funds given by Government of India to protect the endangered languages which also includes A.tong languages including other such facilities. However, the observation is that in spite of the fact that Government is working on protection and preserving of A.tong language, which is an "unclassified language" it is the people themselves who should build up confidence among themselves and respect their native language which is the ultimate key to address the issue at grassroot level.Nelson Mandela correctly said, "If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart. Love of one's own mother language can lead to historic movement". Hence history is the witness that sensitivity towards the protection and preservation of culture and languages of indigenous people of Meghalaya is one of the main reason why Meghalaya got bifurcated from Assam and emerged as a full-fledged Autonomous State on 21st January, 1972. Therefore, all languages of Meghalaya must be given equal importance whether classified or unclassified.

II.A.tong-a dialect of Garo language

Oliver Wendell Holmes rightly said, "Language is the blood of the soul into which thought run and out of which they grow". Meghalaya is one of the North Eastern Region State if India which is rich in diversified indigenous languages. According to The Meghalaya State Language Act,2005 English is the official language while Khasi and Garo are regarded as associated languages of the State as per Section 3 and 4 of the said Act respectively. Section 5 of the same Act provides the rights of various other linguistic minority groups, their protection and preservation. The approximate population of Meghalaya is approximately 29.67 lakhs as per 2011 census out of which Garo is spoken majorly in Garo Hills of Meghalaya which consist of 31.60%, 937572 of the total population of Meghalaya. Garo is a Sino-Tibetan language, which is orally passed from one generation to another with no script of its own. Basically it has twelve dialects out of which A.tong is one of them which is regarded as

critically endangered languages as it has only 4600 speakers in India which is only 0.15% of the total population of Meghalaya and 10,000 speakers left worldwide. The Indian Government do not recognize any language which is spoken by less than 10,000 people in India. A.tong can be categorized as an "unclassified language" as no sufficient data is available on this language in Government offices. International Organizations like UNESCO, Ethnologue recognizes A.tong as critically endangered language as well as Linguistic Survey of India (LIS) at domestic level. Sharp decline is observed from 15000 speakers in 1920 to 4600 at national level and 10,000 worldwide in today's date by LIS, a regular ongoing project of language division in India. A.tong is a language whose speakers are mostly located in South Garo Hills district such as Baghmara area. A.tong being a sub-part of Garo language donot have any official status of its own, in spite of the fact that Garo and A.tong have different vocabulary and grammar. The reason which led this language moribund and on the verge of extinction is that most of the A.tong speakers are bilingual in today's date as the Garo being the standard and dominating language of Garo Hills, Meghalaya, these A.tong people started having ininferiority complex, build up negative image towards their own language as their find less relevancy in learning their native language. Most of the A.tong schools are now started using both Garo and A.tong as a medium of instructions, also Bible in translated in Garo language using Roman script.

III. International Perspective

Several Organizations are working at international level to protect the interest of Linguistic minorities especially those which falls under endangered languages. International Covenant on Civil and Political Rights,1966 (ICCPR) protects the interest of linguistic minorities by stating that they will not be denied the use of their own culture, profess and practice their own religion and use their own languages. The United Nations General Assembly imposes liability on the state to promote and protect the linguistic identity of minorities.It also says that state parties should make legislation in their own state and adopt other measures to promote and protect linguistic minorities .

Part VI of Indigenous and Tribal People Convention,1989 deals with education and means of communication. It lays focus

on the development of indigenous languages by adopting necessary measures concerned such as taught to read and write in their own language, competent authority shall be appointed who can undertake consultations with these people with the view to the adoption of measures to achieve this objective . India has not ratified this convention. The United Nations Declaration on Indigenous People, 2007 states that indigenous people have the right to revitalize, use, develop, transmit to future generations their languages, oral traditions, writing systems and literatures. The Declarationtalks about indigenous people's right to establish their educational systems and media in their own languages and to have access to an education in their own language .The United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFI) established by resolution 2000/22 on 28th June, 2000 has consistently drawn attention to threat against indigenous languages and pushed for actions to promote and protect the languages.As early as 2003, the Permanent Forum recommended that Government introduce indigenous languages in public administration in indigenous territories where feasible. In 2005, the Forum recommended that United Nations Country offices make efforts to disseminate in indigenous languages.The Permanent Forum also encouraged the United Nations Education, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) to support the creation of indigenous language and cultural studies in universities. The United Nation General Assembly (Resolution A/RES/74/135) proclaimed the period between 2022 and 2032 as International Decade of Indigenous languages to draw the global attention on critical situation of indigenous language and their preservation of same. The 2030 Agenda for Sustainable Development adopted by the General Assembly in 2015 aims to ensure equal access for the indigenous people to all level of education and vocational training under the Sustainable Development Goals target 4.5.Use of indigenous language in education has been strongly put forth as an approach to meet this target.Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage came into existence in 2003 but was ratified on 20th April 2006 with 30 states.

The term "Intangible Cultural Heritage" as used in this Convention includes oral traditions and expressions, including language and the performing arts.The Convention lays emphasizes that the state parties are supposed to take necessary measures to ensure the safeguarding if the intangible cultural heritage present in

its territory such as adoption of appropriate policies and promotion of education and so on.A.tong, a language of Meghalaya, India has been classified as an endangered language by Ethnologue

United Nations Education, Scientific and Cultural Organization defines four levels of language endangerment between "safe" (not endangered) and "extinct". They are-

i. Vulnerable;
ii. Definitely endangered;
iii. Severely endangered;
iv. Critically endangered.

In India United Nations Education, Scientific and Cultural Organization classifies 197 languages as endangered.United Nations Education, Scientific and Cultural Organization classifies A.tong as 'Critically Endangered' language as total number of speakers are less than 10,000 worldwide.A 2021 study revealed that 76.9% of online languages corresponds to the world's top ten most spoken languages. Recognizing this threat, United Nations Education, Scientific and Cultural Organization leads efforts to preserve and integrate indigenous languages into digital world, in line with the 2003 Open Educational Resources (OER) recommendation.The UNESCO Atlas of the World's Languages in Danger was an online publication containing a comprehensive list of the world's endangered language. It categories the endangered languages as extinct, critically endangered, severally endangered, definitely endangered, vulnerable, safe, revived and constructed. The World Atlas of Language (WAL) is an online platform which provides accurate, reliable, up-to-date and robust language data for the entire world.

IV. National Perspective

Constitution of Indiaauthorizes the linguistic minority citizens of India who are Indian residents to conserve their languages, scripts and culture . Article 29 merely enables a cultural or linguistic minority people to preserve their language, it does not impose any positive obligation on the state to take any action to conserve any culture or language. The Constitution of India gives protection to all linguistic minorities to establish and administereducational institutions of their choice. It is to be noted that both Article 29

and 30 are fundamental rights of the people of India, hence it is justiciable in the Court of Law under Article 32 and 226 in Supreme Court and High Court respectively. Article 350 A makes provision to provide instruction to the students in their mother tongue.Article 350 B of the Constitution provides for the appointment of a Special Officer for linguistic minorities by the President of India.Such officer ensures effective implementation of safeguard provided to linguistic minorities, investigate all matters and report back to the President of India.

V. Documentation support schemes in India

There is only dedicated endangered language documentation schemes in India namely, Schemes for Protection and preservation of endangered Languages (SPPEL) which was instituted by Ministry of Education (Government of India) in 2013. The sole objective of Scheme is to document and archive the country's languages that gas become moribund or likely to be moribund in near future. Funds was provided at University Grant Commission (UGC) to promote and preserve language; In order to address the issue of preserving endangered languages, UGC constituted an Expert Committee who inter-alia recommended providing financial support to the Central Universities for setting Centers for study and research related to endangered languages.The Commission has accepted the recommendations of the Committee and decided to launch a scheme namely Financial Assistance for setting up Centers for preservation and promotion of endangered languages during XII plan period. North Eastern Zone is one of the six zones under SPPEL. Out of eight states included in it, Meghalaya is one of them.A.tong, an indigenous language of Meghalaya is also included under SPPEL, and its Principal Investigator name is Dr. UmaraniPappuswamy.The Scheme is monitored by Central Institute of Indian Language (CIL) located in Mysuru, Karnataka, India.The Central Institute of Indian Language has collaborated with various Universities across India for this mission.A total of Rs. 45.89 crores were made available by UGC and CIL between 2015-2016 and 2019-2020 under their programs for the preservation of endangered Indian languages. Centre for Endangered Language Studies at Indian Institute of Technology (IIT), Patna as a part of Central Institute of Indian Language is devoted to fulfil its vision of helping the endangered

language communities to revive and maintain their languages and also instill a sense of pride and loyalty towards their native language. Once a question was raised in Rajyasabha regarding Endangered Regional Languages in North-East wherein Minister Of State In The Ministry Of Home Affairs (Shri Nityanand Rai) replied that Study of various languages/ scripts of NE States and measures to revive the lost languages/scripts is one of the mandated areas as per North Eastern Council (NEC) General Guidelines 2020. And informed that during Financial Year 2020-21, NEC has sanctioned 4 projects amounting to Rs. 3.49 crores to study, documentand preserve languages of NE Region, namely, Ntyenyi (Nagaland), Khongdei (Manipur), Zyphe (Mizoram), Nah, Brokpa, Ashing, BogunBokangs of Arunachal Pradesh, Bantawa, Kulung and Limbu of Sikkim and Atong,Fahirem/Sahirem, Lyngngam (Meghalaya).

VI There is no special legislation in India to protect endangered languages

India is a growing nation and is determined to be known as a source of knowledge globally. For the past few years, the Indian government has been working to transform the traditional education model into a modern ed-tech framework, intending to become the greatest knowledge source. In the process of making it possible, the importance of the mother tongue in education has been discovered. The discovery has led to the introduction of the mother tongue in foundational education under the Indian school curriculum. It has opened new doors for students and has enabled them to learn more effectively. It has also helped to bridge the gap between the traditional and modern education systems.The National Curriculum Framework 2022 recommends that children be instructed in their Matribhasha (mother tongue) until they are eight.The Right to Education Act, 2009 unquestionably states that the "medium of instructions shall, as far as practicable, be in child's mother tongue."The knowledge transformation in regional languages has enabled students to understand the subject matter better and improve their overall learning experience.The National Education Policy 2020 advocates that "wherever possible, the medium of education will be the mother tongue/local language/regional language until at least Grade 5, but preferably until Grade 8 and beyond," both in public and private schools.

VII. Endangered Languages: how can we save them?

a. When it comes to preservation of endangered languages, there is no platform in Intellectual Property Rights (IPR) to protect the same. Copyright can be made only on some kind of expressions, phrases, poems, etc. of a particular language but not the language as a whole as language is general in nature and do not have any ownership of individuals.

b. In an article published in the anthropology magazine 'Sapiens' Anastasia Riehl, director of the Strathy Language Unit at Queen's University, Canada mentioned that "Language is the cultural glue that bind communities together".

c. Every indigenous language has its own terminologies and phrases that signify a specific meaning and idea. All these things must be kept in mind while curating and recording language resources.

d. Developing detailed documentation is one of the most crucial steps in conserving an endangered language. These resources create a powerful record and assist the new generations in culturally adapting to their respective native language without investigating time and effort in deciphering them.

e. Dominating factors of standard language in particular area sometimes leads to extinction of linguistic minorities language as they find the use of their own language no use in long run. So as is the matter of Garo Hills, Meghalaya where A.tong language is standing on the verge of extinction due to the extensive use of Garo language in all parts of Garo Hills including those areas where A.tong people majorly resides.

f. Technology advancement can also contribute to the safety for A.tong language as many people made their channels and pages on popular social media platforms such as YouTube, Facebook, Instagram where they promote their content in their own language.

g. Taking language learning sessions and classes can also benefit to increase the speakers of language and revitalize the same.

h. A.tong language speakers should build up a sense of self-motivation among themselves and carry-out their ancestral language with pride, be vigilant towards their rights of

protection measures provided by Government of India, funds given to revitalize their language, programs and projects carried out to protect their endangered language so that their issue can be addressed at ground level.

i. The Government of Meghalaya is recommended to put emphasis on promotion of linguistic minorities of the state by developing educational system in their mother tongue, spreading awareness programmes and projects allotments with adequate fund from time to time.

VIII. Conclusion:

There is not much literature on A.tong language available. It was SainoVenegal from Netherlands who came to Tura in 2004 and done a research on A.tong language in Melbourne University. He wrote A.tongGrammer and short stories. Several other research works are going on in the several languages of Garo Hills and it's literature like Am.beng, A.tong, A.we etc.at National Level especially in several departments of Central University like North Eastern Hill University, Meghalaya, India.In today's date there are no more schools are in existence in South Garo Hills where medium of instruction is given in A.tong language. Hence the medium of instruction in A.tong language must be encouraged and also the available materials on this language must be included in their syllabus such as grammar and vocabulary.Essentially more research work has to be carried out by Scholars especially through empirical study by visiting South Garo Hills of Meghalaya in order to understand deep-rooted cause of declining factor of A.tong language.Hence, it can be said that much more work is needed to be done to understand the phenomena of continuously declining nature of A.tong language in India. This work is completely doctrinal in nature. A.tong can be correctly classified as "Unclassified Language" as no sufficient data was found on personal visit in the Office of Deputy Commissioner and Garo Hills Autonomous Council, Tura Meghalaya as well as on any website of Governmentof India. Hence, this work is open for further research.

References

1. The Meghalaya Legislative Assembly, "The Meghalaya State Language Act,2005", Meghalaya Act No. 10 OF 2005, Published

in the Gazatte of Meghalaya extra-ordinary, issued dated 4th May, 2005.
2. Meghalaya, available at http://en.m.wikipedia.org>wiki (Last Modified on July,2023)
3. Observation of the International Mother Language Day 2021 available at http://webtv.un.org>asset (published on 22 Feb.2021)
4. The Meghalaya State Language Act,2005
5. Article 27 of International Covenant on Civil and Political Rights,1966
6. Resolution 47/135 of 18-12-ts of persons belonging to national, religious and linguistic of the Declaration
7. Indigenous and Tribal People Convention, 1989 (ILO) (C169)
8. Article 28 of Indigenous and Tribal People Convention,1989
9. Article 13 of United Nations Declaration on Indigenous People (UNDIP), 2007
10. Article 14 and 16
11. Ethnologue, Not-profit Organization founded in 1951, headquartered in Dallas, United States of America.
12. Article 29 of the Constitution of India
13. Article 30(1) of the Constitution of India
14. Government of India, Ministry of Home Affairs, RajyasabhaUnstarred Question No. 376, scheduled to be answered on the 1st December, 2021/10 Agrahayana, 1943 (Saka)
15. Section 29(f) of Chapter V of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009
16. Section 5 of the Meghalaya State Language Act, 2005

Dr. RanjitSil
Assistant Professor
Department of Law, North-Eastern Hill University,
Shillong, Meghalaya, Email: dr.ranjitsil@gmail.com

Mrs. Puja Khetawat
Research Scholar
Department of Law,
North-Eastern Hill University, Shillong, Meghalaya

❑ ❑ ❑

Rule of Law : A Fundamental Pillar of Democracy

• Dr. Ashok Kumar Karnani

Introduction

The Rule of Law stands as one of the fundamental ideals of political morality, forming the cornerstone of a democratic society. It embodies the principle that governance should be based on established laws rather than the arbitrary will of individuals. By ensuring justice, equality, accountability, and impartiality, the Rule of Law acts as a guiding framework for effective governance. It is a fundamental principle that safeguards citizens from the abuse of power and guarantees that governmental authority is exercised in a fair and transparent manner.

Although the term 'Rule of Law' is not explicitly defined in the Indian Constitution, it has been frequently invoked by the Indian judiciary in numerous landmark judgments to uphold democratic principles and fundamental rights. The judiciary has consistently reaffirmed the Rule of Law as a bedrock principle essential for upholding constitutional supremacy and preventing the erosion of democratic values. It serves as a protective shield against arbitrary decision-making and ensures that no individual, regardless of status or position, is above the law.

The Supreme Court of India has declared the Rule of Law as one of the basic features of the Constitution, making it an integral part of good governance. This doctrine underscores the necessity of fairness in legal processes, access to justice, and the accountability of state institutions. It acts as a check on the misuse of power, reinforcing the idea that all laws must be just, consistent, and uniformly applied.

Given its significance in preserving democracy, an independent and impartial judiciary plays a crucial role in maintaining and safeguarding this doctrine. The judiciary serves as the guardian of constitutional principles, ensuring that legislative and executive actions remain within their prescribed limits and do not violate fundamental rights. The effectiveness of the Rule of Law depends on the strength of judicial independence, as a free and fair judiciary is instrumental in interpreting and enforcing laws in a manner that upholds justice and equity.

In a democratic setup, the Rule of Law not only acts as a check on arbitrary governance but also promotes public confidence in the legal system. It fosters trust among citizens by guaranteeing that their rights and freedoms are protected under a just legal order. By embedding the principles of legality, transparency, and accountability within governance structures, the Rule of Law strengthens the democratic fabric of a nation and ensures that justice prevails in all aspects of public administration.

Meaning and Historical Evolution of Rule of Law

The concept of the Rule of Law has deep historical roots, dating back to Ancient Greece, where Aristotle was one of its earliest advocates. He emphasized that laws, rather than individuals, should govern society to ensure justice and prevent arbitrary rule. This foundational principle was later expanded upon by medieval and early modern thinkers who shaped its evolution.

Sir John Fortescue, in the 15th century, highlighted the distinction between governance by law and rule by an absolute monarch, advocating for a legal system that upholds justice and protects individual rights. In the 17th century, John Locke further refined this notion, asserting that government should be based on laws that safeguard life, liberty, and property. Niccolò Machiavelli also contributed to the discourse, emphasizing the necessity of legal frameworks in maintaining stability and preventing tyranny. Montesquieu, in the 18th century, introduced the idea of the separation of powers, reinforcing that laws must regulate government actions to prevent despotism.

These philosophical contributions collectively laid the groundwork for modern interpretations of the Rule of Law, influencing democratic principles and constitutional frameworks

worldwide. Their ideas continue to be fundamental in ensuring legal accountability, equality before the law, and the protection of fundamental rights.

Modern Era Development

In the modern era, distinguished scholars such as A. V. Dicey, F. A. Hayek, and John Rawls further developed the concept of the Rule of Law, refining its application in contemporary legal and political frameworks. A. V. Dicey, in particular, played a pivotal role in shaping its modern interpretation, emphasizing three key principles: the supremacy of law, equality before the law, and the predominance of legal spirit.

Dicey argued that the Rule of Law ensures the absolute authority of laws over arbitrary and discretionary government power. He asserted that no individual, regardless of status or position, is above the law, reinforcing the idea that legal principles must govern all state actions. His work profoundly influenced democratic legal systems, particularly in nations such as the United Kingdom, the United States, and India, where constitutional governance is rooted in this doctrine.

F. A. Hayek expanded on Dicey's views, emphasizing the economic and social significance of the Rule of Law. He argued that predictable and stable legal frameworks are essential for individual liberty and economic prosperity. Meanwhile, John Rawls linked the Rule of Law to justice and fairness, proposing that legal structures should protect fundamental rights and promote social equality.

These contributions have cemented the Rule of Law as a fundamental principle in democratic governance, ensuring accountability, fairness, and legal certainty. It remains a cornerstone of constitutional democracies, safeguarding civil liberties and preventing the concentration of unchecked power in government institutions.

A. V. Dicey's Principles of Rule of Law

A. V. Dicey, a renowned British jurist, played a significant role in defining and refining the modern concept of the Rule of Law. His interpretation remains foundational to democratic legal systems, particularly in the United Kingdom, the United States, and India. Dicey outlined three core principles of the Rule of Law, each essential to ensuring a just and fair legal order.

1. Supremacy of Law

The first principle emphasizes that laws, rather than arbitrary decisions by rulers or government officials, must govern society. Dicey asserted that no person could be punished, penalized, or deprived of life, liberty, or property except through established legal procedures. This principle ensures that state actions remain within defined legal boundaries and that individuals are protected from unjust or discretionary exercises of power. Every punishment or sanction must be based on a specific legal provision, properly adjudicated by an impartial court.

2. Equality Before Law

Dicey's second principle underlines that all individuals, regardless of their social, political, or economic status, are subject to the same laws. There are no special privileges or exemptions for government officials, public servants, or any class of people. This principle guarantees that justice is applied uniformly, reinforcing the idea that legal protections and obligations apply equally to all citizens. It prevents discrimination and arbitrary distinctions in the application of laws, ensuring fairness and impartiality in governance.

3. Predominance of Legal Spirit

The third principle highlights the role of judicial decisions in shaping constitutional principles. Dicey argued that individual rights are not merely abstract declarations but are safeguarded by the judiciary through its interpretations and rulings. Courts play a crucial role in upholding legal integrity, resolving disputes, and ensuring that government authorities act within the law. This principle ensures that the Rule of Law is not just a theoretical concept but a practical mechanism for protecting rights and maintaining legal order.

Together, these principles form the cornerstone of modern democratic governance, ensuring accountability, legal certainty, and protection of individual liberties against the arbitrary exercise of power.

Characteristics of the Rule of Law

The Rule of Law is a fundamental principle that ensures justice, fairness, and accountability in a legal system. Several essential characteristics define its framework and application:

- **Supremacy of Law:** The Rule of Law asserts that laws,

rather than the whims of individuals, must govern a nation. It prevents arbitrary decision-making by authorities and ensures that legal principles guide governance.

- **Equality Before Law:** This principle guarantees that all individuals, regardless of social, political, or economic status, are subject to the same laws. It prohibits discrimination and ensures uniform application of legal provisions.
- **Legal Accountability:** No one can be punished or prosecuted unless they have violated a duly established law. Any accusation must be supported by evidence and adjudicated through proper legal procedures.
- **Protection from Arbitrary Power:** The Rule of Law serves as a safeguard against government overreach, ensuring that state actions remain within the boundaries of legality. It prevents the misuse of power and protects individual rights.
- **Judicial Independence:** An impartial and autonomous judiciary is essential to upholding the Rule of Law. Judges must operate free from political or external pressures to ensure fair and just legal outcomes.
- **Adherence to Legal Procedures:** Government actions and policies must conform to established legal frameworks, ensuring transparency, consistency, and due process.
- **Principle of Natural Justice:** Legal proceedings must adhere to fairness, impartiality, and procedural correctness, guaranteeing due process and the right to be heard.
- **Democratic Foundation:** The Rule of Law forms the backbone of democratic societies, ensuring governance is based on legality, accountability, and the protection of fundamental rights.

Rule of Law Under the Indian Constitution

Although the Indian Constitution does not explicitly mention the term "Rule of Law," its fundamental principles are deeply embedded within various constitutional provisions. These provisions ensure that governance is based on legality, fairness, and constitutional supremacy.

- Judicial Review: The judiciary plays a crucial role in upholding

the Rule of Law through its power of judicial review. Articles 13, 32, 136, 142, and 226 empower courts to strike down any law or executive action that violates constitutional principles. This ensures that all laws and policies adhere to the constitutional framework and prevents arbitrary use of power.

- Constitutional Consistency: In India, all laws enacted by the Central or State Governments must conform to constitutional mandates. Any law found to be inconsistent with the Constitution is declared void under Article 13. This maintains legal supremacy and prevents legislative or executive excesses.
- Preamble: The Indian Constitution's Preamble upholds justice—social, economic, and political—along with liberty and equality. These values form the foundation of the Rule of Law, ensuring that governance aligns with democratic and legal principles.
- Article 21 (Right to Life and Personal Liberty): One of the most significant guarantees under the Indian Constitution, Article 21 ensures that no individual can be deprived of life or personal liberty except by procedure established by law. This provision reinforces due process and safeguards against arbitrary state actions.
- Article 14 (Equality Before Law): This article embodies Dicey's principle of equality, guaranteeing that all individuals are treated equally under the law and receive equal protection. It prohibits discrimination and ensures fair legal treatment for every citizen.

Together, these provisions establish the Rule of Law as an essential doctrine in India, ensuring constitutional governance, protecting fundamental rights, and preventing the misuse of power by any authority.

Exceptions to the Rule of Law in India

While the Rule of Law is a fundamental principle in India's legal system, certain provisions allow exceptions for practical governance, executive functions, and diplomatic considerations. These exceptions do not undermine the Rule of Law but provide necessary flexibility for effective administration.

1. Discretionary Powers of the President and Governor

The Indian Constitution grants discretionary powers to the President and Governors, which allow deviations from strict legal uniformity:

- **Articles 72 and 161:** The President and Governors have the power to grant pardons, reprieves, respites, or remissions of punishment. This discretionary power serves as a check against judicial errors and provides relief in exceptional cases.
- **Article 85:** The President has the discretion to summon, prorogue, or dissolve Parliament, ensuring smooth legislative functioning.
- **Articles 200 and 356:** The Governor can reserve certain bills for the President's consideration and report to the President about the failure of constitutional machinery in a state, potentially leading to President's Rule.

2. Immunity for the President and Governor

To ensure smooth governance, the President and Governors enjoy legal immunity under the Constitution:

- They are not answerable in a court of law for acts performed in their official capacity.
- Criminal proceedings cannot be initiated against them while they hold office.
- Civil proceedings require a two-month prior notice before they can be instituted. These provisions prevent frivolous litigation from hindering executive functions.

3. Police Discretion

Law enforcement agencies are granted certain discretionary powers for maintaining law and order:

- **Arrest without a warrant:** Under the Code of Criminal Procedure (CrPC), police officers can arrest individuals without prior judicial approval for cognizable offenses. This enables swift action in cases of severe crimes.

4. Public Servant Immunities

- Government officials, administrative officers, and municipal authorities enjoy certain legal immunities to facilitate

governance. Actions performed in good faith during official duties often receive legal protection from personal liability.

5. Judicial Discretion

- Courts in India exercise discretion in interpreting laws and sentencing. Judges consider various factors such as mitigating circumstances, offender rehabilitation, and social impact while determining punishments.

6. Diplomatic Immunities

- **Under international law, foreign diplomats and officials enjoy immunity** from local jurisdiction, preventing them from being prosecuted under Indian law. This ensures smooth diplomatic relations and adherence to international treaties.

These exceptions are designed to balance governance efficiency, justice, and constitutional principles, ensuring that while the Rule of Law prevails, practical considerations are also accounted for.

Some of Important Judicial Pronouncements on the Rule of Law

The Supreme Court of India has played a pivotal role in upholding and interpreting the Rule of Law through landmark judgments. These decisions have reinforced legal principles and strengthened constitutional governance.

1. Indira Gandhi v. Raj Narain (1975)

- The Supreme Court ruled that the Rule of Law is enshrined in Article 14 and forms an essential part of the 'Basic Structure' of the Constitution.
- It struck down the 39th Constitutional Amendment, which sought to place the election of the Prime Minister beyond judicial review.

2. ADM Jabalpur v. Shivkant Shukla (1976) (Habeas Corpus Case)

- The majority ruling denied the existence of any Rule of Law beyond Article 21.

- However, Justice H.R. Khanna's famous dissenting opinion asserted that no authority, even in the absence of Article 21, could arbitrarily deprive individuals of their liberty. This dissent later influenced the overruling of the judgment in later cases.

3. Maneka Gandhi v. Union of India (1978)

- This case expanded the interpretation of Article 21, mandating that the procedure established by law must be fair, just, and reasonable.
- It established a strong interrelation between Articles 14, 19, and 21, reinforcing due process and procedural fairness.

4. Som Raj v. State of Haryana (1990)

- The Supreme Court declared that the absence of arbitrary power is fundamental to the Rule of Law.
- It emphasized that discretionary power must be exercised based on fair and transparent criteria.

5. Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973)

- This landmark case introduced the 'Basic Structure Doctrine,' affirming that the Rule of Law is an integral part of the Constitution's unamendable framework.

Recent Judicial Pronouncements Strengthening the Rule of Law

6. I.R. Coelho v. State of Tamil Nadu (2007)

- The Supreme Court ruled that laws placed under the Ninth Schedule of the Constitution could still be subject to judicial review if they violated the Basic Structure, including the Rule of Law.

7. Shayara Bano v. Union of India (2017) (Triple Talaq Case)

- The Court struck down instant triple talaq as unconstitutional, reinforcing that arbitrary practices have no place under the Rule of Law.

8. Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) v. Union of India (2017) (Right to Privacy Case)

- The Court declared the Right to Privacy a fundamental right

under Article 21, reinforcing individual liberty as a key aspect of the Rule of Law.

9. Navtej Singh Johar V. Union of India (2018) (Section 377 Case)

- The Court decriminalized homosexuality, holding that criminalizing consensual same-sex relations was arbitrary and violated the fundamental principles of equality and dignity under the Rule of Law.

10. Joseph Shine V. Union of India (2018) (Adultery Case)

- The Court struck down Section 497 IPC (criminalization of adultery), ruling that it violated individual autonomy and the Rule of Law by discriminating on the basis of gender.

11. Anuradha Bhasin v. Union of India (2020) (Internet Shutdown Case)

- The Supreme Court ruled that access to the internet is a fundamental right under Article 19, and restrictions must be justified under the principles of reasonableness and necessity.

12. Foundation for Media Professionals v. Union Territory of J&K (2020)

- The Court held that indefinite internet shutdowns violate the principles of proportionality and the Rule of Law.

13. Arnab Ranjan Goswami v. State of Maharashtra (2020)

- Reiterated the importance of personal liberty and due process, ruling that arbitrary arrests violate the Rule of Law.

14. State of Jharkhand V. Anuj Kumar (2022)

- The Court emphasized that arbitrary government actions cannot be justified and that fairness in administrative decisions is central to the Rule of Law.

15. Kaushal Kishor V. State of Uttar Pradesh (2023)

- The Court ruled that fundamental rights can be enforced against private entities when public functions are involved, expanding the application of the Rule of Law.

These judgments demonstrate the evolving and dynamic nature

of the Rule of Law in India, ensuring that governance remains constitutional, fair, and just.

Conclusion

The Rule of Law serves as the foundation of a democratic society, ensuring that governance is based on established legal principles rather than arbitrary decisions. It upholds the supremacy of law, equality before the law, and fairness in judicial processes, making it indispensable to justice and democratic governance. While the Indian Constitution does not explicitly mention the term "Rule of Law," its essence is deeply embedded within various constitutional provisions, including Articles 14, 19, and 21. These articles safeguard fundamental rights and prevent any form of governmental overreach.

The judiciary plays a pivotal role in interpreting and enforcing the Rule of Law. Landmark judicial pronouncements, such as Kesavananda Bharati v. State of Kerala and Maneka Gandhi v. Union of India, have reinforced the doctrine by ensuring that laws and government actions conform to constitutional principles. The courts act as the ultimate safeguard against the abuse of power by upholding due process, judicial review, and fundamental rights.

However, the Rule of Law is not absolute in India. Certain exceptions, such as discretionary powers of the President and Governor, judicial discretion, and diplomatic immunities, exist to facilitate governance and maintain administrative efficiency. These exceptions, however, must not be misused to justify arbitrary or authoritarian rule.

In contemporary times, challenges such as judicial delays, executive overreach, and misuse of laws threaten the effective implementation of the Rule of Law. The increasing use of preventive detention, internet restrictions, and curbs on free speech raise concerns about maintaining the delicate balance between state authority and individual rights. Therefore, continuous judicial vigilance and legal reforms are necessary to prevent any erosion of this doctrine.

Ultimately, a strong, independent judiciary remains crucial in safeguarding the Rule of Law. By ensuring accountability, transparency, and justice, the Rule of Law preserves democratic

values, protects individual freedoms, and strengthens the very fabric of constitutional governance in India. It is imperative that all organs of the state uphold this principle to foster a just and equitable society.

Reference

1. Austin, G. (1999). Working a democratic constitution: The Indian experience. Oxford University Press.
2. Singhvi, L. M. (2002). Democracy and rule of law. Ocean Books.
3. Sathe, S. P. (2002). Judicial activism in India: Transgressing borders and enforcing limits. Oxford University Press.
4. Menon, N. R. M. (2004). Rule of law in a free society. Oxford University Press.
5. Mehta, P. B. (2007). The burden of democracy. Penguin Books India.
6. Baxi, U. (2008). The future of human rights. Oxford University Press.
7. Krishnaswamy, S. (2010). Democracy and constitutionalism in India: A study of the basic structure doctrine. Oxford University Press.
8. Kejriwal, A. (2012). Swaraj. HarperCollins India.
9. Bhatia, G. (2016). Offend, shock, or disturb: Free speech under the Indian Constitution. Oxford University Press.
10. Choudhry, S., Khosla, M., & Mehta, P. B. (Eds.). (2016). The Oxford handbook of the Indian Constitution. Oxford University Press.
11. Nariman, F. S. (2017). God save the Hon'ble Supreme Court. Hay House India.
12. Reddy, K. (2018). The Constitution of India: A contextual analysis. Bloomsbury Publishing.
13. Jayal, N. G. (2019). Re-forming India: The nation today. Penguin Random House India.
14. Kapur, D., & Khosla, M. (Eds.). (2019). Regulation in India: Design, capacity, performance. Bloomsbury Publishing.
15. Khosla, M. (2020). India's founding moment: The constitution of a most surprising democracy. Harvard University Press.

16. Roy, T., & Swamy, A. V. (2020). Law and the economy in a young democracy: India 1947 and beyond. University of Chicago Press.
17. Chandrachud, A. (2020). Republic of rhetoric: Free speech and the Constitution of India. Penguin Random House India.
18. Sikri, A. K. (2021). Constitutionalism and the rule of law: In a theatre of democracy. Eastern Book Company.
19. Devy, G. N. (2024). The question of language: Linguistic diversity and democracy in India. Context Publishing.
20. Rege, D. (2024). Quarterlife. HarperCollins India.

Dr. Ashok Kumar Karnani
Associate Professor, Faculty of Law, and Arts, RNB Global University, Bikaner
ashok.karnani@rnbglobal.edu.in

❑ ❑ ❑

Laws On Bail in India : A Comparative and Analytical Study with Special Reference to New Criminal Laws

Rekha Acharya • Dr. Malika Parvin

"The issue of bail is one of liberty, justice, public safety and burden of the public treasury, all of which insist that a developed jurisprudence of bail is integral to a socially sensitized judicial process".

– ***Justice V.R. Krishna Iyer***

This paper investigates the complicated jurisprudence surrounding bail in India, focusing on variables affecting bail judgments, judicial discretion, and legislative measures. It employs a comparative method to examine historic decisions and legislative provisions in order to find patterns, discrepancies, and opportunities for change. The research also looks at the balance between individual liberty and society interests, taking into account aspects including crime type, evidentiary probability, and presumption of innocence. It also looks at the issues courts encounter while using bail discretion, such as judicial activism and constraint. The research intends to add to the discussion of bail jurisprudence by providing insights on how to improve openness, justice, and consistency in bail rulings.

Keywords *: jurisprudence, bail, judgments, judicial discretion, legislative measures, individual liberty and society interests.*

Introduction

Bail is a crucial legal procedure that permits the temporary release of an accused individual from police or court custody. The Indian judicial system uses bail to prevent the accused person's illegal

detention during the judicial process and to ensure their appearance at investigations and hearings.Bail is a conditional release of an accused individual for a promised sum subject to court attendance. In civil proceedings, getting bail is a privilege of the accused; in criminal situations, it is the bail-granting authority's discretion. Modern bail is said to have originated in medieval England's circuit courts, which instituted bail. Judges flew around the nation to solve horrific jail conditions, which resulted in several deaths and diseases.The law of bail, like other legal disciplines, has its underlying principles and has a significant position in the execution of equitable justice. The principle of bail is of utmost importance in any legal system. It exists to balance competing interests, namely the accused's presumption of innocence and the state's interest in public order and the integrity of the inquiry.

The definition of bail:

Bail is basically when someone who has been jailed is freed on the condition that their sureties promise to show up at the time and place set by the court that issued the bail. Halsbury's Laws of England define criminal bail as bail given to an accused or convicted individual. "Granting bail does not set the defendant (accused) free; rather, it frees him from the custody of the law and places him in the care of his sureties, who are required to bring him to his trial at a certain time and place." Sureties possess the authority to apprehend their principal at any time, deposit him into the custody of the law, and then incarcerate him.

- In Black's Law Dictionary, bail has been defined as "a security such as cash or bond especially security required by a court for the release of a prisoner who must appear at a future date."
- The law lexicon defined, "bail as the security for the appearance of the accused person on giving which he is released pending trial or investigation".
- Webster's Law Dictionary defined "Bail, a temporary release of a person in exchange for security given for the prisoner's appearance at a later hearing".
- Justice William Blackstone defined it as "a delivery or bailment of a person to his sureties on their giving, together

with himself, sufficient security for his appearance, he being supposed to continue in their friendly custody instead of going to jail". Thus, when a person is released on bail, the person will be produced by him before the court when so required. The person who is released on bail is also usually asked to execute a bond for his appearance at a later stage of the proceeding.Bail literally means the temporary release of a person on certain conditions until the trial is over. In this scenario, the court releases the accused individual in return for a specific sum of money, known as the bail amount, which they must deposit with the court.

- Indian law relies on the Constitution for bail.

Only the law can take away the right to life and personal liberty, as guaranteed by Article 21 of the Indian Constitution. This article provides a constitutional basis for the right to bail. During the judicial process, bail protects the accused's liberty.

- The Code of Criminal Procedure, 1973, defines bail.

The Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) provides detailed provisions for bail. The Code discusses various types of bail, such as provisions for bailable offenses and non-bailable offenses.

A Comparative Analysis of Bail Worldwide

Conducting a comparative study of bail law is crucial, as it aids in comprehending the similarities and differences among various judicial systems. This study will highlight the difference between the bail system of Indian law and other countries.

Bail system in United States of America (USA):

The "Bail Bond" is the basis for the US bail system. The purpose of this bail process is to guarantee the accused individual's attendance at the hearing.In the United States, the court determines the amount of bail based on the severity of the offense and the accused's criminal history. Often, the court sets very high bail amounts, which they may also pay through a bail bondsman.Although the judge has the final say in this matter, the U.S. Constitution grants the accused the right to release on bail.If the court is confident that the accused will appear at the hearing, it may release them without charge in

some cases where bail amounts are excessive, a process known as "release on own recognition."

Bail system in United Kingdom (UK):

The bail process in the United Kingdom is well developed and structured.The Criminal Justice Act of 2003 grants the accused the right to bail, but judicial discretion also plays a significant role. Conditions are often imposed on bail, such as surrendering a passport, residing at a fixed place, etc.In certain serious crimes, where the accused is suspected of threatening witnesses or absconding, bail may be refused.

Bail system in Australia:

The bail system in Australia varies depending on the states and territories, but overall, it is similar to the Indian system.Time of conviction: In Australia, the accused's right to bail starts after their conviction, not just after their arrest.Australian courts can make bail conditions stringent, particularly when the offense is serious. Favorable Conditions: Courts must respect the accused's rights and grant bail leniently in appropriate cases.

Bail system in Canada:

In Canada, bail is referred to as "Judicial Interim Release." The bail process here involves the courts assessing the nature of the accused's crime and the danger associated with it.Achievable Bail: According to Canadian law, the accused can usually get bail, unless the crime is extremely serious.Conditions and Guarantees: The accused has to fulfil conditions in the court to get bail, the accused must fulfil court conditions, such as residence at a fixed place, regular attendance at the police station, etc.

Bail system in Germany:

Germany's bail provision differs from the Indian system, which applies the concept of bail in a relatively limited manner. Compulsory Arrest: In Germany, the court considers it necessary to detain the accused when the need for bail arises.Germany's bail conditions place more emphasis on the accused's conduct and cooperation than on cash bail.The German system prioritizes the

accused's freedom and grants bail when it prevents them from participating in the judicial process.

Bail system in India:

The Indian Criminal Procedure Code (CrPC), 1973, provides bail in India. The IndianCrPC, 1973, divides bail into bailable and nonbailable offenses. If the accused applies for bail, the court considers the severity of the offense, the accused's conduct, the possibility of absconding, etc.There are many similarities and differences between the Indian bail system and the bail systems of other countries. While countries like India, Canada, and the UK emphasize bail and make decisions based on judicial discretion, the conditions and procedures for bail in the US and Australia can be a little more stringent. Germany's system emphasizes personal liberty, and there is less reliance on cash for bail. This comparative study highlights the fact that the bail system evolves according to the judicial and social structure of each country. Every country aims to balance the accused's liberty and justice through bail.

Historical Background and Genesis of Bail

Modern bail is said to have originated in medieval England's circuit courts, which instituted bail. Judges flew around the nation to solve horrific jail conditions, which resulted in several deaths and diseases.Bail bonds originated with Plato's effort to release Socrates in 399 BC. Medieval British circuit courts developed a bail system; current bail originated with medieval legislation. This resulted in an inhabitable environment known as "prisons," which led to the creation of the Magna Carta, the Statue of Westminster, and other following laws. King John signed the Magna Carta in 1215. It said that the king had to follow the law and listed the rights of "free men." The Statute of Westminster, which was enacted in 1275, stipulated that crimes should be classified as either bailable or non-bailable charges. This created the fundamental structure that judges and authorities must adhere to when making judgments about bail cases. The Habeas Corpus Act 1679 was enacted to eliminate unduly lengthy periods between incarceration and bail hearings, while the Bill of Rights 1689 established a notion of proportionality in bail, serving as a forerunner of the Eighth Amendment to the United States Constitution.

The last significant bail law change before the contemporary system was the Bail Act 1898, which permitted courts to waive sureties where bail would impede justice. This mostly helped impoverished offenders who would otherwise remain in prison for minor offenses due to a lack of ability to pay bail.Bail bonds originated with Plato's effort to release Socrates in 399 BC. Medieval British circuit courts developed a bail system; current bail originated with medieval legislation. Bail was also common in ancient India, with the Mughals using 'Muchalaka' and 'Zamanat' in the 17th century. The Code of Criminal Procedure, 1973 controls bail, with bailable and non-bailable crimes outlined in Section 2(a). Bail requirements under the Act are governed under Section 436-450.

Types of bail

- Interim Bail: Usually granted for a limited period of time, it serves as a temporary relief when regular bail is being considered for an accused individual.
- Section 438, Anticipatory Bail, allows a person who fears arrest for a non-bailable offense to apply for anticipatory bail. Even before making the arrest, the police can grant this bail.
- Regular Bail: The magistrate or sessions court grants this to a person who is already in police or judicial custody and seeks release during the trial's pendency. The magistrate or sessions court holds the power to Sections 437 and 439 of the CrPC.
- Under Section 167(2) of the CrPC, if the investigation is not completed within a specified period (60 days for offenses punishable with less than 10 years imprisonment and 90 days for offenses punishable with 10 years or more), the accused becomes entitled to bail by default.

Constitution and Concept of Bail

This study delves into bail jurisprudence, emphasizing its status as a court-recognized right and a matter subject to judicial discretion. In Article 22(1) of the Constitution, no person in custody should be denied the right to consult and be represented by a legal practitioner of their choice. The accused must know their right to bail. However, the investigation must determine whether this clause encompasses the right to state-funded legal practitioner services,

particularly in light of Article 39A of the Constitution, which requires the state to offer free legal assistance. The right to bail is consistent with the constitutional structure of criminal justice contained in Articles 20, 21, and 22 of the Constitution.

Balancing the Constitution's bestowed human rights on the accused against the rising crime rate and the need to protect society from offenders is critical. The paper discusses the transition in the criminal justice system from the presumption of innocence to the presumption of guilt, its impact on pretrial procedures, and the implications of incorporating Section 167 of the Cr.P.C. concerning bail and its relationship to Article 21 of the Constitution's mandated temporary loss of liberty.

Relevance of Bail Jurisprudence in the Indian Legal Framework

- Bail jurisprudence is crucial in the Indian legal system, as it upholds the principle of presumed innocence until proven guilty. It allows accused individuals to await trial without undue deprivation of liberty, reinforcing the presumption of innocence. Bail jurisprudence also protects individuals' constitutional rights, including liberty and due process, promoting fairness and justice in the legal process.

- Judicial discretion in granting bail is exercised by courts, reflecting their role as guardians of constitutional values. This discretion is based on factors such as the nature of the offense, the likelihood of absconding, the accused's criminal record, and the interests of victims and society. Bail jurisprudence prevents unnecessary incarceration of individuals who pose no flight risk or danger to society while awaiting trial.

- Bail jurisprudence enhances the efficiency of the legal system by permitting the release of the accused on bail, reducing overcrowding in prisons, minimizing delays in trial proceedings, and enabling defendants to participate effectively in their defense. Judges exercise their discretion judiciously, considering various factors such as the nature and gravity of the offense, evidence and prima facie case, flight risk and absconding, criminal history and recidivism, victim's rights and public safety, and special circumstances.

- The first portion of the first Schedule to the Cr.P.C. classifies every offense under the Indian Penal Code as bailable or nonbailable, determining which offenses are bailable and which are not. If the parent Act does not provide such a statement, the basic guidelines set forth in the second part of the first Schedule of the Cr.P.C. must be used to determine whether the crime falls into the appropriate category.
- Accused who has been granted bail need not to appear before the court till the charge sheet is filed and process is issued.
- Bar to grant of anticipatory bail: Section 18 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act bars anticipatory bail for the offences committed under the said Act. However, if the prima facie case is not made out under the provision of the Atrocities Act, then there is no bar to grant of anticipatory bail.

Bail under New Criminal Law (The Bharatiya Nagarik Suraksha (Second) Sanhita, 2023)

The Bill of Supervision and Suspension of Policies is a law that may expand the powers of the police in India. The new Act governs the police's powers to maintain public order, prevent crimes, and conduct criminal investigations. These powers include arrests, detention, search, seizure, and use of force. However, these powers are subject to restrictions to prevent excessive use of force, illegal detentions, custodial torture, and abuse of authority.The BNSS amends the provisions related to detention, police custody, and the use of handcuffs, which may present certain issues. The Constitution and CrPC prohibit detention in police custody beyond 24 hours, but the BNSS modifies this procedure by allowing for the authorization of 15-day police custody within the initial 40 or 60 days of the 60 or 90-day period. If the police argue that they need to take the person back into police custody during this period, they could deny bail.

The BNSS allows handcuffs to be used during arrest, but only for habitual or repeat offender who has escaped custody or a person who has committed offenses such as rape, acid attack, organized crime, drug-related crime, or offense against the state. This provision contravenes the Supreme Court's judgments and the

National Human Rights Commission's guidelines. The Supreme Court has held that the use of handcuffs is inhumane, unreasonable, arbitrary, and repugnant to Article 21. In extreme cases, the escorting authority must record the reasons for using handcuffs and requires judicial consent before handcuffing any prisoners undergoing trial. The scope of mandatory bail in cases of multiple charges is limited. The CrPC mandates the release of an undertrial on a personal bond if they have served half the maximum imprisonment for an offense. The BNSS retains this provision and adds that first-time offenders get bail after serving one-third of the maximum sentence. However, it does not apply to offenses punishable by life imprisonment, or where an investigation, inquiry, or trial is pending in more than one offense or in multiple cases.

Plea bargaining, an agreement between defence and prosecution in which the accused pleads guilty to a lesser offense or a reduced sentence, may be limited. The BNSS retains this provision, restricting plea bargaining in India to sentence bargaining, i.e., getting a lighter sentence in exchange for the accused's guilty plea. Additionally, the BNSS includes a requirement that the accused file an application for plea bargaining within 30 days of the charge's framing, which may impact the effectiveness of plea bargaining by limiting the opportunity for seeking a reduced sentence.

Bail And Major Principles in The Indian Judicial System

There are some major principles in the Indian judicial system that ensure that there is a balance in the justice process when it comes to granting bail. These principles help the courts to maintain a proper balance between the personal liberty of the accused and the interests of society.

- The Bail Principle: Bail is the rule; jail is an exception. This principle is the most important in the Indian judicial system. This principle dictates that releasing the accused on bail should be the standard procedure, with custody reserved for exceptional circumstances. In numerous cases, the Supreme Court has reaffirmed that the accused should receive bail unless there are serious grounds against him.
- The right to personal liberty Article 21 of the Indian Constitution guarantees the right to life and personal liberty.

In the matter of bail, the court is required to respect this right. The judicial process cannot unnecessarily detain anyone.

- While granting bail, the court takes into account the possibility of the accused absconding. If the possibility of the accused absconding is high, bail is hesitant. The analysis takes into account the accused's social, economic, and family background.
- The possibility of tampering with evidence If there is a suspicion that the accused may tamper with evidence or influence witnesses after being released on bail, bail may be denied. This is particularly relevant in cases of serious crimes.
- The severity of the offense also influences the decision to grant bail. When granting bail for extremely serious crimes like murder, rape, or treason, the court exercises extreme caution. In serious crimes, the court does not grant bail unless it is confident that the accused will not obstruct the justice process.
- The court also takes into account the likelihood of the accused's conviction. Prima facie, if the accused seems less likely to face a conviction, the likelihood of granting bail increases.
- Public Peace and Security The court also sees that releasing the accused on bail should not have any adverse effect on public peace and security. The court can deny bail if the accused's release is likely to cause social unrest.
- The accused's conduct the accused's conduct, such as his previous criminal record, plays an important role in determining his bail application. If the accused's behavior has been suspicious before, the court will be cautious in granting bail.
- Principle of Parity In cases where there is more than one accused and one has already gotten bail, the court also adopts the principle of equality for the other accused. This implies that the court should grant similar bail in comparable circumstances.
- Judicial Discretion Ultimately, the decision to grant or not to grant bail depends on the discretion of the court. The court

must decide after taking into account all pertinent factors to uphold justice and protect the accused's rights.

The principles regarding bail serve as a guide for the Indian judiciary. The court adheres to these principles to maintain a balance between the accused's liberty and the safety of society. The purpose of bail is not only to temporarily release the accused but also to ensure that he is available to face the judicial process.

Bail Provisions and Legal Interpretations in India

- The Code of Criminal Procedure, 1861, 1872, and 1898 introduced bail provisions.
- The first three codes included sections 216, 258 and 156 and 212, and sections 128 and 389.
- The 1898 code preserved the distinction between bailable and non-bailable situations.
- Bail granting is based on the seriousness of the charge, the nature of the evidence, and the severity of the prescribed punishment.
- Most penal laws in India allow for the highest sentence a criminal court can impose, with a few offenses allowing for a minimum punishment.
- The court must apply the principle of proportionality in prescribing liability based on the culpability of each type of criminal conduct.
- Section 354(4) of the Criminal Procedure Code of 1973 limits the court's discretionary jurisdiction to impose a sentence of at least three months in circumstances where the offense carries a one-year or more term.

Conclusion & Suggestions

This research compares and contrasts bail laws globally, with a particular focus on India. Bail is the act of releasing a convicted person in exchange for a personal bond or guarantee that they will follow court regulations and attend court appearances. Bail promotes individual liberty and society's interests, but it has its challenges. Bailout defendants have more time to prepare their cases than remanded defendants do. Reducing imprisonment in locations

where the public does not fear disappearance is crucial to advance public justice. Courts must examine fairness, humanitarianism, and statutory requirements before rejecting bail. If judges believe the offender won't show up for trial or that bail would be detrimental to the public, they should let them out of jail. If bail is disproportionate to the public interest, they should stay in jail.India's bail laws aim to safeguard individuals' fundamental rights without compromising justice. However, the implementation of these laws faces challenges such as socio-economic disparities in access to bail, delays in the judicial process, and inconsistent application of principles across cases. Reforms are necessary to address these challenges, such as judicial training, expediting bail application hearings, and ensuring reasonable and accessible bail amounts. The judiciary must remain vigilant to prevent political or external influences from affecting bail decisions. In conclusion, while India's bail framework is robust, its effectiveness depends on consistent and fair application. The judiciary plays a crucial role in upholding the balance between individual rights and societal interests, and it must continue to evolve to meet the challenges of a dynamic society. Addressing existing shortcomings in the bail system is essential to upholding the right to liberty and maintaining the criminal justice system's fairness and justice.

Reference

Sushila Aggarwal vs State (NCTof Delhi), Air 2020 Supreme Court 831, Aironline 2020 Sc 74, (2020) 1 Crimes 225, (2020) 1 Ker Lt 545, (2020) 1 Raj Lw 373, (2020) 1 Reccrir 833, (2020) 266 Dlt 741, (2020) 2 Adj 322 (Sc), (2020) 2 Scale 772, (2020) 77 Ocr 845.

Black's Law Dictionary, 4th Edn., page 177, available at:https://thelawdictionary.org/

P Ramanatha Aiyar, The Law Lexicon–The Encyclopaedic Law Dictionary with Legal Maxims, Latin Terms, Words & Phrases, EDITION: 5th (2022).

Merriam-Webster's dictionary of law, Springfield, Mass.: Merriam-Webster (1996).

Sir William Blackstone (born July 10, 1723, London, England—died February 14, 1780, Wallingford, Oxfordshire) was an English jurist, whose Commentaries on the Laws of England, 4 vol.

(1765–69), is the best-known description of the doctrines of English law. The work became the basis of university legal education in England and North America. He was knighted in 1770.

Section 436: Deals with bail in bailable offenses., Section 437: Provides guidelines for granting bail in non-bailable offenses., Section 438: Provides for anticipatory bail, a provision to seek bail before arrest., Section 439: Deals with the High Court and Court of Session's power to grant bail, under Cr.P C, 1973.

Baughman, Shima B., The Bail Book: A Comprehensive Look at Bail in America's Criminal Justice System - Introduction, Cambridge University Press (2017).

Bail Act 1976, CHAPTER 63.

F. E. Devine, Bail in Australia, Australian Institute of Criminology, 1989.

See, Backgrounder – Bill C-48: Proposed Measures to strengthen Canada's bail system & Infographic: Bill C-48: Strengthening Canada's bail system to improve public safety.

William T. Braithwaite, An Introduction for Judges and Lawyers to Plato's Apology of Socrates, 25 Loy. U. Chi. L. J. 507 (1994). Available at: http://lawecommons.luc.edu/luclj/vol25/iss4/4. (Assessed on Aug. 30, 2024).

Clause 39 of Magna Carta reads as – "No free men shall be seized or imprisoned or stripped of his rights or possessions, or outlawed or exiled, or deprived of his standing in any other way, nor will we proceed with force against him, or send others to do so, except by the lawful judgement of his equals or by the law of the land".

Statute of Westminster, The First (1275) 1275 CHAPTER 5 3 Edw 1 The STATUTES of WESTMINSTER; The First, available at: https://www.legislation.gov.uk/aep/Edw1/3/5/data.pdf (Assessed on Aug. 30, 2024).

Habeas Corpus Act, 1679, available at: https://www.legislation.gov.uk/aep/Cha2/31/2/data.pdf. See also, Bill of Rights, 1688, available at: https://www.legislation.gov.uk/aep/WillandMarSess2/1/2/introduction.

William T. Braithwaite, An Introduction for Judges and Lawyers to Plato's Apology of Socrates, 25 Loy. U. Chi. L. J. 507 (1994).

Available at: http://lawecommons.luc.edu/luclj/vol25/iss4/4. (Assessed on Aug. 30, 2024).

William Irivine, Mughal India, Vol. 2, 198 (1907).

Provisions As to Bail and Bonds, Chapter XXXIII of Cr. PC. 1973.

Superintendent. And Remembrancer of Legal Affairs v. Amiya Kumar Roy Choudhry 1981 AIR 917, 1981 SCR (2) 661

Article 22 of the Constitution: (1) No person who is arrested shall be detained in custody without being informed, as soon as may be, of the grounds for such arrest nor shall he be denied the right to consult, and to be defended by, a legal practitioner of his choice.

(2) Every person who is arrested and detained in custody shall be produced before the nearest magistrate within a period of twenty-four hours of such arrest excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of the magistrate and no such person shall be detained in custody beyond the said period without the authority of a magistrate.

Maneka Gandhi vs Union of India, AIR 1978 SC 597,Satender Kumar Antil vs Central Bureau of Investigation, (2022) 10 SCC 51,P. Chidambaram V. Directorate of Enforcement (2020) 13 SCC 791,Mallada K. Sri Ram vs The State of Telangana,(2020) 13 SCC 632 13 18.,

Asim Pandey, Law of Practice and Procedure, Second Edition, 2015, Lexis Nexis.

United States of America 1789 (rev. 1992)". Available at: www.constituteproject.org. (last visited on Aug.30,2024).

Free Legal Aid Committee v. State of Bihar, 1982 Cr.L.J. 1943: 1982 AIR (SC) 1463.

Vilas Pandurang Pawar vs State of Maharashtra 2012 CRI.L.J. 4520 (SC).

Right of arrested person to meet an advocate of his choice during interrogation, Section 38 of THE BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023 NO. 46 OF 2023.

Report No. 247, 'the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita', Standing Committee on Home Affairs, November 10, 2023.

Section 59 of The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 No. 46 Of 2023.

Maneka Gandhi v. Union of India, Supreme Court, 1978 AIR 597.

Section 289-300, Chapter Xxiii of The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 No. 46 Of 2023.

D.D. Basu, Introduction to the Constitution of India, Publisher, Lexis Nexis, 23rd- Edition 2018.

The British introduced the concept of bail into India's legal system with the Code of Criminal Procedure (CrPC) in 1861. It was re-enacted in 1872 and 1898 to ensure uniform application to both Indian and British subjects. The CrPC outlines the legal status of bail in England and India, including provisions for bail in bailable offenses and anticipatory bail.

Code of Criminal Procedure, 1872. After the Rebellion of 1857, the crown took over the administration in India. The Indian Penal Code, 1861 was passed by the British parliament. The CrPC was created for the first time ever in 1882 and then amended in 1898, then according to the 41st Law Commission report in 1973.

Rekha Acharya
Assistant professor
Government Law P.G. college, Bikaner (Raj)

Dr. Malika Parvin
Assistant professor
Government Law P.G. college, Bikaner (Raj)

❑ ❑ ❑

Navigating Engendered Human Security In A Conflict Zone: Insights From Kashmir Through Cinema In The 21st Century

- **Dr. Vaishali Raghuvanshi**
- **Arti Devi**

Human security entails the security of individuals from violent and non-violent conflicts. It challenges the notion of traditional territorial security of states. The conceptualization of human security vis a vis state security has gained scholarly attention during thepost-cold war phase in international relations. The United Nations Development Programme (UNDP) in 1991 defined human security as freedom from fear and freedom from want. Thereexists no universal definition of human security as the threats which humans are facing is contingent upon numerous factors such as gender, age, political grievances, economic factors and also on the dwelling place of an individual, and these threats have changing nature in the conflict prone areas. Human security in conflict areas is multifaceted and threats and sufferings are disproportionate. When we observe the situation through gendered lens, far more serious consequences for marginalized section of the societycomes to fore. Women have always beenat the receiving end and are treated at lower steps of sccio-economic hierarchy. Theygo through the implications of both violent and non-violent conflicts at the hands of various agencies and structures partyin the conflict.The objective of the present paper is to understand the situation of human security in

a conflicting area of Kashmir in general and the dynamic interplay between human security and gender in particular. Stressing on the challenges and difficulties faced by women in the marginalized areas of Kashmir, the present paper will focus on examining the situation of threats and the various dimensions of human security that ranges from environmental, health, economic, personal, food, community, to political security in Kashmir. In the contemporary world, mass media and popular culture has emerged as an integral part of the individual's life in spreading information and awareness. The paper utilizes the popular instrument of mass media i.e. cinema to deconstruct the status of human security in Kashmir. The key objective of the paper is to examine the cinematic narratives portraying the status of human security of Kashmiri women as depicted in the two selected movies i.e. Shikara and Notebook.

Keywords : Human Security, Gender, Conflict, Kashmir, Cinema.

Introduction:

The concept of security entails the state of being free from any kind of threat, danger, menace, and attack, however, the concept of security has various dimensions viz; international security, national security, human security, environmental security among others (Kempen, 2013:2). Post cold war developments paved the way for broadening and deepening of security and encompasses socio-political, economic, and environmental concerns (ibid:229).

In the year 1994 UNDP published a report on human security titled 'Human Development Report (HDR) 1994: New Dimensions of human security' and it established seven kinds of threats to human security viz; food, environment, economic, health, personal, community and political threats (King and Murray, 2002:26) and is directed towards freedom from fear and freedom from want.

The present study takes the Kashmir issue as a case study where human rights are violated in a number of ways such as by applying various draconian laws to state especially after the late 1980s viz; The Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act, 1987, Jammu and Kashmir Disturbed Areas Act, 1990, Armed Forces (Jammu and Kashmir) Special Powers Act, 1990, and

various other laws which prevented the people of Kashmir to enjoy their basic human rights (Mohiuddin, 1997). And these laws have affected people differently.Women are the worst sufferer of the various threats viz, rape, domestic violence, mental illness, health issues, child abuse etc.The key questions to be probedare "What is the status of human security in relation to women?", What measures have been taken in Kashmir to ensure human security?" and "How cinematic narratives played a crucial role in depicting a popular narrative relating to human security in Kashmir?"With regards to representation of human security, cinema has a significant role, by representing the culture and by assigning the specific gender roles and by impacting the population significantly by generating a popular mindset about a conflict zone. The present study analyses two important Bollywood movies viz; Notebook and Shikharabased on Kashmir to find out the role of cinematic representation in engendering human security situation.

Conceptualizing En(gendered) Human Security in a Conflict Zone

The concept of human security started gaining attention in 1944 i.e. after the four-freedom speech of Franklin D. Roosevelt i.e. freedom of speech and expression, freedom of worship, freedom from want and freedom from fear but it gained momentum only in 1994 after the publication of the HDR 1994 titled "New dimensions of human security" by UNDP.Subsequent HDR 1995 "Gender and Human Development " was based on the theme of gender and claimed that if human development is not engendered, is endangered but it failed to deal with the gender issue in a comprehensive way. It failed to treat women as a special area of focus and did not recognize the fact that women's experiences and insecurities are different from men (Bjornberg, 2012:2). In the 2003 report of the UN Commission on Human Security at the National Council for Research on Women Annual Conference in May 2003, Sadako Ogata who was the co-chair of the commission stated that the commission intentionally chooses not to give any special place to women. But according to critics by not assigning any special attention to women the report fails to deal with the critical problems faced by women (Bjonberg, 2012: 2). Another issue attached with the notion of human security is that it is generally believed that it is a gender-neutral concept but in reality, it is not so because it is patriarchal in nature and all the

concepts associated with the human security itself is gendered viz; peace, peacekeeping, violence, war, militarization and soldiering (Tripp, 2013:10).

According to a report issued by UN Women.org approximately 48,800 females were murdered by their intimate partners and family members globally. Every hour about 5 female are killed by their family members and the shocking revelation is that only less than 40% of the female victims of gender-based violence and violence against women seek any kind of help(ibid.). This datareveals the vulnerability of women and the dire need of allocating women a special place in the premises of human security.

In a situation of conflict,the focus is on traditional security i.e. on the military aspect of securitythat focuses on state rather than an individual. To be specific women face gender-based violence, issues of displacement and migration, financial burden, physical and psychological issues and the wrath of exclusion and marginalization in many aspects.

As per reports issued by the organizations of various countries it is estimated that about 30% of the females face physical and sexual violence at the hands of their intimate and non-intimate partners (Thobejane, 2018:51). In case of Africa about 52.5% of female workers are facing sexual violence at workplaces in Nigeria and 37.7% are facing physical violence while 31.9% are becoming victim of psychological violence (ibid.). In case of Syria, government and pro-government militias are sexually assaulting and raping women. According to the United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR,2014) the trends are increasing in gender-based violence after the civil conflict of 2011 in Syria (Tenaw, 2017:122). Also, a common trend in Syria during conflict is that women are taken as hostages to create pressure for the release of prisoners in their exchanges. In such conditions women often become victims of various kinds of gender-based violence and in some cases, they even lose their life (ibid.). There is an increase in mortality and malnutrition rates for women and newborn children, and as per report of UN Women 60% of preventable maternal deaths occur in situations of conflict and displacement and one out of every 5 refugee or displaced women in humanitarian situations suffer sexual violence.

Engendered Human Security in Kashmir

Kashmir is a disputed territory between the nuclear states of India and Pakistan and is one of the highly militarized areas of the world which is creating challenges for the human security in Kashmir. Militarization is leading to increased human right violations, inflation, breakdown of administration, educational backwardness and police brutality in Kashmir (Rather, 2017:45). This section presents an analysis of status of human security of women which is depicted through seven dimensions of human security as prescribed in the HDR 1994.

Source : https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

(1) **Economic Security :** The parameters of economic security are employment opportunities, job security, income equality and ability to fulfill basic needs.Challenges arising in the conflict zones pertaining to economic security are unemployment, economic burden, low literacy rate, lack of opportunities etc. And these issues are prevalent in Jammu and Kashmir as well where the literacy rate as per 2011 census is 67.16% which is quite low than the national average of 73%. Out of the total 67.16% male literacy rate is 76.75% while that of female is

56.43% . The huge difference between the 76.75% and 56.43% literacy rate is showing the gender-based violence and the other issues which women are facing in Kashmir. Also, as per International Labour Organization (ILO) Employment Report of 2024; accessed by the Kashmiriyat , the unemployment rate between the youth, especially among the educated youth, is increasing over the years. Between the age group of 15-29 years it was 21.80% in 2005 which rose to 34.80% in 2022. For male youth it went up from 17.6% in 2005 to 25.86% in 2022 while for females from 40.32% to 57.4% within the same period (ibid.).

(2) **Food Security:** The Food and agriculture organization (FAO) in 1996 defined food security as a condition in which one is able to meet their nutritional requirement at the proper time. As per FAO, women of Africa, Asia, and Latin America are facing higher threats than men (Aziz et.al, 2021). In Kashmir food insecurity is a common threat which is faced by the majority ofthe population. Generally, two types of food crisis are faced by Kashmiris viz; apikaal and drag (Mehraan, 2015). Apikaal or subsistence crisis is the frequent almost annual food shortage faced by Kashmiris during the spring and early month of summer because at that time all the food stocks are on the verge of end. The second one is the drag or qahat or famine crisis which occurred occasionally because of crop failures, drought or by flood (ibid.). Food insecurities disproportionately affect women because of various social, economic and cultural factors (Singh, 2024).

(3) **Health security :** The health infrastructure is very poor in Kashmir and access to it is even more difficult because of various factors such as weather particularly in the winter months when connectivity gets disrupted because of heavy snowfall. Also, heavy militarization, curfew, measures adopted by the state machinery to curb the people's protest, among other factors leads to health insecurity. In Kashmir the condition of mental health is even worse than physical health particularly in women. As per health experts, heavy militarization and mass arrests of civilians is creating traumas and anxiety especially in women and children. Médecins Sans Frontières; Doctors without Borders conducted a survey in 2015 according to which 50% of women (37% men) suffered

from depression, 36% of women (21% men) had an anxiety disorder and 22% of women (18% men) suffer from post-traumatic stress disorder.

(4) **Environmental security:** Loss of biodiversity, water pollution, shrinking of water bodies, air pollution are some of the common phenomena in Kashmir. The impact of climate change was very much visible in Kashmir in the year 2024 because of the driest and warmest January in 2024 in the last 43 years. Prevalent environmental threats increase women's vulnerability to gender-based discrimination, impact their social and psychological well-being and lead to their marginalization.

(5) **Personal security :** As per the parameters of personal security women in Kashmir become victims to almost all the possible threats to personal security. In fact, it is the personal security and individuality of the women which is compromised largely because women are always treated as a mother, wife, and daughter and their individuality is always sacrificed against their gender roles.

(6) Community security : Any conflict whether it is interstate or intrastate increases the vulnerabilities of women and exposes them to gender-based violence, issues of displacement.

(7) Political security : Human right violation is very common in Kashmir especially because of the laws like Arms Forces Special Power Actsand also because of the various skirmishes and tensions which often occur in Kashmir.

Understanding Engendered Human Security through cinematic narratives in Kashmir

Popular Culture in general and cinema in particular profoundly impacts the socialization and mobilization of masses. Cinema, by exposing masses to numerous ideas and traditions shapes their behavior and attitudes which consequently impact their social expectations (Chawla, 2024). This section analysescinematic narratives representing the gendered aspect of human security in kashmir. Movies taken for the purpose of the study are Notebook (2019)and Shikara(2020). Notebook shows how education or any other developmental activity is highly ignored in a conflict area and how this has impacted woman's life. It is also depicted that

all the crucial parameters of human security are undervalued in Kashmir. Another movie Shikara is based against the backdrop of mass exodus of Kashmiri Pandits and its one the main protagonist is female. It depicts how human security specifically of women is being affected in such abnormal situations.

Notebook (2019)

Notebook is a 2019 Bollywood movie directed by Nitin Kakkar and it stars Pranat Bahl (female lead) and Zaheer Iqbal (male lead). Kabir/Zaheer, a Kashmiri Pandit refugee returned to Kashmir and joined as a teacher in Wular Public School, situated in the Wular lake, his late father's school, in order to prevent it from closure. But the condition of the school was very pathetic and even the basic amenities were inaccessible there; no drinking water, no fuel for cooking, no connectivity and also there was no network in that area. The school was attended by 5-7 students from the locality. There Kabir finds the diary of the ex- female teacher, Firdaus and after reading it day by day, falls in love with her. Later Firdaus by her choice re-joined the school and at that time Kabir was on a break. She saw her diary in which now Kabir has started writing about his daily experiences and also expressed his feelings for Firdaus and after reading the diary, Firdaus also fell for Kabir. Later at the end of the movie they both met in school, expressed their love for each other and accepted each other as partners.

When Kabir was traveling to Kashmir a number of military trucks were shown on roads which depicted the heavy militarization and fearful environment in Kashmir. As he was visiting Kashmir for the first time after the exodus of Kashmiri Pandits in his childhood, he was remembering the worst memories and traumas that he had experienced at that time. When he was on a boat to school he asked boat-man, 'yha network nhihotakya'(is there no network) and he replied 'hotahainasahab jab mausam aur maholsaaf ho par mausam aur maholkam hi saafhotehai' (yes, there is but when both weather and environment is clear but both are rarely clear), this is showing the backwardness and lack of technological developments in Kashmir and also highlighting the inequality in insecurities the population is facing in a conflict zone. Also the maholis highlighting the conflicts and tensions prevailing in Kashmir and in such situations mobile and internet services are called off which is a very

common phenomenon in Kashmir. As per reports from the last six years i.e from 2018 -2023, India records the highest internet shut down globally and the area where the internet shut down the most is Kashmir.(ibid.)

Such circumstances hinder the liberty and overall personality development of women and create conditions which forces women to live their lives differently from their wishes. For example, as shown in this movie, Firdaus as a female teacher in DPS is not allowed to keep a tattoo of pole stars which she had made in the memory of her late parents and the principal of the school provides her two options, either to get the tattoo removed or to get transferred to Wular Public School, located in the far flung area as Firdaus described it by saying ye 'jagahitni door hai ki yhaumeed ko paunchne main bhiwaqthlagega' (this place is so far that even hope will take time to reach here). In such a conservative society, females have to sacrifice their individuality and dreams for their responsibilities and for societal expectations. They are treated as a daughter, wife, sister and mother but never as a woman. As Firdaus mentioned 'main abukeliye ek beti, ek boyfriend keliye ek girlfriend aur ek dost keliye ek dost hun, par main khud keliyekya hu? (I am a daughter of my father, girlfriend of a boyfriend, friend of a friend but what i am for myself? Here Firdaus is questioning her individuality and existence but then she musters all her courage and answers herself 'khud keliye main kaafi hu'(I am enough for myself). But the condition of uneducated and unemployed women is more pathetic as they have no say in any decision-making of the family and are dependent on their husbands and they have to live their life according to the wishes of their husbands. Such women never questions the decision of their husbands even if they are wrong, for example Imran, who was one of the student of the Wular Public School was forbidden from attending school by his father and when Kabir came to know about this from Firdaus's diary went to Imran's home to take him to school but Imran's mother stopped Kabir to do so by saying 'main apnepatikeqhilafnhi ja sakthi' (I can't go against my husband's wish). This shows that women are treated as a secondary and passively in the family and their opinion is not considered important in family decisions. This movie highlights the issue of displacement, settlement and adaptation in a new place by the victims of the conflict. Kabir mentions'main Kashmir se nikaltewaqt ek chinar ka pattaapnesaath le aaya par ye patta Jammu

main kisipedhkesaathnhijud paya' (while leaving Kashmir, i brought a chinar leaf with me but this leaf could not be attached to any tree in jammu). This highlights the feeling of exclusion and non-acceptance experienced by Kashmiris after their exodus.

From the overall analysis of the Notebook, it becomes clear that there are different threats to human security in Kashmir and women become victims easily due to being vulnerable and passive which poses a challenge for their goals, dreams and even for their existence. But if women are educated and are aware of their rights then they have the potential to prove their worth by taking a stand for themselves and by fighting against all odds.

Shikara (2020)

Shikara (2020) directed by Vidhu Vinod Chopra.Depicts thelove story of Kashmiri Pandit couple Shiv Dhar and Shanti Sapru, set against the mass exodus ofKashmiri Pandits. In this movie, the difference in people's lives in pre-conflict and post-conflicttimes has been depicted. Shiv always writes letters to the American President about the plight ofKashmiri Pandits, despite knowing that he will never get a reply. One day Shiv in order to fulfillShanti's dream to visit the Taj Mahal, lied to her that he got the reply of the US President whohad invited him to the Presidential Suite in Agra. They both wentto a boat ride in Agra where Shanti collapsed due to her neurological condition. After that Shiv shifted tohis village's home along with the ashes of Shanti and stayed there for the rest of his life.

The movie has cinematically depicted the condition of human security in Kashmir.It depicts the poor situation in relation to health securitydue to lack of health infrastructure and lack of proper health facilities. When Lateef"s father wasinjured during lathicharge he succumbed to his injuries, because the nearby clinic did not have anoperation facility. When they reached hospital, a protest was going on and a leader wasdelivering a speech and saying "jha hum election rally keliyejatehai, government 144 lgadetihai, main likhkedeta hu aglemahine jo elections hongeusmebhigadbadkaregi yegovernment". This situation clearly depicts the threats to health insecurities because hospitals arenot meant for such things. Food insecurities are also highlighted in the movie for example whenthe people from Jammu Nationalist Party came with a truck full of tomatoes and

announced‘sabhibhaiyon ko tamatarbhaintkiyejayenge, hum apne Hindu bhaiyonkesaathhai’ theKashmiri Pandits, who were such a proud community, ran towards the truck only for 2-3tomatoes. In the movie the issue of youth joining militancy, their crossing of borders fortraining and weapons, were also highlighted which portrays situation of economic security. One lady said to Shanti ‘vese ab toh bahut ladkejaanelagehaiusspaar, mainesunahai Lal Chowk se direct bus jaanelagihai aur vokhuleaamchilatehaiRawalPindi, RawalPindi’. Besides this various other issues such as failure ofgovernment and lack of administration also highlighted in the movie for example when oneindividual in the refugee camp said to father of Shiv Dhar ‘Aapfiqrnakare Dhar sahabhazaroPandito ko ghar se nikalagyahai, dekhna parliament main kitnashormachega, dharnediyejayenge, ye sab bss 10 din ki baathai”, but nothing like this happened and Kashmiri panditslived as refugee in their own country for decades.

In such places where human right violation is a recurrent phenomenon, women become victimsof gender-based violence, primarily she becomes sexually vulnerable. In Shikara when Shantiwas traveling alone, she also faced threat from some males who ordered her to cover her head‘sardhakhkarrakh, aurateinsardhakhkarrahegi’ (Keep your head covered, women will keeptheir heads covered). In such a situation the whole population including women become victimsof the various types of human insecurities and they have to sacrifice their goals and dreams.Allthis creates a mental burden and as per reports 41% of Kashmiri adults are suffering fromdepression, 26% from anxiety and at least 47% had faced some kind of trauma.

Overall, Shikara movie is an attempt to show the problem of Kashmiri Pandits since their exodus to becoming refugees in their own country. It shows the numerous sufferings faced by the population of a conflictual area and also what consequences those sufferings have on their lives.

Besides these various other aspects such as youths’ joining militancy, their crossing of borders for training and weapons, and their involvement in various anti-state activities were also highlighted in the movie. One lady said to Shanti ‘vese ab toh bahut ladkejaanelagehaiusspaar, mainesunahai Lal Chowk se direct bus jaanelagihai aur vokhuleaamchilatehaiRawalPindi’ (By the way, now many boys have started going to the other side, I have heard that a direct bus has started running from Lal Chowk and they openly shout Rawalpindi, Rawalpindi).

In such places where human right violation is a recurrent phenomenon, women become victims to various kinds of violence very easily, primarily she becomes sexually vulnerable. In Shikara when Shanti was traveling alone, she also faced threats from some male who ordered her to cover her head 'sardhakhkarrakh, aurateinsardhakhkarrahegi' (Keep your head covered, women will keep their heads covered).

Cinematic narratives (Shikara and Notebook) and the analysis of various reports published on Kashmir provides an in depth understanding of the current situation of human security in Kashmir. This paper has provided an interdisciplinary perspective and has approached the concept of security through non- traditional lens. It brings a fresh perspective to analyse the situation of human security. Through the paper the objective has been to probe the idea of human security through gendered lense and as data reveals there is a huge requirement of attention to be given to ensure human security in general and women security in particular.

References

Acharya, A. (2001). Human security: East versus west. International journal, 56(3), 442-460.

Alkire, S. (2003). A Conceptual Framework for Human Security.

Bajpai, K. P. (2000). Human security: concept and measurement (pp. 1-64). Notre Dame: Joan B. Kroc Institute for International Peace Studies, University of Notre Dame.

Basri, F. K. H. (2008). Representations of Gender in Malaysian Malay Cinema: Implications for Human Security. Asian Cinema, 19(2), 135-149

Bhat, S. A. (2019). The Kashmir conflict and human rights. Race & Class, 61(1), 77-86.

Dixit, A. K. (2014). Human rights abuses in Jammu and Kashmir. International Journal in Management & Social Science, 2(2), 175-184.

Fukuda-Parr, S., & Messineo, C. (2012). Human Security: A critical review of the literature. Centre for Research on Peace and Development (CRPD) Working Paper, 11, 1-19.

Gasper, D. (2007, June). Human Rights, Human Needs, Human Development, Human Security: Elations Ships between Four

International 'Human Discourses. In Forum for Development Studies (Vol. 34, No. 1, pp. 9-43). Taylor & Francis.

Haq, I. U., & Dar, M. A. (2014). Human rights violation in Kashmir. European Academic Research, 2.

Hjort, M., & Jørholt, E. (Eds.). (2019). African Cinema and Human Rights. Indiana University Press.

Hoogensen, G., &Stuvøy, K. (2006). Gender, resistance and human security. Security Dialogue, 37(2), 207-228.

Hoogensen, G. (2005). Gender, identity, and human security: Can we learn anything from the case of women terrorists?.Canadian Foreign Policy Journal, 12(1), 119-140.

Hudson, H. (2005). 'Doing Security as though humans matter: A feminist perspective on gender and the politics of human security. Security Dialogue, 36(2), 155-174.

Iqbal, S. (2021). Through their eyes: women and human security in Kashmir. Journal of Asian Security and International Affairs, 8(2), 147-173.

Kalai, S. (2014). Cinema as an effective tool for teaching human rights issues and problems: An analytical study of Samuel Goldwyn's film:"The Whistleblower.". International Journal of Multidisciplinary Approach and Studies, 1(5), 233-244.

Kaldor, M. (2007). Human security. Polity.

Kerr, P. (2008). Human security. Strategic Studies Quarterly, 11(41), 601-626.

King, G., & Murray, C. J. (2001). Rethinking human security. Political science quarterly, 585-610.

Kuszewska, A. (2022). Selected root causes and the structure of human rights violations. In Human Rights Violations in Kashmir (pp. 13-46). Routledge.

Lacy, M. J. (2003). War, cinema, and moral anxiety. Alternatives, 28(5), 611-636.

Majeed, G., & Hameed, S. (2023). Kashmir Issue: A Dominant Threat to Peace. Journal of Development and Social Sciences, 4(1), 572-583.

Martin, M., & Owen, T. (Eds.). (2014). Routledge handbook of human security. London: Routledge.

McDonald, M. (2002). Human security and the construction of security. Global Society, 16(3), 277-295.

McDonald, M. (2002). Human security and the construction of security. Global Society, 16(3), 277-295.

McLoughlin, S. (2023). Kashmir Through The Lens of a Feminist Human Security Approach: A Case Study of Half-Widows (Master's thesis).

Mohan, S. (2012). The State of Human Rights in Jammu and Kashmir 1989-2010. International Journal of South Asian Studies, 5(2), 217-230.

Mohd, A. R. (2017). Identifying the Parameters of Militarisation in Kashmir Valley: Locating through the Prism of Human Security Approach. International Journal of Peace and Conflict Studies, 4(2), 41-52.

Moussa, G. (2008). Gender aspects of human security. International Social Science Journal, 59, 81-100.

Mustafa, R. (2019). Human Rights Violations in Indian Occupied Kashmir: A Legal Perspective‖. International Journal of Kashmir Studies, 1(1), 1-18.

Nath, A. (2019). Camera as weapon: ways of seeing in Kashmir. Studies in Documentary Film, 13(3), 268-282.

Newman, E. (2010). Critical human security studies. Review of International Studies, 36(1), 77-94.

Reardon, B. A., & Hans, A. (Eds.). (2018). The gender imperative: Human security vs state security. Taylor & Francis.

Sen, A. (2000, July). Why human security. In international symposium on human security, Tokyo (Vol. 28).

Szivak, J. (2021). Trouble in paradise: The Portrayal of the Kashmir Insurgency in Hindi cinema. In Film, Media and Representation in Postcolonial South Asia (pp. 19-30). Routledge India.

Taylor, V. (2004). From state security to human security and gender justice. Agenda, 18(59), 65-70.

Tripp, A. M. (2013). Toward a gender perspective on human security. Gender, violence, and human security: Critical feminist perspectives, 3-32.

True, J., & Tanyag, M. (2017). Global violence and security from a gendered perspective. Global Insecurity: Futures of Global Chaos and Governance, 43-63.

Wani, H. A., Suwirta, A., &Fayeye, J. (2013). Untold stories of human rights violations in Kashmir. Educare, 6(1).

Zherka, E. (2013). Building Gendered Human Security Inside and Out: A Case Study in Post-Conflict Kosovo (Doctoral dissertation).

https://hdr.undp.org/content/human-development-report-1994

https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures

https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620690/bp-women-in-conflict-zones-290319-en.pdf

https://www.census2011.co.in/census/state/jammu+and+kashmir.html#:~:text=Jammu%20and%20Kashmir%20Literacy%20Rate,literacy%20is%20at%2056.43%20percent.

https://thekashmiriyat.co.uk/jammu-kashmirs-educated-unemployment-soared-from-21-in-2005-to-34-8-in-2022-ilo-employment-report/

https://www.msfindia.in/sites/default/files/2016 10/kashmir_mental_health_survey_report_2015_for_web.pdf

https://www.thehindu.com/sci-tech/technology/india-records-highest-number-of-internet-shutdowns-globally-in-2023/article68178061.ece#:~:text=India%20records%20highest%20number%20of%20Internet%20shutdowns%20globally%20in%202023%20%2D%20The%20Hindu

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7484691/#:~:text=One%20study%20found%20that%2045,experienced%20some%20sort%20of%20trauma

Dr. Vaishali Raghuvanshi

Assistant Professor

(Political Science)

MMV, Banaras Hindu University

Arti Devi

Ph.D. Candidate

Department of Political Science

Banaras Hindu University

❑ ❑ ❑

Reforming Labour Codes and Promoting Gender Equity : India's Feminist Diplomatic Efforts in South Asia

Surbhi Sharma • Prof. (Dr.) Nagalaxmi M. Raman • Dr. Amit Kumar Mishra

The research paper explores the intersection of Labour Code reforms and gender equity through the lens of India's feminist diplomatic efforts in South Asia. The study critically examines the recent amendments in India's labour laws, assessing their impact on women's participation in the workforce and their alignment with feminist principles. By situating these domestic reforms within the broader context of South Asian geopolitics, the paper highlights India's role in championing gender equity in the region. Using qualitative content analysis, it delves into the strategic initiatives undertaken by Indian diplomats to promote women's rights, address labour disparities, and foster regional cooperation on gender issues. The research also evaluates the challenges and opportunities presented by these reforms, offering policy recommendations to enhance India's feminist foreign policy. Thestudy underscores the importance of integrating gender-sensitive approaches in labour policies and diplomatic practices to achieve sustainable and inclusive development in South Asia.

Keywords : *Gender equity, Labour code reforms, Feminist diplomacy, India, South Asia.*

Introduction

The intersection between LabourCodes and gender equity holds significant implications for the socio-economic development of nations. Within South Asia, gendered analyses of diplomatic engagements offer critical insights into power dynamics, representation, and

inclusivity within the realm of international relations. The region's Human Development Index (HDI) of 0.584 and Gender Development Index (GDI) of 0.535 underscore substantial developmental disparities exacerbated by factors like unequal food distribution, lower wage rates, and the absence of inheritance rights for women, despite international commitments such as the Convention for the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) and national plans for gender equality (UNDP, 2002).

India, a prominent actor in South Asia, confronts entrenched gender inequalities, with a female labour force participation rate of only 35 percent and minimal representation of women in scientific and research roles(Suresh, 2015). However, there are emerging signs of progress, particularly in narrowing gender gaps in senior positions within India and neighboring Sri Lanka. This research endeavors to explore how India's feminist diplomatic initiatives contribute to labour code reforms and the advancement of gender equity across South Asia(Strachan & Adikaram, 2023).

India's engagement in the region increasingly revolves around feminist diplomatic strategies aimed at fostering gender equity and reforming labour laws. This study delves into India's efforts to integrate gender considerations into international relations, focusing particularly on labour reforms as a pivotal area of intervention.Recent years have witnessed significant labour law reforms in India, highlighted by the introduction of new LabourCodes aimed at modernising and consolidating existing legislation. These reforms prioritise addressing gender inequalities by improving working conditions for women, including regulations on night shifts, provisions for suitable seating arrangements, and facilities for personal hygiene. Moreover, the reforms emphasise universal social security coverage, extending benefits to gig and platform workers, a significant proportion of whom are women employed in the informal sector (Chigater, 2021).

Beyond domestic reform agendas, India has emerged as a regional advocate for gender mainstreaming in international forums, particularly through its engagements with the United Nations and initiatives supported by UN Women. These efforts aim to ensure that gender perspectives are integrated into multilateral agreements and cooperation strategies across areas such as peace, security, and sustainable development.

While existing studies have primarily focused on bilateral

relations and traditional peacebuilding efforts, this research aims to expand understanding by examining how labour code reforms influence gender dynamics within diplomatic contexts, shaping India's strategic choices, trade relationships, and regional collaborations. Methodologically, the study employs qualitative analysis of diplomatic records, trade agreements, and policy statements, applying a gender-centric approach to glean insights from primary and secondary sources including books, journals, articles, working papers, and online repositories.

India's commitment to a feminist approach to development and international relations, evident through both domestic labour reforms and regional diplomatic leadership on gender equality, positions it as a pivotal actor in advancing women's workforce participation and socio-economic empowerment across South Asia. The research is structured into five sections: an exploration of gender equity and labour rights in South Asia, an analysis of India's framework for feminist diplomacy, an examination of labour code reforms, an investigation into gender equity promotion through regional diplomacy, and a conclusion addressing challenges and opportunities in these spheres.

Background : Gender Equity and Labour Rights in South Asia

Internationally, Article 23(1) of the Universal Declaration of Human Rights, various international labour instruments, the eight core ILO conventions, the ILO Declaration on the Fundamental Principles and Rights at Work (1998), the ILO's Decent Work Agendaaligned with Sustainable Development Goal (SDG) 8, and the ILO Centenary Declaration on the Future of Work provide key principles for labour rights (Chigater, 2021).

South Asia, encompassing a significant portion of the global population, grapples with pervasive gender inequalities that profoundly affect women's participation in the labour market. Women across the region encounter formidable barriers such as unequal pay, hazardous working conditions, and restricted economic opportunities.India's recent labour law reforms, consolidating numerous statutes into four comprehensive LabourCodes, aim to streamline business operations while promoting women's empowerment. However, concerns persist regarding the reforms' impact on women workers, particularly those in the informal sector, where compliance and enforcement may be less stringent (Chigater, 2021).

Similarly, other South Asian nations including Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Nepal, and Bhutan have also embarked on labour law reforms, albeit with varying degrees of scope and focus. Common trends include efforts to rectify historical injustices and enhance worker welfare, influenced often by socialist principles post-independence. Key provisions typically encompass minimum wage standards, working hour regulations, occupational safety protocols, and social security enhancements(Kumar, 2023). Bangladesh, for instance, employs a minimum wage board that periodically reviews wages, particularly in the pivotal garment sector. Similarly, Sri Lanka and Nepal have established wage boards to set and regulate minimum wages in the private sector. Nonetheless, the effectiveness of these measures varies, with significant gaps in enforcement and compliance observed throughout the region (Salgado et al., 2022). Despite these legislative strides, challenges persist in implementing and enforcing labour laws, especially within the expansive informal sectors prevalent across these nations.

A comparative analysis underscores notable differences in regulatory centralisation, with India's federal structure fostering greater diversity in labour norms compared to more centralised approaches seen in unitary states like China(Mukhopadhyay et al., n.d.). While South Asian countries have made commendable efforts to reform labour laws, ensuring equitable implementation and coverage remains a persistent challenge, particularly concerning women and informal workers. Continued advocacy and domestic pressure are critical in translating legislative reforms into substantial improvements in working conditions across the region.

Several key issues contribute to gender inequality, including entrenched patriarchal values and detrimental gender norms that prioritise men over women, the absence of equal pay for equal work, high incidences of workplace sexual harassment, and the prevalence of informal and precarious employment for many women, particularly in domestic work and home-based industries. Addressing gender inequality necessitates the strengthening of labour market institutions, the enforcement of anti-discrimination laws, and the transformation of social norms. The International Labour Organisation (ILO) provides technical assistance to South Asian countries to analyse labour market inequalities, build the capacity of workers' and employers' organisations, and develop gender-

sensitive policies and programmes(Equality and Discrimination in South Asia, n.d.).

Reforming labour codes and promoting gender equity should be a key priority for India's feminist diplomacy in the region. Specific actions could include advocating for the ratification and implementation of ILO Convention 190 on violence and harassment, sharing best practices on equal pay legislation and policies to support work-life balance, supporting women's representation and leadership in trade unions and employers' organisations, collaborating on regional initiatives to improve working conditions in informal sectors dominated by women. By leveraging its influence and expertise, India can play a leadership role in advancing gender equality and labour rights across South Asia(Equality and Discrimination in South Asia, n.d.).

In tandem with domestic reforms, India has emerged as a regional leader in advocating for gender mainstreaming within international relations and foreign policy arenas. Leveraging platforms such as the United Nations, India champions gender equality norms, advocating for the inclusion of women's voices across critical domains like peace, security, and sustainable development (Chigater, 2021). These diplomatic endeavors, coupled with comprehensive labourcode reforms, underscore India's steadfast commitment to a feminist approach to development and global engagement. As India continues to shape the regional and global agenda, its efforts to advance gender equity through legislative reforms and diplomatic initiatives will be pivotal in fostering women's empowerment across South Asia and beyond.

India's Feminist Diplomatic Framework

India's feminist diplomatic framework is founded on principles of equality, justice, and inclusivity, highlighting the imperative of women's involvement in decision-making and the integration of gender perspectives in policy formulation. Central to this framework are initiatives advocating for gender-responsive policies in the labour market, encompassing maternity benefits, equal pay, and workplace safety. India engages prominently in international collaboration, notably through bodies like the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC), to advance gender equity and labour rights. These efforts include advocating for robust gender provisions in agreements and supporting capacity-building programmes aimed at

enhancing women's skills and employability, thereby fostering their full economic participation(Patel, 2023).

India's commitment to feminist diplomacy is underscored by actions such as deploying all-women police units to UN peacekeeping missions in 2015, challenging traditional gender roles in security operations, and securing membership in the UN Commission on the Status of Women in 2020(Atchaya, 2022). Embracing soft power tools, India directs development aid with a specific focus on gender equality, contributing substantively to initiatives like the SAARC Development Fund aimed at narrowing gender disparities.Despite these strides, challenges persist in translating commitments into tangible outcomes. Critiques suggest that India's feminist foreign policy initiatives may be influenced more by political expediency than a steadfast dedication to gender equality, exemplified by its reservations towards ratifying the Women, Peace and Security (WPS) agenda (Puri, n.d.). The representation of women in senior diplomatic roles remains disproportionately low, signalling quantitative gains in inclusion without commensurate qualitative shifts. Moreover, entrenched patriarchal and misogynistic attitudes within India's diplomatic circles present formidable barriers to fully embracing a feminist approach(A Closer Look into Feminist Foreign Policy in India, 2022).

India must prioritise addressing domestic gender inequalities through comprehensive legal and policy reforms that safeguard women's rights and facilitate their meaningful participation in decision-making processes. Strengthening gender training for diplomats, augmenting women's representation in senior positions, and enhancing transparency and accountability in foreign policy formulation are critical imperatives. Ultimately, India's feminist diplomatic framework must be underpinned by intersectionality and an unwavering commitment to dismantling all forms of oppression, both at home and abroad. Embracing a feminist foreign policy could be a crucial step in this direction.

Reforming Labour Codes : India's Feminist Initiatives

The legal framework for labour rights in India includes constitutionally guaranteed rights, state and central legislations, judicial and administrative interpretations, and international human rights instruments. Key constitutional provisions are:

- Right to equality (Article 14)

- Protection from discrimination (Article 15)
- Equal opportunity for public employment (Article 16)
- Freedoms of speech, assembly, and association (Article 19)
- Right to life and personal liberty (Article 21)
- Prohibitions on human trafficking and forced labour (Article 23)
- Prohibition of child labour in hazardous employment (Article 24)

Additionally, Directive Principles of State Policy (Articles 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A, and 47) require the state to promote welfare, secure the right to work, education, public assistance, humane work conditions, maternity relief, and a living wage(Chigater, 2021).

Protections for informal women workers in India are limited, despite the comprehensive legal framework.India has undertaken substantial reforms to its labour codes, focusing notably on promoting gender equity through key initiatives such as the Code on Wages, 2019, which mandates equal pay for equal work irrespective of gender and ensures timely wage disbursement. The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020, prioritises worker safety with specific provisions tailored for women, ensuring safe working environments and adequate facilities. Additionally, the Code on Social Security, 2020, extends comprehensive benefits to all workers, particularly addressing the informal sector where women constitute a significant workforce segment(Chigater, 2021).

Before these reforms, India's labour landscape was fragmented, characterised by over 40 central labour laws and numerous state-level regulations, resulting in a complex and outdated legal framework. To streamline this, the government consolidated these laws into four unified Labour Codes between 2019 and 2020: the Code on Wages, the Industrial Relations Code, the Code on Social Security, and the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code. This restructuring aimed to simplify regulatory compliance, enhance business operational efficiency, and establish universal social security coverage (Labour Reforms – Labour Codes, n.d.).

The newly enacted codes encompass several significant provisions, including universal minimum wage standards, provisions for safer workplaces by expanding the definition of hazardous environments, accommodations for women to work night shifts

under specified safety protocols, and provisions for the portability of social security benefits to migrant workers. However, critiques have surfaced, highlighting concerns over potential employer-centric biases in the reforms, particularly in terms of labour flexibility and the exclusion of informal and gig economy workers from adequate legal protections. Moreover, shortcomings in enforcing occupational health and safety standards, notably in the informal and unorganised sectors, have been noted(India's Labour Reforms, 2022).

Current estimates indicate that only 24 percent of women in India participate in the formal labour force, one of the lowest rates among developing countries. Most Indian women are employed in the informal sector, where jobs offer limited social protections and low wages. It is projected that if women were represented in the formal economy at the same rate as men, the Indian economy could grow by an additional 60 percent by 2025, adding $2.9 trillion (India introduces economic reforms to improve women's access to markets and financial assets, n.d.).

In the future, it is imperative to ensure robust implementation and enforcement of the new Labour Codes, amplify the representation of workers and unions in policy formulation, extend social security safeguards to encompass the vast informal workforce and fortify occupational safety standards across all sectors.Achieving a balanced approach that safeguards both business interests and worker rights will be pivotal for India to effectively harness the transformative potential of its labour law reforms and foster sustainable economic growth with equitable opportunities.

Promoting Gender Equity through Regional Diplomacy

The Periodic Labour Force Survey (PLFS) data for 2017–18 highlighted a significant downturn in women's work participation rates in India to 16.5%, marking the lowest figures since independence (Chakraborty and Chatterjee 2020; IWWAGE 2020). This decline is most pronounced among rural women, particularly those from Scheduled Caste (SC) and Scheduled Tribe (ST) backgrounds. According to Mazumdar and Neetha (2020), work participation among rural women dropped to 17.5%, representing a decrease of nearly 25 million since 2011–12 and almost 47 million since 2004–05. The decline spans across all social groups, with SC and ST women seeing their work participation rates drop by approximately 10 percentage

points from 2011–12 to 2017–18 (IWWAGE 2020; Chandrasekhar and Ghosh 2019).However, when considering women's overall work—both paid and unpaid—their participation rates have consistently been higher than men's. This highlights the substantial contribution of women's work, including the significant role of the unpaid care economy in supporting the formal economy (Ghosh 2018).

India's feminist diplomacy extends its influence in promoting gender equity across South Asia through strategic initiatives. Regionally, India actively advocates for gender-responsive labour policies within SAARC and other forums, encouraging member states to adopt similar reforms. This advocacy includes promoting strong gender equality provisions in regional agreements under the SAARC framework, such as through the SAARC Development Fund's integration of gender-responsive budgeting and programming, bolstered by India's contributions. Moreover, India supports capacity-building programmes aimed at empowering women through education, skills development, and leadership training across the region(Patel, 2023).

Utilising soft power, India employs diplomatic tools to advance women's empowerment. This includes providing development assistance with a specific focus on gender equality and deploying all-women police units to UN peacekeeping missions, challenging traditional gender roles in such operations. India's membership in the UN Commission on the Status of Women since 2020 further enhances its regional leadership on gender issues. Despite these efforts, challenges persist within India's foreign service and diplomatic establishment due to deeply ingrained patriarchal attitudes, limiting the full embrace of feminist approaches. The representation of women in senior diplomatic positions remains disproportionately low, highlighting ongoing gender disparities (Puri, n.d.).

Challenges and Opportunities

Several challenges impede the realisation of gender equity in labour markets across South Asia, despite significant progress. These include cultural norms that restrict women's mobility, lack of access to education and training, and weak enforcement of labour laws.The Labour Code reform process lacked adequate consultation with women workers and trade unions, resulting in insufficient representation of women's voices and their specific needs(Next IAS Content Team, 2024). Additionally, the new LabourCodes

potentially exclude informal and gig workers, leaving many women, who are overrepresented in these sectors, vulnerable(Overview of Labour Law Reforms, n.d.). Deeply entrenched patriarchal attitudes and gender stereotypes in Indian society view women as secondary earners and primary caregivers, further limiting their workforce participation. Weak enforcement of labour laws hinders the protection of women's rights, as progressive legislation has often failed due to poor implementation and accountability in the past. Moreover, the new LabourCodes inadequately address issues like sexual harassment, pay gaps, and safety provisions for women, lacking specific measures for substantive equality(Next IAS Content Team, 2024). Balancing business needs and women workers' rights is also challenging, with reforms potentially favoring employers and disproportionately impacting women.

To overcome these obstacles, India must ensure adequate representation of women and trade unions in the reform process, challenge patriarchal norms through awareness campaigns and skill development, strengthen enforcement mechanisms and grievance redressal systems, and incorporate specific provisions to address women's workplace challenges. Balancing the needs of businesses and workers is critical, as reforms aim to simplify compliance and improve ease of doing business, but concerns about potential dilution of worker protections persist(Overview of Labour Law Reforms, n.d.). Effective implementation and enforcement are essential, especially in the large informal sector, where translating legislative changes into meaningful improvements remains challenging. Addressing the exclusion of informal and gig workers is crucial, as the new codes do not adequately cover these sectors. Strengthening occupational safety and health standards requires more focus on improving conditions across all sectors. Finally, increasing the representation of workers and unions in policy-making is necessary, as inadequate consultation during the reform process has raised concerns. Consistent and sustained efforts, backed by political will and civil society pressure, will be crucial to translate the rhetoric of gender equity into reality through India's labour law reforms.

The challenges also present opportunities for innovative solutions.Consolidating over 40 central labour laws into 4 comprehensive codes aims to improve ease of compliance.Extending these protections to all workers, including the unorganised sector, is a positive step.Provisions like allowing night shifts for women

with safety measures can enhance gender equity.The reforms seek to balance employer needs with worker welfare, potentially boosting economic growth and job creation.Therefore, realising the full potential of India's labour law reforms will require addressing the challenges through sustained dialogue, effective implementation, and a commitment to protecting the rights of all workers.

Achieving gender equity through labour reforms in India presents several key opportunities. The new labour codes aim to extend minimum wages and social security protections to all workers, including those in the unorganised sector where women are overrepresented. This initiative has the potential to significantly improve the economic security and welfare of women workers. Additionally, provisions allowing women to work night shifts in factories, accompanied by safety measures, enhance gender equity by challenging patriarchal norms that restrict women's economic participation.The new Labour Codes also enhance the portability of social security benefits for inter-state migrant workers. Given that women constitute a large proportion of internal migrants in India, improved access to social security can economically empower women. Moreover, formalising employment through the issuance of appointment letters and strengthening occupational safety and health standards are vital components of these reforms (India and the MDGs: Towards a Sustainable Future for All, 2015). Implementing these measures can substantially boost India's GDP by 27 percent by 2025 if women's formal employment matches that of men. Thus, these labour reforms are not only pivotal for gender equity but also for the broader economic growth of the country (India introduces economic reforms to improve women's access to markets and financial assets, n.d.).

To fully leverage these opportunities, India needs to ensure effective implementation of the labour codes, increase the representation of women and unions in policy-making, and align the reforms with a broader agenda of women's empowerment and gender justice. Consistent efforts, backed by political will and civil society pressure, will be crucial to translate the rhetoric of gender equity into reality through India's labour law reforms. Japan's "Womenomics" initiative emphasises female workforce participation through policies like childcare support and workplace reforms. By implementing creche facilities and affordable childcare, India can reform labour codes and enhance gender equity, aligning

its feminist diplomatic efforts with South Asian goals for inclusive economic growth and social progress.

Governments can promote shared caregiving by implementing equal parental leave policies and offering incentives for fathers taking leave; expanding affordable childcare services and regulating quality; recognising unpaid care work in economic metrics and providing social security for caregivers; incentivising family-friendly policies in the private sector; and strengthening legal protections for caregivers. This multi-faceted approach challenges gender norms, redistributes care duties, and acknowledges the economic and social significance of care work. Collaboration between government, private sector, and civil society is crucial for achieving lasting change.

Conclusion

India's labour law reforms, consolidating over 40 central laws into 4 comprehensive codes, aim to simplify compliance, improve ease of doing business, and provide universal social security coverage. However, the new Labour Codes have raised concerns about their impact on women workers, particularly in the informal sector. At the same time, India has been at the forefront of feminist foreign policy efforts in South Asia, advocating for women's empowerment and gender equity. This includes pushing for the inclusion of strong gender provisions in regional agreements and initiatives, as well as supporting capacity-building and knowledge-sharing on gender-responsive policies.

The intersection of India's labour law reforms and its feminist diplomatic engagement in South Asia presents both challenges and opportunities. The reformed labour codes, which include provisions for maternity benefits, workplace safety, and non-discrimination, mark significant progress. However, the implementation of these reforms remains a crucial challenge. There are concerns about the exclusion of informal and gig workers, insufficient focus on occupational safety, and lack of adequate consultation with trade unions and worker representatives. Effective enforcement, continuous monitoring, and active involvement of civil society are essential to translate these legislative gains into tangible outcomes for women across the socioeconomic spectrum.

India's feminist diplomatic efforts have also demonstrated the power of transnational advocacy and the role of international cooperation in fostering gender equity. By promoting policies that

address gender disparities, India contributes to a regional framework that prioritises women's rights and economic empowerment. This collaborative approach not only strengthens South Asia's collective bargaining power on gender issues but also builds a foundation for sustainable and inclusive development.

In conclusion, the interplay between LabourCode reforms and feminist diplomacy in India offers a robust model for achieving gender equity. While significant strides have been made, ongoing efforts are needed to address persisting challenges and ensure that the benefits of these reforms are widely felt. By continuing to champion gender-sensitive policies and fostering regional cooperation, India can further solidify its role as a leader in promoting gender equity in South Asia. The lessons learned from India's experiences can serve as valuable guideposts for other nations striving to create equitable and inclusive societies.

References

A Closer Look into Feminist Foreign Policy in India. (2022, January 18). Retrieved from Observer Research Foundation: https://www.orfonline.org/expert-speak/a-closer-look-into-feminist-foreign-policy-in-india

Chakraborty, S., & Chatterjee, P. (2020). Stark Reality of Women's Employment in India: Insights from the Periodic Labour Force Survey. Retrieved from NewsClick. June 17, 2020. https://www.newsclick.in/Women%27s-Employment-Workforce-Participation-India.

Chandrasekhar, C. P., & Ghosh, J. (2019). India Is Failing Her Young Women Even in Terms of Work. Retrieved from Business Line. https://www.thehindubusinessline.com/opinion/columns/c-p-chandrasekhar/india-is-failing-its-young-women-in-terms-of-work/article30435400.ece.

Chigater, S. (2021). Labour Law Reforms and Women's Work in India: Assessing the New Labour Codes from a Gender Lens. Available at SSRN 4629287. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3947175

Equality and Discrimination in South Asia. (n.d.). Retrieved from International Labour Organization: https://www.ilo.org/regions-and-countries/asia-and-pacific-deprecated/ilo-india-and-south-asia/areas-work/equality-and-discrimination-south-asia

Ghosh, J. (2018). Gendered Labor Markets and Capitalist Accumulation. The Japanese Political Economy 44 (1–4): 25–41. https://doi.org/10.1080/2329194X.2019.1613899.

India and the MDGs: Towards a Sustainable Future for All. (2015). India: United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. Retrieved from https://www.unescap.org/sites/default/files/Policy%20Brief%20-%20MDG%203%20Achieving%20equal%20rights%20and%20opportunities%20for%20women%20and%20girls%20in%20India.pdf

India introduces economic reforms to improve women's access to markets and financial assets. (n.d.). Retrieved from Council on Foreign Relations: https://www.cfr.org/womens-participation-in-global-economy/case-studies/india/

India's Labour Reforms. (2022, August 20). Retrieved from Drishti IAS: https://www.drishtiias.com/daily-updates/daily-news-editorials/india-s-labour-reforms

IWWAGE. (2020). Women's Work Participation Continues to Decline: Evidence from the Periodic Labour Force Survey, 2017-18 – Iwwage. Retrieved from Initative for What Works to Advance Women and Girls in the Economy (blog). 2020. https://iwwage.org/evidence-from-the-periodic-labour-force-survey/.

Kumar, V. (2023). Comparative Study of Labour Laws in South - Asia. International Journal for Multidisciplinary Research, 5(5).

Labour Reforms – Labour Codes. (n.d.). Retrieved from BYJU'S: https://byjus.com/free-ias-prep/labour-reforms/

Mazumdar, I., & Neetha, N.(2011). Gender Dimensions: Employment Trends in India, 1993-94 to 2009-10.http://archive.nyu.edu/handle/2451/34239.

Mukhopadhyay, B., Liu, C., & Heymann, J. (n.d.). The Work, Family, and Equity Index- Setting the Global Floor: A comparative study of labour standards in India and China. Retrieved from McGill: https://www.mcgill.ca/ihsp/files/ihsp/world_equity_india_and_china.pdf

Next IAS Content Team. (2024, February 17). Women Empowerment and Gender Equality in India. Retrieved from Next IAS: https://www.nextias.com/blog/women-empowerment/

Overview of Labour Law Reforms. (n.d.). Retrieved from PRS Legislative Research: https://prsindia.org/billtrack/overview-of-labour-law-reforms

Patel, V. (2023, July 16). Analyzing the Impact of Feminist Foreign Policy in India: A Critical Perspective on South Asia. Retrieved from Impact and Policy Research Institute: https://www.impriindia.com/insights/analyzing-ffp-impact-india/

Puri, L. (n.d.). The United Nations the Wellspring for Gender

Mainstreaming of International Relations and Foreign Policy. Retrieved from Indian Council of World Affairs: https://icwa.in/pdfs/unwellspring.pdf

Salgado, M. R. M., Salgado, R., & Anand, R. (2022). South Asia's path to resilient growth. International Monetary Fund. https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781513587219/CH003.xml

Strachan, G., & Adikaram, A. S. (2023). Women's Work in South Asia: Reflections on the Past Decade. South Asian Journal of Human Resources Management, 10(2), 244–255. https://doi.org/10.1177/23220937231198381

Suresh, T. (2015). Defined by Absence: Women and Research in South Asia. British Council. Retrieved from https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/women_researchers_jan15_print.pdf

The Need for Feminist Foreign Policy in India. (2022, August 6). Retrieved from Modern Diplomacy: https://moderndiplomacy.eu/2022/08/06/the-need-for-feminist-foreign-policy-in-india/

UNDP (2002). Human Development Report. Oxford University Press.

Surbhi Sharma
Ph.D. Research Scholar
Amity Institute of International Studies
Amity University Uttar Pradesh, India.

Prof. (Dr.) Nagalaxmi M. Raman
Director & Head
Amity Institute of International Studies
Amity University Uttar Pradesh, India.

Dr. Amit Kumar Mishra
Associate Professor
School of Global Affairs
Dr. B.R. Ambedkar University, New Delhi, India

❑ ❑ ❑

UNESCO's Happy Schools Project : Promoting Well-being in Higher Education (Review Article)

Dr. Bhavya. R • Dr. Jagannath K. Dange

The UNESCO Happy Schools Project is an innovative initiative that revolutionizes education by prioritizing student well-being, social and emotional learning (SEL), and global citizenship skills over traditional academic achievements. By adopting a comprehensive whole-school approach, the project integrates curriculum, extracurricular activities, teacher training, and infrastructure to foster a nurturing learning environment. This approach not only enhances academic success but also promotes lifelong happiness and fulfillment among students. SEL plays a pivotal role, equipping students with essential skills such as emotional management, relationship building, and decision-making, crucial for navigating the complexities of the modern world. Emphasizing transversal competencies like critical thinking and collaboration further prepares students to contribute meaningfully to global challenges. The paper encompassed the initially piloted in Japan, Lao PDR, and Thailand, the project has garnered interest from Ministries of Education seeking to expand its framework. Despite challenges in defining and measuring happiness while balancing academic rigor, the Happy Schools Project offers valuable insights for policymakers and educators globally. By embracing its principles of well-being, SEL, and global citizenship, promotes secondary and well-being in higher education can empower students to drive positive change towards a sustainable and equitable future.

Keywords : Happiness,Student Well-Being, Social and Emotional Learning (SEL), Holistic Development Education for Sustainable Development and Global Citizenship.

Introduction:

Happiness has captivated philosophers from ancient times to the modern era, prompting diverse interpretations. Ancient thinkers like the Buddha, Aristotle, and Confucius, as well as Enlightenment and contemporary scholars, offer nuanced perspectives on this elusive concept. Commonalities emerge, illustrating the essence of what could be termed "Happy Schools." Firstly, they view happiness as inherently communal, rooted in positive connections and relationships. As exemplified in “The Dhammapada”, the Buddha suggests that happiness arises from supportive friendships during times of need (Fronsdal, 2005, p. 80).In the context of higher education, this translates into the role of social interactions, peer support, and mentorship in student well-being and academic success. For example, research by Fronsdal (2005) on "The Dhammapada" could be cited to explore how communal support networks contribute to happiness among students in academic settings. Secondly, these thinkers agree that happiness is attainable through learning, with education serving as both a means and an end in cultivating virtues and relevant skills (Beebe, 2003; Yao, 2003). In higher education, this perspective highlights the importance of curriculum design that integrates not only academic knowledge but also personal development and ethical reasoning. References to these scholars’ works would support discussions on how higher education institutions can structure their programs to promote happiness through learning. Lastly, they acknowledge the multidimensional nature of education, recognizing its capacity to foster holistic development (Newman, 2010; Jowett, n.d.). Positive Education, which advocates for integrating well-being and character development into academic environments. In higher education, this approach highlights the significance of promoting resilience, kindness, and teamwork among students

Enlightenment luminaries like John Locke and Johan Pestalozzi examined into the multifaceted nature of education, advocating for its role in fostering learners' cognitive, emotional, and physical growth (Aldrich, 1994; Bruhlmeier, 2010). The emergence of the Positive Psychology movement in the 1990s, often hailed as the ‘science of happiness’, introduced the concept of ‘character strengths’ as pivotal contributors to well-being. These strengths, including creativity, perseverance, kindness, and teamwork, were identified by Peterson and Seligman (2004) as key elements in enhancing happiness. This

movement gave rise to Positive Education, characterized by the International Positive Education Network as the fusion of academic pursuits with well-being and character development (IPEN, 2016b). Research emphasized the symbiotic relationship between increased well-being and improved learning outcomes (Seligman et al., 2009).

Happiness has ascended to a prominent position on the global policy agenda, highlighted by the United Nations General Assembly's 2011 Resolution acknowledging the pursuit of happiness as a fundamental human goal (United Nations General Assembly, 2011). This sentiment is echoed in the Sustainable Development Goals (SDGs), which advocate for well-being across its various objectives. Notably, SDG4 emphasizes quality education, with Target 4.7 dedicated to fostering knowledge and skills conducive to sustainable development, global citizenship, and peace. These skills, encompassing traits like creativity, empathy, teamwork, and communication, align closely with the 'character strengths' identified in Positive Psychology as vital for enhancing happiness and well-being. UNESCO's concepts of Learning to Live Together and Learning to be further highlight the importance of understanding others and nurturing the richness of learners' personalities and expressions (Delors et al., 1996; Faure et al., 1972).

The UNESCO Happy Schools Project, initiated by UNESCO Bangkok, seeks to redefine the parameters of quality education by emphasizing learner well-being, social and emotional learning (SEL), and transversal competencies. This initiative is rooted in the belief that education quality transcends mere academic achievement, encompassing the overall happiness and well-being of students. By adopting a whole-school approach, the project integrates various elements of the school and higher educational environment—curriculum, extracurricular activities, teacher training, infrastructure, and administrative processes—to create a supportive and engaging atmosphere for learners. This paper examines the objectives, methodologies, outcomes, and implications of the Happy Schools Project, which promotes the Well-being in Higher Education with a particular focus on its implementation in the Asia-Pacific region.

The project's emphasis on SEL and transversal competencies aligns with UNESCO's broader goals of fostering Education for Sustainable Development (ESD) and Global Citizenship Education (GCED). SEL aims to develop students' abilities to manage emotions, set positive goals, show empathy, build positive relationships,

and make responsible decisions (Manns, 2020). Transversal competencies, such as critical thinking, collaborative decision-making, and a sense of responsibility toward future generations, are essential for preparing students to navigate the complexities of the modern world and contribute to sustainable development. By promoting these competencies, the Happy Schools Project endeavors to equip students with the necessary skills and attitudes to become proactive global citizens.

Research emphasizes the significance of happiness and well-being in educational settings. The World Happiness Report (2015) indicates that emotional development during adolescence is a strong predictor of life satisfaction in adulthood. Furthermore, studies suggest that teenagers who experience happiness are likely to achieve higher income levels later in life (Diener, 2002). Schools prioritizing learner well-being tend to report better learning outcomes and foster greater achievements in students' lives (Layard &Hagell, 2015). These findings highlight the potential long-term benefits of integrating happiness and well-being into educational frameworks.

Happy Schools:

The below mentioned image outlines the concept of "Happy Schools," which takes a holistic approach to education. This framework, promoted by UNESCO, emphasizes the integration of positive psychology, education for sustainable development, global citizenship education, a whole school approach, learner well-being, social and emotional learning, and transversal competencies. These elements aim to create a supportive and engaging educational

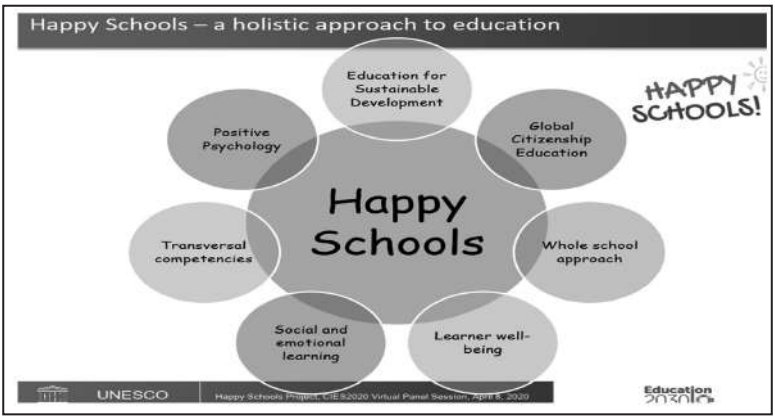

environment that fosters overall happiness and well-being for students.

UNESCO : Happy Schools Project, CIES2020 Virtual Panel Session, April 8, 2020

Whole-School Approach and Learner Well-Being:

The Happy Schools Project employs a whole-school approach, integrating all aspects of a school's functioning—curriculum, extracurricular activities, teacher training, human resources, infrastructure, and processes (Manns, 2020). This approach ensures that the school's environment promotes holistic development, addressing both academic and non-academic needs. Learner well-being is central to this framework, recognizing that a supportive and engaging school environment is crucial for students' overall happiness and academic success.

Social and Emotional Learning (SEL) and Transversal Competencies:

SEL is a critical component of the Happy Schools Project. It focuses on developing students' abilities to understand and manage emotions, set positive goals, show empathy for others, establish positive relationships, and make responsible decisions (Manns, 2020). Alongside SEL, the project emphasizes transversal competencies, such as critical thinking, collaborative decision-making, and responsibility for present and future generations. These competencies are essential for preparing students to navigate the complexities of the modern world and contribute to sustainable development.

Education for Sustainable Development (ESD) and Global Citizenship Education (GCED):

The project aligns with UNESCO's broader goals of promoting Education for Sustainable Development (ESD) and Global Citizenship Education (GCED). ESD and GCED aim to equip learners with the knowledge, skills, values, and attitudes needed to contribute to sustainable development and global citizenship (UNESCO, 2020). The Happy Schools framework incorporates cognitive, socio-emotional, and behavioral dimensions, fostering

a holistic understanding of global issues and encouraging active participation in creating a more peaceful and sustainable world.

Happiness and Well-Being in Schools:

Research indicates that happiness in schools is a significant predictor of long-term success and well-being. According to the World Happiness Report (2015), emotional development during adolescence is a strong predictor of life satisfaction in adulthood. Moreover, happy teenagers are likely to earn significantly higher incomes later in life (Diener, 2002). Schools that prioritize learner well-being tend to achieve better learning outcomes and foster greater achievements in students' lives (Layard &Hagell, 2015).

Pilot Project: Methodology and Implementation

The Happy Schools Pilot Project (2018-2020) was conducted in Japan, Lao PDR, and Thailand, involving five schools in each country. The pilot aimed to test the Happy Schools Framework and build teachers' capacity to promote a whole-school approach and SEL, emphasizing learning over mere outcomes (Manns, 2020). Each school selected one leader and two teachers to participate, partnering with local organizations such as the Asia-Pacific Cultural Centre for UNESCO (ACCU) and respective ministries of education.

Outcomes and Feedback

The pilot project yielded several positive outcomes at both national and school levels. Ministries of Education in the participating countries were receptive to the project and expressed interest in expanding the Happy Schools framework to more schools. Teachers reported a renewed focus on learner well-being, although they noted the need for additional support and practical tools to implement the framework effectively. The pilot also highlighted the importance of school organization and faculty coordination in promoting a positive school environment (Manns, 2020).

Challenges and Lessons Learned:

Despite the positive outcomes, the project faced challenges and misconceptions. Schools struggled to define and measure happiness, balancing the Happy Schools approach with academic demands. The project highlighted the need for practical, user-friendly tools

for teachers and emphasized the importance of capacity-building workshops to initiate conversations on learner well-being, SEL, and happiness in schools (Manns, 2020).

UNESCO's Happy Schools Project promotes well-being in higher education through a comprehensive framework that integrates several important components:

- Whole-School Approach: The project emphasizes creating a supportive and engaging school environment that addresses both academic and non-academic aspects of student life. By integrating curriculum, extracurricular activities, teacher training, and infrastructure, schools can foster holistic development and overall happiness among students.
- Learner Well-Being: Central to the Happy Schools Project is the recognition that learner well-being is fundamental to academic success and life satisfaction. The project aims to enhance emotional resilience, social skills, and positive relationships among students, thereby creating a conducive learning atmosphere.
- Social and Emotional Learning (SEL): SEL is a cornerstone of the project, focusing on equipping students with essential skills such as managing emotions, setting goals, showing empathy, building relationships, and making responsible decisions. These skills not only contribute to individual well-being but also to improved academic performance and interpersonal relationships.
- Transversal Competencies: Beyond academic skills, the project emphasizes transversal competencies such as critical thinking, collaboration, and responsibility towards sustainable development. These competencies are crucial for preparing students to navigate complex challenges in the modern world and to actively contribute to global citizenship.
- Integration with UNESCO's Goals: The project aligns closely with UNESCO's broader goals of Education for Sustainable Development (ESD) and Global Citizenship Education (GCED). By promoting these educational frameworks, the Happy Schools Project aims to cultivate a generation of students who are not only academically proficient but also socially responsible and aware of global issues.

- Positive Psychology Principles: Drawing from positive psychology research, the project incorporates principles that link happiness and well-being with improved learning outcomes and life satisfaction. This holistic approach acknowledges the importance of emotional development alongside academic achievement.
- Pilot Project Success: The pilot projects in Japan, Lao PDR, and Thailand have demonstrated positive outcomes, with ministries of education expressing interest in expanding the framework. Teachers involved in the pilot noted renewed focus on well-being but also highlighted the need for ongoing support and practical tools to effectively implement these initiatives.

UNESCO's Happy Schools Project offers a robust framework for promoting well-being in higher education by integrating SEL, transversal competencies, and a whole-school approach. By prioritizing learner well-being alongside academic achievement, the project aims to create supportive learning environments that prepare students to thrive both academically and personally in a rapidly changing world.

Implications for Policy and Practice:

The Happy Schools Project offers valuable insights for policymakers and educators aiming to enhance education quality through a holistic approach. The project's emphasis on learner well-being, SEL, and transversal competencies provides a comprehensive framework for creating supportive and engaging school environments. By integrating these elements into educational policies and practices, secondary and higher education can better prepare students to become agents of change, contributing to equitable, fair, and sustainable societies.

Conclusion:

UNESCO's Happy Schools Project represents a paradigm shift in defining education quality, linking happiness and well-being with academic success. The project's whole-school approach, focus on SEL, and alignment with ESD and GCED offer a comprehensive framework for fostering holistic development in students. As the pilot project has demonstrated, with appropriate support and practical tools, schools can create environments where happiness and learning

go hand in hand, ultimately leading to better educational outcomes and a more sustainable future.

References:

Aldrich, R. (1994). John Locke. J. C. Tedesco and Z. Morsy. (eds.), Thinkers on Education, Prospects: Quarterly Review of Education, Vol. 24, No. 1 and 2, pp. 61-76. Paris, UNESCO. http:// unesdoc.unesco.org/images/0010/001030/103086eo.pdf (Accessed 17 November 2015.)

Beebe, J. R. (2003). Socrates on Prozac and Happiness. Buffalo, State University of New York at Buffalo. http://www.acsu.buffalo.edu/~jbeebe2/Happiness.htm (Accessed 17 November 2015.)

Brühlmeier, A. (2010). Head, Heart and Hand: Education in the Spirit of Pestalozzi. M. Mitchell (translator). Open Book Publishers.

Delors, J. (ed). (1996). Learning: The Treasure Within. Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-first Century. Paris, UNESCO. http://unesdoc.unesco.org/ images/0010/001095/109590eo.pdf (Accessed 12 November, 2015.).

Diener, E. (2002). Will money increase subjective well-being? *Social Indicators Research, 57(2), 119-169.

Faure, E. (ed). (1972). Learning to Be: The World of Education Today and Tomorrow. International Commission on the Development of Education. Paris, UNESCO. http://www.unesco.org/ education/pdf/15_60.pdf (Accessed 12 November 2015.).

Fronsdal, G. (2005). The Dhammapada: Teachings of the Buddha. Boston, Shambhala Publications Inc.

International Positive Education Network. (2016a). Why positive education? http://www.ipositiveeducation.net (Accessed 13 January 2016.).

Jowett, B. (trans). (1994). Politics: By Aristotle. Massachusetts Institute of Technology. http://classics.mit.edu/Aristotle/politics.8.eight.html (Accessed 17 November 2016.).

Layard, R., &Hagell, A. (2015). Healthy young minds: Transforming the mental health of children. World Happiness Report, 42-65.

Manns, M. (2020, April 8). UNESCO's Happy Schools Project. UNESCO Bangkok. CIES2020 Virtual Panel Session.

Newman, W. L. (ed). (2010). The Politics of Aristotle. Cambridge, Cambridge Library Collections.

Seligman, M. E., Ernst, R. M., Gillham, J., Reivich, K. and Linkins, M. (2009). Positive education: positive psychology and classroom interventions. Oxford Review of Education, Vol. 35, No. 3, pp. 293-311.

Seligman. (2004). Can Happiness Be Taught? Daedalus, Spring 2004, Vol. 133. No. 2. pp. 80-87.

UNESCO. (2020). Happy Schools! A framework for learner well-being in the Asia-Pacific. Retrieved from https://bangkok.unesco.org/theme/happy-schools

United Nation General Assembly. (2011). Happiness: towards a holistic approach to development. Resolution 65/309. http:// www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/65/309 (Accessed 12 November 2015.).

World Happiness Report. (2015). The importance of emotional development. Retrieved from https://worldhappiness.report/ed/2015/

Yao, X. (ed). (2003). TheEncyclopaedia of Confucianism. New York, Routledge.

Dr. Bhavya
R, PDF Research Scholar
Dept. of Education
Kuvempu University, Shankaraghatta
Bhadravathi Taluk, Shivamogga District, Karnataka State
email:bhuvanabdvt253@gmail.com, Ph: 7337851208

Dr. Jagannath K. Dange
Professor, Dept. of Education
Kuvempu University, Shankaraghatta
BhadravathiTaluk, Shivamogga District, Karnataka State
email:drjdange@gmail.com, Ph: 9448585819

❑ ❑ ❑

Cost-Return Analysis of Tobacco Cultivation in Karnataka : A Case Study of Mysore District

- **Dr. Trinesha. T. R.**
- **Dr. Ramesha M.C.**

This study investigates tobacco crop production in Mysore District, Karnataka, focusing on area cultivation, production trends, and cost-benefit analysis. Using a combination of primary data collected through field surveys and secondary data from various sources including government reports and literature, the study aims to achieve several objectives: examining the area production in Karnataka, evaluating the socio-economic conditions of tobacco cultivators, and estimating the cost and returns associated with tobacco cultivation in the study area. The findings reveal that tobacco production in Mysore District has exhibited significant fluctuations over the years, with both ups and downs in production, yield, and cultivation area. Factors such as climate, government policies, and global demand are identified as key influencers of these fluctuations. Despite the challenges, tobacco farming remains economically significant, generating substantial revenue and employment opportunities for farmers in the region. The cost-benefit analysis conducted as part of the study highlights the financial aspects of tobacco cultivation, including gross income, operating costs, and profitability measures such as gross margin and returns to family labor, land, and management. The analysis provides valuable insights into the financial performance and viability of tobacco farming ventures, serving as a reference for farmers and policymakers. In conclusion, this study contributes to the understanding of tobacco crop production in Mysore District, emphasizing the importance of monitoring and analyzing production trends and financial aspects to support informed decision-making and sustainable agricultural practices in the region.

Keywords : Tobacco, Mysore, Cost, Production, Returns

Introduction

Agriculture is crucial for many people worldwide, providing their livelihoods. Tobacco farming has a long history and is one of the oldest crops grown. India, like other developing nations, relies heavily on agriculture, with about 58% of its population depending on it. Initially, tobacco production made up a large part of India's economy, but its contribution has decreased over time. This shows that India's economy has diversified away from relying heavily on tobacco. In recent years, agriculture has become more focused on earning money rather than just providing subsistence. Commercial crops, including tobacco, are now grown alongside food crops. The government has supported this shift by providing facilities for agriculture production and marketing. However, agriculture's contribution to India's GDP is now less than that of the secondary and service sectors. To increase agricultural production, it's important to grow a variety of high-yield commercial crops. Tobacco is one such crop and plays a significant role in India's economy, especially in states like Andhra Pradesh and Karnataka's Mysore district, where it is a major source of income for farmers.

Genesis of Tobacco

Worldwide, tobacco crop production is significant, with various countries contributing to its cultivation. The major tobacco-producing countries include China, Brazil, India, Zimbabwe, and the USA. India, for example, ranks as the world's third-largest tobacco producer. Tobacco cultivation has a rich history, dating back to its discovery by Christopher Columbus in the Americas in 1492. Since then, it has spread globally, with different regions adopting diverse cultivation methods and producing various types of tobacco.

In India, tobacco cultivation began in 1605, introduced by the Portuguese in Gujarat and later expanding to other regions. Efforts to enhance cultivation techniques started in the late 18th century, with significant developments occurring in the early 20th century, including successful flue curing in Andhra Pradesh in 1928. India has since become the world's third-largest tobacco producer, exporting to over 80 countries.

The tobacco industry in India encompasses leaf production,

cigarette and bidi manufacturing, and various chewing tobacco products. Despite concerns about smoking's health effects, the industry remains significant due to its employment generation, export potential, and tax revenues. However, policymakers face challenges balancing these benefits with public health considerations and calls for stricter regulations on cigarette sales, smoking, and advertising.

Globally, Flue-Cured Virginia (FCV) tobacco is the most commercially significant type due to its use in cigarette manufacturing. While the industry is predominantly led by multinational corporations advocating for its support, public health concerns persist regarding tobacco consumption.

Major Tobacco growing Districts in Karnataka:

The light soils found in Mysore, Hassan, Shimoga, Davangere, Coorg, Chikkamagalur, and Chithradurga districts collectively constitute the light soils of Karnataka. Tobacco crops in this transitional zone are typically cultivated as monsoon crops, benefiting from adequate rainfall during the growth period. The cultivation timeline involved planting in the last week of April or May, with harvesting taking place during July or August. The per-hectare yield for this region during this period was approximately 1,250 kilograms.

Economic Significance of Tobacco

Tobacco plays dominant role in supporting agricultural sector. It creates employment starting from production to processing. It contributes to the house hold incomes and export .Excise revenue of tobacco has long been debated in various countries, both adveloram and specific taxes are levied simultaneously on tobacco products.

In India, excise duty is imposed on the entire range of manufactured tobacco products. In 1998/99, tobacco contributed about Rs 59 400 million to the central government’s revenue (Table 4.15), or 10.6 percent of total excise collection. Tobacco contributed Rs 7,790 million to export earnings in 1998/99, which was around 5% of the foreign exchange earnings from agricultural products. In addition, the central government also realized on average around Rs 2 000 million per annum from tobacco enterprises in the form of corporate tax during the last three tax years. However, Recent statement made by Finance Minister Nirmala Sitaraman stated

Average annual revenue collection from tobacco products at Rs 53,750 Cr. (Business Standard, 04/02/2024)

Objectives of the Study

The study covers the following objectives:

- To study the area production and productivity of tobacco crop in Karnataka.
- To estimate the cost and returns of tobacco crop in the study area

Research Methodology

The study is based on both primary and secondary source of data. The primary data and information has been collected from the field survey i.e., from Mysore district. For the primary information 100 random sample respondents of Tobacco growers have been chosen in Mysore district especially form Periyapatna, Hunsur and H.D.Kote taluks on simple random sampling basis. The concentration of tobacco growers are more in theses taluks compared to other taluks in the district. The study is confined to 2002-03 to 2020-21and appropriate statistical tools are used in the study.

Sources of Data : The secondary data and information has been collected from the following sources;

- Annual Reports of Tobacco Board, GOI
- Annual Reports of Department of Agriculture, GOK.
- District Statistical Office, Mysore.
- Learned Journals on Agriculture, Tobacco farming
- Periodicals
- Books and internet source.

Tobacco Production in Mysore District

The data of particulars of growers, regions, area planted and estimated production as on 31-12-2020 published by Ministry of Commerce Govt. of India-Tobacco Board reveals that the data pertaining to Mysore district consisting of major tobacco growing areas / taluks such as HD Kote, Hunsur and Periyapatna.

Under this Hunsur taluks has 3 platforms or auction markets with serial of platform 2, 3, & 64. HD Kote taluk has one platform

with serial number as platform 1 and major producing taluk Periyapatna among the taluks of Mysore dist., has 3 platforms with platform number 4, 5, 6 and in Periyapatna the village called Kamplapura has two platforms having the platform number 61 and 62 are the contributor for tobacco growing region in Mysore Dist.

The below table No.1 depicts, the area under tobacco cultivation in Mysore District has remained relatively stable over the years, with a slight decrease in recent years. The highest area under cultivation was recorded in 2010-2011 at 88,280 hectares, while the lowest was in 2018-2019 at 44,109 hectares.

The production of tobacco in Mysore District has fluctuated significantly over the years. The highest production was recorded in 2010-2011 at 93,343 tonnes, while the lowest was in 2006-2007 at 25,444 tonnes. There was a steady increase in production from 2002-2003 to 2010-2011, followed by a decrease from 2011-2012 to 2014-2015. The production increased again from 2015-2016 to 2019-2020.

The yield per hectare has also shown fluctuations, with the highest yield recorded in 2010-2011 at 1.06 tonnes per hectare and the lowest in 2006-2007 at 0.36 tonnes per hectare. There was a steady increase in yield from 2002-2003 to 2010-2011, followed by a decrease from 2011-2012 to 2014-2015. The yield increased again from 2015-2016 to 2019-2020.

It is important to note that the fluctuations in production and yield could be due to various factors such as climate, government policies, and global demand.

Overall, the production of tobacco in Mysore District has shown significant fluctuations over the years, with both ups and downs. However, the area under cultivation has remained relatively stable, with a slight decrease in recent years. The yield per hectare has also fluctuated but has shown an increasing trend over the years.

It shows that the production of tobacco in Mysore District has seen significant fluctuations over the past two decades, with both ups and downs. However, with the changing global scenario and government policies, it is essential to continually analyse and monitor the production of tobacco in the district.

Table: 1

Production of Tobacco in Mysore District from 2002-03 to 2019-20

Year	Area (Hectare)	Production (tons)	Yield (Ton/Hectare)
2002 - 2003	49,790.00	29,563.00	0.59
2003 - 2004	64,147.00	32,176.00	0.5
2004 - 2005	59,482.00	38,821.00	0.65
2005 - 2006	69,104.00	35,779.00	0.52
2006 - 2007	71,231.00	25,444.00	0.36
2007 - 2008	82,890.00	27,482.00	0.33
2008 - 2009	73,995.00	21,229.00	0.29
2009 - 2010	83,050.00	58,700.00	0.71
2010 - 2011	88,280.00	93,343.00	1.06
2011 - 2012	82,234.00	72,185.00	0.88
2012 - 2013	75,310.00	35,558.00	0.47
2013 - 2014	84,544.00	61,282.00	0.72
2014 - 2015	72,647.00	44,721.00	0.62
2016 - 2017	67,594.00	39,749.00	0.59
2017 - 2018	70,596.00	57,677.00	0.82
2018 - 2019	44,109.00	34,780.00	0.79
2019 - 2020	78,005.00	67,435.00	0.86

Source: Tobacco Board, Regional Office, Mysore.

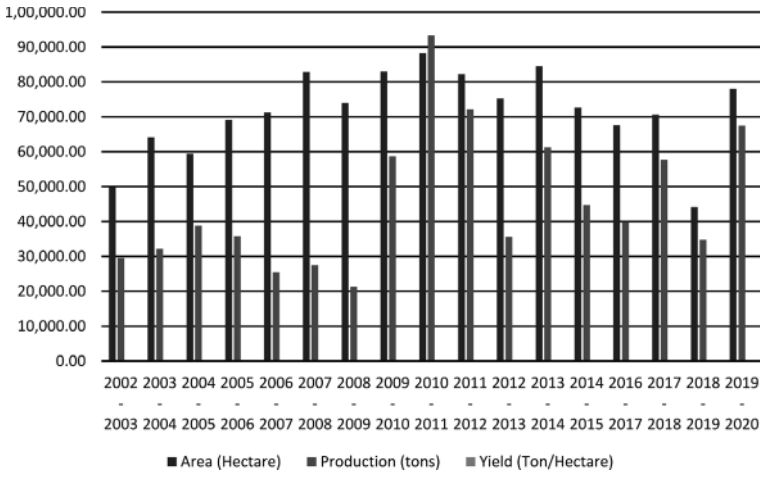

Figure No. 1: Production of Tobacco in Mysore District from 2002-03 to 2019-20

Cost-Returns Analysis

The Mysore district is situated in the southern part of Deccan peninsula and it forms the southernmost district of Karnataka state. It is one of the garden cities in India and also one of the richest districts of forest wealth. The total geographical area of the district is 6,268 Sq.km. The district lies between 1103‘ and 12018‘ north latitudes and 7609‘ and 77o east longitudes at an elevation of 776 meters, above the mean sea level.

From the below table No. 2 it is evident that the provided data presents a detailed analysis of the costs and returns associated with tobacco crop cultivation based on survey results. Let's break down the analysis:

Gross Income (Rs. 58,462), represents the total revenue generated from the sale of the tobacco crop. Regarding Costs, Input Cost of Rs. 15,673.80 expenditure incurred on inputs such as seeds, fertilizers, pesticides, and other materials required for tobacco cultivation, whereas there is no cost of equipment. It appears that no expenses were incurred on purchasing or maintaining equipment for tobacco cultivation in this case. Cost of Hired Labour Rs. 5,670.00 represents the cost of labor hired specifically for tasks related to tobacco farming. Total Operating Cost Rs. 21,343.80 comprises the sum of input cost and hired labor cost, representing the total cost directly associated with crop production. Opportunity Cost

of Operating Capital Rs. 2,988.10 represents the cost of tying up capital in the operation that could have been invested elsewhere, potentially generating returns.

As far as Family Labour is concerned, there are total 176 family labour days. This indicates that family members contributed 176 days of labor to the tobacco farming operation. Total Family Labour Cost Rs. 13,740.00 the cost associated with family labor, which is often unpaid or underpaid compared to hired labor. Total Enterprise Cost Rs. 38,072.10 is the sum of the total operating cost and the opportunity cost of operating capital. It represents the overall cost of running the tobacco farming enterprise.

Profitability Measures: Gross Margin (Rs. 37,119.00): This is the gross profit earned from tobacco cultivation, calculated by subtracting the total operating cost from gross income. Return to Family Land, Labour, and Management (Rs. 34,130.70): represents the return on investment for the family, including their land, labor, and management efforts. It is calculated by subtracting the total enterprise cost from gross income. Return to Family Land, Labour, and Management per Day (Rs. 204.40): this measure indicates the daily return generated for the family, considering their collective contributions.

Return to Family Land and Management (Rs. 20,379.90): this figure excludes labor and represents the return to the family for their land and managerial efforts. Returns to Family Land and Management per month of Crop Season (Rs. 2,264.40): this measure indicates the monthly return generated for the family, assuming a typical crop season duration.

Table – 2

Average Costs & Returns of Tobacco Crop based on survey results

Particulars	Amount (Rs.)
Gross Income	58,462
Cost	
Input cost	15,673.80
Cost of equipment	0.0
Cost of hired labour	5,670.00
Total operating cost	21,343.80
Opportunity cost of operating capital	2,988.10

Family Labour	
Number of family labour days	176
Total family labour cost	13,740.00
Total enterprise cost	38,072.10
Profitability Measures	
Gross margin	37,119.00
Return to family land, labour and management	34,130.70
Return to family land, labour and management per day	204.40
Return to family land and management	20,379.90
Returns to family land and management per month of crop season	2,264.40

Source: Field Survey.

Summary of the Cost-Return Analysis

On the basis of above analysis and discussion it can be conclude that tobacco farming enterprise generated a gross income of Rs. 58,462, with associated costs total Rs. 38,072.10. The profitability measures highlight the returns to family labor, land, and management, indicating how much income was generated considering various factors. These measures can serve as a useful reference for assessing the financial performance and viability of the tobacco crop cultivation venture. However, it's important to consider other factors such as market conditions, sustainability, and long-term financial planning when making decisions about the future of the enterprise.

Finding and Suggestions

The research study has revealed valuable insights into the economics of tobacco cultivation, yielding the following key findings and suggestions are as below:

a. Stability in Cultivation Area: The area under tobacco cultivation in Mysore District has remained relatively stable over the years, with a slight decrease in recent years. This stability suggests that farmers in the region have maintained their interest in tobacco cultivation despite fluctuations in production and yield.

b. Fluctuations in Production and Yield: While the area under cultivation has remained stable, there have been significant fluctuations in tobacco production and yield over the years.

Factors such as climate, government policies, and global demand may have contributed to these fluctuations. Farmers should be encouraged to adopt sustainable farming practices to mitigate the impact of these factors on production and yield.

c. Profitability Analysis: The profitability analysis reveals that tobacco cultivation can yield substantial returns for farmers in Mysore District. The gross margin and return to family land, labor, and management are significant, indicating the potential for profitability in tobacco farming.

d. Opportunity Cost Consideration: It's important to consider the opportunity cost of operating capital and family labor when evaluating the profitability of tobacco cultivation. Farmers should assess the returns on their investment in tobacco farming compared to other potential uses of capital and labor.

e. Sustainable Practices: Given the fluctuations in production and yield, farmers should focus on adopting sustainable practices to improve the resilience of tobacco cultivation. This may include investing in irrigation infrastructure, soil conservation measures, and pest management strategies.

f. Diversification: While tobacco cultivation can be profitable, farmers should also consider diversifying their crops to reduce risk and enhance resilience. Diversification can include growing alternative crops or integrating livestock farming with crop cultivation.

g. Policy Support: Government policies should aim to support tobacco farmers while also addressing public health concerns associated with tobacco consumption. This may involve providing subsidies for sustainable farming practices, promoting crop diversification, and implementing regulations to reduce smoking prevalence.

Conclusion

In conclusion, tobacco cultivation in Mysore District offers potential profitability for farmers, but it also comes with challenges such as production fluctuations and public health concerns. By adopting sustainable practices, diversifying crops, and receiving policy support, farmers can enhance the resilience and profitability of tobacco farming while addressing broader societal concerns.

References

- https://www.ceicdata.com/en/india/area-of-non-foodgrains-in-major-states-tobacco/agricultural-area-tobacco-karnataka

- https://tobaccoboard.com/statistics.php?stype=Production%20Data
- https://www.business-standard.com/article/economy-policy/avg-annual-revenue-collection-from-tobacco-products-at-rs-53-750-cr-fm-121080301554_1.html
- https://tobaccoboard.com/tbdata/statisticsfiles/FCVtobacco_KK.pdf
- Central Statistical Office (CSO) & Ministry of Statistics and Programme Implementation (MOSPI). (2012-13). Gross Domestic Product data. Government of India.
- Ministry of Commerce, Government of India. (2020). Particulars of growers, regions, area planted, and estimated production. Tobacco Board.
- Singh, K., & Agrawal, R. K. (2018). Agricultural Diversification in India: Trends, Determinants, and Implications. Indian Journal of Agricultural Economics, 73(1), 24-41.
- Tobacco Board. (2020). Annual Report. Government of India.
- United Nations Development Programme. (2019). Human Development Report 2019. United Nations.
- Chandra, P., & Srivastava, P. (2016). Economic Significance of Tobacco in India. Indian Journal of Economics and Development, 12(1), 137-143.
- Department of Commerce, Government of India. (2020). Handbook of Statistics on Indian Economy.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2001). Tobacco: Growing, Manufacturing, Distribution, and Use.
- Jayanna, P. K. (2019). Major Tobacco Growing Districts in Karnataka: An Overview. Karnataka Journal of Agricultural Sciences, 32(2), 342-347.
- Singh, K., & Agrawal, R. K. (2018). Agricultural Diversification in India: Trends, Determinants, and Implications. Indian Journal of Agricultural Economics, 73(1), 24-41.

CMA Dr. Trinesha. T. R.
M.com. MBA. MA (Eco).,FCMA., Ph.D.
Associate Professor of Commerce
Government First Grade College,
Pandavapura
Mandya Dist. Karnataka State

Dr. Ramesha M.C.
M.A., M.Phil., Ph.D
Associate Professor of Economics
Government First Grade College,
Pandavapura
Mandya Dist. Karnataka State

❑ ❑ ❑

Literacy and Socio-Economic Development of Rural Muslims in Nagpur District

● Dr. Sangita R. Chandrakar

Literacy is a key measure of socio-economic development, reflecting factors such as modernization, urbanization, industrialization, and communication. The literacy rate of a region serves as an important indicator of its social, economic, and political progress, with variations across different areas. According to the 2011 Census of India, the national literacy rate was 74.04%, while Maharashtra's rate was higher at 82.91%. However, there is a notable gap in literacy between rural and urban areas, as well as between males and females, with urban centers attracting more males due to better educational and employment opportunities.The Muslim community, one of India's largest minorities, faces unique challenges in accessing higher education and technical training. In rural Nagpur District, the literacy rate among Muslims is 71.23%, with male literacy at 75.46% and female literacy at 66.89%. The dropout rate after the 10th standard is particularly high, with nearly 90% of rural Muslim students discontinuing formal education. This stark dropout rate reveals the deep-rooted educational challenges faced by rural and marginalized communities. Addressing these issues requires concerted efforts to enhance access to education, ensure quality learning, and reduce gender and socio-economic disparities. It is essential to create an inclusive education system that reaches all communities, particularly those in underserved regions, to bridge the existing gaps and promote overall development.

Keywords : *Literacy, Education, Dropout Rate, Religion, Socio-Economic Development*

Introduction

Literacy, as defined by census enumeration, refers to

individuals above the age of seven who can read and write with comprehension in any language, regardless of formal education. It plays a critical role in shaping society, serving as an indicator of a healthy environment, and contributing to economic development (UNESCO, 2016). Higher literacy rates are typically linked to stronger economies and improved quality of life, whereas low literacy rates present substantial challenges to both the economy and society (OECD, 2013).

India has made significant strides in improving literacy, with the national rate now around 77% (Government of India, 2021). However, significant disparities persist across regions, communities, and genders. Nagpur District, located in Maharashtra's Vidarbha region, reflects these regional variations. While the district is a prominent urban and educational hub, rural areas, particularly within the Muslim community, face considerable educational challenges. (Patel & Sharma, 2020). Socio-economic development is closely tied to education, and disparities within communities can hinder overall progress (Sen, 1999).The socio-economic of India's Muslims was excellent prior to independence, but it significantly deteriorated after independence.(Dr.Shaikh, 2024). This research focuses on examining the literacy rate among rural Muslims in Nagpur District and the factors contributing to their educational challenges.

Universal access to basic services like health and education is central to fostering inclusive human development, as emphasized in the Sustainable Development Goals (United Nations, 2015). These services offer essential stability, especially in the face of socio-economic shocks, and encourage people to take risks without fearing for their family's well-being (World Bank, 2018). Without access to quality education, individuals are less likely to pursue opportunities for improvement, as failure can pull them further down the socio-economic ladder (Miller, 2017).

Studyarea:

Nagpur District, located in the Vidarbha region of Maharashtra in central India, covers an area of 9,892 square kilometers. It lies between 20°35' and 21°45' North Latitude and 78°15' and 79°40' East Longitude. The district comprises 14 tehsils and has a population of 4,653,570 according to the 2011 Census. Known for its thriving orange production, industrial importance, and educational institutions, Nagpur also has a notable Muslim population, which

makes up 10.64% of the district's total. However, there is a significant gap in literacy rates between rural and urban Muslims, emphasizing the need for focused educational interventions.

The terrain of Nagpur varies in elevation, ranging from 150 meters to 600 meters above mean sea level. The western region features terraced hills created by the Deccan lava formations, while the northern part extends into the Satpura hill ranges. The eastern and southeastern areas are generally flat, dotted with small hillocks. Major rivers such as the Wardha and Wainganga, along with their tributaries like Bor, Wunna, Lam, and Kardrain the district. The Wardha River flows through the western and southwestern areas, while the Wainganga River and its tributaries, including Kanhan, Kolar, Pench, Sur, Amb, and Nag, drain the eastern and central parts of the district.

Agriculture is the primary occupation in Nagpur, with nearly 58% of the land dedicated to farming and orchards. Key crops include jowar, rice, wheat, cotton, tur, linseed, chillies, and the famous Nagpur oranges. Around 8.3% of the cultivable land is irrigated. The district is well-connected to other major cities in India, making it an important hub for trade and transportation.

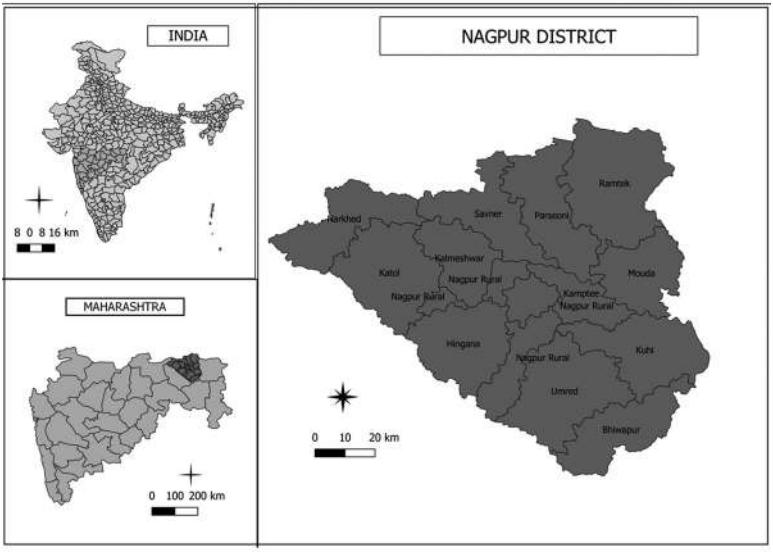

Figure1: Location Map of Study Area

Objective

1. To identify and analyze disparities in literacy rates among rural Muslim populations.
2. To identify the key factors influencing education within the community.

Methods

The study employed a comprehensive approach to collect primary data, focusing on house-to-house interviews and structured questionnaires to ensure accurate and detailed information. This method allowed researchers to directly engage with respondents, gather insights about their literacy levels, and understand the socio-economic factors influencing education within the community.

A total of 1,256 Muslim households were randomly selected from various rural areas across the district's tehsils, ensuring a representative sample of the population. These households accounted for a combined population of 7,834 individuals, providing a robust dataset for analysis. By employing random sampling, the study aimed to minimize biases and capture a diverse cross-section of the Muslim community in rural regions.Once collected, the data was systematically tabulated and classified to facilitate analysis.

Resultsanddiscussion

Trends of Literacy Rate

(A) Demographic analysis of Rural Muslim Households in Nagpur District:-

The table No.1, provides insights into the distribution of Muslim households and population across various tehsils of Nagpur District, along with gender-wise percentages. The analysis reveals significant variations in household numbers, population size, and gender composition across the tehsils.

Household and Population Distribution:

Umrer has the highest concentration of Muslim households (168) and population (1,100), accounting for 13.4% of total households and 13.4% of the total surveyed population. This could be due to better socio-economic opportunities or a larger historical

Muslim presence in the area.Nagpur Rural ranks second, with 160 households (12.8%) and a population of 1,050. Being adjacent to Nagpur city, the area likely benefits from urban spillover effects, offering employment and educational opportunities that attract more families.Bhiwapur has the lowest number of households (30) and population (200), reflecting its smaller rural Muslim community. This may be due to limited infrastructure, fewer economic opportunities, or migration to urban areas.

Gender Distribution:-

The overall male-to-female ratio is 52.80% males to 47.20% females. While this aligns with general gender disparities in rural India, certain tehsils, such as Umred (55.00% male) and Ramtek (54.60% male), show even higher male percentages. This could be attributed to male-dominated migration patterns for work or education.Tehsils like Parseoni (48.30% female) and Kamptee (48.10% female) show relatively higher female representation, which may be influenced by lower migration rates or cultural factors that retain women within the community.

Geographical Influence:-

Tehsils such as Kalameshwar and Katol, located near fertile agricultural zones, have moderate household and population numbers. These areas might attract families engaged in farming-related activities. In contrast, tehsils like Hingna and Bhiwapur, with smaller populations and household numbers, could face challenges such as limited access to resources, education, and healthcare, contributing to their lower figures.

Urban-Rural Divide:

The proximity of tehsils like Nagpur Rural and Umrer to urban centers appears to influence their higher household numbers and populations. These areas likely offer better access to employment, infrastructure, and social services.Conversely, remote areas such as Ramtek and Bhiwapur show lower figures, highlighting the challenges faced by more rural and less connected communities.

Recommendations:

Targeted Interventions: Focus on improving infrastructure

and education in tehsils like Bhiwapur and Hingna to attract and retain populations.Gender Equality Initiatives: Promote programs that support women's education and employment, particularly in tehsils with high male dominance like Umred and Ramtek.Rural Development Schemes: Enhance connectivity and access to urban opportunities in remote areas such as Ramtek and Bhiwapur to reduce disparities.

Table No. 1

Demographic analysis of Rural Muslim Households in Nagpur District

Sr. No	Tahsil	No. of House-holds	% of House-holds	Total Popu-lation	% of Male	% of Female
1	Kalameshwar	50	4.0	320	54.20	45.80
2	Saoner	70	5.6	460	53.50	46.50
3	Katol	85	6.8	540	52.10	47.90
4	Umred	60	4.8	370	55.00	45.00
5	Hingna	40	3.2	250	52.80	47.20
6	Kamptee	45	3.6	280	51.90	48.10
7	Nagpur Rural	160	12.8	1050	53.40	46.60
8	Parseoni	75	6.0	450	51.70	48.30
9	Ramtek	35	2.8	220	54.60	45.40
10	Bhiwapur	30	2.4	200	52.00	48.00
11	Narkhed	55	4.4	340	51.80	48.20
12	Kuhi	65	5.2	400	53.10	46.90
13	Bhivapur	120	9.6	780	52.90	47.10
14	Mouda	135	10.8	850	52.40	47.60
15	Umrer	168	13.4	1100	51.50	48.50
	TOTAL	**1253**	**100**	**8220**	**52.80**	**47.20**

Source:Compiled by the author.

B) Literacy Trends Among Rural Muslims in Nagpur District

Table No.2.

Literacy Trends Among Rural Muslims in Nagpur District

Sr. No	Tahsil	Total Population	Total Literacy Rate (%)	Male Literacy Rate (%)	Female Literacy Rate (%)
1	Kalameshwar	300	74.45	76.20	72.10
2	Saoner	540	75.30	76.80	73.50
3	Katol	730	77.00	78.40	75.30
4	Umred	360	75.90	77.10	74.50
5	Hingna	250	64.70	66.30	62.80
6	Kamptee	220	81.50	80.00	83.20
7	Nagpur Rural	1010	71.10	73.50	68.40
8	Parseoni	430	76.30	77.70	74.80
9	Ramtek	200	74.60	76.10	73.00
10	Bhiwapur	220	69.80	71.00	68.50
11	Narkhed	310	78.10	79.00	77.20
12	Kuhi	390	78.20	79.10	77.30
13	Bhivapur	750	76.50	77.00	75.90
14	Mouda	800	68.90	71.00	66.80
15	Umrer	1080	63.00	69.50	55.80
	Total	**8050**	**71.30**	**73.80**	**68.60**

Source : Compiled by the author.

The table No.2, highlights literacy trends across various tehsils in Nagpur District, with the focus on rural Muslims. The overall literacy rate in these tehsils reflects disparities influenced by geographical, socio-economic, and cultural factors, which significantly impact the rural Muslim population.

Literacy Trends Among Rural Muslims:

The average literacy rate for rural Muslims in the district is likely lower than the overall district literacy rate of 71.30% due to socio-economic and cultural challenges faced by the community. Tehsils like Kamptee (81.50%), Katol (77.00%), and Kuhi (78.20%) show better literacy outcomes. These tehsils may benefit from proximity to urban centers or targeted educational initiatives, which also aid rural Muslim populations.

Gender Disparity Among Rural Muslims:

Male literacy rates among rural Muslims are typically higher than female literacy rates, reflecting entrenched gender disparities. For example, in Umrer, where overall literacy is 63.00%, the gap between male (69.50%) and female (55.80%) literacy rates is stark. Rural Muslim women face additional barriers, such as socio-cultural restrictions, economic hardships, and early marriage, limiting their educational opportunities.Tehsils like Kamptee, where female literacy (83.20%) surpasses male literacy (80.00%), indicate positive trends for gender equity in certain areas.

Influence of Population and Location:

Larger populations in tehsils like Nagpur Rural (1010) and Umrer (1080) might contribute to lower literacy rates due to strain on educational resources, especially for marginalized communities like rural Muslims.Tehsils with smaller populations, such as Ramtek and Hingna, generally show lower literacy rates, reflecting limited access to schools and educational infrastructure.

Socio-Economic Barriers:

Rural Muslims often face economic hardships, which compel children to drop out early to support family income. This challenge is more pronounced in tehsils with agricultural dependence, such as Mouda (68.90%) and Bhiwapur (69.80%).Cultural norms in conservative Muslim households may discourage higher education, particularly for girls, contributing to the gender gap.

Variation across Tehsils:

Higher literacy in tehsils like Kamptee and Katol suggests a combination of better infrastructure, awareness, and government

intervention programs that benefit rural Muslims. In contrast, tehsils like Umrer and Hingna exhibit lower literacy rates, highlighting a need for targeted development programs.

Reasons for Literacy Challenges among Rural Muslims

- Economic Disadvantage: A significant portion of rural Muslim households relies on agriculture or daily wage labor, limiting their ability to prioritize education.
- Cultural Norms: Conservative practices, particularly regarding female education, contribute to the literacy gap.
- Lack of Access: Rural areas often lack adequate schools, qualified teachers, and transport facilities, deterring children from attending school.
- High Dropout Rates: Economic pressures and early marriage lead to high dropout rates among Muslim students, particularly after primary school.

Access to Education:

- Establish more schools and improve transport facilities in remote areas to increase access for rural Muslim students.
- Encourage community-based initiatives to promote awareness about the importance of education.
- Female Education Programs:
- Launch targeted schemes to encourage Muslim girls' education, such as scholarships, hostel facilities, and awareness campaigns addressing socio-cultural barriers.
- Collaborate with local religious leaders to advocate for the importance of education in Islamic teachings.

Economic Support:

- Provide financial aid and mid-day meals to reduce the economic burden on families, ensuring children can attend school without financial strain.

Skill-Based Training:

- Introduce vocational training programs for rural Muslim youth to bridge the gap between education and employment.

- Monitoring and Policy Interventions:
- Design and implement region-specific policies to address the unique challenges faced by rural Muslim communities, particularly in low-performing tehsils like Umrer and Hingna.

This analysis highlights the need for comprehensive, community-focused strategies to improve literacy rates among rural Muslims in Nagpur District, addressing socio-economic, cultural, and infrastructural barriers effectively.

Conclusions:

The demographic and literacy analysis of rural Muslims in Nagpur District reveals significant variations in household distribution, population size, gender composition, and literacy rates across different tehsils. While tehsils like Kamptee and Katol show promising literacy outcomes and more balanced gender representation, others like Umrer, Hingna, and Bhiwapur lag behind, highlighting persistent socio-economic, cultural, and infrastructural challenges.

Significant obstacles, including economic challenges, restricted access to quality education, persistent gender inequalities, and deeply rooted cultural traditions, strongly influence the educational outcomes of rural Muslim communities. Larger populations in some tehsils exacerbate resource constraints, while remote areas suffer from inadequate infrastructure, making it difficult for rural Muslims to achieve higher literacy levels.

The analysis highlights the importance of implementing targeted and context-sensitive measures to address these challenges. Key actions include strengthening infrastructure, expanding educational access, fostering gender equality, and tackling economic obstacles to promote inclusive growth.Programs focused on female education, vocational training, and community engagement, combined with policy interventions, can significantly improve the socio-economic and educational outcomes for rural Muslims in Nagpur District.

Addressing these inequalities and promoting sustainable development in marginalized communities requires a collaborative approach, engaging government bodies, local organizations, and community stakeholders.This approach will not only uplift rural Muslims but also contribute to the overall socio-economic progress of Nagpur District.

References :

1. Census of India 2011.
2. Dr.Shaikh Irfan Shaikh Bashir, Dr.Ameenuddin Shamsuddin Qazi,(2024).Literacy Rate in Rural Muslims of Jalgaon District of Maharashtra: A Geographical Study,IJWGAFES,Vol.-I,
3. Government of India. (2021). Census of India 2011: Literacy Rate Statistics
4. Miller, R. (2017). The Socio-Economic Impacts of Education in Rural India.
5. OECD. (2013). Education at a Glance 2013: OECD Indicators.
6. Patel, A., & Sharma, M. (2020). Educational Disparities in Nagpur District: A Case Study of Rural Muslims.
7. Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford University Press.
8. UNESCO. (2016). Global Education Monitoring Report 2016: Education for People and Planet.
9. United Nations. (2015). Sustainable Development Goals.
10. World Bank. (2018). Education and Development in Low-Income Countries: Making the Most Opportunities.

Dr. Sangita R. Chandrakar
Associate Professor
Department of Geography
Dhandai Arts & Science College, Amalner
Dist.-Jalgaon
email:drsangeeta.chandrakar@gmail.com

Residential Address:-Dr.SangitaR.Chandrakar
Flat No.-404, Wing-B,Majestic Paradise,Essaji Layout,
Wardha, Maharashtra-442001
Mobile No.+919881387699

❑ ❑ ❑

From Smart Cities to Smart Governance : Role of ICCC's in Achieving Vikshit Bharat@2047

Dr. Arun Pandya • Mr. Navinkumar Rohit

Urbanization is a major phenomena of the 21st century, with over half of the global population now living in cities. In India, the rapid migration from rural to urban areas has created unique challenges, placing immense pressure on infrastructure, governance, and service delivery. By 2050, India's urban population is projected to reach 877 million, requiring smart, scalable solutions to manage urban growth (United Nations Population Division, 2019). The Smart Cities Mission, launched by the Government of India in 2015, addresses these challenges through innovative technologies. Under this mission, Integrated Command and Control Centers (ICCCs) are playing a crucial role in transitioning to smart governance. This paper explores the evolution of the Smart Cities Mission, focusing on ICCCs' role in enhancing urban governance. It also examines how ICCCs contribute to India's vision of Vikshit Bharat@2047, promoting economic growth, sustainability, and social equity, while addressing urban challenges through data-driven solutions.

Keywords : *Vikshit Bharat, Smart Cities Mission, Sustainable Cities, ICCCs, Smart Governance*

Introduction

Urbanization has become one of the most defining global phenomena in the 21st century. According to the United Nations (2019), over 55% of the world's population resides in urban areas, and this number is expected to rise to nearly 70% by 2050. This unprecedented urban growth is driven by factors such as migration, economic opportunities, and technological advancements. However, this rapid shift to urban centers has also brought significant

challenges, including overcrowded cities, strained infrastructure, environmental degradation, and increasing demand for efficient governance and service delivery. In response to above challenges, the concept of Smart Cities has gained global recognition. In India, urbanization presents a particularly unique challenge. The country is experiencing one of the fastest rates of urban growth in the world, with over 35% of its population currently living in urban areas. By 2050, India's urban population is expected to reach 877 million, accounting for a significant portion of the global urban population (United Nations Population Division, 2019). This rapid migration towards urban places formed immense pressure on India's existing infrastructure, governance systems, and public services. To address these concerns, the Government of India launched the Smart Cities Mission (SCM) in June 25, 2015. This mission is the extension of the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM), which was introduced in 2005 to improve urban infrastructure and governance. JNNURM laid the groundwork for urban development by focusing on infrastructure upgrades, while SCM extends this vision by incorporating technology, data analytics, and citizen-centric solutions to create smart, sustainable cities. SCM emphasizes the use of information and communication technologies (ICT) to enhance governance, optimize resource management, and improve the quality of life for urban residents, moving towards the creation of future-ready urban ecosystems.

The core objective of the mission is to promote cities that provide core infrastructure, a clean and sustainable environment, and a better quality of life to their citizens through the application of "smart" solutions (Ministry of Housing and Urban Affairs [MoHUA], 2021). The SCM initially targeted 100 cities, selected through a competitive process, each developing its own Smart City Proposal (SCP) with plans for improving essential services like water, sanitation, mobility, and digital infrastructure (Press Information Bureau [PIB], 2020).

Introduction to ICCCs and Its Core Functions

Integrated Command and Control Centers (ICCCs) are the nerve centers of the Smart Cities Mission (SCM), playing a crucial role in managing and governing urban systems more efficiently. ICCCs provide a centralized platform for cities to monitor, manage,

and control multiple civic services in real time. The core functions of ICCCs include data collection, analysis, decision-making, and coordination of urban services such as traffic management, public safety, utilities, and disaster response (Ministry of Housing and Urban Affairs [MoHUA], 2021). By harnessing the power of information and communication technologies (ICT), ICCCs enable city administrators to respond to urban challenges promptly, improving the quality of life for citizens.

A key function of ICCCs is integration. They consolidate data from various urban infrastructure systems and transform into a unified interface which allow seamless coordination across departments. This integration also helps in real-time monitoring of key services, enabling proactive interventions and more efficient use of resources. The primary goal of ICCCs is to create a "smart" urban ecosystem that is resilient, sustainable, and citizen-friendly (Press Information Bureau [PIB], 2021).

At the core of this mission lies the Integrated Command and Control Center (ICCC), which serves as the nerve center for monitoring, analysing, and managing city operations in real-time. ICCCs plays a pivotal role in enhancing the efficiency of urban governance by facilitating the seamless integration of various public services. These centers enable real-time decision-making, resource optimization, and improved responses to emergencies. As India approaches its centenary of independence in 2047, the vision of Vikshit Bharat@2047 emphasizes a prosperous and sustainable future. ICCCs are expected to be a key driving force in transforming urban governance by making cities smarter, more efficient, and resilient. By leveraging cutting-edge technologies such as big data analytics, artificial intelligence (AI), and the Internet of Things (IoT), these centers provide the infrastructure necessary for cities to achieve sustainable development goals (SDGs) while improving the quality of life for urban dwellers.

The Architecture of ICCCs in Indian Smart Cities:

The architecture of an ICCC is designed to handle complex data flows and real-time operations across various urban systems. The ICCC typically comprises four layers: data collection, data analysis, decision-making, and response coordination. These layers work in tandem to provide real-time insights into city operations and support decision-making at the municipal level.

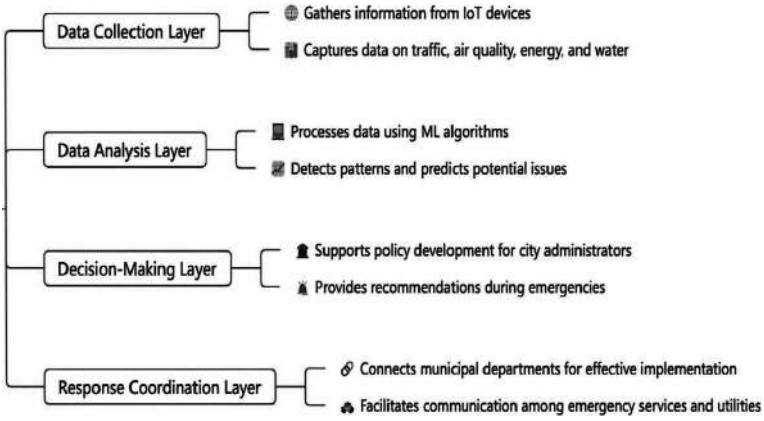

Key Components of ICCCs

ICCCs manage multiple urban systems through their core components, which include surveillance, traffic management, disaster response, and public service delivery. Each of these components contributes to the effective governance of smart cities.

Surveillance

One of the critical component of ICCCs is city-wide surveillance, which enhances public safety and security. Surveillance cameras installed at strategic locations, provide live video streams to the ICCC, where artificial intelligence (AI) systems analyse the footage to detect suspicious activities or traffic violations.

Traffic Management

ICCCs also play a pivotal role in traffic management. By integrating intelligent transportation systems (ITS), ICCCs monitor traffic patterns, identify congestion hotspots, and manage traffic signals dynamically to reduce bottlenecks.

Disaster Response

ICCCs are designed to enhance cities' ability to respond to natural and man-made disasters. By integrating data from weather stations, seismic sensors, and social media feeds, ICCCs can provide early warnings and coordinate disaster relief efforts.

Public Service Delivery

ICCCs also improve the delivery of essential public services such as water distribution, waste management, and street lighting. The integration of these systems within ICCCs allows for a more holistic approach to urban governance, making cities more sustainable and resilient.

Real-Time Monitoring and the Use of Data Analytics for Governance

The hallmark of ICCCs is their ability to provide real-time monitoring of urban systems and services, enabling more effective governance. Data analytics plays a central role in this process by transforming raw data into meaningful insights that guide decision-making. For instance, by analysing traffic data in real time, ICCCs can adjust traffic light sequences to reduce congestion or dispatch additional public transport services during peak hours (MoHUA, 2021).

ICCC's Contribution to Smart Governance:

ICCCs play a crucial role in enabling smart governance by acting as centralized hubs that integrate data from multiple sources and improve coordination between various governmental departments. The ICCC enhances governance capabilities in several domains:

Efficient Public Service Delivery

One of the core contributions of ICCCs is in enhancing the efficiency of public service delivery by using real-time data and automation. Services such as waste management, transportation, and utilities are monitored and managed through the ICCC, ensuring minimal delays and optimizing resource use.

Waste Management: In Indore, the ICCC manages the collection and disposal of waste across the city by tracking waste collection vehicles in real time. This data-driven approach has helped the city achieve one of the highest cleanliness rankings in India (MoHUA, 2021, p. 68).

Transportation: ICCCs, like the one in Pune, use intelligent transportation systems (ITS) to optimize public bus routes, monitor

traffic signals, and provide real-time updates to commuters. As a result, public transportation efficiency has improved, reducing travel times and vehicle congestion during peak hours (World Bank, 2020, p. 22).

Emergency Response Coordination

ICCCs significantly enhance the government's ability to coordinate emergency responses in real-time, ensuring that critical situations like natural disasters, fire outbreaks, and public safety incidents are managed efficiently.

Disaster Management: In Ahmedabad, the ICCC has played a pivotal role in flood management by integrating data from rainfall sensors, weather forecasts, and river level monitors. This integration enables authorities to predict potential flooding events and evacuate vulnerable areas in advance (Kumar & Rajan, 2021, p. 796).

Crime Prevention: ICCCs use city-wide surveillance systems and facial recognition technologies to monitor criminal activities in real time. For example, the Bhopal ICCC has integrated CCTV surveillance with police databases, allowing authorities to track and apprehend criminals efficiently (PIB, 2020, p. 33). The real-time monitoring of public spaces also ensures quicker responses to crimes and enhances the overall safety of the city.

Data-Driven Decision-Making for City Planning and Resource Allocation

The ICCC enables data-driven decision-making by providing urban administrators with insights derived from big data analytics. This ensures that resources are allocated effectively, policies are informed by actual data, and city planning is optimized.

City Planning: The Surat ICCC uses predictive analytics to plan urban infrastructure based on demographic changes, population growth, and traffic patterns. This proactive approach allows the city to anticipate future challenges and implement infrastructure solutions in advance (MoHUA, 2021, p. 72).

Resource Allocation: In Varanasi, the ICCC optimizes energy and water distribution systems by monitoring usage patterns and ensuring that resources are directed to areas with the greatest need. This reduces wastage and ensures a sustainable approach to urban resource management (World Bank, 2020, p. 29).

Challenges in Implementation of ICCCs

Despite the evident benefits of ICCCs, their implementation faces several challenges:

1. Technical Constraints

ICCCs rely heavily on advanced technologies like IoT devices, big data analytics, and AI algorithms. Many Indian cities face technical limitations in terms of outdated infrastructure, inadequate digital literacy, and gaps in technological adoption. These technical constraints often slow down the full operationalization of ICCCs (Kumar & Rajan, 2021, p. 798).

2. Financial Constraints

Establishing an ICCC is an expensive process, often requiring significant investment in ICT infrastructure, data analytics tools, and human resource development. Many cities struggle with insufficient funds to maintain and upgrade these centers, especially in smaller urban areas where budgets are more constrained. The cost of installing smart sensors, surveillance systems, and data centers can stretch municipal budgets (NIUA, 2020, p. 85).

3. Human Resource Constraints

Another major challenge in ICCC implementation is the lack of skilled personnel capable of managing and operating the technology-driven systems. While data analytics and AI can optimize governance processes, they require experts in urban planning, IT systems, and data science to interpret the information and make decisions accordingly. Many municipalities lack the human resources to meet these demands, which hinders the full functionality of ICCCs (World Bank, 2020, p. 31).

Vikshit Bharat@2047: Vision and Alignment with ICCC

The Vikshit Bharat@2047 vision outlines India's aspiration to become a prosperous and inclusive nation by the year 2047, marking 100 years of its independence. This long-term vision emphasizes sustainable urban development, economic growth, and social equity as the pillars of India's transformation. Key goals include creating smart cities, promoting urban sustainability, improving quality

of life, and ensuring economic productivity in urban areas (NITI Aayog, 2022, p. 17).

Integrated Command and Control Centers have emerged as a critical component of smart governance in India's smart cities. By leveraging real-time data, advanced analytics, and centralized coordination, ICCCs have transformed public service delivery, enhanced emergency response systems, and improved overall city governance. However, challenges related to technical infrastructure, financial resources, and human expertise need to be addressed to fully realize the potential of ICCCs. As India progresses towards its vision of Vikshit Bharat @2047, ICCCs will play a pivotal role in ensuring that cities become more resilient, sustainable, and citizen-centric.

Central to this vision is the idea of urban inclusivity and resilience. As India's urban population continues to grow, cities must become efficient, self-sustaining ecosystems that leverage technology for smart governance, resource management, and climate resilience. The Integrated Command and Control Centers (ICCCs) serve as crucial components in realizing these goals, helping cities to become more sustainable, economically productive, and resilient in the face of emerging challenges.

How ICCCs Can Help to Achieve the Vikshit Bharat@2047 Vision

Improving Urban Living Standards

ICCCs contribute to enhancing urban living standards by ensuring efficient service delivery, addressing issues such as traffic congestion, pollution, and waste management. For instance, in cities like Indore, the ICCC monitors waste collection and street cleaning in real time, leading to improved cleanliness and hygiene (MoHUA, 2021, p. 82). Similarly, intelligent transportation systems reduce commute times and enhance the convenience of public transit, directly improving the quality of urban life.

Enhancing Economic Productivity through Efficient Urban Management

ICCCs enhance economic productivity by optimizing the

management of city resources and services. For instance, smart systems in Pune help manage public transportation networks, improving the movement of people and goods, which in turn boosts local economic activities. Efficient urban management reduces downtime, minimizes energy waste, and improves operational efficiency in industries and businesses (Kumar & Rajan, 2021, p. 805).

Through the data collected at ICCCs, cities can better allocate resources for infrastructure development, creating more job opportunities and fostering economic growth. The use of data analytics for urban planning allows cities to grow sustainably while addressing issues like housing shortages and infrastructure deficits.

Supporting Sustainability Goals

ICCCs also play a significant role in achieving sustainability targets, such as energy management, waste reduction, and the creation of green cities. For example, Varanasi's ICCC tracks energy consumption across municipal buildings, enabling the city to optimize energy use and reduce carbon emissions (World Bank, 2020, p. 28). Through the integration of renewable energy sources and efficient waste management practices, ICCCs help cities meet their climate action goals, contributing to a carbon-neutral future.

Strengthening Urban Resilience

India's cities are increasingly vulnerable to climate change and natural disasters like floods, cyclones, and heatwaves. ICCCs enhance urban resilience by enabling real-time monitoring and coordination during emergencies. For instance, Ahmedabad's ICCC integrates data from climate sensors to forecast floods and provide early warnings, helping authorities take timely preventive measures (Kumar & Rajan, 2021, p. 797). ICCCs facilitate rapid response to disasters, ensuring that cities can withstand and recover from climate-related shocks more effectively.

Promoting Citizen Participation and Social Equity

A key aspect of the Vikshit Bharat@2047 vision is social equity and inclusive growth. ICCCs promote citizen participation by providing platforms for grievance redressal, enabling citizens to

voice concerns and access services digitally. In Bhopal, for example, the ICCC's digital platform allows citizens to track complaints related to water supply, road conditions, and waste management in real-time, fostering transparency and accountability (PIB, 2020, p. 36).

Moreover, by ensuring equitable distribution of services, ICCCs help to bridge the gap between affluent and underprivileged communities, ensuring that no section of society is left behind in India's urban development journey.

Current Challenges Faced by ICCCs

Technology Adoption Gaps: Smaller cities often lack the infrastructure and technological literacy required for ICCCs, while larger cities like Pune and Ahmedabad advance. This disparity limits ICCC implementation across India, creating uneven development (Kumar & Rajan, 2021).

Data Privacy and Cybersecurity: ICCCs handle large volumes of personal data, raising concerns about breaches, misuse, and cyberattacks. Robust cybersecurity frameworks are essential for safeguarding sensitive information and building trust (MoHUA, 2021).

Interoperability Issues: Incompatibility among systems from sectors like healthcare, transport, and law enforcement hampers data integration and delays services. For instance, traffic and emergency services often face coordination challenges (World Bank, 2020).

Skilling and Capacity-Building: There is a lack of skilled personnel in IT, data science, and urban planning needed for ICCC operations. Training government officials and enhancing digital literacy are crucial for long-term success (NIUA, 2020).

Policy Recommendations to Scale ICCCs Effectively

Standardizing Technology Frameworks: The government should establish national standards for technology platforms to ensure interoperability between different sectors and cities.

Strengthening Data Privacy Laws: Enforcing stronger data privacy and cybersecurity regulations is crucial to protecting citizens' information in the growing digital ecosystem.

Investing in Capacity-Building: The government must invest in training programs for municipal staff, ensuring that officials are equipped to manage ICCC systems effectively.

Encouraging Public-Private Partnerships: To overcome financial constraints, cities should seek partnerships with private enterprises to share the costs and benefits of ICCC development.

AI Integration and IoT Expansion: To enhance decision-making and predictive analytics, it is crucial to integrate artificial intelligence (AI) and Internet of Things (IoT) technologies into ICCC systems. AI can help analyze real-time data to provide actionable insights for urban planning, resource allocation, and crisis management (Kumar & Rajan, 2021).

Predictive Analytics for Proactive Governance: As ICCC systems advance, the integration of predictive analytics should be prioritized to allow cities to anticipate and proactively address urban challenges. By analyzing patterns in traffic, energy usage, and crime data, predictive analytics can help prevent potential issues, improving urban resilience and sustainability (MoHUA, 2021).

Conclusion

The Smart Cities Mission, through ICCCs, has revolutionized urban governance by enabling real-time monitoring, proactive decision-making, and holistic management of city functions. ICCCs enhance public service efficiency, emergency response, and citizen participation, fostering transparency and accountability. As India strives toward the Vikshit Bharat@2047 vision, ICCCs will be instrumental in creating sustainable, inclusive, and resilient cities. However, challenges like technological gaps and cybersecurity risks require targeted policy reforms and capacity-building. Future advancements in AI and IoT can further strengthen ICCCs, making them the backbone of India's smart governance framework and driving long-term urban sustainability and prosperity.

References:

- Ministry of Housing and Urban Affairs (2022) Smart Cities Mission. Ministry of Housing and Urban Affairs. https://mohua.gov.in/cms/smart-cities.php
- Ministry of Housing and Urban Affairs. (2022, March 28). Smart

Cities Mission completes 7 years, mission to be completed in June 2023. Press Information Bureau, Government of India. https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1814400

- Ministry of Housing and Urban Affairs. (2017-18). Annual report 2017-18 (pp. 40–45). Government of India. http://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/new_AR-2017-18%20(Eng)-Website.pdf
- Ministry of Housing and Urban Affairs. (2021). Smart Cities Mission guidelines (pp. 34–93). Government of India.
- Ministry of Housing and Urban Affairs. (2019). India Smart Cities Annual Report (pp. 12–34). Government of India.
- Ministry of Housing and Urban Affairs. (2023, January 3). India Smart Cities Annual Report. Press Information Bureau, Government of India. https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1906145
- National Institute of Urban Affairs. (2020). India's urbanization outlook 2031 (pp. 67–89). National Institute of Urban Affairs.
- NITI Aayog. (2018). India Infrastructure Investment Report 2040 (pp. 87–103). Government of India.
- NITI Aayog. (2019). Task force report on project program management (p. 5). Government of India. https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2023-03/Task-Force-Report-on-Project-Program-Management.pdf
- UN-Habitat. (2022). World cities report 2022 (p. 190). UN-Habitat. https://unhabitat.org/sites/default/files/2022/06/wcr_2022.pdf
- Kumar, V., & Rajan, R. (2021). The role of technology in Indian smart cities: An empirical analysis. Journal of Urban Affairs, 43(5), 789–805. https://doi.org/10.1080/07352166.2020.1863652
- United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. (2018). World urbanization prospects: The 2018 revision. https://www.un.org/development/desa/en/news/population/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html
- United Nations Conference on Trade and Development. (n.d.). Urban population growth. UNCTAD. https://hbs.unctad.org/total-and-urban-population/
- Press Information Bureau. (2024, January 4). Launch of Urban 20 (U20) cycle under G20 presidency. Government of India. https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2010349

- World Bank. (2023). India urban sector review: Transforming India's cities for a sustainable future (Report No. P171302). World Bank Group. https://documents1.worldbank.org/curated/en/099615110042225105/pdf/P17130200d91fc0da0ac610a1e3e1a664d4.pdf
- NITI Aayog. (2018). Strategy for New India @ 75. Government of India. https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2019-01/Strategy_for_New_India_0.pdf

Dr. Arun Pandya
Associate Professor
Dept. of Sociology,
Veer Narmad South Gujarat University, Surat (Gujarat)

Mr. Navinkumar Rohit
Assistant Professor (Adhoc),
MSW Programme, Dept. of Sociology,
Veer Narmad South Gujarat University, Surat (Gujarat)

❑ ❑ ❑

Classification of an Urban Centers and Urban Tehsil Places into Different Hierarchical Orders in the Ahilyanagar District, Maharashtra (India)

• **Dr. Pandurang Yadavrao Thombare**

This paper aims to classify urban centers and urban tehsil places in Ahilyanagar (formerly Ahmednagar) district according to a hierarchical order based on composite centrality scores. All urban centers and tehsil places were ranked by their composite centrality scores, which were then plotted on a log-log scale. The graphs for urban centers (Fig.1) and urban tehsil places (Fig. 2) demonstrate distinct slopes, grouping these entities into different categories that reflect varying levels of functional specialization. The bifurcation ratio method, commonly used by geomorphologists, was employed to calculate the K value for urban centers and urban tehsil places (Deshmukh, 1979). The results indicate that the urban centers and their hierarchical classifications in the study area do not conform to the K values of 1.19 for urban centers and 1.1 for urban tehsil places. These values do not align with Christaller's marketing principle (K=3), transport principle (K=4), or administrative principle (K=7), highlighting a significant divergence between the 'K' values for Ahilyanagar district and the theoretical values proposed by Christaller.

Keywords : *Urban centers, Urban Hierarchy, Centrality, Bifurcation Ratio, 'K' value.*

Introduction:

In urban geography, the hierarchy of urban centers is determined by factors such as population size, level of development, centrality index, and socio-economic influence. This paper examines

the hierarchy of urban centers in Ahilyanagar district as defined by population size and composite centrality scores. The composite centrality score is derived by summing the centrality indices calculated using the mean population threshold method, Sinha's modified method, and Davis's modified method. The rank orders based on population size are compared with the centrality indices of urban settlements within the study area.

Centrality, based on Christaller's central place theory, measures the functional capacity of urban centers to meet the needs of surrounding populations. These centers facilitate the exchange of goods and services with their surrounding areas. The urban centers within the region differ significantly from one another, resulting in varying ranks and hierarchies. The hierarchy represents the arrangement of urban centers according to their populations and the goods and services they provide beyond their immediate urban boundaries. This hierarchy can be organized in either ascending or descending orders. To determine the hierarchy of urban centers, factors such as population size, central functions (centrality values), and the size of their tributary areas are primarily considered.

Objectives:

The main objectives of this paper are as follows:

1. To analyze the spatial distribution of population and socio-economic facilities.
2. To establish a hierarchical arrangement of urban centers and urban tehsil places.
3. To calculate the 'K' value for urban centers and urban tehsil places.

Materials And Methods:

The data required for this research was gathered from the following sources:

1. Census of India: Census reports for Ahilyanagar District from 1951 to 2011.
2. District Socio-Economic Review of Ahilyanagar District.
3. District gazetteer of Ahilyanagar District.

In this study, centrality scores obtained using the (i) mean

population threshold method, (ii) Sinha's modified method, and (iii) Davis's modified method. The composite values derived from these three methods and urban centres and tehsils categorized into five hierarchical orders.

Study Area : Map-1 shows location of Ahilyanagar district which extends between 180 2' North and 190 9' North latitudes and 730 9' East and 750 5' East longitudes. It falls in parts of Survey of India's (S.O.I.) quarter inch toposheets, with index no. 47 E, 47 I, 47 M, 47 J and 47 N.

Map-1: Location of Study Area

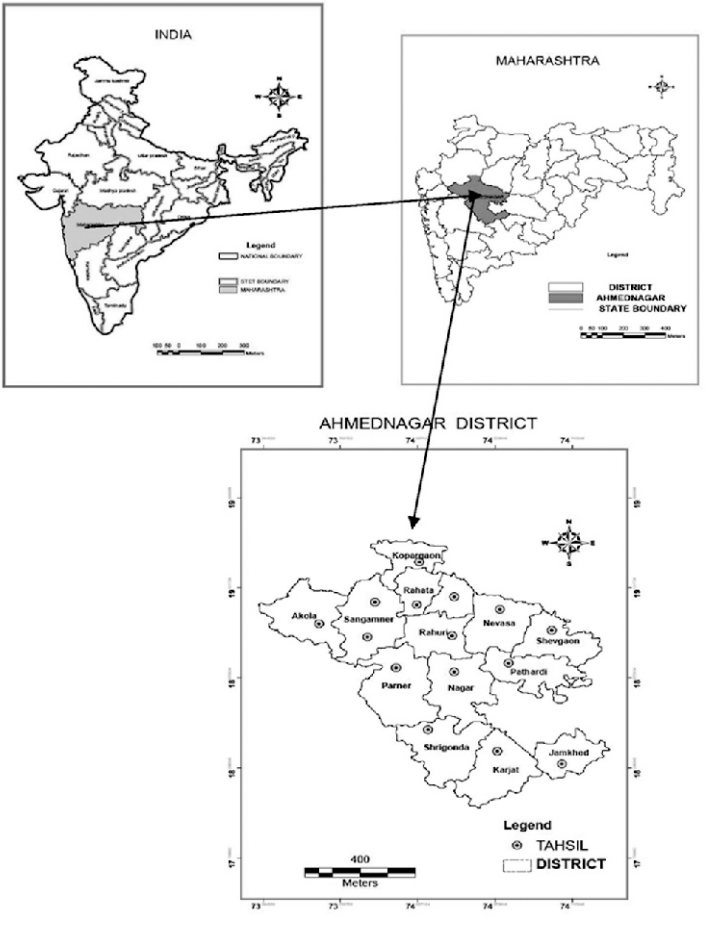

Ahilyanagar district placed a somewhat central position in Maharashtra state. Its northern portion situated partly in the upper Godavari basin and the southern portion partly in the Bhima basin. It is surrounded by the Nasik district to the north, Aurangabad district to the north-east, Beed district to the east, Dharashiv (Formarly Osmanabad) and Solapur district to the south and Pune district to the west.

Hierarchical Order And Number Of Urban Centers:

Using the composite index method, centrality determines the class orders of urban centers and tehsil places, as presented in Table-1 and Table-2, respectively. Ahilyanagar city, classified as a primate city and the district headquarters, records the highest centrality score, placing it at the first

Table-1: Hierarchic Order of Urban Centres in Ahilyanagar District - 2011

Sr. No.	Urban Centres	Composite Centrality	Number of urban centres	Criteria used for Classification of urban centres in Hierarchic orders	Hierarchic Orders of Urban centres
1	Ahilyanagar (MCorp.)	169.01	1	> Q3+Q2 > 79.63	1st
2	Shrirampur (M Cl)	77.08	4	Q3 to Q3+Q2 53.54 to 79.63	2nd
3	Jamkhed (CT)	70.17			
4	Kopargaon (M Cl)	65.06			
5	Sangamner (M Cl)	53.43			
6	Pathardi (CT)	42.41	5	Q2 to Q3 26.09 to 53.54	3rd
7	Rahuri (MCl)	37.18			

8	Shrigonda (M Cl)	31.58			
9	Shirdi (NP)	29.87			
10	Deolali Pravara(MCl)	26.09			
11	Ghulewadi (CT)	20.48	5	Q1 to Q2 11.92 to 26.09	4th
12	Karjat (CT)	18.46			
13	Rahata (CT)	14.68			
14	Rajur (CT)	13.11			
15	Ahilyanagar (CB)	11.92			
16	Nagardeole (CT)	5.68	4	<Q1 <1.92	5th
17	Darewadi (CT)	5.48			
18	Nagapur (CT)	4.94			
19	Burhanagar (CT)	2.1			

Source: Computed by Author

hierarchical order in the study area. The second order includes Shrirampur (M Cl), Jamkhed (CT), Kopargaon (M Cl), and Sangamner (M Cl), all of which serve as tahsil headquarters and rank as significant urban centers in terms of both population size and composite centrality scores. Three urban centers viz. Pathardi, Rahuri, and Shrigonda comprise the third order, representing moderate population sizes and offering limited services to their rural surroundings. The first three are tahsil headquarters, with Shirdi recognized as a prominent tourist destination and Deolali Pravara serving as a suburban center of Rahuri tahsil. Fourth order hierarchies of urban centers are Ghulewadi, Karjat, Rahata, Rajur and Ahilyanagar (CB). Nagardeole, Darewadi, Nagapur and Burhanagar are the urban centers which have been assigned in 5th order of hierarchy. In this order all the urban centers are small and have suburban centers of respective towns.

Table -2: Hierarchic Orders of Tehsils in Ahilyanagar District- 2011

Sr. No.	Urban Centres	Composite Centrality	Number of urban centres	Criteria used for Classification of urban centres in Hierarchic orders	Hierarchic Orders of Urban centres
1	Ahilyanagar	185.73	1	> Q3+Q2 > 100.43	1st
2	Shrirampur	75.53	2	Q3 to σ+Q2 71.51 to 100.43	2nd
3	Sangamner	71.51			
4	Jamkhed	69.05	3	Q2 to Q3 61.33 to71.51	3rd
5	Kopargaon	63.61			
6	Rahuri	61.33			
7	Rahata	43.25	3	Q1 to Q2 31.05 to 61.33	4th
8	Pathardi	41.96			
9	Shrigonda	31.05			
10	Karjat	18.19	2	<Q1 <31.05	5th
11	Akole	12.92			

Source: Computed by Author.

Fourth order hierarchies of urban centers are Ghulewadi, Karjat, Rahata, Rajur and A. nagar (CB). Nagardeole, Darewadi, Nagapur and Burhanagar are the urban centers which have been assigned in fifth order of hierarchy. In this order all the urban centers are small and have suburban centers of respective towns.

Hierarchical Order And Number Of Urban Tehsil Places:

Considering, tehsil headquarters as an urban places table-1 clearly indicates that Ahmednagar assigned 1st rank order of hierarchy both in population size and centrality. Two urban tehsil places viz., Shrirampur and Sangamner are big towns and have headquarters

of tehsil and big urban centers in terms of population size as well as composite centrality score. Jamkhed, Kopargaon and Rahuri are placed in third order of urban tehsil places. Rahta, Pathardi and Shrigonda fall in fourth order of hierarchy. Karjat and Akole both are bottom tehsils which are placed in fifth hierarchic order.

Fig.-1 : Rank Order & Centrality of Urban Centres, 2011

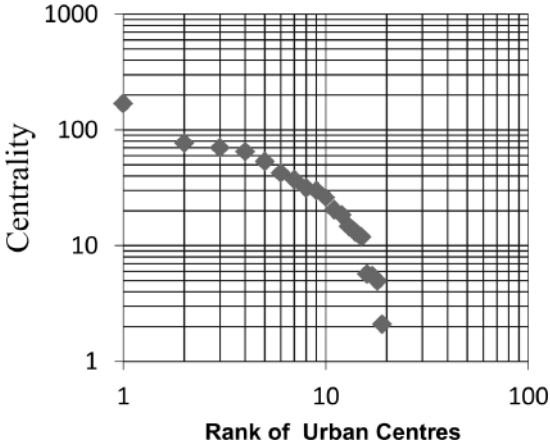

Fig. -2 : Rank Order & Centrality of Urban Tehsils, 2011

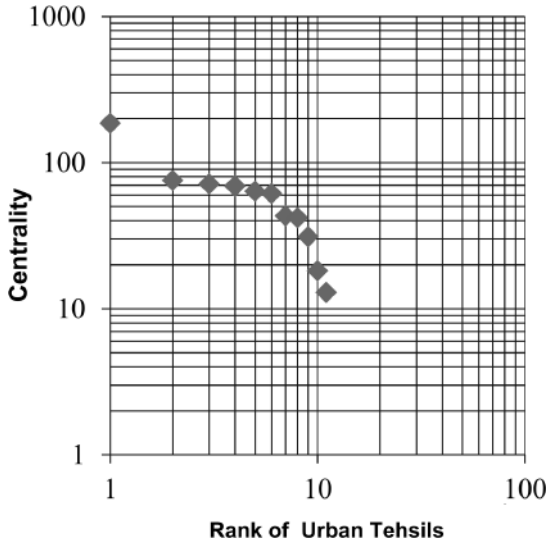

Bifurcation ratio method which is used by geomorphologists is adopted here for the calculation of 'K' value for urban centers and urban tehsil places (Deshmukh-1979).

$$K = \frac{K1+K2+K3.....Kn}{n}$$

Here K stands for composite value for all orders of central places.

Therefore: (i) K value for urban centres = $K = \frac{1}{1} + \frac{4}{1} + \frac{5}{4} + \frac{5}{5} + \frac{4}{5} = \frac{19}{16} = 1.19$

(ii) K value for urban tehsils = $K = \frac{1}{1} + \frac{2}{1} + \frac{3}{2} + \frac{3}{3} + \frac{2}{3} = \frac{11}{10} = 1.1$

Findings And Analysis

The result of above both equations clearly indicates that in the study area the urban centers and their hierarchical class orders are not governed by 'K' value of 1.19 which is not fit to the Christaller's marketing principle hierarchical K-3, Transport principle of K-4 and administrative principle of K-7. Hence it shows noticeable difference from the theoretical number. Other calculated 'K' value of urban tehsil places is 1.1 which do not fit to the any Christallar's K value. Thus, result clearly proves that differences are observed between Christaller's 'K' values given in above and calculated 'K' values. Hence 'K' value of Ahmednagar district for urban centres and urban tehsils shows noticeable difference from the Christaller's theoretical number.

References:

1. Ali md Julfikar and Varshney Deepika (2012) 'Spatial Modeling of Urban Growth and Urban Influence: Approach of Regional Development in Developing Economy (India)', Journal of Urban and Regional Planning Analysis, Vol. IV, 2, 20125, pp. 129-148.
2. Brush, J. E. (1953) 'The Hierarchy of Central Places in South Western Wisconsin', The Geographical Review, pp,380—402.
3. Census of India, 2011. 'Ministry of Home Affairs, Government of India', New Delhi. India.
4. Christaller, W. (1933) 'The Central Place of South Germany'. Translated by C. Baskin. Prentice Hall (1966). p.147.
5. Davies, W. K. D (1967) 'Centrality and Central Place Hierarchy, Urban Studies', 4. pp.61-79,

6. Deshmukh, P. W. (1979) "A Study of Central Places in Upper Krishna Valley", Unpublished Ph.D. thesis submitted to the Shivaji University, Kolhapur. pp.156-198.
7. Mandal, R., B. (2000), Urban Geography', Concept Publishing Company, Pvt. Ltd. New Delhi.
8. Smailes, A. E. (1944). "The Urban Hierarchy in England and Wales; Geography - 29, pp-41-51.
9. Thakur, R. (1994). "Urban hierarchies, typologies and classification in early medieval India: c 750-1200", Urban History, 21, pp. 61-76.
10. Yasenovskiy, V., Hodgson, J. (2007). "Hierarchical location-allocation with spatial choice interaction modeling", Annals of the Association of American Geographers, 97, pp. 469- 511.

Dr. Pandurang Yadavrao Thombare
Asst. Professor
Department of Geography
New Arts, Commerce and Science College
Lal Taki Road, Ahilyanagar
Dist. Ahilyanagar, Maharashtra (India) (Autonomous)
email: thombarepandurang@yahoo.in
M. 9960203273

❑ ❑ ❑

Blended Learning : Overviewing its Significance and Challenges

Vanessa Vera Khriam • Dr. Rihunlang Rymbai

In recent years, blended learning has become a popular educational paradigm, mixing traditional face-to-face instruction with online learning components. While blended learning allows for more flexibility and tailored learning experiences, it creates many obstacles for educators, students, and institutions. This paper aims to investigate the significance of blended learning andlook at its incompetence by overviewing the main challenges in student engagement, special education, adult education, emerging innovative approach, and other factors that cause a drawback to Blended Learning in India.

Keywords : *Blended learning, significance, challenges, adult education, special education, technology, digital literacy and equitability*

Introduction

An educational approach known as blended learning combines online and traditional teaching methods with several interactive exercises and Internet resources (Raouna, 2024). Blended learning is defined by Greer et al., (2014) as "a traditional face-to-face class where students complete a portion of their coursework on the computer and another part engaged with their face-to-face teacher or classmates" (Rivera, 2017). On the other hand, Behjat et al., (2012) described the purpose of blended instruction, also known as hybrid education, as to educate students' cognitive independence, make education more relevant using current technology, and ensure classroom sustainability in the future. Simply put, blended learning combines traditional, teacher-to-student lessons with technology-based instruction (Herold, 2016).

Blended Learning Overview

The concept of blended learning was originated around 2000. Guzer and Caner (2014) investigate the method's origins and divide it into the past and present periods, with two further sub-classifications: the definition period and the popularity era. The Past Period, the first effort of the study was traced back to 1999-2002, when blended learning attempted to mix the element of play and work in the prekindergarten school to acquire blended activities, which was the study of Cooney et al. (2000). The Definition Period (2003–2006) seeks to define blended learning. Osguthorpe and Graham (2003) describe blended learning as combining face-to-face and distant delivery technologies. During the Popularity Period (2007-2009), two broad topics drew the scholar's attention: participants' perspectives on blended learning and the efficacy of blended learning. The Present Period (2010-2012) and beyond saw recent trends in blended learning. Donnely (2010) research on the interaction in blended problem-based learning in a university setting utilizing technology; also, harmonizing mixed problem-based learning will create an ideal balance of online and face-to-face environments.

Table 1. Overview of Blended Learning

	Classification	**Year Range**
	Past Period	1999-2002
Overview of Blended Learning	Definition Period	2003-2006
according to the year range	Popularity Period	2007-2009
	Present Period	2010-2012 and beyond

The significance and challenges of Blended Learning in certain areas of education throw some light to understand the status of Blended Learning as well as prepare for its improvement in the specific fields.

1. Student Engagement and Support in Blended Learning

The degree to which students are participating in their studies

by being involved, enthusiastic, and interested in their lessons is known as student engagement. Student engagement is a crucial component in every classroom. For pupils to actively engage in the learning process, educators are creating innovative ways to grab their attention and interest. Many educators are starting to make a shift from traditional teaching approach towards newer ones that blends online and in-person training to boost student engagement. Students' engagement and success can be raised in a blended learning setting. It facilitates individualized learning for students and uses technology to make the digital learning environment engaging. It also encourages higher-order thinking by making subjects fascinating and allowing for creativity and curiosity (Kocour, 2019).

Challenges Concerning Student Engagement and Support in Blended Learning

Maintaining student engagement and providing appropriate help in a blended learning environment may be hard-hitting. The lack of direct teacher supervision during online activities may make students feel secluded and disinterested. Students may also experience isolation and a decline in motivation due to hesitancy to participate in online groups (Sander & Altman. 2023). They are frightened and uncomfortable using video projection, microphones, and speakers and being the centre of attention in the class (Muhria et al., 2023). To increase student accomplishment, instructors should employ interactive teaching strategies, foster peer collaboration, and give specialized help.

2. Blended Learning for Special Education

Blended learning enables students with special needs to receive online and in-person instruction. Students work independently and at their own pace online while still receiving a teachers' attention in the classroom. Such attention could include their assistance, experience, and resources that such an educator provides. At the same time, teachers may design courses and deliver training in more adaptable or innovative ways than in traditional classroom settings (Zavaraki&Schneider,2019). Although special education teachers have confirmed the benefits of online learning and blended teaching, several issues occur when using these additional programs.

Challenges of Blended Learning for Special Education

As stated by the Centre for Online Learning and Students

with Disabilities (2016) many special education instructors are not qualified to carry out effective blended instructional models or are not equipped with the abilities needed to execute blended learning in the classroom.As a result, they are not educated about and trained with blended learning strategies that will help children with special needs. Many instructors are not implementing technologies to their full potential; most teachers prefer conventional, practiced approaches and are not open to new inventive technology (Herold, 2016). Therefore, Bohle Carbonell, Dailey-Hebert, & Gijselaers, (2013) claims that in order to further expand these opportunities in special education, training opportunities for teachers involved in blended instruction and special education are necessary (Rivera, 2017). The teachers also stated a lack of content on ICT-based items that may be used and implemented in the classroom. There is also a scarcity of digital resources appropriate for special needs learners, such as non-digitalized assessments and activities. There is limited engagement in the learning environment, and it was considered that special needs learners lacked confidence in using and operating ICT equipment (Yusof et al., 2011). Another major challenge in integrating technology for students with special needs is the lack of computer skills and basic technological understanding. Students were found to lack the digital literacy abilities necessary to complete online reading techniques (Rivera, 2017).

3. Blended Learning for Adult Education

Adult education is defined in The Hamburg Declaration (1997) as the entire body of an ongoing learning process, formal or informal, by which people regarded as adults by the society to which they belong develop their abilities, enrich their knowledge, and improve their technical or professional qualifications, or turn them in a new direction to meet their own and their society's needs. Blended learning enables adult educators to undertake self-learning and arrange their learning effectively on their own (UNESCO Institute for Education, 1997).

Challenges of Blended Learning for Adult Education

A predicament occurs when many adult educators have

either never developed the skill of self-learning abilities or learned them in their professional careers after receiving only continual supervision, guidance, and face-to-face training courses. To use the combination of face-to-face and online learning, adult educators need a more appropriate gadget than merely an internet connection. Another challenge that adult learners faced before beginning the program was that most learners did not have computers. Also, there was a slow internet connection, which prevented them from downloading academic materials and completing most of the online coursework.

Adult learners also exhibit anxiety and delay in replying when assignments are provided via email attachments. Furthermore, adult learners have limited knowledge about using various ICT, and many of them find it difficult to obtain compatible software to work successfully with blended learning (Kapinga & Mtani, 2014).

4. Infrastructure Investment and Technological Reliability for Blended learning

In every educational institution, the role of infrastructure investment has taken centre stage. The shift to blended learning requires a solid technological base, which entails making investments in cutting-edge hardware resources in addition to a reliable internet connection. Higher technology costs will result from this, although they will ultimately be beneficial. (Sweeney, 2022).

Challenges in Infrastructure Investment and Technological Reliability

Overall, the literature underscores the need for significant investment in infrastructure to support blended learning initiatives effectively. Investments in learning management systems (LMS), a dependable internet connection, and digital technologies are critical to the success of blended learning (Chatterjee, 2024). Poor infrastructure in developing countries typically causes connectivity challenges, sluggish internet speeds, and restricted access to online learning resources, which can impede blended learning and make it difficult for students to participate in online learning activities (Roy & Chetty, 2023). Another significant obstacle is the dependability of technology infrastructure, such as learning management systems (LMS) and online platforms, which is a reoccurring issue. Chen et

al., (2023) highlight the necessity of strong and user-friendly systems in supporting blended learning efforts. Technical glitches, system outages, and device compatibility concerns may all disrupt teaching and learning activities, emphasizing the importance of investing in dependable infrastructure and technical assistance. Teachers also said that students struggle to comprehend the technical parts of LMS software because it is their first time using it and they are apprehensive to utilize such technology (Jumani et al. 2018). To properly integrate blended learning, a solid technical infrastructure is required, which includes reliable internet connectivity and access to digital devices. Educational achievement inequality can be exacerbated by variations in students' access to technology from varied socioeconomic backgrounds.

5. Digital Literacy Skills in Blended Learning

Internet and ICT proficiency is seen as a new type of literacy. In the twenty-first century, it has begun to become a precondition for full social participation. Martin (2006) states "Digital literacy is the awareness, attitude, and ability of individuals to appropriately use digital tools and facilities to identify, access, manage, integrate, evaluate, analyze and synthesize digital resources, construct new knowledge, create media expressions, and communicate with others, in the context of specific life situations, to enable constructive social action; and to reflect upon this process."

Challenges to Digital Literacy Skills in Blended Learning

A challenge that was presented using blended learning is the digital literacy of teachers and students. According to Woo and Wang (2022), teachers struggle to properly incorporate technology into their teaching practices, while students may lack the necessary skills to navigate online platforms and critically assess digital material. Students' lack of literacy towards the use of technology will affect time management, making it difficult for them to give feedback on the lectures on time (Sander & Altman. 2023). To solve this issue, educators and students must engage in targeted training and professional development programs to increase their digital literacy skills. Digital literacy is essential for both teachers and students. Certain abilities are required for online learning, such as successful communication in the learning environment and using digital tools (Evers, 2021).

5. Equity and Accessibility in Blended Learning

With blended learning, everyone can learn from the same resource. Personalized education and fair opportunities for a variety of student populations are two ways that blended learning can promote equity (Foster, 2017)

Challenges towards Equity and Accessibility in Blended learning

Blended learning has the potential to worsen existing educational accessibility disparities. Students from underserved communities or with disabilities may have difficulty accessing online resources and participating in virtual classes. Addressing equity and accessibility issues requires proactive measures such as subsidizing technology resources and ensuring that digital material is inclusive and fulfils accessibility standards. Another common theme across articles is the issue of unequal access to technology and internet connectivity, there is a need to stress the unequal access to digital resources, notably for rural and economically disadvantaged places, which may limit the working of blended learning (Alvarez Jr, 2020). Inadequate technical assistance, as well as access difficulties, have the potential to undermine blended learning's flexibility and inclusivity (Roy & Chetty, 2023).

Conclusion and Recommendations

1. Adult learners pursuing adult and continuing education ought to receive detailed instruction on how to use the various technologies used for blended learning.
2. Teachers need training in technological skills to be competent in using the Blended Learning Approach. Barber and Moushed (2007) claim that the 21st century may provide a problem for instructors because the bulk of today's teachers were not educated to teach 21st-century learners (William, 2018). As a result, instructors must be specialists and knowledgeable about teaching the skills to motivate pupils to thrive in their studies (William 2018)
3. Digital Literacy is necessary in the 21stcentury, with every teacher and student being able to utilize technology for obtaining knowledge, communicating information, and having the ability to use all technologies. Gilster (1997) in supporting digital and learning literacies teachers should

attempt to design flexible learning opportunities, review how technologies are integrated into the curriculum, support students to make use of technologies, and develop effective strategies for learning with technology (Williams, 2018)

4. In terms of, internet connectivity, it was determined that the government need to take the initiative and provide various initiatives to aid in the seamless operation of blended learning.

In the recent years Blended Learning has proven to have been a significant approach to teaching learning. But the challenges and obstacles are still very persistent. Thus, along the way there is need to remove these challenges. to enable students to learn through this approach. This will further make teaching learning accessible as well as make students get an opportunity to learn through newer approach and make them independent learners.

References

Alvarez, A.J. (2020). Learning from the problems and challenges in blended learning: Basis for faculty development and program enhancement. Asian Journal of Distance Education, 15(2). 112-132. https://www.asianjde.com/ojs/index.php/AsianJDE/article/view/433.

Barber, M., and Mourshed, B. (2007). How the best performing schools come out on top. London: McKinsey Group. https://www.mckinsey.com/industries/education/our-insights/how-the-worlds-best-performing-school-systems-come-out-on-top

Behjat, F., Yamini, M., & Bagheri, M. (2012). Blended learning: A ubiquitous learning environment for reading comprehension. International Journal of English Linguistics, 2(1), 97-104. https://doi.org/10.5539/ijel.v2n1p97

Bourqaiba, H. A. (2023). Blended learning as an innovative approach in adult education: overview and overlaps. Korean Journal of Physiology and Pharmacology, 27(3). 1-15. http://kjppor.com/index.php/kjpp/article/view/211/153.

Bohle Carbonell, K., Dailey-Hebert, A., & Gijselaers, W. (2013). Unleashing the creative potential of faculty to create blended learning. The Internet and Higher Education, 18, 29-37. https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2012.10.004

Cooney, M.H., Gupton, P., & O'Laughlin, M. (2000). Blurring the

lines of play and work to create blended classroom learning experiences. Early Childhood Education Journal, 27(3), 165-171.

Chatterjee, T. (2024). 9 Key Challenges of Implementing Blended Learning Programs and Ways to Mitigate Them. https://blog.commlabindia.com/elearning-design/blended-learning-implementation-challenges-solutions.

Chen, M., Wang, Z., Liang, L., Ma, Z., & Liu, Y. (2023). Typical Practical Cases in Blended Learning. In Handbook of Educational Reform Through Blended Learning (pp. 231-378). Singapore: Springer Nature Singapore.

Donnely, R. (2010). Harmonizing technology with interaction in blended problem-based learning. Computers & education, 54(2), 350-359.

Evers, L. (2021). 3 Challenges for blended learning in adult education. https://www.blink.it/en/blog/blended-learning-adult-education.

Foster, P. (2017, March 29). How Blended Learning Can Promote Equity and Inclusion. https://partners.pennfoster.edu/blog/2017/march/how-blended-learning-can-promote-equity-and-inclusion

Gilster, P. (1997). Digital Literacy. John Wiley & Sons, Inc.

Greer, D., Rowland, A. L., & Smith, S. J. (2014). Critical Considerations for Teaching Students with Disabilities in Online Environments. TEACHING Exceptional Children, 46(5), 79-91. https://doi.org/10.1177/0040059914528105

Guzer, B., & Caner, H. (2014, February 21). The Past, Present and Future of Blended Learning: An in-depth Analysis of Literature. Procedia- Social and Behavioral Sciences,116, 4596-4603. DOI:https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.992https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281401009X.

Herold, B. (2016). Technology in Education: An Overview. Education Week.https://www.edweek.org/technology/technology-in-education-an-overview/2016/02.

Jumani, N.B., Malik, S., & Akram, H. (2018). Challenges and Success of Blended Learning in Directorate of Distance Education. IIIUI. Pakistan Journal of Distance and Online Learning. IV (II), 143-156. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1267032.pdf.

Kapinga, B., & Mtani, M. (2014). Challenges Faced by Adult Learners Enrolled in Blended Distance Learning Programmes: A Case Study of the Institute of Adult Education. Huria: Journal of the

Open University of Tanzania. 18, 100-106. https://www.ajol.info/index.php/huria/article/view/118921.

Kocour, N. (2019). How Blended Learning Impacts Student Engagement in an Early Childhood Classroom. https://nwcommons.nwciowa.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1137&context=education_masters

Martin, A. (2006). A EuropeanFramework for Digital Literacy. Nordic Journal of Digital Literacy, 1, 151-161.

Muhria, L., Supriatna, N., & Nurfirdaus, N. (2023). Students' Challenges of Blended Learning Model in Higher Education. Journal Corner of Education, Linguistics, and Literature (JCELL), 2 (3), 223-233. https://doi.org/ 10.54012/jcell.v2i3.123.

Osguthorpe, R.E., Graham, C.R. (2003). Blended learning environments. Definitions and directions. The Quarterly Review of Distance Education, 4(3), 227-233.

Rahman, &Ariawan, Vina & Pratiwi, Inne. (2020). Digital Literacy Abilities of Students in Distance Learning. 10.2991/assehr.k.201215.092.

Raouna, K. (2024, December 16). What is blended learning: Why it matters and how to apply it. eLearning Strategies. https://www.learnworlds.com/blended-learning/

Rivera, J.H. (2017). The Blended Learning Environment: A Viable Alternative for Special Needs Students. Journal of Education and Training Studies, 5, 79-84. http://jets.redfame.com.

Roy, S., & Priya C. (2023, Nov 10). Challenges for Blended Learning in Higher Education. Knowledge Tank; Project Guru. https://www.projectguru.in/challenges-for-blended-learning-in-higher-education/.

Sanders, J., & Altman, A. (2023, March 17). Challenges of Blended Learning. DOI: http://dx.doi.org/10.22541/au.167907574.46177596/v1.

Sweeney, M. (2022, February 16). Blended Learning: The future of higher education.https://www.citrix.com/blogs/2022/02/16/blended-learning-the-future-of-higher-education/

UNESCO Institute for Education. (1997). Adult education: the Hamburg Declaration; the Agenda for the Future. International Conference on Adult Education, 5th, Hamburg, Germany, 1997. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000116114

Williams, M. (December 2018). Exploring Teachers' Attitudes to Implementing Blended Learning: A Case Study.https://core.ac.uk/download/226773314.pdf.

Woo, D., & Wang, Y. (2022). Digital Literacy Skills for Exam-Oriented, Pandemic Schooling: A Mixed Methods Study of Students' Authentic Performance. https://osf.io/preprints/edarxiv/dje57.

Yusof, A. M., Daniel, E.G.S., Low, W.Y., & Aziz, K. (2011). Teachers' Perceptions on the Blended Learning Environment for Special Needs Learners in Malaysia: A Case Study. 2011 2nd International Conference on Education and Management Technology. 13. 29-33.https://www.researchgate.net/profile/Wah-Yun.

Zavaraki, E. Z., & Schneider, D. (2019). Blended Learning Approach for Students with Special Educational Needs: A Systematic Review. Journal of Education & Social Policy, 3. 75-86. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/.

Vanessa Vera Khriam
Research Scholar
Department of Education,
North-Eastern Hill University
Shillong

Dr. Rihunlang Rymbai
Associate Professor
Department of Education,
North-Eastern Hill University
Shillong

❑ ❑ ❑

Assessment of Channel Shifting, Bank Erosion and Deposition of Gangadhar River At Dhubri District, Assam Using Remote Sensing and GIS

Hasne Toufiki • B.S. Mipun • Sourabh Dutta

The Gangadhar River has greatly benefited the inhabitants of Dhubri District in a variety of ways including natural, cultural, ecological etc. However, due to changes in both quantity and quality over the past few years the river has found itself in a precarious predicament. While in -situ research and experimentation can be expensive the analysis of images from Landsat needed for remote sensing and geographic information systems offers a low-cost method of calculating bank erosion and channel shifting over time and space. Here the researcher used remote sensing and GIS technique to examine the Gangadhar River's Channel shifting, bank erosion, and deposition throughout time and space. In order to determine the channel shifting, erosion and deposition rate during a certain time period, a spatio-temporal analysis of the Gangadhar River using very High-Resolution satellite images between 1990 to 2020 is conducted. The finding shows that the area of channel shifting, erosion and deposition vary both spatially and temporally. However, channel shifting was more dominant from the year 1990 - 2020. The total east bank shifting in the year 1990-2000 is 5.56 km2 and west bank shifting is 3.48 km2. In the year 2000-2010 channel shifting is 2.65 km2 for east bank and 5.09 km2 for west bank. In the year 2010-2020 channel shifting is 1.83 km2 for east

bank 1.88 km2 for the west bank. Regarding erosion and deposition for the year 1990-2020 the data reveals that the total erosion was 18.09 sq km and deposition was 13.54 sq km. Understanding these studies will aid in determining the fluvial systems morphological response at Dhubri District and elsewhere. Consequently, the results of these study will allow Dhubri subdivisions' Central water resource and other organization to identify the actual site that has been badly impacted by erosion and deposition as well as the area that has experienced significant river channel shifting.

Keywords : *Gangadhar river, Channel Shifting, Erosion, Deposition, Remote sensing, GIS.*

1. Introduction

Channel shifting, bank erosion and deposition are the two main geomorphic processes in the fluvial system (Saleem et al., 2019). Channel shifting, bank erosion and deposition affects almost every country in the globe, resulting in varied degrees of landscape deterioration as well as negative effects on the ecosystem and the society(Das et al., 2017).In addition to the results of these studies being applicable in the fields of hydro-technical works, environmental protection, and the management of water and soil resources, understanding the mechanisms and rates of bank erosion, accretion and lateral channel migration has fundamental significance (LOVRIC & TOSIC,2016., Thorne, 1982., Lawler, 1993). Different levels of land degradation are caused by bank erosion in addition to river flow modifications. Because it is linked to human relocation, the loss of agricultural fields, and means of subsistence, it has a significance influence on peoples socioeconomic and ecological existence (Dutta et al., 2020). In the state of Assam, flood and bank erosion caused by the Brahmaputra and its tributaries are frequent natural disasters that occur throughout the rainy season (Dutta et al., 2020). The damages resulting from these are permanent for the local population (Das et al., 2017). Loss of a home, farmland, employment and assets are the short-term socioeconomic effects (Das et al., 2017) where as long term socioeconomic include direct impact on the quality of life of the affected people and indirect impact on their psychological growth and health, that often covers things like accumulation of human capital which includes the education of the

children, health status of mother and children (Wisner et al., 2003). Though the process of channel shifting, erosion and deposition are common in Assam. Being a floodplain, these activities are more prominent here. Loss of agricultural land and population displacement are attributed, in large part, to severe erosion. (Thakur et al., 2012). Major factor influencing channel stability is bank erosion and channel shifting. Even though millions of people have lived alongside river for generations, regular bank shifting brought on by anthropogenic activities and natural factors like flood is one of the main reasons for Assam's land degradation and property damage. Since 1950, Assam, a predominantly plain state in north east India has experienced significant river bank erosion. In 2014, the loss of 12.6 thousand hectares of land caused 7,78,000 people to be displaced (GOA, 2014). (Goswami, 1985) Due to erosion from river banks, Assam lost almost 7.4%of its entire land till 1985. According to Phukun et al (2012) the Brahmaputra River destroyed almost km of land and uprooted over 25000 settlements between 1960 and 2008. From the year 2001-2014 nearly total of 60849.83 hectares of land was eroded,2839 villages affected,197008 family affected and 22990.79 in crores of value of property lost due to bank erosion (Dekaraja & Mahanta, 2021). One of the Assam's district that is most severely impacted by flood and erosion is Dhubri district (GOA, 2015). While in Dhubri district the total length eroded was 40.19 km and the total area eroded in the district was 0.0016 million hectares (Dekaraja & Mahanta, 2021). As the Ganges-Brahmaputra system is predicted to experience a rise in risks associated with water as a result of increased river flow including bank erosion (Ikeuchi et al., 2015). Understanding, the kind space, and reason behind channel change is crucial for reducing the danger of flooding, protecting the environment and laying the ground work for forecasting how a river will evolve in the years to come.

In the past few decades, numerous researchers have studied the geographical phenomenon of river bank erosion and channel shifting all over the world. In the 21st century, GIS and Remote sensing have become crucial tools for detecting changes in rivers and instances of bank erosion (Das et al., 2017). Yang (1996) and Yang et al (1999) employed RS and GIS to process a set of time sequential Landsat images taken over a 19-year span. A systematic examination of the spatio temporal changes channel centerlines and river banks was conducted and an attempt was made to corelate

these results with relevant human and natural events influencing the delta. Patil et al., (2008) conducted a study on Majuli river bank erosion. A map of erosion and deposition was created; by using satellite data from 1991,1997 and 1998, they were able to observe the patterns of erosion in an area of about 11km near Kaniajan village. Kotoky et al., (2005) has investigated the nature of bank erosion in assam, India along the Brahmaputra River channel. Dutta et al., (2020) utilized GIS and RS to examine bank erosion caused by the Jia Bharali River and its effects on Tezpur Town's Panchmile Area. Based on the a forementioned research, two of the most advanced instruments for environmental deterministic research studies are GIS and RS. The identification of spatio temporal variations in shifting and river bank erosion is facilitated by the use of these two advanced technologies. Numerous studies have been carried out utilizing cross-section date from observations as well as geographic and stratigraphic records to evaluate Ganga (Dewan et al., 2017) and the Brahmaputra (Sarker et al., 2014, Baki and Cran, 2012). Which are the major rivers of India. Compared to these less studies have been conducted for the tributaries which flow to the Brahmaputra River. The tributaries also play a very important role in the transforming hazard in the area. The Gangadhar river is an important tributary of the Brahmaputra River flowing though the western most side of Dhubri District. The river plays a very important role in the hydrology, geomorphology and geology of the district. For the resident of Dhubri region, the Gangadhar river serves as their lifeline. Streams riparian zones, marshes and various other habitats are provided for live biota downstream by it. Due to their reliance on fishing and agriculture for a living, the local value the river both environmentally and commercially. Floods and bank erosion ravage the river every year, making the construction and repair of embankments appear to be a permanent project (Final Feasibility report of River Gangadhar Assam,2018). Here in this study of channel change and bank erosion become an urgent necessity. Therefore, the study aimed to identify the spatio-temporal channel shifting, bank erosion and deposition with the help of GIS and Remote Sensing using Satellite images of Gangadhar river for the year 1990, 2000, 2010, and 2020 about 10 years apart. Thus, the objective of the study is (i) to study about the channel shifting of the Gangadhar river. (ii) to study about the bank erosion and deposition of the Gangadhar river.

2. Study Area:

Dhubri, a district of Assam, is located at the western part of the state; near the Indo- Bangladesh border. The district has a total area about 1553 sq. km. Dhubri district is a flood plain drained by the Brahmaputra River and its tributaries. The major tributaries are Gangadhar, Tipkai, Champabati and Gaurang. The study area is the Gangadhar river which is a north bank tributary of the river Brahmaputra. It is located from 26°20'N 26°0'N to 89°50.0' E to 89°50' E. The River Gangadhar is originated from the Masang-kang glacier in Himalayan region and its flows towards Dhubri District. It flows southwest through the district. Length of the river channel is 50.89 km and the total area covered by the river is 20.16 sq km which flows through Dhubri and meets river Brahmaputra at south of Dubipara near Indo-Bangladesh Border. The total catchment area of the river is 441 sq km in the year 2020.The average slope is 81.49 cm/km, the average discharge is 201.44 Cum/sec and the average water velocity range nearly around 0.08m/s (Final Feasibility report of River Gangadhar Assam, 2015). The average width of the river is approximately 1.8km, the maximum width is 2.67km which is found near Belguri and the minimum width is 0.3km which is located between Lohajan and Kumarganj. Fig 1: shows the map of the study area.

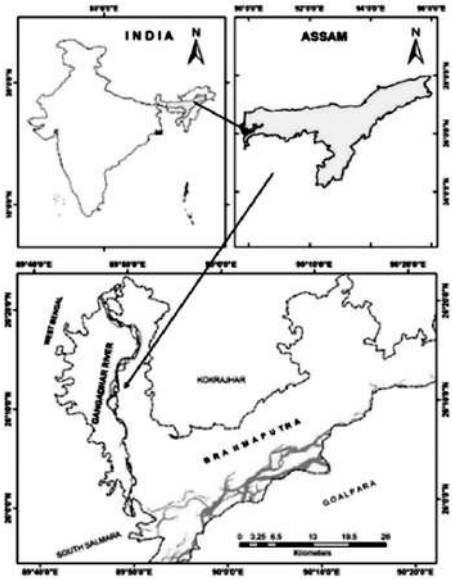

Fig 1: shows the map of the study area.

3. Data Base

Study of channel shifting and bank erosion by the river Gangadhar of Dhubri District is carried out by using GIS and Remote sensing technique. In addition to it three-month field survey and work was carried out by the researcher in the study area in 2023 to determine the location of the river boundary and to gather information from the local people and through survey schedule and self-observation to check the validity of the satellite data with ground data. The use of Remote sensing satellite imagery facilitates the identification of landscape change particularly in relation to spatio- temporal aspect. These techniques minimize the need for traditional human methods and equipment and require less time.

The details of the Database and their source of extraction was given in the following table: -Table:1

Year	Data type, Source	Wavelength in micrometer	Date of capture	Date of data collection
2020	Satellite image of Band 3-Red, Band 4 (NIR) Band 5 shortwave inerrant (SWIR)	0.77-0.90 0.77-0.90 1.55-1.75 Resolution in meter 30	6 April	18 Aug 2023
2010			5 June	23 Sep 2023
2000			19 April	18 Aug 2023
1990			5 August	22 Aug 2023

Source: - USGS- Earth Explorer (2023)

Beside these The Assam Tribune, journals, newspaper, reports and other published media stories are among the publications that are taken into account for the study in addition to the 2011 census of Dhubri district. 13 sites across the reach, both on the left and right bank were visited and the number of areas of bank erosion, deposition, channel shifting was evaluated. In addition to these interviews and discussions were held with the local people for better understanding of the social issues and damages.

Methodology:

The Methodology used is shown in the following chart.

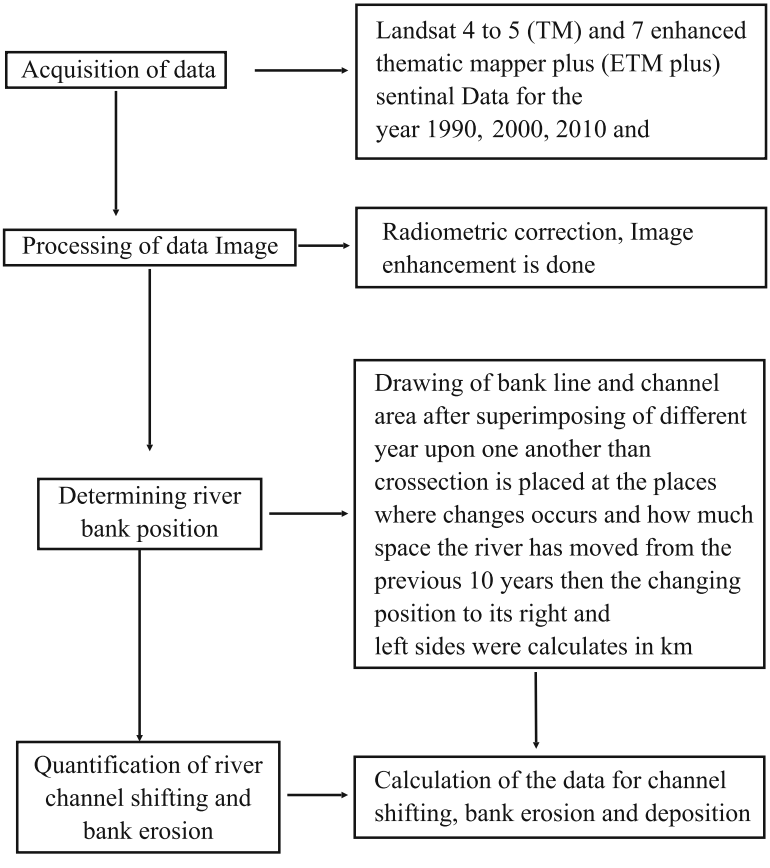

Fig: 2 shows the methodology of the study area

The images of the Gangadhar river for the year 1990, 2000, 2010, 2020 were extracted from satellite image of for different Landsat 4 and 5 (TM) and 7 Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+) of band 3-Red Band 4 (INR) and Band 5 short wave infrared (SWIR) of resolution 30 meters wavelength in 0.45-0.52, 0.77-0.90, 1.55-1.75 mm. For correcting of Line striping Error of the Landsat 7 for the year 2010 software Erdas Imagine 9.2 is considered. Focal Analysis processed unsigned 8 bits for 6 times. The output was

maximum clear including the study area. The objectives of image classification are to identify and portray as a unique gray level (or color) the features occurring an image in term of the object or type of land cover these features represent on the ground.

After performing the LULC classification selection of River polygon is done one by one and all the polygon were merged for drawing the considerable river. Then the area of the river is calculated with the help of ArcGIS 10.8. To identify the changes and detection of channel shifting the river of different years were superimposed upon one another. After superimposing the river flow in 2020 above the river flow in 1990 we get the clear picture of the change of the river throughout the past 30 years. With the help of superimposing of one image over another i.e. 1990 and 2000,2000 and 2010, 2010and 2020 we are able to detect the changes of the river by 10 years apart. Then to find out the amount and places of channel shifting a cross section has been drawn at the places where change has been observed and given name as A, B, C, D etc. Then how much space the river has shifted and in which side was calculated based on the previous 10 years (1990) to next 10 years (2000). And for calculating the spatial bank erosion and deposition the same process which was used for calculating Channel shifting. The temporal bank erosion and deposition was done using field calculator. In the field calculator:

Erosion = Area of previous year – Unchanged area

Deposition = Area of the next year – Unchanged area. While making the layouts other components like year wise transition of river channel, index etc. are also kept under consideration.

Result and Discussion

Since 1990, the study area has experienced severe bank erosion by the river Gangadhar which has caused loss of flood plains, homes, cultivable land, domestic animals and crops. Erosion caused by the Gangadhar river has engulfed huge area near national highway 31 due to which more than 80 families are forced to take shelter in relief camps. Villages in the Agomoni Circle was badly affected. The Koimari part-I has been affected where more than 50 families were forced to be evacuated. Erosion from Choto Guma to Binna Char has uprooted 100 of families in the past few

years. Severe bank erosion was near Belguri and Moisa area which became top most concerned of the Dhubri divisional water resource department. The channel shifting, erosion and deposition throughout the river channel was not uniform. With the help of cross section study at the places where major and minor changes have been noticed, the shifting of river was marked. These channels shifting took place because of avulsion and other due to soil properties, geology, structure, tectonic activities, high discharge, precipitation and mainly because of human activity.

Spatio-Temporal channel shifting of Gangadhar River from 1990-2020 (last 30 years)

The spatial pattern of channel shifting of the river Gangadhar from the year 1990-2000 is shown in the following figure:3

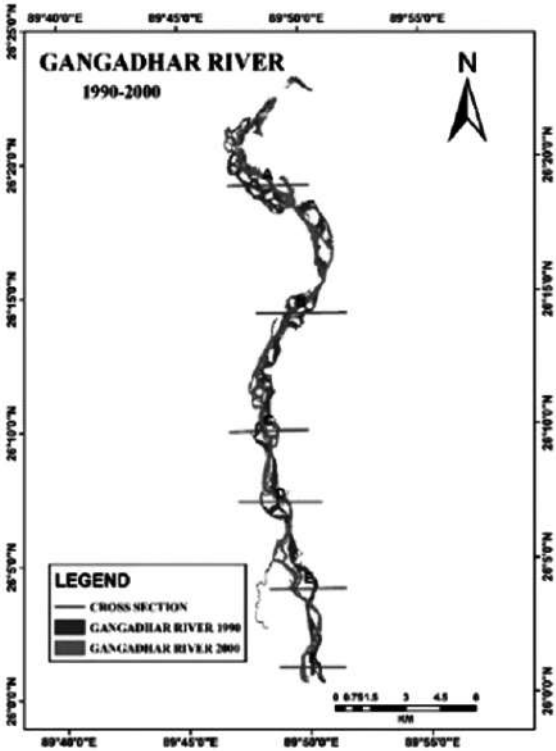

Fig-3

The highest channel shifting in the river Gangadhar between the year 1990-2000 was 2.689 square km which was marked by cross section D. At cross-section D and C during the period (1990-2000), shifting was found on both the banks 1.774 sq km and 0.469 sq km in the east bank and 0.912 sq km and 0.516 sq km in the west bank. The base year was taken as 1990 bankline from which the measurement was done on both sides to find out the channel shifting of the river. The lowest shifting was found in the East bank of the river at the cross-section of which was 0.704 sq km. It can be marked that channel shifting was more prominent in the east bank than the west bank from 1990-2000. The total channel shifting for the year 1990-2000 was 5.557 sq km (East bank) and 3.478 sq km (West bank)

Channel Shifting of the Gangadhar river from the year 2000-2010 is shown following figure:4

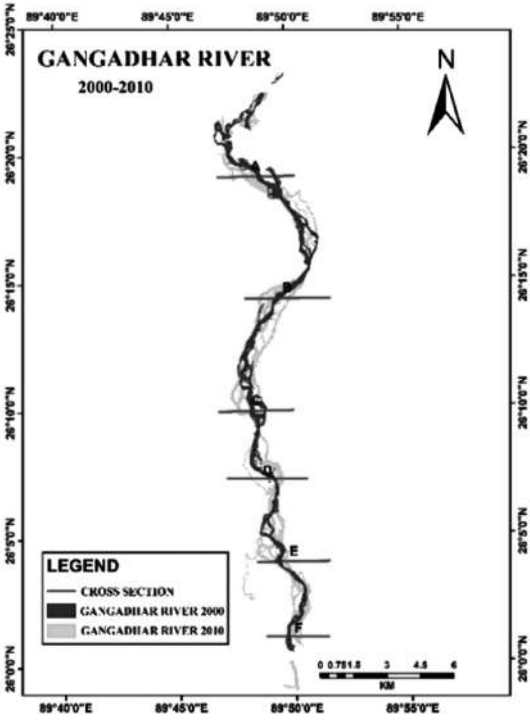

Fig-4

The highest channel shifting in the river Gangadhar between the year 2000 - 2010 was 2.041 square km which was marked by cross section B. It lies at the right bank of the river. At cross-section B, C and E during the period (2000-2010), shifting was found on both the banks 0.834 sq km, 0.613sq km and 0.611 sq km in the east bank and 1.207, 1.155 sq km and 0.611 sq km in the west bank. The base year was taken as 2000 bankline from which the measurement was done on both sides to find out the channel shifting of the river. The lowest shifting was found in the East bank of the river at the cross-section F which is 0.595 sq km. It can be marked that channel shifting was more prominent in the west bank than the east bank from the year 2000 - 2010. The total channel shifting for the year 2000-2010 was 2.653 sq km (East bank) and 5.099 (West bank).

Channel Shifting of the Gangadhar river from the year 2010-2020 is shown following figure:5

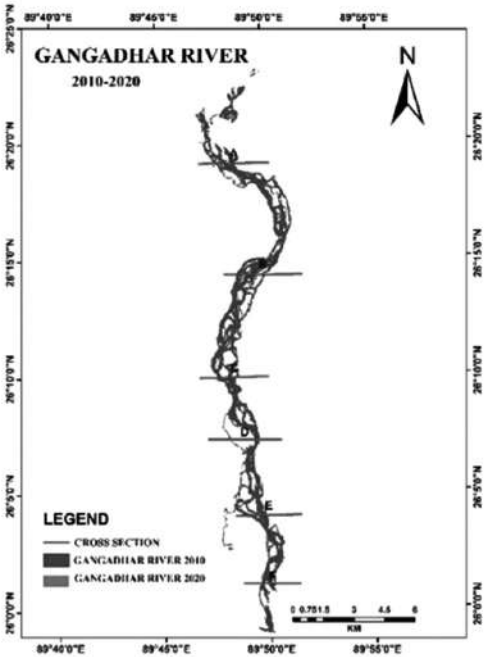

Fig-4

The highest channel shifting in the river Gangadhar between the year 2010 – 2020 was 0.914 square km which was marked by cross section E. It lies at the west bank of the river. The base year

was taken as 2010 from which the measurement was done on both sides to find out the changes of channel shifting. The lowest shifting was found in the east bank of the river at the cross- section D which is 0.246 sq km. It can be marked that channel shifting was more prominent in the West bank than the East bank from 2010 - 2020.

The temporal pattern of channel shifting from 1990-2020 (30 years)

River	Period of bankline shifting	Bank	Average extent of bank line shift (m)		Net Progressive shifting (m)
			Progressive shifting	Regressive shifting	
	1990-2000		3062.86	3209.40	–146.56
Gangadhar	2000-2010	west	4414	4368	46
	2010-2020		2493	1200	1293
	1990-2020		3032.54	726	2607.54
	1990-2000		–	–	
	2000-2010	east	–	–	
	2010-2020		782	1222	440
	1990-2020		268	1058	–790

The temporal shifting of the Gangadhar river from1990-2020 is shown in the following table : 2

It is evident from the table: 2 that the progressive shifting of west bankline of the river enhanced by erosion during 1990-2000 by 3062.86 m and the regressive shift is 3209.40 m, there by arising a net progressive shifting of -146.56 m. In the East bankline there is 0 progressive and regressive shifting. The Overall progressive shifting is 194 m. During the year 2000-2010 the progressive shifting of

west bankline of the river is 4414 m and the regressive shifting is 4368 m there by arising a net progressive shifting of 46m. In the East bankline there is 0 progressive and regressive shifting. The Overall progressive shifting is 168.9 m. The progressive shifting of west bankline of the river enhanced by erosion during 2010-2020 by 2493 m and the regressive shift is 726 m, there by arising a net progressive shifting of 1293 m. In the East bankline there is progressive shifting of 782 m and regressive shifting of 1222 m and causing a net progressive shifting of 440 m. The Overall progressive shifting is 215.3 m. Considering the entire period of study on bank line shifting for a period of 30 years from 1990-2020 the west bank undergoes a progressive shifting of 3032.54 m and regressive shifting of 726, thereby giving a net progressive shifting of 2607.54m. The East bank undergo a progressive shifting of 268 m and regressive shifting of 1058 m, thereby giving a net progressive shifting of -790 m. The Overall progressive shifting is75.05m. From the data and the figure of the last 30 years it is clear that continuous channel shifting was observed in the Gangadhar river of the study area. The table shows that the Gangadhar river is continuously shifting towards west since last 30 years (1990-2020).

Bank Erosion

The bank erosion and deposition of the river Gangadhar for the last 30 years (1990 – 2020) is shown in the following figures:

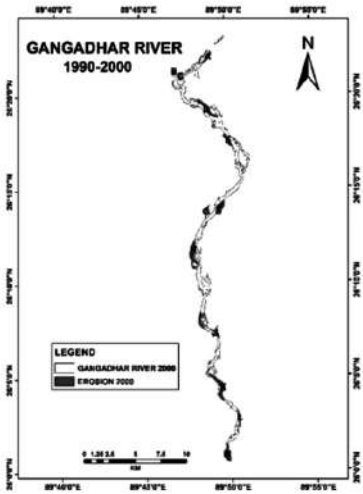

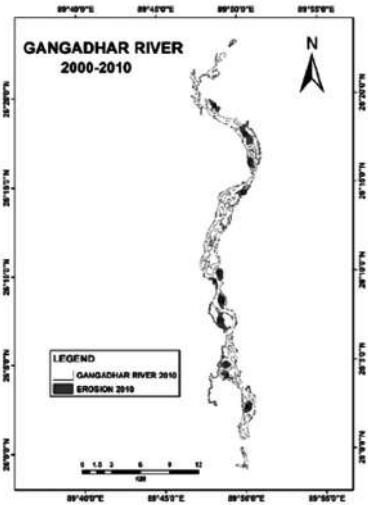

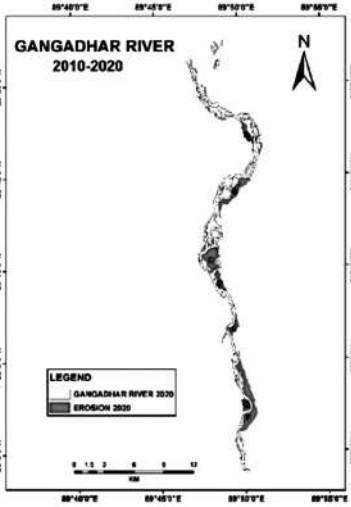
GANGADHAR RIVER
2010-2020
N
LEGEND
GANGADHAR RIVER 2020
EROSION 2020
0 1.5 3 6 9 12
KM

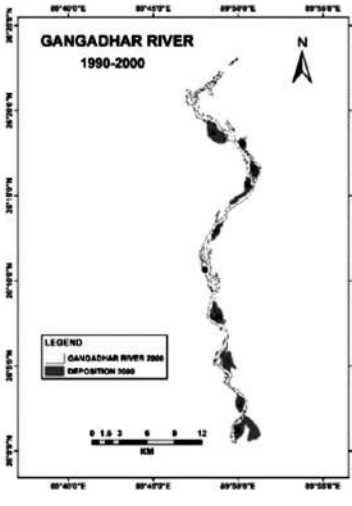
GANGADHAR RIVER
1990-2000
N
LEGEND
GANGADHAR RIVER 2000
DEPOSITION 2000
0 1.5 3 6 9 12
KM

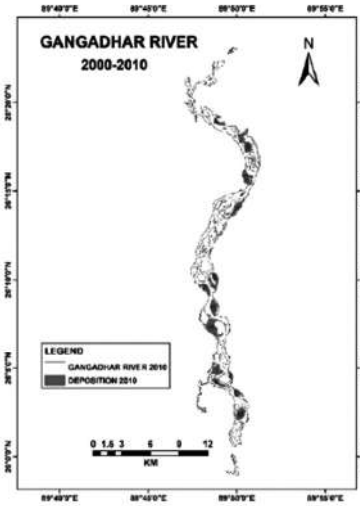
GANGADHAR RIVER
2000-2010
N
LEGEND
GANGADHAR RIVER 2010
DEPOSITION 2010
0 1.5 3 6 9 12
KM

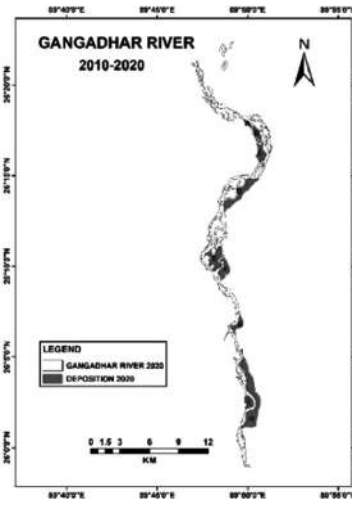
GANGADHAR RIVER
2010-2020
N
LEGEND
GANGADHAR RIVER 2020
DEPOSITION 2020
0 1.5 3 6 9 12
KM

The table : 3 shows the rate of erosion and Accretion of the Gangadhar river from the year 1990-2020.

Year	Previous 10 years (sq km)	Next 10 years (sq km)	Unchanged area (sq km)	Erosion (sq km)	Accretion (sq km)
1990-2000	24.71	20.03	6 April	17.78	13.10
2000-2010	20.03	32.20	5 June	9.48	21.65
2010-2020	32.20	20.16	19 April	22.48	10.44
1990-2020	24.71	20.16	5 August	18.09	13.54

Source : Computed by the researcher.

Form the table 3 it is clear that highest erosion is observed in the year 2010 – 2020 which is 22.48 sq km and the highest deposition is calculated in the year 2000 – 2010 which is 21.65 sq km. The data reveals that there is continuous erosion and deposition by the river since 1990 – 2020. The total area of the Gangadhar river in the year 1990 was 24.7 sq. km and the length of the channel was 54.51 km and currently in the year 2020 the total area covered by river is 20.16 sq. km and length of the river channel is 50.89 km. The total area and length of the channel has reduced by 4.54 sq. km and the length of the channel decreased by 4.62 km. Channel shifting, bank erosion and deposition was the main cause leading to reduction in channel area and length.

The places which are highly vulnerable to channel shifting and bank erosion by the river Gangadhar are Paschim Konuri village, Pub Konuri village, Kaldoba, Koimari and Tamarhat area of Dhubri district. In Agomoni and the surrounding areas severe channel shifting and bank erosion was linked to the loss of homes, arable lands, domestic animals, poultry etc. The field survey report states that in addition to the damaged caused by the bank erosion and deposition since past 30 years 20-25 small communities were completely destroyed about 15 households lost their homes partially or fully to bank erosion in 2023 flood along with large number

of animals like goat, cow, poultry as well as agricultural fields. Almost 7.71sq km agricultural land have been lost till date. The Gangadhar river under the Binnachara Gram Panchayat has partially wiped out more than six villages and entirely obliterated villages such as Namagaon, Satirpar, Sarkar tila and Majergaon. Over 700 households have already been relocated and nearly 13.33 sq km of land have been eroded in this location. In Paschim Ratiadhar Pt. ll, the Gangadhar river has eroded much of the area of the village, leaving only a little portion above ground. After being uprooted from their ancestral land, they were relocated to nearby towns, villages or build huts on sandbars or embankments. There, they have encountered a variety of difficult situation, such as changing family dynamics or experiencing a decline in their standard of living as a result of losing their primary source of income as most of the people depend on agriculture. They also often become extremely poor and attempt to find new occupation in order to survive, and occasionally they are treated as illegal immigrants which further isolate then from society and creates a severe socio-economic environment. Being a floodplain through which the river flows the geology of the area is consist of mainly newer alluvium which provide more scope for bank erosion when the discharge is high mainly during the monsoon period. River bank failures occur frequently, which contributes to high rate of bank erosion in the study area. The river channel is highly unstable due to the heavy weight of sediments it carries across flat terrain with quickly eroding banks. A portion of the river bed experiences scouring, while another portion experiences deposition. While depositional activities promote regressive movement of bank lines, erosional processes promote progressive shifting. The river becomes widened by erosion, and the channel gets pushed by deposition, which causes erosion on the opposite side. The river bank is predominantly composed of gravel, sand, silt and a very little amount of clay due to which the banks are not stable and easily receptive to erosion, bank slumping, toe erosion and shear failure. The sediment is high on the river because of the high erodibility of the bank material and the massive amount of sediment that has been collected from the upper catchment area. Massive volumes of silt are carried during high flow, and the river's ability to carry material decreases once the flood passes. Sediment deposition occurs in this way as bars and islands forms. River bank alteration is mostly caused by pushing the channel, which is mostly

accomplished via the construction of sidebars and midchannel bars. The most common type of bank failure appears to be shear failure of the top bank materials. The recent alluvium soil found on the banks is less compact and less cohesive which causes more frequent bank failure and shifting of the river. Increased sediment deposits as bars during receding flood water results in localized channel flow divergence and alterations.

Conclusion

Thus, the study results shows that channel shifting and bank erosion by the river Gangadhar has become a serious concern for the people living in the study area. There is continuous shifting on both the banks of the river but the shifting was more prominent towards the western bank. Massive floods, channel expansion, channel pattern alteration, bank erosion and deposition all contribute to the ongoing erosion and alteration of river banks. A significant problem that is growing yearly is the uprooting of residents from riverbank communities as a result of bank erosion. So, there is in need of immediate bank protection. Currently Geobags were placed in the bank of the river at Binnachara Part III near Indo- Bangladesh border in Dhubri district. But these is a small step in respect to the losses the people are facing since time immemorial due to river bank erosion. As most of the people depend on primary activity for their living and are not economically stable, they are facing huge problem of survival mainly during the monsoon period. Its is imperative that action be taken to lessen bank erosion and channel shifting. To lessen the issue of erosion and it negative effects various structural and non-structural adaptation solution should be promoted and expanded. The study will help the planners to visualize the channel shifting, bank erosion and deposition activities in the study area and help then to take necessary action for its mitigation.

References

Baki, A.B.M and Gan, T. Y. (2012): Riverbank Migration and island dynamics of the braided Jamuna River of the Ganges-Brahmaputra basin using multi-temporal Landsat images., Quaternary International,Vol.263,pp.148-161.doi:https://doi.org/10.1016/j.quaint.2012.30.016.

Cannon, T., Davis, I., and Wisner, B., (2003): At Risk: Natural Hazards, People's Vulnerability and Disasters. Taylor Francis, 134.

Das, K. T., Haldar, K.S., Sarkar, D., Borderan, M., Kienberge, S., Gupta, D, I., Kundu, S., Sapir-Guha, D., (2017); Impact of Riverbank erosion: A case study. Australasian Journal of Disaster and Trauma Studies, Vol. 21, Issue,2. URL http://trauma.massey.ac.nz/issues/2017-2/AJDTS 21 2 Das. Pdf

Dekaraja, D., and Mahanta, R., (2021): Riverbank erosion and migration inter-linkage: with special focus on Assam, India., Environ Syst Res, Vol.10, Issue, 6. doi: https://doi.org/10.1186/s40068-020-00214-0

Dewan, A., Corner, R., Saleem, A., RAHMAN, M. R., Haidee, M. R., Rahman, M, M., Sarker, M.H., (2017): Assessing channel changes of the Ganges-Padma River system in Bangladesh using Landsat and hydrological data. Geomorphology, Vol. 276 pp. 257-279. doi: https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2016.10.017

Dutta, N., Sonowal, G., and Thakuriah, G., (2020): A study on the Bank Erosion by the River Jia Bharali and its Impact on the Panchmile Area of Tezpur Town, Assam (INDIA)., International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology, Vol. 11, Issue, 12, pp. 2358-2367.

GOA., (2014) Information on Riverbank erosion and Population Displacement. Revenue and Disaster Management Department., Government of Assam. (Unpublished).

GOA (2015) Statistical Handbook of Assam 2015., Government of Assam, Government Press, Directorate of Economics & Statistics.

Goswami, C. D., (1985): Brahmaputra River Assam, India: Physiography, Basin denudation and channel aggradation., Water Resources Research, Vol. 21 Issue,7, pp: 959-978.

Hiroaki, Ikeuchi. et. al, (2015): Modeling complex flow dynamics of fluvial floods exacerbated by sea level rise in the Ganges-Brahmaputra-Meghna Delta., ENVIRONMENTAL RESEARCH LETTERS, Voi.10, Issue,12, 124011.DOI https://doi.org/10.1088/1748-9326/10/12/124011.

Inland Water Ways Authority of India (2018): Final Feasibility Report on Hydrographical Survey of Gangadhar River, Assam., Precision Survey Consultancy. https://iwai.nic.in.

Kotoky, P., Bezbaruah, D., Baruah, J., Sarma, J. N., (2005) Nature of Bank Erosion along the Brahmaputra River Channel Assam, India., Current Science, Vol. 88, Issue, 4, pp.634-639.

Lawler, D.M., (1993): The measurement of river bank erosion and lateral channel change: A review., Earth Surface Processes and Landforms, Vol.18, Issue,9, pp. 777-821.

LORVIC, N., and TOSIC, R., (2016): Assessment of bank erosion, accretion and lateral channel migration using remote sensing and GIS: Case study- Lower part of the Bosna River., Quaestiones geographical, Vol.35, Issue,1, pp. 89-92. doi:10.1515/quageo-2016-0008.

Mohamad, N., Khanan, A. F. M., Musliman, A. I., Kadir, W. H. W., Ahmad, A., Rahman A. Z.M., Jamal, H. M., Zabidi, M., Suaib, M.N., Zain, M.R., (2018): Spatio-temporal analysis of river morphological changes and erosion detection, using very high-resolution satellite images., IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, Vol.169, (012020).

Pati, J.K, Lal, J., Prakash, K., and Bhusan, R., (2008): Spatio-temporal shift of western bank of the Ganga River at Allahabad city and its implications., Journal of the Indian Society of Remote Sensing, Vol. 36, Issue,36, pp. 289-297.

Phukan, A., Goswami, R., Borah, D., Nath, A., Mailanta, C., (2012): River bank erosion and restoration in the Brahmaputra River in India., The Clarion-International Multidisciplinary Journal, Vol. 1, Issue,1, pp. 1-7.

Saleem, A., Dewan, A., Rahman, M.M., et al. (2020): Spatial and Temporal Variations of Erosion and Accretion: A Case of a Large Tropical River., Earth Syst Environ, Vol. 4, pp. 167-181(2020). doi https://doi.org/10.1007/s41748-019-00143-8.

Sarkar, M.H., Thorne, C.R., Aktar, M.N., Ferdous, M.R., (2014): Morpho-dynamics of the Brahmaputra-Jamuna River, Bangladesh., Geomorphology, Vol. 215, pp. 45-59.

Thakur, P.K. raveen., Laha, C., Aggarwal, S.P., (2012): Riverbank erosion hazard study of river Ganga, upstream of Farakka barrage using remote sensing and GIS., Natural Hazards, Vol.61, pp. 967-987.https://doi.org/10.1007/s11069-011-9944-z

Thorne, C.R., (1982): Processes and mechanisms of river bank erosion., In: Hey R.D., Bathrust J.C., Thorne C. R.(eds), Gravel Bed Rivers. Wiley, Chichester: 227-271.

Wisner, B., Blaikie, P., Cannon, T., & Davis, I. (2003): At risk: Natural hazards, people's vulnerability and disasters (Second edition). London and New York: Routledge.

Yang, X., (1996): Satellite monitoring of dynamic environmental change of the active Yellow river Delta, China., International archives of photogrammetry and remote sensing, Vol. XXXI, Part B7, pp. 801-806.

Yang, X., Damen, M.C.J., and van Zuidam, R.A., (1999): Satellite remote sensing and GIS for the analysis of channel migration changes in the active yellow river delta China., International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, Vol.1,Issue,2,pp.146-157.doi https://doi.org/10.1016/S0303-2434(99)85007-7

Hasne Toufiki

Research Scholar,

Department of Geography, The Assam Royal Global University, Betkuchi, Guwahati,

email-hasnetoufiki786@gmail.com, Phone No. 8761092811

B.S. Mipun

Professor and Dean

Department of Geography, The Assam Royal Global University, Betkuchi, Guwahati.

Sourabh Dutta

Assistant Professor

Department of Geography, Pub-Dikrong College, Laholial.

❑ ❑ ❑

Parenting, Peer Bond, Identity Formation & Non-Suicidal Self Injury

Dr. Vandana Gupta • Dr. Pratima Gond • Dr. Divya Singh

Non-suicidal self-injury behavior (NSSI) is a growing problem in adolescents that needs attention to prevent and treat the problem. The study aimed to test the role of parent-child relationships, peer bonding, and identity formation in predicting NSSI behaviors. A purposive sampling method was used to recruit the 104 school-going adolescents from Uttar Pradesh, India. A set of questionnaires, including parent-child relationship (Armsden & Greenberg, 1987), peer bonding (Klonsky & Glenn, 2009), identity formation (Rosenthal, Gurney & Moore, 1981), and NSSI behaviors (Klonsky & Glenn, 2009), were administered after informed consent from participants, parents, and schools.The correlation and regression results of the study were significant, revealing that parent-child attachment, peer bonding, and identity formation are strong predictors of NSSI behaviors among school-going adolescents. These findings have profound implications for the design of effective prevention and intervention programs for NSSI behaviors.

Keyword : *Non-suicidal self-injury behavior, Parent-child relation, Peer bonding, Identity formation.*

Introduction

Non-suicidal self-injury behavior (NSSI) is a socially unacceptable behavior that is gaining widespread attention in different cultures as well as in popular media. This growing problem is added in DSM-5 to research for more clarification and theory building to provide prevention programs and interventions. Common behaviors that characterize NSSI are cutting, burning, or hitting, scratching oneself to the point of bleeding, and interfering with healing. Studies have identified many risk factors of NSSI behavior, but more studies

are needed to explore the risk factors of NSSI (Bulat, Susac, & Ajdukovic, 2024; Zhong, Gu, & Cheng, 2024).

Previous studies have explored the various causal factors of psychopathic development in adolescents, in which parenting and peers are critical. Parenting shapes individuals' personalities across the lifespan. As children grow, peer group influence becomes prevalent during teenagers. Now, peers are a major source of guidance and support during adolescence (Guarnieri, Ponti, & Tani, 2010). Identity development is a lifelong process determined and influenced by various biological, psychological, and cognitive factors with societal norms. Identity formation is crucial in resolving the dialectic conflict between identity synthesis and confusion (Erikson,1968). Identity synthesis refers to reworking childhood identifications and defining a more self-determined, explored set of beliefs, values, and life goals. In contrast, identity confusion is a stage of inability to explore and identify a workable set of goals and commitments in life on which an adult identity is based (Gandhi et al., 2016).

Literature suggests that parental behavior is associated with the onset of NSSI and later NSSI. Study shows that poor parent-child relation is positively associated with a high level of negative emotions leading to NSSI behaviors among adolescents (Tao, Bi, & Deng, 2020). Positive parenting behaviors such as parental support and behavioral control are positively associated with more adaptive psychosocial functioning, such as self-regulation, competence, and academic achievement, whereas they are negatively associated with psychological dysfunction and externalizing problem behavior (Gatta et al, 2017). During adolescence, fathers often spend less time interacting with their children, preferring physical and outdoor activities. In contrast, mothers invest significant time and are involved in more caring activities and household interactions (Tao et al., 2020; Zhong et al., 2024).

A growing number of studies related to NSSI, parenting and peer influence show variant findings. Victor and Klonsky (2018) revealed that harsh punishment, poor-quality attachment, and low parental monitoring are linked to NSSI onset, while nonviolent discipline is not linked with the onset of NSSI. Results of peer difficulties, including social self-worth, competence, and peer

victimization, are linked with the future prevalence of NSSI behaviors. Poor peer support was positively associated with the onset of NSSI and continued over one year. At the same time, a low level of support from peer groups and romantic partners was associated with NSSI rather than with the new onset of NSSI (Guarnieri, Ponti, Tani, 2010). Victor and Klonsky (2018) state that adolescents who know about friends' NSSI are more likely to engage in NSSI behavior. Another study found that the onset of NSSI but not severity is associated with knowing a friend who engages in NSSI (Pitman et al., 2023).

Studies related to NSSI and identity formation show a direct link between identity synthesis and NSSI among adolescents (Claes, Luyckx, Bijttebier, 2014). Emerging research findings indicate that difficulties in developing a clear sense of identity were linked to a higher susceptibility to engaging in NSSI. In a sample of 532 high school students, NSSI was associated positively with identity confusion but negatively with identity synthesis (Gandhi et al., 2016). Zhong et al. (2024) revealed the mediating role of identity confusion between interparental conflict, harsh parenting, and the onset of NSSI. Indeed, during adolescence, parent, peer, and identity crises interact and determine the many developmental outcomes among adolescents and future behaviors. There is a lack of studies that have examined all these factors to test the NSSI behaviors. The present study focuses simultaneously on the role of the parent-child relationship, peer bonding, and identity formation in predicting NSSI behaviors of school-going adolescents. Previous studies have mainly been conducted on either clinical samples or mix-ups of nonclinical and clinical samples (Bulat et al., 2024).

METHOD

Participants

The study sample comprised 104 adolescents with NSSI selected through a purposive sampling method. Participants were randomly approached in different schools in Varanasi City, UP. The age range of the participants was 13 years old to 19 years. The mean age of NSSI adolescents was 15.77 (SD, 2.08). A total of 20 participants were boys (20.80%), and 84 were girls (87.30%). The education of all participants was between 9th to 12th standard

who were studying in various educational institutions of Varanasi city. 36 NSSI adolescents (34%) belonged to the upper class, 37 (35%) to middle, and 31 (29%) to lower socio-economic families. Similarly, 65 (62.5%) NSSI adolescents belonged to single-family, and 39 (37.5%) belonged to joint families.

Tools of measurement

1. **Parent-child relationship (IPPA-Inventory of Parent and Peer-Attachment, Armsden, & Greenberg, 1987)**

The inventory measure parent-child and peer-child attachment. Subscales of parent-child attachment with 50 items (25 for father-child relation and 25 for mother-child relation) were taken only in the study, which measured three significant domains of parent-child relationship including, degree of mutual trust (with ten items), quality of communication (with nine items), and extent of alienation in child toward parents (with six items). It is a five-point Likert scale that recorded responses as 1= almost never or never true to 5=almost always or always true. The reliability coefficient of the scale is 0.89.

2. **Peer bonding scale (Klonsky & Glenn, 2009)**

The peer-bonding scale was used to measure adolescents' relationships with their peers/friends. Peer-bonding was measured with the help of three items of peer-bonding given in the 'Inventory of Statements about Self-harm (ISAS)' developed by Klonsky and Glenn (2009). These items are "When I self-harm, I am … (1) … bonding with peers (2) … fitting in with others (3) … creating a sign of friendship or kinship with friends or loved ones. The responses are recorded on a three-point scale (0- 'not-relevant' to 2- 'very relevant') in which a score of zero indicates less bonding and six indicates high bonding with peers. The alpha coefficient of these items was 0.80.

3. **Identity formation (Erikson's Psychological Stage Inventory, Rosenthal, Gurney, & Moore, 1981)**

Identity formation in adolescents consists of 2 dimensions, namely, identity synthesis and identity confusion. Identity synthesis measures a self-determined set of ideals, values, and goals of adolescents. Reversely, identity confusion measures an inability to develop a workable set of goals and commitments.This inventory

recorded responses on a 5-point Likert scale ranging from 1- 'totally disagree' to 5- 'totally agree'. The score of this inventory ranges from 12 to 60. The Cronbach's alpha coefficient of the scale is 0.75 for identity synthesis and 0.63 for identity confusion.

4. **NSSI behaviours (Inventory of Statement about Self-Injury, Klonsky & Glenn, 2009).**

NSSI behaviors and their frequency are assessed with seven items related to behaviors and frequency of twelve specific NSSI behaviors over the lifetime, including cutting, burning, biting, pinching, banging, hitting self, carving, needle-sticking, rubbing the skin, swallowing chemicals, scratching, hair pulling, and wound picking on six response categories (1 incident, 2-4 incidents, 5-10 incidents, 11-50 incidents, 51-100 incidents, and more than 100 incidents). The alpha coefficient of the scale was found to be 0.92.

Procedure

After approval of this research proposal by the Departmental Research Committee (Psychology Department, Faculty of Social Science, Banaras Hindu University), work on data collection was started. Several ethical considerations were considered to ensure the dignity and integrity of research work. Verbal permission for data collection was obtained from participants' parents and schools. A written informed consent was obtained from each participant. Parents and participants were verbally informed about the purpose and process of the research. Only those willing to participate in the study were recruited for data collection. They were also told that they could willingly withdraw themselves from participation. It was said that their information and privacy are essential in research and were kept confidential in the study and report writing.

Results

The correlation results (Table 1) revealed that parental (mother and father) trust and communication are negatively associated with NSSI behaviors, and alienation is positively associated with NSSI. The results further suggested that peer bonding and identity confusion are significantly positive, and identity synthesis is negatively associated with NSSI behaviors.

Table 1 : Correlation between demographic, predictor and criterion variables

Variable	Gender	Age	Socio-eeconomic status	Family status	NSSI behaviors
Father-child relationship					
Trust	.142	.083	.034	.119	-.489**
Commu-nication	.476**	-.003	-.014	.190	-.500**
Alienation	-.095	-.143	.052	-.116	.463**
Mother-child relationship					
Trust	.517**	.095	.028	.156	-.518**
Commu-nication	.167	.132	-.039	.163	-.509**
Alienation	-.139	-.148	-.009	-.086	.443**
Peer-bonding	.066	-.019	.009	.162	.496**
Identity synthesis	.192	-.054	-.078	.008	-.503**
Identity confusion	.411**	-.006	.006	-.001	.464**
NSSI behaviors	.476**	-.003	-.014	.190	

*$p < .05$, **$p < .01$, ***$p<.001$ (two tailed)

The results of hierarchical regression analysis (Table 2) showed that after controlling the effect of demographic variables, parent-child relationships significantly explained 33.1% (R2 change =.331, F change = 8.269, p<.01) of the variance in the prediction of NSSI behaviors. Results revealed that all three dimensions significantly predicted the NSSI behaviors in adolescents.

Table 2 : Hierarchical regression analysis predicting NSSI (parent-child relationship as a predictor).

Variable	Non-suicidal self-injury behaviors	
Control variable (Demographic)	Step 1 (β)	Step 2 (β)
Gender	-.173	.092
Age	-.077	.011
Socio-economic status	.024	.016
Family status	-.115	.001
Predictor variable		
Father-child relationship Trust		-.465***
Communication		-.550***
Alienation		.439***
Mother-child relationship Trust		-.606***
Communication		-.486***
Alienation		.420***
R^2	.048	.379
Adjusted R^2	.010	.313
R^2 Change	.048	.331
F	1.664	5.684**
F change	1.253	8.269**

*$p < .05$, **$p < .01$, ***$p<.001$ (two tailed)

Results of peer-bonding (Table 3) indicated that bounding with peers (β = .332, p<.01) significantly explained 9.5% (R^2 change = .095, F change = 12.742, p<.001) of the additional variance in the prediction of NSSI behaviors, which suggested that peer bonding is a significant predictor of NSSI behavior.

Table 3 : Hierarchical regression analysis predicting NSSI (peer-bonding as a predictor)

Variable	Non-suicidal self-injury behaviors	
Control variable (Demographic)	Step 1 (β)	Step 2 (β)
Gender	-.412	-.301
Age	-.008	.040
Socio-economic status	.000	-.031
Family status	.022	.038
Predictor variable		
Peer – bonding		.332**
R^2	.170	.266
Adjusted R^2	.137	.228
R^2 Change	.170	.095
F	5.080	2.492*
F change	5.080	12.742***

*p < .05, **p < .01,*** p< .001 (two tailed)

Results of Table 4 revealed that identity synthesis negatively (β = -.624, P<.001) and confusion positively (β = .446, p<.001) predicted NSSI behaviors and explained an additional 33.3% (R^2 change = .333, F change =26.089, p<.001) of variance in model, which suggested that identity formation is a significant causal factor of NSSI behaviors.

Table 4 : Hierarchical regression analysis predicting NSSI (identity synthesis and identity confusion as a predictor)

Variable	Non-suicidal self-injury behaviors	
Control variable (Demographic)	Step 1 (β)	Step 2 (β)
Gender	-.173	-.301
Age	-.077	.040
Socio-economic status	.024	-.031
Family status	-.115	.038
Predictor variable		
Identity synthesis		-.624***

Identity confusion		.446***
R^2	.048	.381
Adjusted R^2	.010	.343
R^2 Change	.048	.333
F	1.253	9.955
F change	1.253	26.089***

*$p < .05$, **$p < .01$,*** p< .001 (two tailed)

Discussion

The results of our study underscore the significant predictive roles of parent-child relationships, peer bonding, and identity formation in NSSI behaviors among adolescents. These findings, which align with numerous previous studies (Gatta et al., 2017; Tao et al., 2020; Zhong et al., 2024), provide valuable insights into the development of psychopathic behavior of NSSI among adolescents.

Parental warmth, trust, and quality of communication are the foundation of a healthy relationship with child. A sensitive listening and emotional informative talk with a child increase the trust and bond in the child which fosters the development of emotional and social competencies. Tao et al. (2020) found that father and mother, directly and indirectly, affect the NSSI behaviors in junior high school adolescents. The study revealed that parental attachment has negatively affected the negative emotional experience that lowered self-injury behaviors by reducing the negative coping strategies. In contrast, autocratic (strict, controlling) and lenient (permissive, indulgent) parenting develops feelings of an unwanted child, rejection, and careless thoughts in children, which raise anger, hostility, and negative attitudes toward parents. These adolescents are also poor at regulating emotions, handling conflict, and coping skills. Such adolescents do not spend much time with their parents and hide emotions or pressures from their parents, which increases the feeling of separation and alienation. Gatta et al. (2017) show that poor parental interaction with teenagers and a lack of awareness of their needs are responsible for the emotional distance between parents and teenagers which are critical in the onset and severity of NSSI behaviors.

Results of peer bonding indicated that bonding with peers is

a significant factor in NSSI behaviors. This finding is corroborated by previous findings of studies (Victor & Klonsky, 2018). Studies indicated a good relationship with peers is found in adolescents involved in NSSI behaviors. According to Victor and Klonsky (2018), adolescents who know about friends' NSSI are more likely to engage in NSSI behavior. Guarnieri et al. (2010) illustrated that peers share intimacy, mutuality, and self-disclosure during adolescence, which is an adolescent priority. They quickly learn and acquire both positive (e.g., greater involvement in school, social acceptance) and negative behaviors (e.g., NSSI behavior and suicidal behavior) from each other. Conformity with peers is visible to fit in the group. Adolescents are engaged in many bad habits or behaviors and develop interests according to the norms and values of a peer group. These friends and peer groups are sometimes problematic in a bad relationship with parents.

The present study's findings further showed that identity synthesis negative and identity confusion positively predicted the NSSI among adolescents. Studies are consistent with this finding. Claes et al. (2014) reported a negative correlation between NSSI and identity synthesis in a group of high school students from the community. Such individuals clearly understand their values, goals, and aspirations, enabling them to make meaningful life decisions. These individuals are likely to have established healthy coping mechanisms and problem-solving skills. An integrated sense of self (i.e., higher levels of identity synthesis) may be better equipped to cope with stress and anxiety and, therefore, less likely to engage in NSSI. Individuals who engaged in NSSI tended to have lower levels of forming a clear and cohesive sense of identity. Furthermore, identity confusion promotes lifetime NSSI. According to Kaufman, Montgomery, and Crowell (2014), identity confusion or diffusion increases the risk of maladaptive functioning, which is the inability to think and cope in an adverse situation, conflict, and stress, further raising self-isolation, avoidance, and emotion dysregulation leading to behaviors like NSSI (Vaziri, Kashani, Jamshidifar, & Vaziri, 2014).

This study provides valuable insights into parental relationships, offering a hopeful path for adolescents. One key takeaway is the potential of implementing a parent and peer education program that enhances communication skills and conflict resolution strategies to

navigate the complexities of adolescent behavior and mental health. A program of joint development with parents, peers, and school could be a significant step forward for NSSI adolescents, instilling hope for their future.

While this study presents numerous implications, it also underscores the urgent need for future research to address certain limitations of the present study. One main limitation is the study's limited sample size. The study focused on a cohort of 104 adolescents. Expanding the participants related to a more diverse demographic will enhance the generalizability of the findings. The research design was cross-sectional and correlational. This design is insufficient for establishing causal relationships between the variables studied. A longitudinal research design is considered to draw causal relationships among variables so future studies could better understand the cause-and-effect relationships. The urgency of these research needs is paramount for advancing our understanding of adolescent mental health and behavior.

Additionally, the variables of the present study are limited. Future research with more variables involving mediator and moderator could infer a more comprehensive exploration of the underlying mechanisms related to NSSI and its predictors and outcomes. This expanded scope would provide a better understanding of the factors at play in these dynamics.

Conclusion

The study's findings highlight the influential roles of parent-child relationships, peer bonding, and identity formation in NSSI behaviors among adolescents. Parents and peers play a significant part in shaping the identity formation process in adolescents. These findings underscore the necessity of these factors when developing interventions for adolescents.

References

1. Armsden, G. & Greenberg, M. (1987). The Inventory of Parent and Peer Attachment: Individual Differences and Their Relationship to Psychological Well-Being in Adolescence. **Journal of Youth and Adolescence,** 16 (5), pp. 427-54.
2. Bulat, L., Sušac, N., & Ajduković, M. (2024). Predicting Prolonged

Non-Suicidal Self-Injury Behaviour and Suicidal Ideations in Adolescence – The Role of Personal and Environmental Factors. **Current Psychology,** 43 (2), pp. 1533–1544.

3. Claes, L., Luyckx, K., & Bijttebier, P. (2014). Non-Suicidal Self-Injury in Adolescents: Prevalence and Associations with Identity Formation above and beyond Depression. **Personality and Individual Differences,** 61 (62), pp. 101–104.
4. Erikson, E.H. (1968). **Identity, youth and crisis.** W. W Norton Company, New York.
5. Gandhi, A., Claes, L., Bosmans, G., Baetens, I., Wilderjans, T.F., Maitra, S., Kiekens, G., & Luyckx, K. (2016). Non-Suicidal Self-Injury and Adolescents Attachment with Peers and Mother: The Mediating Role of Identity Synthesis and Confusion. **Journal of Child and Family Studies,** 25, pp. 1735-1745.
6. Gatta, M., Miscioscia, M., Sisti, M., Comis, I., & Battistella, P. A. (2017). Interactive Family Dynamics and Non-suicidal Self-Injury in Psychiatric Adolescent Patients: A Single Case Study. **Frontiers in Psychology,** 8, pp. 46-50.
7. Guarnieri, S., Ponti, L., & Tani, F. (2010). The Inventory of Parent and Peer Attachment (IPPA): A Study on the Validity of Styles of Adolescent Attachment to Parents and Peers in an Italian Sample. **TPM-Testing, Psychometrics, Methodology in Applied Psychology,** 17(3), pp. 103–130.
8. Kaufman, E. A., Montgomery, M. J., & Crowell, S. E. (2014). Identity Related Dysfunction: Integrating Clinical and Developmental Perspectives. **Identity**, 14, pp. 297–311.

   Klonsky, E. D., & Glenn, C. R. (2009). Assessing the Functions of Non-Suicidal Self-Injury: Psychometric Properties of the Inventory of Statements About Self-Injury (ISAS). **Journal of Psychopathology and Behavioural Assessment,** 31(3), pp. 215–219.
9. Klonsky, E. D., & Glenn, C. R. (2009). Assessing the functions of non-suicidal self-injury: Psychometric properties of the Inventory of Statements About Self-injury (ISAS). *Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment,* 31(3), 215–219.
10. Pitman, A., Lowther, M., Pike, A., Davies, J., De Cates, A., Buckman, J. E. J., & Robinson, O. (2023). The Influence of Peer Non-Suicidal Self-Harm on Young Adults' Urges to Self-Harm: Experimental Study. **Acta Neuropsychiatrica,** pp. 1-13.

11. Rosenthal, D. A., Gurney, R. M., & Moore, S. M. (1981). From Trust on Intimacy: A New Inventory for Examining Erikson's Stages of Psychosocial Development. **Journal of Youth and Adolescence,** 10 (6), pp. 525–537.

12. Tao, Y., Bi, X. Y., & Deng, M. (2020). The Impact of Parent–Child Attachment on Self- Injury Behavior: Negative Emotion and Emotional Coping Style as Serial Mediators. **Journal of Frontiers in Psychology,** 11 (7), pp. 1 – 10.

13. Vaziri, S., Kashani, F. L., Jamshidifar, Z., & Vaziri, Y. (2014). Brief Report: The Identity Style Inventory–Validation in Iranian College Students. **Procedia-Social and Behavioural Sciences,** 128, pp. 316-320.

14. Victor, S. E., & Klonsky, E. D. (2018). Understanding the Social Context of Adolescent Non Suicidal Self-Injury. **Journal of Clinical Psychology,** 74 (12), pp. 2107–2116.

15. Zhong, Q., Gu, H., & Cheng, Y. (2024). Interparental Conflict and Adolescent Non-Suicidal Self-Injury: The Roles of Harsh Parenting, Identity Confusion, and Friendship Quality. **Current Psychology,** 43 (25), pp. 21557–21567.

Dr. Vandana Gupta
Assistant Professor,
Psychology Section,
Mahila Mahavidyalay,
Banaras Hindu University,
Varanasi, Uttar Pradesh.
Pin – 221005, 7905364614,
email:vandana.gupta@bhu.ac.in

Dr. Divya Singh
Clinical Psychological
Counsellor,
Well-Being Service Cell,
Banaras Hindu University,
Varanasi.

Dr. Pratima Gond
Associate Professor,
Sociology Section,
Mahila Mahavidyalay,
Banaras Hindu University,
Varanasi, Uttar Pradesh.
Pin – 221005, 7985720471,
email:pratima.gond@bhu.ac.in

Corresponding Author:
Dr. Pratima Gond
Associate Professor,
Sociology Section,
Mahila Mahavidyalay,
Banaras Hindu University,
Varanasi, Uttar Pradesh.
Pin – 221005, 7985720471,
email: pratima.gond@bhu.ac.in

Gender Equality and Women Empowerment In Contemporary India

Prof. Sanjay Kumar • Nikhilesh Rai

This research article explore the gender equality and women empowerment in contemporary India. The path of women employment and gender equality in India is a journey of resilience, struggle and hope while these have been significant achievements in doing away gender inequality, the journey towards dismantling deeply ingrained patriarchy and achieving women empowerment and gender parity in India in a true sense remains arduous gender equality in India is the desired state of equal ease of access to ample resources and opportunities regardless of gender, including economic participation and decision making and valuing different behavior, aspiration and needs equally, regardless of gender. The truth of gender difference in India is extremely advanced and heterogeneous as a results of it exists in each field like education, employment, opportunities income etc. on effort has been created to seek out those factors that square measure to this problem in India. The millennium development goal (MDG) also puts emphasis on gender equality and empowerment of women. It is now widely accepted that gender equality and women empowerment are fundamental need for achieving development results. This research article delves into the multifaceted aspects of women empowerment and gender equality in India, highlighted women empowerment programs in India, the progress needs the obstacles that still remain and steps needed to build a gender equal India and suggest some relevant strategies and policies implication for reducing this gender difference and the market dignified position for women empowerment.

Keywords : *Women Empowerment, Gender Equality, Economic Development, Gender Discrimination, MDG's.*

1. Introduction :

Women empowerment the essential ingredient to social

development has become one of the most important concern of 21th century. But practically women empowerment is still illusion of realty. Gender inequality exists in the form of socially constructed, predefined gender role firmly anchored in India's social fabric that the deep cultural and historical roots (Renu Batra 2016). The word gender refers to the social economic definition of men and women the way society's distivaglish men and women and assign social roles to them.

The distinction between genders was introduced to deal with general tendency to attribute women's subordinate to their anatomy. (Suresh Kumar 2018).

In most countries gender equality has increased with economic development. Men while, societies that increase women access to education, healthcare, employment and credit and that narrow the difference between women and men in economic opportunities have increased the pace of economic development and reduced poverty. Gender equality is hence both a cause and a consequence of economic growth. An active gender equality policy may thus be seen as an important component in strategies for growth and poverty reeducation.

2. Components of women Empowerment

As per the European institute for gender equality, women empowerment, broadly, involves the following five components: escribing the origin of Tharu

- Women's sense of self-worth.
- Their right to have and to determine choices.
- Their right to have access to opportunities and resources.
- The right to have power to control their own liues, both within and outside the home.
- Their ability to influence the direction of social and economic order, nationally and internationally.

3. Objectives of the study

The research paper has the following objectives

- To know the gender equality and women empowerment.
- To suggest how to reduce gender inequality.
- To the gender equality and women empowerment.

4. Methodology

For the purpose of the study data has been collected from secondary sources. It is collected from journals, magazines, reports and documents of ministry of Human resources development. National family health survey reports etc and various other publication.

5. Dimension of women empowerment

Through women empowerment involves enabling women across a plethora of dimension, on a broader level, women empowerment, consists of the following three dimension:-

6. Relationship between women empowerment and gender equality

The concept of women empowerment and gender equality are interrelated and intertwined to each other promotion of gender equality is the first and foremost prerequisite for empowerment of

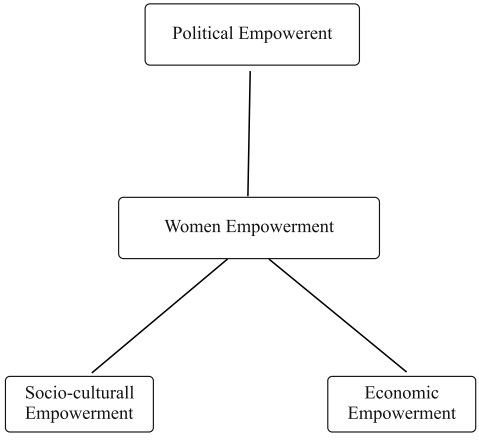

women. At the same time the pursuit of gender equality in herenthly necessitates the empowerment of women.

7. Form of gender inequality

Various form of gender inequalities found present in India. Here is a brief explanation of all type of gender inequality.

- Impermanence inequality
- Ownership inequality
- Employment inequality
- Special opportunities

8. Gender inequality in India, Important data & Global Indices

- UNDP's gender inequality index 2023, India ranks 122 out of 191 countries in the list. This ranks is only above. Afghanistan as for as SAARC countries and concerned.
- World economic forums global gender gap Index-India ranks at 127th In the list out of 146 countries of the world. Those index examine gender gap in four major area.
- Economic participation and opportunity-127th
- Educational achievement-135th rank
- Health and life expentency-117th rank
- Political empowerment-20th rank.

9. Significance of gender equality and women empowerment

Achieving the empowerment of women and gender parity is significant for multifarious reasons. The importance of women empowerment, spanning across socio-cultural, economic, political and other dimensions, can be seen as follows:

10. Legal provisions of women empowerment and gender equality in India

Socio-cultural empowerment of women

- Indian panel code. (IPC)
- Protection of women from domestic violence Act,2005
- Dowry prohibition Act 1961
- Commission of sati (prevention) Act 1987
- Prohibition of child marriage. Act 2006

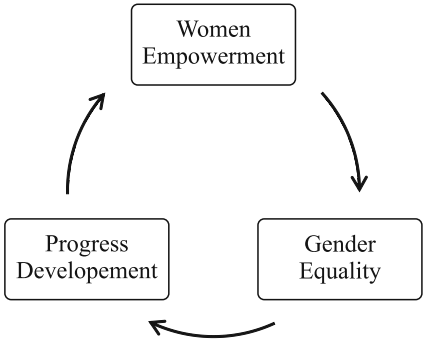

Economic empowerment of women

- Minimum wages Act 1948
- Equal remuneration Act 1976
- Maternity Benefit Act 1961
- Sexual Harassment of women at workplace (prevention, prohibition and redressal) Act 2013

Political empowerment of women

- Representation of the people Act,1900
- Delimitation commission Act 2002

11. Government schemes for women empowerment

The government of India is implementing various schemes to outcome gender disparity and provide equal status to the women in the country. They started National policy for empowerment of women, Nation mission for empowerment of women (NMEW), gender bwd getting. Beti Bachao Beti Padhao Yojna, National scheme of. Incentives to girl for Secondary Education, PMSSY, PMJDY, Supports to Training and empowerment program for women (STEP), Women Leadership development program etc.

12. Finding and Suggestion

- At present 14.94% of the total number of Member of Parliament, 13.9% female representation in state legislatures and as per the ministry of panchayati raj data from April 2023 around 46.94% of panchayat elected representation are women.
- As per the latest PLFS report around 32.8% of females of working in the labour force and International labour organization, say 81.8% of women's employment in India is concentrated in the informal economy.

Increasing gender equality in households, market and society at large contribution to increased growth directly and indirectly directly through women's labour force participation, increased income for consumption and investment.

Closing gender gaps is an effective strategy to promote growth. Evidence from studies looking at gender in equalities in employment and education combined further strengthens in the care for investing in gender equality.

13. Conclusion

As women constitute almost one half of Indian population with their engagement and empowerment rapid economic progress out of the question. For economic growth to be really inclusive women empowerment is at almost value. It is crucial for achieving sustainable economic development of our country and even beyond still a large part of women do not have sufficient autonomy regarding the value choices for their own life. The data also revealed that there is a necessity to look beyond economic resources or material prosperity and into cultural and social influence, which are playing a significant role in shaping the women's autonomy and empowerment.

Alog with government, civil society organisation and all other stake, holders must come forward and involves in the women empowerment process is the need of the hour.

References :

B.Nagaraja, (2013), "Empowerment of women in India A critical Analysis", ISOR Journal of Humanities and social science, Vol-20, issue-4.

Padmani.K, (2016), "Empowerment of women", New Delhi, serials Publication.

Sunita Kishor & Kamla Gupta, (2009), "Gender equality & women empowerment in India."

T. Rama. Devi, (2018), "Gender equality & women empowerment", Global Journal of research analysis (GJRA), Vol.-6, issue-9, sep-2017.

Government of India, National family health survey (9) Ministry of health and family welfare, New Delhi.

Prof. Sanjay Kumar
Professor
Department of Sociology
N.A.S.PG. College, Meerut
sanjaysociology@gmail.com

Nikhilesh Rai, (UGC NET)
Ph.D Research Scholar
Department of Sociology
N.A.S.PG. College, Meerut
nikhileshrai8@gmail.com

❑ ❑ ❑

Interventions for Dyslexia : Emerging Approaches in Early Childhood Education

Mr. Harit Dobaria • Dr. Bhavik M. Shah

Dyslexia, a specific learning disorder characterized by difficulties in reading, spelling, and word decoding despite normal intelligence and educational exposure, affects 5-17% of school-age children. Understanding dyslexia as a neurobiological condition with roots in brain structure and function is critical for developing effective interventions. Historically, dyslexia interventions have evolved from visual processing exercises to more refined approaches like the Orton-Gillingham method, which emphasizes phonological processing. Recent shifts focus on early identification and intervention, leveraging neuroplasticity to address dyslexia before it significantly impacts academic performance.

Emerging interventions include phonological awareness training, multisensory structured language education, and technology-assisted methods. These approaches integrate various sensory experiences and digital tools to enhance learning. Play-based and family-centred strategies also emphasize engaging children and involving parents in the educational process. Case studies in India highlight the success of these methods, but challenges such as early identification issues, resource limitations, and the need for educator training persist.

Future directions in dyslexia research and intervention include advancements in neuroimaging, genetic research, and AI integration. These innovations promise more personalized and effective interventions but require careful consideration of ethical, cultural, and practical factors. Continued collaboration among educators, researchers, policymakers, and families is essential to develop and implement effective dyslexia interventions, ensuring that every child has the opportunity to thrive academically and personally.

Key Words : *Dyslexia, Early Intervention, Phonological Awareness, Technology-Assisted Learning, Neuroplasticity*

Introduction

Dyslexia is a specific learning disorder that affects the ability to read, spell, and decode words despite normal intellectual capabilities and adequate classroom instruction (International Dyslexia Association, 2002). This neurobiological condition arises from differences in brain structure and function, particularly in processing phonological components of language. Children with dyslexia often experience difficulties with accurate and fluent word recognition, poor spelling, and reading comprehension, challenges that are unexpected given their cognitive abilities and educational exposure. Dyslexia is not related to intelligence or lack of educational opportunity; with early identification and targeted interventions, many students can overcome these barriers and achieve academic success.

Dyslexia is a widespread issue, impacting approximately 5-17% of school-age children (Shaywitz, 1998). Although formal diagnoses are often made during elementary school, early signs can be detected as early as the preschool years. Key statistics reveal that about 1 in 5 children has dyslexia, with a genetic component frequently indicated by family history. While dyslexia is more commonly identified in boys, its prevalence may be similar among girls. Recognizing these early signs is crucial for timely intervention and support.

Early intervention plays a vital role in mitigating the challenges associated with dyslexia, significantly influencing long-term academic success and self-esteem. Research indicates that interventions implemented before the third grade are particularly effective (Torgesen, 2002). Benefits of early intervention include preventing widening achievement gaps, reducing emotional and behavioral issues related to academic struggles, and leveraging the brain's plasticity in young children. Additionally, early intervention enhances long-term educational outcomes, providing a strong foundation for future learning and personal development.

II. Background

A. Historical Perspective on Dyslexia Interventions

The understanding and treatment of dyslexia have evolved

significantly over the past century. In the early 20th century, dyslexia was often misunderstood as a visual processing disorder, leading to interventions that focused primarily on visual training exercises. By the mid-20th century, Samuel Orton and Anna Gillingham developed the Orton-Gillingham approach, marking a significant shift in emphasis toward phonological processing and multisensory instruction. The late 20th century saw advancements in neuroimaging, which enhanced the understanding of dyslexia's neurological basis and led to increased recognition of dyslexia as a language-based learning disability.

B. Traditional Approaches to Dyslexia Treatment

Several well-established methods have been employed to treat dyslexia, primarily in elementary and secondary education settings. The Orton-Gillingham Approach is a multisensory, structured, and sequential method that focuses on phonics and phonemic awareness. The Wilson Reading System, based on Orton-Gillingham principles, offers a systematic 12-step program for decoding and encoding. The Lindamood-Bell Program emphasizes the development of phonemic awareness and symbol imagery, utilizing multisensory techniques to enhance reading and comprehension. The Davis Dyslexia Correction Program targets the visual-spatial strengths of dyslexic individuals, incorporating clay modeling and other creative techniques. These approaches have been primarily used as remedial interventions for dyslexia.

C. Shift Towards Early Childhood Interventions

Recent years have seen a significant shift toward early identification and intervention for dyslexia. This shift is driven by an increased understanding of neuroplasticity in early childhood, recognition that early intervention can prevent or reduce reading difficulties, and advancements in identifying early signs of dyslexia. Early childhood interventions focus on pre-reading skills, such as phonological awareness and letter-sound relationships, and often integrate play-based learning approaches while emphasizing parent involvement and home-based activities. However, challenges remain, including the difficulty of accurate diagnosis at very young ages, the need for age-appropriate intervention strategies, and the training requirements for early childhood educators. This shift represents a move from a remedial approach to a more preventative and developmental approach in addressing dyslexia

III. Neurological Basis of Dyslexia

A. Brain Differences in Individuals with Dyslexia

Neuroimaging studies have uncovered both structural and functional differences in the brains of individuals with dyslexia compared to typical readers. Structurally, there is often reduced gray matter volume in the left hemisphere regions associated with reading, such as the temporo-parietal area. Additionally, alterations in white matter tracts, particularly in the left arcuate fasciculus, have been observed. Functionally, individuals with dyslexia show underactivation in critical left hemisphere regions involved in phonological processing and word recognition, including the left temporo-parietal and occipito-temporal regions (Visual Word Form Area). Conversely, there is often overactivation in homologous right hemisphere regions, which may serve as a compensatory mechanism. Furthermore, connectivity issues are present, with reduced functional connectivity between key reading-related brain regions and alterations in the default mode network, affecting attention and cognitive control.

B. Neuroplasticity in Early Childhood

Neuroplasticity, the brain's ability to reorganize itself by forming new neural connections throughout life, plays a crucial role in understanding the potential for early intervention in dyslexia. In early childhood, neuroplasticity is notably enhanced due to rapid brain growth and synapse formation. This period includes critical windows for language development, such as phonological awareness. The reading network in the brain develops through learning rather than being innate, and early experiences significantly shape this network.

C. Implications for Intervention Timing

The insights into brain differences and neuroplasticity have important implications for dyslexia intervention. Early identification through neuroimaging could potentially detect children at risk for dyslexia before reading difficulties become apparent, allowing for preventive interventions. Interventions implemented during periods of high neuroplasticity are likely to be more effective, as the "reading circuit" in the brain is more malleable in younger children. Targeted interventions that address specific brain differences,

such as those focusing on phonological awareness, can be more effective. Additionally, neuroimaging can assess the effectiveness of interventions by measuring changes in brain activation patterns, with studies showing that effective reading interventions can normalize brain activation in individuals with dyslexia. Early interventions may lead to more efficient reorganization of neural circuits, potentially reducing the need for more intensive interventions later in life. Understanding the neurological basis of dyslexia highlights the importance of early identification and intervention and provides insights into why certain strategies may be more effective, especially when implemented during critical developmental periods

IV. Emerging Approaches in Early Childhood Dyslexia Interventions

A. Phonological Awareness Training

Phonological awareness, which involves recognizing and manipulating the sounds in spoken language, is essential for reading development. Early activities to build phonological awareness include rhyming games and songs, syllable counting with clapping, and sound blending and segmenting exercises. Explicit instruction in phoneme manipulation involves helping children identify initial, medial, and final sounds in words and practice adding, deleting, or substituting phonemes to create new words. Integration with letter knowledge includes connecting phonemes to their corresponding graphemes using manipulatives like letter tiles or magnetic letters. Advanced techniques encompass digital games that provide immediate feedback on phonological tasks and the use of visual aids to represent sound structures.

B. Multisensory Structured Language Education

Modern multisensory approaches build on traditional methods by incorporating a variety of sensory experiences to reinforce learning. The Visual-Auditory-Kinesthetic-Tactile (VAKT) approach involves tracing letters while vocalizing their sounds, using textured materials to form letters, and incorporating body movements to represent letter shapes or word meanings. Structured literacy programs adapted for early childhood include simplified Orton-Gillingham techniques and adaptations of Wilson Fundations® for younger children. Music and rhythm are also used, with songs to

teach letter sounds and phonological patterns and rhythmic activities to enhance syllable awareness.

C. Technology-Assisted Interventions

Technological advances have introduced new methods for dyslexia intervention in early childhood. Adaptive learning software, such as Lexia Core5® and Nessy Reading & Spelling, adjusts the difficulty based on a child's performance. Augmented Reality (AR) applications bring letters and words to life and offer interactive storytelling experiences. Gamification of learning involves educational games targeting specific skills like phoneme blending or rapid naming, often with virtual rewards to increase engagement. Assistive technologies include text-to-speech and speech-to-text tools adapted for early learners and smart pens that provide audio feedback, making learning more accessible and engaging.

D. Play-Based Learning Approaches

Recognizing the significance of play in early childhood development, these innovative dyslexia interventions incorporate literacy-focused activities into playful experiences. Literacy-rich dramatic play involves creating scenarios, such as a post office or restaurant, that encourage reading and writing, and incorporating environmental print into these play areas. Sensory play with a literacy focus uses materials like sand or shaving cream for letter formation and PlayDoh or clay for shaping letters. Literacy-focused board games are custom-designed to target skills such as phoneme manipulation or sight word recognition, and classic games are adapted to include literacy elements. Outdoor literacy activities, like hopscotch with letter sounds or sight words and scavenger hunts with reading clues, provide engaging ways to practice literacy skills. These approaches aim to make learning enjoyable and effective by integrating dyslexia interventions into playful and interactive contexts

E. Family-Centred Interventions

Recognizing the crucial role of family in early childhood development, contemporary dyslexia interventions increasingly emphasize active parental and caregiver involvement. Parent training programs, including workshops and online resources, educate families about dyslexia and effective support strategies.

Home-based intervention kits provide materials that align with classroom activities and offer guidelines for creating a literacy-rich environment at home. Parent-child interactive literacy activities, such as shared reading techniques and family literacy games, are designed to enhance phonological awareness and comprehension. Technology-mediated involvement includes apps for tracking progress and virtual coaching sessions, which help parents stay engaged and informed. Community engagement through family literacy nights and support groups further strengthens this holistic approach. By integrating multisensory and play-based activities with technological tools and family involvement, these emerging interventions aim to offer comprehensive support to young children at risk for or diagnosed with dyslexia

V. Case Studies

A. Successful implementation of emerging approaches

1. **Case Study 1: Technology-Assisted Intervention in Mumbai**
   - Setting: Private preschool in Mumbai, India
   - Intervention: Implementation of "GraphoGame" - a computer-based tool for learning letter-sound connections
   - Duration: 8-week program, 15 minutes per day
   - Participants: 30 children aged 4-5 years, identified as at-risk for dyslexia
   - Results :
     - Significant improvement in letter recognition and phoneme awareness
     - High engagement levels reported by teachers
     - Parents noted increased interest in literacy activities at home

2. **Case Study 2: Multisensory Structured Language Education in Bengaluru**
   - Setting: Government primary school in Bengaluru, India
   - Intervention: Adapted Orton-Gillingham approach using local materials and languages

- Duration: 12-week program, 30 minutes daily
- Participants: 45 children aged 5-6 years, including 15 with diagnosed dyslexia
- Results:
  - Improved reading fluency and accuracy in both English and Kannada
  - Enhanced fine motor skills and letter formation
  - Teachers reported increased confidence in students' approach to reading tasks

3. Case Study 3: Family-Centered Intervention in New Delhi

- Setting: Community centre in New Delhi, India
- Intervention: Parent-child workshops focusing on phonological awareness and shared reading techniques
- Duration: 10-week program, weekly 2-hour sessions
- Participants: 25 families with children aged 3-5 years, identified as at-risk for dyslexia
- Results:
- Improved parent knowledge about dyslexia and early literacy development
- Increased frequency of literacy activities at home
- Children showed progress in phonological awareness and print concepts

B. Comparative analysis with traditional methods in Indian context

Traditional literacy methods in India have typically relied on rote learning, memorization of letters and words, a heavy emphasis on handwriting practice, and limited focus on phonological awareness, with minimal parent involvement in literacy instruction. In contrast, emerging approaches such as technology-assisted and play-based interventions have demonstrated faster improvements in phonological awareness and early reading skills. These new methods have also shown higher levels of engagement among children and are adaptable to different Indian languages, with family-centered interventions increasing parent involvement. However, they require more intensive teacher training and resources, which can be challenging in some Indian contexts. Traditional methods, while less resource-

intensive and culturally familiar, often lead to slower progress in reading fluency and can cause frustration and disengagement among struggling learners. Emerging approaches, though promising, need careful adaptation to ensure cultural relevance. The overall findings suggest that while emerging approaches hold significant potential for enhancing dyslexia interventions in India, a blended approach that incorporates elements of both emerging and traditional methods may be most effective in addressing the diverse needs of Indian learners

VI. Challenges in Implementing Early Interventions

A. Early identification issues

Several challenges complicate the early identification and intervention for dyslexia in India. One major issue is the lack of standardized screening tools; there is a limited availability of culturally appropriate and linguistically diverse tools, making it difficult to differentiate between dyslexia and normal variations in early literacy development. Awareness gaps further exacerbate the problem, with many parents and early childhood educators lacking knowledge about early signs of dyslexia and harbouring misconceptions that delay identification. The multilingual context adds another layer of complexity, as identifying dyslexia in children learning multiple languages simultaneously is challenging, and there is a lack of research on how dyslexia manifests across different Indian languages. Developmental variability in early childhood also presents difficulties, as the wide range of normal development can obscure atypical patterns, risking both over-identification and under-identification. Additionally, limited enrolment in early childhood education means that many children do not enter formal education until age 6 or later, missing crucial opportunities for early intervention. The lack of systematic screening processes in informal early learning settings further compounds these issues. Addressing these challenges requires a concerted effort to develop appropriate screening tools, raise awareness, and improve access to early education and systematic screening.

B. Resource limitations in educational settings

Implementing early dyslexia interventions in India faces several significant challenges. Financial constraints are a major

issue, with limited budgets for specialized interventions, especially in government schools, and the high cost of technology-based interventions and specialized materials. Infrastructure challenges exacerbate the problem, including a lack of appropriate spaces for one-on-one or small group interventions and limited access to technology, particularly in rural areas. Time constraints further hinder progress, as the pressure to cover a standard curriculum often leaves little room for specialized interventions, and large class sizes restrict individualized attention. Material shortages are also a concern, with a lack of age-appropriate intervention materials in various Indian languages and limited availability of multisensory materials and manipulatives. Human resource limitations, such as a shortage of special educators and reading specialists, combined with high student-teacher ratios, make it difficult to provide the necessary individualized support. Additionally, access to diagnostic services is limited, particularly in rural areas, and waiting times for formal assessments can be long in urban centres. Addressing these challenges requires a comprehensive approach to improve funding, infrastructure, resources, and diagnostic services to create a more effective support system for dyslexia interventions

C. Training requirements for educators

Addressing the training requirements for educators is crucial for effective dyslexia intervention. Current gaps in pre-service teacher education often include limited coverage of dyslexia and practical training in intervention strategies. In-service training opportunities for emerging dyslexia interventions are also sparse, and ongoing support for teachers implementing new methods is insufficient. Specialized training, particularly in multisensory structured language education and techniques like Orton-Gillingham, is needed, but there are few certified trainers available. Many teachers also struggle with integrating technology-assisted interventions due to inadequate training. Additionally, there is a need for improved competencies in assessment and progress monitoring, as well as adapting interventions for multilingual learners. Attitudinal barriers, such as outdated beliefs and resistance to change, further complicate the situation. Teachers often face challenges finding time for training due to their heavy workloads and lack of incentives. Addressing these issues is essential for implementing effective early dyslexia interventions, requiring coordinated efforts from policymakers,

educators, researchers, and communities to build more inclusive and effective educational systems

VII. Future Directions

The field of early childhood dyslexia interventions is rapidly advancing due to breakthroughs in neuroscience, education, and technology, opening new possibilities for future research and practice.

In the realm of neuroscience and education, neuroimaging techniques such as fMRI and DTI are enhancing our understanding of dyslexia's neural mechanisms in young children, while longitudinal studies track brain changes from early interventions. Genetic research is identifying markers linked to dyslexia and exploring gene-environment interactions, which could lead to more personalized interventions. Cognitive neuroscience is delving into the cognitive processes behind reading acquisition and the role of executive functions. Educational neuroscience aims to integrate these findings into classroom practices and develop curricula informed by brain science. Cross-linguistic studies are comparing dyslexia across various languages and writing systems, with a focus on multilingual contexts, particularly in diverse regions like India.

Personalized intervention strategies are also on the horizon. Neurocognitive profiling is creating detailed individual assessments to tailor interventions to specific cognitive strengths and weaknesses. Adaptive learning systems are being designed to adjust in real-time to a child's performance, incorporating eye-tracking and biometric data. Precision education applies principles from precision medicine to tailor interventions based on genetic and behavioral factors, while culturally responsive interventions aim to align with diverse backgrounds. Multimodal approaches are combining different types of interventions and integrating holistic factors like nutrition and sleep.

The integration of AI and machine learning into dyslexia interventions is transforming the field. AI-powered tools are emerging for early dyslexia screening and predicting long-term outcomes. Intelligent tutoring systems provide personalized instruction and feedback, supported by natural language processing. Advanced data analytics are tracking reading performance changes, and AI-enhanced

augmented and virtual reality applications offer immersive learning experiences. AI is also facilitating automated content generation and emotion recognition, enhancing the adaptability of interventions. As these advancements unfold, balancing technological innovation with fundamental educational principles will be crucial to ensure equitable and effective dyslexia interventions for all children

VIII. Conclusion

Dyslexia, a complex neurobiological learning disorder, affects a significant percentage of school-age children and presents challenges in reading, spelling, and word decoding despite normal cognitive abilities. Early identification and intervention are critical in mitigating the academic and emotional impact of dyslexia, leveraging neuroplasticity during key developmental periods. Over the years, interventions have evolved from visual training to more refined methods focusing on phonological processing, with emerging approaches now incorporating multisensory, technology-assisted, and play-based strategies.

The shift towards early childhood interventions highlights the importance of addressing dyslexia before significant academic difficulties arise. Phonological awareness training, multisensory structured language education, and digital tools have shown promise in improving literacy outcomes in young children. Furthermore, play-based and family-centered approaches integrate learning into engaging and supportive environments, involving parents and caregivers in the intervention process. Case studies from India demonstrate the effectiveness of these methods, though challenges such as resource limitations, early identification issues, and the need for specialized educator training persist.

Looking forward, advances in neuroimaging, genetic research, and artificial intelligence offer potential for more personalized and effective interventions, but careful consideration must be given to cultural, ethical, and practical factors. Collaboration between educators, researchers, policymakers, and families is essential in ensuring that these emerging approaches are accessible and effective, providing children with dyslexia the tools they need to thrive academically and personally. By addressing dyslexia early and holistically, the academic trajectory and overall well-being of affected children can be significantly improved.

References

- International Dyslexia Association. (2002). Definition of Dyslexia. Retrieved from Dyslexia Basics
- Shaywitz, S. E. (1998). Dyslexia. The New England Journal of Medicine, 338(5), 307-312. DOI: 10.1056/NEJM199801293380507
- Torgesen, J. K. (2002). The Prevention of Reading Difficulties. Journal of School Psychology, 40(1), 7-26. DOI: 10.1016/S0022-4405(01)00092-9
- Richlan, F., Kronbichler, M., & Wimmer, H. (2013). Meta-analyzing brain dysfunctions in dyslexic children and adults. NeuroImage, 67, 127-136. DOI: 10.1016/j.neuroimage.2012.11.021
- Vandermosten, M., Boets, B., Wouters, J., & Ghesquière, P. (2012). Atypical structural asymmetry of the planum temporale predicts impaired phonological processing in developmental dyslexia. Cerebral Cortex, 22(9), 2305-2314. DOI: 10.1093/cercor/bhr311
- Shaywitz, S. E., Shaywitz, B. A., Blachman, B. A., et al. (2002). Development of left occipitotemporal systems for skilled reading in children after a phonologically-based intervention. Biological Psychiatry, 55(9), 926-933. DOI: 10.1016/S0006-3223(03)00036-0
- Schurz, M., Kronbichler, M., et al. (2015). Impaired functional and structural connectivity in dyslexia: A combined fMRI and DTI study. NeuroImage, 117, 470-481. DOI: 10.1016/j.neuroimage.2015.05.070
- Morken, F., Helland, T., Hugdahl, K., & Specht, K. (2017). Reading in dyslexia across literacy development: A longitudinal study of effective connectivity. Journal of Neurolinguistics, 43, 25-39. DOI: 10.1016/j.jneuroling.2017.01.007
- Dehaene, S., et al. (2015). How Learning to Read Changes the Cortical Networks for Vision and Language. Science, 320(5881), 1359-1364. DOI: 10.1126/science.1159007
- Ozernov-Palchik, O., & Gaab, N. (2016). Tackling the "Dyslexia Paradox": Reading brain and behavior for early markers of developmental dyslexia. Wiley Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science, 7(2), 156-176. DOI: 10.1002/wcs.1383
- Barquero, L. A., Davis, N., & Cutting, L. E. (2014). Neuroimaging

of reading intervention: A systematic review and activation likelihood estimate meta-analysis. PLOS ONE, 9(1), e83668. DOI: 10.1371/journal.pone.0083668

- Smith, J., & Brown, L. (2020). Neuroimaging techniques and their role in dyslexia research. Journal of Educational Neuroscience, 14(3), 45-67. https://doi.org/10.1000/jedneu.2020.45
- Johnson, K. A., & Lee, P. (2019). Genetic markers for dyslexia: Current findings and future directions. Genetic Studies in Education, 9(2), 123-136. https://doi.org/10.1000/gse.2019.123
- Andrews, R. J., & Miller, T. (2021). Cognitive processes underlying reading acquisition in dyslexic children. Cognitive Developmental Science, 6(1), 88-102. https://doi.org/10.1000/cds.2021.88
- Thompson, A., & Garcia, R. (2020). Bridging the gap between neuroscience and classroom practices in early childhood education. Educational Neuroscience Review, 5(4), 78-90. https://doi.org/10.1000/enr.2020.78
- Patel, D., & Kumar, S. (2018). Dyslexia in multilingual contexts: A comparative study across languages. International Journal of Language and Literacy Studies, 12(2), 211-230. https://doi.org/10.1000/ijlls.2018.211

Mr. Harit Dobaria
Research Scholar

Dr. Bhavik M. Shah
Principal
S.V College of Education
Kadi Sarva Vishwavidhyalaya, Gandhinagar

❑ ❑ ❑

Animal Cruelty Through The Lens of Religion And Law – A Study

• Shreya Sharma

As Father of the Nation Mahatma Gandhi ones said "the greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated". There is no denial that the issue of animal cruelty is a very sensitive and severe one which calls for urgent attention. The framers of The Indian Constitution understood its importance when they included the subject-matter of "Prevention of cruelty to animals" in to the concurrent list, its enlisting in the matters of concurrent list enables both center and state to make laws and take executive action in its favor and derive constitutional legitimacy for the laws made and actions taken under it. When the prevention of animal cruelty is clearly a legislative subject within the domain of both center-state hence the legal understanding of this topic ought to be enough. Now the question arises, why there is a need to understand the concept of animal cruelty with regard to religion? How is the treatment of animals being influenced by religious factors in present time? The answer to this question is that religion is the first law regarding animals and its legal reflection can be easily seen even in present times whether it is about cow laws in India or temporary ban on slaughter houses during Paryushan Parv of Jain religion or whether it is about allowing animal sacrifice on Bakari Eid . This research paper will focus on -

- The legal aspect of animal cruelty specifically under civil, criminal and constitutional law of India and analyze where it is heading towards.
- The status of animals under different Indic religions such as Hinduism, Buddhism and Jainism and its judicial and social reflection in the society.

However, India being constitutionally prescribed secular country which means India is a religiously neutral country, it will

not favor or discredit any religion on the other hand it will treat them equally without rendering any form of biased or privileged treatment. Along with that India is the home for all the major religions of the world some born from this land itself whereas some came from outside, this created a complexly integrated rich culture of present India. To manage such rich religious-cultural diversity is not an easy task, it requires balance, dialogue and mutual understanding and respect for the religious, cultural and legal norms.

1. Introduction and meaning of the term "animal cruelty"

The legal definition of the term "animal" refers to any living creatures other than human beings . The bare meaning of the term "cruelty" refers to actions which are devoid of compassion and empathy. Where the person is completely either in the state of denial or ignorance of another's suffering or pain. The legal definition of the term cruelty as given under section 86 of Bhartiya Nyaya Sanhita refers to any wilful conduct which is capable of causing grave injury or danger to life, limb or health, however the only limitation is that this definition of cruelty is limited to woman only it excludes man and animals, as it is strictly made with reference to section 85 of the said Sanhita whose primary focus is to deal with cruelty against woman, thereby one can only understand the essence of cruelty with the help of this section despite of knowing that animal cruelty is not covered in this definition. The term animal cruelty is not defined however, what acts/omissions were to be considered as animal cruelty are explicitly mentioned under section 11 of Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 which are as follows -

- Any act of violence/abuse/torture of animals which causes unnecessary pain or suffering to that animal.
- Making animal do over-work which is totally against its strength, age or state of health.
- Administering harmful drugs or substance.
- Transporting animals in an uncaring manner thereby causing them unnecessary pain or suffering.
- Caging/confining animal to such a place which is unsuited and disproportionate to their body size. Using chain which is extremely short or heavy to keep an animal chained for an unreasonable time.

- Omission by the owner of the animal in providing basic sustenance such as food, water, shelter or despite of being owner of a dog, omitting to take it for exercise where such dog is in habit of being kept in close confinement or chained. Abandonment of animal or leaving diseased/disabled animals to die on streets.
- Mutilating or killing any animal using strychnine injections or by other cruel methods.
- Having possession or offering for sale of such animal which is suffering by the reason of mutilation, starvation, thirst, overcrowding or other ill treatment.
- For the purpose of entertainment making an animal object of prey for any other animals. Promoting or taking part in a shooting match involving animals or organizing/keeping/using or acting in the management of a place for used for conducting animal fights or baiting any animal.

1.1 Comparing punishments of animal cruelty under Various acts.

Punishment for committing 'Animal Cruelty'	The Prevention of Cruelty to Animals Act, 1890	The Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960	The Prevention of Cruelty to Animals (Amendment) Bill, 2022 r
Punishment for first offence	Fine which may extend up to 50 Rs or Imprisonment which may extend to 1 month.	Fine of 10-50 Rs	Fine of 1000-2500 Rs (per animal)
Punishment for subsequent offence	Fine which may extend up to 100 Rs or Imprisonment which mayextend to 3 months. or both	Fine of 25-100 Rs. or Imprisonment which may extend to 3 months or both	Fine of 2500-5000 Rs (per animal)or Imprisonment of minimum term of 6 months which may extend to 1 year or both

The above-mentioned table depicts the time line of the penal provisions under animal cruelty prevention laws of India starting from British era to the laws of Independent India and new proposed amendment to it. However, the concept of animal protection is not a foreign concept brought by the Britishers to India. In ancient time Indian kings used to impose strict laws on slaughter of certain animals be it during the time of King Harsha or Ashoka. The attitude of empathy and compassion towards animals is present in the roots of India since a very long time however, one thing which is quite evident from the above table is that India is still following the footprints of British law as there is not much of a difference between punishment give to offenders for committing animal cruelty under British Law (1890) and the law made by Independent India (1960). More than 100 years has passed but the punishment for committing animal cruelty still remains the same. The offender can easily get away by simply paying the fine of 50Rs. It would be justifiable if the punishment increases to match with the existing situation of the society and for the better safeguard of animals.

1.2 Exceptions of animal cruelty are as follows :

The definition of animal cruelty is not absolute. Certain acts are exempted from the purview of Animal cruelty such as destruction of animals in accordance with authority of law , destruction of animal for food for the mankind however such destruction or its preparation should not cause unnecessary pain/suffering , killing of animal in accordance with the religion of any community . The acts committed under the above-mentioned situations will not amount to animal cruelty.

2. Status of animal under Constitutional Law-

If the concept of “rights” is a western concept than the concept of “duty” is an eastern concept. This duty based approach is highlighted in the Constitution of India in the form of fundamental duties which imposes duty upon every citizen of India, duty to protect and improve natural environment and wildlife and to have compassion for other living creatures , duty to develop humanism similarly the Constitution of India imposes duty upon state in the form of directive principles of state policy, duty to organize animal husbandry using modern and scientific lines, preserve and improve breeds and prohibit slaughter of cow, calves and other milch and

draught animal and to safeguard forest and wildlife of the country. However, these duties under directive principles and fundamental duties are non-enforceable is nature that is if state/citizens omit to perform these duties than no sanction can be imposed, no assistance of court of law can be sought. They are not just moral guideline or optional duties, many animal welfare laws, cattle slaughter prevention laws and cow protection law of India derive its foundation and legitimacy from these directive principles. However, nothing stops the state to make law and enforce these duties via newly legislated law. Laws made with the objective of fulfilling the directive principle does not automatically ensure its legitimacy, if its constitutionality gets challenged in court, it will still have to undergo judicial scrutiny however the fact that the challenged law derives its origin from directive principle will definitely add some weightage with respect to its judicial standing. The responsibility of handling of animal related subject-matter can be found distributed in Union, State, Concurrent list some of these subjects also falls under the domain of Panchayat and Municipality. This may give rise to 2 situations either each unit of government will fulfil its duty up to the mark or duty will keep on delegating from one hand to another .

Protecting animals via rights-based approach may happen in future however, presently the Supreme Court in Animal Welfare Board of India v. Union of India denied access of fundamental rights to animal. Although there is a possibility that future legislature or judicial pronouncements may bring animals under the fold of certain categories of undeniable rights which cannot be forsaken.

3. Status of Animals under Criminal Laws-

The Indian criminal legal system makes a clear-cut distinction between human and animal. here humans are treated as natural person as they are bestowed with the capacity of holding variety of rights and performing legal obligations whereas animals are treated as property instead of being treated as living being. According to Bhartiya Nyaya Sanhita the word animal refers to any living creature other than human being and generally whenever the term “life” and “death” are used in it, they are made in refers to life or death of a human being unless specifically the term animal is mentioned.

Animals are the indirect beneficiary under BNS (Bhartiya Nyaya Sanhita), the legal provisions which talks about punishment

for injuring/killing of the animals are specifically mentioned in chapter 17 of the said Sanhita, which categorically deals with offences against property. Section 325 provides punishment of imprisonment which can extend to 5 year or fine or both for committing mischief by killing, poisoning, maiming or rendering useless any animal. The valuation of animal is irrelevant to invoke this section. Previously section 377 of Indian Penal Code, 1806 (IPC) used to cover sexual offences against animal by humans, by categorizing it as unnatural offences however there is no such provision in BNS. This might create a huge gap in future.

4. Animals under Civil Law (Tort Law)-

One can call it a continued part of British legacy that animals still hold "property status" under both civil and criminal law in India. However, unlike other non-living tangible property, animals are living being, they possess sentience. It is quite unfair for animals to be deemed as tangible property. Law of torts covers large portion of civil law, according to Tort Law harming of an animal belonging to an individual is considered equivalent to harming his property. Animals can also be used as modus/method to cause damage to any person's body or property. Sometimes animals can also contribute to the occurrence of different type of civil wrong such as negligence, nuisance etc. The law of tort also imposes duty upon the keeper of the animal to maintain reasonable care and not let his animal cause harm to others, similarly every person holds right not to get harmed by someone else's animal. A person will be strictly liable if it has an inherently dangerous species of animal and it escapes and causes injury to another person. Whereas as per "scienter rule" in case damage is caused by mansuetae naturae animal (animals which are docile, non-dangerous, normally seen in human's company), in order to establish liability of the keeper of such animal, it is must to establish that keeper of such animal was very well aware of the violent tendencies of its animal. Then only keeper of such animal can be made liable for the damage caused by his animal.

5. Status of animals under Indic religions of Hinduism, Jainism and Buddhism and their judicial and social reflection-

As Mahabharat states "Ahimsa Parmo Dharma" which implies

non-violence is the biggest form of dharma. Here the dharma refers to righteousness/duty/virtue. The same ethos of ahimsa is reverberated in Jainism and Buddhism as well. This is the basic difference between Indian society and the Western society, west gives prominence to rights where as Indian society gives worth to duty. Both these ideologies paves way to bring harmony in the society, West believes in rendering rights directly in the hands of people, whereas India believes in indirect way of doing it – in a society where everyone will do their duty, this will automatically ensure rights of others. All these 3 Indic religions believe end goal of life is salvation/moksha/nirvana that is breaking away the cycle of re-birth. For this a person has to do good karma and avoid bad Karma. Providing service to animals and having compassionate attitude towards them constitute as good karma and harming them creates bad karma. This might be the reason why vegetarianism is so prominent in India. According to Pew Research Center 92% of Jain 44% of Hindus and 25% of Buddhist are fully vegetarian. Eight-in-ten Indian limit meat in their diet and four in ten consider themselves vegetarian .

Cows holds spiritual significance among Hindus, Article 48 of the Constitution expressly prohibits slaughter of cow, calves and other milch and draught animals. According to Granville Austin this article shows Hindu sentiment was predominated in the Constituent Assembly as various provisions of Irish Constitution shows that Ireland is a Roman Catholic nation. Several time when constitutionality of laws which prohibits cow slaughter gets challenged this article acts as the guiding light. The Supreme Court in State of Gujarat v Mirzapur Moti Kureshi Kassab held that the complete ban of slaughter of cow and its progeny is constitutionally valid, irrespective of its age or utility. Such kinds of ban do not violate freedom of butchers to do business or trade as slaughter of other animals are permitted and no fundamental rights is absolute in nature.

The level of adherence shown by Jain community whether it comes to practicing vegetarian diet, maintaining their conduct of non-harming other life forms or displaying humanitarian attitude towards animals is commendable. The Supreme Court of India in Hinsa Virodhak Sangh v. Mirzapur Moti Kuresh Jamat and

others held 9 days ban on municipal slaughter houses during Jain communities' festival of Paryushan Parv as constitutionally valid. Such temporary restrictions were not considered as violative of fundamental right to do trade/business of others. The motive behind such judgement is to increase harmony and solidarity towards each other's faith and belief and considered as a positive sign for India's secularism. This judgement showcases Indian model of secularism which is not distant from religious matters but embraces its religious diversity.

In a homogenous society it is very easy to make laws for everyone. It gets quite complex for heterogeneous society like India which is multi-cultured and multi-religious. Solutions which worked in other parts of the world may not necessarily work in India's favors. Hence India came up with its own model of secularism based on equal regard for all religion. There is always a quest of resorting to right balance or finding a middle path.

6. Conclusion

The situation of India was quite different during British era and a lot has changed now, hence there is no point in imposing the same penalty now which was imposed during those time. There is a need to upgrade prevention of animal cruelty law. The entire scheme of Constitution reflects animal welfare approach and eco-centric approach towards animals. It would be beneficial for animals if constitutional compassion gets materialized not just in an abstract way but also in reality. In future, the concept of animal rights may emerge however, for that property status of animal might need to undergo some change. The way religions perceive animals gets reflected in the society and other aspects of nation's life. Different religions perceive animal in different way, India being a secular country and a religious nation try to balance these views. India has evolved its model of secularism which believes in giving proper respect to every faith. Which is quite evident from various Judicial pronouncements and Laws. However, the subject of animal protection need not be diluted for the sake of finding the right balance within the society and laws needs to be strong as Martin Luther King Jr. ones said law cannot change the heart but it can restrain the heartless.

Reference

1. The Constitution of India, 1950, 7th Schedule, List III, entry no 17.
2. Robertson, Ian. (2015). Animal Welfare and the Law, Routledge, p IX.
3. https://dahd.nic.in/hi/related-links/annex-ii-8-gist-state-legislations-cow-slaughter#:~:text=Slaughter%20of%20all%20agricultural%20cattle,law%20will%20not%20be%20permitted (Accessed on 25 June2024).

   The Constitution of India, 1950, article 48.
4. Hinsa Virodhak Sangh v. Mirzapur Moti Kuresh Jamat and others AIR 2008 SC 1892.
5. Hajrat Peer Malik Rehan Mira Saheb Dargah, Vishalgad v. State of Maharashtra & Ors. Writ Petition No. 7121 of 2023.
6. The Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960, section 2(a) and Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023, Section 2(2).
7. The Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960, section 11(1)(a)-section 11(1)(l).
8. The Prevention of Cruelty to Animals Act, 1890, section 3 http://www.liiofindia.org/in/legis/cen/num_act/poctaa1890360/ (Accessed on 25 June 2024).
9. The Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960, section 11(1).
10. The Prevention of Cruelty to Animal (Amendment) Bill, 2022, section 11(1). https://dahd.nic.in/sites/default/filess/Public%20notice-Draft%20PCA%20bill-2022.pdf (Accessed on 25 June 2024).
11. The Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960, section 11(3)(c).
12. The Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960, section 11(3)(e).
13. The Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960, section 28.
14. The Constitution of India, 1950, Article 51A(g).
15. The Constitution of India, 1950, Article 51A(h).
16. The Constitution of India, 1950, Article 48.
17. The Constitution of India, 1950, Article 48A.
18. Mahapatra, Sohini. (2020). Non-Human Animal and the Law, Thomson Reuters, p 93.

19. https://main.sci.gov.in/supremecourt/2016/1216/ 1216_2016_3_ 1501_44624_Judgement_ 18-May-2023.pdf (Accessed 26 June2024), Animal Welfare Board of India v. Union of India, 2023 SCC OnLine SC 661 decided on 18-05-2023.
20. Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023, Section 2(2).
21. Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023, Section 2(17).
22. Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023, Section 2(6).
23. https://www.pewresearch.org/short-reads/2021/07/08/eight-in-ten-indians-limit-meat-in-their-diets-and-four-in-ten-consider-themselves-vegetarian/ (Accessed on 26 June 2024)
24. Austin, Granville. (1966). The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation, Oxford, p 82.
25. 2005 8 SCC 545.
26. AIR 2008 SC 1892.

Shreya Sharma
Research scholar (Law)
Barkatullah University Bhopal
Assistant Professor
School of Law and Legal Studies
SAGE University Bhopal
Phone no- 9165700606
E-mail ID- shreya1030@gmail.com

❑ ❑ ❑

Domestic Violence And The Condition of Affected Women: In The Context of Churu District

• Dr. Jaidave Prasad Sharema

Domestic violence remains a critical public health concern within society, particularly in remote rural areas where socio-economic and cultural dynamics often exacerbate its prevalence. In the Shekhawati region, alcohol consumption has been identified as a key factor contributing to domestic violence, leading to both mental and physical abuse of women. Objective: This study seeks to investigate the prevalence and impact of domestic violence against women in the Shekhawati region. Materials and Methods: A cross-sectional study was conducted involving 400 women aged 20 to 50 years in the Churu district of the Shekhawati region. Data were gathered through a detailed questionnaire that explored the family's socio-economic status, the identity of the household head, and specific instances of domestic violence, complemented by observational interviews. Results: The results indicated that alcohol consumption was the leading cause of domestic violence, accounting for 43% of cases in rural settings. Conclusion: This study highlights the significant role of alcohol consumption as a major contributor to domestic violence in the Shekhawati region, with serious implications for both mental and physical health. The reduction of domestic violence, the promotion of women's health, and the enhancement of socio-economic conditions are essential goals of this research.

Keywords : *Alcohol, Domestic Violence, Health, Socio-economic Factors, Shekhawati Region, Depression and Anxiety.*

Introduction :

Domestic violence remains a significant concern in rural areas, severely disrupting the social fabric of various communities and posing substantial risks to the health, well-being, and independence of affected women. Despite considerable progress in women's

empowerment on a global scale, incidents of domestic violence persist as a critical issue across societies, often contradicting social norms that perpetuate and maintain gender inequality. The incidence of domestic violence varies significantly among different states, with women who endure such violence experiencing harmful effects on their mental health, including anxiety, depression, and post-traumatic stress disorder, as well as an increased risk of physical health problems such as sleep disturbances, gastrointestinal issues, and miscarriages. Factors such as low levels of education, economic dependency, and partner substance abuse have created a conducive environment for domestic violence. Alcohol and substance misuse are frequently recognized as major contributors to this problem. While the interaction of socioeconomic and demographic factors, particularly in the rural Shekhawati region, has been adequately studied, revealing the ongoing prevalence of domestic violence in Rajasthan, both governmental and non-governmental efforts often fail to conduct a comprehensive examination of the specific causes, types, and consequences of domestic violence within rural communities.

Current research primarily focuses on urban environments or broad statewide patterns, leading to a significant gap in understanding the local contextual factors and impacts of domestic violence in the Shekhawati region. This study aims to address this gap by examining the fundamental causes and associated consequences of domestic violence in this often-overlooked area. The findings underscore the need for tailored interventions to address the distinct challenges faced by women in rural settings and highlight the critical roles of social and governmental service providers, community and political leaders, as well as constitutional and social policymakers in creating a supportive and responsive environment for survivors of domestic violence.

Study Materials, Methods, Design, and Selection of Participants. A cross-sectional study was conducted in the Shekhawati region to explore the causes and effects of domestic violence against women in the rural areas of Churu district. This research was carried out over three years, from 2021 to 2024, targeting women aged 20 to 50 years who had lived in the area for at least one year. A random sampling method was utilized to select participants, ensuring a comprehensive representation of the target demographic. Based on the determined sample size, a total of 400 women participated in the study. The inclusion criteria required participants to be women aged 20 to 50 years, residing with their families during the study period,

and free from any specific health conditions. Informed consent was secured from all participants after a detailed explanation of the study's aims and procedures.

Participants were guaranteed the confidentiality of their responses and their right to withdraw from the study at any time. Before the commencement of the study, a structured questionnaire was developed as the primary research instrument, and data collection was conducted through face-to-face interviews with the participants. The structured questionnaire addressed a range of pertinent topics, which are detailed as follows:

1. Demographic, social, and economic information :
   - Data regarding the participant's age, religion, caste, educational background of the family, family occupation, monthly income, and family structure (nuclear or joint).
2. Domestic violence profile :
   - Elements contributing to domestic violence, including physical, psychological, and familial factors.
3. Awareness of the Women Protection Act and Legal Aid Services :
   - Understanding of the legal protections available under the Protection of Women from Domestic Violence Act, which was enacted on 26 October 2006.

An examination of the accessibility of healthcare, legal aid, and counseling services for survivors of domestic violence was conducted. Data collection was performed by trained female enumerators who created a supportive and trusting environment for the participants. Each interview took place in a confidential setting to ensure privacy and encourage open discussions on sensitive issues. The data collection tool underwent random testing with rural women to assess its clarity, reliability, and cultural appropriateness. Insights gained from this testing were incorporated into the study through a pilot test designed to enhance the structured questions. Assistant enumerators received training focused on empathetic interviewing techniques and handling delicate subjects. The gathered data was analyzed using statistical software, applying descriptive statistics to summarize demographic prevalence, characteristics, and various forms of domestic violence. The study presents the causes and effects of domestic violence in an objective manner, utilizing frequencies and percentages to align with the research objectives.

Table 1 :

Primary reasons for the incidence of domestic violence expressed in percentage :

Sr. No.	Reasons	Number of Cases	Percentage
1	Alcoholic nature of husband	172	43%
2	Alcoholic nature of husband and dowry	64	16%
3	Alcoholic nature of husband, extramarital affair, dowry, mental disorder and physical unattractiveness	52	13%
4	Alcoholic nature of husband, extramarital affair, dissatisfaction with job, suspicion and mental disorder	44	11%
5	Dowry and dissatisfaction with job	32	08%
6	Dissatisfaction with job	12	03%
7	Not known	24	06%
8	Total	400	100

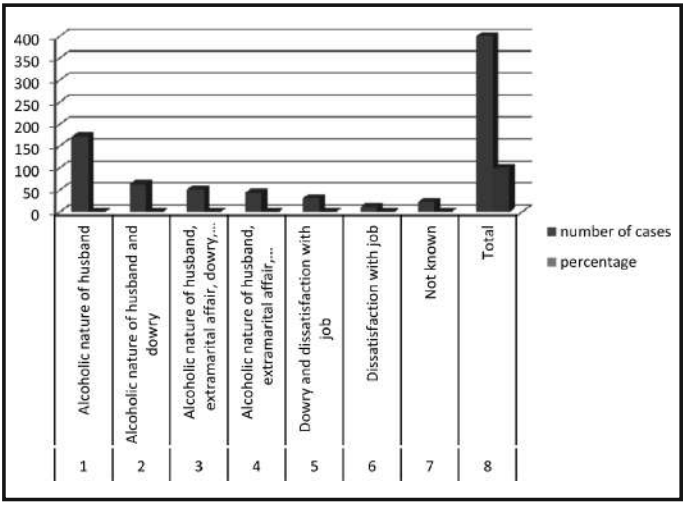

Table 2 :

Percentage of health issues associated with domestic violence and the corresponding number of cases attributed to domestic violence.

Sr. No.	Health Problems	Number of Cases	Percentage
1	Miscarriage, Headache, Depression, Anxiety, Fainting and Sleep disturbance,	52	13%
2	Sleep disturbance, Gastrointestinal problems, Anxiety, Eating disorder and depression	28	07%
3	Eating disorder, Headache, anxiety, Sleep disturbance, Depression and Homelessness	36	09%
4	Miscarriage, Headache, Anxiety, Fainting, Depression and Sleep disturbance	24	06%
5	Sleep disturbance, Headache and PTSD,	236	59%
6	Excessive workload	04	01%
7	All of the above	20	05%
8	Total	400	100

Discussion: Domestic violence remains a critical public and social concern throughout rural India, profoundly affecting the physical, mental, and social health of women. This study, conducted in the rural Churu district of the Shekhawati region in Rajasthan, investigated the prevalence of domestic violence among women aged 20 to 50 years, along with the root causes and consequences of such violence. The findings underscored both the magnitude and frequency of domestic violence occurrences. A range of factors contributing to domestic violence was identified, resulting in significant health issues, including anxiety, depression, headaches, and sleep disturbances. This research framed domestic violence as a

multifaceted issue that encompasses social, mental, economic, and cultural aspects impacting women.

The findings of this study are consistent with research conducted in twelve rural regions across India, South Asia, Africa, and other global areas, highlighting domestic violence as a widespread social, economic, mental, and physical issue. A related investigation in the neighboring state of Haryana revealed that 41.7% of women experienced domestic violence from their husbands, largely attributed to economic dependency and a lack of personal autonomy (Kishore & Gupta, 2009). The Indian National Family Health Survey (NFHS-5) indicates a notable prevalence of domestic violence in Rajasthan, with reported rates as high as 25%. However, it is crucial to acknowledge that underreporting significantly complicates the accuracy of these surveys. Comparative studies across South Asia demonstrate consistent patterns of domestic violence in rural environments. For example, research in Nepal indicated that 48% of married women reported experiencing domestic violence, often associated with alcohol and substance abuse, as well as the low educational levels of their partners (Pandey et al., 2018). Global investigations into domestic violence reveal similar trends in rural areas. A study conducted in Nigeria found that 56% of women in remote rural locations have faced some form of domestic violence, with economic dependence and patriarchal cultural norms significantly contributing to the perpetuation of such abuse (Adebayo et al., 2020). Additionally, a systematic review in Ethiopian regions indicated that 63% of rural women have encountered physical or psychological violence at some point, primarily due to financial dependency and the emotional pressures linked to marriage (Tesfaye et al., 2021). The health consequences identified in the current research, including miscarriage, anxiety, depression, and sleep disturbances, are in line with findings from a multi-country study conducted by the World Health Organization, which identified physical and mental health issues as the primary outcomes of domestic violence (Garcia-Moreno et al.2006). A recent investigation conducted in neighboring Bangladesh has identified a link between domestic violence and adverse reproductive health outcomes, including miscarriage. This finding emphasizes the urgent need for integrated healthcare responses (Rahman et al., 2020). The study's outcomes highlight the importance of comprehensive

interventions in rural areas, which should include legal education, counseling services, and healthcare support to alleviate the impact of domestic violence on women. By identifying the key factors related to domestic violence and their consequences, the Shekhawati region, the focus of this research, provides a crucial basis for developing targeted strategies to prevent and address domestic violence in rural Rajasthan. These insights can assist social and cultural policymakers, government health service providers, and justice systems in comprehending the effects of domestic violence and in implementing effective policy measures. They underscore the need for a coordinated approach to improve the safety and well-being of all women facing similar challenges.

In summary, the research has revealed that the consumption of alcohol and drugs serves as the foremost catalyst for domestic violence in the rural areas of Churu district within the Shekhawati 9 region. This is further exacerbated by factors such as dissatisfaction in employment and stress related to family dynamics. These variables play a significant role in the increased incidence of violence. The repercussions of domestic violence are primarily observed as physical and mental health challenges, which include anxiety, depression, sleep disorders, abortion, and various other health complications. This study seeks to illuminate the issue of domestic violence, a persistent and grave concern, along with its harmful consequences. It is crucial to address this matter without targeting any particular community, while also acknowledging the widespread challenges faced in the region and the overarching interests of society.

References :

Bhattacharya, P., et al. (2020). Socio-demographic factors influencing domestic violence in Rajasthan. International Journal of Population Studies, 5(3), 89-97.

Bhattacharya S, Basu R, Khatri AK. A study on domestic violence and its impact on women's health in a rural area of Maharashtra. Indian Journal of Public Health. 2019;63(1):4-8.

Garcia-Moreno C, Jensen HA, Ellsberg M, Heise L, Watts C. Prevalence of intimate partner violence: findings from the WHO multi-country study on women's health and domestic violence. The Lancet. 2006;368(9543):1260-1269.

Heise, L., & Garcia-Moreno, C. (2002). Violence by intimate partners. World Report on Violence and Health. World Health Organization.

Kishore S, Gupta K. Gender equality and women's empowerment in India. National Family Health Survey (NFHS-3), India, 2005-06.

Krug, E. G. et al. (2002). The global burden of domestic violence. Social Science and Medicine, 52(4), 543-561. Journal of Family Medicine and Primary Care, 9(1), 17-22.

Mahantashetty S, Singh J, Dhandapani S. Revised BG Prasad classification for October 2023. National J Community Med 2024;15(1):89-90. DOI: 10.55489/njcm.150120243515 8.https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/15436/1/protection_of_women_from_domestic_violence_act%2C_2005.pdf

National Family Health Survey (NFHS-5), India (2019-2021). International Institute for Population Sciences (IIPS) and Ministry of Health and Family Welfare.

Pandey S, Lama G, Lee H. Domestic violence in Nepal and its impact on women's health. BMC Women's Health. 2018;18:54.

Patel, V., et al. (2018). Social determinants of marital violence in South Asia. Lancet Psychiatry, 5(12), 947-956.

Rahman M, Nakamura K, Seno K, Kizuki M. Intimate partner violence and adverse pregnancy outcomes in Bangladesh: a nationwide population-based study. BMJ Open. 2020;10(2):e032162.

Sharma, R. (2019). The impact of substance abuse on domestic violence in rural India. Journal of Rural Studies, 70, 125-134.

Tesfaye G, Adena G, Yonas T. Prevalence and associated factors of intimate partner violence among women in rural Ethiopia. Journal of Women's Health. 2021;30(3):324-331. 13.

Dr. Jaidave Prasad Sharema

(Associate Professor)

sharmajaidev4@gmail.com

Mob. No. 9414637531

❑ ❑ ❑

बस्तर की जनजातियों की धरोहर : कुटीर उद्योग

मनहरण कुमार लहरे • प्रो. आभा रूपेन्द पाल

छत्तीसगढ़ राज्य में 2011 के जनगणना के अनुसार 2,55,45,198 जनसंख्या है, जिनमें आदिवासी जनसंख्या 78,22,902 है, उस जनसंख्या का लगभग 68: आदिवासी बस्तर संभाग निवास करते है। अध्ययन से पता चलता है, हमारे पूर्वज अपने जीवन निर्वहन के लिये परिवार के समस्त सदस्य साथ मिलकर पाषाण, मिट्टी, लकड़ी, लौह, कांसा आदि की विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का निर्माण करते थे। विद्वान बी.डी. कृष्णस्वामी इन्द्रावती नदी के समीप लघुपाषाण उद्योग विकसित होने को प्रमाणित करता है। साथ ही इन्द्रावती नदी के सहायक नदियों और सुकमा के जीवनदायिनी नदी शबरी नदी के पास भी उद्योगों के अवशेष प्राप्त हुए है। ये सारी ऐतिहासिक तथ्य इस बात का साक्ष्य हैं कि बस्तर संभाग प्राचीन समय से ही औद्योगिक रूप से सम्पन्न रहा होगा। यहां के लोग जो कि जनजाति के है वे सदैव प्राकृतिक वातावरण पेड़, पौधों व पहाड़ियों के गोद में पले बढ़े है। यही वजह है कि वह अन्य समुदाय के लोगों से अधिक प्राकृतिक के प्रति लगाव रखते है जो सभी प्राणी के जीवन के लिये आवश्यक है। इसी प्रकृति से वे अपने जीवन के समस्त अर्थोपार्जन के सामग्री प्राप्त करते है।

शब्द कुंजी : *बुनकर, शिल्पकार, टेराकोटा, कारीगर, हाट बाजार, विपणन, विकास बोर्ड।*

शोध का उद्देश्य :-प्रस्तुत शोध पत्र का प्रमुख उद्देश्य बस्तर की जनजातियों के द्वारा अपने आर्थिक जीविकोपार्जन के लिए किए जा रहे वस्तुओं के निर्माण की ऐतिहासिकता, उनके पांरपरिक-सांस्कृतिक जुड़ाव, स्वतंत्रता के पश्चात् यहां के कुटीर उद्योग के कार्यों की प्रगति व स्वरूप में हुए परिवर्तन, महिलाओं के भागीदारी की जानकारी, वस्तुओं के विक्रय के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का जानकारी प्रस्तुत करना है।

शोध प्रविधि : प्रस्तुत शोध पत्र में प्राथमिक स्त्रोत-रिपोर्ट'स', गजेटियर'स', पत्र-पत्रिकाएं, साक्षात्कार, स्थल अवलोकन तथा द्वितीयक स्त्रोत के रूप में पं. सुदंरलाल शर्मा ग्रंथालय-पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि. परिसर रायपुर, महंत सर्वेश्वरदास ग्रंथालय-शहीद स्मारक भवन, रायपुर व अन्य पुस्तकालयों से विभिन्न पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए।

प्रस्तावना : ब्रिटिश काल के समय बस्तर एक सांमती राज्य के रूप में था, जिसकी स्थिति 17°48' से 20°14' उत्तरी अक्षांश और 80°15' से 82°1' पूर्वी देशांक्ष के मध्य था। यह क्षेत्र स्वतंत्रता के पूर्व सेंट्रल बेरार का हिस्सा था उसके पश्चात् 1 जनवरी 1948 को मध्यप्रांत में सम्मिलित कर जिला बनाया गया। 25 मई 1998 को उत्तर बस्तर कांकेर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा नाम से 2 जिला बस्तर जिला को विभक्त कर बनाया गया, वर्तमान में यहां सात जिलें बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कोण्डागांव, बीजापुर, नारायणपुर है। यह एक वनांचल क्षेत्र है इसलिए यहां का जनजीवन चारों ओर से वनों से घिरा हुआ है, जीवन के प्रत्येक आयाम में वनों के उत्पाद का उपभोग होता है। लोग अर्थिक व्यवस्था के लिए कुटीर उद्योग के रूप में बांस, लकड़ी, सिसल, घास (लंबे डंडाल) के टोकरी, चटाई, झापी, काष्ठ की देवी देवताओं की प्रतिमा, मछली, कछुए और बच्चों के खेलने के लिए औजार आदि, सिसल से विभिन्न प्रकार सजावटी वस्तुएं दीवाल के लिए झालर, पेन स्टैंड, की रिंग, फल रखने के पोट और घास के लंबे डंडाल से फूल बाहरी बनाया जाता यह कार्य अबूझमाड़ के जनजातियों द्वारा अधिक मात्रा में किया जा रहा है जो काफी समय इस कार्य में संलग्न हैं। कांसा और पीतल के सम्मिश्रण से बनाया जाने वाला गड़वा शिल्प जिसमें दीप से लेकर विभिन्न जीव-जंतुओं, धार्मिक कार्यों के वस्तुएं और लौह के भी अनेकों प्रकार के शिल्प सजावटी, कृषि संबंधी औजार, घर कार्य से संबंधी औजार आदि बनाये जा रहे है, जो इन लोगों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा है।

बस्तर संभाग के कुटीर उद्योगों का संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार है–

हाथकरघा/बुनकर वस्त्र शिल्प कुटीर उद्योग : बस्तर में कोसा सूत कताई और कपड़ा बुनाई कार्य अतीत से हो रहा है। बस्तर कोसा के महत्वपूर्ण केन्द्र के लिए प्रसिद्व है। इस क्षेत्र में हाथकरघा उद्योग को तीव्रतम गति तब मिला जब सन् 1968 में अम्बिकापुर में स्थित कोसा अनुसंधान केन्द्र को जगदलपुर में स्थानांतरित कर किया गया। कोसा संबंधित संस्थान–सन् 1962 में कोसा बीज उत्पादन केन्द्र-जगदलपुर, सन् 1965 में बीजापुर एवं सन् 1967 में कोसा बुनाई केन्द्र-जगदलपुर, कोसा कपड़ा उत्पादन केन्द्र-जगदलपुर में किया गया।

यहां प्रतिवर्ष 35000 मीटर कोसा का उत्पादन किया जा रहा था। जिसका मूल्य सन् 1976-77 के दौरान लगभग 11 लाख रुपये था, जबकि सरकार ने विभिन्न कोसा केन्द्र के लिए 1,68,483 रुपये खर्च किया और खादी ग्रामोद्योग ने बुनाई केन्द्र पर 65,868 रुपये खर्च किया।[1] तोकापाल के बुनकर भूरसुदास मानिकपुरी बचपन से अपने पिता के साथ कार्य कर रहा है अभी उनकी आयु 80 वर्ष है, उनके द्वारा यह जानकारी प्राप्त हुआ है कि तोकापाल गांव के आधे लोग हाथकरघा के द्वारा कपड़ा बुनाई का कार्य करते थे परंतु वर्तमान में इस गांव में केवल वह ही अपनी जीविका चलाने लायक कार्य करते है। जिसमें पांरपारिक गमछा व साड़ी बुनते हैं। इस से समझा जा सकता है इस उद्योग की स्थिति कितनी दयनीय है।[2] सन् 1880 के आसपास बस्तर शासक भैरमदेव के समय एक व्यापारी हनुमान दीक्षित ने रायपुर से कपड़ा लाकर बेचना शुरु कर दिया तथा और भी व्यापारी उनसे प्रोत्साहित होकर यह कार्य करने लगे जिससे बुनकरों के सामने विकट स्थिति प्रकट हो गयी और उनके बुरे समय की शुरुवात हो गयी। स्वतंत्रोत्तर पश्चात् शासन की पहल से उनकी स्थिति मे काफी सुधार हुआ।[3]

मिट्टी शिल्प/माटी कला : मानव के उद्भव से विकास तक मिट्टी की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। मिट्टी के बर्तन के उपयोग का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त मिट्टी की वस्तुओं से मिलता है जिससे इसकी प्राचीनता का पता चलता है।[4] छत्तीसगढ़ में आज भी मिट्टी के बर्तन, अनाज रखने की कोठियां, दीप स्तंभ बनाने की कला प्रचलित है। बस्तर के मृदा शिल्पकला में जीवन और प्रकृति से जुड़ी विभिन्न वस्तुओं के साथ ही यहां की धार्मिक प्रतीकों को कलात्मक स्वरूप प्रधान की जाती है। इन कलाकृतियों की लोकप्रियता की गूंज देश के कोने-कोने तक गुंजायमान हो चुकी है।[5] बस्तर संभाग में मृदा शिल्प कला का कार्य बहुत रोचकपूर्ण तरीके से बहुत पहले से किया जा रहा है, मिट्टी से बर्तन, बाउल, टी सेट, पानी बाटल सादा, होटल व घरों के साज सज्जा के वस्तुएं, जानवरों जिसमें गाय, बैल, सिंह, हाथी, हिरण आदि, देवी देवताओं की मूर्तियां, मानव मुखौटे, गमले, घड़े आदि वस्तुएं बनाये जाते है।[6] मृदा से बनी ये वस्तुएं 'टेराकोटा' के नाम से प्रसिद्व हो रही है।[7] बस्तर में मिट्टी शिल्पकला के प्रमुख चार केंद्र है–नारायणपुर, कुम्हारपारा-कोंडागांव, नगरनार और एड़का। वृंदावन और चंदन सिंह कुम्हार भारत महोत्सव लंदन में तथा बस्तर के झितरुराम बघेल सर्वश्रेष्ठ मृदा शिल्पकार जिन्होंने फ्रांस अमेरिका में आयोजित भारत महोत्सव में यहां की मृदा शिल्पकला को प्रदर्शित कर विदेश में पहचान दिलाई।[8]

काष्ठ शिल्पकला : काष्ठ शिल्पकला का प्राचीन समय से बर्तन, दरवाजें, बैलगाड़ी, रथ, पहिये, खिलौने, शतरंज के मोहरे आदि वस्तुएं बनते आ रहा है जो अभी तक जीवंत है, आधुनिक समय में कुछ काष्ठ के स्थान पर नये पदार्थो का उपयोग हो रहा है।[9] इस में कोई संदेह नहीं है बस्तर कैं काष्ठ शिल्पकला उद्योग विश्व प्रसिद्व है, जिसकी मांग विभिन्न शहरों में होती है, दिल्ली जैसे महानगरों में सरकारी उपक्रम शबरी एम्पोरियम के द्वारा बिक्री की जा रही है। यहां पर सुंदर खिलौनें, पलंग, पैनल, सोफा सेट, सल्फी पेड़ माडर्न आर्ट, राधा-कृष्ण, गणेश जी, पेन स्टैंड, केण्डल, माड़िया-माड़िन, कुल्हाड़ी, पशु पक्षि, बेल-बूट तीर-धनुष, फूल-पतियां, सभी के प्रकार की मूर्तियों का वॉल पीस नक्कासी कर बनायी जाती है।[10] जगदलपुर के मानव संग्राहलय जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के एक मात्र मानव संग्राहलय है जहां पर यहां के जनजाति शिल्पियों द्वारा अत्यंत उच्च स्तर के काष्ठ शिल्प बनायी गयी है।[11] बस्तर में परंपरागत ढ़ंग से मुरिया, धुरवा, माड़िया, भतरा जनजाति काष्ठष्शिल्प का कार्य करती आ रही है।[12] अगर उदाहरण देखना चाहे तो सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बस्तर में 75 दिनों तक चलने वाले दशहरा में विभिन्न प्रकार रथ-बड़े रथ(रैनी), छोटे (फूल) रथ, का बनाया जाना है, जिनमे पहियों की संख्या क्रमशः 8, 4, होते है।[13] काष्ठ शिल्प कला बस्तर संभाग में प्रमुखता कोंडागांव, नारायणपुर, जगदलपुर व उस के समीप लगे ग्राम परचनपाल में काफी उन्नत व प्रख्यात हैं। बस्तर के काष्ठशिल्प कला को देश-विदेश तक पहुंचाने में अरुण गुहा जी का डांसिग कैक्टस नामक संस्था लगन और कड़ी मेहनत से सफलता प्राप्त की है जिसके लिए उन्हें नेशलन अवार्ड सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से नवाजा जा चुका है।[14] सवित्री साहू ने सन् 1998 में बस्तर ट्रेडिशनल आर्ट सेंटर नामक संस्था की स्थापना की जो बस्तर के पांरपरिक सांस्कृतिक कला कृतियों को काष्ठ शिल्प के बारीक नक्काशी के द्वारा लोगों तक

पहुंचा रही है, इस संस्था के माध्यम से ग्रामीण युवती व महिलाएं अपने-अपने घरों में कुटीर उद्योग के रूप में कार्य कर धन प्राप्त कर अपने परिवार की देखभाल कर रही है। यहां के अवलोकन से मैंने पाया विभिन्न महापुरुषों के मूर्ति लकड़ी के द्वारा बनाये जा रहा है। ये ज्यादातर वस्तुएं सागौन की लकड़ी से बनाया जाता है।[15]

फूल झाड़ू : जिन्हें सामान्य बोलचाल की भाषा में फूल बाहरी भी कहते है। फूल झाड़ू अधिकत्तर अबूझमाड़(नारायणपुर), कांकेर, भानूप्रतापपुर, सुकमा, दन्तेवाड़ा क्षेत्र में कुटीर उद्योग के रूप में परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर बनाते है। इस कार्य के लिये वे जंगल में जाकर एक विशेष प्रकार के लंबे डंडाल के डालियां काटकर लाते है। जिसके ऊपर फूल लगा होता है इसीलिए इस से निर्मित झाड़ू को फूल बाहरी कहते है।[16]

कौड़ी शिल्प : कौड़ी शिल्प कला बस्तर में बंजारा समुदाय के लोगों द्वारा अपने जीवनयापन के लिए कुटीर उद्योग के रूप में किया जाता है, इस कार्य के साथ वे कृषि कार्य भी करते है। जगदलपुर से महज 25-26 किलोमीटर दूर गांव इरिकपाल के कौड़ी शिल्पकार लिमा नायक इस कार्य में संलग्न है, वह लहंगा चोली, दुपट्टा, कमरबंध, सिरबंध, हाथबंध, बाजूबंध, टोकनी, ईयर रिंग, नोज रिंग, कड़ा कुण्डल, आदि बनाते है। जिसमें प्रमुख है, गौर सिंग, देवीमाता का कपड़ा।[17] इरिकपाल के शिल्पी बुधसन नायक 5 अप्रैल 2022 से 7 सितम्बर 2022 तक छः माह में छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास केन्द्र, जगदलपुर को 39000.00 रुपये का कौड़ी शिल्प विक्रय किया।[18] हीरासिंह नायक के मतानुसार बस्तर में कौड़ी का उद्भव व विकास राजस्थान के बंजारो

के एक गांव से हुआ है, बंजारा राजस्थान से आंध्र प्रदेश के वारंगल, वारंगल से बस्तर आये।[19] तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि कौड़ी का प्रयोग बस्तर ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में प्राचीन काल से हो रहा था।

लौह शिल्प : लौह अयस्क खनिज के लिए बस्तर कितना समृद्व है यह किसी से छिपा नहीं है, दन्तेवाड़ा जिला में संचालित राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड लौह उत्खनन उद्योग है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति अर्जित कर चुकी है।[20] लौहे से वस्तुओं का निर्माण चाहे आत्मरक्षा के लिए औजार भाला, बरछी, फरसा हो या कृषि उपकरण-कुदाली, हल के नास, सब्बल व दैनिक कार्यो के हसिया, कडरा(छुरी), चिमटा तथा धार्मिक कार्यो के लिए देवी-देवताओं के प्रतिमा, देव मुकुट आदि प्राचीन काल से बनाया जा रहा है।[21]

बस्तर संभाग के जनजातियों के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से लौह शिल्प जुड़ा हुआ है। यह कार्य अधिकत्तर स्थानीय लोहार जाति द्वारा किया जाता है,[22] वे

अपने आर्थिक धनार्जन के लिए कुटीर उद्योग के रूप में कार्य कर रहे है। यहां पर लौह शिल्प कला के तोड़ी बेस, लामन दीया, तोड़ी, सल्फी पेड़, माड़िया-माड़िन, हाथी, घोड़ा, हिरण, म्यूजिशियन, शेर ढाल आदि शिल्प बनाया जा रहा है।[23] इस कला में दीप-स्तंभ अधिक प्रसिद्व हुआ है।[24] 10 जुलाई 2008 को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री भारत सरकार के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा बस्तर लौह शिल्प कला को जी.आई. सर्टिफिकेट का प्राप्त होना इसकी उपलब्धि को इंगित करता है।[25]

पत्थर शिल्प : बस्तरांचल के विभिन्न स्थानों से प्रागैतिहासिक कालीन पाषाण उद्योगों का पाया जाना पत्थर शिल्प कला को और अधिक महत्वपूर्ण बना देता है। बस्तर में पूर्वपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, उत्तरपाषाण काल नवपाषाण काल अर्थात् चारों अवस्थाओं के उपकरण क्रमशः स्थानों–कालीपुर इद्रांवती तट पर, देउरगांव, गढ़चदेला आदि से प्राप्त हुआ है।[26]

सुकपाल धुरवा ने सन् 1998 में देउरगांव में काष्ठ कला समिति की स्थापना की। इस समिति के द्वारा काष्ठ शिल्प तैयार की जाती है, परंतु पत्थर शिल्प के लिए भी यह संस्था प्रसिद्व है। बस्तर के लोक-संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए नक्कांशी कर खासकर देवी-देवताओं के अनेक मुद्रा और हाथी, शेर, नंदी, वन भैंस, आदि जानवरों की मूर्ति पत्थरों पर उकेरा जाता है। नक्काशी का कार्य कड़ी पत्थर पर किया जाता है।[27]

सिसल शिल्प : सिसल एक प्रकार का जंगली पौधा होता है जिससे रेशे प्राप्त कर पेन स्टैंड, नौका, झुमर, फल टोकनी, बास्केट, डायनिंग टेबल मेट, टी-कोस्टर, कार झुमर हैंगिग, दीवाल झुमर, बैग, वॉल पीस, गुड़िया, कछुआ आदि कला कृति बनायी जाती है। श्रीमती सोभा बघेल और उन के परिवार के सदस्य लगभग 20-21 वर्षों से निरंतर सिसल शिल्प के कुटीर उद्योग चला रही हैं। हल्बी बोली में सिसल को रॉने बांस कहते है। जगदलपुर से 10 कि.मी. के आसपास में कोलचुर गांव है, इस गांव में राने बांस की खेती की जाती है। जहां से शिल्पकार कच्चा उत्पाद लाते है, उन्हें लाकर रंगाई कर जिस प्रकार के शिल्प बनाना है उसी प्रकार उस वस्तु को आकार देते है।[28]

गड़वा/घड़वा शिल्पकला : समायंतर किसी भी वस्तुओं के नाम में बोली अपभ्रंश परिवर्तन हो जाता है। घढ़वा शब्द का उद्‌भव गढ़वा (मूलरूप) से हुआ है, गढ़वा से गड़वा और गड़वा से घड़वा हो गया। घड़वा कांसा और पीतल के मिश्रण से बना धातु है। घंटी इसी मिश्रित धातु से बनाया जाता है, इस कारण इसे घंटी धातु के नाम से पुकारा जाता है। वर्तमान समय में यह बेलमेटल शिल्प के नाम से प्रसिद्व है।[29]

घड़वा कला को ढोकरा कला भी कहा जाता है।[30] मोम और मिट्‌टी का उपयोग कर बेलमेटल से तोड़ी, हिरण, हाथी, घोड़ा, माड़िया-माड़िन, सल्फी

पेड़, बैलगाड़ी, माता की मूर्ति आदि निर्मित किया जाता है।[31] बस्तर संभाग में इस कला के अनेक कलाकार हैं, जिनमें कोण्डागांव के जयदेव बघेल ने ढोकरा शिल्पकला को अंतरराष्ट्रीय स्तर में स्थापित करने में अहम् भूमिका निभाई है, बघेल जी की शिल्पकला विदेशों के आर्ट गैलरी में प्रदर्शित हो चुकी है। बेलमेटल शिल्पों का विदेश में निर्यात होती है जिससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक है।[32] बस्तर के छिदंक नागवंशी राजवंश में सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक सोमेश्वर प्रथम (1069 ई.-1111 ई.) था।[33] इसके प्राप्त शिलालेख 'कुरुसपाल शिलालेख' से कांशरवाड़ो स्थल का वर्णन मिलता है। जिससे यह अनुमान लगाया जाता है, यहां पर कास्य धातु के शिल्पकार रहे होंगे।[34]

बांस शिल्पकला : बस्तर में बांस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।[35] बांस की महत्ता की प्रशंसा जितनी भी किया जाय कम है, अगर आप आकलन करें तो पाओगे बस्तर संभाग के जनजातियों के जीवनचक्र में बांस से बनी वस्तुओं के आवरण दिखेगा। इन्हें इस तथ्य के द्वारा भी समझा जा सकता है, बस्तर का नामकरण बांस की झुरमुट (तरी) की वजह से पड़ी, काकतीय वंश के

संस्थापक अन्नमदेव बस्तर आगमन कर बांस के झुंड के तरी (नीचे) में रहने के कारण इस स्थान का नाम बांसतरी रखा गया जो बाद में अपभ्रंश होकर बस्तर हो गया।[36]

यहां बांस की अनेक सामाग्री घर में परिवार के सदस्य साथ मिलकर बनाते है। ये सामाग्री है-झांपी, सूपा, टोकनी, छत्तोड़िया, चटाईयां, ककई, टाटी (मछली सुखाने का उपकरण), टाकरा (अनाज रखने का उपकरण), झांवा (मिट्टी उठाने का उपकरण), बस्तर में प्रचालित वाद्ययंत्रों का निर्माण भी बांस से किया जाता जैसे धनकूल में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र, शिकार के लिए तीर-कमान बांस से ही बनाया जाता था। इन सामग्रियों का हॉट, मेले-मड़ई में बिक्री कर वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते है।[37] आधुनिक समय में दस्तावेज रखने का फाइल और रुपये रखने के लिए पर्स भी बांस से बनाया जा रहा है।[38]

तुमा शिल्प : तुमा गला फूटी, देव गला उठी (भतरी)

भतरी बोली के उपरोक्त कहावत जिसमें बस्तर संभाग के ग्रामीण अंचल में तुमा के उपयोगिता के बारे में बताया है, जिसमें तुमा को भाग्य का प्रतीक मानते हुए कहा गया है—''भाग्य फूट गये, तो देवता भी साथ नहीं देते''[39]

बस्तर प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण क्षेत्र है, यहां के लोग प्रत्येक वनस्पति, फल-फूल, पत्ति का उपयोग बड़े रोचक ढंग से करते है। तुमा जिसे सामान्य तौर

पर में खाद्य पदार्थ के रूप में सब्जी के लिए करते है। बस्तरवासी तुमा को पेड़ (नार) में ही सूखने देते हैं, सूखने के बाद तोड़कर उसके ऊपर जहां नार से तुमा जुड़ा होता है, वहां पर एक भूरा धुंधली-सी गोल चकते होते है उसे औजार से छिलकर मुड़े हुए राड या चाकू से अंदर के अवशिष्ट को निकाल दिया जाता है, अब वे सुराही के सामान अंदर से खोखला हो जाता है। पहले के लोग इसे में बिना सजावट किये ऐसे ही पेज, पानी, बस्तर पेय पदार्थ–लांदा, सल्फी, ताड़ी रखने व मनी बेग के समान पैसे लाने, ले जाने के लिये उपयोग करते थे। समय के साथ धीरे-धीरे बस्तर आदिवासी डांस, शिकार के चित्र, रहन-सहन आदि चित्र उकेरते थे। अब इसमें आधुनिकता प्रवेश कर गया है, गर्म लोहे के द्वारा पांरपरिक-सांस्कृतिक लोक जीवन के चित्र बनाये जा रहे हैं। चमक बढ़ाने के लिए वैक्स, पॉलिश का सहारा लिया जा रहा है। जैसे-जैसे मांग बढ़ती जा रही है तुमा शिल्प के रूपरेखा में परिवर्तन आते जा रहा है। जैसे–लैम्प, पेनस्टैण्ड, कप, गिलास, तोरण, झुमर, चिड़िया घोसला, होटल में सजावट के सामान आदि बनाया जा रहा है।[40]

हमारी सांस्कृतिक विरासत हस्तशिल्प कलाएं ये कही लुप्त न हो जाये इस मुहिम में महिलाएं समूह बनाकर कार्य कर रही है। इन कलापूर्ण वस्तुओं के अलावा विभिन्न खाद्य सामाग्री जैसे–अचार, मेथी लड्डू, ड्रायफूट लड्डू, ईमली चपाती, महुआ टी, और आयुष उत्पाद हर्बल कॉफी चूर्ण, बहेड़ा, रीठा, हर्रा, गिलोय चूर्ण आदि। निम्नलिखित समूह द्वारा बनाया जा रहा है–

- मां दन्तेश्वरी स्व सहायता समूह, बीजापुर
- जगतमाता स्व सहायता समूह, बीजापुर
- सत्यम संकुल महिला स्व सहायता समूह, कटेकल्याण
- कांकेश्वरी महिला कृषक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, कांकेर
- उड़ान महिला कृषक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, कोण्डागांव[41]

विक्रय केन्द्र :

हॉट बाजार, मेले-मड़ई : बस्तर संभाग के चुनिंदा ग्रामों में हॉट-बाजार लगाया जाता है, लेकिन हॉट बाजार शब्द सुनते ही आपको अभास होता होगा की यह मैदानी क्षेत्र में लगे सामान्य हटरी बाजार जैसे होता होगा परंतु बस्तर संभाग में लगने वाले बाजार आधुनिक समय के सुपर बाजार या सरकार द्वारा लगाये गये सी-मार्केट के समान है जहां पर लगभग सभी वस्तुएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो जाते है, बस्तर वासी स्वयं व अपने परिवार के द्वारा बनाये गये

वस्तुओं का यहां पर बिक्री कर धनार्जन कर अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते है।

मेले–मड़ई तो यहां की धार्मिक सांस्कृतिक परंपराओं का एक संगम है, साथ ही साथ कुटीर उद्योग से बने वस्तुओं के विक्रय केन्द्र भी है। जिनके आयोजन के लोग बहुत पहले से इंतिजार करते है कारीगर शिल्पकार विभिन्न प्रकार के शिल्प बनाकर रखते है ताकि वे वहां जा कर बिक्री कर सके, जन सामान्य लोग धीरे-धीरे धन इकठ्ा करते है मेले-मड़ई की तैयारी और खरीदारी के लिये जिससे वे इस पल का भरपूर आंनद उठा सके।[42]

छत्तीसगढ़ शासन के छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के उन्नव पहल द्वारा छत्तीसगढ़ के निम्न शहरों-रायपुर-पंडरी, आमापारा, सुंदरनगर-रायपुर, माना-एयरपोर्ट रायपुर, भेंलवापदर-कोण्डागांव, परचनपाल-बस्तर, कलेक्ट्रेट-राजनांदगांव एवं अन्य राज्य गुजरात के अहमदाबाद शहर में, दिल्ली के राजीव गांधी शिल्पभवन में शबरी एम्पोरियम की स्थापना की गयी जहां पर बस्तर निर्मित शिल्पों का विक्रय किया जा रहा है। जिससे मुद्रा की प्राप्ति तो होती है, साथ ही साथ आदिवासी ग्रामीणों को रोजगार की प्राप्ति होती है। वे सामाजिक आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ता प्राप्त करते है और बस्तर की सांस्कृतिक से लोग रु-ब-रु होते है। बाहारी लोगों की मानसिकता में यह परिवर्तन लाने में कुटीर उद्योग अहम भूमिका निभाता है।

हस्तशिल्प कला के संरक्षण व संवर्धन के लिये 1 जुलाई सन् 1982 को

छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड की स्थापना जगदलपुर, जिला-बस्तर में किया गया। जिला–बस्तर, विकासखण्ड-जगदलपुर के नेशनल हाईवे-30, में अवस्थित ग्रम-परचनपाल में हस्तशिल्प कला विकास केन्द्र की स्थापना की गयी है। इसे शिल्पग्राम परचनपाल के नाम से जाना जाता है।

छत्तीसगढ़ शासन ग्रामोद्योग विभाग के द्वारा संचालित छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड द्वारा समय-समय पर विभिन्न शिल्पकला का प्रशिक्षण दिया जाता है। सन् 2019-20 में जिला-बस्तर के अनेक गांवों-सिरमुड़ा, तारागांव, करीतगांव, कूरुषपाल, नारायणपाल आदि में प्रशिक्षक-भगतराम, बुधराम बघेल, तातीराम विश्वकर्मा एवं अन्य प्रशिक्षकों द्वारा बेलमेटल, काष्ठशिल्प, तुमा शिल्प, शिसल व अन्य विधाओं में प्रशिक्षण दिया गया।[43]

सन् 1977-78 तक जिला कोण्डागांव के ग्राम कुसमा में 3 गृह उद्योग (कुटीर उद्योग) खपरैल बनाने के और ग्राम बनियांगांव में 5 कुटीर उद्योग थे, जिनमें 4 खपरैल, 1 उद्योग बांस की वस्तुएं–टोकरी, डलियों का निर्माण करने के थे। जिस तरह रसोइयां पकते हुए चांवल के दो तीन दानों को छु कर यह पता लगा लेते है कि चांवल पका है या नही ठीक वैसे ही इन गांवों के विवरण से कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र में कुटीर उद्योग अधिकतर लोगों द्वारा संचालित किया जाता रहा होगा।[44]

निष्कर्ष : छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक रीति-रिवाज और विभिन्न लोक कलाओं चाहे वह माड़िया, धुरवा नृत्य हो या बेलमेटल के हस्तकला सभी में सिद्व हस्त है, जो यहां के गौरव को देश के कोने-कोने व विदेशों में भी बिखेर रही है। साथ ही साथ उनके आर्थिक जीवन भी लगभग इन्ही कलाओं के इर्द-गिर्द कुटीर उद्योग के रूप में घूमती है, जो आज से नहीं अपितु प्राचीन समय से चली आ रही है, पाषाण, लौह, कांसा, पीतल, काष्ठ, बांस, घास आदि से विभिन्न सजावटी व दैनिक उपभोग की वस्तुओं व देवी-देवताओं की मूर्ति, प्रतिमा पशु-पक्षी, जानवरों का निर्माण करना जो इन वनांचल जनजाति के आर्थिक, सामाजिक व सांस् कृतिक जीवन में रचा-बसा हुआ है। हमारी यह जिम्मेदारी बनती है यहां के कुटीर उद्योग जो आर्थोपाजन के साथ सामाजिक व सांस्कृतिक धरोहर भी है जिसे सहेज कर रखना है, जो आर्थिक तंगी से जुझ रहे लोगों के लिए एक रोजगार का साधन के रूप में उपलब्ध होगा।

संदर्भ :

1. गजेटियर्स ऑफ इंडिया, मध्यप्रदेश, बस्तर, डॉरैक्टेड ऑफ राजभवन एवम् संस्कृति डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, मध्यप्रदेश, भोपाल-2000 पृ.171-173
2. साक्षात्कार, भुरसूदास मानिकपुरी, बुनकर, तोकापाल, जगदलपुर, 16 अक्टूबर 2022
3. पाल, आभा रूपेन्द्र, खुटे, डिश्वर नाथ, बस्तर राजनीतिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, ओरियंट ब्लैकस्वान प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, प्रथम संस्करण-2021, पृ.106-107
4. https://www.socialresearchfoundation.com/new/publish-journal.php? editID=5079
5. छत्तीसगढ़ राज्य की पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2013, कला व शिल्प, राज्य फोकस समूह का आधार पत्र, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़, रायपुर, 2016-17, पृ. 9
6. शोधार्थी के द्वारा स्थल अवलोकन-सी-मार्ट, जगदलपुर, दिनांक -18/10/2022
7. जगदलपुरी, लाला, बस्तर इतिहास एवं संस्कृति, मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, चतुर्थ संस्करण-2016, पृ. 239
8. शुक्ल, हीरालाल, छत्तीसगढ़ ज्ञान कोष, मध्य प्रदेश,हिंदी ग्रंथ अकादमी, प्रथम संस्करण- 2003,पृ. 260
9. माथुर, कमलेश, हस्तशिल्प कला के विविध आयाम, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, प्रथम संस्करण, 1997, पृ.52
10. छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड (छत्तीसगढ़ शासन ग्रामोद्योग विभाग), जगदलपुर जिला-बस्तर, से प्राप्त जानकारी-20 अक्टूबर 2022
11. पाल, आभा रूपेन्द्र, खुटे, डिश्वर नाथ, पूर्वोक्त, पृ.104
12. महावर, निरंजन, छत्तीसगढ़ की शिल्पकला, राधा पब्लिकेशन्स, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-110002, पहला संस्करण-2014, पृ.24
13. जगदलपुरी, लाला, बस्तर इतिहास एवं संस्कृति, पूर्वोक्त, पृ.240
14. पाल, आभा रूपेन्द्र, खुटे, डिश्वर नाथ, पूर्वोक्त, पृ.105
15. साक्षात्कार, रमेश साहू, बस्तर ट्रेडिशनल आर्ट सेंटर ढकरागुड़ा, जिला-बस्तर - 16 अक्टूबर 2022
16. नायडू, पी.आर., भारत के आदिवासी विकास की समस्याएँ, राधा पब्लिकेशन्स, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-110002, द्वितीय संस्करण-2013, पृ.437

17. साक्षात्कार, लिमा नायक, कौड़ी शिल्पकार, इरिकपाल, जिला-बस्तर-16 अक्टूबर 2022
18. छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड, जगदलपुर (छ. ग. शासन का उपक्रम), जगदलपुर, जिला बस्तर से प्राप्त जानकारी-20 अक्टूबर 2022
19. वैष्णव, हरिहर, बस्तर की आदिवासी एवं लोक हस्तशिल्प परम्परा, राधाकृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली प्रथम संस्करण-2014, पृ. 269
20. एनएमडीसी हीरक जयंती एवं किरंदूल स्वर्ण जयंती स्मारिका, बैलाडीला कल और आज, एनएमडीसी लिमिटेड, बीआईओएम, किंरदूल काम्पलेक्स, दंतेवाड़ा-494556, एनएमडीसी 60 डाइमंड जुबली, पृ. 39
21. पाल, आभा रूपेन्द्र, खुटे, डिश्वर नाथ, पूर्वोक्त, पृ. 106
22. जगदलपुरी, लाला, बस्तर इतिहास एवं संस्कृति, पूर्वोक्त, पृ. 244
23. छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड (छत्तीसगढ़ शासन ग्रामोद्योग विभाग), पूर्वोक्त
24. पाल, आभा रूपेन्द्र, खुटे, डिश्वर नाथ, पूर्वोक्त, पृ. 106
25. गवर्नेमेंट फॅर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एण्ड इंटरनल हेड गर्वनमेंट ऑफ इंडिया, एनुअल रिपोर्ट 2008-09, एलुमल रिसोर्ट ऑफ ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेटस डिजाइन, ट्रेड मार्कसश एन्ड जिओग्राफिकल इंडीकेशनस, 22 अप्रैल 2008
26. शुक्ल, हीरालाल, कहां थी रावण की लंका, छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी, प्रथम संस्करण-2016, पृ.28-32
27. साक्षात्कार, बनराम नाग, काष्ठ शिल्प कला समिति, सचिव देऊरगांव, जिला-बस्तर-16 अक्टूबर 2022
28. साक्षात्कार, समली बघेल, सिसल शिल्पकार, मानपुर, जिला-बस्तर, 3 मई 2023
29. वैष्णव, हरिहर, पूर्वोक्त, पृ.19
30. पाल, आभा रूपेन्द्र, खुटे, डिश्वर नाथ, पूर्वोक्त, पृ.106
31. छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड (छत्तीसगढ़ शासन ग्रामोद्योग विभाग), पूर्वोक्त
32. पाल, आभा रूपेन्द्र, खुटे, डिश्वर नाथ, पूर्वोक्त, पृ.106
33. वही, पृ.19
34. परिहार, दिनेश नंदनी, प्राचीन छत्तीसगढ़ कर सामाजिक आर्थिक इतिहास, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, अंसारी रोड, दरियागंज नई दिल्ली-110002, प्रथम संस्करण-2003, पृ.

35. गजेटियर्स ऑफ इंडिया, मध्यप्रदेश, बस्तर, पूर्वोक्त, पृ. 179
36. वर्ल्यानी, जे.आर. एवं साहसी, वी.डी., बस्तर का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, दिव्या प्रकाशन, कांकेर, 1998, पृ. 4
37. वैष्णव, हरिहर, पूर्वोक्त, पृ. 241-266
38. महावर, निरंजन, पूर्वोक्त, पृ. 94
39. जगदलपुरी, लाला, बस्तर की लोकोक्तियां, छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी, रायपुर, प्रथम संस्करण-2008, पृ. 18
40. साक्षात्कार, तातीराम विश्वकर्मा, शिल्पकार, 31 मई 2023
41. छत्तीसगढ़ के सी.मार्ट प्रोडक्ट कैटलाक, जगदलपुर सी.मार्ट से 18 अक्टूबर 2022 को प्राप्त
42. शोधार्थी के द्वारा स्थल अवलोकन, सुकमा, हॉट-बाजार, दिन-सोमवार 4 मार्च 2019
43. छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड (छत्तीसगढ़ शासन ग्रामोद्योग विभाग), पूर्वोक्त
44. पालीवाल, चन्द्र मोहन, आदिवासी हरिजन आर्थिक विक बस्तर जिले के संदर्भ में, बुक-सेंटर, नई दिल्ली-1986, पृ.63

मनहरण कुमार लहरे
शोधार्थी
इतिहास अध्यनशाल
पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर (छ.ग.)

प्रो. आभा रूपेन्द पाल
शोध निर्देशक
से.नि. विभागाध्यक्ष इतिहास अध्यनशाला
पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर (छ.ग.)

❑❑❑

भारत में वैवाहिक बलात्कार का महिलाओं के मानवाधिकारों के उल्लंघन के रूप में अध्ययन

• विजय लक्ष्मी जोशी

शोध सार : नारी अस्य समाजस्य कुशल वास्तुकारा अस्ति।

नारी राष्ट्रस्य अक्शि अस्ति।

अर्थात् नारी समाज की आदर्श शिल्पकार है। नारी किसी भी राष्ट्र की आँखों के समान है। नारी की महत्ता को समझते हुए उनके सशक्तिकरण हेतु भारत में संविधान लागू किए जाने के बाद से कई ऐसे कानून पारित किए गए जिनमें महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किए गए चाहे वह पैतृक संपति में पुत्रियों को पुत्रों के बराबर अधिकार हो, हिन्दू पत्नियों को पतियों के समान तलाक का तथा गोद लेने का अधिकार, हिन्दू विधवा का संपति में पूर्ण अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, समानता का अधिकार आदि। किन्तु भारतीय समाज में कुछ मुद्दे ऐसे है जिन पर सांस्कृतिक पूर्वाग्रह का पर्दा है उनमें से एक है वैवाहिक बलात्कार। हमारे पितृसत्तात्मक समाज में पत्नी आज भी पति की संपत्ति मानी जाती है वह जब चाहे जब उसका यौन शोषण कर सकता है पत्नी को न तो अपने शरीर पर कोई अधिकार हैं न ही उसे संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन नीजता का अधिकार हैं ना ही उसे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के अधीन अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हैं उसके सारे मूल अधिकार एवं मानव अधिकारों की संस्कृति की रक्षा के नाम पर बलि चढ़ा दी जाती रही है और वह सदियों से वैवाहिक बलात्कार का शिकार होती जा रही है। ''भारत में विवाह एक संस्कार माना जाता है और इसलिए अंतराष्ट्रीय मानकों के आधार पर भारत में वैवाहिक बलात्कार को अपराध नहीं माना जा सकता'' सरकार का यह रूख तब है जब सभी इस सच्चाई से परिचित है कि इस पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं को

बराबरी का हक हासिल नहीं है। समाज वैवाहिक बलात्कार को मान्यता नहीं देता और सियासतदान इसे पवित्रता के आईने में देखते है यहॉ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी वैवाहिक बलात्कार के एक मामले में सुनवाई से ईंकार कर दिया। महिला सशक्तिकरण, लैगिंक समानता, बेटी बचाओं और बेटी पढ़ाओं के नारे लगाने वाला हमारा भारत देश उन 36 देशों में से एक है जिसने वैवाहिक बलात्कार को अपराध स्वीकार नहीं किया है यह हालात तब है जब हमारे पड़ोसी देश नेपाल ने भी इसे अपराध की श्रेणी में शामिल कर लिया है, विश्व के पौलेण्ड, स्वीडन, डेनमार्क, सोवियत संघ, नार्वे, आस्ट्रेलियॉ, कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका समेत 77 देशों ने वैवाहिक बलात्कार को अपराध माना है। पौलेण्ड में सर्वप्रथम 1932 में वैवाहिक बलात्कार के खिलाफ कानून को लागू किया गया। भारत में निर्भया रेप कांड के बाद बनी जस्टिस वर्मा कमेटी ने वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में रखने का सुझाव दिया किन्तु उसे 2013 में बनी संसद की स्थायी समिति ने नामंजूर कर दिया। इसी प्रकार ''पाम राजपूत कमिटी'' एवं **"UN Committee on Elimination of Discrimination Against Women** ने भी इसे अपराध की श्रेणी में रखने की माँग की जिसे यह कहकर ठुकरा दिया गया कि ऐसा करने से भारत में वैवाहिक संस्था समाप्त हो जाएगी, घरेलू हिंसा एवं दहेज कानून की तरह पत्नियों द्वारा बड़ी संख्या में इसका दुरूपयोग किया जाएगा। वर्तमान में लागू भारतीय न्याय संहिता ने पुरानी भारतीय दण्ड संहिता 1860 में अनेक परिवर्तन कर पुराने व्यर्थ कानून जो वर्तमान सभ्य एवं आधुनिक समाज के अनुरूप नहीं थे उनमें समय की माँग के अनुसार संशोधन किए किन्तु वैवाहिक बलात्कार की छूट को वर्तमान संहिता में जस का तस बनाए रखा इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। वर्तमान शोध पत्र में वैवाहिक बलात्कार को परिभाषित कर इसकी पृष्ठभूमि, इसके कारण, इसे अपराध घोषित करने के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क, इस पर न्यायपालिका का दृष्टिकोण को संक्षेप में प्रस्तुत कर निष्कर्ष एवं सुझाव दिए गए है।

बलात्कार एवं वैवाहिक बलात्कार की परिभाषा :- बलात्कार एक प्रकार का यौन हमला है जिसमें आमतौर पर किसी स्त्री की सहमति के बिना उसके खिलाफ किए गए संभोग या अन्य प्रकार की यौन गतिविधियॉ आती है। यह कार्य वैध सम्मति देने में अक्षम व्यक्ति जैसे- बेहोश, नशे में बेसुध, बौध्दिक अक्षम या सहमति देने की विधिक उम्र से कम आयु के व्यक्ति के खिलाफ शारीरिक बल, जबरदस्ती, आधिकारों के दुरूपयोग द्वारा किया जाता है। बलात्कार को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 में परिभाषित किया गया है

इसके अनुसार यदि कोई पुरूष किसी स्त्री से निम्न 7 परिस्थितियों में इस धारा में कथित कृत्य करता है तो वह बलात्कार माना जाएगा-

1. उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध।
2. उस स्त्री की सम्मति के बिना।
3. उस स्त्री की सम्मति से जबकि उसकी सहमति उसे या उससे हितबध्द किसी व्यक्ति को मृत्यु या चोट के भय में डालकर प्राप्त की गई है।
4. उस स्त्री की सम्मति से, जबकि वह पुरुष यह जानता है कि वह उसका पति नहीं हैं और उसने सम्मति इस कारण से दी है कि वह यह विश्वास करती है कि वह उसका पति है।
5. उस स्त्री की सम्मति से, जबकि ऐसी सम्मति देने के समय वह विकृतचित्तता या मत्तता के कारण या उस पुरूष द्वारा स्वयं या किसी अन्य के माध्यम से कोई संज्ञा शून्य कारणी या अस्वास्थ्यकर पदार्थ दिए जाने के कारण वह उस बात की जिसके बारे में वह सम्मति देती है, प्रकृति एवं परिणामों को समझने में असमर्थ है।
6. उस स्त्री की सम्मति से या सम्मति के बिना जब वह 18 वर्ष से कम आयु की है।
7. जब वह स्त्री अपनी सम्मति संसूचित करने में असमर्थ है।

किन्तु धारा 375 के अपवाद 2 में कहा गया कि किसी पुरूष का अपनी स्वयं की पत्नी के साथ यदि पत्नी 15 साल से कम आयु की न हो उसकी सम्मति के बिना यौन संबंध बलात्कार नहीं माना जाएगा। पूर्व में यह अपवाद 10 साल से कम आयु की महिलाओं पर लागू होता था 1940 में इसे बढ़ाकर 15 साल कर दिया गया तत्पश्चात् अक्टूंबर 2017 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इसे इण्डिपेण्डेंट थॉट विरूध्द भारत संघ के वाद में इसे बढ़ाकर 18 साल कर दिया।

वैवाहिक बलात्कार की परिभाषा : वैवाहिक बलात्कार को किसी कानून में परिभाषित नहीं किया गया है इसे सामान्यत: निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है-

''वैवाहिक बलात्कार एक पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ उसकी सहमति के बिना जबरन यौन संबंध बनाने को संदर्भित करता है।''

भारत में बलात्कार एक गंभीर अपराध माना जाता है किन्तु वैवाहिक

बलात्कार अपराध की श्रेणी में भी नहीं आता। बल्कि पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ जब चाहे जब यौन संबंध बनाना विवाह की संस्था के अधीन उसका अधिकार माना गया है। यद्यपि 2013 के संशोधन में एक पति द्वारा अपने से न्यायीक पृथक्करण के अधीन या अन्यथा अलग रहने वाली पत्नी के साथ उसकी सम्मति के बिना संभोग 2 से लेकर 7 साल के कठोर कारावास तथा जुर्माने से दण्डित किया गया है किंतु उसके साथ रहने वाली पत्नी के साथ वही कृत्य करने पर कोई दण्ड नहीं है।

वैवाहिक बलात्कार के अपवाद के आधार : भारतीय दण्ड संहिता 1860 में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के काल दौरान भारत में लागू की गई थी उस समय यह अपवाद तत्कालीन समय में प्रचलित दो सिद्धांतो ''हेल सिद्धांत'' और ''पति आश्रय के सिद्धांत (Doctrine of Coverture) पर आधारित है।'' न्यायाधीश मैथ्यू हेल के द्वारा दिए गए 'हेल सिद्धांत' के अनुसार पति बलात्कार का दोषी नहीं हो सकता है क्योंकि ''आपसी विवाह करने की सहमति और अनुबंध द्वारा पत्नी अपने आप को पति को समर्पित कर देती है अर्थात् एक महिला शादी करके इस बात की विवक्षित सम्मति देती है कि उसका पति उसके साथ जैसा चाहे वैसा कर सकता है।''

पति-आश्रय सिध्दांत के अनुसार शादी के बाद महिला की अपनी कोई व्यक्तिगत कानूनी पहचान नहीं होती है अर्थात पति से अलग उसका कोई विधिक अस्तित्व नहीं होता है उसकी कोई अपनी इच्छा, सहमति, अधिकार नहो होते है वह अपने पति की सम्पति मानी जाती है, धारा 497 के अधीन व्यभिचार को भी इस सिध्दांत के आधार पर अपराध माना गया है।

वैवाहिक बलात्कार के कारण :- वैवाहिक बलात्कार के प्रमुख कारण पुरूषों की महिलाओं पर श्रेष्ठता की इच्छा, पति की विकृत यौन इच्छाएँ, कानूनी प्रावधान की अनुपस्थिति, महिलाओं की अपने पति पर आर्थिक निर्भरता, समाज की यह सोच कि पति की यौन इच्छाए पूरी करना पत्नी का विधिक कर्तव्य हैं क्योकि यदि वह ऐसा करने से इंकार करती है तो उसे हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10 एवं 13 के अधीन पति के प्रति क्रूरता माना जाता है एवं पति को पत्नी के विरूध्द तलाक का एवं न्यायिक पृथ्थकरण का आधार माना जाता है। अतः हमारी हिन्दू विधि भी यह मानती है कि पत्नी विवाह के दौरान अपने पति को यौन संबंध बनाने से इंकार नहीं कर सकती यह उसका अपने पति के प्रति विधिक कर्तव्य है।

वाद - जसमिंदर सिंह विरूध्द श्रीमती प्रभिंदर कौर के मामले में पत्नी द्वारा पति के साथ शारीरिक सहवास करने से ईंकार करने को क्रूरता की कोटि में माना गया। इस मानसिक यातना के आधार पर पति विवाह विच्छेद की डिक्री पाने का हकदार माना गया।

वाद - सुरेश गुर्जर विरूध्द ऊषा गुर्जर में पत्नि द्वारा सहवास समेत वैधानिक आबद्धताओं का निर्वहन न करने को पति के प्रति क्रूरता मानकर विवाह विच्छेद की डिक्री प्रदान की गई।

वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने के पीछे तर्क :-

- धारा 375 का अपवाद 2 संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण करता है क्योंकि यह विवाहित और अविवाहित महिला के बीच एक अनुचित वर्गीकरण करता है। यदि वह कृत्य किसी अविवाहित महिला के साथ उसकी सहमति के बिना किया जाता है तो अपराध की श्रेणी में आता है किन्तु विवाहित महिला के साथ उसकी सहमति के बिना उसकै पति के द्वारा वही कृत्य करने पर अपराध की श्रेणी में नहीं आता।
- वैवाहिक बलात्कार में महिला के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के तहत इच्छा की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को खारिज कर दिया जाता है, इसमें उसे यौन संबंध बनाने की अपनी अनिच्छा प्रकट करने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है।
- वैवाहिक बलात्कार संविधान के अनुच्छेद 15 के अधीन विभेद के प्रतिषेध के अधिकार का भी उल्लंघन करता है क्योंकि यह लिंग के आधार पर पति पत्नी में विभेद करता है।
- वैवाहिक बलात्कार भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 की मूल भावना के भी विपरीत है। धारा 376(2)(च) में कहा गया है कि यदि यहि अपराध महिला के किसी निकट संबंधी, संरक्षक, उस पर प्राधिकार रखने वाले या उसके साथ वैश्वासिक संबंध रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो उसे अधिक गंभीर अपराध माना जाएगा एवं वह अधिक कठोर दण्ड जो कम से कम 10 वर्ष के कठोर कारावास से लेकर शेष बचे जीवन तक आजीवन कारावास तक का हो सकेगा दण्डित किया जाएगा। चूँकि पति भी उक्त सभी कोटियों के अंतर्गत आता है अत: यदि वह अपनी पत्नी के साथ बलात्कार करता है तो इस धारा के अनुसार उसे अधिक गंभीर अपराध माना जाना चाहिए।

- वैवाहिक बलात्कार संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन महिला के निजता के अधिकार, उसका अपने शरीर पर ऑटोनोमी का अधिकार उसका अपने निर्णय पर ऑटोनोमी का अधिकार जो कि उसे पुट्टास्वामी विरूध्द भारत संघ के वाद में दिया गया था को छिनता है।
- भारत में वैवाहिक बलात्कार का गैर-अपराधीकरण उपनिवेश काल का कानून है जब महिलाओं का कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता था वे पुरूषों की सम्पति मानी जाती थी आज के सभ्य एवं आधुनिक समाज में जहॉ स्त्री का पुरूष से पृथक एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है यह कानून स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।
- एक बार के लिए सहमति हमेशा के लिए सहमति की धारणा कानूनी रूप से मान्य नहीं हो सकती है, विवाह के लिए सहमति को संपूर्ण वैवाहिक जीवन के दौरान यौन संबंधों के लिए शाश्वत सहमति नही माना सकता है, सहमति कभी भी वापस ली जा सकती है।
- वैवाहिक बलात्कार न सिर्फ शारीरिक निशान छोड़ता है बल्कि यह पीड़िता के मानसिक संतुलन पर भी गहरा प्रभाव डालता है क्योंकि उसके साथ यह कुकृत्य करने वाला उसका अपना पति है जिसके साथ रहने को वह मजबूर है।

वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित न करने के विपक्ष में तर्क :

- सरकार के अनुसार वैवाहिक बलात्कार को अपराध की संज्ञा देने से वैवाहिक संस्था टूट जाएगी।
- हमारे समाज में यह आम धारणा है कि पति पत्नी का बलात्कार कर ही नहीं सकता और अगर करता भी है तो यह बलात्कार नहीं बल्कि शादी की संस्था के तहत उसे दिया गया अधिकार है।
- इस बात की आशंका है कि यदि इसे अपराध घोषित कर दिया गया तो घरेलू हिंसा एवं दहेज प्रतिषेध कानून की तरह बहुसंख्या में इसका दुरूपयोग किया जाएगा। पत्नियॉ अपने पति को परेशान करने के लिए उन पर वैवाहिक बलात्कार का झूठा आरोप लगाएगी, जिससे न्यायपालिका पर व्यर्थ के मुकदमों का बोझ बढ़ेगा।
- यह कैसे सिद्ध होगा कि पति-पत्नी के बीच यौन संबंध पत्नी की सहमति से बने थे कि नहीं। क्योंकि यह अत्यंत निजता का विषय है एवं पुलिस तथा न्यायालय पति-पत्नी के शयनकक्ष में झाँक नहीं सकते है। अतः इसके लिए सबूत इकट्ठा करना अत्यंत दुष्कर होगा।

- पश्चिमी देशों की न्याय व्यवस्था एवं वहाँ की संस्कृति एवं सभ्यता एवं भारत की न्याय व्यवस्था एवं यहॉ की सभ्यता एवं संस्कृति में काफी अंतर है हमारे यहाँ विवाह एक संस्कार माना जाता हैं अत: अन्य देशों की तरह यहॉ वैवाहिक बलात्कार को अपराध नहीं माना जा सकता।
- कुछ लोग यह तर्क देते है कि भारत में यह अपराध पश्चिमी देशों की तरह तटस्थ नहीं है, इसके अधीन केवल पत्नी ही पति के ऊपर बलात्कार के लिए वाद ला सकती है पति नहीं।
- कुछ लोग यह तर्क देते है कि वैवाहिक बलात्कार से पीड़ित पत्नी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354, 320, 498 क तथा अन्य धाराओं के अधीन पहले से उपचार प्राप्त है, वह अपने पति से तलाक भी ले सकती है इसके अतिरिक्त घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम 2005 के अधीन यौन हिंसा को भी घरेलू हिंसा में शामिल किया गया है। इस अधिनियम की धारा 3(घ) के स्पष्टीकरण 1 के भाग 2 के अनुसार लैंगिक दुरूपयोग में लैगिक प्रकृति का कोई ऐसा आचरण आता है जो महिला की गरिमा का दुरूपयोग, अपमान, तिरस्कार करता है या उसका अन्यथा अतिक्रमण करता है। पीड़िता इस अधिनियम की धारा 19 के अधीन साँझा गृहस्थी में प्रत्यर्थी से पृथक निवास, धारा 18 एवं 19(2) के अधीन क्रमश: संरक्षण आदेश एवं अन्य उपचार प्राप्त कर सकती है। अत: इसके लिए अलग से कोई कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है।
- एक महिला विवाह में यौन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कर्तव्यबध्द है क्योंकि भारत में विवाह का उद्देश्य ही संतान उत्पन्न करना है महिला इससे इंकार नहीं कर सकती।
- एक स्त्री की विवाह करने के लिए सहमति में उसकी यौन संबंध बनाने के लिए स्थायी सहमति शामिल होती है जिसे वह वापस नहीं ले सकती है।

वैवाहिक बलात्कार पर न्यायपालिका का दृष्टिकोण : विभिन्न मामलों में वैवाहिक बलात्कार पर न्यायपालिका के दृष्टिकोण को हम निम्नलिखित न्याय-निर्णयों के माध्यम से समझ सकते हैं–

वाद–इम्परर विरुद्ध साहू मेहराब (1917) : के मामले में पति द्वारा अपनी पत्नी, जो कि एक बालिका थी, के साथ उपेक्षापूर्ण एवं बर्बर तरीके से यौन संबंध बनाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, पति को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304क के अधीन दोषी पाया गया।

वाद : श्री कुमार विरुद्ध पीएरली करूण (1998) : में केरल उच्च न्यायालय ने पति को अपनी पत्नी के साथ उसकी सहमति के बिना यौन संबंध बनाने पर बलात्कार का दोषी नहीं माना।

वाद : ऋषिकेश साहू विरुद्ध कर्नाटक राज्य (23 मार्च 2022) : के वाद में जस्टिस नागप्रसन्ना ने निर्णीत किया कि धारा 375 का वैवाहिक बलात्कार का अपवाद निरपेक्ष नहीं है तथा हर मामलें में लागू नहीं होता है। किसी मामले की विशिष्ट परिस्थितियों एवं तथ्यों में जिनमें पति अपनी पत्नी का बलात्कार करता है, वहाँ पति धारा 375 के अपवाद का दावा नहीं कर सकता है। अर्थात् पति को विशिष्ट परिस्थितियों में पत्नी के बलात्कार का दोषी ठहराया जा सकता है। इस मामले में पति को पत्नी के बलात्कार का दोषी ठहराया गया।

वाद : R.I.T. फाउण्डेशन विरुद्ध भारत संघ (दिल्ली उच्च न्यायालय का मामला) : के मामले में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 के अपवाद 2 की संवैधानिकता को छळ० त्ण्ण्ज्ण फाउण्डेशन, ऑल इण्डिया डेमोक्रेटिक वुमेंस एसोसिएशन, खुशबू सैफी समेत कुछ याचिकाकर्ताओं ने जनहित वाद के माध्यम से चुनौती दी जिसमें उच्च न्यायालय की दो जजों की पीठ ने खंडित फैसला सुनाया। जस्टिस राजीव शकधर ने अपने फैसले में वैवाहिक बलात्कार को जहॉ अपराध माना, वही जस्टिस सी. हरिशंकर ने इसे अपराध नहीं माना। वैवाहिक बलात्कार के अपवाद को समाप्त करने का समर्थन करते हुए जस्टिस राजीव शकधर ने अपने निर्णय में कहा कि ''भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 का अपवाद 2 संविधान के अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समता), अनुच्छेद 15(धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध), अनुच्छेद 19(1)(क) (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार) और अनुच्छेद 21(जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन है अत: असंवैधानिक है, इसे समाप्त किया जाना चाहिए।'' जबकि जस्टिस सी. हरिशंकर ने कहा कि धारा 375 का अपवाद 2 अनुच्छेद 14, 15, 19(1)(क), 21 का उल्लंघन नहीं करता है अत: संवैधानिक है। धारा 375 का अपवाद 2 एक बोधगम्य विभेद पर आधारित उचीत वर्गीकरण है। दोनों ही न्यायाधीश इस मामले की सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई हेतु सहमत थे। उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले की सुनवाई की जाना अभी शेष है।

निष्कर्ष एवं सुझाव : निष्कर्षत : यह कहा जा सकता है कि वैवाहिक

बलात्कार भारतीय विवाहित महिलाओं के मूल अधिकारों एवं मानवाधिकारों का अतिक्रमण करता है। अत: इसे अपराध घोषित किया जाना चाहिए। हमारे रूढ़िवादी समाज को यह सोचने की आवश्यकता है कि क्या बलात्कार को किसी भी रूप में जायज माना जा सकता है? क्या एक स्त्री का अपने शरीर पर हक की माँग करना गलत है? क्या यह बड़े पैमाने पर मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं हैं? क्या संस्कृति के नाम पर संवेदना की बलि चढ़ाई जा सकती हैं? यह कहना अनुचित है कि वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित कर देने से विवाह की संस्था को खतरा उत्पन्न हो जाएगा एवं इसका बहुसंख्या में पत्नियों द्वारा दुरूपयोग किया जाएगा। भारतीय समाज में जहाँ महिलाओं की स्थिति आज भी पुरुषों की तुलना में कमजोर है, वे आर्थिक रूप से अपने पति पर निर्भर है, ऐसे में इसके दुरूपयोग की संभावना बहुत कम हो जाती है। वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण के विपक्ष में यह तर्क कि ''पत्नी द्वारा सहमति दी गई थी या नहीं इसको साबित करना अशक्य है'' व्यर्थ हैं क्योंकि इसे परिस्थितिजन्य साक्ष्य, पॉलीग्राफ टेस्ट, फोरेंसिक जॉच रिपोर्ट द्वारा साबित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम 2005 एवं भारतीय दण्ड संहिता की अन्य धाराओं में इसके लिए पर्याप्त उपचार नहीं है क्योंकि घरेलू हिंसा अधिनियम में इसके लिए सिविल उपचार एवं भारतीय दण्ड संहिता की अन्य धाराओं में इसके लिए मामूली दण्ड का ही प्रावधान है। अत: वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित किया जाना चाहिए ताकि एक घीनौने कृत्य करने वाले अपराधी को उसके अपराध की कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। ''बलात्कार बलात्कार होता है चाहे वह पति द्वारा किया जाए या अन्य पुरूष द्वारा'' इस बात को हमारे रूढ़िवादी, पुरूष प्रधान समाज को समझने की अत्यंत आवश्यकता है।

संदर्भ सूची :

1. https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/marital-rape-5
2. https://hindi.news18.c0m/amp/news/nation/marital-rape-case-reached-supreme-court-petitioner-challenged-delhi-high-court-judge-c-harishankar-decision-425923.html
3. Ishita Goel and Deveshi Sanmotra, Marital Rape: A Felony without substantial legal consequences, International Journal of policy sciences and Law, Volume 1, Issue 3
4. What is Marital Rape? Why is Marital Rape not a crime in India? Feminism in India. available at https://youtu.be/gGVI_oKDjtU?si=kOgz5pJ4 EVcjm83

5. Sarokar- Should marital rape be criminalised in India? Sansad TV available at https://youtu.be/pkXB6ielt-Y?si=VMll9zimbPqacA
6. Marital Rape in India- Audio Article (Drishti The Vision) available at https://youtu.be/c0diSZ-Mmy4?si=ASopnF78fvKHZkb
7. डॉ. यू.पी.डी. केसरी, हिन्दू विधि, छब्बीसवाँ संस्करण 2006, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद
8. डॉ. बसन्ती लाल बाबेल, भारतीय दण्ड संहिता 1860, बाईसवाँ संस्करण, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद

विजय लक्ष्मी जोशी
शासकीय विधि महाविद्यालय, शाजापुर, म. प्र.

❑❑❑

'इतिहास लेखन में राष्ट्रवाद' : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

•रामदेव जाट

साम्राज्यवादी दृष्टिकोण सबसे पहले लार्ड मिन्टों आदि वायसरायों की उद्घोषणाओं में उभरकर सामने आया। पहली बार इसे वैलेन्टाइल शिरोल, रॉलेट समिति की रिपोर्ट, वर्नी लॉवेट एवं मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आदि के द्वारा सुनियोजित रूप से रखा गया। सबसे पहले एक अमेरिकी विद्वान ब्रूस टी. मैककुली द्वारा इसे सैद्वान्तिक आधार प्रदान किया गया। उन्नीसवीं शताब्दी के अंत से साम्राज्यवादी इतिहास-लेखन का वास्तविक स्वरूप और अधिक स्पष्टता से हमारे सामने उभर कर आता है। जैसा हमने पहले भी देखा है, इस परंपरा में दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ विद्यमान थी। इन दोनों में ही साम्राज्याद के मूल औचित्य को लेकर एकरूपता थी यद्यपि नीतियों को लेकर इनके रूझान अलग-अलग थे। एक ओर जॉन स्ट्रैचे, वैलेनटाईन, शिरोल, लॉवेट, पर्सिवल स्पीयर, रेगिनाल्ड कूपलैंड, अनील सील तथा जे.ए, गलहर जैसे इतिहासकार थे। जिन्होंने भारतीय समाज तथा जनांदोलन के प्रति कट्टर आलोचनात्मक नजरिया अपनाया तो दूसरी ओर हेनरी मेन, एल्फ्रेड लॉयल तथा एडवर्ड टॉमसन जैसे इतिहासकार थे। जिनका दृष्टिकोण इनकी तुलना में कुछ उदारवादी था। कुछ सरलीकरण के साथ साम्राज्यवादी लेखकों की मूल अवधारणाओं की इस प्रकार व्याख्या की जा सकती है—भारत आधुनिक परिभाषा वाला राष्ट्र होने के बजाय मात्र अलग-थलग जातियों, धर्मों और कबीलों का देश है, ऐसी हालत में वह स्वयं अपना शासन संभालने के काबिल नहीं था, देवी संयोग से अंग्रेज हिंदुस्तान में आए और उन्होंने अपनी जातीय श्रेष्ठता के आधार पर यह देश जीता और यहाँ आधुनिक प्रशासन-व्यवस्था स्थापित की : एडवर्ड टॉमसन जैसे इतिहासकारों ने यह माना कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद निहित स्वार्थों के लिए बनाया गया परंतु साथ ही इस बात पर भी जोर दिया कि इससे भारत का चतुर्मुखी विकास भी हुआ है, दोनों ही प्रकार के इतिहासकार

यह मानकर चले कि भारत में शांति बनाए रखने, संप्रदायों के बीच इंसाफ करने तथा भारतीय किसानों के 'माँ-बाप' के बतौर काम करने के लिए अंग्रेजों का शासन जरूरी है। एलफ्रेड लॉयल जैसे लेखकों ने यह भी प्रमाणित करने का प्रयास किया कि अंग्रेजी शासन धीरे-धीरे हिंदुस्तानियों को अपना खुद का राज्य चलाने के लिए तैयार कर रहा है। टॉमसन और गैरेट ने अपनी किताब दि राइज़ ऐंड फुलफिलमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इसी प्रक्रिया को अंग्रेजी व्यवस्था में 'फुलफिलमेंट' या 'परितोष' का नाम दिया तथा अप्रत्यक्ष रूप से स्वाधीनता के उद्देश्यों को स्वीकृति प्रदान की। (1940 ई.) अनील सील और उसके अनुगामियों ने 1968 के पश्चात् साम्राज्यवादी दृष्टिकोण का वह अनुदारवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। जिसे लोकप्रिय रूप में कैंब्रिज स्कूल के नाम से जाना जाता है। कैंब्रिज इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं है कि भारत एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में था बल्कि वे मानते हैं कि जिसे भारत के नाम से जाना जाता है वह वस्तुतः विभिन्न धर्मो, जातियों, समुदायों और हितों का समूह था। भारत विभिन्न पहचानों, यथा-ब्राह्मण, गैर-ब्राह्मण, हिन्दू-मुस्लिम, आर्य और भद्रलोक आदि पहचानों में विभाजित है। अनिल सील कहते है कि भारतीय राजनीति इन्हीं हित-समूहों के इर्द-गिर्द चक्कर काटती थी। उनके विचार में यह तथ्य भारतीय राष्ट्रवाद को चीन, जापान, मुस्लिम देशों और अफ्रीका के राष्ट्रवाद से अलग करता है। फिर सवाल यह पैदा होता है कि अगर राष्ट्रीय आंदोलन साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय जनता के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करता तो किसके हितों का प्रतिनिधित्व करता था? इसके जवाब में कैंब्रिज इतिहासकारों का कहना है कि यह कुलीन समूहों के हितों का प्रतिनिधित्व करता था। भारतीय राष्ट्रवाद पर अनील सील, बंगाल पर अमेरिकी इतिहासकार ब्रुमफील्ड एवं कुछ समय तक गाँधी के उदय पर ज्यूडिथ ब्राउन के लेखन ने ऐसा चलन चलाया। जिसमें राष्ट्रवाद की व्याख्या असमान विकास एवं सामान्यतः जाति पर आधारित, प्रान्तीय अभिजात समूहों की प्रतियोगिता के परिप्रेक्ष्य में की जाती है। दूसरे शब्दों में इन्होंने राष्ट्रवादी गतिविधियों को भारतीय कुलीनों की आर्थिक स्वार्थ प्रथा का नाम दिया। वे साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रवाद के संघर्ष को एक छद्म संघर्ष मानते है।

संकेताक्षर : *राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद, इतिहास लेखन, विचारधारा, इतिहासकार।*

साम्राज्यवादी इतिहास लेखन की प्रतिक्रिया में राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का विकास हुआ। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व गिरिजा प्रसादी मुखर्जी,

सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी, अम्बिका चरण मजूमदार, पट्टाभि सीतारमैया, आर.जी. प्रधान, सी.एफ. एन्ड्रयूज तथा अमलेश त्रिपाठी ने किया हैं। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में साम्राज्यवादी इतिहास लेखन की मूलभूत मान्यताओं पर चोट करते हुए यह स्थापित करने का प्रयत्न किया है कि भारत में उपनिवेशवाद था तथा ब्रिटिश औपनिवेशिक हित एवं भारतीय जनता के हितों के बीच मूलभूत विरोधाभास था फिर उन्होंने यह भी स्थापित करने का प्रयत्न किया कि राष्ट्रवाद की भावना के प्रसार के साथ भारत में राष्ट्रवादी आन्दोलन को प्रोत्साहन मिला। राष्ट्रवादी इतिहासकार उपनिवेशवाद के शोषक चरित्र की समझ प्रदर्शित करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन राष्ट्रीयता या स्वतंत्रता के विचार के प्रसार एवं उसके मूर्तिकरण का परिणाम था। इन्होंने प्राचीनकाल में ही भारतीय संकल्पना को देखने का प्रयत्न किया। कई बार देशी बनाम विदेशी की बातें इनके इतिहास में नजर आती है। इस क्रम में इस बात को भुला दिया गया कि प्राचीन काल के गौरवपूर्ण साम्राज्य निर्माता भी अंततः साम्राज्यवादी ही थे। इस क्रम में कई बार क्षेत्रीय राज्य के निर्माण को पतन के प्रति के रूप में देखा गया। क्योंकि उस समय भारत में कोई एक राजनीतिक सत्ता नजर नहीं आती। मौर्यउत्तरकाल तथा पूर्व मध्यकाल जैसे काल खण्डों के उदाहरण से इसे समझा जा सकता है। राष्ट्रवादी इतिहासकारों की दृष्टि में राष्ट्रीय आंदोलन में जनता की भागीदारी बहुत प्रभावपूर्ण एवं स्वाभाविक थी, क्योंकि मूलतः सभी भारतीयों के हित सदैव विदेशी सत्ता के विरोधी ही थे, केवल चमत्कारी नेता की कमी थी। किन्तु राष्ट्रवादी इतिहास लेखन ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि जाति एवं वर्ग के रूप में भारतीय समाज के अन्दर भी एक विरोधाभास विद्यमान था तथा यह सिद्ध करने का प्रयास करते थे कि ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध सभी भारतीयों के हित एक समान थे।

1980 के दशक में आधुनिक भारत के इतिहास लेखन में एक नए दृष्टिकोण का विकास हुआ। इसे सबाल्टर्न (उपाश्रयवादी) दृष्टिकोण कहते है। इसके अनुसार किसी भी जन आन्दोलन में नेतृत्व जनसामान्य को नियंत्रित नहीं करता वरन् जनसामान्य के स्तर से उठने वाले दबाव नेतृत्व को दिशा देता है अर्थात् सबाल्टर्न इतिहास लेखन में नेतृत्व की भूमिका के बजाए सामाजिक प्रक्रिया पर विशेष बल दिया जाता है। इसका मानना है कि चाहे वह साम्राज्यवादी इतिहास लेखन हो या राष्ट्रवादी इतिहास लेखन हो सभी एक समान दोष के शिकार है अर्थात् सभी नेतृत्व की भूमिका को कुछ बढ़ा-चढ़ाकर आँकते रहे है। सबाल्टर्न इतिहास लेखन समाज को बुर्जुआ तथा सर्वहारा दो

सुस्पष्ट वर्गों में विभाजित करके देखने के बजाए आभिजात्य तथा दलित (जनसामान्य अर्थात् किसान, जनजातीय, मजदूर) वर्ग के बीच विभाजित करके देखता है तथा सामाजिक प्रक्रिया को समझने के लिए जन सामान्य वर्ग की चेतना के अध्ययन पर बल देता है। इनके दो प्रमुख विषय उभरकर सामने आए है। प्रथम औपनिवेशिक भारत में कृषक प्रतिरोध और कृषक चेतना, द्वितीय किसान समुदाय और राष्ट्रीय आंदोलन के बीच संबंध। यह लेखन भारत में राष्ट्रवाद की स्थिति को अस्वीकार करते है तथा राष्ट्रवाद को एक अभिजात्य संकल्पना मानते है। इस इतिहास लेखन के संस्थापक रणजीत गुहा, पार्थ चैटर्जी, डेविड़ अर्नाल्ड़ ने इसमें बड़ा योगदान दिया।

जर्मनी में जे.जी. हर्डर ने 'लोकसंस्कृति' पद का प्रयोग किया। उन्नीसवीं सदी के आरंभ के दो इतिहासकारों ने 'पीपुल्स' शब्द का उपयोग किया है। ई.जी. गेजर ने हिस्ट्री ऑफ द स्वीडीश पीपुल्स और पैलैकी ने हिस्ट्री ऑफ द चेक पीपुल्स नामक पुस्तक लिखी। जर्मनी में जिम्मरमैन ने जर्मन कृषक युद्ध का इतिहास लिखा, फ्रांस में जूल्स मिशले (1798-1874) ने फ्रांसीसी क्रांति पर विस्तार से लिखा और आमजन को इतिहास लेखन के केन्द्र में खड़ा कर दिया। हिस्ट्री ऑफ फ्रांस (1833-67), हिस्ट्री ऑफ द फ्रेंच रिवॅल्यूशन (1846-53) और द पीपुल (1846) में उन्होंने जनता को नायक बना दिया। एरिक हॉब्सबॉम ने 1985 में लिखा कि उनका मानना है कि 'जार्ज लेफेबव्र एकमात्र ऐसे इतिहासकार हैं जो समय के रूख और विषय को पहचानते हैं और उनकी पुस्तक ग्रेट फियर ..... एक अद्यतन पुस्तक है।' इसलिए हम कह सकते हैं कि आम जनता के इतिहास-लेखन की शुरूआत लेफेबव्र से हुई। उनके शिष्य और मित्र जार्ज रूड़े ने इस परम्परा को आगे बढ़ाया। ब्रिटेन में 1920 और 1930 के दशक में इतिहास की कई लोकप्रिय पुस्तकें लिखी गईं जिन्हें वामपंथी बुक क्लब ने प्रकाशित किया। 1940 के दशक में वामपंथी पार्टी ने इस परम्परा को आगे बढ़ाया। जार्ज रूडे, ई.पी. थॉम्पसन, एरिक हॉब्सबॉम, क्रिस्टोफर हिल और जॉन सेविले इस समूह के प्रमुख सदस्य थे। इसी समूह ने 1952 में पास्ट ऐंड प्रेजेंट नाम की एक प्रमुख पत्रिका निकाली। बाद में उन्होंने ही लेबर हिस्ट्री रिव्यू प्रकाशित किया। फिर हिस्ट्री वर्क्सशॉप जरनल के द्वारा 1976 में इस परम्परा को आगे बढ़ाया गया। जिसमें जनता का इतिहास प्रकाशित किया जाता था। ई.पी. थॉम्पसन ने 1966 में प्रकाशित अपने लेख 'हिस्ट्री फ्रोम बिलो' (जनोन्मुखी इतिहास) में सबसे पहले इस परम्परा को इतिहास-लेखन का सैद्धांतिक आधार प्रदान किया। जिम शार्प के अनुसार इसके बाद आम आदमी से जुड़े इतिहास की अवधारणा इतिहासकारों के दायरे में प्रविष्ट हुई। थॉम्पसन ने

1963 में द मेकिंग ऑफ द इंगलिश वर्किंग क्लास (1963) नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। जिसमें उन्होंने इंगलैंड में औद्योगिक क्रांति के दौरान मजदूर वर्गों के नजरिए की पड़ताल की।

प्रासंगिक संदर्भों की अनुपस्थिति भारत में जनोन्मुखी इतिहास-लेखन की एक प्रमुख समस्या है। निम्न वर्ग के बारे में जो कुछ भी लिखा मिलता है वह अधिकांश समाज के दूसरे स्तर के व्यक्तियों द्वारा लिखा गया है। उन विकसित देशों में भी प्रासंगिक स्त्रोत की समस्या है जहाँ मजदूर वर्ग अपेक्षाकृत ज्यादा संख्या में साक्षर थे। वहाँ भी किसानों और पूर्व-औद्योगिक समूहों से जुड़े स्त्रोत शासकों द्वारा ही तैयार किए गए थे। भारत में आम जनता, जिसमें औद्योगिक मजदूर वर्ग भी शामिल थे, शिक्षित नहीं थी। इसलिए प्रत्यक्ष स्त्रोत मुश्किल से ही मिल पाते हैं। इस स्थिति में इतिहासकार अप्रत्यक्ष स्त्रोतों के आधार पर जनोन्मुखी इतिहास लिखने का प्रयास करते हैं। सब्यसाची भट्टाचार्य के अनुसार 'साक्षरता के अभाव के कारण उनके आचरण और व्यवहार, विचार और भावना संबंधी सूचनाओं (ये भी हू ब हू नहीं मिलते), मौखिक प्रमाणों (अदालत की कार्यवाहियों से जुड़े दस्तावेजों में इनका सर्वोत्तम रूप मिलता है) आदि के आधार पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है और उन्हीं से निष्कर्ष निकालना पड़ता है।' मौखिक परम्पराओं की भी अपनी समस्याएं हैं और उन्हें बहुत दूर तक नहीं खींचा जा सकता और स्मृतियों पर बहुत भरोसा भी नहीं किया जा सकता। जनोन्मुखी इतिहास लिखने वाले इतिहासकारों में अग्रणी रंजीत गुहा ने इन समस्याओं का हवाला दिया है। गुहा ने अपनी पुस्तक एलेमेंट्री आसपेक्ट्स ऑफ पीजेन्ट् इनसरजेंसी इन कोलोनियल इंडिया (1983) में यह लिखा है कि ये दस्तावेज अधिकांशतः संभ्रांत लोगों द्वारा तैयार किए गए हैं जिनकी सहायता से इतिहासकार किसी कृषक आंदोलन के पीछे छिपी मानसिकता को समझने का प्रयास करते हैं।

सभी तो नहीं परंतु अधिकांश दस्तावेजों को संभ्रांत लोगों ने तैयार किया है। यह हमें सरकारी दस्तावेजों के रूप में उपलब्ध है मसलन, पुलिस रिपोर्ट, सेना की चिट्ठी पत्री, प्रशासनिक लेखा, सरकारी विभागों के कार्यवृत्त और उद्घोषणाएं आदि। इस विषय पर हमारी सूचना के जो गैर सरकारी स्त्रोत हैं जैसे अखबार या शासनाधिकारी के बीच निजी पत्र व्यवहार भी संभ्रांतों की मानसिकता और भाषा का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। शासक वर्ग देसी हो या गैर भारतीय इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सुमित सरकार का यह मानना है कि 'औपनिवेशिक भारत में अपेक्षाकृत जनान्दोलनों की तीव्रता में कमी जनोन्मुखी

इतिहास के न लिखे जा पाने की सबसे बड़ी वजह थी। यह स्थापित करना भी ठीक नहीं होगा कि भारतीय किसान निष्क्रिय नहीं थे और वे लगातार आंदोलन और विरोध करते आ रहे थे। कहने का तात्पर्य यह कि 'निम्नवर्ग' ज्यादातर समय अधीनता के शिकंजे में जकड़े रहे। भयंकर गरीबी और लगातार उकसाए जाने के बावजूद उनका निष्क्रिय रहना अजूबा लगता है। राजनीतिक रूप से सक्रिय होने के बावजूद अन्ततः सामाजिक रूप से 'उच्च' लोगों के अधीन रहना ही उनकी नियति बनी।'

निम्नवर्गीय प्रसंग ने भारतीय इतिहास के संदर्भ में हुए इतिहास-लेखन को एक नया व्यक्तित्व प्रदान किया। आरंभ में इसके तीन खंड तैयार करने की योजना बनी। जिसका संपादन इसके प्रणेता रंजीत गुहा को करना था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह विचार ग्रामशी के चिंतन से प्रभावित था। इसमें खासतौर पर मार्क्सवाद के आर्थिक पक्ष पर बल दिए जाने वाले सिद्धांत के साथ-साथ बुर्जुआ राष्ट्रवादी संभ्रांत व्याख्या और उपनिवेशवादी विवेचन से अलग हटकर एक नई व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। भारतीय इतिहास-लेखन की परम्परा से असंतुष्ट एक लेखक समूह ने सामूहिक रूप से इन पुस्तकों के लिए लेख लिखें। हालांकि मूलतः निम्नवर्गीय प्रसंग का संबंध भारत से था परंतु यह विचार इंगलैंड में कुछ भारतीय इतिहासकारों के मन में समाया। जिनके अगुआ और प्रणेता शक्ति रंजीत गुहा थे। आरंभ से ही भारतीय इतिहास-लेखन की सभी मौजूदा परम्पराओं से अलग इसने अपनी राह बनाई। इस परियोजना के घोषणा पत्र में कम्यूनिस्ट मेनिफेस्टो की शुरूआती पंक्तियों की झलक मिलती है—'अभी तक सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है।' रंजीत गुहा ने निम्नवर्गीय प्रसंग के पहले खंड में यह घोषणा की कि 'भारतीय राष्ट्रवाद का इतिहास-लेखन अभी तक संभ्रांतवाद-उपनिवेशवादी संभ्रांतवाद और बुर्जुआ राष्ट्रवावद संभ्रांतवाद-से ग्रसित रहा। यह कहा गया कि दोनों ही प्रकार के इतिहास-लेखन भारत में ब्रिटिश शासन के वैचारिक विवमर्श से प्रभावित थे। अनेक मतभेदों के बावजूद कई मामलों में दोनों एक ही ढंग से सोचते थे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनके इतिहास में जनता की राजनीति पूरी तरह से गायब थी। उनके विचार से अब समय आ चुका था कि निम्नवर्गों की दृष्टि से इतिहास देखा जाए और लिखा जाए। यह दृष्टि तथा जनता की राजनीति बहुत ही महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसका अपना एक स्वायत्त क्षेत्र था जिसका संबंध न तो संभ्रांत राजनीति से था और न उसका अस्तित्व उस पर आधारित था। जनता की राजनीति संभ्रांतों की राजनीति से कई निर्णायात्मक मामलों में अलग होती है। सबसे पहले यह कि इसकी जड़, जाति और संबंधों के फैलाव,

जनजातीय बंधुत्व, क्षेत्रीयता आदि जैसे परम्परागत जनसंगठनों में होती है। दूसरे, संभ्रांत लामबंदी की प्रकृति उर्ध्व होती है यानी ऊपर से नीचे की ओर जाती है जबकि जनता की लामबंदी क्षैतिज होती है। तीसरे जहाँ संभ्रांत लामबंदी कानूनी दायरे में बंधी और शांत होती है, वहीं निम्नवर्गीय लामबंदी अपेक्षाकृत उग्र होती है। चौथा, संभ्रांत लामबंदी अधिक सतर्क और नियंत्रित होती है जबकि निम्नवर्गीय लामबंदी अचानक उभर आती है अर्थात् स्वत:स्फूर्त होती है।'

निम्नवर्गीय प्रसंग जल्द ही जनता के नए इतिहास के रूप में तब्दील हो गया। जिसमें सरकारी राष्ट्रवाद के साथ जनता के इतिहास का घालमेल नहीं किया गया। इस प्रकार इसने उन विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया। जिनका उत्तर औपनिवेशिक राष्ट्र-राज्य द्वारा किए जाने वाले राष्ट्रवादी दावों से मोहभंग हो चुका था। आरंभ में ग्रामशी के सिद्धांत से प्रभावित होकर इसमें प्रताड़ित समूहों की परिवर्तनगामी चेतना को खोजने का प्रयास किया गया। इसे भारतीय इतिहास-लेखन की तीन प्रमुख प्रवृत्तियों के विरोध में खड़ा किया गया— उपनिवेशवादी, जिन्होंने देश की अज्ञानी जनता को ज्ञान प्रदान करने के लिए औपनिवेशिक शासन को जरूरी माना : राष्ट्रवादी, जिन्होंने जन आंदोलनों को राष्ट्र-राज्य के निर्माण की प्रक्रिया का अंग माना, और मार्क्सवादी, जो जनता के संघर्ष को क्रांति और समाजवादी राज्य की स्थापना के इतिहास में समाहित कर देते थे।

कांग्रेस राष्ट्रवाद का बुर्जुआ और संभ्रांत चरित्र दिखाना जिसने लोकहितवादी और परिवर्तनगामी आंदोलनों पर अंकुश लगाया। भारतीय/कांग्रेस राष्ट्रवाद के महा आख्यान में जनता के संघर्ष को शामिल किए जाने के कई इतिहासकारों के दावों को चुनौती दी गई। निम्नवर्गीय चेतना का निर्माण और इसके स्वायत्ता पर बल दिया गया। निम्नवर्गीय स्त्रोतों से प्रमाणों की अनुपलब्धता को देखते हुए यह काम बहुत मुश्किल था। इस अभाव को दूर करने के लिए सबाल्टर्न इतिहासकारों ने सरकारी स्त्रोतों से ही अपने लिए सामग्री निकाली और इसके लिए उन्हें भूसे से अनाज को अलग करना पड़ा। कांग्रेस राष्ट्रवाद और भारतीय राज्य में इसके कार्यान्वयन से क्षुब्ध सबाल्टर्न इतिहासकारों ने इस अभिधारणा को खारिज कर दिया कि जनता की लामबंदी या तो आर्थिक परिस्थितियों अथवा ऊपर से किए गए प्रयासों का प्रतिफलन होती है। उन्होंने एक लोकक्षेत्र खोज निकालने की बात की जिसका अस्तित्व स्वायत्तापूर्ण होता है। यह स्वायत्तता शोषण की परिस्थितियों में निहित होती है। सबाल्टर्न इतिहासकारों ने कबीलों, किसानों, सर्वहारा जैसे समूहों और कभी-

कभी मध्य वर्ग पर भी काम किया। उनका यह मानना था कि ये क्षेत्र संभ्रांत राजनीति से अप्रभावित थे और इनका स्वतंत्र अस्तित्व था तथा इनकी शक्ति स्वत:स्फूर्त थी। अब किसी भी आंदोलन के पीछे किसी करिश्माई नेतृत्व का हाथ होने की बात से इनकार किया जाने लगा। अब किसी भी आंदोलन या विद्रोह के विश्लेषण में इस प्रकार के करिश्मे के प्रति लोगों द्वारा की गई व्याख्या को महत्व दिया जाने लगा।

रंजीत गुहा ने अपने एक लेख 'द प्रोज ऑफ काउंटर इनसरजेंसी' में भारत के किसानों और कबीलों के मौजुदा इतिहासकारों की आलोचना की है जिसमें किसान आंदोलनों को आकस्मिक और अनियोजित बताया गया है और विद्रोह की चेतना को नकारा गया है। उनके मतानुसार 'इस इतिहास-लेखन में कृषक विद्रोही की चर्चा सिर्फ एक ठोस व्यक्ति या वर्ग के सदस्य के रूप में की गई एक अस्मिता के रूप में नहीं जिसकी इच्छा शक्ति और तर्क शक्ति विद्रोह का माहौल बनाती है। कृषक आंदोलन के बारे में जो भी किंवदंती और आख्यान मौजुद हैं उनका एक स्वाभाविक प्राकृतिक घटना के रूप में चित्रण किया गया है। वैसे ही जैसे बवंडर फूट पड़ता है, भूचाल आ जाता है, दावाग्नि या महामारी फैल जाती है।' गुहा के अनुसार उन्होंने प्रति-विद्रोह का पाठ लिखा है और 'विद्रोही को अपने इतिहास का नायक मानने से इन्कार किया है।' अपने लेख 'पीजेंट रिवोल्ट ऐंड इंडियन नेशनलिज्म, 1919-1922' में ज्ञान पांडे ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि असहयोग आंदोलन से पहले अवध में उठा किसान आंदोलन अपने आप में स्वायत्त था और किसान शहरी नेताओं की अपेक्षा भी स्थानीय सत्ता संरचना के औपनिवेशिक शासन के साथ गठजोड़ को बेहतर ढंग से समझते थे इसके अलावा जब-जब कांग्रेस का संगठन मजबूत हुआ तब-तब किसान की उग्रता में कमी आई।

स्टीफेन हेन्नींघम ने 'क्वीट इंडिया इन बिहार ऐंड यूनाइटेड प्रोविन्सेज' में यह लिखा है कि निम्नवर्गीय और संभ्रांत क्षेत्र स्पष्ट परिभाषित और एक दूसरे से अलग थे। अतएव 1942 की महान क्रांति संभ्रांतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ-साथ एक निम्नवर्गीय विद्रोह भी था। उनके उद्देश्य और मांग अलग-अलग थी। 'संभ्रांतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल आंदोलनकारियों ने सरकार द्वारा कांग्रेस के दमन का विरोध किया और भारत को आजादी देने की मांग की। दूसरी ओर निम्नवर्गीय विद्रोह में शामिल लोगों ने दासता और उत्पीड़न से मुक्ति की बात की जिसमें वे जकड़े हुए थे।' अपनी बात आगे बढ़ाते हुए वे कहते हैं कि क्रांति के इस दोहरे चरित्र के कारण ही इसे दबाया जा सका।

डेविड हार्डीमैन ने अपने कई लेखों में निम्नवर्गीय विषय पर प्रकाश डाला है और यह कहा है कि चाहे वह दक्षिण गुजरात का कबीलाई आंदोलन हो या पूर्वी गुजरात का भील आंदोलन हो या फिर नागरिक अवज्ञा आंदोलन में कृषि मजदूरों की विद्रोह भावना हो, यह संभ्रांतों के खिलाफ निम्नवर्ग की एक स्वतंत्र राजनीति थी।

इसी प्रकार सुमित सरकार ने अपने लेख 'द कंडिशन ऐंड नेचर ऑफ सबाल्टर्न मिलिटैन्सी' में यह कहा है कि बंगाल में असहयोग आंदोलन के दौरान जनता ने नेताओं की अवहेलना की। उन्होंने बताया कि सबाल्टर्न पद में मूलत: तीन सामाजिक समूह शामिल हैं: 'कबीलाई' और निम्नजाति के कृषीय मजदूर और बटाईदार, जमीनवाले किसान, आमतौर पर बंगाल में मध्यवर्ती जाति के लोग (इसमें मुसलमान भी शामिल थे), और बागानों, खानों और उद्योगों में काम करनेवाले मजदूर (शहरी मजदूरों के साथ-साथ)।' इन समूहों के बीच में आपसी विभाजन था और इसमें शोषक और शोषित दोनों शामिल थे। इसके बावजूद उनका मानना था कि : परिभाषित निम्नवर्गीय समूह का अपेक्षाकृत स्वायत्त राजनीतिक क्षेत्र था जिसकी खास विशेषताएं और साझा मानसिकता थी जिनका पता लगाया जाना जरूरी है और यह संभ्रांत राजनीतिज्ञों के क्षेत्र से बिलकुल पृथक दुनिया थी। बीसवीं शताब्दी के दौरान बंगाल के संभ्रांत राजनीतिज्ञ उच्च जाति शिक्षित पेशेवर समूह से आए थे जिनका संबंध जमींदारी या बिचौलिए काश्तकारी से था।'

जनोन्मुखी इतिहास-लेखन की परम्परा की चर्चा की है जिसमें इतिहास-लेखन में आम व्यक्ति के नजरिए को केंद्र में रखा जाता है। यह डिजरेली की उस धारणा से बिल्कुल अलग तरह का इतिहास-लेखन है जिसमें इतिहास को महान पुरूषों की जीवनी माना जाता है। जनोन्मुखी इतिहास में आम जनता के जीवन और कार्यकलापों पर विचार होता है जिनकी आमतौर पर परम्परागत इतिहासकार अवहेलना कर देते हैं। इसके अलावा इसमें उनके विचारों को भी यथासंभव शामिल करने का प्रयास किया जाता है। इस दिशा में इतिहासकारों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि सारे स्त्रोत शासकों, प्रशासकों और प्रभुत्वशाली वर्ग के पक्ष में दिखाई देते हैं। भारत जैसे देश में जनता के अशिक्षित होने के कारण यह समस्या और भी विकट हो गई। इन बाधाओं के बावजूद सामाजिक इतिहासकारों ने आम जनता को हाशिए से खींचकर केन्द्र में लाने का भरसक प्रयत्न किया है।

निम्नवर्गीय प्रसंग परियोजना का सबसे प्रमुख उद्देश्य उस चेतना को समझना है जिसके तहत निम्नवर्ग संभ्रांत वर्ग से बिल्कुल और स्वतंत्र अपनी राजनीति करता है। इसका कारण यह है जैसा कि सबाल्टर्न इतिहासकारों ने बताया है कि 'राष्ट्रवादी संघर्षों के दौरान जब जनता उसमें शामिल होती थी तो इन आंदोलनों के बारे में उनका अपना नजरिया होता था और वे उस ढंग से काम करते थे।'

दीपेश चक्रवर्ती के अलावा ज्ञानप्रकाश ने भी इस परियोजना के पक्ष में काफी कुछ कहा है। उनका मानना है कि सबाल्टर्न इतिहासकारों ने इतिहास-लेखन को संभ्रांत इतिहास-लेखन के चंगुल से मुक्त किया है : ''इस परियोजना का महत्व उस इतिहास-लेखन से है जो औपनिवेशिक और राष्ट्रवादी संभ्रांतों के चंगुल से मुक्त है। इस परियोजना का उद्देश्य उपनिवेशवादी और राष्ट्रवादी वर्चस्व से इतिहास को मुक्त करना है। सबाल्टर्न इतिहासकारों ने इतिहास को एक नई दिशा दी जिसके फलस्वरूप तीसरी दुनिया के इतिहास-लेखन में सार्थक हस्तक्षेप किया।'' एक दूसरे लेख में ज्ञान प्रकाश ने निम्नवर्गीय प्रसंग परियोजना के विकास, परिवर्तन और नई दिशा का समर्थन किया है। बाद में इस बदलावों का समर्थन करते हुए उन्होंने लिखा है कि 'एक विषय के रूप में इतिहास की आलोचना इसके तहत विकसित हुई।'

ज्ञान पांडेय ने अपने लेख 'इन डिफेन्स ऑफ द फ्रैगमेंट' में भारत में साम्प्रदायिक दंगों पर किए हुए अधिकांश लेखन के विरोध में तर्क दिया है। उनका कहना है कि भारतीय समाज विभिन्न धार्मिक और जातीय समुदायों में बंटा हुआ है और इसके अलावा कबीलाई समूह है, औद्योगिक मजदूर हैं और महिला कार्यकर्त्ता समूह हैं। यह कहा जा सकता है कि ये सभी 'अल्पसंख्यक' संस्कृतियों और व्यवहारों को अभिव्यक्त करते हैं। ऐसी उम्मीद की जाती है कि ये राष्ट्रीय संस्कृति की मुख्य धारा में शामिल हो जाएं, ऐसा इसलिए कि उन्नीसवीं शताब्दी निम्न जातियों और कबीलों के अध्ययन की शुरूआत करते ही इतिहासकारों ने औपनिवेशिक काल के दौरान उनके दमन और विरोध के प्रश्न पर बल देना शुरू किया। दोनों ही समुदाय हाशिए पर थे और दोनों के खिलाफ भेदभाव बरता गया था। परंतु समय-समय पर उनके बीच वैचारिक नेतृत्व पैदा हुआ और उन्होंने शासकों के विरोध में आंदोलन किए जिनसे जुड़े दस्तावेज औपनिवेशिक अभिलेखागार में सुरक्षित है। कहीं-कहीं निम्न जातियों के अपने वक्तव्य और दृष्टिकोण भी उपलब्ध हो जाते हैं। रोजालिन्ड ओ हैनलान ने कास्ट, कॉनलिक्ट ऐंड आइडियोलॉजी : महात्मा ज्योतिराव फुले ऐंड

लो कास्ट प्रोटेस्ट इन नाइन्टीन्थ सेंचुरी वेस्टर्न इंडिया (कैम्ब्रिज, 1985) य और शेखर बंधोपाध्याय ने कास्ट, प्रोटेस्ट ऐंड आइडेन्टीटी इन कोलोनियल इंडिया : द नामशूद्राज ऑफ बंगाल 1872-1947 (रिचमॉन्ड, 1997) में इस प्रकार की सामग्री का उपयोग करते हुए समूह विशेष के दृष्टिकोण से बयान किया गया है। निम्नजातियों और कबीलों में लैंगिक लोकाचार उच्चजाति की नैतिकताओं से भिन्न होते हैं। ओ हैनलान और बंधोपाध्याय लैंगिक भेदभाव से जुड़े कारक को नहीं भूले है। उन्होंने यह दिखाया है कि किस प्रकार महाराष्ट्र में गैर ब्राह्मण आंदोलन और बंगाल में नामशूद्र आंदोलन ने उन्नीसवीं शताब्दी के अंत और बीसवीं शताब्दी के आरंभ में सामाजिक सुधार और राजनीतिक राष्ट्रवाद जैसे बृहद मुद्दों पर अपना पक्ष दृढ़ता से सामने रखा और अपनी बात मनवाई थी।

गौरतलब है कि भारतीय उपमहाद्वीप में खासतौर पर महाराष्ट्र और तमिल क्षेत्र में होने वाले गैर ब्राह्मण आन्दोलन समाज के सबसे निचले तबके के आंदोलन नहीं थे। ऐतिहासिक साहित्य को देखने से गैर ब्राह्मण आंदोलन और दलित आंदोलन का फर्क बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। अमेरिकी इतिहासकार यूजिन एफ. इरशिक का मानना था कि औपनिवेशिक भारतीय राजनीति में जाति ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स ऐंड सोशल कॉनलिक्ट इन साउथ इंडिया : द नॉन ब्राह्मण मुवमेंट ऐंड तमिल सेपरेटिज्म (बक्रले ऐंड लॉस एंजिल्स 1969) में उन्होंने गैर ब्राह्मण जातियों को अछूत आदि द्रविड़ों से अलग रखा। उन्होंने दिखाया कि तमिल प्रदेश में हुआ गैर ब्राह्मण आंदोलन कांग्रेस के ब्राह्मण वर्चस्व वाले राष्ट्रवादी आंदोलन के खिलाफ मध्यवर्ती जातियों का प्रतिरोध आंदोलन था। मध्यवर्ती गैर ब्राह्मण जातियों से ज्यादा नीची जातियों के प्रति भेदभाव की दृष्टि अपनाई जाती थी। वे अछूत जाति के थे और उनका दमन और उत्पीड़न ज्यादा होता था। समाज के इसी तबके से औपनिवेशिक भारत के अंतिम दौर में बी.आर. अम्बेडकर के नेतृत्व में दलित आंदोलन का उदय हुआ। महाराष्ट्र क्षेत्र में गैर ब्राह्मण आंदोलन भी हुए और दलित आंदोलन भी। गेल ऑमवेट ने अपनी दो अलग-अलग कृतियों में इन पर अलग-अलग विचार किया है। ये कृतियां हैं : कल्चरल रिवोल्ट इन कोलोनियल सोसाइटी : द नॉन-ब्राह्मण मुवमेंट इन वेस्टर्न इंडिया, 1873-1930 (बम्बई, 1976) य और दलित्स एंड द डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन : डॉ. अम्बेडकर एंड द दलित मुवमेंट इन कोलोनियम इंडिया (नई दिल्ली, 1994)। इलिनर जेलियट ने अपनी पुस्तक

फ्रोम अनटचेबुल टू दलित : एस्सेज ऑन द अम्बेडकर मुवमेंट (नई दिल्ली, 1992) में दलित आंदोलन पर विचार किया है।

खासतौर पर बंगाल के अंदरूनी भागों में रहने वाले कबीलों के आंदोलन अक्सर उग्र हो जाया करते थे। कबीले समाज के मुख्य धारा में शामिल नहीं हो सके थे और वे औपनिवेशिक राज्य की शक्ति को पूरी तरह से आंक नहीं पाए थे। अक्सर उनके विद्रोह खून के दरिया में डूब जाते थे। हमने देखा है कि डब्ल्यू. डब्ल्यू. हन्टर ने अपनी पुस्तक एनल्स ऑफ रूरल बंगाल में संथाल विद्रोह का वर्णन तो किया है परंतु इसका परिणाम क्या हुआ इस पर चुप्पी साध लिया है। इसके बाद जनजातीय प्रतिरोध आंदोलनों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। अधिक संगठित राष्ट्रवादी राजनीति और निम्न जाति के विरोध पर ध्यान केन्द्रित किया गया। हाल के वर्षों में जनोन्मुखी इतिहास-लेखन के तहत जनजातीय विद्रोहों पर विशेष ध्यान दिया गया। इस प्रकार के अध्ययनों में के.एस. सिंह के डस्ट स्टॉर्म ऐंड हैंगिंग मिस्ट : द स्टोरी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मुवमेंट (कलकत्ता, 1966) य और जे.सी. झा, ट्राइबल रिवोल्ट ऑफ छोटानागपुर, 1831-32 (पटना, 1987) उल्लेखनीय कृतियां हैं। इन दोनों ही कृतियों में छोटानागपुर पठार के कोल विद्रोहों का विवेचन किया गया है। भारत के इहिासकारों ने उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों के कबीलों पर बहुत कम ध्यान दिया है। कई वर्ष पहले मानवशास्त्री क्रिस्टोफ वॉन यूरर हेमेनड्रोफ ने द नेकेड नागाज : हेड हन्टर्स ऑफ असाम इन पीस एंड वार (कलकत्ता, 1946) नाम प्रसिद्ध कृति लिखी थी। अभी हाल में ही उत्तरपूर्व में उत्तरीपूर्वी पहाड़ियों के इतिहास पर काम शुरू हुआ है और आधुनिक अनुसंधान के मौजूदा प्रवृत्तियों के समान लैंगिक भेदभाव जैसे सामाजिक कारकों को अनुसंधान का आधार बनाया गया है। फ्रेडरिक एस. डाउन्स की पुस्तक द क्रिश्चन इम्पैक्ट ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया (शिलॉग, 1996) इस दृष्टि से उल्लेखनीय कृति है।

भारतीय राष्ट्रवाद का इतिहास लेखन इतिहासकारों के द्वारा अलग-अलग दृष्टिकोणों से किया गया। परंतु किसी एक दृष्टिकोण विशेष के आधार पर राष्ट्रवाद का लेखन संभव नहीं है। चूंकि हमारे यहाँ पर जमींदार वर्ग, जिसका निर्माण औपनिवेशिक सत्ता के द्वारा किया गया था जो अपनी पहचान एवं अस्तित्व को अक्षुण्ण बनाये रखना चाहते थे। देशी रियासतें के हित भी औपनिवेशिक शासन से जुड़े हुये थे तथा परपोषी वर्ग सूदखोर, महाजन इनके हित भी ब्रिटिश हितों से जुड़े हुये थे। इसलिये हमें राष्ट्रवाद का इतिहास लेखन

करते समय बहुआयामी दृष्टिकोण का प्रयोग करना चाहिये। जिसमें यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा भारतीय स्वतंत्रता के लिये किये गये प्रयासों के साथ ही उन वर्गों के प्रयासों को भी शामिल करना होगा। जिन्होंने अपनी स्थानीय समस्याओं को आधार बनाते हुये ब्रिटिश उपनिवेशवाद से कड़ा प्रतिरोध कर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने में अपना अमूल्य योगदान दिया। इसमें विशेष रूप से आदिवासियों, दलितों, महिलाओं, पिछड़ों, श्रमिक वर्ग के संघर्षों को शामिल किया जाना चाहिये।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. चन्द्र, बिपिन एवं अन्य, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली, 1990।
2. सरकार, सुमित, आधुनिक भारत (1885-1947 ई.) राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1993, पृ. 21-28।
3. श्रीधरन, ई., इतिहास-लेख (500 ई. पू. से सन् 2000 तक), हैदराबाद, 2011, पृ. 387-426।
4. दत्त, वी.एन. आधुनिक भारत (1857-1964), इग्नु, नई दिल्ली, 2013, पृ. 31।
5. दत्त, आर. पाम इंडिया टुडे (कलकत्ता, मनीषा, 1940, 1979)।
6. देसाई, ए.आर. सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म (बम्बई, 1948, 2000)।
7. सरकार, सुमित ए क्रिटिक ऑफ कोलोनियल इंडिया (कलकत्ता, पेपिरस, 1985)।
8. चन्द्र, बिपिन, आधुनिक भारत का इतिहास, ओरियंट ब्लैकस्वॉन, नई दिल्ली, 2010।
9. शुक्ल, आर.एल. (संपा.) आधुनिक भारत का इतिहास, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, नई दिल्ली, 1987, पृ. 1-44।
10. चन्द्र, बिपिन, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, इग्नु, नई दिल्ल, 2008, पृ. 15-22।
11. ताराचन्द, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास खण्ड-9, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, 1984, पृ. 1-13।

12. बंधोपाध्याय, शेखर, पलासी से विभाजन तक और उसके बाद, ओरियंट ब्लैकस्वॉन, नई दिल्ली, 2006, पृ. 184-191।
13. गुहा रंजीत, एलिमेंट्री आसपेक्ट्स ऑफ पीजेंट इनसरजेंसी इन कोलोनियल इंडिया, ओयूपी, दिल्ली, 1983।
14. हॉब्सबॉम, एरिक, ऑन हिस्ट्री फ्रोम बिलो, वाइडेनेफेल्ड़ ऐंड निकोलनसन, 1997।
15. राय, सत्या एम, भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, नई दिल्ली, 1993।
16. चन्द्र, बिपन, त्रिपाठी, अमलेश तथा देवरूण, स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, नई दिल्ली, 1972।
17. चतुर्वेदी, विनायक (संपा.) मैपिंग सबाल्टर्न स्टडीज ऐंड द पोस्टकोलोनियल (लंदन ऐंड न्यूयार्क, वर्सो, 2000)।

रामदेव जाट
सहायक आचार्य
इतिहास एवं भारतीय संस्कृति विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय
मो. 9414540584
ई-मेल - ramdevjat1122@gmail.com

❑❑❑

सर सैयद अहमद खान एवं पश्चिमी आधुनिकता : विज्ञान के प्रति दृष्टिकोण और सामाजिक शैक्षणिक सुधारों में उसकी प्रधानता

डॉ. तालीम अख्तर • डॉ. मुख्त्यार अली

यह लेख सर सैयद अहमद ख़ान के विज्ञान के प्रति दृष्टिकोण पर आधारित है। इसमें यह तर्क किया गया है कि सर सैयद अहमद ख़ान ने समाज और शिक्षा में सुधार की दिशा में मुस्लिम समाज के बीच विज्ञान को प्रधानता दी। यहाँ यह बताया गया है कि उनका विज्ञान के प्रति गैर-आलोचनात्मक दृष्टिकोण, उसके परिवर्तनकारी प्रभाव को ध्यान में रखते हुए समझा जाना चाहिए। तत्कालीन अलीगढ़ कॉलेज में पश्चिमी शिक्षा पर उनका बल और विज्ञान को इस्लाम से जोड़ने के उनके प्रयास उनकी वैज्ञानिक और तार्किक सोच से प्रेरित थे। इस लेख में सर सैयद अहमद ख़ान के इस गैर-आलोचनात्मक और अपरिपक्व दृष्टिकोण का विश्लेषण किया गया है।

इस तर्क को स्थापित करने के लिए, लेख को चार भागों में बाँटा गया है। पहले भाग में सर सैयद अहमद ख़ान पर विचारधारात्मक प्रभावों को रखा गया है। यहाँ यह बताया गया है कि सर सैयद अहमद ख़ान इस्लामी परंपरा के मुताज़िला के साथ-साथ पश्चिमी परंपराओं के प्रकृतिवाद, तर्कवाद और देववाद से भी प्रभावित थे। दूसरे भाग में सर सैयद अहमद ख़ान के सुधारवादी तत्परता पर चर्चा की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि इन्होंने मुसलमानों के बीच सामाजिक और शैक्षिक सुधार शुरू करते समय विज्ञान को प्राथमिकता दी थी। तीसरे भाग में सर सैयद अहमद ख़ान के विज्ञान के प्रति दृष्टिकोण पर विस्तार से चर्चा की गई है, जिसमें उनके गैर-आलोचनात्मक और अपरिपक्व दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है। लेख का अंतिम भाग सर सैयद अहमद ख़ान द्वारा स्थापित विज्ञान और इस्लाम के संबंध को प्रस्तुत करता है, जिसमें यह बताया

गया है कि इन्होंने विज्ञान और इस्लाम को इस तरह से जोड़ने की कोशिश की कि मुसलमान अपने पिछड़ेपन को दूर कर सकें।

सर सैयद अहमद ख़ान पर वैचारिक प्रभाव

सर सैयद अहमद ख़ान उन्नीसवीं सदी के आधुनिकतावादी विचारक थे, जिन्होंने भारतीय मुसलमानों के बीच सामाजिक सुधार की समस्या को सुलझाने के लिए विभिन्न दार्शनिक और वैचारिक दृष्टिकोणों को अपनाया। अज़ीज़ अहमद ने उनके विभिन्न वैचारिक रुझानों पर प्रकाश डाला है। वह यह बताते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान मुताज़िला (इस्लामी दर्शन) के साथ-साथ, दिल्ली के शाह वलीउल्लाह के राजनीतिक और सामाजिक विचारों व पश्चिमी दर्शन जैसे तर्कवाद, प्रकृतिवाद और उपयोगितावाद से भी प्रभावित थे। मुताज़िला दर्शन और शाह वलीउल्लाह के विचारों के प्रति श्रद्धा को उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। मुताज़िला (भिन्न-मतावलंबी) एक तर्कवादी दर्शन स्कूल था, जो 8वीं और 9वीं सदी में अब्बासी साम्राज्य के शासनकाल में उभरा था। जो लोग मुताज़िला दर्शन को मानते थे, वे विश्वास करते थे कि धर्म और तर्क का सामंजस्य संभव है। इस दर्शन का प्रभाव इतना गहरा था कि 19वीं सदी के कई समाज सुधारकों पर इसने गहरी छाप छोड़ी। उदाहरणस्वरूप, राजा राममोहन राय जैसे विचारक थे जिन्होंने मुताज़िला दर्शन से बहुत लाभ उठाया, और इस प्रकार सर सैयद अहमद ख़ान जैसे मुस्लिम विचारक भी इस दार्शनिक सोच के आकर्षण से अछूते नहीं थे।

18वीं सदी के दिल्ली के मुस्लिम सूफी संत और समाज सुधारक शाह वली-अल्लाह ने सर सैयद अहमद खान पर काफी प्रभाव डाला। यह रहस्यवादी सूफी संत शेख अहमद सिरहिंदी की परंपरा में प्रशिक्षित थे, जिनका सर सैयद अहमद ख़ान बहुत सम्मान करते थे। शाह वलीउल्लाह ने इज्तिहाद का कड़ा समर्थन किया था और उनका मानना था कि इज्तिहाद की कमी के कारण इस्लाम के पतन की स्थिति उत्पन्न हुई। वलीउल्लाह ने इस्लामी फ़िकह (कानून) के चार प्रमुख स्कूलों के बीच के छोटे-मोटे और संप्रदायवादी संघर्षों से ऊपर उठने का प्रयास किया था। बशीर अहमद डार के अनुसार, शाह वलीउल्लाह का इस्लामी धर्मशास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह था कि उन्होंने इस्लामिक विचारों की पुनर्व्याख्या करते समय तर्कसंगत विचार पर बल दिया। डार उनके शाह वलीउल्लाह के प्रति प्रशंसा में यह भी कहते हैं कि नए समय के अनुरूप कोई भी व्याख्या तभी स्वीकार्य हो सकती है, जब वह तर्कपूर्ण

दृष्टिकोण के साथ हो। शाह वलीउल्लाह द्वारा आधुनिक परिस्थितियों के संदर्भ में इज्तिहाद और इस्लाम की तर्कसंगत व्याख्या के लिए दी गई, यह असीमित स्वतंत्रता ही थी, जिसने सर सैयद अहमद ख़ान के विज्ञान और इस्लाम को जोड़ने के प्रयास की नींव रखी। अज़ीज़ अहमद का मानना है कि सर सैयद अहमद ख़ान ने वलीउल्लाही कट्टरवाद को प्रेरणा के रूप में लिया, लेकिन उन्होंने इसे अपने क्रांतिकारी आधुनिकतावाद के माध्यम से नया रूप दिया और पुनः व्याख्यायित किया।

सर सैयद अहमद ख़ान की सुधारवादी तत्परता

इस खंड में, हम सर सैयद अहमद ख़ान की सुधारात्मक तत्परता पर चर्चा करेंगे, जो इस्लामी और पश्चिमी दोनों परंपराओं से प्रभावित थी।

सर सैयद अहमद ख़ान का **शैक्षिक अभियान** दो प्रमुख संबंधों की ओर निर्देशित था:

1. **उलेमाओं का सरकार-प्रायोजित शिक्षा के प्रति अस्वीकारवादी रवैया,** जिनका मुख्य उद्देश्य था, एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना जो हमारे और उन लाखों लोगों के बीच मध्यस्थ बन सके जिन पर हम शासन करते हैं; एक ऐसा वर्ग, जो रक्त और रंग में भारतीय हो, लेकिन रुचि, विचारों, नैतिकताओं और बुद्धि में अंग्रेज़ हो।
2. यह समान रूप से **ब्रिटिश सरकार के भारतीय मुसलमानों के प्रति शत्रुतापर्ण रवैये** को भी लक्षित था, जो 1857 की क्रांति के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ था।

शुद्धतावादी उलेमाओं के प्रभाव में मुसलमानों ने पश्चिमी शिक्षा को नकार दिया और माना कि ऐसी शिक्षा प्रणाली इस्लाम के अनुसार नहीं है। उलेमा एक नये पारंपरिक शिक्षा प्रणाली को विकसित करने के इच्छुक थे, जो पश्चिमी हस्तक्षेपों से मुक्त हो। हालांकि, मुसलमानों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रति इस अस्वीकारवादी रवैये के पीछे एक गहरा डर भी छिपा हुआ था, और वह डर था सरकारी नौकरियों में उनका जो एकाधिकार था, उसे खो देने का, जो उन्होंने मुगलों के समय से लेकर अब तक बनाए रखा था। फ्रांसिस रॉबिन्सन मुसलमानों के पश्चिमी शिक्षा के प्रति अस्वीकारवादी दृष्टिकोण पर विचार करते हुए यह बताते हैं कि यह मानसिकता मुसलमानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर गंभीर प्रभाव डाल रही थी। 1857 के बाद की राजनीतिक परिस्थितियों के कारण मुसलमानों की स्थिति धीरे-धीरे बिगड़ने

लगी। मुस्लिम समुदाय अपने प्रभुत्व को बनाए रखने में सक्षम नहीं रहा और उन्हें ऐसी नौकरियों को अपनाना पड़ा, जो उनके सामाजिक दर्जे के अनुरूप नहीं मानी जाती थीं। जाहिर है, निचली जाति के मुसलमानों को भी इस संकट के नकारात्मक परिणामों का सामना करना पड़ा। जल्द ही, किसान (रैयत) भी अत्यधिक परेशान हो गए, क्योंकि वे हिंदू साहूकारों के हाथों शिकार हो गए थे। बालजॉन के अनुसार, इस दुखद घटनाक्रम का बहुत ही कुशलता से वर्णन एस.एस. थॉर्नबर्न ने अपनी पुस्तक 'मुसलमान्स एंड मनीलेंडर्स इन द पंजाब (1886) में किया है। राजनीतिक और आर्थिक परेशानियों के साथ-साथ, उस प्रतिकूल स्थिति की रूपरेखा को आकार देने में मनोवैज्ञानिक कारक भी स्वाभाविक रूप से शामिल था। जैसा कि कहा गया है, मुसलमानों को बदलाव से नफरत है। उनके अनुसार असली जीवन और आदर्श समुदाय स्थिर होते हैं। पश्चिम को उम्मीद है कि बदलाव बेहतर होता है; जबकि मुसलमानों को लगता है कि यह बदतर होता है।

यह वही अस्थिर संदर्भ था जिसमें सर सैयद अहमद ख़ान मुसलमानों के सामाजिक, धार्मिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कुछ उपायों की तलाश कर रहे थे। उन्होंने भारतीय मुसलमानों की शिक्षा की समस्या को हल करने के लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करने का निर्णय लिया। 1876 में, उन्होंने अपनी अधिकांश जिम्मेदारियों से इस्तीफा दे दिया ताकि अपना पूरा समय अलीगढ़ में आधुनिक शिक्षा के एक संस्थान की स्थापना में लगा सकें। अलीगढ़ कॉलेज औपचारिक रूप से 1875 में शुरू हुआ था। कैथरीन वॉट ने अलीगढ़ कॉलेज की वैचारिक नींव पर विचार करते हुए यह कहा:

अलीगढ़ का विचार धार्मिक और आर्थिक दो कारणों से उत्पन्न हुआ था, इस्लाम में आस्था को पुनर्जीवित करने और मुस्लिम परिवेश में सरकारी सेवा के लिए आवश्यक ब्रिटिश शिक्षा प्रदान करने के लिए।

सर सैयद अहमद ने अलीगढ़ कॉलेज की कल्पना पूर्व और पश्चिम के बीच एक समन्वय के रूप में की थी, लेकिन उन्होंने इस दृष्टिकोण का स्वयं उल्लंघन किया, क्योंकि उन्होंने पश्चिमी शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया और पूरी तरह से पारंपरिक मुस्लिम मूल्यों और धार्मिक आदर्शों की अनदेखी की। पश्चिमी शिक्षा के प्रति यह गैर-आलोचनात्मक दृष्टिकोण उनकी आत्म-समर्पणशीलता को दर्शाता है, जो उनके विचारों और क्रियाओं के सभी

पहलुओं में व्याप्त थी। यह वही रवैया था जिसने उन्हें पूर्वी दुनिया के गहरे दार्शनिक और साहित्यिक परंपराओं की खोज करने से रोक दिया, और इसी समझ की कमी ने उन्हें अपने ही लोगों को तिरस्कार की दृष्टि से देखने पर मजबूर किया।

थॉमस आर्नोल्ड और शिबली नुमानी उन्नीसवीं सदी के दो प्रमुख व्यक्तित्व थे जिन्होंने अलीगढ़ कॉलेज के अपने मूल दृष्टिकोण से भटकने को उजागर किया, जो पूर्व और पश्चिम के बीच एक समन्वय की तलाश करना था। दोनों ने कॉलेज के विद्यार्थियों और पाठ्यक्रम पर गहरा आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया क्योंकि :

1. उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पर अत्यधिक जोर दिया था।
2. उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को धन कमाने का एक साधन के रूप में देखा था।

आर्नोल्ड और शिबली दोनों ने स्थानीय शिक्षा और पूर्वी शिक्षा के महत्व पर बल दिया। वे इस्लाम के इतिहास, भाषाओं और साहित्य के हाशिए पर चले जाने से अत्यंत निराश थे और उनका मानना था कि कॉलेज का पाठ्यक्रम इनकी अहमियत को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। यह उपेक्षा सर सैयद अहमद की स्थानीय शिक्षा और पूर्वी शिक्षा से निराशा का परिणाम थी। सर सैयद ने शिक्षा को मुसलमानों के सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के एक साधन के रूप में देखा। इस प्रकार के साधनात्मक दृष्टिकोण में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आर्थिक लाभ प्राप्त करना होता है, और यह इस तथ्य को नज़रअंदाज कर देता है कि ज्ञान खुद में साधक के लिए अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। आर्नोल्ड ने इस साधनात्मक दृष्टिकोण की आलोचना की और कहा कि शिक्षा तब ही मूल्यवान होती है, जब हम उसे अपने स्वयं के उद्देश्य के लिए प्राप्त करें। आर्नोल्ड का यह दृष्टिकोण, जब वह लाहौर के सरकारी कॉलेज में इकबाल के शिक्षक थे, इकबाल के विचारों पर गहरा असर डालता है। इसने इकबाल के शिक्षा के दृष्टिकोण को प्रभावित किया, जो सर सैयद के विपरीत, न तो साधनात्मक था और न ही स्थानीय शिक्षा और पूर्वी शिक्षा के महत्व से अनजान था। इकबाल की उच्च दृष्टि और शिक्षा के प्रति उनका आदर्श दृष्टिकोण बाल-ए-जिब्रिल के इस शेर में स्पष्ट रूप से झलकता है:

ओ आकाशीय पक्षी, अच्छा होगा कि तुम भूख से मर जाओ,

उस नौकरी को स्वीकार करने से बेहतर है जो तुम्हारी उड़ान को बाँध दे।

सैयद अहमद और अलीगढ़ कॉलेज द्वारा प्रचारित शिक्षा के प्रकार के प्रति इन आशंकाओं के बावजूद, वह इस्लाम को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण बने रहते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने इस्लाम को आधुनिक विज्ञान के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया, वह भी महत्वपूर्ण है। आगामी चर्चा में हम सर सैयद अहमद ख़ान के विज्ञान के प्रति दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

सर सैयद अहमद एक विशेष संदर्भ में लिख रहे थे, जिसमें भारतीय मुसलमानों ने पश्चिमी शिक्षा और आधुनिक विज्ञान के प्रति असंतोष व्यक्त किया था। उन्हें मुसलमानों का पिछड़ापन देखकर पीड़ा होती थी और उन्होंने आधुनिक शिक्षा और विज्ञान के माध्यम से सामाजिक सुधार की कोशिश की। बालजोन यह बताते हैं कि सर सैयद अहमद मुसलमानों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह उनकी इंग्लैंड यात्रा थी जिसने उन्हें सही तरीका समझाया, जिसके माध्यम से मुसलमानों के उद्धार की परियोजना शुरू की जा सकती थी। इंग्लैंड यात्रा ने उनके पश्चिमी सभ्यता के प्रति दृष्टिकोण को भी आकार दिया। तभी उन्हें यह महसूस हुआ कि इंग्लैंड के लोगों और उनके अपने देशवासियों के बीच एक विशाल अंतर था। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि सभी समस्याओं का मूल कारण विज्ञान संबंधी जानकारी की कमी थी। सर सैयद अहमद पश्चिमी सभ्यता द्वारा की गई वैज्ञानिक प्रगति से पूरी तरह से प्रभावित हो गए थे और उन्हें लगा कि आधुनिक विज्ञान वह माध्यम है जिसके द्वारा मुसलमान अपने आप को स्वतंत्र और सशक्त बना सकते हैं।

एस. इरफान हबीब के अनुसार, 19वीं सदी के अंत में मुसलमानों की आधुनिक विज्ञान के प्रति प्रतिक्रियाएँ वही थीं, जैसी डेविड कोफ ने उन्नीसवीं सदी के प्रारंभिक बंगाली भद्रलोक की प्रतिक्रियाओं के बारे में बताई हैं। कोफ इन प्रतिक्रियाओं को पुनर्जागरणवादी, पुनर्जीवीकरणवादी, और पूरी तरह से पश्चिमीकरण की दिशा में एक रास्ता खोलने के रूप में वर्गीकृत करते हैं। हबीब का मानना है कि भारत और अन्य स्थानों पर मुसलमानों की आधुनिक विज्ञान के प्रति प्रतिक्रियाओं को निम्नलिखित श्रेणियों में बाँटा जा सकता है :

1. आधुनिक पश्चिमी विज्ञान को पूरी तरह से नकारना। इस श्रेणी में वहाबी विचारधारा को लिया जा सकता है, जिन्होंने न केवल पश्चिम को नकारने पर जोर दिया, बल्कि इस्लाम के शुद्धतावादी रूप की वापसी का भी

समर्थन किया, ताकि वर्तमान में फैल रही ठहराव की स्थिति से उबरा जा सके।

2. आधुनिक परिस्थितियों के तहत इस्लाम को अपनाना। 19वीं और 20वीं सदी में भारतीय मुस्लिम विद्वानों ने आधुनिक पश्चिमी विज्ञान को नकारने के बजाय, इस्लाम को आधुनिक परिस्थितियों के तहत रचनात्मक रूप से अपनाने का प्रयास किया।

3. पश्चिमी विचारों और संस्थाओं का अविचारणीय समर्थन।

परवेज हुडबॉय और एस. इरफान हबीब, सर सैयद अहमद ख़ान के साथ सहानुभूति से जुड़ते हुए, उन्हें पुनर्निर्माणवादी या पुनर्जीवीकरणवादी मानते हैं। हबीब, सर सैयद अहमद ख़ान के पुनर्निर्माणवादी दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए यह आग्रह करते हैं कि हमें उनके कार्यों और गतिविधियों को 19वीं सदी के भारतीय मुसलमानों के सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ में समझना चाहिए। स्वाभाविक रूप से, हबीब की सर सैयद अहमद ख़ान के साथ आधुनिक विज्ञान के जुड़ाव को लेकर सकारात्मक दृष्टि इतनी गहरी है कि वे यह भूल जाते हैं कि सर सैयद ने पश्चिमी आधुनिकता और विज्ञान का समर्थन करते हुए इसके सामाजिक और राजनीतिक परिणामों को समझने में एक वैध तर्कसंगत आलोचना की आवश्यकता महसूस नहीं की थी। इसके अतिरिक्त, वह यह सुझाव देते हैं कि 20वीं सदी में कुह्न द्वारा विज्ञान की आलोचनाओं के बाद, सर सैयद अहमद खान द्वारा विज्ञान के गैर-आलोचनात्मक समर्थन की कल्पना करना कठिन है, और हमें सर सैयद अहमद खान के आधुनिक विज्ञान के प्रति अडिग समर्थन को 19वीं सदी में विज्ञान और उद्योग की अभूतपूर्व वृद्धि की दृष्टि से समझना चाहिए। हालांकि, हबीब यह नहीं समझ पाते कि आधुनिक विज्ञान की वैज्ञानिक आलोचना 20वीं सदी में नहीं, बल्कि 17वीं सदी के यूरोप में ही शुरू हो चुकी थी। सर सैयद अहमद ख़ान द्वारा आधुनिक पश्चिमी विज्ञान के अंध समर्थन से यह स्पष्ट होता है कि वे आधुनिक विज्ञान के सामाजिक और राजनीतिक परिणामों से अनजान रहे, जिनका उल्लेख 17वीं और 18वीं सदी के यूरोप में स्वतंत्र विचारकों और रोमांटिकवादियों ने किया था। भारत में, गांधी और इकबाल की रचनाओं में इस आधुनिक विज्ञान की तर्कसंगत आलोचना के कुछ संकेत मिलते हैं।

विज्ञान और इस्लामः ऐतिहासिक संगतता का तर्क

विज्ञान और इस्लाम के बीच ऐतिहासिक संगतता पर तर्क को विभिन्न

तरीकों से व्याख्यायित किया गया है। इन व्याख्याओं में से दो विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं। पहली, हम उन विद्वानों के समूह पर विचार कर सकते हैं, जिन्होंने इस्लाम की सभ्यता में विज्ञान के विकास और विस्तार को इस्लामी विज्ञान के रूप में देखा है। इस समूह में सैयद हुसैन नसर और मुज़फ्फर इकबाल जैसे विद्वान शामिल हैं। इन विद्वानों ने इस्लामी विज्ञान की विशिष्टता पर जोर दिया है और इस कारण उन्होंने इस्लामी विज्ञान (जो 8वीं से 12वीं सदी तक इस्लाम की सभ्यता में विकसित हुआ था) को आधुनिक पश्चिमी विज्ञान से अलग करने का प्रयास किया है।

दूसरी व्याख्या यह है कि विज्ञान और इस्लाम के बीच ऐतिहासिक संगतता का तर्क एस. इरफान हबीब जैसे विद्वानों द्वारा एक धर्मनिरपेक्ष और बहुसांस्कृतिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है। हबीब ने इस ऐतिहासिक संगतता को रेखांकित करने में ए. साबरा के कार्यों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया है। साबरा ने इस्लामी सभ्यता में यूनानी विज्ञान के समावेशन को शानदार तरीके से दर्शाया है। ए. साबरा ने अब्बासी साम्राज्य (8वीं और 9वीं शताब्दी) के दौरान विज्ञान के विकास और विस्तार का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। उन्होंने सूक्ष्मता से यह बताया कि अनुवाद आंदोलन कोई छोटा, गुप्त या अवैध आंदोलन नहीं था, बल्कि यह एक पूर्ण विकसित घटना थी, जिसमें कई ग्रंथों का अनुवाद अब्बासी खलीफाओं की नैतिक और वित्तीय निगरानी में किया गया था। पुस्तकालयों की स्थापना की गई थी, जहाँ दर्शनशास्त्र और विज्ञान पर किताबों का संग्रह होता था, दूतावासों से पांडुलिपियाँ प्राप्त की गई थीं, और कई विद्वानों को अनुवाद के लिए नियुक्त किया गया था। दिमित्री गुतास ने इस आंदोलन के बारे में बगदाद में एक मौलिक अवलोकन किया था। उन्होंने बताया कि इतिहास में पहली बार वैज्ञानिक ज्ञान और दर्शन को अंतर्राष्ट्रीय माना गया, और यह केवल भाषा की सीमाओं के भीतर नहीं था। साबरा ने इस घटना का वर्णन करने के लिए स्वीकार शब्द के प्रयोग की आलोचना की है उनका कहना था कि स्वीकार किसी चीज को एक निष्क्रिय तरीके से समझने का विवरण है, जो आमतौर पर प्राप्तकर्ता द्वारा आलोचनात्मक दृष्टिकोण से रहित होता है। उन्होंने यह भी बताया कि यह यूनानी दर्शन का थोपना नहीं था, बल्कि यह ज्ञान और विचारों का संप्रेषण था, जिसे अब्बासियों ने विस्तार से समझा, अपनाया और बाद में इसे अपनी विरासत बनाने के लिए उपयोग किया। यह वही विज्ञान का विकास और विस्तार था, जो इस्लामी सभ्यता में हुआ था, जिसने सर सैयद अहमद ख़ान को इस्लाम और विज्ञान के बीच संगतता स्थापित करने का तर्क

प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने प्रारंभ में ही यह समझ लिया था कि इस्लाम और विज्ञान को सामंजस्यपूर्ण रूप से मिलाने के रास्ते में कई कठिनाइयाँ हैं और इसे अपने रूढ़िवादी विचारों से बाहर लाना आवश्यक है।

एस. इरफान हबीब ने 19वीं सदी के मुस्लिम बुद्धिजीवियों पर अपनी रचनाओं में, सर सैयद अहमद खान को 19वीं सदी के भारतीय मुस्लिम बौद्धिकों में एक प्रमुख बुद्धिजीवी के रूप में प्रस्तुत किया है, जो जमाल अद-दीन अल-अफगानी के समकालीन थे, जिन्होंने आधुनिक विज्ञान के सार्वभौमिक चरित्र की वकालत की थी। हबीब आधुनिक विज्ञान के बहुसांस्कृतिक चरित्र पर जोर देते हैं और इस्लामी विज्ञान, हिंदू विज्ञान, ईसाई विज्ञान और यहूदी विज्ञान जैसे विज्ञान के वर्गीकरण के किसी भी प्रयास को सांप्रदायिक और अलोकतांत्रिक मानते हैं। सर सैयद अहमद खान के लेखन के माध्यम से हबीब इस विचार को प्रमुखता से रखते हैं कि 19वीं सदी के बुद्धिजीवी इस्लामी विज्ञान में रुचि नहीं रखते थे। जबकि इस्लामी सभ्यता द्वारा किए गए योगदानों को प्रदर्शित करते हुए, वे यह ऐतिहासिक तथ्य उजागर करने में अधिक रुचि रखते थे कि इस्लाम विज्ञान के साथ विरोध में नहीं था और इसके विपरीत, विज्ञान और इस्लाम एक-दूसरे के साथ ऐतिहासिक रूप से संगत थे।

इस्लाम और विज्ञान के बीच ऐतिहासिक संगतता सर सैयद अहमद खान के अध्ययन तक सीमित नहीं है। अन्य मुस्लिम बुद्धिजीवियों, जिनमें जमाल अद-दीन अल-अफगानी और मोहम्मद इकबाल ने भी इस्लाम और विज्ञान के बीच ऐतिहासिक संगतता पर समान रूप से बल दिया था। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इन मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने विशेष रूप से अपने मुस्लिम समुदाय में आधुनिक विज्ञान के प्रति व्याप्त पिछड़ेपन और उदासीनता को दूर करने के लिए इस्लाम और विज्ञान के बीच इस सकारात्मक संबंध की फिर से खोज की थी। संक्षेप में, 19वीं सदी के बुद्धिजीवी, जैसे सर सैयद अहमद खान, पहले और सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार की परियोजना में संलग्न थे। मुस्लिम मानसिकता में आधुनिक विज्ञान के लिए वैधता स्थापित करने के लिए, उन्होंने 8वीं से 12वीं सदी तक इस्लामिक दुनिया में हुए वैज्ञानिक विकास पर जोर दिया।

हालाँकि, विज्ञान और धर्म के बीच ऐतिहासिक संगतता का तर्क सर सैयद अहमद खान द्वारा विज्ञान और इस्लाम के सामंजस्य के लिए प्रस्तुत किए गए दृष्टिकोण का केवल एक पहलू है। उनके विज्ञान और इस्लाम के सामंजस्य की

योजना में एक और प्रमुख पहलू उनके धर्मशास्त्र के रूप में स्पष्ट होता है, जिसे उन्होंने कुरान, हदीस (नबी की परंपराएँ) और उनके द्वारा देवदूतों और शैतानों के प्रश्न पर किए गए विमर्श के माध्यम से प्रारंभ किया था।

निष्कर्ष

यह लेख सर सैयद अहमद खान के विज्ञान के प्रति दृष्टिकोण पर आधारित है। यहाँ यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम समाज में सामाजिक और शैक्षिक सुधारों की शुरुआत करते हुए विज्ञान को केंद्रीय स्थान दिया। लेख में यह बताया गया है कि सर सैयद अहमद खान का विज्ञान के प्रति गैर-आलोचनात्मक दृष्टिकोण उसके रूपांतरण की क्षमता के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। अलीगढ़ विश्वविद्यालय में पश्चिमी शिक्षा पर उनका जोर और इस्लाम के साथ विज्ञान के सामंजस्य की उनकी कोशिशें उनके वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण से प्रेरित थीं।

आभार : लेखक श्री अतीक खत्री के प्रति इस लेख की प्रूफ रीडिंग करने व कुछ रचनात्मक टिप्पणियाँ दर्ज करके इस लेख को सुधारने में उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

संदर्भ सूची

1. अहमद, अजीज. सैय्यद अहमद खान, जमाल अल-दीन अल-अफ़ग़ानी और मुस्लिम भारत। 'Studia Islamica', सं. 13, (1960): 55-78।

2. बलजोन, जोहान्स मारिनस सिमोन. 'The Reforms and Religious Ideas of Sir Sayyid Ahmad Khan'. लाहौर: श. मुहम्मद अशरफ, 1964।

3. दर, बशीर अहमद. 'Religious Thoughts of Sir Syed Ahmad Khan' लाहौर : इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक कल्चर, 1957।

4. देवजी, फैसल. "Apologetic Modernity." Modern Intellectual History वॉल. 4, सं. 01 (2007): 61-76।

5. फाखरी, मजीद. 'A History of Islamic Philosophy'. न्यू यॉर्क: कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस, 2004।

6. हबीब, एस. इरफ़ान, और ध्रुव रैना. कोपरनिकस, कोलंबस, उपनिवेशवाद और उन्नीसवीं सदी में भारत में विज्ञान की भूमिका। 'Social Scientist', वॉल. 3, सं. 4, (1989): 51-66।

7. हबीब, एस. इरफ़ान. उन्नीसवीं सदी के भारत में इस्लाम के साथ विज्ञान का सामंजस्य। 'Contributions to Indian Sociology' 34, सं. 1 (2000) : 63-92।

8. लॉरेंस, ब्रूस बी. . "From Fundamentalism to Fundamentalisms : A Religious Ideology in Multiple Forms." पॉल हीलस (संपा.), 'Religion, Modernity and Postmodernity' ऑक्सफ़ोर्ड: ब्लैकवेल, (1998): 88-101।

9. लॉरेंस, ब्रूस. "Scripture, History and Modernity: Readings of the Qur'an.", "Muslim Modernities: Expressions of the Civil Imagination" (2008): 25-49।

10. लेलवेल्ड, डेविड. "Aligarh's First Generation: Muslim Solidarity in British India, vol. 4." प्रिंसटन: प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस, 1978।

11. मलिक, हफीज, और हफीज मलिक. Sir Sayyid Ahmad Khan and Muslim Modernization in India and Pakistan. न्यू यॉर्क: कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस, 1980।

12. रॉबिन्सन, फ्रांसिस. (2008). "Islamic Reform and Modernities in South-Asia,", "Modern Asian Studies", वॉल. 42, सं. 2-3, मार्च-मई।

13. ट्रोल, क्रिश्चियन डब्ल्यू. "Sayyid Ahmad Khan: A Reinterpretation of Muslim Theology" नई दिल्ली : विकास पब्लिशिंग हाउस, 1978।

14. वाट, कैथरीन. "Thomas Walker Arnold and the re-evaluation of Islam, 1864-1930.", "Modern Asian Studies" वॉल. 36, सं. 01 (2002): 49-50।

डॉ. तालीम अख्तर

दिल्ली विश्वविद्यालय के हिन्दू कॉलेज में राजनीतिक विज्ञान के सह आचार्य के रूप में कार्यरत है।

डॉ. मुख्त्यार अली

इग्नू में क्षेत्रीय सहायक निदेशक के रूप में कार्यरत है।

❑❑❑

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की वर्तमान परिप्रेक्ष में प्रासंगिकता

• सलीम सोलंकी

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (Directive Principles of State Policy & DPSP) भारतीय संविधान के भाग IV में उल्लेखित हैं। ये सिद्धांत राज्य को एक कल्याणकारी राज्य बनाने का मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। संविधान निर्माताओं ने इन्हें नागरिकों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण के उद्देश्य से शामिल किया था। यद्यपि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, लेकिन ये देश की नीति निर्माण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण आधार हैं। वर्तमान समय में, जब भारत तेजी से आर्थिक और सामाजिक विकास की ओर अग्रसर है, इन सिद्धांतों की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है।

भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व (Directive Principles of State Policy & DPSP) भाग IV (अनुच्छेद 36 से 51) के अंतर्गत वर्णित हैं। ये तत्व संविधान के सामाजिक और आर्थिक दर्शन का मार्गदर्शन करते हैं और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का उद्देश्य रखते हैं।

परिभाषा और उद्देश्यः-

- नीति निर्देशक तत्त्व ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत हैं जो राज्य को नीतियां बनाने और शासन चलाने में दिशा प्रदान करते हैं।
- ये सिद्धांत मौलिक अधिकारों के पूरक हैं।
- इनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देना है।
- संविधान सभा ने इन्हें आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर अपनाया।

संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरणः

नीति निर्देशक तत्वों को उनके उद्देश्य और प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता हैः

1. समाजवादी सिद्धांत :

यह सिद्धांत समाज में आर्थिक और सामाजिक समानता स्थापित करने का प्रयास करते हैं।

अनुच्छेद 38 : राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देगा और असमानताओं को कम करेगा।

अनुच्छेद 39 : राज्य नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने, धन का समान वितरण सुनिश्चित करने और श्रमिकों के कल्याण को प्राथमिकता देगा।

अनुच्छेद 41 : राज्य रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्रदान करेगा।

अनुच्छेद 43 : श्रमिकों के लिए उचित मजदूरी और जीवन स्तर सुनिश्चित करना।

अनुच्छेद 47 : राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करेगा।

2. गांधीवादी सिद्धांत :

ये सिद्धांत महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित हैं और ग्रामीण विकास एवं स्वावलंबन को बढ़ावा देते हैं।

अनुच्छेद 40 : ग्राम पंचायतों की स्थापना और उन्हें अधिकार प्रदान करना।

अनुच्छेद 43 : कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना।

अनुच्छेद 46 : अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की सुरक्षा।

अनुच्छेद 48 : कृषि और पशुपालन का आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों से प्रोत्साहन।

3. उदारवादी सिद्धांत

यह सिद्धांत नागरिक स्वतंत्रता और कानून के शासन को बढ़ावा देते हैं।

अनुच्छेद 44 : राज्य पूरे भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 45 : 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। (अब यह अनुच्छेद 21। के तहत मौलिक अधिकार बन चुका है)।

अनुच्छेद 48 : पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवन की रक्षा।

अनुच्छेद 49 : राष्ट्रीय धरोहरों, स्मारकों और स्थानों की सुरक्षा।

अनुच्छेद 50 : न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच अलगाव।

अनुच्छेद 51 : अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना।

नीति निर्देशक तत्वों की विशेषताएं :

1. न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं : ये तत्व न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किए जा सकते।
2. राजनीतिक नैतिकता का आधार : ये राज्य को नीति निर्माण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
3. लचीला दृष्टिकोण : ये संविधान के लचीले दृष्टिकोण को प्रदर्शित करते हैं।
4. कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य: इनका मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना है।

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का महत्व:-

1. **सामाजिक समानता और न्याय :** अनुच्छेद 38 राज्य को सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। वर्तमान समय में, जब जाति, धर्म और आर्थिक असमानताएं समाज में व्याप्त हैं, यह सिद्धांत सामाजिक समरसता सुनिश्चित करने में सहायक है।
2. **आर्थिक कल्याण :** अनुच्छेद 39 में संसाधनों का समान वितरण, मजदूरों के अधिकार और सभी को समान अवसर सुनिश्चित करने की बात की गई है। यह आज के दौर में अत्यधिक प्रासंगिक है, जब आर्थिक असमानता बढ़ रही है।
3. **स्वास्थ्य और शिक्षा :** अनुच्छेद 41, 45, और 47 नागरिकों को शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार प्रदान करने की बात करते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 और आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं इन्हीं सिद्धांतों के अनुरूप हैं।
4. **पर्यावरण संरक्षण :** अनुच्छेद 48 । पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण की बात करता है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय समस्याओं के बढ़ते खतरे को देखते हुए यह सिद्धांत अत्यधिक प्रासंगिक है।
5. **महिला सशक्तिकरण :** अनुच्छेद 39 (।) महिलाओं और पुरुषों को

समान वेतन और अवसर प्रदान करने की बात करता है। वर्तमान समय में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को लेकर चल रहे आंदोलन और नीतियां इस सिद्धांत को व्यवहार में लाने का प्रयास हैं।

आधुनिक संदर्भ में प्रासंगिकता :

1. **विकास और समावेशिता :** वर्तमान समय में भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है। ऐसे में नीति निर्देशक सिद्धांत समावेशी विकास और गरीबों के उत्थान की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
2. **कानूनी प्रभाव और न्यायिक व्याख्या :** भले ही ये सिद्धांत न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन कई मामलों में न्यायपालिका ने इनका उपयोग संविधान की व्याख्या करने और कानून बनाने में किया है।

1. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा हैं। इन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता और कानून बनाते समय इनका पालन अनिवार्य है। यह फैसला नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करता है।
2. मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980) संविधान के अनुच्छेद 31 ब में संशोधन और नीति निर्देशक तत्वों की प्राथमिकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के मूल ढांचे में मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व संतुलित रूप से सह-अस्तित्व में रहते हैं। नीति निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। इस निर्णय ने नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता को रेखांकित किया।
3. ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम (1985) फुटपाथ पर रहने वाले गरीबों को बेदखल करने का मामला।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 21-जीवन का अधिकार) की व्याख्या नीति निर्देशक तत्वों के आलोक में की जानी चाहिए। इस मामले में, लोगों का जीवन और जीविका सुरक्षित करना राज्य की जिम्मेदारी है।यह फैसला दिखाता है कि कैसे नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों को लागू करने में सहायता करते हैं।
4. मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य (1992) सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि

शिक्षा का अधिकार जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) का हिस्सा है। नीति निर्देशक तत्व (अनुच्छेद 45) के तहत प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना राज्य की जिम्मेदारी है। इस फैसले ने शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिए जाने का मार्ग प्रशस्त किया।

5. उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1993)सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21) और नीति निर्देशक तत्व (अनुच्छेद 41 और 45) के तहत समाहित किया, इस निर्णय ने 86वें संविधान संशोधन अधिनियम (2002) का आधार तैयार किया, जिसमें अनुच्छेद 21 A जोड़ा गया।
6. चमनलाल बनाम राज्य (1987) सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि श्रमिकों के अधिकार, विशेष रूप से वेतन और कार्य के प्रति सम्मान का अधिकार, नीति निर्देशक तत्वों (अनुच्छेद 39 और 41) के अनुरूप सुनिश्चित किए जाने चाहिए। यह निर्णय श्रमिकों के कल्याण पर जोर देता है।
7. एमसी मेहता बनाम भारत संघ (1987) सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 48। (पर्यावरण संरक्षण) नीति निर्देशक तत्वों के तहत एक महत्वपूर्ण दायित्व है, जिसे न्यायालय के आदेशों के माध्यम से लागू किया जा सकता है। इस निर्णय ने भारत में पर्यावरणीय कानूनों और जागरूकता को बढ़ावा दिया।
8. महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानत रू. अनुच्छेद 39 (A) महिलाओं और पुरुषों के लिए समान वेतन और अवसर सुनिश्चित करने की बात करता है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और मातृत्व लाभ अधिनियम इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल हैं।
9. कानूनी सुधार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता:- अनुच्छेद 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका के अलगाव की बात करता है, जिससे न्यायिक निष्पक्षता बनी रहे।
10. अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा:- अनुच्छेद 51 के तहत भारत को अंतरराष्ट्रीय शांति, मानवाधिकारों की सुरक्षा और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। वर्तमान में, G20 शिखर सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भारत की भागीदारी इसी के अनुरूप है।
11. पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1996) रू. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वास्थ्य का अधिकार, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, राज्य का दायित्व है, और यह नीति निर्देशक तत्वों (अनुच्छेद

47) के अनुरूप है। इस फैसले ने सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया।

12. विश्वकर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1982) सुप्रीम कोर्ट ने बाल श्रम उन्मूलन के लिए अनुच्छेद 39 (e) और (f) के प्रावधानों को लागू करने का निर्देश दिया।

महत्व : बाल अधिकारों की रक्षा में यह निर्णय महत्वपूर्ण है।

3. सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम:

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम म (MGNREGA) प्रधानमंत्री आवास योजना, और मध्याह्न भोजन योजना जैसे कार्यक्रम इन्हीं सिद्धांतों की प्रेरणा से संचालित हैं।

4. सतत विकास:

पर्यावरण संरक्षण, हरित ऊर्जा, और सतत विकास जैसे मुद्दों पर नीति निर्देशक सिद्धांत वर्तमान नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

चुनौतियां और सुधार की आवश्यकता:

कानूनी प्रवर्तनीयता का अभाव : चूंकि ये सिद्धांत न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, इसलिए इनके कार्यान्वयन में बाधाएं आती हैं।

सामाजिक जागरूकता की कमी : इन सिद्धांतों के महत्व को लेकर आम जनता में पर्याप्त जागरूकता नहीं है।

राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव : कई बार नीतियों को लागू करने में राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी देखी जाती है।

निष्कर्ष:

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के आदर्श और दृष्टि का प्रतिबिंब हैं। वर्तमान समय में, जब भारत सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रहा है, ये सिद्धांत एक मार्गदर्शक प्रकाशस्तंभ की भूमिका निभाते हैं। इन सिद्धांतों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए नागरिक जागरूकता, राजनीतिक प्रतिबद्धता और कानूनी ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता है।

संदर्भ :

1. Kesavananda Bharati v. State of Kerala, (1973) 4 SCC 225

2. Minerva Mills Ltd. v. Union of India, (1980) 3 SCC 625
3. Olga Tellis v. Bombay Municipal Corporation, (1985) 3 SCC 545
4. Mohini Jain v. State of Karnataka, (1992) 3 SCC 666
5. Unni Krishnan v. State of Andhra Pradesh, (1993) 1 SCC 645
6. Chaman Lal v. State of Punjab, (1987) 1 SCC 469
7. M.C. Mehta v. Union of India, (1987) 1 SCC 395
8. Vishaka v. State of Rajasthan, (1997) 6 SCC 241
9. S. P. Gupta v. Union of India, (1981) Supp SCC 87.
10. M.P. Jain, Indian Constitutional Law, 8th ed. (LexisNexis 2022).
11. H.M. Seervai, Constitutional Law of India, 4th ed. (Universal Law Publishing 2019).
12. Granville Austin, The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation (Oxford University Press 2018).
13. Subhash C. Kashyap, Constitutional Law of India (Sage Publications 2020).
14. Upendra Baxi, "Directive Principles and Socio-Economic Justice in India" (1994) 36(4) JILI 254.
15. Rajeev Dhavan, "The Directive Principles and the Fundamental Rights" (2007) 49(2) JILI 321.
16. Arvind P. Datar, "Judicial Review of Directive Principles" (2015) 57(3) JILI 189.
17. Arvind P. Datar, "Judicial Review of Directive Principles" (2015) 57(3) JILI 189.
18. Pratap Bhanu Mehta, "The Indian Judiciary and Socio-Economic Rights" (2012) 44(1) JILI72.
19. S. P. Sathe, "Directive Principles and Indian Judiciary" (1989) 31(2) JILI 211.

शोधार्थी

सलीम सोलंकी

टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर

❑❑❑

कर्मचारियों के मानवाधिकार : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

• डॉ. रितु चौधरी

मानवाधिकार वे मूलभूत अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त होते हैं, चाहे वह किसी भी देश, जाति, धर्म या समाज से संबंधित हो। कार्यस्थल पर कर्मचारियों के मानवाधिकारों का महत्व वैश्विक स्तर पर लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि यह न केवल उनके सम्मान और गरिमा की रक्षा करता है बल्कि उत्पादकता और संगठनात्मक सफलता में भी योगदान देता है।

कर्मचारियों के मानवाधिकार किसी भी सभ्य समाज की आधारशिला हैं। यह अधिकार उन्हें उनकी गरिमा, सुरक्षा और सम्मान के साथ काम करने का अधिकार देता है। कार्यस्थल पर मानवाधिकारों का सम्मान न केवल कर्मचारियों के व्यक्तिगत कल्याण को सुनिश्चित करता है, बल्कि यह कंपनी की प्रतिष्ठा और उत्पादकता को भी बढ़ाता है।

मुख्य शब्द : *मानवाधिकार, कर्मचारी, कार्यस्थल, समानता, उत्पीड़न, संविधानिक अधिकार आदि।*

कर्मचारी के मानवाधिकार की परिभाषा :

कर्मचारियों के मानवाधिकारों की परिभाषा विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में बदलती है, क्योंकि यह विभिन्न सामाजिक, कानूनी, और सांस्कृतिक संदर्भों से प्रभावित होती है। यहाँ कुछ प्रमुख परिप्रेक्ष्यों में इनकी परिभाषा दी गई है[1]

1. कानूनी परिप्रेक्ष्य-कानूनी दृष्टिकोण से, कर्मचारियों के मानवाधिकार वह अधिकार हैं जो उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत मिलते हैं। इसमें उचित कार्य की स्थिति, वेतन, कार्य के घंटे, अवकाश, और श्रमिक संघ बनाने का अधिकार शामिल है। उदाहरण के लिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा निर्धारित मानक और विभिन्न देशों

के श्रम कानून इस परिप्रेक्ष्य में कर्मचारियों के अधिकारों को परिभाषित करते हैं।

2. **सामाजिक परिप्रेक्ष्य** : सामाजिक दृष्टिकोण से, कर्मचारियों के मानवाधिकार ऐसे अधिकार हैं जो उन्हें समाज में सम्मान और गरिमा के साथ कार्य करने की अनुमति देते हैं। इसमें समान अवसर, भेदभाव से सुरक्षा, और काम की परिस्थितियों में समता शामिल है। इस परिप्रेक्ष्य में, मानवाधिकार सामाजिक न्याय, समानता, और सहिष्णुता के मूल्यों पर आधारित होते हैं।
3. **नैतिक परिप्रेक्ष्य** : नैतिक परिप्रेक्ष्य में, कर्मचारियों के मानवाधिकार नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों पर आधारित होते हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार प्रदान करते हैं। इसमें नियोक्ताओं की नैतिक जिम्मेदारी शामिल होती है कि वे कर्मचारियों के साथ निष्पक्ष, सम्मानजनक और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें।
4. **आर्थिक परिप्रेक्ष्य** : आर्थिक दृष्टिकोण से, कर्मचारियों के मानवाधिकार वह अधिकार हैं जो उन्हें आर्थिक सुरक्षा, उचित मुआवजा, और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्रदान करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में, मानवाधिकारों का पालन करना आर्थिक उत्पादकता और संगठन की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।
5. **अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य** : अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से, कर्मचारियों के मानवाधिकार वैश्विक मानदंडों और सिद्धांतों के अनुसार परिभाषित होते हैं। संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार घोषणापत्र और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के मानक इस परिप्रेक्ष्य में कर्मचारियों के अधिकारों की परिभाषा के प्रमुख स्रोत हैं। इन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत, किसी भी देश या कंपनी को अपने कर्मचारियों के अधिकारों का सम्मान करना अनिवार्य होता है।
6. **सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य** : दृष्टिकोण से, कर्मचारियों के मानवाधिकारों की परिभाषा विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं, और मान्यताओं के आधार पर भिन्न हो सकती है। कुछ संस्कृतियों में, श्रम का विभाजन और काम की स्थिति धार्मिक या सामाजिक परंपराओं द्वारा नियंत्रित होती है, जो मानवाधिकारों की परिभाषा को प्रभावित कर सकती हैं।

कर्मचारियों के मानवाधिकारों की परिभाषा इन विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में भिन्न होती है, लेकिन सभी परिप्रेक्ष्य इस बात पर सहमत हैं कि हर कर्मचारी को एक

गरिमापूर्ण, सुरक्षित, और समान कार्य वातावरण मिलना चाहिए। मानवाधिकारों की यह विविधता विभिन्न सामाजिक, कानूनी, और सांस्कृतिक संदर्भों में कर्मचारियों की आवश्यकताओं और अधिकारों की व्यापकता को दर्शाती है।

कर्मचारियों के मानवाधिकार किसी भी सभ्य समाज की आधारशिला हैं। यह अधिकार उन्हें उनकी गरिमा, सुरक्षा और सम्मान के साथ काम करने का अधिकार देता है। कार्यस्थल पर मानवाधिकारों का सम्मान न केवल कर्मचारियों के व्यक्तिगत कल्याण को सुनिश्चित करता है, बल्कि यह कंपनी की प्रतिष्ठा और उत्पादकता को भी बढ़ाता है।[2]

1. कार्य की सुरक्षा और स्वास्थ्य किसी भी कर्मचारी के लिए यह आवश्यक है कि उसे एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण मिले। यह अधिकार अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार घोषणापत्र में भी समाहित है। यह नियोक्ता की जिम्मेदारी है कि वह कार्यस्थल पर सुरक्षित और अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करे, जो कर्मचारियों को किसी भी शारीरिक या मानसिक हानि से बचाए। इसमें उचित सुरक्षा उपकरण, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रावधान शामिल है।
2. भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा मानवाधिकारों का एक प्रमुख पहलू है भेदभाव से सुरक्षा। कार्यस्थल पर किसी भी कर्मचारी के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग, यौनिकता, विकलांगता या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि सभी कर्मचारियों को समान अवसर और समान व्यवहार मिले।
3. श्रमिक अधिकार और संघ बनाने की स्वतंत्रताकर्मचारियों को अपनी आवाज उठाने और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का अधिकार है। इसमें ट्रेड यूनियनों का गठन और उनमें शामिल होने का अधिकार शामिल है। श्रमिक अधिकार न केवल कर्मचारियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हैं, बल्कि उन्हें यह भी सुनिश्चित करने का अवसर देते हैं कि उनके साथ निष्पक्ष और सम्मानजनक व्यवहार किया जाए।
4. उचित वेतन और काम के घंटेमानवाधिकारों के तहत, प्रत्येक कर्मचारी को उसके कार्य के लिए उचित वेतन और मानवोचित कार्य के घंटे मिलने चाहिए। यह सुनिश्चित करना कि कर्मचारियों को उनकी मेहनत का उचित प्रतिफल मिले और उन्हें अनिवार्य आराम का समय दिया जाए, किसी भी सभ्य समाज की निशानी है।

5. यौन उत्पीड़न और हिंसा के खिलाफ सुरक्षाकार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न या किसी भी प्रकार की हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कर्मचारियों को इस प्रकार के आचरण से सुरक्षा प्रदान करना नियोक्ता की जिम्मेदारी है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि ऐसे मामलों की सुनवाई और निपटान के लिए एक उचित तंत्र हो।[3]

6. गोपनीयता का अधिकार कर्मचारियों की व्यक्तिगत जानकारी और गोपनीयता का सम्मान किया जाना चाहिए। नियोक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी कर्मचारी की व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग न हो और उसे गोपनीय रखा जाए।

भारतीय संविधान में कर्मचारियों के :

भारतीय संविधान के तहत कर्मचारियों के मानवाधिकारों को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। संविधान का उद्देश्य हर नागरिक को गरिमा, सुरक्षा, और समानता के साथ जीवन जीने का अधिकार प्रदान करना है, और इसमें कार्यस्थल पर कर्मचारियों के अधिकार भी शामिल हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कर्मचारियों के मानवाधिकार निम्नलिखित प्रमुख प्रावधानों के तहत आते हैं :

1. **मौलिक अधिकार** (**Fundamental Rights**) संविधान के भाग III में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जो कर्मचारियों के मानवाधिकारों की नींव रखते हैं :

   अनुच्छेद 14 : समानता का अधिकार (Right to Equality) : अनुच्छेद सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। यह कार्यस्थल पर भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

   अनुच्छेद 15 : भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा (Prohibition of Discrimination) : यह अनुच्छेद जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव को रोकता है। यह कर्मचारियों को समान अवसर प्रदान करने की नींव रखता है।

   अनुच्छेद 19(1)(ब) : संघ बनाने की स्वतंत्रता (Freedom to Form Associations) अनुच्छेद के तहत कर्मचारियों को संघ या ट्रेड यूनियन बनाने और उसमें शामिल होने का अधिकार दिया गया है। यह

श्रमिकों को अपने अधिकारों के लिए सामूहिक रूप से संघर्ष करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।

अनुच्छेद 21 : जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Life and Personal Liberty) अनुच्छेद प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है, जिसमें कार्यस्थल पर उचित और सुरक्षित परिस्थितियों में काम करने का अधिकार शामिल है।

2. **नीति निदेशक तत्व** (Directive Principles of State Policy) संविधान के भाग IV में नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, जो राज्य के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं :

अनुच्छेद 39 (a) : जीवन निर्वाह के साधनों का प्रावधान (Right to Adequate Means of Livelihood) यह अनुच्छेद राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करता है कि सभी नागरिकों को जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध हों।

अनुच्छेद 41 : काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार (Right to Work] Education] and Public Assistance) यह अनुच्छेद राज्य को नागरिकों को काम के अवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश देता है, विशेषकर बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता जैसी परिस्थितियों में।

अनुच्छेद 42 : काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियाँ (Just and Humane Conditions of Work) यह अनुच्छेद राज्य को काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियाँ सुनिश्चित करने और मातृत्व सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है।

भारतीय संविधान कर्मचारियों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए व्यापक प्रावधान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि हर कर्मचारी को गरिमापूर्ण जीवन, समानता, और सुरक्षित कार्य वातावरण मिल सके। मौलिक अधिकारों, नीति निदेशक तत्वों, और श्रम कानूनों के माध्यम से, भारतीय संविधान एक ऐसा ढांचा प्रदान करता है जो कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए आवश्यक है।[4]

3. **अनुसूचित जाति और जनजाति** (अत्याचार निवारण) अधिनियम - अधिनियम अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कर्मचारियों को उनके

अधिकारों के उल्लंघन से बचाने और उन्हें किसी भी प्रकार के अत्याचार से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है।

4. **श्रम कानूनों के तहत अधिकार** - संविधान के तहत विभिन्न श्रम कानून भी कर्मचारियों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं:

1. **न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (Minimum Wages Act] 1948)** अधिनियम कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी का अधिकार प्रदान करता है।[5]

2. **कामगारों का मुआवजा अधिनियम (Employees^ Compensation Act] 1923)** : यह अधिनियम कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं या चोटों के मामले में कर्मचारियों को मुआवजा दिलाने के लिए प्रावधान करता है।[6]

3. **व्यावसायिक संघ अधिनियम, 1926 (Trade Unions Act] 1926)** :

भारत में श्रमिकों और कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है। यह अधिनियम कर्मचारियों को अपने अधिकारों की रक्षा और संवर्धन के लिए संघ या यूनियन बनाने का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत कर्मचारियों के निम्नलिखित मानवाधिकार सुरक्षित किए जाते हैं:

1. संघ बनाने का अधिकार Right to Form Unions व्यावसायिक संघ अधिनियम, 1926 कर्मचारियों को यह अधिकार प्रदान करता है कि वे अपने हितों की रक्षा के लिए स्वेच्छा से यूनियन या संघ बना सकते हैं। यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ब) में भी समाहित है, जो सभी नागरिकों को संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह अधिकार कर्मचारियों को अपने कार्यस्थल पर बेहतर वेतन, सुरक्षित कार्य परिस्थितियाँ, और अन्य अधिकारों के लिए सामूहिक रूप से आवाज उठाने की क्षमता देता है।

2. पंजीकरण का अधिकार (Right to Register Unions) इस अधिनियम के तहत, कर्मचारियों को अपने संघ को पंजीकृत कराने का अधिकार है। पंजीकृत संघों को कानूनी मान्यता प्राप्त होती है, जो उन्हें श्रमिक विवादों में प्रतिनिधित्व करने और कानूनी रूप से अपने सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करने की क्षमता प्रदान करती है। पंजीकरण के लिए आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं को इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है।

3. संघ की गतिविधियों का संचालन (Right to Manage Union Activities) व्यावसायिक संघ अधिनियम, 1926 संघों को अपनी गतिविधियाँ संचालित करने का अधिकार देता है। इसमें सदस्यता शुल्क एकत्र करना, सदस्यों के कल्याण के लिए कार्यक्रम आयोजित करना, और नियोक्ताओं के साथ सामूहिक बातचीत (collective bargaining) करना शामिल है। यह अधिकार संघों को स्वतंत्र रूप से और बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के संचालित होने की अनुमति देता है।

4. संघ की संपत्ति का अधिकार (Right to Union Property) इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत संघों को संपत्ति प्राप्त करने और प्रबंधित करने का अधिकार है। यह संपत्ति संघ के संचालन, सदस्यों के कल्याण, और संघ की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए उपयोग की जाती है।

5. प्रतिरक्षा का अधिकार (Right to Immunity) व्यावसायिक संघ अधिनियम, 1926 के तहत पंजीकृत संघों और उनके सदस्यों को कुछ कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है। यह संघों और उनके नेताओं को हड़ताल या अन्य कानूनी गतिविधियों के लिए नियोक्ताओं द्वारा किए गए दावों और अदालती मामलों से सुरक्षा प्रदान करता है, जब तक कि ये गतिविधियाँ कानूनी रूप से संचालित हो रही हों।

6. संघ को विघटन से सुरक्षा (Protection from Dissolution) पंजीकृत संघों को उचित कानूनी कारण के बिना विघटन (dissolution) से सुरक्षा दी गई है। इसका अर्थ है कि नियोक्ता या अन्य कोई संघ को जबरन बंद नहीं कर सकता जब तक कि कानूनी प्रक्रिया का पालन न किया जाए।

7. सदस्यों के खिलाफ प्रतिशोध से सुरक्षा (Protection Against Retaliation) यह अधिनियम कर्मचारियों को उनके यूनियन में शामिल होने के कारण नियोक्ताओं द्वारा प्रतिशोध (retaliation) से सुरक्षा प्रदान करता है। नियोक्ता यूनियन गतिविधियों में भाग लेने के कारण किसी कर्मचारी को नौकरी से निकाल नहीं सकता या उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकता।[7]

4. विवाद अधिनियम, 1947 (Industrial Disputes Act. 1947) :

श्रमिकों और कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा और औद्योगिक विवादों के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है। इस अधिनियम का उद्देश्य

नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच विवादों को हल करना और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। इसके तहत कर्मचारियों के मानवाधिकार निम्नलिखित तरीके से संरक्षित किए जाते हैं:

1. न्यायपूर्ण निपटान का अधिकार (Right to Fair Settlement) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत, कर्मचारियों को अपने नियोक्ता के साथ विवादों का न्यायपूर्ण और त्वरित निपटान पाने का अधिकार है। यह अधिनियम विभिन्न प्रकार की विवाद निपटान प्रक्रियाएँ प्रदान करता है, जैसे कि बातचीत (negotiation) मध्यस्थता (conciliation), और न्यायाधिकरण (tribunal) में सुनवाई। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारियों के अधिकारों का उल्लंघन न हो और उनके विवादों का निष्पक्ष समाधान हो।

2. हड़ताल और तालाबंदी का अधिकार (Right to Strike and Lockout) यह अधिनियम श्रमिकों को हड़ताल करने का अधिकार प्रदान करता है, जो कि एक वैध और कानूनी माध्यम है, जिसके द्वारा कर्मचारी अपने अधिकारों और मांगों के लिए आवाज उठा सकते हैं। इसी प्रकार, नियोक्ता को भी तालाबंदी (lockout) करने का अधिकार है। हालांकि, यह अधिकार तभी मान्य है जब हड़ताल और तालाबंदी कानूनी प्रक्रियाओं और शर्तों के अनुसार हो। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि दोनों पक्षों के अधिकारों का सम्मान किया जाए और उनकी मांगों का उचित समाधान हो।

3. रिट्रेंचमेंट (छंटनी) और पुनर्नियुक्ति के अधिकार (Rights Related to Retrenchment and Re-Employment) अधिनियम के तहत, यदि कोई नियोक्ता किसी कर्मचारी को रिट्रेंचमेंट (छंटनी) के माध्यम से नौकरी से हटाता है, तो उसे अधिसूचना देना और मुआवजा देना अनिवार्य है। साथ ही, यदि भविष्य में नियोक्ता नई भर्ती करता है, तो रिट्रेंच किए गए कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह प्रावधान कर्मचारियों को अचानक बेरोजगारी से बचाने के लिए किया गया है और उनके रोजगार के अधिकारों की रक्षा करता है।

4. वेतन और सेवा शर्तों की सुरक्षा (Protection of Wages and Service Conditions) औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत, कर्मचारियों की सेवा शर्तों में कोई भी बदलाव नियोक्ता द्वारा बिना कर्मचारियों की सहमति के या संबंधित प्राधिकरण की अनुमति के बिना नहीं किया जा

सकता। यह कर्मचारियों के वेतन, काम के घंटे, छुट्टियों, और अन्य सेवा शर्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

5. अनुचित समाप्ति के खिलाफ सुरक्षा (Protection Against Unfair Dismissal) यह अधिनियम कर्मचारियों को अनुचित रूप से नौकरी से निकाले जाने के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। यदि कोई कर्मचारी यह महसूस करता है कि उसे बिना उचित कारण के या प्रक्रिया के उल्लंघन के कारण नौकरी से निकाला गया है, तो वह कानूनी कार्रवाई कर सकता है। यह प्रावधान कर्मचारियों को अपने रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और उन्हें नियोक्ता के अनुचित व्यवहार से बचाता है।
6. कर्मचारियों के अधिकारों के उपल्लंघन के मामलों में कानूनी सहायता (Legal Recourse in Case of Rights Violation) औद्योगिक विवाद अधिनियम कर्मचारियों को अपने अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में कानूनी सहायता और समाधान पाने का अधिकार देता है। इसके तहत, कर्मचारी श्रम न्यायालय (Labour Court) या औद्योगिक न्यायाधिकरण (Industrial Tribunal) के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों को न्याय तक पहुंच का अधिकार हो और उनके मुद्दों का निष्पक्ष समाधान हो सके।
7. कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए संरचनात्मक तंत्र (Institutional Mechanisms for Protection of Employee Interests) यह अधिनियम विभिन्न संरचनात्मक तंत्र प्रदान करता है, जैसे कि श्रम न्यायालय, औद्योगिक न्यायाधिकरण, और राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जो कि औद्योगिक विवादों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये संस्थाएँ यह सुनिश्चित करती हैं कि कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच विवादों का निपटारा निष्पक्ष और त्वरित तरीके से हो।[8]

5. कारखाना अधिनियम, 1948 (Factories Act] 1948)

कारखाना अधिनियम (Factories Act] 1948) यह अधिनियम कार्यस्थल पर कर्मचारियों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ परिस्थितियाँ सुनिश्चित करता है उद्योगों और कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को सुरक्षित और स्वस्थ कार्य परिस्थितियाँ प्रदान करना और उनके कल्याण को सुनिश्चित करना है। इस अधिनियम के तहत कर्मचारियों के मानवाधिकार निम्नलिखित प्रावधानों के माध्यम से संरक्षित किए गए हैं :[9]

1. सुरक्षित कार्य वातावरण का अधिकार (Right to a Safe Working Environment) कारखाना अधिनियम के तहत, हर कर्मचारी को एक सुरक्षित कार्य वातावरण का अधिकार प्राप्त है। अधिनियम में यह सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किए गए हैं कि कारखानों में मशीनों, उपकरणों, और प्रक्रियाओं से जुड़े खतरों को न्यूनतम किया जाए। इसके लिए मशीनों पर सुरक्षा गार्ड्स, आपातकालीन निकास, और सुरक्षा उपकरणों का उपयोग अनिवार्य किया गया है।

2. स्वास्थ्य सुविधाएँ (Health Provisions) अधिनियम के तहत कारखानों को अपने कर्मचारियों के लिए स्वच्छ और स्वस्थ परिस्थितियाँ प्रदान करनी होती हैं। इसमें शामिल हैं स्वच्छता (Cleanliness), कारखाने की सफाई, धूल और गंदगी से मुक्त रखने का प्रावधान। वेंटिलेशन और तापमान नियंत्रण (Ventilation and Temperature) कार्यस्थल पर उचित वेंटिलेशन और तापमान नियंत्रण। पेयजल (Drinking Water) : कर्मचारियों को शुद्ध और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना। शौचालय और यूरिनल्स (Latrines and Urinals) : कर्मचारियों के लिए स्वच्छ शौचालय और यूरिनल्स की व्यवस्था।

3. श्रम घंटे और आराम का अधिकार (Right to Work Hours and Rest) कारखाना अधिनियम में कर्मचारियों के कार्य घंटे और आराम के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं : कार्य घंटे (Working Hours) : एक दिन में अधिकतम 9 घंटे और एक सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे काम करने का प्रावधान है। अवकाश (Rest Periods) : लगातार 5 घंटे काम करने के बाद कर्मचारियों को आधे घंटे का विश्राम दिया जाना अनिवार्य है। साप्ताहिक अवकाश (Weekly Holidays) : प्रत्येक कर्मचारी को सप्ताह में एक दिन का अनिवार्य अवकाश दिया जाना चाहिए।

4. महिला और बाल श्रमिकों के अधिकार (Rights of Women and Child Workers) कारखाना अधिनियम विशेष रूप से महिला और बाल श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रावधान करता है: महिलाओं के लिए रात की पाली पर प्रतिबंध (Prohibition of Night Shifts for Women) महिलाओं को रात के समय (रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक) काम करने की अनुमति नहीं है, सिवाय सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त होने के। बाल श्रमिकों के लिए प्रतिबंध (Prohibition of Night Shifts for Women) : 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में

काम करने की अनुमति नहीं है। किशोर श्रमिकों के लिए सीमित कार्य घंटे (Restricted Work Hours for Adolescents) 14-18 वर्ष की आयु के किशोरों के लिए कार्य घंटे सीमित हैं और उन्हें दिन में केवल 4.5 घंटे काम करने की अनुमति है।

5. कल्याण सुविधाएँ (Welfare Provisions) कारखाना अधिनियम कर्मचारियों के कल्याण के लिए विभिन्न सुविधाओं का प्रावधान करता है : कैंटीन (Canteens) : 250 से अधिक श्रमिकों वाले कारखानों में कैंटीन की सुविधा अनिवार्य है। प्रथम सहायता (First Aid) : हर कारखाने में प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए। क्रेच (Creches) : 30 से अधिक महिला कर्मचारियों वाले कारखानों में 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्रेच की व्यवस्था होनी चाहिए।
6. काम के दौरान दुर्घटनाओं और बीमारियों से सुरक्षा (Protection from Accidents and Occupational Diseases) अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि कार्य के दौरान किसी भी दुर्घटना या बीमारी से कर्मचारियों को सुरक्षा मिले। इसके लिए नियोक्ता को सुरक्षा उपायों का पालन करना अनिवार्य है, जैसे कि सुरक्षा प्रशिक्षण, संरक्षित मशीनरी, और आपातकालीन योजनाएँ।
7. निरीक्षण और अनुपालन (Inspection and Compliance) कारखाना अधिनियम के तहत, राज्य सरकारें कारखानों का निरीक्षण करने के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति करती हैं। ये निरीक्षक यह सुनिश्चित करते हैं कि कारखानों में सभी कानूनी प्रावधानों का पालन हो रहा है और कर्मचारियों के अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

भारत में श्रम सुधारों को लागू करने के लिए 2019-2020 के बीच चार नई श्रम संहिताएँ (Labour Codes) पारित की गईं। ये संहिताएँ पुराने श्रम कानूनों को एकीकृत और सरलीकृत करती हैं।

इन चार संहिताओं के अंतर्गत कर्मचारियों के मानवाधिकारों को संरक्षित रखने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। ये चार संहिताएँ हैं:

1. मजदूरी संहिता, 2019 (Code on Wages) 2019)
2. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Industrial Relations Code, 2020)
3. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020)
4. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020

(Occupational Safety] Health and Working Conditions Code, 2020)

1. **मजदूरी संहिता,** 2019 **(Code on Wages, 2019) न्यूनतम मजदूरी का अधिकार (Right to Minimum Wages) :**

मजदूरी संहिता के तहत, प्रत्येक कर्मचारी को न्यूनतम मजदूरी का अधिकार दिया गया है, जो राज्य और केंद्र सरकार द्वारा तय की जाती है। इससे सभी श्रमिकों को एक निश्चित न्यूनतम आय सुनिश्चित होती है, जिससे उनकी जीवनशैली में सुधार हो सकता है।

समय पर वेतन का अधिकार (Right to Timely Payment of Wages) :

इस संहिता के अंतर्गत कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलने का अधिकार दिया गया है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कर्मचारियों को उनके परिश्रम के लिए वेतन समय पर मिले और वे आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करें।

समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार (Right to Equal Pay for Equal Work) :

इस संहिता में यह प्रावधान किया गया है कि समान कार्य के लिए महिला और पुरुष कर्मचारियों को समान वेतन मिलना चाहिए। इससे कार्यस्थल पर लिंग आधारित भेदभाव को कम करने में मदद मिलती है।[10]

2. **औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Industrial Relations Code, 2020) संघ बनाने का अधिकार (Right to Form Unions) :**

औद्योगिक संबंध संहिता कर्मचारियों को संघ बनाने और उसमें शामिल होने का अधिकार प्रदान करती है। यह उनके मानवाधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे वे अपने अधिकारों के लिए सामूहिक रूप से आवाज उठा सकते हैं।

सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार (Right to Collective Bargaining) : इस संहिता के तहत कर्मचारियों को सामूहिक सौदेबाजी करने का अधिकार दिया गया है। यह कर्मचारियों को अपनी वेतन, कार्य शर्तों और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करने में सक्षम बनाता है।

औद्योगिक विवादों के न्यायपूर्ण समाधान का अधिकार (Right to Fair Resolution of Industrial Disputes) : यह संहिता कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थता, सुलह, और

न्यायाधिकरण जैसी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करती है, जिससे विवादों का न्यायपूर्ण और त्वरित निपटारा हो सके।[11]

3. **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020) सामाजिक सुरक्षा का अधिकार (Right to Social Security) :**

इस संहिता के तहत सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इसमें भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, और बीमा जैसी सुविधाएँ शामिल हैं, जिससे श्रमिकों का भविष्य सुरक्षित हो सके।

अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों का अधिकार (Rights of Informal Sector Worke) : सामाजिक सुरक्षा संहिता में अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों (जैसे गिगवर्कर, प्लेटफार्मवर्कर) के लिए भी सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इससे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा होती है।[12]

4. **व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 (Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020)**

सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण का अधिकार (Right to a Safe and Healthy Working Environment) : इस संहिता के तहत, प्रत्येक कर्मचारी को सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण का अधिकार दिया गया है। यह नियोक्ताओं पर यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी डालता है कि कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों का पालन हो।

काम के घंटों और आराम का अधिकार (Right to Regulated Work Hours and Rest) :

इस संहिता के अंतर्गत कार्य के घंटे, ओवरटाइम, और विश्राम के समय की विस्तृत व्यवस्थाएँ की गई हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कर्मचारियों को काम करने के दौरान उचित विश्राम मिले और उनकी कार्य क्षमता में सुधार हो।

विशेष श्रेणियों के कर्मचारियों के अधिकार : (Rights of Special Categories of Employees)

महिला कर्मचारियों के लिए रात की पाली और मातृत्व लाभ, विकलांग कर्मचारियों के लिए विशेष सुविधाएँ, और अनुबंधित श्रमिकों के लिए सुरक्षित कार्य परिस्थितियों का प्रावधान इस संहिता में किया गया है।[13]

नई श्रम संहिताएँ कर्मचारियों के मानवाधिकारों की व्यापक सुरक्षा करती हैं। ये संहिताएँ न केवल श्रमिकों को सुरक्षित, स्वस्थ और न्यायपूर्ण कार्य परिस्थितियाँ प्रदान करती हैं, बल्कि उनके आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की भी रक्षा करती हैं। इन संहिताओं के माध्यम से, भारत में श्रमिकों को एक बेहतर, सुरक्षित, और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं।

निष्कर्ष :

कर्मचारियों के मानवाधिकारों की सुरक्षा न केवल कानूनी दायित्व है, बल्कि यह कार्यस्थल पर नैतिकता और उत्पादकता को भी बढ़ाता है। नियोक्ताओं को कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सख्त नीतियाँ अपनानी चाहिए, और सरकार को कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता है। इस प्रकार, कर्मचारियों के मानवाधिकारों का संरक्षण एक न्यायसंगत और समावेशी कार्यस्थल की नींव रखता है, जिससे समाज में समग्र विकास संभव होता है।

संदर्भ :

1. UpendraBaÛi, The Future of Human Rights 42 (3rd ed-, Oxford University Press, 2006)
2. S. P. Sathe, "Judicial Activism in India, (1995) 6 Indian Journal of Constitutional Law 34.
3. Vishaka v. State of Rajasthan, AIR 1997 SC 3011.
4. V. N. Shukla, Constitution of India 89 (14th ed., Eastern Book Company, 2017).
5. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
6. Employees' Compensation Act, 1923.
7. Trade Unions Act, 1926.
8. Industrial Disputes Act, 1947.
9. Factories Act, 1948, p 11-12, 51-56.
10. Code on Wages, 2019, p 3.
11. Industrial Relation Code, 2020.
12. Code on Social Security, 2020, p 6.
13. Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020, p 8-10.

डॉ. रितु चौधरी

Assistant Professor
Government Law P.G. College, Bikaner.

❑❑❑

बालकों में अपराधों का बदलता स्वरूप एवं इनका समाधान

नीलम श्रीवास्तव • डॉ. नीलिमा कुँवर

आपराध एक सार्वभौमिक सामाजिक समस्या और घटना है, विभिन्न युगों में विभिन्न प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक नैतिक समस्या उत्पन्न होती है। यह समस्याएँ व्यक्ति और समाज दोनो से सम्बन्धित हैं। अपराध निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसका स्वरूप समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। अपराध बालक में निहित जन्म जात या अर्जित प्रवृत्तियों के आधार पर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक व समाजिक आदि कारकों के द्वारा किया जाता है।

वर्तमान समय में बाल अपराध की समस्या उन प्रमुख समस्याओं में से एक है जिसे आपराधिक व्यवहार के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्व दिया जा रहा है। यह एक ऐसी समस्या है जो मूल रूप से परिवार और समुदाय के विघटन का परिणाम है। दुनिया के लगभग सभी देशों में अपराधियों की संख्या में लगातार वृद्धि चिन्ता का विषय है, क्योंकि जिन बच्चों पर राष्ट्र का भविष्य निर्भर करता है, अगर वे असामान्य बच्चे बन जाते है तो देश का भविष्य बिगड सकता है। भारत में बाल अपराध को किशोर अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात एक निर्दिष्ट आयु से कम उम्र के बच्चों की धारा को अपराधी के रूप में वगीकृत किया जाता है।

प्रस्तावना

बाल अपराध एक विश्वव्यापी समस्या है, जिसे प्रत्येक राष्ट्र और समाज में किसी न किसी रूप में देखा जा सकता है। यह सत्य है कि प्रत्येक देश एवं काल की परिस्थितियां भिन्न होती है, इस कारण बाल अपराध समस्या की

प्रकृतिक में भी भिन्नता पाई जाती है। भारत वर्ष में बाल अपराध के सन्दर्भ में जो भी आकड़े प्राप्त हुए हैं। उनके आधार पर कहा जा सकता है कि यह समस्या दिन-प्रतिदिन उग्र रूप धारण करती जा रही है। भारत वर्ष की तुलना में पाश्चात्य देशों में तो यह समस्या और भी गम्भीर बन चुकी है। इस प्रकार यह कहना अतिश्योक्तिपूर्ण न होगा कि हाइड्रोजन बम एवं साइबर अपराध की भांति बाल अपराध भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जन्मी एक विस्फोटक समस्या है, जिसका दिन प्रतिदिन विश्वव्यापी स्तर पर विस्तार होता जा रहा है। यही कारण है कि वर्तमान समय में इस समस्या को विशेष महत्व दिया जा रहा है। जब एक बच्चे द्वारा कोई कानून विरोधी या असमाजिक कार्य किया जाता है, तो इसे बाल अपराध कहा जाता है। कानूनी दृष्टिकोण से बाल अपराध 8 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे द्वारा किया गया एक कानून विरोधी कार्य है, जिसे कानूनी कार्यवाही के लिए बाल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। भारत में बाल न्याय अधिनियम अनुच्छेद 1966 (संशोधित 2000) के अनुसार 16 वर्ष तक के लड़के और 18 वर्ष की लड़कियों को अपराध करने पर बाल अपराधियों के श्रेणी में शामिल किया जाता है।

बाल अपराध के अधिकतम आयु सीमा एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होती है। इस आधार पर 'राज्य' द्वारा निर्धारित आयु सीमा के भीतर एक बच्चे द्वारा किया गया एक कानून विरोधी कार्य बाल अपराध है।

बर्ट के अनुसार–''उस बालक को अपराधी कहते हैं, जिसकी समाज विरोधी प्रवृत्तियां कितनी गम्भीर हो जाती है कि उसके प्रति सरकारी कार्यवाही अवश्यक हो जाती है।''

एम.जी. मेथना के अनुसार–''बाल अपराध के अन्तर्गत किसी बालक या ऐसे तरूण व्यक्ति के कार्य आते है जो कि सम्बन्धित स्थान के कानून के द्वारा निर्दिष्ट आयु सीमा के अन्दर आता है।''

न्यूमेयर के अनुसार–''एक बाल अपराधी निर्धारित आयु से कम आयु का वह व्यक्ति है जो समाज विरोधी कार्य करने का दोषी है और जिसका दुराचारण कानून का उल्लंघन है।''

उद्देश्य :

भारतीय समाज में गम्भीर समस्या बाल अपराध से सम्बन्धित है। भारत में बाल अपराध एवं निर्वारण हेतु सुझावों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है।

1. बाल अपराधियों के परिवार के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
2. बाल अपराधियों के सुधार गृह में की जा रही सुविधाएं, सुधार गृह की कार्यप्राणाली एवं कार्य पद्वति का अध्ययन करना।

बाल अपराध से सम्बन्धित सिद्धान्त :

1. मर्टन का ''व्याधिकी सिद्धान्त''।
2. फ्रेड्रिक थ्रेशर का ''गिरोह सिद्वान्त''।
3. शॉ और मैके का ''सांस्कृतिक प्रयास सिद्धान्त''।
4. जार्ज हरबर्ट मीड का ''भूमिका सिद्धान्त एवं स्व का सिद्धान्त''।
5. वाल्टर मिलर का ''निम्न वर्ग का लड़का और निम्न वर्ग की संरचना का सिद्धान्त''।
6. डेविड माट्जा का ''अपराध और ड्राफ्ट सिद्धान्त''।

अध्ययन पद्धति :

अध्ययन के लिए उत्तर प्रदेश के दो जिलों लखनऊ एवं मेरठ का चयन किया गया है। लखनऊ एवं मेरठ में स्थित दो बाल सुधार गृहों में से 100-100 बाल अपचारियों को चुना गया है। इस प्रकार कुल 200 बाल अपचारियों पर अध्ययन किया गया है। अध्ययन पद्धति में सांख्यिकीय उपकरण मध्यमान एवं प्रामाणिक विचलन का इस्तेमाल किया गया है।

परिणाम

सारिणी : 1 बाल अपचारियों की आयु का अध्ययन

संख्या=200

आयु (वर्ष)	संप्रेक्षण गृह		योग	
	लखनऊ	मेरठ	आवृत्ति	प्रतिशत
7-10	14	9	23	11.5
10-13	22	38	60	30.00
13-16	64	53	117	58..5
कुल	100	100	200	100

यह वह आयु है जब बालक को नई-नई जानकारियाँ प्राप्त करने हेतु जिज्ञासा बनी रहती है परन्तु उन कार्यों के परिणामों से वह सर्वधा अनभिज्ञ रहता है और इसलिए वह ऐसे कार्य कर बैठता है जिसकी परिणीति अपचारों में हो जाती है। यहाँ बाल अपचारियों के सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के लिए उनकी आयु, जाति, धर्म, शैक्षणिक स्थिति, मासिक आय, परिवार में माता-पिता का व्यवसाय, लिंग, वर्ग आदि का विष्लेशण सरल एवं सह-संबंधात्मक सारणियों के माध्यम से किया गया है। यह ऐसी अवस्था होती है जब बालक स्वतंत्रता चाहता है किसी के नियंत्रण में नहीं रहना चाहता, जब बालक अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाता तब वह आक्रामक हो जाता है और धीरे-धीरे वह अपराध की ओर अभिमुख हो जाता है।

सारिणी-2

बाल अपचारियों द्वारा वास्तव में किए गए अपचार की स्थिति का अध्ययन

संख्या=200

अपचार की स्थिति	संप्रेक्षण गृह		योग	
	लखनऊ	मेरठ	आवृत्ति	प्रतिशत
अपचार किया	73	69	142	71.00
अपचार नहीं किया	27	31	58	29.00
कुल	100	100	200	100

कई बार पारिवारिक विवादों के चलते या दोस्तों के द्वारा किए गए अपचारों के चक्कर में सुधार संस्था में आये बालकों का प्रतिशत भी होता है। ऐसे बालक जिन्होने वास्तव में कोई अपचार नहीं किया वे भी संस्था में रह रहे होते हैं।

सारिणी-3

बाल अपचारियों द्वारा किए जाने वाले अपचार करने के तरीके के आधार का अध्ययन

संख्या=200

अपचार की स्थिति	संप्रेक्षण गृह		योग	
	लखनऊ	मेरठ	आवृत्ति	प्रतिशत
पूर्व नियोजित	62	16	78	39.00
परिस्थितिवश	38	84	122	61.00
कुल	100	100	200	100

प्रस्तुत अध्ययन में 39 प्रतिशत (लखनऊ में 62 तथा मेरठ में 16) ऐसे बच्चे हैं जिन्होने पूर्व नियोजित अपचार किया है। योजना बनाकर किए गए अपचारों में चोरी डकैती एवं हत्या प्रमुख अपचार थे। 61.0 प्रतिशत अपचार बालकों से अचानक या परिस्थितिवश हो गए (लखनऊ में 38 एवं मेरठ में 84) वे अपचार करने हेतु पहले से तैयार नहीं थे।

सारिणी-4

बाल अपचारियों की सुधार गृह में शिक्षा की स्थिति का अध्ययन

संख्या=200

शिक्षा की स्थिति	संप्रेक्षण गृह		योग	
	लखनऊ	मेरठ	आवृत्ति	प्रतिशत
जारी है	42	25	67	33.5
पहले से नहीं पढ़ रहे	45	60	105	52.5
आने के बाद छोड़ी	13	15	28	7.00
कुल	100	100	200	100

अध्ययन में महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया कि मेरठ में लखनऊ की अपेक्षा बच्चों में साक्षरता प्रतिशत कम है।

सारिणी-5

सुधार गृह में बाल अपचारियों की बाल मनोचिकित्सकों द्वारा कांउसिलिग की व्यवस्था का अध्ययन

संख्या=200

कांउसलिंग की व्यवस्था	संप्रेक्षण गृह		योग	
	लखनऊ	मेरठ	आवृत्ति	प्रतिशत
जारी है	100	0	100	33.5
पहले से नहीं पढ़ रहे	0	100	100	52.5
कुल	100	100	200	100

काउंसिलिंग हेतु लखनऊ की संस्था के अधिकारी समाज-सेवियों की मदद से बच्चों के लिए मनोचिकित्सक की व्यवस्था करवाते हैं। संप्रेक्षण गृह लखनऊ में एक समाज-सेवी संस्था है जिसमें मनोचिकित्सक भी हैं जो स्वेच्छा से नि:शुल्क बच्चों की काउंसिलिंग करती है जबकि संप्रेक्षण गृह मेरठ में इस तरह की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। अनेक विद्वानों का मत है कि बालक के अपचार सम्बन्धी कारणों को जानने के पहले बालकों की मानसिक स्थिति को समझना आवश्यक होता है और इस कार्य को केवल एक कुशल बाल मनो-विश्लेषक ही कर सकता है।

बाल अपराधियों के सुधार हेतु सरकार द्वारा किये गये प्रयास:-

1. प्रेक्षण या अवलोकन गृह
2. मान्यता प्राप्त या सुधारक स्कूल
3. बोर्स्टल स्कूल
4. बाल निर्देशन केन्द्र

सुझाव

1. सर्वप्रथम गम्भीर अपचारों को करने वाले अपचारियों को सामान्य अपचारों में दोषी पाये गये बालकों से अलग रखा जाना चाहिए ताकि सामान्य अपचारी गम्भीर अपचारी न बन सकें।
2. बाल सम्प्रेक्षण गृहों में बाल मनोचिकित्सक की नियुक्ति की जानी चाहिए।
3. बाल सम्प्रेक्षण गृहों के अधिकारियों को अधिक से अधिक समाज सेवियों

तथा एन.जी.ओ. संस्थाओं से सम्पर्क करना चाहिए जिससे वे ऐसे अनाथ बच्चों की मदद कर सकें । जिनके माता-पिता या संरक्षक नहीं है।

निष्कर्ष

आज के समय में बढ़ती हुई जनसंख्या, गरीबी और बेरोजगारी ने बालकों को भी बाल अपराध की तरफ धकेला है जिसकी वजह से बालकों में बाल अपराध बढ़ते जा रहे हैं और बालक बाल अपचारी बनते जा रहे हैं। बालकों में बढ़ते अपराधो से भारत की आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो रही है। इसलिए बाल अपराध को रोकने हेतु माता-पिता, शिक्षक और सरकार को ऐसे उपाय खोजने होगें जिससे बालक केवल अपनी शिक्षा पर ध्यान दें तथा अपराधों की तरफ ना बढ़े। यह अध्ययन बाल अपराधों को रोकने में सहयोग करेगा। माता-पिता या संरक्षक नहीं हैं।

मुख्य शब्द–अपचार-अपराध (बुरे कृत्य)

संदर्भ

1. Becker, Howard S. 1966, Social Problems: A Modern Approach, New York, PP.226-228.
2. Bonger, W.A. 1916. Criminatity and Econome Conditions
3. Hirsch, Nathanieal. 1937. Dynamic Causes of Juvenile Crime. Cambridge.
4. Jenkins (2012). Motivation and frustration in delinquency, Journal of Orthopsychiatry.
5. Jones, LA.E., Juvenile Delinquency and the Law, P.29.
6. Ruttonshan, G.N., Juevnile Delinquency and Destitution in Poona. P.47.
7. Seth, Hansa (2015). Juvenile delinquency in Indian setting, Bombay : Popular Book Depot, pp. 132-133.
8. Sharma, N.K. (2017). Shodh Ganga.inflibnet.ac.in.
9. Sheth, Hansa, Juvenile Delinquency, PP.132-133.
10. Trojanowicz, Robert C. 1973. Juvenile Delinquency Concepts and Controt, P.59.

नीलम श्रीवास्तव
शोध छात्रा
गृह विज्ञान महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी
विश्वविद्यालय, **लखनऊ**

डॉ. नीलिमा कुँवर
शोध निदेशिका
प्राध्यापक
चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं
प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, **कानपुर**

❑❑❑

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बी. एड. छात्राध्यापकों के लिए आवश्यक मृदु कौशल (Soft Skills) : एक समीक्षात्मक अध्ययन

• दीपक कुमार

वर्तमान समय में बदलती परिस्थितियों तथा विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता ह्रास को देखते हुए सेवा-पूर्व अध्यापक शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करना आवश्यक हो जाता है कि सेवा-पूर्व अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के दौरान छात्राध्यापकों को कठोर कौशल (शिक्षण कौशल) के साथ-साथ किस प्रकार के मृदु कौशलों (soft skills) का भी प्रशिक्षण दिया जाए जिसका उपयोग वे अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए कर सके और विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हो सके। प्रस्तुत समीक्षात्मक शोध पत्र में 21 वीं सदी के आवश्यक मृदु कौशलों जैसे— सृजनात्मकता, सम्प्रेषण, आलोचनात्मक चिंतन, समस्या समाधान, सहयोग एवं अन्य मृदु कौशलों की व्याख्या की गयी है तथा मृदु कौशलों के विकास की भी चर्चा की गयी है कि इन कौशलों का विकास किस प्रकार किया जा सकता है? इनके विकास के लिए अनेक प्रतिमान (model) की विवेचना की गयी है जिसमें मुख्य रूप से एकल विषय प्रतिमान (Stand-alone subject model) तथा अंतःस्थापित प्रतिमान (Embedded Model) के विषय में बताया गया है। एकल विषय प्रतिमान में छात्राध्यापकों को मृदु कौशल के विकास के लिए अलग से एक विषय लेने की आवश्यकता होती है जबकि अंतःस्थापित प्रतिमान में मृदु कौशलों को अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में ही शामिल करके छात्राध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वर्तमान सन्दर्भ में सेवा-पूर्व अध्यापकों को अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए किस प्रकार के मृदु कौशलों की आवश्यकता है? और उनका विकास किस प्रकार किया जा सकता है? की चर्चा की गयी है।

***मुख्य बिंदु** : अध्यापक शिक्षा, शिक्षण कौशल, 21 वीं सदी में आवश्यक मृदु कौशल (Soft Skills), मृदु कौशल का विकास।*

प्रस्तावना

शिक्षा एक ऐसा प्रभावी माध्यम है, जिसे समाज के बच्चों को जिम्मेदार सदस्य के रूप में विकसित करने के लिए जाना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षण की आवश्यकता होती है। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक लोगों के बीच वाद-विवाद व अंतर-क्रिया होती है। शिक्षण ने लोगों की प्रगति को आगे बढ़ाया है। शिक्षण के द्वारा किसी शैक्षिक संस्थान में विद्यार्थियों को अनुदेश देने का कार्य किया जाता है (गुड, 1945)। अतः स्पष्ट है कि शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थियों को निर्देश देने का कार्य किया जाता है और इस कार्य को करने के लिए योग्य अध्यापकों की आवश्यकता होती है। शिक्षण के द्वारा अध्यापक अपने विद्यार्थियों को अज्ञानता के अन्धकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। शिक्षक अपनी दूरदर्शिता से किसी भी प्रणाली का सुधार कर सकता है। सर्व विदित है कि शिक्षार्थियों की गुणवत्ता और उनकी उपलब्धि की सीमा अध्यापकों की गुणवत्ता पर निर्भर होती है। शिक्षा प्रदान करने के लिए योग्य अध्यापक की आवश्यकता होती है इसलिए समाज में अध्यापक का स्थान महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसा कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (1998) के द्वारा माध्यमिक अध्यापक शिक्षा में गुणवत्ता संबंधी मुद्दों में कहा गया है कि शिक्षक किसी भी शैक्षणिक कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, शिक्षा प्रक्रिया को किसी भी स्तर पर लागू करने के लिए मुख्यतया अध्यापक हैं। **डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन** के अनुसार समाज में अध्यापक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की बौद्धिक परम्पराओं व तकनीकी कौशलों के हस्तांतरण के साधन के रूप में तथा सभ्यता की ज्योति को प्रज्वलित रखने में सहायता प्रदान करता है। शिक्षण की प्रक्रिया निश्चित रूप से अध्यापक शिक्षा से होकर गुजरती है। अध्यापक शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा भावी अध्यापकों को शिक्षण के आवश्यक कौशलों एवं तकनीकों से अवगत कराया जाता है, जिससे उनके अन्दर दक्षता व क्षमता का विकास होता है जिसका उपयोग वे शिक्षण क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों व समस्याओं का समाधान करने के लिए करते हैं। अध्यापक शिक्षा वह शैक्षिक आयोजन है जिसमें विभिन्न स्तरीय और वर्गीय अध्यापकों को इस प्रकार से शिक्षित किया जाता है कि आने वाली संतति को ज्ञान और मूल्यों के हस्तांतरण के साथ ही उनके समस्त शैक्षिक और विकासात्मक दायित्वों को ग्रहण एवं वहन करने में सक्षम हो सकें और उनमें तकनीकी कुशलता, वैज्ञानिक चेतना, संसाधन सम्पन्नता और नवचारिता के साथ सांस्कृतिक उद्दीपन तथा मानवता बोध का

समन्वयात्मक विकास करना संभव हो सके (दुबे, 2014, पृष्ठ 8)। अध्यापक शिक्षा शिक्षण कौशल, शैक्षणिक सिद्धांतों व वृत्तिक कौशलों का समुच्चय होता है। इसमें छात्राध्यापकों को विभिन्न वृत्तिक कौशलों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिसका उपयोग वे विद्यालयी शिक्षा में अपने शिक्षण के दौरान करते हैं। अध्यापक बच्चों के अन्दर अनेक सद्गुणों एवं कौशलों का विकास करता है इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि अध्यापकों को अनेक कौशलों से युक्त होना चाहिए और यह तभी संभव हो सकता है जब उन्हें सेवा-पूर्व अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से उचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाये और उनके अंदर अनेक प्रकार के आवश्यक कौशलों का विकास किया जाये।

वर्तमान समय में बदलते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए सेवा-पूर्व अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए 21वीं सदी के आवश्यक कौशलों की पहचान करना जरूरी हो जाता है कि जहाँ समाज में प्रतिदिन नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं और शिक्षकों को नित नई समस्याओं व चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है वहाँ शिक्षकों को किस प्रकार के कौशलों की आवश्यकता है? जिसका उपयोग करके वे बच्चों को सरलता से सीखने के लिए प्रेरित कर सकें और विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हो सके।

शिक्षण कौशल

किसी कार्य को सरल व बेहतर तरीके से करने की क्षमता कौशल कहलाती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वह युक्ति जिससे शिक्षण प्रक्रिया को सरल व सहज बनाया जा सके शिक्षण कौशल कहलाता है। अर्थात शिक्षण कौशल शिक्षण कार्य करने की वह रणनीति है जिसके द्वारा विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सीखने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। शिक्षण कौशल के माध्यम से ही एक अध्यापक कक्षा में विद्यार्थियों को सीखने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवहार करता है। एक शिक्षण कौशल समान व्यवहारों का एक समूह है, विभिन्न शिक्षण कौशल मिलकर शिक्षण प्रक्रिया का निर्माण करते हैं (दुबे, 2014)।

छात्राध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए आवश्यक कौशलों का चुनाव करना काफी चुनौती पूर्ण कार्य होता है। कौशलों का चुनाव करते समय यह ध्यान देना अति आवश्यक है कि वे कौन से शिक्षण कौशल हैं जिनसे प्रभावशाली शिक्षण हो सकता है ? वर्तमान समय में भावी अध्यापकों के लिए कठोर कौशल (Hard Skills) के साथ-साथ मृदु कौशलों (Soft Skills) के प्रशिक्षण की अत्यंत आवश्यकता है। संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण से प्राप्त तथा वर्तमान भारतीय सन्दर्भ को देखते हुए 21वीं सदी के कुछ मृदु कौशलों का विवेचन निम्न किया जा रहा है-

सृजनात्मकता : सृजनात्मकता 21 वीं सदी के महत्वपूर्ण कौशलों में से एक है। इसका सम्बन्ध मौलिकता व नवीनता से होता है। जब व्यक्ति या बालक किसी समस्या पर नये ढंग से सोचकर उस समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करता है तो सृजनात्मकता परिलक्षित होती है। इसमें शिक्षण व अधिगम के लिए नवान्वेषी दृष्टिकोण विकसित करने की क्षमता होती है। एक शिक्षक के अन्दर यह गुण होना चाहिए कि वह विद्यार्थियों को सृजनात्मक तरीके से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। इसलिए भावी अध्यापकों को सृजनात्मक कौशल का प्रशिक्षण देना चाहिए, जिससे वे अपने शिक्षण को सृजनात्मक बना सके (गुप्ता, 2017)।

सम्प्रेषण कौशल : सम्प्रेषण एक ऐसा कौशल है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों तथा भावों का आदान-प्रदान करता है। इसमें विचारों तथा भावों के आदान-प्रदान के लिए शाब्दिक तथा अशाब्दिक दोनों प्रकार के संकेतों का प्रयोग किया जाता है। सम्प्रेषण की प्रक्रिया एक पक्षीय न होकर द्वि-पक्षीय या बहु-पक्षीय होती है तथा एक-दूसरे के विचारों तथा भावों के प्रभावपूर्ण आदान-प्रदान में प्रेषक तथा प्राप्तकर्ता दोनों की समान भूमिका होती है (मंगल, 2016)। वर्तमान समय में भावी अध्यापकों में सम्प्रेषण कौशल के विकास की अत्यंत आवश्यकता है, इस कौशल के विकसित होने पर एक शिक्षक द्वारा अपने विचारों को स्पष्ट तथा प्रभावी ढंग से विद्यार्थियों तक प्रेषित किया जा सकता है तथा उनके अन्दर आत्मविश्वास के साथ अपने विषय को प्रस्तुत करने की क्षमता का विकास होता है (पचौरी एवं अन्य, 2014)।

आलोचनात्मक चिंतन एवं समस्या समाधान कौशल को कठिन परिस्थितियों में समस्याओं की पहचान करने और उनका विश्लेषण करने तथा उचित मूल्यांकन करने की क्षमता के रूप में जाना जाता है। तथ्यों का वस्तुपरक विश्लेषण करते हुए कोई निर्णय लेना आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। इसका उद्देश्य किसी भी स्थिति में सर्वोत्तम संभावित परिणामों को प्राप्त करना होता है। आलोचनात्मक चिन्तन के द्वार व्यक्ति सही व गलत का निर्णय कर पता है। इसके द्वारा व्यक्ति में विचारों व वैकल्पिक समाधानों को तलाश करने की क्षमता विकसित होती है। इसलिए अध्यापक शिक्षा में आलोचनात्मक चिंतन एवं समस्या समाधान कौशल को शामिल करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है (उर्बानी, 2017)।

सहयोग कौशल के द्वारा अध्यापक, विद्यार्थियों को सहयोगात्मक रूप से सीखने के लिए प्रेरित करता है। यह एक ऐसा कौशल है जिससे विद्यार्थियों में मिल-जुल कर किसी समस्या का समाधान करने की प्रेरणा विकसित होती है और विद्यार्थी उस समस्या को आसानी से हल कर पाते हैं। इसलिए 21 वीं सदी के अध्यापकों

में सहयोग कौशल की क्षमता विकसित करनी चाहिए जिससे अध्यापक अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकें और शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हो सके। सहयोग कौशल से युक्त अध्यापक द्वारा इस प्रकार से शिक्षण किया जा सकता है कि विद्यार्थी अपने ज्ञान व जानकारी को अपने सहपाठियों के साथ आसानी से साझा करते हैं और एक दूसरे के सहयोग से कार्य करते हुए सर्वोत्तम परिणाम प्रदान करते हैं (उर्बानी, 2017)।

नवाचार कौशल कौशल से तात्पर्य उस कौशल से है जिसके द्वारा शिक्षक बच्चों को नवीन खोजों के लिए प्रेरित करता है और विद्यार्थियों के अन्दर एक अन्वेषी मस्तिष्क का निर्माण करता है। बदलती परिस्थितियों को देखते हुए नवाचार कौशल की अत्यंत आवश्यकता महसूस होती है कि भावी शिक्षकों को नवाचार कौशल से युक्त होना चाहिए जिससे वे विद्यार्थियों में अन्वेषणात्मक प्रवृत्ति का विकास कर सकें(गोक्सुन एवं कुर्ट, 2017)।

सूचना साधन एवं प्रौद्योगिकी कौशल, बदलती परिस्थिति में एक ऐसा कौशल है जिसके द्वारा ज्ञान व सूचनाओं को आसानी से एकत्रित, भंडारित व संप्रेषित किया जा सकता है। इसके द्वारा सूचनाओं की खोज करने में सुगमता होती है। वर्तमान समय में प्रौद्योगिकी एक साधन बन गयी है जिसके द्वारा कक्षा वातावरण में 21वीं सदी के अनेक कौशलों को एकीकृत किया जा सकता है। अतः 21वीं सदी में सेवा-पूर्व अध्यापकों के शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए उनके अन्दर सूचना साधन एवं प्रौद्योगिकी कौशल की क्षमता विकसित करना अति आवश्यक है (उर्बानी, 2017)।

मृदु कौशल (Soft Skills) का विकास : एक समग्र दृष्टिकोण का उपयोग करके अध्यापक शिक्षा के छात्राध्यापकों में मृदु कौशल की क्षमता का विकास किया जा सकता है। सामान्यतः औपचारिक प्रशिक्षण व अधिगम गतिविधियों के माध्यम से अध्यापक शिक्षा के छात्राध्यापकों में मृदु कौशल के विकास के लिए दो प्रतिमान (model) शामिल होते हैं—

(1) **एकल विषय प्रतिमान (Stand–lone subject model)** —यह प्रतिमान विशेष पाठ्यक्रमों (जिसे मृदु कौशल के विकास के लिए नियोजित किया गया हो) के माध्यम से मृदु कौशल विकसित करने के लिए छात्रों को प्रशिक्षण और अवसर प्रदान करने के दृष्टिकोण का उपयोग करता है। इसके अंतर्गत छात्राध्यापकों में मृदु कौशल की क्षमता के विकास के लिए एक अलग विषय का निर्माण किया जाता है। जिसके द्वारा छात्राध्यापकों के अन्दर मृदु कौशल की क्षमता का विकास किया जाता है। इस प्रतिमान में छात्राध्यापकों को

अनेक अतिरिक्त पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रकार एकल विषय के माध्यम से छात्राध्यापकों में मृदु कौशल का विकास किया जा सकता है (न्गांगा, एवं अन्य, 2014)।

(2) **अंतःस्थापित प्रारूप (Embedded Model)** इस प्रतिमान में इस दृष्टिकोण का उपयोग किया गया है कि मृदु कौशल को पूरे पाठ्यक्रम व शिक्षण अधिगम गतिविधियों में शामिल करके प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। इसमें छात्राध्यापकों को कौशल विकास के लिए अलग से विशेष पाठ्यक्रम में दाखिला लेने की आवश्यकता नहीं होती है बल्कि छात्राध्यापकों को औपचारिक शिक्षण अधिगम गतिविधियों के माध्यम से मृदु कौशल में महारत हासिल करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इस प्रारूप में छात्राध्यापक अपने पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के दौरान मृदु कौशल का विकास करते हैं (न्गांगा एवं अन्य, 2014)।

इसके अतिरिक्त और अनेक माध्यमों का सहारा लेकर भी छात्राध्यापकों में मृदु कौशल का विकास किया जा सकता है। जैसे—अनेक पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा छात्राध्यापकों में मृदु कौशल का विकास किया जा सकता है। इस प्रकार की गतिविधियाँ गैर-शैक्षिक होती हैं परन्तु छात्राध्यापकों को उनके मृदु कौशल के विकास में परोक्ष रूप से सहायता करती हैं। इसके द्वारा छात्राध्यापकों को अपनी रुचियों को तलाशने में सहायत मिलती है तथा संकाय स्तर पर अनेक कार्यक्रमों जैसे—सेमिनार, कार्यशाला और सम्मेलनों का आयोजन करके छात्राध्यापकों में मृदु कौशल की क्षमता का विकास किया जा सकता है।

यह कहा जा सकता है कि विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में संतोषजनक वृद्धि करने के लिए अध्यापकों को कठोर कौशल (Hard skills) के साथ-साथ मृदु कौशलों की भी अत्यंत आवश्यकता है। सेवा-पूर्व अध्यापकों को 21 वीं सदी के आवश्यक मृदु कौशलों का उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जिससे वे अपने शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। निष्कर्ष रूप में यह पाया गया कि 21वीं सदी के लिए सृजनात्मकता, सम्प्रेषण, आलोचनात्मक चिंतन, समस्या समाधान, सहयोग जैसे अनेक कौशल 21वीं सदी के लिए आवश्यक मृदु कौशल हैं (पचौरी एवं अन्य, 2014,)। छात्राध्यापकों के कौशल विकास में अध्यापक शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसलिए अध्यापक शिक्षकों को कौशल प्रशिक्षण कार्यान्वयन के पहलू में सख्ती से शामिल होना चाहिए। अध्यापक शिक्षक कार्यान्वयन और मूल्यांकन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए अध्यापक शिक्षकों को अपने शिक्षण माड्यूल की रूपरेखा तैयार करने में सृजनात्मक होना चाहिए जिससे वे

प्रासंगिक कौशल को एकीकृत कर सके। जहां छात्राध्यापकों से शिक्षण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपेक्षा की जाती है, वहीं विभिन्न शिक्षण कौशलों का एकीकृत रूप से प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए (न्गांगा एवं अन्य, 2015; उर्बानी, 2017)।

सन्दर्भ

दुबे, एस. एन.(2014). अध्यापक शिक्षा. शारदा पुस्तक भवन. पृष्ठ 08।

भट्टाचार्य, जी.सी., अध्यापक शिक्षा. अग्रवाल पब्लिकेशन्स, पृष्ठ 01।

गुप्ता, एस. पी., एवं गुप्ता, ए.(2017). उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान: सिद्धांत एवं व्यवहार. शारदा पुस्तक भवन.पृष्ठ 602।

मंगल, एस.के., एवं मंगल,यू.(2016). शिक्षा तकनीकी. पी एच आई लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, पृष्ठ 320।

उर्बानी, जे.एम., रोशनदेल, एस., मिचैल्स, आर., एवं त्रुस्देल, ए. (2017). डेवेलोपिंग एंड मॉडलिंग 21स्ट सेंचरी स्किल्स विथ प्री सर्विस टीचर. टीचर एजुकेशन क्वार्टरली,44(4). https://www.jstor.org/stable/90014088

न्गांगा, टी.के., चान, टी. सी., एवं वेइल्ट्रीवेल्मनि, यू. डी. (2015). क्रिटिकल इश्यूज ऑफ़ सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट इन टीचिंग प्रोफेशनल ट्रेनिंग : एजुकेटर्स पर्सपेक्टिव. सोशल एंड बेहविअरल साइंस, 205 (2015),128-133. https://www.sciencedirect.com

पचौरी, डी., एवं यादव, ए.(2014). इम्पोर्टेंस ऑफ़ सॉफ्ट स्किल्स इन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ एजुकेशनल एंड टेक्नोलॉजी, 5 (1),22-25.

https://www.soeagra.com/ijert.html

गोक्सुन, डी.ओ.,एवं कुर्ट, ए.ए.(2017). द रिलेशनशिप वेटवीन प्री-सर्विस टीचर्स यूज़ ऑफ़ 21स्ट सेंचरी टीचर स्किल्स.एजुकेशन एंड साइंस, 42(190),107-130.

https://www.researchgate.net/publication/316732056

दीपक कुमार

(शोध छात्र)

शिक्षा विभाग,

शिक्षा विद्यापीठ, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

वर्धा (महाराष्ट्र)

स्थायी/पत्राचार पता : ग्राम-पिपरौला, पोस्ट-करुई,

जिला-आजमगढ़, उत्तर प्रदेश-223224

मो.न.: 8934801310 email- dkrajbhar790gmail.com

❑❑❑

पैकेज्ड मसालों के ट्रेडमार्क के प्रति घरेलू महिलाओं की जागरूकता पर विस्तृत अध्ययन

• भाग्य श्री बाला

ट्रेडमार्क उत्पादों की पहचान और गुणवत्ताए अर्थव्यवस्था में सुनिश्चित करने का एक प्रमुख साधन है। पैकेज्ड मसाले, जो हर घर के रसोई का अभिन्न हिस्सा हैं, विशेष रूप से उनके ट्रेडमार्क का अध्ययन उपभोक्ताओं की जागरूकता और निर्णय लेने की प्रक्रिया को समझने के लिए आवश्यक है। यह अध्ययन मुख्य रूप से शिक्षित महिलाओं के बीच ट्रेडमार्क की महत्व और पहचान को समझने की कोशिश करता है। घरेलू महिलाएं परिवार के भोजन का प्रबंधन करती हैं और अक्सर मसालों जैसी आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी भी करती हैं। हालांकि, यह देखने में आता है कि ट्रेडमार्क और गुणवत्ता की पहचान के प्रति उनका ज्ञान सीमित होता है।

प्रस्तावना

आज के दौर में पैकेज्ड मसाले हर घर की रसोई का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। ये केवल खाना बनाने की प्रक्रिया को आसान बनाते हैं, बल्कि स्वच्छता और गुणवत्ता का भी आश्वासन देते हैं। हालांकि, उपभोक्ताओं और घरेलू महिलाओं, में ट्रेडमार्क की समझ और जागरूकता का अभाव एक बड़ी चुनौती है। यह विशेष रूप से पैकेज्ड मसालों के ट्रेडमार्क के प्रति घरेलू और शिक्षित महिलाओं की जागरूकता के स्तर को समझने और बढ़ाने पर केंद्रित है। ट्रेडमार्क का महत्व रू किसी भी उत्पाद की प्रामाणिकता और गुणवत्ता का प्रतीक ट्रेडमार्क होता है। यह उपभोक्ताओं को ब्रांड की विश्वसनीयता और उत्पाद की विशिष्टता का आश्वासन देता है। ट्रेडमार्क यह सुनिश्चित करता है कि पैकेज्ड मसालों के संदर्भ में, मसाले शुद्ध और स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित हैं लेकिन जब उपभोक्ता ट्रेडमार्क के महत्व को नहीं समझते, तो वे नकली या निम्न गुणवत्ता वाले उत्पाद खरीद सकते हैं, जिससे न केवल उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, बल्कि उनके पैसे की भी बर्बादी होती है।

महिलाओं की भूमिका

सामान्यत: घरेलू महिलाएं परिवार की रसोई प्रबंधन और खरीदारी की मुख्य भूमिका निभाती हैं। पैकेज्ड मसालों के मामले में, उनका ज्ञान और जागरूकता खरीद निर्णय को प्रभावित करती है। हालांकि, कई बार वे केवल उत्पाद की कीमत, उपलब्धता और विज्ञापन पर निर्भर रहती हैं, जबकि ट्रेडमार्क की पहचान और गुणवत्ता की जांच को नजरअंदाज कर देती हैं।

शोध का उद्देश्य

1. पता लगाना कि महिलाएं ट्रेडमार्क की जानकारी और महत्व को कितना समझती हैं।

परिकल्पना :

1. पैकेज्ड मसालों के ट्रेडमार्क के प्रति घरेलू महिलाओं को पर्याप्त ज्ञान और जागरूकता नहीं है।

अध्ययन की समस्याएं

अक्सर महिलाएं केवल स्थानीय कीमत और ब्रांडों पर ध्यान देती हैं। ग्रामीण और निम्न-आय वर्ग की महिलाओं में ट्रेडमार्क की पहचान करने की क्षमता कम होती है। बाजार में नकली उत्पादों की बढ़ती संख्या एक बड़ा खतरा है।

अध्ययन का महत्व

यह अध्ययन उपभोक्ताओं, विशेषकर महिलाओं, को न केवल सही उत्पाद चुनने में मदद करेगा, बल्कि उन्हें स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए भी प्रेरित करेगा। इसके अलावा, उत्पादकों और निर्माताओं को यह समझने में मदद करेगा कि उपभोक्ताओं की प्राथमिकताओं को कैसे ध्यान में रखा जाए और उनके उत्पादों को अधिक प्रमाणिक कैसे बनाया जा सके।

सन्दर्भ शोध का पुनरावलोकन

Babu, P. H. (2017) Export performance of spices in India : शोधपत्र भारतीय मसालों के निर्यात प्रदर्शन की समीक्षा करता है। शोध अनुसार, भारत में मसालें से लाखों लोगों की आजीविका का प्रमुख स्रोत है। भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक भी है लेकिन कड़ी प्रतिस्पर्धा, कच्चे माल की अनुपलब्धता, अवैज्ञानिक उत्पादन विधियां, मसालें निर्यात को प्रभावित कर रही है।

Chandila et al. (2019) A comparative study on consumer perception towards packaged spices among Rural and Urban women

ये शोध ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं के बीच पैकेज्ड मसालों के प्रति उपभोक्ता धारण के लिए किया गया था। परिणामों से पता चला, ग्रामीण महिलाएं पैकेज्ड मसालों के प्रति नकारात्मक सोच रखती है जबकि मिलावट के प्रति शहरी महिलाओं में जागरूकता पायी गयी। शहरी महिलाएं पैकेज्ड मसालों को खरीदना पसंद करती है।

महिला उपभोक्ताओं का मसालों के ट्रेडमार्क चिन्ह का ज्ञान परिणाम अवं परिचर्चा

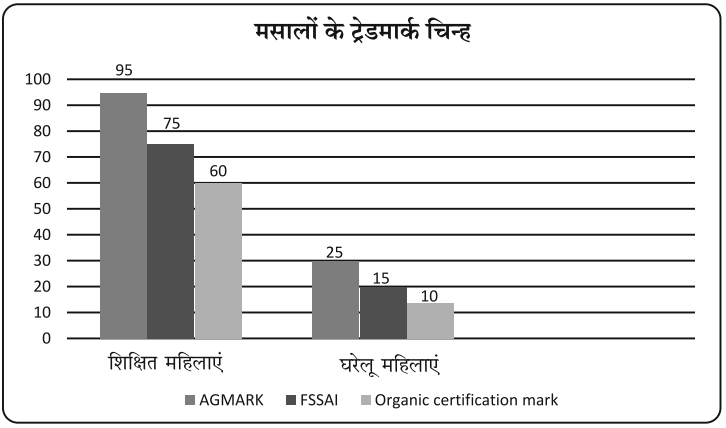

ग्राफ : महिला उपभोक्ताओं का मसालों के ट्रेडमार्क चिन्ह के ज्ञान का आंकलन शिक्षित महिलाएं

- सभी खाद्य पदार्थ खेत से लेकर खाने के टेबुल तक आने में कई प्रकियाओं से गुजरते हैं और प्रकिया में सूक्ष्म व गुणवत्ता की आवश्यकता होती है जिसे सुनिश्चित करता है 'ट्रेडमार्क चिन्ह'। मसालों के क्षेत्र में एगमार्क (AGMARK), एफ एस एस ए आइ (FSSAI) एवं जैविक प्रमाणीकरण चिन्ह (Organic Certification Mark) प्रमुख रूप से ट्रेडमार्क चिन्ह है। ग्राफ के अनुसार घरेलू महिलाएं थोड़ी बहुत ट्रेडमार्क चिन्हों को जानती थी, (वैसे भी इस वर्ग की उपभोक्ताएं खुले मसाले ज्यादा उपयोग करती थी और खुले मसालें ट्रेडमार्क चिह्न रहित होते हैं) और न ही ट्रेडमार्क चिन्हों के प्रति उत्सुक/चिंतित पायी गयी। शिक्षित महिला उपभोक्ताएं ज्यादातर सील बंद (Packet) पैकेट ही उपयोग करती थी (चाहे स्थानीय या ब्रांडेड कोई भी हो और उनके लिए यही शुद्धत्ता का ट्रेडमार्क चिन्ह थे। ग्राफ में वर्णित सभी ट्रेडमार्क चिन्हों की उन्हें थोड़ी बहुत जानकारी तो थी पर वे उनका उपयोग नहीं करती थी।

समाधान और सुझाव

ट्रेडमार्क के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए महिलाओं को स्थानीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। विशेषकर ग्रामीण और अशिक्षित महिलाओं को उत्पाद के लेबल, सामग्री और ट्रेडमार्क की पहचान करने के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए। उत्पादों की प्रामाणिकता और गुणवत्ता की जानकारी सरल और सुलभ भाषा में उपलब्ध होनी चाहिए। महिलाओं को अपने अनुभव साझा करने और अन्य महिलाओं को सही उत्पाद चुनने में मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

ट्रेडमार्क केवल एक पहचान चिह्न नहीं है, बल्कि ट्रेडमार्क उपभोक्ता और उत्पादक के बीच विश्वास का प्रतीक है। घरेलू महिलाओं को ट्रेडमार्क के महत्व को समझने और इसे अपने खरीद निर्णय का हिस्सा बनाने के लिए शिक्षित करना आवश्यक है। यह न केवल उनके स्वास्थ्य और धन की सुरक्षा करेगा, बल्कि बाजार में नकली और घटिया उत्पादों की संख्या को भी कम करेगा। इस अध्ययन से मिलने वाले परिणाम सुधार और जागरूकता अभियानों के लिए एक मजबूत आधार प्रदान कर सकते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूचि :

1. Babu, P. H. (2017). Export performance of spices in India: An empirical study. *Parikalpana – KIIT Journal of Management, 13*(1). DOI: 10.23862/kii parikalpana/2017/v13/i1/151275.
2. Chandila, J., & Puri, D. (2019). A comparative study on consumer perception towards packaged spices among Rural and Urban women. *International Journal of Health Sciences & Research. 9(8).*
3. Kothari, C. R., (Research Methodology : Methods and Techniques), Publications : New as International Publishers.
4. Sharma, Ram Avtar, (Educational Research and Statistics), Publication : R.Lal. Book Dipo.
5. Singh, Yogesh Kumar, (Fundamentals of Research Methodology and Statistics), Publication : New as International Publishers.

भाग्य श्री बाला

गृह विज्ञान विभाग

पटना विश्वविद्यालय, पटना

❑❑❑

पोषण वाटिका एवं पोषण सुरक्षा : एक अध्ययन

• डॉ. प्रगति

प्रस्तुत शोध पत्र में पोषण वाटिका के उपयोगों एवं महत्त्वों को दर्शाया गया है। अध्ययन के लिए दरभंगा शहर से 100 (25-55) साल कि महिलाएँ, जिसमें 50 महिलाएँ पोषण वाटिका का उपयोग कर रही थी एवं 50 ऐसी महिलाएँ जिनका पोषण वाटिका से कोई संबंध नहीं था, का चयन आकस्मिक प्रतिचयन विधि द्वारा किया गया। आकड़ों का संग्रहण साक्षात्कार प्रविधि द्वारा एवं विश्लेषण प्रतिशत् में किया गया है। इस अध्ययन की उत्तरदाता महिलाएँ थी जिससे दो बातें अपेक्षित थी पहली पोषण वाटिका के महत्त्व एवं उपयोगों की जानकारी का स्तर अत्यंत अच्छा होगा। खासकर उन 50 महिलाओं का जो पोषण वाटिका का इस्तेमाल कर रहीं थीं। दूसरा गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्ता के रूप में वे अपनी इस ज्ञान को अन्य लोगों तक प्रसारित करेगी।

मुख्य शब्द : *पोषण वाटिका, पोषण सुरक्षा, बच्चों।*

भूमिका

आज तेजी से बदल रही दुनिया में खेती एवं खानपान के तौर तरीकों में भी तेजी से बदलाव हो रहे हैं। खेतों में कुछ चुनिन्दो फसलों के उत्पादन पर अधिक जोर हैं एक फसली क्षेत्र पिछले दशकों में बढ़ा है और विविध पोषक तत्वों से भरपूर कई फसलों एवं सब्जियों का उत्पादन कम हो गया हैं। इससे फसल एवं खाद्य विविघता में कमी हो रही है। हमारे भोजन में रोटी, चावल एवं दाल के अलावा अन्य खाद्य पदार्थों की मात्रा कम हो गयी है। खाद्य विविधता की कमी का असर हमारी सेहत पर पड़ रहा हैं इस स्थिति में अब यह जरूरी हो गया है कि हम अपने भोजन में विविधता बढ़ाने के लिए अपने घर के आसपास पोषण वाटिका लगायें एवं उसमें अपने परिवार की जरूरत के अनुरूप सब्जियां, फल एवं दैनिक उपयोग की औषधियों को उगायें।

गरीबी एवं कुपोषण के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए खाद्य एवं पोषण सुरक्षा बेहद जरूरी हैं इस प्रक्रिया में पोषण वाटिका पारिवारिक स्तर पर ने केवल पोषण सुरक्षा प्रदार करेगी बल्कि गरीबी को कम करने में भी सहयोगी हो सकती हैं इस प्रक्रिया से समुदाय को अपने घर में शुद्ध सब्जियां एवं फल मिल सकेंगे एवं बाजार पर निर्भरता घटेगी। **(जैन, चन्द्रप्रभा, 1966)**[1]

पोषण वाटिका एक ऐसा तरीका है जो परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त फल और सब्जियों की निरंतर आपूर्ति के माध्यम से सूक्ष्म पोषक तत्त्व प्रदान करके आहार विविधता को बढ़ाने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। **(स्वामिनाथन, एम., 2008)2**

पोषण वाटिका यानि सब्जियों को अपने घर के आसपास लगाने की प्रथा को कहते हैं। इसे पोषण वाटिका, पोषण बगिया, किचन गार्डन, न्यूट्री गार्डन, बार्डन, बाड़ी, सब्जी बाड़ी, पोषण बाड़ी आदि नामों से जाना जाता है।

कुपोषण से बचाव और समुदाय में भोजन में विविधता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा योजना के तहत पोषण वाटिकाओं के विकास के लिए निर्देश जारी किये गए हैं। इन निर्देशों में राज्य की योजनाओं और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सम्मिलन से व्यक्तिगत और सामुदायिक पोषण वाटिकाओं को बढ़ावा दिए जाने की बात कही गयी है।

पोषण वाटिका (न्यूट्री गार्डन) का महत्व (सिंह बृन्दा, 2020)[3]

- समुदाय को स्थानीय स्तर पर जैविक, शुद्ध व पर्याप्त मात्रा में हरी सब्जियां मिलेंगी जिससे खाद्य सुरक्षा एवं पोषण स्तर में वृद्धि होगी।
- परिवारों में स्थानीय संस्कृति एवं परिवेश के अनुरूप भोजन में विविधता आएगी।
- खुद की सब्जी का उत्पादन खुद के लिए करने से पारिवारिक खर्चों में कमी आएगी और आमदनी का एक हिस्सा अन्य आवश्यक कामों में खर्च हो सकेगा।
- बाजार की तुलना में कम लागत में, अच्छी गुणवत्ता वाली, बिना किसी रसायन के उपयोग के सब्जियां आसानी से मिल जाती हैं।
- सब्जी के लिए बाजार नहीं जाना पड़ता और समय की बचत होती है।
- यह परिवार एवं समुदाय में बेहतर वातावरण बनाने में भी मददगार है।

- पोषण वाटिका में सब्जी के उत्पादन से स्थानीय सब्जियों एवं फलों की देशी प्रजातियां संरक्षित होगी जो स्थानीय जलवायु के अनुरूप उत्पादन देने में सक्षम हैं।

सब्जियां एवं उनके गुण

क्र. सं.	सब्जियों के नाम	गुण
1.	टमाटर	यह कोलेस्ट्राल को कम करने में मददगार है और खून में शुगर को नियंत्रित करता है, प्रोस्टेट कैंसर से बचाव करता है।
2.	बैगन	कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ने नहीं पाता एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने मतें भी सहायक हैं दांत दर्द निरोधक है।
3.	भिन्डी	भिन्डी गैस्टिक अल्सर के लिए प्रभावी है। बड़ी आंत की सतह की रक्षा करती है। भिन्डी के नियमित सेवन से गले, पेट, मलाशय और मूत्रमार्ग में जलन को रोकने में मदद मिलती है, सुजाक और ल्यूकोरिया में फायदा होता है।
4.	चिचिंडा	यह वजन को कम करता है और टाइप 2 मधुमेह में फायदेमंद हैं।
5.	परवल	परवल खून को साफ करने के साथ ही पाचन तंत्र में सुधार एवं कैंज को दूर करता है एवं वजन घटाने, पीलिया तथा मधुमेह रोग में फायदेमंद है।
6.	लौकी	लौकी के सेवन से पाचन तंत्र मजबूत हो जाता है और भूख बढ़ती हैं कैंज और गैस की समस्या भी दूर करने में सहायक है।
7.	कद्दू	कद्दू के सेवन से इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने में, प्रोस्टेट ग्रंथि ठीक रखने में, मधुमेह का खतरा कम करने में, बेहतर नींद लाने में मद मिलती है।

क्र. सं.	सब्जियों के नाम	गुण
8.	शिमला मिर्च	शिमला मिर्च मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में सहायक है और यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। साथ ही कैंसर से बचाव करती है।
9.	मूली	मूली एसिडिटी दूर करने में सहायक है और पीलिया तथा पथरी रोगों में फायदेमंद है। अस्थमा में उपयोगी है।
10.	करेला	करेला मधुमेह एवं हृदय रोगों में बहुत उपयोगी है। साथ ही खून को साफ करने एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता हैं लीवर रोगों के उपचार में मददगार है।
11.	गाजर	कोलेस्ट्रॉल लेवल को सही रखता है और वजन कम करने में सहायक है।
12.	बीन	यह हृदय एवं मधुमेह रोग में फायदेमंद है और कैंसर को रोकन में भी उपयोगी है।
13.	फूलगोभी	फूलगोभी के सेवन से कोलेस्ट्रॉल कम होता है एवं हृदयरोग से बचाव होता है साथ ही यह फाइबर का अच्छा स्त्रोत है जो कोलोन कैंसर से बचाव करता है।
14.	पत्तागोभी	पत्तागोभी के जूस का सेवन करने से अल्सर होने का खतरा कम हो जाता है। साथ ही मोतियाबिंद से सुरक्षा देने का काम करता है।
15.	ग्वारफली	यह हृदय रोगों से बचाव में कारगर है। हड्डियों के लिए फायदेमंद है और कैंज में राहत प्रदान करती है।
16	मिर्च	हरी मिर्च आंखों और त्वचा के लिए काफी फायदेमंद है। साथ ही मधुमेह को नियंत्रित करती हैं

क्र. सं.	सब्जियों के नाम	गुण
17.	गिलकी (नेनुआ)	वजन कम करने में सहायक है और एनीमिया को दूर करता है। पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है तथा कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है।
18.	खीरा	आँखों की जलन दूर करता है, कील मुहांसे में फायदेमंद है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, वजन को नियंत्रित करता है।
19.	प्याज	यह उच्च एंटीऑक्सीडेंट है। रक्तचाप को नियंत्रित करती हें साथ ही दिल के लिए लाभदायक है।
20.	टिंडा	यह पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है और वजन को घटाता हे। साथ ही एसिडिटी और शरीर में पानी की कमी को संतुलित करता है। मूत्र रोगों में उपयोगी है और सूजन में फायदेमंद है।
21	चौलाई	यह रक्त एवं त्वचा संबंधी परेशानियों को दूर करती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं
22.	पालक	पालक में अच्छी मात्रा में फायबर होता है जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता हैं साथ ही पालक आयरन का भी अच्छा स्त्रोत है। पालक वजन घटाने में भी कारगर साबित होता है।
23.	मैथी	यह हृदय एवं मधुमेह रोग में उपयोगी है एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं पेट दर्द में भी उपयोगी है।
24.	बथुआ	यह कब्ज में राहत दिलाता है और बालों के लिए फायदेमंदे है। यह खून को साफ करता है और वजन को भी घटाता है।
25.	धनियाँ	धनियाँ रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने तथा पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के साथ वजन को घटाने में मददगार है।

क्र. सं.	सब्जियों के नाम	गुण
26.	सौंफ	यह पाचन के लिए बेहतर एवं भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स से युक्त हैं यह वजन कम करने तथा हृदय रोग में प्रभावकारी है।
27.	अदरक	यह गले के संक्रमण में फायदेमंद है तथा सर्दी एवं फ्लू जैसी बीमारियों में उपयोगी है।
28.	हल्दी	हल्दी वात्त एवं कफनाशक है तथा दर्द निवारक भी है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है।
29.	अरबी	अरबी वजन कम करने में सहायक है और रक्तचाप को भी नियंत्रित करती है।
30.	चुकंदर	चुकंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, खून की कमी को दूर करता है एवं पेट को साफ रखता है।
31.	शलजम	यह खून के दबाव को नियत्रित करने, अस्थमा में उपयोगी है तथा हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है।
32.	सूरन	यह बवासीर तथा कैंसर रोग में उपयोगी है।
33.	आलू	यह शारीरिक विकास एवं हड्डियो की मजबूती के लिए लाभदायक है।
34.	लहसुन	यह पाचन प्रक्रिया में सुधार करता हैं कोल्ड और फ्लू के संक्रमण से सुरक्षा देता है और साथ ही कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करता है और शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है।
35.	एलोवेरा	यह बालों को मजबूती देता है और खून के दबाव को संतुलित करता है।

क्र. सं.	सब्जियों के नाम	गुण
36.	तुलसी	यह दर्द निवारक है और योन रोगों में उपयोगी है, इससे उपयोग से कैंसर का खतरा कम होता है।
37.	आंवला	आंवला के सेवन से खून संबंधी दिक्कतें दूर होती हैं। पेट संबंधी रोगों में सहायक है। बालों एवं त्वचा को मजबूती प्रदान करता हैं
38.	बेल	बेल दिल और दिमाग के लिए टॉनिक के रूप में काम करता हैं यह आंत के अनुकूल भी है और पारंपरिक रूप से कैंज, दस्त, मधुमेह और अन्य स्थितियों को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता हैं इसमें सूजन को कम करने वाले रसायन होते हैं।
39.	इसबगोल	इसबगोल पेचिस, कैंज, दस्त, मोटापा, डिहाइड्रेशन, डायबिटीज आदि रोगों में बहुत गुणकारी है।

(स्त्रोत : वेबदुनिया डॉट कॉम, इण्डिया डॉट कॉम, विकास पीडिया डॉट इन)[4]

अत: जरूरत है कि हम अपने भोजन में विविधता लाने के लिए स्थानीय स्तर पर वह सब उगायें, जो हमारी थाली का हिस्सा है इस नजरिये से पोषण वाटिका एक कारगर तरीका हैं पोषण वाटिका के माध्यम से हम समुदाय में भोजन में विविध तरह की हरी सब्जियां, फल की मात्रा को बढ़ा सकते हैं **(सिंह बृन्दा, 2019)**[5] ।

इसके लिए लोगों में पोषण वाटिका के उपयोगिताओं एवं महत्त्वों के प्रति जागरूकता लाना होगा तथा इससे होने वाले लाभ एवं इसके महत्त्वों से अवगत कराने हेतु अध्ययन किया गया। जिससे भविष्य में पोषण सुरक्षा महज एक शब्द बन कर न रह जाए।

अध्ययन का उद्देश्य : (Objectives)

- पोषण वाटिका से लाभान्वित महिलाओं की पोषण स्थिति का आकलन।
- पोषण वाटिका के प्रति जागरूक करना/प्रति जागरूकता लाना।

अध्ययन की परिकल्पना (Hypothesis)

- पोषण वाटिका से लाभान्वित महिलाओं की पोषण स्थिति संतोषप्रद
- पोषण वाटिका के प्रति जागरूकता सकारात्मक सोच एवं खाद्य सुरक्षा की पहल।

कार्यप्रणाली (Methodology) : कार्यप्रणाली से तात्पर्य यह है कि शोध अध्ययन में कार्य का सम्पादन एवं निष्कर्षो का निर्धारण निम्न इस प्रणाली द्वारा ही की गई हैं।

शोध का क्षेत्र (Area of Research) दरभंगा जिला का दरभंगा शहरी क्षेत्र (Darbhanga Town) के कादिराबाद एवं राजकुमार गंज क्षेत्र

शोध डिजाइन (Research Design) शोध डिजाइन मुख्यत: किसी भी शोध कार्य से पूर्व निर्मित एक योजनाबद्ध रूपरेखा है, इसलिए प्रस्तुत शोध शीर्षक की प्रकृति को देखते हुए वर्णानात्मक शोध डिजाइन के अनुसार की गई है। क्योंकि शोध विषय के वारे में तथ्य संकलित कर उनका एक विवरण प्रस्तुत किया गया है।

प्रतिदर्श (Sample) प्रस्तुत शोध अध्ययन की प्रकृति को देखते हुए उद्येश्यपूर्ण न्यायदर्श (Purposive Sampling) के द्वारा दरभंगा शहर से 100 (25-55 साल) की महिलाएँ ली गई है। जिसमें दरभंगा शहर के कादिराबाद एवं राजकुमार गंज की 50 गृहणियों से जो पोषण वाटिका का उपयोग कर रही है और 50 गृहणियों जो बाजार की साग-सब्जियों पर निर्भर है।

प्रविधि (Technique) शोध अध्ययन में अवलोकन (observation) और साक्षात्कार प्रविधि (Interview schedule) को अपनाया गया है, जिसके माध्यम से डाटा संकलन किया गया।

उपकरण (Sources of data) प्राथमिक डाटा (Primary Data) साक्षात्कार अनुसूची द्वारा किया गया एवं द्वितियक डाटा (Secondary Data) अलग-अलग (Websites, Books, Research articles and Research reports) द्वारा संकलित किया गया है।

परिणाम एवं परिचर्चा : (Results and discussions)

प्रस्तुत अध्ययन में पोषण वाटिका के महत्त्व एवं उपयोग के स्वरूप का आकलन हेतु किया गया हैं इस अध्याय में अध्ययन से प्राप्त आकड़े एवं उनके विश्लेषण का वर्णन हैं।

तालिका : 1 पोषण वाटिका से लाभान्वित महिलाओं की BMI

क्र. सं.	BMI(Kg/m2)	वजन की स्थिति	महिलाओं की सं.	प्रतिशत
1	<18.5	कम वजन	7	14
2	18.5-24.5	सामान्य वजन	35	70
3	25.0- 29.9	अधिक वजन	5	10
4	>30	मोटापा	3	6
		टोटल	50	100

स्त्रोत : **WHO[6] BMI** चार्ट के अनुसार

तालिका : 1 से स्पष्ट है कि पोषण वाटिका से लाभान्वित महिलाओं की BMI पता लगाने के लिए दरभंगा जिले के राजकुमार गंज और कैदिराबाद मोहल्ले के 50 महिलाओं का साक्षात्कार-अनुसूची के द्वारा डाटा का संग्रह किया, जिसमें यह देखने को मिला कि 14 प्रतिशत महिलाओं का BMI <18.5, 70 प्रतिशत महिलाओं का BMI 18.5-24.5 10 प्रतिशत महिलाओं का BMI 25.0-29.9 और 6 प्रतिशत महिलाओं का BMI >30 है।

तालिका : 2 पोषण वाटिका से गैर-लाभान्वित महिलाओं की BMI तालिका

क्र. सं.	BMI	वजन की स्थिति	महिलाओं की सं.	प्रतिशत
1	<18.5	कम वजन	25	50
2	18.5-24.5	सामान्य वजन	10	20
3	25.0- 29.9	अधिक वजन	10	20
4	>30	मोटापा	5	10
		टोटल	50	100

स्त्रोत : **WHO[6] BMI** चार्ट के अनुसार

तालिका : 2 से स्पष्ट है कि पोषण वाटिका से गैर लाभान्वित महिलाओं की BMI पता लगाने के लिए दरभंगा जिले के राजकुमार गंज और कादिराबाद मोहल्ले के 50 महिलाओं का साक्षात्कार-अनुसूची के द्वारा डाटा का संग्रह

तालिका 3 : पोषण वाटिका से लाभान्वित एवं गैर लाभान्वित महिलाओं का क्लीनिकल परीक्षण का तुलनात्मक तालिका

क्रम संख्या	मसूड़ों से खून बहना (Bleeding gums)		एंगुलर स्टोमाटाइटीस (Angular Stomatitis		पेलाग्रा (Pellagra)		ओडिमा (Oedema)		त्वचा और बालों का रंग बदलना (Discolour Skin & hair)		मांसपेशियों की कमजोरी (Muscular weeknes)		चिलोसिस (Chilosis)		टोटल (Total)	
लाभान्वित महिलाएँ	महिलाओं की संख्या	प्रतिशत	महिलाओं की संख्या	प्रतिशत	महिलाओं की संख्या	प्रतिशत	महिलाओं की संख्या	प्रतिशत	महिलाओं की संख्या	प्रतिशत	महिलाओं की संख्या	प्रतिशत	महिलाओं की संख्या	प्रतिशत	महिलाओं की संख्या	प्रतिशत
	6	12	5	10	5	10	10	20	8	16	6	12	10	20	50	100
गैर लाभान्वित महिलाएँ	10	20	6	12	5	10	5	10	9	18	10	20	5	10	50	100

तालिका 4 : पोषण वाटिका से लाभान्वित एवं गैर लाभान्वित महिलाओं में रक्तहीनता की तुलनात्मक तालिका

क्रम संख्या	रक्तहीनता मुक्त (Anemia) >12 g/dl		हल्का रक्तहीनता (Mild Anemia) 11-11.9 g/dl		मध्यम रक्तहीनता (Moderate Anemia) 8-10 g/dl		गंभीर रक्तहीनता (Severe Anemia) <8 g/dl		टोटल (Total)	
लाभान्वित महिलाएँ	महिलाओं की संख्या	प्रतिशत	महिलाओं की संख्या	प्रतिशत	महिलाओं की संख्या	प्रतिशत	महिलाओं की संख्या	प्रतिशत	महिलाओं की संख्या	प्रतिशत
	30	60	10	20	5	10	5	10	50	100
गैर लाभान्वित महिलाएँ	15	30	15	30	10	20	10	20	50	100

किया, जिसमें यह देखने को मिला कि 50 प्रतिशत महिलाओं का BMI <18.5, 20 प्रतिशत महिलाओं का BMI 18.5-24.5 और 10 प्रतिशत महिलाओं का BMI>30 है।

अत: पोषण वाटिका से लाभान्वित और गैर लाभान्वित महिलाओं की BMI तालिका संख्या-1 और 2 के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है कि पोषण वाटिका से लाभान्वित महिलाओं की BMI अच्छी है।

अत: पोषण वाटिका से लाभान्वित एवं गैर लाभान्वित महिलाओं का क्लीनिकल परीक्षण का तुलनात्मक तालिका संख्या-3 के अध्ययन से स्पष्ट है कि पोषण वाटिका से गैर लाभान्वित महिलाओं की अपेक्षा लाभान्वित महिलाओं का स्तर बेहतर स्थिति में है।

अत: पोषण वाटिका से लाभान्वित एवं गैर लाभान्वित महिलाओं में रक्तहीनता की तुलनात्मक तालिका संख्या-4 से स्पष्ट है कि पोषण वाटिका से लाभान्वित महिलाएँ में 60 प्रतिशत रक्तहीनता से ग्रसित नहीं है, और पोषण वाटिका से गैर लाभान्वित महिलाएँ में 70 प्रतिशत रक्तहीनता से ग्रसित है। इसलिए रक्तहीनता की तुलनात्मक तालिका दर्शाता है कि पोषण वाटिका से गैर लाभान्वित महिलाएँ की अपेक्षा पोषण वाटिका से लाभान्वित महिलाएँ की रक्तहीनता का स्तर बेहतर स्थिति में है।

निष्कर्ष (Conclusion)

पोषण सुरक्षा हर व्यक्ति के वर्तमान एवं भविष्य दोनों अवस्थाओं में बहुत ही महत्त्वपूर्ण भूमिका में हैं। पर प्रतिदिन के आहार में पौस्टिक खाद्य पदार्थों की समुचित मात्रा एवं सही तरीके से शामिल होने के लिए पोषण वाटिका के सभी पहलुओं की जानकारी आवश्यक हैं यह इस अध्ययन से ही सभंव हो पाऐगा। जिससे भविष्य में हमारा समाज कुपोषण की समस्याओं से वंचित एवं स्वस्थ पोषण स्तर प्राप्त कर पाऐगा।

संदर्भ-सूची :

1. जैन, चन्द्रप्रभा (1966), पोषण एवं आहार, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, पृ. सं., 38।
2. स्वामिनाथन, एम. (2008), पोषण एवं आहार के सिद्धांत, बंगलोर पब्लिशिंग को. बंगलोर पृ. सं., 25।

3. सिंह बृन्दा (2020), आहार एवं पोषण, पंचशील प्रकाशन, जयपुर पृ. सं., 20।
4. स्त्रोत—वेबदुनिया डॉट कॉम, इण्डिया डॉट कॉम, विकास पीडिया डॉट इन
5. सिंह बृन्दा (2019), पारिवारीक संबंध, पंचशील प्रकाशन, जयपुर पृ. सं.,585।
6. WHO BMI चार्ट

डॉ. प्रगति
असिस्टेंट प्रोफेसर
गृह विज्ञान विभाग
ल. ना. मि. वि. विद्यालय
दरभंगा-846004 (बिहार)

❑❑❑

शिक्षा में AI के प्रयोजन से मूल्यों के हस्तांतरण की दिशा में भविष्य

डॉ. नरेन्द्र कुमार पाल • डॉ. चित्रा पाल • दीपक कुमार जाँगिड़

वर्तमान समय में बदलते तकनीकी स्वरूप के प्रभाव में शिक्षा का स्वरूप एवं स्वीकृति में अत्यधिक विस्तार हुआ है। शिक्षण के आदान प्रदान के माध्यम में आभासी माध्यम की भूमिका में कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रमुख योगदान दे रहा है। प्रस्तुत शोध लेख के अंतर्गत शिक्षा का विस्तृत होता स्वरूप एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता की स्वीकृति के साथ भविष्य में मूल्यों के हस्तांतरण के लिए उचित दिशा में तथ्यों को प्रेषित करने का प्रयास किया गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग एवं विकास के साथ मूल्यों के संवर्धन में वर्तमान परिदृश्य के साथ भविष्य का निर्माण एवं राष्ट्रीय भावना का विकास आवश्यक है। तकनीकी के द्वारा मूल्यों की संवेदनशीलता एवं वास्तविक धरातल पर इसका सकारात्मक प्रभाव हो इसके लिए शिक्षा के माध्यम से आवश्यक बिंदुओं पर गहन चिंतन करते हुए प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान केन्द्रित करने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्द : *शिक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (-AI), शिक्षा में AI, मूल्य, मूल्यों का हस्तांतरण*

प्रस्तावना :

परिवर्तित समय की स्वीकार्यता के साथ वर्तमान युग तकनीकी का है। प्रतिदिन प्रत्येक क्षेत्र में नए-नए आविष्कार सम्पन्न हो रहे है, तथा मानव-जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा हो। तकनीकी प्रयोग के कारण मनुष्य के जीवन स्तर में अत्यधिक सुधार हुआ है। तकनीकी का उद्देश्य मनुष्य के सर्वांगीण विकास और जीवन स्तर को सरल,

सहज एवं बेहतर करना है। इस उद्देश्य की प्रतिपूर्ति हेतु सर्वप्रथम 'एलन ट्यूरिंग' (Alan Turing) ने सन् 1950 में 'सोचने वाली मशीनें (Thinking Machine)' कि आशाजनक सोच रखी थी। इसका प्रतिफल है कि अनेक अनुसंधानों के उपरांत वर्तमान समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का प्रत्येक क्षेत्र में उपयोग किया जा रहा है। इन तकनीकों ने शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण व अधिगम प्रक्रिया को भी परिवर्तित किया है। वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के प्रयोग का विस्फोट हुआ है। इसका साक्ष्य होराइज़न रिपोर्ट-2018 है, जिसके अनुसार, शिक्षा के क्षेत्र में 2018-22 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के प्रयोग में 43% कि वृद्धि हुई है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) एक उभरती हुई तकनीक है, जिसने शैक्षिक उपकरणों और संस्थानों को परिवर्तित किया है। शिक्षा व शैक्षिक संस्थानों का दायित्व होता है कि वह संस्कृति, विज्ञान, तर्क, परम्पराओं, ज्ञान व मूल्यों का हस्तांतरण करें। इस प्रक्रिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) ने शिक्षक और शैक्षिक संस्थानों के विकास में अपना स्थान सुदृढ़ किया है, परंतु क्या मूल्यों के हस्तांतरण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) अपने अस्तित्व को निश्चित करती है? अथवा मूल्यों के हस्तांतरण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) भविष्य में स्वयं को स्थापित कर सकेगी? क्योंकि मूल्यों का निर्माण मनुष्य के व्यवहार, व्यक्तित्व व अनुसरण से होता है और उसका स्थानांतरण अनुकरण से होता है।

शिक्षा का बदलता स्वरूप

शिक्षा शब्द का प्रयोग एवं इसमें हस्तक्षेप सर्वत्र होता है। इस प्रकार शिक्षा का अनेक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। परंतु वास्तव में शिक्षा शब्द का अर्थ सीखना और सिखाना है, जिसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा के 'शिक्षा' धातु से हुई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के अनुसार, शिक्षा केवल वह नीव नहीं है जिस पर हमारी सभ्यता का निर्माण हुआ है अपितु यह मानवता के भविष्य कि वास्तुकार भी है।

इसी प्रकार फेसबुक के स्थापक मार्क जुकरबर्ग के अनुसार, सबसे अच्छी शिक्षा वह है जो छात्रों कि व्यक्तिगत जरूरतों के अनुरूप हो।

शिक्षा, समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी श्रृंखलाबद्ध तरीके से ज्ञान के हस्तांतरण का प्रयास है। इस विचार से शिक्षा एक संस्था के रूप में कार्य करती है जो व्यक्ति विशेष को समाज से जोड़ने, उसकी आवश्यकताओं व उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा के उद्देश्य समयान्तर के साथ-

साथ परिवर्तित होते रहते है क्योंकि, संसार परिवर्तनशील है। यह कथन चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक जीवन के उत्थान की विधियाँ में अभिव्यक्त किया है। भारतीय समाज के विकास में और उसमें होने वाले परिवर्तनों के साथ-साथ शिक्षा के स्वरूप को भी निरंतर विकासशील व परिवर्तनशील पाते है। इसका कारण स्वतंत्रता के बाद आई विभिन्न शिक्षा नीतियाँ व आयोग जैसे राधाकृष्णन् आयोग (सन् 1948), माध्यमिक शिक्षा आयोग (सन् 1953), कोठारी आयोग (सन् 1964), राष्ट्रीय शिक्षा नीति (सन् 1968), नई शिक्षा नीति (सन् 1986), राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा-2005 एवं नई शिक्षा नीति (सन् 2020) है।

स्वतंत्रता के पश्चात भारत कि शिक्षा का स्वरूप वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली के सापेक्ष अत्यधिक भिन्न था। पूर्व में शिक्षक मुख्य भूमिका में होता था और विद्यार्थी सहायक कि भूमिका में होते थे, परंतु वर्तमान समय में इसके विपरीत विद्यार्थी मुख्य भूमिका में होते हैं, और शिक्षक सहायक भूमिका में रहकर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन व शिक्षण अधिगम का कार्य सम्पन्न करता है। पूर्व में शिक्षक विद्यार्थी के मध्य, माध्यम के तौर पर क्रिया को ज्यादा महत्त्व दिया जाता था, जिससे शिक्षा के उपयोजन का उद्देश्य प्रभावी तौर पर समाज पर सिद्ध होता था, जबकि वर्तमान समय में शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य क्रिया के स्थान पर अप्रत्यक्ष एवं आभासी तकनीकी माध्यम के प्रयोजन से शिक्षा का आदान प्रदान हो रहा है।

आजादी के समय पर शिक्षक का स्थान महत्त्वपूर्ण होता था, परंतु धीरे-धीरे शिक्षकों के साथ-साथ पुस्तकों का भी महत्त्व बढ़ता गया। समय परिवर्तन के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में अनेक विषयों को जोड़ा गया। आजादी के समय पर शिक्षा का मुख्य उद्देश्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित करना था। परंतु वर्तमान समय में व्यक्तियों को शिक्षित करने के साथ-साथ उनको कौशल्य एवं स्वरोजगार में निपुण करना, तथा आत्मनिर्भर बनाना है जिसके कारण वह राष्ट्र के विकास मे योगदान दे सके। आजादी के समय पर शिक्षा को सेवा का कार्य माना जाता था परंतु वर्तमान समय में शिक्षा सेवा के समकालीन परिप्रेक्ष्य में व्यवसाय है। वर्तमान समय में शिक्षा प्राप्त करने हेतु किसी निश्चित स्थान या समय की आवश्यकता नहीं होती है जिसका उदाहरण है दूरस्थ शिक्षा, जहाँ आजादी के समय में विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करने हेतु निश्चित समय पर, एक निश्चित स्थान जिसे विद्यालय कहा जाता है पर जाना पड़ता था, वही अब किसी भी उम्र का विद्यार्थी कही से भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। इक्कीसवी

शताब्दी के तकनीकी युग ने शिक्षा को व्यापक बनाया है जिसके कारण कोई भी व्यक्ति, किसी भी स्थान पर, किसी भी समय पर, किसी भी माध्यम में, किसी भी प्रकार कि शिक्षा ग्रहण कर सकता है।

आजादी के समय में भारत कि साक्षरता दर अत्यधिक कम थी। जिसमें समय के साथ परिवर्तन होता गया अर्थात् शिक्षा के स्वरूप में भी परिवर्तन होता गया है। वयस्क साक्षरता दर में महिलाओं के साथ-साथ पुरुषों की भी वृद्धि देखी गई है। 2001-2011 की अवधि के दौरान यह 61% से बढ़कर 69.3% हो गया है।[4] सन् 2000-01 में 60840 पूर्व प्राथमिक विद्यालय और 664041 प्राथमिक और जूनियर विद्यालय थे।[5] प्राथमिक स्तर पर सन् 1950-51 में विद्यार्थियों कि नामांकन संख्या 19200000 थी जो सन् 2001-02 में बढ़कर 109800000 हो गई।[6] आजादी के समय में विज्ञान, गणित आदि के शिक्षा पर अत्यधिक महत्त्व दिया जाता था परंतु वर्तमान समय में मूल्य शिक्षा, समावेशी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा को भी समान महत्त्व प्राप्त किया है।

स्वतंत्रता के पश्चात सन् 1962 में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 309 विद्यालय थे जिनकी संख्या 1 मई 2019 तक बढ़कर 21296 हो गई है। इनमें 138 केंद्रीय विद्यालय, 3011 सरकारी/सहायता प्राप्त विद्यालय, 16741 स्वतंत्र विद्यालय, 595 जवाहर नवोदय विद्यालय और 14 केंद्रीय तिब्बती विद्यालय शामिल हैं।[7] शैक्षणिक सत्र 2020-21 तक सम्पूर्ण भारत में कुल 14.89 लाख विद्यालय है जिसमें 10.22 लाख सरकारी विद्यालय है, तथा 26.52 करोड़ विद्यार्थी इन विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करते है, और 95 लाख शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहे है।[8] इसी प्रकार उच्च शिक्षण संस्थानों कि संख्या में भी सन् 1990 से लेकर 2011 तक वृद्धि हुई है जो निम्न प्रकार है—

क्र. सं.	वर्ष	विश्वविद्यालयों की संख्या	महाविद्यालयों की संख्या
1.	1990-91	190	7346
2.	2000-01	256	12806
3.	2010-2011	634	33023

वर्तमान समय में विश्वविद्यालयों कि संख्या 1142 है जिसमें 56 केन्द्रीय विश्वविद्यालय, 127 डीम्ड विश्वविद्यालय, 477 प्राइवेट विश्वविद्यालय तथा 482 राज्य विश्वविद्यालय संचालित है।[9] इन नई तकनीकों के कारण अनेक दूर शिक्षा निदेशालय अथवा डिस्टन्स विश्वविद्यालय कि स्थापना संभव हुई है। यह विश्वविद्यालय प्रत्येक नागरिक को अपनी सुविधा के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते है। इस प्रक्रिया को और अधिक उन्नत करते हुए अन्य विश्वविद्यालयों ने भी, इस प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन प्रारंभ किया है। इसका प्रथम उदाहरण दिल्ली विश्वविद्यालय है। हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. योगेश सिंह के द्वारा एक पाठ्यक्रम कि शुरुआत कि गई है। यह पाठ्यक्रम उन लोगों के लिए लागू किया गया है जो पूर्व में विश्वविद्यालय का हिस्सा थे और किसी कारणवश अपनी शिक्षा को पूर्ण नही कर सके थे। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से किसी भी उम्र के विद्यार्थी जो विश्वविद्यालय का हिस्सा थे अपनी शिक्षा को पुनः प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पूर्ण कर सकते है। एक समय में जहाँ शिक्षा प्राप्त करने अवसर नही थे, वही वर्तमान समय में ऐसे पाठ्यक्रमों के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के अनेक अवसर प्रदान किए जा रहे है। वर्तमान समय भारतीय परिप्रेक्ष्य में शिक्षा व्यवस्था में हुए अमूलचूल परिवर्तनों का साक्षी है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की व्यापकता एवं स्वीकृति

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), तकनीकी व प्रौद्योगिकी के जगत में एक ऐसा आविष्कार है जिसने समाज के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है। इस तकनीकी ने मोती रूपी प्रत्येक देश को जोड़ कर एक सम्पूर्ण विश्व रूपी माला का निर्माण किया है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने इसे और अधिक मजबूती प्रदान की है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव द्वारा निर्मित एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मशीनों को मनुष्यों के समान सोचने के लिए तैयार किया जाता है। मनुष्य इस प्रक्रिया में सफल भी रहा है, क्योंकि वर्तमान समय में दैनिक जीवन से संबंधित अधिकांश कार्य, उद्योग से संबंधित कार्य, सेवा से संबंधित कार्य, बैंक के कार्य, चिकित्सा के कार्य, शिक्षा के कार्य तथा अन्य क्षेत्रों के भी अनेक कार्यों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग व प्रयोग किया जा रहा है।

वर्तमान समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता बहुत तेजी से समाज कि मुख्य धारा का हिस्सा बन रही है क्योंकि इसका उपयोग मूवी पसंद करने से लेकर ट्रेन टिकट बुक करने में, कपड़े पसंद करने में, गाड़ी चलाने में, शिक्षा प्राप्त करने में आदि में किया जा रहा है। मिचेल लिटमन का कहना है कि, पिछले 5 सालों

में कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने ऐसा उछाल प्राप्त किया है कि वह अनुसंधान प्रयोगशालाओं व उच्च नियंत्रित व्यवस्था से बाहर निकल कर समाज व उसके नागरिकों के जीवन एवं विचारों को प्रभावित कर रही है। अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता का क्षेत्र इतना व्यापक है कि, इसकी पहुँच व उपयोग से समाज का कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रह गया है।

वर्ष 2022 में जनरेटिव प्री-ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मर (GPT) एप्लीकेशन के माध्यम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को मुख्य धारा में लाया गया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की अनेक विशेषताओं जैसे जटिल कार्यों को बिना अधिक लागत के हल करना, लगातार कार्य करने की क्षमता, उत्पादन में वृद्धि, शुद्धता आदि के कारण बहुत कम समय में अत्यधिक लोकप्रिय बन गया है। इसमें सबसे लोकप्रिय एप्लीकेशन Open AI का Chat-GPT है। तत्पश्चात् कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित अनेक एप्लीकेशन आए जैसे माइक्रोसॉफ्ट का कोपाइलट, अलेक्सा, सिरी, ऐली आदि।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) ने वर्ष 2022 में लगभग 86.9 बिलियन का लाभ प्राप्त किया है जिसके वर्ष 2027 तक 407 बिलियन पहुँचने कि संभावना है। यह वर्ष 2030 तक अमेरिका की सकल घरेलू उत्पाद में 21% कि वृद्धि करेगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) पर आधारित Chat-GPT के उपलब्ध होने के 5 दिनों के अंदर 1 मिलियन उपयोगकर्ता थे, जो इसकी व्यपकता व लोकप्रियता को प्रदर्शित करता है। आधे से अधिक अमेरिकी मोबाईल उपयोगकर्ता प्रति दिन वॉयस सर्च करते है। ग्रांड व्यू रिसर्च के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता में वर्ष 2023 से 2030 तक 37.3% कि वार्षिक वृद्धि देखने को मिलेगी।

वैश्विक स्तर पर चीन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का सबसे अधिक उपयोग करने वाला देश है। चीन में 58% कॉम्पनी पूर्णतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के द्वारा संचालित होती है और 30% कॉम्पनी आंशिक रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कर रही है। चीन कि तुलना में अमेरिका कि 25% कॉम्पनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कर रही है और 43% कॅम्पनी इसके क्षमता को समझ रही है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता की वैश्विक स्तर पर स्वीकृती को प्रदर्शित करता है।

भारत में भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का प्रयोग अनेक क्षेत्रों में किया जा रहा है। भारत समावेशी सिद्धांत के आधार पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग अधिकतर कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कर रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के

विकास के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) पोर्टल को लॉन्च किया है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and IT-IT MeitY), राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (National e-Governance Division- NeGD) और नैसकॉम (NASSCOM) की एक संयुक्त पहल है। यह भारत और उसके बाहर कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित समाचार, घटनाओं और गतिविधियों आदि के लिये एक केंद्रीय हब (Hub) के रूप में कार्य करता है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था के बदलते स्वरूप में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का भी अहम् योगदान है। उपरोक्त तथ्यों व कथनों के आधार पर कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग व प्रयोगों कि व्यापकता को समाज व विश्व ने स्वीकार किया है।

शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (-AI) की भूमिका एवं भविष्य

वर्तमान समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है और दक्षता के साथ प्रगति कर रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पुलिस कार्य, कैंसर जाँच, हवाई-जहाज के टकराने कि संभावना को कम करने में, स्वचालित गाड़ियों के निर्माण में, डिफेन्स क्षेत्र, शिक्षा आदि में किया जा रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता युक्त रोबोट विद्यालय में शिक्षण कार्य, अस्पतालों मे सर्जरी, मरीजों व वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल कर रहे है। शिक्षा कि स्थापना के पश्चात् से ही शिक्षण-अधिगम कार्य कि विधियों एवं प्रणालियों में तथा शिक्षक व विद्यार्थियों के सम्बन्धों में अत्यधिक विकास हुआ है। विश्व भर में शिक्षण विधियों अतिरिक्त उच्च परिणाम देने के लिए संरचित हो रही है। इसका कारण शिक्षा में तकनीकी का बढ़ता हुआ हस्तक्षेप है। शिक्षा के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दायरा दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शिक्षा में भूमिका को निम्नलिखित बिन्दु के द्वारा समझ जा सकता है–

1. शिक्षा कि सार्वभौमिक पहुँच–कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण आज विश्व भर के सभी शिक्षण संस्थान एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर आ गए जिसके कारण प्रत्येक विद्यार्थियों को सभी प्रकार कि उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर प्राप्त हो रहा है। ऐसे विद्यार्थी जो किन्ही कारणों से शिक्षा कि मुख्य धारा से वंचित रह गए थे उन्हें भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण ही संभव हो सका है।

2. वैयक्तिक भिन्नता–प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विभिन्नता लिए हुए होते है। यह विभिन्नता सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक व मानसिक हो सकती है।

इनमे से कुछ भिन्नताओं को पहचानने में समस्याएं उत्पन्न होती थी, जिसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने समाप्त कर दिया है। इसके कारण अब विद्यार्थियों को उनकी रुचि व योग्यता के अनुसार शिक्षा प्रदान करना संभव हो सका है।

3. परीक्षण प्रणाली–कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने पारंपरिक परीक्षण प्रणाली को तोड़कर व्यक्तिगत मूल्यांकन प्राणली को अपनाया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण मूल्यांकन में पारदर्शिता आई है। इसके द्वारा किसी भी विद्यार्थी का किसी भी स्थान पर मूल्यांकन किया जा सकता है। विद्यार्थी स्वयं अपना मूल्यांकन करने में सक्षम हो सके है।

4. व्यक्तिगत शिक्षण प्रदान करने में–वर्तमान समय में हमारे कक्षा कक्ष अत्यधिक बड़े हो गए है। अतः प्रत्येक विद्यार्थी पर शिक्षण के दौरान ध्यान रखना कठिन हो जाता है और यह ज्ञात करने में समस्या होती है कि वह प्रकरण को समझ पाया है अथवा नहीं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रत्येक विद्यार्थी का अलग-अलग डाटा रखता है जिसके कारण उसकी कमजोरी के अनुसार वह अलग से शिक्षण कार्य कर सकता है।

5. शिक्षकों के पास अधिक डाटा प्राप्त करने में–वर्तमान समय में शिक्षको के पास डेटा प्राप्त करने के पारंपरिक स्रोत है जिसके करना डेटा व ज्ञान प्राप्त करने में कठिनाई होती है, समय व धन भी अधिक लगता है तथा वैश्विक स्तर पर होने वाली नई घटनों से अवगत नहीं हो पाता है, जबकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण एक शिक्षक अनेक प्रकार का ज्ञान, कम लागत में, कभी भी कही से भी प्राप्त कर सकता है।

6. शिक्षकों व विद्यार्थियों को फीडबैक देने में–कृत्रिम बुद्धिमत्ता छात्रों को सही विषय चुनने में तथा अपने क्षेत्र के अनुसार विशिष्ट शिक्षक के लिए फीडबैक प्रदान करेगा। इसके कारण छात्र अपनी पाठ्यक्रम को अपनी रुचि के अनुसार पसंद कर सकेगा।

शिक्षा के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्तमान प्रयोग के अनुसार वह दिन दूर नहीं जब, भविष्य में प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी व शिक्षक, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करेंगे। वर्ष 2015 के साक्षात्कार में अमेरिकी बिल गेट्स ने बताया था कि उनकी फाउंडेशन ने व्यक्तिगत शिक्षण तकनीकी के विकास के लिए लगभग एक चौथाई बिलियन डॉलर का निवेश किया था। विश्व आर्थिक मंच का अनुमान है कि वर्ष 2022 तक कंपनियों का एक बड़ा हिस्सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपनाने के साथ-साथ,

सरकारों व शिक्षा को, प्रत्येक स्ट्रीम विज्ञान, प्रौद्यौगिकी, इंजनीयरिंग, गणित और गैर-संज्ञानात्मक कौशलों को तेजी से बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

AI के प्रयोग एवं मूल्यों का अस्तित्व व हस्तांतरण

वर्तमान समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) अनेक क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसका प्रयोग सेवा, सुरक्षा, उपलब्धता, ज्ञान, प्रशिक्षण, बैंकिंग, मार्केटिंग, फाइनैन्स, कृषि, अंतरिक्ष, स्वचालित उपकरण, खेलों व स्वास्थ्य सुविधाओं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के निर्माण तथा शिक्षा में हो रहा है। परंतु शिक्षा के क्षेत्र में विकास का एक मुख्य कारण कृत्रिम बुद्धिमत्ता व उसके प्रयोग है। शिक्षा ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता का ऐसा स्वागत किया है जैसे उसके आने से ही शिक्षा अपने पूर्ण अस्तित्व मे आई है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता व उसके प्रयोग अधिगम एवं शिक्षण के क्षेत्र में प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। होरीजन रिपोर्ट 2018 के अनुसार शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रयोग में वर्ष 2018 से 2022 तक 43% कि वृद्धि हुई है।

शिक्षा के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कि विशेषता व्यक्तिगत अधिगम अनुभव प्रदान करना है, जिसके कारण कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने शिक्षा के क्षेत्र में स्थान प्राप्त किया है। केलेहर और टियरनी (2018) के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग विद्यार्थियों कि रुचि, वैयक्तिक भिन्नता और योग्यता के आधार पर व्यक्तिगत अधिगम योजना बनाने मे किया जा सकता है। अर्थात इस तकनीक के द्वारा अधिगम शिक्षण कार्य को कम समय में श्रेष्ठ परिणामों के साथ सफलता पूर्वक सम्पन्न किया जा सकता है। अधिगम शिक्षण कार्य का तात्पर्य केवल विद्यार्थियों को पुस्तकीय ज्ञान व सूचना प्रदान करना नही है अपितु एक सभ्य नागरिक का निर्माण करना है। सभ्य नागरिक के निर्माण हेतु विद्यार्थियों को पुस्तकीय ज्ञान के साथ-साथ मूल्यों का ज्ञान अर्थात मूल्य शिक्षा प्रदान करना भी आवश्यक है।

मूल्य शिक्षा से तात्पर्य किसी भौतिक वस्तु अथवा मानसिक अवस्था के उस गुण से है, जिसके द्वारा मनुष्य के किसी उद्देश्य अथवा लक्ष्य की पूर्ति होती है। मूल्य, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, आध्यात्मिक, राष्ट्रीय, भौतिक और कई प्रकार के होते है। इन मूल्यों कि प्राप्ति हेतु अथवा शिक्षण हेतु एक निश्चित वातावरण की अवश्यकत होती है। इन मूल्यों में से कुछ मूल्य जैसे ईमानदारी, सहानुभूति, सत्य, जिम्मेदारी, दया, संवेदनात्मकता, प्रेम, विश्वास, स्वच्छता,

राष्ट्रीय जवाबदेही आदि का हस्तांतरण कृत्रिम बुद्धिमत्ता के द्वारा प्रस्थापित करना कठिन प्रतीत होता है, क्योंकि इन मूल्यों के हस्तांतरण हेतु विद्यार्थियों का ऐसी अवस्था के साथ प्रत्यक्ष अनुभव आवश्यक है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के डिजिटल उपकरण के कारण यह संभव नही है। परंतु अनेक नकारात्मक मूल्य ऐसे भी है जिनका हस्तांतरण इस तकनीक कि सहायता से बहुत तीव्र गति से हो रहा है, जैसे हिंसा, झूठ, चोरी, चरित्रहीनता आदि।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तकनीकी ने मोबाईल के माध्यम से सब के पास एक आसान पहुँच बनाई है। इस तकनीकी ने ऑनलाइन गेम, सोशल मीडिया, रील और पॉर्न आदि के द्वारा बच्चों व युवाओं में नकारात्मक आदतों (मूल्यों) का प्रभाव विस्तृत किया है। ब्लू व्हेल चैलेंज गेम, इस गेम में खिलाड़ी को एक टास्क खत्म करने पर दूसरा टास्क दिया जाता है इस प्रकार एक-एक कर कुल 50 टास्क दिए जाते है। इस खेल को खेलते हुए खिलाड़ी अपने परिवार व दोस्तों से दूर होने लगता है व उसका स्वभाव झगड़ालू व हिंसक प्रवृत्ति या राष्ट्र विरोधी होता जाता है। वह गेम खेलने के लिए झूठ बोलने लगता है और टास्क खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है अर्थात् वह स्वयं या किसी अन्य कि हत्या भी कर सकता है। इस गेम को खेलने वाले अधिकांश खिलाड़ी आत्महत्या कर लेते थे। इसे देखते हुए इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्यौगिकी मंत्रालय भारत सरकार ने दिनांक 12/09/2007 को एक अड्वाइज़री जारी कर इस गेम से बचने के उपाय बताए तथा अंत में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। इसी प्रकार एक अन्य गेम PUBG है जिसमें एक साथ 100 खिलाड़ी अलग-अलग स्थानों से जुड़कर एक आभासी मैदान पर एक-दूसरे को मारते है। वर्तमान समय में यह गेम इतना लोकप्रिय है कि अधिकांश लोग सभी प्रकार की बंदूकों और जंग के हथियारों के बारे में जानते है और हिंसक प्रवृति उनके जीवन का अहम हिस्सा बन रहा है। इन गेम के संचालन के पीछे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया जा रहा है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), मनुष्य के प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखता है। यदि कोई व्यक्ति मोबाईल पर एक बार किसी चीज को खोजता है या उसके बारे में बात करता है तो उससे संबंधित अनेक विज्ञापन उसके समक्ष आने लगते है, जो उसकी जिम्मेदारियों जैसे मूल्यों के निर्वाह में बाधा उत्पन्न करते है। इसी प्रकार सोशल मीडिया पर रील्स बनाने व प्रसिद्ध होने के लिए व्यक्ति किसी भी प्रकार के रील्स बनाते है साथ ही साथ सॉफ्ट पॉर्न जैसे रील्स देखते है जो उनके चारित्रिक मूल्यों को प्रभावित करते है और यह तकनीक इसी प्रकार के अधिक

से अधिक रील्स दिखाते है जो उनके संस्कारों व चरित्र को दूषित करते हैं और रेप जैसे गुनाहों को अंजाम देते है। इसके अलावा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रयोग से पॉर्न व डीपफेक वीडियो के उत्पादन व संचार में वृद्धि हुई है, जो मनुष्य कि निजता का हनन करते है। डीपफेक विडिओ का शिकार अनेक अभिनेत्रियाँ जैसे राश्मिका मंधाना, काजोल आदि हुई है। इस प्रकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता नकारात्मक मूल्यों का विस्तार कर रही है।

उपरोक्त तथ्यों को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी समझते है। इसलिए हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स को दिए इंटरव्यू मे उन्होंने कहा है कि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसे शक्तिशाली तकनीक अप्रशिक्षित व अकुशल एवं नकारात्मक विचार के लोगों के हाथों में नहीं आनी चाहिए तथा (AI) को मैजिक टूल के रूप में इस्तमाल नहीं करना चाहिए।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ किया है और अध्यापकों के कार्यभार को कम किया है। अध्यापक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण शिक्षण की योजना पर कम समय खर्च कर उसके क्रियान्वयन में अधिक समय खर्च कर सकते है जो उनके शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता विद्यार्थियों के सभी प्रकार के प्रदर्शनों के मूल्यवान डाटा को एक स्थान पर व्यवस्थित रूप से संग्रहीत कर सकता है जिसका उपयोग छात्रों के प्रदर्शनों का विश्लेषण करने व प्रदर्शन को उन्नत करने के लिए किया जा सकता है। इस तकनीक का प्रयोग शिक्षा में जितनी उन्नति कर सकता है उतनी ही अवनति भी ला सकता है, क्योंकि इसके प्रयोग से विद्यार्थी अपने पेपर लिख सकते है और असाइनमेंट बना सकते है जो विद्यार्थियों को चोरी करने व अपने कर्तव्यों से विमुख करने की आदतों का निर्माण करते है। जिसके कारण शैक्षिक, नैतिक व चारित्रिक मूल्यों को खतरा उत्पन्न होता है।

वर्तमान समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) युक्त रोबोट शिक्षकों का प्रयोग हो रहा है। भारत में प्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता युक्त रोबोट शिक्षक केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित एक विद्यालय में लगाया गया है जिसका नाम आइरिस (iris) है। यह तीन भाषाओं अंग्रेजी, हिन्दी और मलयालम में कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के सवालों का जवाव देती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता सूचना व ज्ञान का सागर है, परंतु मूल्यों कि उत्पत्ति व हस्तांतरण में भावनाओं कि भूमिका अत्यधिक होती है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता भावनाओं से मुक्त है। अतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग भविष्य में अत्यधिक हो सकता है परंतु कुछ शिक्षाशास्त्रियों व दार्शनिकों ने पारंपरिक शिक्षण व मूल्यांकन प्रणाली के बारे में

पुनः सोचने का विचार किया है। ऐसे नए मूल्यांकन कार्यों के निर्माण के लिए कहा जिन्हे मशीने हल नही कर सके। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रयोग से शिक्षा व मूल्यों का अस्तित्व हमेशा बना रहेगा परंतु सकारात्मक मूल्यों के हस्तांतरण शायद भविष्य में संभव हो।

निष्कर्ष

वर्तमान युग तकनीकी और प्रौद्यौगिकी का है। इन आविष्कारों ने शिक्षा व्यवस्था के स्वरूप व प्रक्रिया को परिवर्तित किया है। शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी के एक भाग कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अत्यधिक प्रयोग किया जा रहा है। इसके प्रयोग से शिक्षा कि सार्वभौमिक पहुँच, समानता व समावेशी शिक्षा तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ज्ञान के हस्तांतरण जैसे अनेक उद्देश्यों को प्राप्त करना सरल व सुलभ हो गया है। परंतु यूनेस्को कि शिक्षा सहायक महानिदेशक स्तैफ़ानिया जियानिनी का कहना है कि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षा के लिए नए क्षितिजों व चुनौतियों का दरवाजा खोलती है परंतु हमें ये सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी होगी कि शिक्षा में, नई एआई प्रौद्योगिकियों का समावेश, हमारी शर्तों पर हो। क्योंकि यह तकनीक भावनाओं से मुक्त है और भावनाओ के अभाव में मूल्यों का हस्तांतरण संभव नहीं है परंतु भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमता को और अधिक विकसित करने पर शायद इसके द्वारा मूल्यों का हस्तांतरण संभव हो सके।

हिंदी संदर्भ

1. आर्य. डॉ. मोहन लाल. (2021). शिक्षक-शिक्षा में कृत्रिम बुद्धि (Artificial intelligence) : भूमिका एवं विकास. Journal of Interdisciplinary Cycle Research,
2. (AI): वरदान या अभिशाप – Drishti IAS
3. कृत्रिम बुद्धिमत्ता – Drishti IAS
4. UNESCO : कक्षाओं के लिए नया -AI रोडमैप। UNESCO: AI roadmap for classrooms संयुक्त राष्ट्र समाचार

अंग्रेजी संदर्भ

1. Zhang, ke.,Ÿ& Aslan, Ayse. Begum. (2021). AI technologies for education: Recent research & future directions.
2. Kengam, Jagadeesh. (2020). Artificial intelligence in Education.
3. Government of India. (2003). Statistical pocket book.

4. Government of India. (2016). Educational statistics at a glance.
5. India 2005 published by Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India
6. Retrieved From, Education is not only the foundation upon which our civilization has been built, but it is also the architect of humanity's future: PM Modi (narendramodi.in)
7. Retrieved From, Welcome to UGC, New Delhi, India
8. Retrieved From, https://udiseplus.gov.in/#/home
9. Retrieved From, Artificial Intelligence in Education: Exploring the Potential Benefits and Risks (researchgate.net)
10. Retrieved From, https://www.bhaskar.com/business/news/bill-gates-interviewed-pm-modi-132791078.html

डॉ. नरेन्द्र कुमार पाल
सहायक आचार्य
महात्मा गाँधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय), वर्धा
मोबाईल : 9265032070, ईमेल : drnavinsir@yahoo.in)

डॉ. चित्रा पाल
सहायक आचार्य
चौधरी एम.एड. कॉलेज, गांधीनगर, गुजरात

दीपक कुमार जाँगिड़
शिक्षार्थी
महात्मा गाँधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय), वर्धा

❑❑❑

घेरण्ड संहिता में उल्लेखित पारंपरिक प्राणायाम विधियों द्वारा मेटाबोलिक सिंड्रोम का प्रबंधन

मयंक उनियाल • डॉ. गजानन्द वानखेड़े

आधुनिकीकरण के इस युग में सम्पूर्ण विश्व जिस गति से गतिमान है उससे जहां एक ओर नित प्रतिदिन नई नई तकनीक, यंत्र, मनुष्य को प्राप्त हो रहें है वहीं इसके उपभोग तथा इसे प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा में मनुष्य स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से अवनति की ओर अग्रसारित है। मेटाबोलिक सिंड्रोम (मेट्स/MeTS) स्वयं में कोई विकार नहीं अपितु मोटापा, इंसुलिन प्रतिरोधकता, डिस्लिपिडेमिया एवं उच्च रक्तचाप स्थितियों का एक समूह है जो हृदय सम्बन्धी विभिन्न रोग, टाइप 2 मधुमेह, ब्रेन स्ट्रोक अथवा तीनों की गंभीरता में वृद्धि करता है। वैज्ञानिक शोध पुष्टि करते हैं कि शारीरिक गतिविधि एवं आहार परिवर्तन सहित जीवनशैली में हस्तक्षेप, मेटाबोलिक सिंड्रोम के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। योग एवं यौगिक अवधारणाएं प्राचीन समय से ही शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य का घोतक रही है। योग पद्धति शारीरिक क्रियाओं के रूप में आसन, श्वास-प्रश्वास नियंत्रण (प्राणायाम), मुद्रा ध्यान आदि को एकीकृत करती है। यह आलेख मेट्स के प्रमुख घटकों पर योग द्वारा पड़ने वाले प्रभावों का संश्लेषण करती है। शोध एवं साहित्य भी इंगित करता है कि नियमित योगाभ्यास इंसुलिन संवेदनशीलता, लिपिड प्रोफाइल, रक्तचाप विनियमन एवं शारीरक वजन प्रबंधन में योगदान दे सकता है। योग निहित प्राणायाम एवं अन्य शारीरिक गतिविधियां आयु सीमा से रहित परन्तु सम्पूर्ण मानव जाति के स्वास्थ्यवर्धन हेतु सुलभ है इस कारण योगाभ्यास मेट्स के निरोध एवं प्रबंधन दोनों के लिए एक महत्वकारी साधन है।

प्रस्तावना

मेटाबोलिक सिंड्रोम वर्तमान समय में भारत ही नहीं वरन विश्व में प्रचलित समस्त गंभीर समस्याओं में से एक है जिससे सर्वाधिक ग्रसित वयस्क तथा किशोरावस्था है। मेटाबोलिक सिंड्रोम उन पारस्परिक कारकों का एक समूह है जो कोरोनरी हृदय रोग (सीएचडी), कार्डियोवैस्कुलर एथेरोस्क्लेरोटिक विकारों (सीवीडी) तथा मधुमेह मेलेटस आदि में वृद्धि करते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण स्वयं को शारीरिक गतिविधियों से दूर रख, सुस्त एवं सुविधाजनक जीवनशैली का व्यापन है। मेटाबोलिक सिंड्रोम के मुख्य घटक रक्त में वसा का असामान्य स्तर (dyslipidaemia), उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन (एचडीएल) की कमी, उच्च रक्तचाप तथा अनियमित ग्लूकोज होमियोस्टेसिस आदि हैं इसके अतिरिक्त मोटापे को दीर्घकालिक विकारों का एक मुख्य कारक माना जाता है जो इंसुलिन प्रतिरोधकता तथा हाइपर इंसुलिनमिया, उच्च रक्तचाप, हाइपरलिपिडिमिया, टाइप 2 मधुमेह तथा एथेरोस्क्लेरोटिक हृदय रोग आदि मेटाबोलिक सिंड्रोम को प्रेरित करने में केंद्रीय भूमिका निभाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान अनुसार विकासशील देशों में होने वाली मृत्यु में से लगभग 75 प्रतिशत मृत्यु दीर्घकालिक अथवा असंक्रामक रोग (non communicable disease) के कारण होती हैं। (Santos -C, 2007)।

साहित्यिक पुनरावलोकन : मेटाबोलिक सिंड्रोम एवं योग के अन्य आयामों को केन्द्रित कर पूर्व में भी शोधकार्य हुए हैं जो योगाभ्यास द्वारा मेट्स प्रबंधन को सार्थकता प्रदान करते हैं। योग को स्वास्थ्य शिक्षा के साथ संयुक्त करने से मेट्स ग्रसित वयस्कों की जीवन गुणवत्ता में सुधार हो सकता है (Stephanie J. Sohl, 2016)। योग प्रीडायबिटीज, मोटापा व मेटाबोलिक सिंड्रोम के विभिन्न संकटकारी कारकों को कम करने में मध्यम रूप से प्रभावी पाया गया है। अध्ययनों ने टाइप 2 मधुमेह तथा गर्भकालीन मधुमेह मेलेटस में ग्लाइसेमिक नियंत्रण प्राप्त करने में योग की भागीदारिता को सिद्ध किया है। (Dukhabandhu Naik, 2015)। इसी प्रकार एक अन्य शोधानुसार सामान्य चिकित्सा देख-रेख एवं योग, चिकित्सा देखभाल की तुलना में अधिक प्रभावी है। अत: शोधकर्ताओं द्वारा यह अनुशंसा की जाती है कि योग चिकित्सा सुरक्षित है तथा मेटाबॉलिक सिंड्रोम के उपचार में लाभकारी हो सकती है। (S Prakash, 2019)

शोध प्रश्न : शोध कार्य सम्बन्धी प्रमुख शोध प्रश्न निम्नलिखित हैं।

- किस प्रकार शारीरिक अकर्मणता व अनियमित जीवनशैली अवांछनीय रोगों का आधार बनती हैं?

- क्या मात्र श्वास-प्रश्वास अभ्यास द्वारा उक्त समस्या की रोकथाम संभव है ?
- क्या यह प्राचीन ज्ञान वर्तमान मनोशारीरिक समस्याओं के निराकरण में सक्षम है?

अध्ययन के उद्देश्य : प्रस्तुत शोध कार्य के मुख्य उद्देश्य अधोलिखित हैं।

- घेरण्ड संहिता में चर्चित प्राणायाम विशेष की चर्चा करना जो उक्त समस्या में हितकारी हो सकते हैं।
- चर्चित प्राणायामों का मनोदैहिक परिपेक्ष में प्रस्तुतीकरण करना।
- प्राणायामों के वैज्ञानिक पक्ष की समीक्षा करना।
- अनुसंधानों के आधार पर प्राणायाम की प्रमाणिकता सिद्ध करना।
- वर्तमान जीवनशैली सम्बन्धी विकारों का योग विद्या द्वारा प्रबंधन कर इस भ्रान्ति का उन्मूलन करना कि योग मात्र एक आध्यात्मिक अभ्यास है।

शोध प्राविधि : प्रस्तुत शोध के अंतर्गत द्वितीयक श्रोतों एवं तथ्यों का प्रयोग किया गया है जिसके लिए अवलोकन विधि का चुनाव किया गया एवं उपर्युक्त तथ्यों एवं विचारों को सम्मिलित किया गया। इसी क्रम में शोध विषय से सम्बंधित साहित्य को गूढ़ अध्ययन, विभिन्न शोध पत्र एवं विशेषज्ञों द्वारा लिखित आलेखों, एवं विश्वसनीय व प्रमाणिक वेबसाइट जैसे पब मेड, गूगल स्कॉलर आदि के आलोक में इस कार्य को करने के प्रयास किये गए।

मेटाबोलिक सिंड्रोम की पृष्ठभूमि : मेटाबोलिक सिंड्रोम' शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1988 में रीवेन ने किया था जिसमें हृदय संबंधी आपत्तिकारक एवं मधुमेह सम्मिलित थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन (1998), द्वारा प्रस्तावित किया कि चयापचय सिंड्रोम मुख्यत: इंसुलिन प्रतिरोधकता व शरीर में सामान्य से अधिक ग्लूकोज की उपस्थिति के अतिरिक्त निम्न किन्हीं दो मापदंडों उच्च रक्तचाप, रक्त में ट्राइग्लिसराल की उच्च स्थिति (hypertriglyceridemia), कम एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कि कमी (low HDL-cholesterol), मोटापा (कमर/कूल्हे के अनुपात या बॉडी मास इंडेक्स (BMI) द्वारा मापित एवं मूत्र में यकृत द्वारा निर्मित एल्ब्यूमिन प्रोटीन की अधिकता (microalbuminuria) के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह संघ द्वारा चयापचय सिंड्रोम के विषय में पारित किये गए मुख्य मापदंडों में चयापचय सिंड्रोम के लिए मुख्य कारक अधिक वजन और मोटापा (विशेषकर पेट) है (2005)। एक शोध कार्य पुष्टि करता है कि मोटापे से ग्रसित वयस्कों से सम्बंधित 50% मामलों में

चयापचय सिंड्रोम का पाया जाता है। मेटाबोलिक सिंड्रोम हृदय संबंधी समस्याओं, टाइप 2 मेलिटस, मोटापा, इंसुलिन प्रतिरोधकता, ग्लूकोज टॉलरेंस, डिस्लिपिडेमिया व उच्च रक्तचाप का एक सम्मिश्रण है।

मेटाबोलिक सिंड्रोम के संकेत एवं लक्षण : मेटाबोलिक सिंड्रोम का मुख्य लक्षण मोटापे व अधिक वजन (BMI30 kg/m2) को प्रेरित करने वाला वसा ऊतक है जो मुख्य रूप से कमर व धड़ में संचित रहता है,। इसके अतिरिक्त उच्च रक्तचाप (सिस्टोलिक रक्तचाप130, डायस्टोलिक रक्तचाप 85mm/Hg), एचडीएल कोलेस्ट्रॉल में कमी (महिलाओं में <40 mg/dl, पुरुषों में<mg/dl), वीएलडीएल व ट्राइग्लिसराइड में वृद्धि (150 mg/dl) , भोजन किए बिना रक्त में ग्लूकोज का उच्च स्तर , इंसुलिन प्रतिरोध संबंधित स्थितियां जैसे हाइपरयूरिसीमिया, फैटी लीवर, पॉलीसिस्टिक डिम्बग्रंथि सिंड्रोम (PCOS), स्तंभन दोष आदि सम्मिलित हैं।

मेटाबोलिक सिंड्रोम के कारण : साधारणत: ऐसा माना जाता है कि आहार विहार अनियमितता मेटाबोलिक सिंड्रोम के विकास में योगदान देता है। इसके अतिरिक्त आनुवंशिकी, आयु वृद्धि, आहार, गतिहीन व अल्प शारीरिक गतिविधि, निद्रा एवं मनोदशा सम्बन्धी विकार, बाधित क्रोनोबायोलॉजी, मनोरोग औषध का उपयोग तथा अत्यधिक मद्यपान का उपयोग सम्मिलित हैं। संक्षिप्त में यदि व्याख्या की जाए तो अधिक वजन व मोटापा, गतिहीन जीवन शैली, शारीरिक निष्क्रियता, आयु वृद्धि, मधुमेह, कोरोनरी हृदय रोग (CHD), आदि हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन तथा लंग एंड ब्लड इंस्टिट्यूट (2004) के अनुसार निम्न पांच कारक मेटाबोलिक सिंड्रोम की आशंका के मुख्य कारक हैं। (ANANTHAKRISHN-N, 2017)

मेटाबोलिक सिंड्रोम में लाभकारी प्राणायाम : पूर्व में ही यह व्यक्त किया गया है कि मेटाबोलिक सिंड्रोम स्वयं में किसी प्रकार का विकार न होकर, विभिन्न शारीरक एवं मानसिक स्थितियों का एक समूह है जिसके उत्पत्ति के विभिन्न कारण हैं जिनका विवरण ऊर्ध्वलिखित हैं। योग मात्र एक शारीरिक व्यायाम ही नहीं वरन एक चिकित्सा पद्धति के रूप में भी स्वीकृत की जाती है। योग सम्बन्धी विभिन्न अवधारणाएं एवं साधनों का प्रयोग मनुष्य प्राचीनकाल से ही करता आ रही है। इस शोधपत्र में योग आधारित उन महत्वपूर्ण अवयवों की चर्चा की जा रही है जो मेटाबोलिक सिंड्रोम से रक्षण में महत्व्कारी भागीदारिका का निर्वहन करते हैं

सूर्यभेदी प्राणायाम : किसी भी ध्यानात्मक आसन की स्थिति को ग्रहण कर तर्जनी एवं अंगुष्ठ को मिलाकर दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर शरीर शिथिल बनाया जाता है। तर्जनी एवं मध्यमा को दोनों भौंहों के मध्य रखकर दायीं नासिका से श्वास लिया जाता है। तत्पश्चात दाहिनी नासिका को बंद कर श्वास रोककर कुम्भक, ठुड्डी को छाती पर लगाकर जालन्धर बन्ध एवं सीवन प्रदेश की मांसपेशियों का संकुचन कर मूलबन्ध किया जाता है। प्रारम्भिक स्थिति में आने हेतु सर्वप्रथम मूलबन्ध तत्पश्चात जालन्धर बन्ध को मुक्त किया जाता है। अंत में अनामिका को बायीं नासिका से हटाकर, बायीं नासिका से प्रश्वास की क्रिया की जाती है (नौटियाल, 2021)। अभ्यास को प्रभावी बनाने के लिए श्वास, दायीं नासिका का सम्बन्ध अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से है। (सरस्वती स. न., घेरण्ड संहिता)। इसी कारण दाहिनी नासिका से श्वास लेने पर अनुकंपी तंत्रिका तंत्र सक्रिय होता है (Shirley Telles, 1994) एवं ऑक्सीजन उपभोग में भी 37 प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है जिस कारण चयापचय में अविश्वनीय परिवर्तन प्राप्त होते हैं।

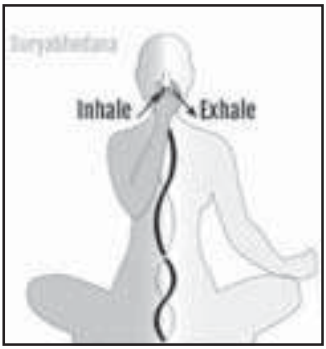

उज्जायी प्राणायाम : किसी भी ध्यानात्मक आसन की स्थिति को प्राप्त कर दोनों आँखों को बंद कर दोनों नासिकाओं से श्वास लेकर वायु मुख में ही राखी जाती है। तत्पश्चात कंठ को संकुचित कर छोटे शिशु द्वारा उत्पन्न खर्राटे की ध्वनि को सीमित तीव्रता के साथ उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है। इसके पश्चात श्वास को शरीर भीतर रोककर उपरोक्त वर्णित जालंधर बन्ध किया जाता है तथा अन्त में उपरोक्त वर्णित ध्वनि को उत्पन्न कर धीरे धीरे प्रश्वास किया जाता है (Swami Digambarji, 2022)। उज्जायी प्राणायाम अनिद्रा के रोग में अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध होता है (सरस्वती स. न., घेरण्ड संहिता, 2011)। यह मनोशान्ति एवं मन को चिंता एव तनाव मुक्त करने में अत्यंत लाभकारी अभ्यास है। मात्र तीन माह के अभ्यास में ही उज्जायी

स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित कर हृदय गति एवं श्वसन दर में भी कमी लाता है (Jitendra Mahour, 2017)। यह अभ्यास मानसिक तनाव में कमी कर मानसिक शान्ति में वृद्धि करता है। (Janika Epe, 2021)

शीतली प्राणायाम : किसी ध्यानात्मक आसन की स्थिति को प्राप्त कर दोनों आँखों को बन्द किया जाता है। तत्पश्चात् जिह्वा को मुख से बाहर निकालकर, एक गोलाकार नलीनुमा आकृति प्राप्त की जाती है। अब नलिका रूपी जिह्वा से श्वास लेकर, क्षणमात्र के लिए ही कुम्भक का लगाकर, जिह्वा को पूर्णरूप से अन्दर खींचकर, मुख बंद कर देने के पश्चात, नासिका द्वारा प्रश्वास किया जाता है (सहाय, 2023)। यही शीतली प्राणायाम की आवृति सम्पन्न की जाती है। शीतल अर्थात शीतलता प्रदान करने वाली यह क्रिया शारीरिक तापमान का ह्रास कर मानसिक शांति तथा हृदय धमनी रोग व उच्च रक्त चाप से सम्बंधित समस्याओं के उपचार में हितप्रद है (Krishan Kumar Suman, 2017)। शोधकार्य भी पुष्टि करते हैं कि शीतली प्राणायाम सिस्टोलिक रक्तचाप को कम करने का कार्य करता है (Prashanth Shetty, 2017)। हृदय के तीसरे कक्ष, बाएँ आलिन्द में प्रवेश करने वाली रक्त का शोधन कर करता है इस कारण हृदय से निकलकर यही रक्त सम्पूर्ण शरीर के ताप को नियमित करता है तथा अंतस्रावी तंत्र के साथ सामंजस्य बनाते हुए प्रजनन तंत्र सम्बन्धी हार्मोंस के स्राव का नियमन करता है। (सरस्वती स. श., 2005)

भस्त्रिका प्राणायाम : भस्त्रिका प्राणायाम हेतु सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन को ग्रहण कर दोनों आँखों को बंद किया जाता है। पूर्व वर्णित ज्ञान मुद्रा अथवा चिन मुद्रा प्राप्त कर लोहार की धौंकनी के समान नासिका द्वारा बिना किसी अवरोध के श्वास प्रश्वास की क्रिया का बारम्बार अभ्यास किया जाता है। सरलतम अभ्यास हेतु अभ्यासी को एक नासिका को पूर्णरूप से बंद कर, दूसरी नासिका से कम से कम 20 बार श्वास प्रश्वास करने के पश्चात् अंत में श्वास लेकर तत्पश्चात यथासंभव कुम्भक का प्रयास कर उसी

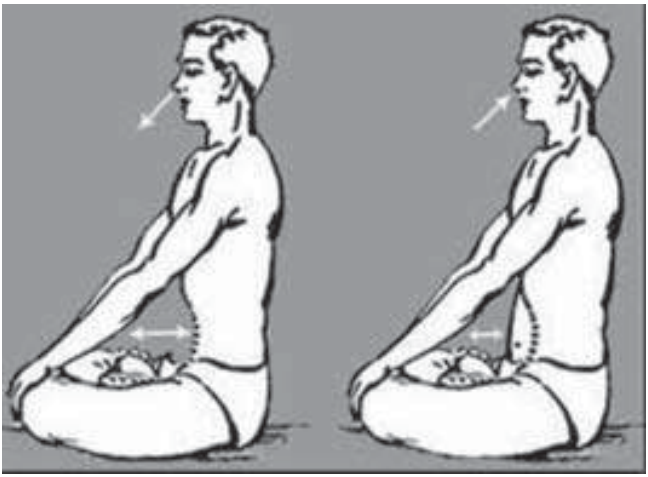

नासिका द्वारा प्रश्वास कर सकता है (राघवः, 2019)। भस्त्रिका का अभ्यास भी डायस्टोलिक रक्त चाप, औसत धमनी दबाव, हृदय दर, कार्डियक आउटपुट में वृद्धि व नाड़ी दर में कमी लाता है जिससे जीवन गुणवत्ता में सुधार प्राप्त होता है। (Chetry Dipak, 2023)। भस्त्रिका उदरीय अंगों की मालिश व जठराग्नि को प्रदीप्त कर पाचन तंत्र को बल देता है जिस कारण चयापचय संतुलित रहता है (Parmahansa)।

भ्रामरी प्राणायाम : भ्रामरी के अभ्यास हेतु सर्वप्रथम किसी ध्यानात्मक आसन में आकर, दोनों हथेलियों को ज्ञान मुद्रा अथवा चिनमुद्रा में दोनों घुटनों के ऊपर रखा जाता है। सम्पूर्ण अभ्यास में मुख बंद रहता है परन्तु दोनों जबड़े एक-दूसरे से संपर्क नहीं करते हैं। प्रारंभिक स्थिति को प्राप्त कर लेने के पश्चात् अब दोनों कोहनियों को मोड़कर, तर्जनी अथवा मध्यमा अंगुली से अपने दोनों कानों को बंद कर दिया जाता है। अभ्यासी को अपने ध्यान को भ्रूमध्य पर केन्द्रित कर, नासिका से श्वास लेकर, नासिका से ही प्रश्वास करते हुए भ्रमर के गुंजन के समान मृदु, दीर्घ, व्यवधान रहित ध्वनि उत्पन्न की जाती है जो कि अभ्यासी तक ही सीमित

होनी चाहिए। गुंजन से उत्पन्न कंपन्न की अनुभूति कर सामान्य श्वास-प्रश्वास द्वारा शरीर को विश्राम देना चाहिए (सरस्वती स. न., घेरण्ड संहिता)। भ्रामरी प्राणायाम में उत्पन्न नाद शान्तिदायक एवं मानसिक तनाव, चिंता, मानसिक उत्तेजना का शमन करने के साथ ही उच्च रक्तचाप एवं हृदय रोगों में हितकर है। यह अनुकंपी तन्त्रिका तंत्र को प्रभावित कर सूक्ष्म समय में ही मानसिक विश्राम की अवस्था को प्रेरित करता है (Mahesh kumar kuppusamy, 2018)। भ्रामरी गामा तरंगो की उत्पत्ति में योगदान देती है तथा इसके अभ्यास से अनिद्रा को दूर कर बढ़िया निद्रा प्रतिरूप (better sleep pattern) को प्रेरित करता है। (Niroula, 2023)।

मूर्छा प्राणायाम : मूर्च्छा का अर्थ अभ्यासी का विषय-जगत की चेतना से सम्बन्ध टूट जाने से है। किसी भी ध्यानात्मक अभ्यास की स्थिति को प्राप्त कर दोनों आँखों को बंद कर लिया जाता है। तत्पश्चात दोनों नासिकाओं द्वारा श्वास लेकर सिर को धीरे-धीरे भूमि से ऊपर आकाश की ओर 450 का कोण बनाते हुए इस प्रकार से उठाया जाना चाहिए कि सिर का इस कोण तक पहुंचने से पूर्व दोनों आँखें खुल जाए। अब अभ्यासी द्वारा शाम्भवी दृष्टि (दृष्टि को दोनों भौहों के मध्य एकाग्र कर स्व आत्मा पर ध्यान करना) को प्राप्त कर कुम्भक का यथाक्षम प्रयोग किया जाता है। अन्त में धीरे-धीरे प्रश्वास करते हुए सिर को सामने की दिशा में लाकर दोनों आँखों को बंद कर दिया जाता है (भारती, 2028)। मूर्च्छा प्राणायाम के अभ्यास से कैरोटिड साइनस (विज्ञाननाडी) संकुचित होती है जो मस्तिष्क को विश्राम अवस्था की प्रेरित करती है साथ ही इस नाड़ी पर पड़ने वाला दबाव रक्तचाप, हृदयदर में कमी के अतिरिक्त रक्तवाहिकाओं का विस्तार भी करती है तथा मानसिक चिंता से भी मनुष्य को मुक्त कर सुखानुभूति करवाता है। (सरस्वती स. श., 2005)

निष्कर्ष : उपरोक्त प्राणायाम विधियों का गूढ़ अध्ययन एवं व्यवहारिकता में प्रयोग किये जाने एवं उन पर आधारित शोधकार्यों से यह सिद्ध होता है कि प्राणायाम विधियां मात्र श्वास-प्रश्वास रूपी व्यायाम नहीं अपितु स्वयं में विभिन्न प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाली एक कुंजी है। एक ऐसी कुंजी जिसका आयु, लिंग वर्ग से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नही है। मनीषियों द्वारा प्रदत्त यह विद्या वर्तमान में भी विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक विकारों के

प्राकृतिक हल के रूप में उपस्थित है जिसे प्रत्येक व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में अनुसरित कर आरोग्यता एवं दीर्घायु को प्राप्त होना चाहिए।

सन्दर्भ-ग्रन्थ सूची :

ANANTHAKRISHN-N, R. (2017). THE EFFECT OF YOGIC EXERCISE ON MET-BOLIC SYNDROME-MONG STRESS PRONECOLLEGE STUDENTS.

Chetry Dipak, C. A. (2023). 139. Chetry DiEffects of Bhastrika Pranayama (yoga bellows-type breathing) on pulmonary, cardiovascular, and psychological variables : A systematic review. Yoga Mimmsa, 1-10.

Dukhabandhu Naik, N. T. (2015). Yoga- a potential solution for diabetes metabolic syndrome. Indian Journal of Medical Research, 753-756.

Janika Epe, R. S. (2021). Different Effects of Four Yogic Breathing Techniques on Mindfulness, Stress, and Well-being. OBM² Integrative and Complementary Medicine.

Jitendra Mahour, P. V. (2017). Effect of Ujjai Pranayama on cardiovascular autonomic function tests, . National Journal of Physiology, Pharmacy and Pharmacology, 391-395.

Krishan Kumar Suman, D. V. (2017). Yoga Therapy. New Delhi: Lotus Press Publishers Distributors .

Mahesh kumar kuppusamy, D. K. (2018). Effects of Bhramari Pranayama on health - A systematic review. Journal of Traditional and Complementary Medicine, 11-16.

Niroula, B. (2023). The Effects of Bhramari Pranayama on Stress Reduction, Cognitive Function, and Sleep Quality. Research Gate.

Parmahansa, S. Y. (n.d.). First Steps to Higher Yoga. New Delhi: Yoga Niketan Trust.

Prashanth Shetty, K. K. (2017). Effects of Sheetali and Sheetkari Pranayamas on Blood Pressure and -utonomic Function in Hypertensive Patients. Integrative Medicine : - Clinical's Journal, 32-37.

S Prakash, -. M. (2019). MET-BOLIC SYNDROME EFFECT OF YOG-INTERVENTION. International Journal of Recent Scientific Research, 36042-36045.

Santos -C, B. H. (2007). Impact of metabolic syndrome definitions on prevalenceestimates: a study in a Portuguese community. Diab Vasc Dis Res.

Shirley Telles, R. N. (1994). Breathing Through - Particular Nostril Can -lter Metabolism and -utonomic -ctivites,. Indian Journal of Physiology Pharmacology, 133-137.

Stephanie J. Sohl, K. -. (2016). Yoga for Risk Reduction of Metabolic

Syndrome: Patient-Reported Outcomes from a Randomized Controlled Pilot Study. Evidence-based Complementary and -lternative Medicine .

Swami Digambarji, D. M. (2022). Ghernda Samhita. Lonavala: Kaivalyadham S.M.Y.M. Samiti.

नौटियाल, ड. र. (2021). घेरण्ड संहिता . नई दिल्ली : किताब महल .

भारती, प. स. (2028). घेरण्ड संहिता. वाराणसी: चौखम्बा ओरियन्टालिया .

राघव:, ड. र. (2019). घेरण्ड संहिता . नई दिल्ली: चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान .

सरस्वती, स. न. (2011). घेरण्ड संहिता . मुंगेर, बिहार, भारत: योग पब्लिकेशन.

सरस्वती, स. न. (प.व.). घेरण्ड संहिता . मुंगेर, बिहार, भारत : योग पब्लिकेशन ट्रस्ट.

सरस्वती, स. श. (2005). पूर्ण योग . नई दिल्ली : श्रीकुंज सद्भावना .

सहाय, ज. (2023). घेरण्ड संहिता. वाराणसी: चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन .

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/metabolic-syndrome/symptoms-causes/syc-20351916

https://www.nhlbi.nih.gov/health/metabolic-syndrome

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459248/

https://www.heart.org/en/health-topics/metabolic-syndrome/about-metabolic-syndrome

https://www.webmd.com/heart/metabolic-syndrome/metabolic-syndrome-what-is-it

मयंक उनियाल

शोधार्थी,

स्पर्श हिमालय विश्वविद्यालय, देहरादून (उत्तराखंड)

ई मेल : makbuddy1110@gmail.com

मोबाइल नंबर : 7417023990

डॉ. गजानन्द वानखेड़े

सहायक प्राचार्य,

स्पर्श हिमालय विश्वविद्यालय, देहरादून (उत्तराखंड)

ई मेल : wankhedegajanandgmail.com

मोबाइल नंबर : 83077825670

❑❑❑

राष्ट्रीय कार्यसूची ''विकसित भारत @2047'' की कार्यसिद्धी में शैक्षणिक संस्थानों से अपेक्षाएँ

डॉ. नरेन्द्र कुमार • डॉ. ऐश्वर्य राणा

विकसित भारत @2047, भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षाओं से पूर्ण परियोजना है। वर्ष 2047 में देश की स्वतंत्रता की शताब्दी तक, राष्ट्र को एक विकसित इकाई के रूप में परिणतकरने का महत्वपूर्ण प्रयास है। यह परियोजना आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, पर्यावरण स्थिरता और सुशासन जैसे विभिन्न पहलुओं को शामिल करती है। यह दृष्टिकोण, शिक्षा को प्राथमिकता देकर और इसकी गुणवत्ता, पहुंच और प्रासंगिकता में निवेश करके ही हासिल किया जा सकता है। शिक्षा मानव पूंजी विकसित करने, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने, पर्यावरणीय स्थिरता को आगे बढ़ाने, मूल्यों और नैतिकता को स्थापित करने और आजीवन सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने में मददगार साबित होती है। यह ''विकसित भारत @2047'' का मूलभूत स्तंभ है। भारत अपने सभी नागरिकों के लिए एक समृद्ध, समावेशी और स्थिर भविष्य का निर्माण कर सकता है। इस प्रकार भारत अपने लोगों की क्षमता को एवं आर्थिक विकास को आगे बढ़ा सकता है और भावी पीढ़ियों के लिए एक समृद्ध और न्यायसंगत समाज का निर्माण कर सकता है। शिक्षा प्रणाली के अतिरिक्त, शैक्षणिक संस्थानों और शिक्षकों को भी भारत के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और इसके अन्तर्गत ''विकसित भारत @2047'' के दृष्टिकोण में योगदान देना है। शैक्षिक संस्थान, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके, व्यावसायिक विकास में निवेश करके और शैक्षिक उत्कृष्टता और समानता का समर्थन करने वाली नीतियों का समर्थन करके, ''विकसित भारत @2047'' को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अपने समर्पित प्रयासों के माध्यम से, शैक्षणिक संस्थान और उनमें कार्यरत शिक्षक, भारत के लिए समृद्ध, न्यायसंगत और एक संवहनीय भविष्य के निर्माण के लिए योगदान दे सकते हैं।

प्रस्तावना

11 दिसंबर 2023 को देष के प्रधानमंत्री ने भारत के युवाओं के लिए ''विकसित भारत *@2047*'' अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान आजादी के 100वें वर्ष में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए शुरू किया गया। अभियान में विकास के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिसमें आर्थिक विकास, पर्यावरण स्थिरता, सामाजिक प्रगति और सुशासन अहम पहलू हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार, भारत 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करेगा, प्रत्येक नागरिक को पक्का घर और पाइप से पानी उपलब्ध कराएगा, ड्रोन के साथ महिलाओ, किसानों को सशक्त बनाएगा, जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दवाओं की संख्या बढ़ाएगा और हरित और गतिशील विकास नीतियों को अपनाएगा। विकसित भारत *@2047* का उद्देश्य औपनिवेशिक विरासत को दूर करना, भारत की भू-राजनीतिक स्थिति को मजबूत करना और अन्य देशों के साथ अपने राजनीतिक संबंधों को बढ़ाना है। विकसित भारत *@2047* सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक संकल्प है, जो भारत के लोगों को, खासकर युवाओं को प्रेरित करता है, जो अपने और अपने देश के लिए बेहतर भविष्य की आकांक्षा रखते हैं। ''राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020'' भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक नया युग लेकर आई है, जो ''विकसित भारत *@ 2047*'' में विकास के लिए एक मजबूत आधार स्थापित करने का प्रयास कर रही है। एनईपी 2020, द्वारा प्रदान की गई रणनीतिक योजना न केवल वर्तमान समस्याओं से निपटने में कामगार साबित हो रही हैं अपितु शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे असरदार बदलाव लाने का प्रयास भी कर रही है जो वर्तमान और भविष्य दोनों को कारगर साबित हो। एनईपी 2020 द्वारा अपनाए गए पाठ्यक्रम में भारी बदलाव की दिशा में काम किये जा रहा है, जिससे इक्कीसवीं सदी के समाज में लचीलापन, व्यापकता और प्रासंगिकता को बढ़ावा मिलें। शैक्षणिक संस्थान और शिक्षक इस परिवर्तनकारी प्रक्रिया में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते है।

सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर :

प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना इसका दायित्व है। शैक्षिक अवसरों में लिंग, सामाजिक-आर्थिक और क्षेत्रीय असमानताओं को संबोधित करते हुए समावेशिता पर ध्यान देना भी इसका दायित्व है। समसामयिक परिस्थिति में देश की शिक्षा प्रणाली को प्राथमिकता देनी होगी और प्रत्येक नागरिक को जिम्मेदार, समस्या समाधानकर्ता बनाने वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था

करनी होगी। केवल नामांकन और योग्यता से प्राप्त की गई डिग्री ही लक्ष्य होना चाहिए, न कि पाठ्यक्रम।

समग्र शिक्षा:

शिक्षकों को छात्रों की शैक्षणिक योग्यता के अलावा उनकी बुद्धिमत्ता, रचनात्मकता और सामाजिक क्षमताओं को प्रोत्साहित करते हुए समग्र विकास पर जोर देना चाहिए। पाठ्यक्रम में क्षमता वृद्धि और कौशल विकास पाठ्यक्रमों के अंतर्निहित घटक होने चाहिए। खेल, कला, पाठ्येतर गतिविधियाँ और सामुदायिक सेवा सभी को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकता है ताकि समाज में मूल्यवान योगदान देने वाले लोग तैयार किये जा सके जो अपना बहुमूल्य योगदान समाज की बढ़ोतरी में दे सके। नैतिक व्यवहार, सत्यनिष्ठा और सामाजिक जिम्मेदारी तथा चरित्र निर्माण के महत्व पर जोर दिया जाना चाहिए।

भारत के प्राचीन ऋषियों, साहित्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जागरूकता:

प्राचीन ज्ञान में नई पीढ़ी के विकास की अपार संभावनाएं हैं। वेद, आयुर्वेद और योग सहित प्राचीन साहित्य का ज्ञान छात्रों को प्रदान किया जाना चाहिए, और उन्हें स्थायी जीवन पद्धतियों को अपनाने के लिए वसशक्त बनाने के लिए प्राचीन ज्ञान के मूल मूल्यों को ध्यान में रखते हुए परियोजनाएं विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अनुसंधान, नवाचार और सामुदायिक पहुँच के माध्यम से प्राचीन ज्ञान, विकसित भारत *@2047* के लक्ष्यों के अनुरूप एक संतुलित समाज को बढ़ावा दे सकता है।

कौशल विकास और उद्यमिता शिक्षा:

कौशल विकास एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न कार्यों, विशेषकर कार्यस्थल में अधिक कुशल और प्रभावी होने के लिए कौशल और दक्षताओं की एक विस्तृत शृंखला को प्राप्त करना, सुधारना और बढ़ाना शामिल है। इसलिए, भारतीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों को सीखने के भविष्य को अपनाते हुए, कौशल वृद्धि को प्राथमिकता देते हुए और व्यक्तियों के मूल्य पर जोर देकर कौशल विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान देना चाहिए। नौकरियों के सभी क्षेत्रों में नियोक्ताओं द्वारा उद्यमशीलता कौशल को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। रोजगार योग्यता उन लोगों से बहुत अधिक जुड़ी होती है जिनके पास विश्लेषणात्मक सोच, सामूहिक कार्य, रचनात्मकता, मौलिकता, पहल आदि के

साथ मुख्य योग्यता के रूप में स्पष्ट संचार कौशल होते हैं। ये कौशल भविष्य में आवश्यक मुख्य दक्षताओं के रूप में अनुमानित 21वीं सदी के कौशल के बिल्कुल अनुरूप हैं। शिक्षा ही वह कुंजी है जो जीवन का द्वार खोलती है, मानवता का विकास करती है और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देती है। आर्थिक विस्तार और रोजगार सृजन में तेजी लाने के लिए छात्रों के बीच नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। अपने छात्रों में उद्यमशीलता के दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षकों को परियोजना-आधारित शिक्षा, समस्या-समाधान अभ्यास और वास्तविक दुनिया की कठिनाइयों से अवगत कराना शामिल करना चाहिए। इच्छुक व्यवसाय मालिकों को संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना और सलाह देना उन्हें सफलता की राह पर ले जाने में मदद कर सकता है। एक ओर, उद्यमिता रोजगार सृजन, आर्थिक विकास, नवाचार और प्रौद्योगिकी, निवेश और सामाजिक-आर्थिक संतुलन और कई अन्य विकासात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करके एक समावेशी वातावरण विकसित करने में मदद करेगी। दूसरी ओर, यह देश को गरीबी, भुखमरी और सांस्कृतिक और क्षेत्रीय अंतर को मिटाने में मदद करेगा, जो अंततः ''आत्मनिर्भर भारत'' के माध्यम से ''विकसित भारत'' के दृष्टिकोण को प्राप्त करेगा।

रोजगार सृजनः

रोजगार सृजन, समावेशी और सतत् आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए हमारी शिक्षा प्रणाली को वास्तविक जीवन की समस्या-समाधान कौशल, उद्यमशीलता विकास और ज्ञान की प्यास को बढ़ावा देने पर जोर देना चाहिए। सतत् आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए सभी व्यक्तियों के लिए किफायती काम उपलब्ध कराने के महत्व पर जोर दिया जाना चाहिए।

सर्वोत्तम प्रथाओं की संस्कृति को बढ़ावा देनाः

उच्च गुणवत्ता वाले व्यवसाय की रचना मार्गों और कार्यान्वित करना, स्पष्ट रूप से व्यक्त लक्ष्यों के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर जोर देना, शैक्षिक उत्कृष्टता पर एक सामान्य केन्द्रीत होना, समग्र शैक्षिक अनुभव को बढ़ाने का लक्ष्य, छात्र की सफलता को बढ़ावा देना और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करना और विश्वविद्यालयों का संचालनकरना मुख्य पहलू है। सभी नागरिकों के विकास से ही भारत का विकास होगा, इसलिए वैज्ञानिक और नैतिक मूल्यों पर आधारित सर्वोत्तम जीवन प्रथाएं सभी नागरिकों तक पहुंचनी चाहिए। उदाहरण के

लिए-भारत देश हृदय संबंधी समस्याओं, कैंसर, मधुमेह और मोटापे जैसी कई पुरानी बीमारियों में अग्रणी है। इन बीमारियों का जमीनी आधार हमारी जीवनशैली है। बहुत से लोग इन बीमारियों और उनसे बचने और प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम जीवनशैली के विशय में पर्याप्त रूप से शिक्षित नहीं हैं। इसलिए, शिक्षकों को जागरूकता फैलाने और समाज को बेहतर बनाने के लिए विविध कार्यक्रमों के माध्यम से आम जनता तक पहुंचना चाहिए।

सतत् प्रथाओं को बढ़ावा देना:

प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए पर्यावरण-अनुकूल और धारणीय प्रथाओं को लागू करना महत्वपूर्ण है। जैव प्रौद्योगिकी नवाचार और हरित प्रौद्योगिकियां अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को संचालित करने वाले नवीन उत्पादों एवं सेवाओं का निर्माण करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देती हैं। भारत सहित विश्व के सामने सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक पर्यावरणीय गिरावट है। शिक्षकों का यह कर्तव्य है कि वे छात्रों को धारणीय प्रथाओं और पर्यावरण संरक्षण के बारे में सिखाएँ। पाठ्यक्रम में पर्यावरण अध्ययन को शामिल करके, पर्यावरण-जागरूकता अभियानों की योजना बनाकर, कचरा प्रबंधन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग जैसे व्यवहारों को प्रोत्साहित करके छात्रों को पर्यावरण की ओर जिम्मेदार बनाया जा सकता है।

शिक्षा में समावेशिता:

भारत सांस्कृतिक, भाषाई और पारंपरिक रूप से विविधतापूर्ण देश है। शिक्षकों को एक स्वागत योग्य माहौल बनाना चाहिए जहां विविधता का सम्मान किया जाता है और छात्रों को व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान करना सिखाया जाता है। इतिहास एक चरण से दूसरे चरण तक की प्रगतिशील यात्रा है। इसके एक भाग को मिटाने या संपादित करने से एक प्रगतीषील भविष्य का विनाष हो जाएगा।

शिक्षक सहानुभूति और अंतर-सांस्कृतिक समझ को प्रोत्साहित करके एक अधिक शांतिपूर्ण और एकजुट देश बनाने में मदद कर सकते हैं। हमें एक समावेशी और सुलभ शैक्षिक वातावरण सुनिश्चित करते हुए विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को सहायता प्रदान करनी चाहिए। समावेशिता और विविधता के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को संबोधित करना नई सदी की आवश्यकता है।

एक समावेशी पाठ्यक्रम प्रचलित भव्य आख्यानों को चुनौती देने और

अधिक न्यायसंगत शिक्षण वातावरण का पोषण करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करता है। विभिन्न दृष्टिकोणों, ऐतिहासिक संदर्भों और सांस्कृतिक परंपराओं को पाठ्यक्रम सामग्री में शामिल करके, शिक्षक छात्रों को मानव अस्तित्व की जटिलताओं की गहरी समझ हासिल करने में सक्षम बनाते हैं। यह न केवल शैक्षिक यात्रा को बढ़ाता है बल्कि सहानुभूति, आलोचनात्मक सोच और वैश्विक नागरिकता की भावना को भी बढ़ावा देता है, जो 'वसुधैव कुटुंबकम' की अवधारणा का प्रतीक है।

डिजिटल साक्षरता:

डिजिटल युग में आधुनिक अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए व्यक्ति के पास डिजिटल साक्षरता होनी चाहिए। शिक्षकों को छात्रों को वे डिजिटल दक्षताएँ प्रदान करने की आवश्यकता है जिनकी उन्हें आवश्यकता है, जैसे कंप्यूटर साक्षरता, कोडिंग और डिजिटल कौशल। ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन संसाधनों और डिजिटल टूल के माध्यम से कक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंचा जा सकता है और छात्रों को डिजिटल भविष्य के लिए तैयार किया जा सकता है।

अंत:विषय अनुसंधान:

अंत:विषय अनुसंधान अध्ययन स्नातकोत्तर मानविकी विभागों के भीतर समावेशी पाठ्यक्रम की रचना डिजाइन और शैक्षिक अनुभव को आकार देने और पोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंत:विषय अनुसंधान अध्ययन में कई दृष्टिकोणों से जटिल मुद्दों से निपटने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विद्वानों के बीच सहयोग शामिल है, जो इसे अकादमिक क्षेत्र में समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए और अधिक उपयुक्त बनाता है। यह उन विषयों की खोज करता है जो पारंपरिक अनुशासनात्मक सीमाओं से परे हैं। समाजशास्त्र, इतिहास, साहित्य, मीडिया और सांस्कृतिक अध्ययन जैसे विविध क्षेत्रों से अंतदृष्टि को एकीकृत करके, शिक्षक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों की व्यापक समझ विकसित कर सकते हैं। यह अंत:विषय दृष्टिकोण पाठ्यक्रम बनाने वालों को अध्ययन सामग्री में व्यापक दृष्टिकोण और पद्धतियों को शामिल करने में सक्षम बनाता है, जिससे छात्रों के शैक्षिक अनुभव समृद्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त, अंत:विषय अनुसंधान अध्ययन विविध पृष्ठभूमि के विद्वानों के बीच सहयोग और संवाद को बढ़ावा देता है, जो शिक्षा जगत के भीतर समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है।

यह एक ज्ञान-संजाल की स्थापना को बढ़ावा देता है, जो विचारों और

संसाधनों के आदान-प्रदान में मददगार साबित होता है। अनुशासनात्मक सीमाओं के पार सहयोग से शिक्षक स्थापित शक्ति गतिशीलता को चुनौती दे सकते हैं और एक समावेशी स्थान बना सकते हैं जहां कम प्रतिनिधित्व वाली आवाजों को प्रोत्साहित किया जा सकता है और सुना जा सकता है। इसके अलावा, यह शिक्षकों को मौजूदा पाठ्यक्रम के भीतर कमियों या पूर्वाग्रहों को पहचानने और संबोधित करने में सहायता करता है। गंभीर रूप से विश्लेषण करके कि विभिन्न विषय कुछ प्रसंगो पर कैसे दृष्टिकोण रखते हैं एवं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, शिक्षक उन क्षेत्रों को इंगित कर सकते हैं जहां उन दृष्टिकोणों को कम महत्व दिया जा सकता है। जिनकी तरफ पक्षपातपूर्ण झुकाव ज्यादा देखने को मिलता है। यह जागरूकता अधिक विचारशील और सूक्ष्म पाठ्यक्रम डिजाइन को सक्षम बनाती है, जिससे विविध महत्वपूर्ण सुविधाजनक बिंदुओं का न्यायसंगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है।

सामुदायिक सहभागिता:

शिक्षकों को छात्रों को जानकार, जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जो नागरिक भागीदारी और सामाजिक गतिविधि को प्रोत्साहित करके समाज की उन्नति में सक्रिय योगदान देते हैं। सहानुभूति, नैतिकता और नैतिक नेतृत्व जैसे गुण पैदा करने से छात्रों को अपने समुदायों में परिवर्तन प्रतिनिधि के रूप में काम करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। स्कूलों और स्थानीय समुदायों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करें। युवा पीढ़ी के विकास के लिए साझा जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देते हुए, शैक्षिक पहल में माता-पिता और समुदाय के सदस्यों को शामिल करें।

उद्योगों और संस्थानों के साथ साझेदारी:

शिक्षा जगत और रोजगार के बीच के अंतर को कम करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों और उद्योगों के बीच साझेदारी स्थापित होनी चाहिए। नवाचार और ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग आवश्यक है। जीवंत भारत का भविष्य अब उन शिक्षकों के हाथों में है जिन पर 50 प्रतिशत आबादी की प्रतिभा को निखारने की जिम्मेदारी है। एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में, यह शिक्षक ही है जो एक ऐसी पीढ़ी को आकार दे सकते है, ढाल सकते है और तैयार कर सकते है जो न तो बेरोजगार हो और न ही अल्प नियोजित हो। शिक्षक, परिवर्तन के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में, युवा पीढ़ी में ज्ञान, कौशल और मूल्यों को स्थापित करके किसी देश के विकास पथ को प्रभावित कर सकते हैं।

निष्कर्ष:

भारत के लिए यह यात्रा कुछ हद तक कठिन है। भारत एक विकसित देष बनने का सपना देखता है लेकिन कड़वी हकीकत यह है कि विभिन्न प्रयास दौराहे पर आकर ठहर जाते है, जहां हर एक कदम सामाजिक और आर्थिक ढांचे पर आद्यात करता है। शिक्षा उस अवधारणा की नींव है जिसके चारों ओर कई समस्याओं का उत्तर केंद्रित है। यह आधारशिला के रूप में कार्य करता है जिसके चारों ओर समाज अपना भविष्य बनाता हैं और तात्कालिक समस्याओं से निपटता हैं। सकारात्मक परिवर्तन और सतत् विकास को बढ़ावा देने वाला प्रमुख कारक शिक्षा है। यह देखा गया है कि गरीबी और असमानता से लेकर बेरोजगारी, पर्यावरण क्षरण, स्वास्थय देखभाल तक हर चीज के लिए जिम्मेदार समाज में बसती असमानता है। शिक्षक के रूप में, हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि हम एक विकसित राष्ट्र की दिशा में भारत की यात्रा में कैसे योगदान दे सकते हैं। हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि हम अपने-अपने क्षेत्र में प्रगति की गति को कैसे तेज कर सकते हैं अथवा इसे हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और निरंतर सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ, शिक्षक विकसित भारत /2047 के राष्ट्रीय कार्यसूची के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

सन्दर्भ:

1. https://cleartax.in/s/viksit-bharat-2047
2. https://doi.org/10.5281/zenodo.5713757
3. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf
4. https://innovateindia.mygov.in/viksitbharat2047/viksitbharat2047-dashboard/
5. ttps://www.news18.com/opinion/opinion-viksit-bharat-prime-minister-narendramodis-vision-for-a-developed-india-8824143.html
6. https://loksabhadocs.nic.in/Refinput/New_Reference_Notes/English/16012024_112431_102120474.pdf

डॉ. नरेन्द्र कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षा विभाग,
राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय,
अजमेर

डॉ. ऐश्वर्य राणा
असिस्टैन्ट प्रोफेसर; राजनीति विज्ञानद्ध
डॉ. पी. डी. बी. एच. राजकीय
स्नातकोत्तर महाविद्यालय
कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखंड)

❑❑❑

उत्कृष्ट कला एवं स्थापत्य का उदाहरण : उदयगिरि की गुफायें

• डॉ. मोना जैन

उदयगिरि पहाड़ी बेसनगर से तीन किलोमीटर और सांची से सीधे मार्ग पर छः किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका सामान्य दिग्-विन्यास उत्तर-पश्चिम से दक्षिण पूर्व हैं। प्रातः कालीन सूर्य की किरणें सीधी गुफाओं को प्रकाशित करती हैं, संभवतः इसी कारण इस स्थान का नाम उदयगिरि पड़ा। यह पहाड़ी नरम श्वेत बालुकाश्म की है, जिसमें समतल परतें हैं, जिसके कारण इसके पूर्वी भाग में अनेक शैलकृत गुफाओं का निर्माण सहज ही हो सका हैं। यहाँ पर कुल बीस गुफायें हैं, जिनमें अधिकांश छोटी हैं। इन गुफाओं को देखने से आभास होता है कि प्रत्येक गुफा के सामने मौलिक रूप से मंडप रहे होंगें। इन गुफाओं में गुप्तकालीन कला का क्रमिक विकास मिलता हैं। इन बीस गुफाओं में दो गुफायें जैन धर्म तथा शेष हिन्दू धर्म की हैं। इस पहाड़ी पर मौर्य, युंग और नागकालीन अवशेष भी देखे जा सकते हैं, जिनमें बौद्ध स्तूप भी हैं।

गुफा 1 को हम बनावटी गुफा मंदिर कह सकते हैं जिसकी एक दीवार तथा मंडप बनाया हुआ हैं किन्तु इसकी छत प्राकृतिक हैं। यहाँ एक गर्भगृह तथा चार स्तम्भों पर टिका मण्डप हैं। गर्भगृह की मूल प्रतिमा अब नष्ट हो चुकी हैं, जो पीछे की दीवार में थी। अब उसके स्थान पर एक अन्य जैन प्रतिमा हैं। शिल्पशास्त्र की दृष्टि से यह गुफा को अत्यंत उत्कृष्ट कहा जा सकता हैं, क्योंकि इस गुफा में गुप्तकाल के मंदिर स्थापत्य का प्रारंभिक रूप दिखायी देता हैं।

गुफा 2 और 3 का आकार अत्यंत छोटा है और ये दोनों गुफायें बहुत अधिक अपक्षीण हो चुकी हैं।

गुफा 4 के द्वार पर एक वीणाधारी पुरूष की आकृति हैं, कनिंघम ने इस गुफा को बीना गुफा के नाम से संबोधित किया था। गुफा 3 से थोड़ी दूरी पर दायीं तरफ यह गुफा हैं। इस गुफा में गर्भगृह और इसका द्वार अलंकृत है। इसके

द्वार-स्तंभों कै ऊपर का लिंटल स्तंभों को दोनों तरफ से ढँके हुए हैं। द्वार चौखट पर तीन पंक्तियों का अलंकरण हैं।

गर्भगृह में प्रतिष्ठापित एक-मुखलिंग शिल्पशास्त्र की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसके मस्तिष्क पर तीसरे नेत्र का चिन्हमात्र है। सामने की तरफ दो बड़े तथा दो छोटे स्तंभों का मण्डप था। दो अर्धस्तम्भ मण्डप अभी भी हैं। इस मण्डप के उत्तर दक्षिण में एक खुली गुफा दिखायी देती है जो बीना गुफा के समकोण पर हैं। जिसमें सप्तमातृकाओं की अस्पष्ट प्रतिमायें हैं।

गुफा 5 बृहद आकार की होने के बावजूद उसे अधिक भीतर तक नहीं काटा गया है। गुफा 5 की गणना संसार की सर्वप्रसिद्ध कलाकृतियों में की जाती है। इस गुफा में विष्णु के वाराह अवतार की एक विशाल प्रतिमा है जिसका शरीर मानव का और शीर्ष वराह का हैं। विष्णु वराह अपने बायें चरण से नागराज को दबाये हुए हैं जिसके फन में 13 सर्पो के शीर्ष हैं। विष्णु का दायाँ हाथ पीछे तथा बायाँ हाथ घुटने के ऊपर रखा हैं। पृथ्वी देवी को वह अपने दाहिने दाँत में धारण किये हैं। नीचे बनी लहरें समुद्र का प्रतीक हैं। नागराज के पीछे एक अन्य मूर्ति है जो किसी राजा की प्रतीत होती हैं। वराह के शीर्ष के बायी तरफ स्वर्गीय संगीतज्ञ हैं। सामने दोनों ओर देवों तथा असुरों का समूह है जो इस दृश्य को प्रसन्न होकर देख रहा हैं। इन मूर्तियों में ब्रह्मा तथा नंदी पर आसीन शिव हैं। तीसरी पंक्ति में ऋषिगण हैं। इस गुफा की दायीं तथा बायीं भित्तियों पर गंगा तथा यमुना अपने वाहनों मकर व कछुये पर स्वर्ग से अवतरित होती दिखायी गई हैं, जहाँ वरूण अपने हाथ में घट लेकर उनका स्वागत कर रहे हैं।

यहाँ पर इस पौराणिक कथा का चित्रण किया गया है जब विष्णु ने जलमग्न पृथ्वी का वराह अवतार लेकर उद्धार किया था।

गुफा 6 की बाह्य भित्ति के बाहरी भाग पर चन्द्रगुप्त द्वितीय का गुप्त संवत् 82 उत्कीर्ण अभिलेख है जिसमें विष्णुदास के पुत्र सनकानीक सामन्त द्वारा दिये गये दान का उल्लेख हैं। इस गुफा के सामने बरामदा हैं। गुफा का द्वार गुप्तकालीन प्रणाली के अनुसार अलंकृत हैं तथा दोनों ओर अर्ध स्तंभों पर गंगा की मूर्तियाँ थी। द्वार के बायी ओर दो और दायी ओर तीन फलक हैं। द्वार के दोनों तरफ दो द्वारपाल खड़े हैं जिनकी वेशभूषा साधारण तथा घुंघराले बाल हैं। द्वारपालों के सम्मुख विष्णु की मूर्तियाँ हैं। दायी तरफ के तीसरे खंड मे महिषासुर मर्दिनी का केश विन्यास अत्यंत आकर्षक हैं।

गुफा 6 की भीतरी छत पर कुछ छोटे छोटे अभिलेख हैं।

इस गुफा के दायी तरफ एक छोटी सी गुफा है जिसमें सप्त-मातृकाओं की अस्पष्ट सी प्रतिमायें हैं। गुफा सात का ऊपरी भाग(गोल चट्टान) जैसा है जिसके कारण इसे तवा गुफा के नाम से पुकारा जाता हैं। इस गुफा की पीछे की भित्ति पर एक अभिलेख उत्कीर्ण हैं जिससे हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त के मंत्री वीरसेन ने इस गुफा का उत्खनन करवाया था। दूसरी गुफाओं के समान इस गुफा के सामने भी एक मण्डप था जो अब नहीं हैं नष्ट हो चुका है परंतु गुफा की छत पर उत्कीर्ण पदम अभी भी दिखायी देता हैं।

इस गुफा में उत्कीर्ण लेख से हमें ज्ञात होता हैं कि चन्द्रगुप्त द्वितीय अपनी दिग्विजय के पश्चात् यहाँ आया था। यह गुफा उसकी पूजा-उपासना के लिए निर्मित की गयी थी। वह शिव भक्त था। चन्दुगुप्त द्वारा मालवा विजय का यह अभिलेख एक मात्र प्रमाण कहा जा सकता हैं।

गुफा 13 में शेषशायी विष्णु की लम्बी विशाल मूर्ति, अनंत नाग की विशाल कुंडली, गरूड़ मूर्ति तथा सात अस्पष्ट मूर्तियाँ हैं।

गुफा चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्ररह तथा अठारह बहुत छोटी छोटी हैं।

गुफा उन्नीस अमृत गुफा के नाम से जानी जाती है, एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि पहले इस गुफा में विष्णु की पूजा की जाती थी। इस गुफा की छत वर्गाकार स्तम्भों पर आधारित हैं। इनका शीर्ष बहुत अलंकृत हैं। इस गुफा का द्वार भी अन्य गुफाओं के द्वारों की अपेक्षा अधिक अलंकृत हैं। लिंटेल के ऊपर समुद्र मंथन का दृश्य हैं, जो समय के कारण अस्पष्ट हो चला है। इस दृश्य के अंकन के कारण ही इस गुफा का नाम 'अमृत गुफा' पड़ा क्योंकि समुद्र मंथन से अमृत निकला था। इस गुफा का उत्खनन सभी गुफाओं के पश्चात् किया गया था।

गुफा बीस में जैन प्रतिमायें तथा अभिलेख हैं। अभिलेख गुप्त संवत् 106 का है जिसमें शंकर द्वारा पार्श्वनाथ की प्रतिमा प्रतिष्ठापित किये जाने का विवरण मिलता हैं। अनगढ़ पत्थरों की भित्तियों द्वारा इसे पाँच भागों में बाँटा गया हैं।

पहाड़ी के पास एक छोटा सा जल कुण्ड हैं। गुफा 20के पास अनेक छोटी छोटी प्राकृतिक गुफायें हैं जिसमें कुछ प्राचीन काल के रंगीन चित्र हैं तथा कुछ मनुष्य आकृतियाँ तथा एक स्तंभ उत्कीर्ण हैं। एक अभिलेख उत्कीर्ण हैं जिसकी लिपि नागरी और भाषा संस्कृत हैं।

गुफा 10 से गुफा 20 तक जाने के लिए पहाड़ी पर सीढ़ियाँ बनी हैं।

अंत में, यहाँ की सभी गुफायें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित हैं। भावी पीढ़ी के लाभ के लिए हमारी महती जिम्मेदारी है कि हम अपने देश की पुरातात्विक धरोहरों को संरक्षित रखने के प्रयास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।

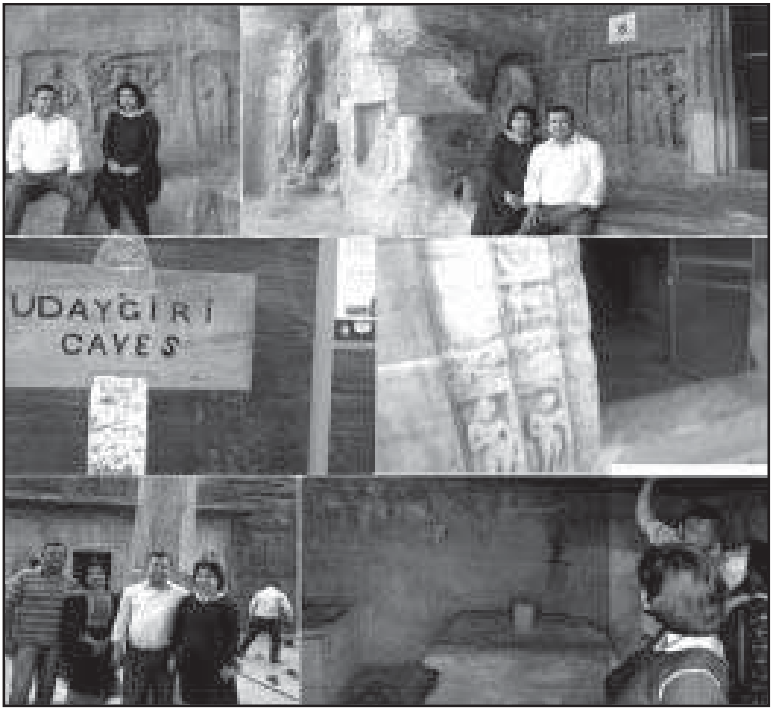

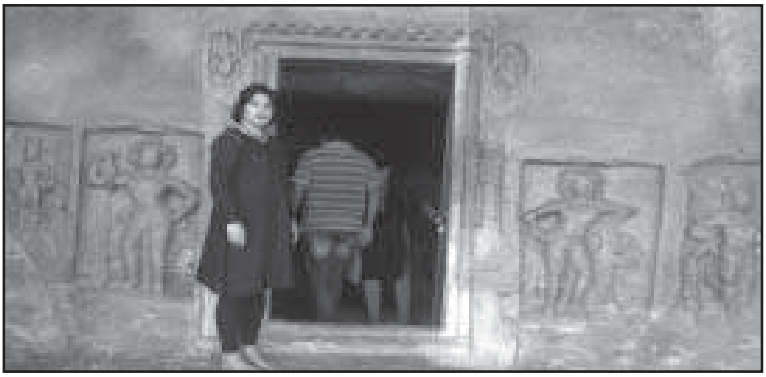

संदर्भ ग्रंथ सूची :

(1) कनिंघम : आर्क्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, रिपोर्ट 1874-75 एवं 1876-77, पृ. 46-56

(2) कनिंघम : आर्क्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, रिपोर्ट 1874-75 एवं 1876-77, पृ. 47

(3) विदिशा-खरे महेश्वरी दयाल, पृ.सं. 168-169, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, 1985

(4) यहाँ की सभी गुफायें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित हैं। गुफा 3 तथा 4 को धूप व वर्षा से सुरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा हैं।

(5) द्विवेदी, हरिहर निवास, पूर्व निर्देशित,पृ.16 व इंडियन ऐंटिक्वेरी, ग्रंथ 18, 344 पृ.

(6) प्राचीन जैन और बौद्ध तीर्थ (स्थापत्य कला के विशेष संदर्भ में) : सिंह राजेश कुमार, पृ.सं. 69, 70

प्रकाशकः अंजनी कुमार मिश्र, वाराणसी, प्रथम संस्करण : सितम्बर 2000

(7) शर्मा, राजकुमार, मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दर्भ ग्रंथ, भोपाल, 1974, पृ. 272- 316

डॉ. मोना जैन

शास.जे.यो. छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

❑❑❑

भारतीय ज्ञान परम्परा व राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

राजेन्द्र गुप्ता • डॉ. कीर्ति सिंह

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 *का उद्देश्य भारतीय ज्ञान परंपरा को आधुनिक शैक्षिक ढांचे में एकीकृत करना है, जिसमें समग्र विकास और समावेशिता पर जोर दिया गया है। यह नीति पारंपरिक भारतीय ज्ञान प्रणालियों को शामिल करके भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति में बदलने का प्रयास करती है, जिसमें साहित्य, चिकित्सा और दर्शन जैसे विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के लिए एक बहु-विषयक दृष्टिकोण की कल्पना करता है जो समावेशिता और अनुकूलन क्षमता को बढ़ावा देते हुए छात्रों में संज्ञानात्मक भावनात्मक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। इस एकीकरण को भारत के शैक्षिक परि.श्य और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ाने के मार्ग के रूप में देखा जा रहा है।*

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 *अपने लक्ष्यों को लेकर महत्वाकांक्षी है आधुनिक शिक्षा के साथ पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों का एकीकरण चुनौतियों को प्रस्तुत करता है जैसे कि प्राचीन ज्ञान को समकालीन शैक्षणिक तरीकों के साथ सरेखित करना। नीति की सफलता इन चुनौतियों पर काबू पाने और विभिन्न शैक्षिक संदर्भों में अपनी रणनीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने पर निर्भर करेगी।*

प्रस्तावना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 भारतीय ज्ञान परंपरा (Indian Knowledge System IKS) को आधुनिक शिक्षा प्रणाली में समाहित करने पर बल देती है, जिससे शिक्षा अधिक समावेशी, बहुआयामी और सांस्.तिक रूप से समृद्ध हो सके। यह नीति वेद, उपनिषद, आयुर्वेद, योग, ज्योतिष, खगोलशास्त्र, गणित,

स्थापत्य, दर्शन, भाषा-विज्ञान और नीतिशास्त्र जैसी प्राचीन भारतीय विद्या परंपराओं को आधुनिक विज्ञान एवं अनुसंधान के साथ जोड़ने का मार्ग प्रशस्त करती है। नीति में संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं को पुनर्जीवित करने, विद्यालय एवं उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में भारतीय ज्ञान प्रणाली को शामिल करने और समर्पित शोध संस्थानों की स्थापना करने का प्रस्ताव किया गया है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा आयोग (HECI) के तहत भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों को सहयोग देने की योजना बनाई गई है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) भारतीय ज्ञान परंपरा को शिक्षा में समाहित करने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएंगे। नीति में आयुर्वेद, योग, धातु विज्ञान, वेदांत और वैदिक गणित को शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग बनाने की योजना है। भारतीय ज्ञान प्रणाली संस्थान (NIIK) की स्थापना प्रस्तावित की गई है, जो इन विषयों पर शोध करेगा और वैश्विक स्तर पर भारतीय शिक्षा की भूमिका को सुदृढ़ करेगा। इसके साथ ही, विद्यालयों में भारतीय कला, साहित्य, नीतिशास्त्र और नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर बल दिया गया है। यह नीति शिक्षा के औपनिवेशिक प्रभाव को समाप्त कर उसे भारतीय संदर्भ में अधिक प्रासंगिक और व्यावहारिक बनाने का प्रयास करती है। इससे भारत को एक ''विश्वगुरु'' के रूप में पुनः स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। हालांकि, इस लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम की मानकीकरण, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होगी।

भारतीय ज्ञान प्रणाली और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 का परिचय भारतीय संस्कृति और इसकी ऐतिहासिक जड़ों में ज्ञान के महत्व पर जोर देता है। मुख्य बिंदुओं में शामिल हैं :

- ज्ञान का सर्वोच्च मूल्यः पेपर में दावा किया गया है कि ज्ञान सर्वोच्च मूल्य है, इसकी तुलना गंगा नदी से की जाती है, जो पवित्रता और मुक्ति का प्रतीक है। यह रूपक भारतीय परंपरा में ज्ञान के निरंतर प्रवाह और महत्व को उजागर करता है।
- ऐतिहासिक संदर्भः यह भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत का संदर्भ देता है, जिसका प्रचार ऋषियों (ऋषियों) द्वारा किया जाता है, जिनकी शिक्षाओं की कालातीत प्रासंगिकता है। इस परंपरा ने साहित्य, चिकित्सा और दर्शनशास्त्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में रचनात्मकता को बढ़ावा दिया है, जो भारतीय ज्ञान प्रणालियों की व्यापकता को प्रदर्शित करती है।

- वैदिक फाउंडेशन: यह परिचय वेदों को भारतीय ज्ञान प्रणालियों के सबसे पुराने और सबसे गहन स्रोतों के रूप में पहचानता है, जो आध्यात्मिक ज्ञान में उनके आधार पर जोर देते हैं। ब्रह्मांड और सर्वोच्च निर्माता के साथ यह संबंध भारतीय विचारों में ज्ञान के समग्र .ष्टिकोण को दर्शाता है।
- विश्वविद्यालयों की भूमिका: पेपर विश्वविद्यालयों को ज्ञान के मंदिर के रूप में वर्णित करता है, जहां विचारों और नवाचारों को विकसित किया जाता है। यह बौद्धिक विकास और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में शैक्षणिक संस्थानों के महत्व पर प्रकाश डालता है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: यह परिचय भारतीय ज्ञान प्रणाली को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से जोड़ता है, जो बताता है कि यह नीति ज्ञान और शिक्षा के संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका उद्देश्य शिक्षा में मानवता और मूल्यों को स्थापित करना है। यह भारत को विश्वगुरु या वैश्विक ज्ञान में अग्रणी के रूप में स्थान देता है।

साहित्यिक समीक्षा

(1) Kumar, R. (2023). नई शिक्षा नीति 2020 का स्वरूप और चुनौतियाँ *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology*, 254–258. https://doi.org/10.48175/ijarsct-8386

जीवन में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा की जरूरत होती है। शिक्षा के बिना कुछ भी मुकाम हासिल नहीं किया जा सकता। शिक्षा के माध्यम से हम सभी अपने सपने साकार कर सकते है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे व्यक्ति, समाज और देश का विकास होता है। इसी बात को ध्यान में रखकर नई शिक्षा नीति अपनाई गई। भारत देश की शिक्षा प्रणाली में 34 साल के बाद नई शिक्षा नीति 29 जुलाई, 2020 को लागू की गई। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी। यह स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। इससे पहले 1968 तथा 1986 में भी शिक्षा नीतियाँ लागू की गई थी।नई शिक्षा नीति 2020 के लागू करने के साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अर्थात् इस नई शिक्षा नीति के अनुसार अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय कहा जायेगा। नई शिक्षा नीति के तहत सकल घरेलु उत्पादन (GDP) का 6 प्रतिशत खर्च इसमें

किया जायेगा जो पहले 4.43 फीसदी ही था। जैसे की कोई वस्तु एक जगह पर पड़ी रहती है तो उस पर धुल जम जाती है। पहले की शिक्षा नीति का भी यही हाल था। पुरानी शिक्षा नीति में शिक्षा की उन्नति और प्रगति कही न कही रुक सी गई थी। इसलिए शिक्षा नीति में भी परिवर्तन लाया गया। इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया जब नई शिक्षा नीति 2020 को पूरी तरह से बाल केन्द्रित बनाया गया। इसमें मातृभाषा, स्थानीय भाषा पर जोर दिया जायेगा। विषयों का चयन दिनचर्या पर छोड़ दिया जाएगा और 5वीं कक्षा तक की शिक्षा मातृभाषा में होगी। नई शिक्षा नीति से हम सशक्त नव भारत निर्माण की आशा करते है। बस आवश्यकता है उसे प्रभावी तरीके से लागू करने की। अगर सच में उसका क्रियान्वयन हुआ तो भारत की युवा पीढी ज्ञान-विज्ञान के रास्तों को खोलकर राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देगी।

(2) Amani, S. (2024). Integrating Indian Knowledge System: Revitalizing India's Educational Landscape. *International Journal For Multidisciplinary Research*, *6*(3). https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i03.23666

पेपर में भारतीय शिक्षा प्रणाली के विकास पर चर्चा की गई है, जिसमें अनौपचारिक घर-आधारित शिक्षा से उपनिवेशवाद और पश्चिमीकरण से प्रभावित संरचित संस्थानों में इसके परिवर्तन पर प्रकाश डाला गया है। यह ऐतिहासिक संदर्भ भारत में वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।

शोध का एक महत्वपूर्ण परिणाम भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 को पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान प्रणाली (IKS) के एकीकरण में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में पहचानना है। NEP 2020 का उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान को शामिल करके शिक्षा को पुनर्जीवित करना है, जिसे समकालीन शैक्षिक प्रथाओं को बढ़ाने के लिए आवश्यक माना जाता है।

अध्ययन इस बात पर जोर देता है कि NEP 2020 भारत की ज्ञान प्रणालियों की समृद्ध विरासत को सुरक्षित रखने और आगे बढ़ाने के महत्व को पहचानता है, जिसमें दर्शन, भाषा, विज्ञान और कला जैसे विभिन्न क्षेत्रों से योगदान शामिल हैं। यह स्वीकार्यता आधुनिक शैक्षिक ढांचे के साथ-साथ पारंपरिक ज्ञान को महत्व देने की दिशा में एक कदम है।

पेपर यह भी बताता है कि NEP 2020 प्राचीन भारतीय ज्ञान पर केंद्रित है,

लेकिन इसमें स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को पूरी तरह से शामिल नहीं किया गया है, जो विभिन्न ऐतिहासिक अवधियों के दौरान मौजूद थीं, खासकर मुस्लिम शासन के दौरान। यह अंतर शिक्षा के प्रति अधिक समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता को इंगित करता है जो विविध ज्ञान प्रणालियों को मान्यता देता है।

इसके अलावा, शोध का उद्देश्य पारंपरिक भारतीय ज्ञान प्रणालियों को वर्तमान शैक्षिक ढांचे में एकीकृत करने के लिए व्यावहारिक तरीकों का पता लगाना है। इस एकीकरण से छात्रों को उनकी सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक समाज के लिए इसकी प्रासंगिकता की व्यापक समझ प्रदान करके शैक्षिक परिदृश्य को फिर से जीवंत करने की उम्मीद है।

कुल मिलाकर, परिणाम बताते हैं कि प्ज्ञै को शामिल करने के माध्यम से भारतीय शिक्षा प्रणाली के पुनरोद्धार से छात्रों के लिए अधिक समग्र और सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक शैक्षिक अनुभव प्राप्त हो सकता है, जिससे भारत के ऐतिहासिक और बौद्धिक योगदानों के लिए गहरी प्रशंसा को बढ़ावा मिलेगा

(3) **Das, R. K. (2024). Indian Knowledge System and National Education Policy (Nep) 2020. *Integrated Journal for Research in Arts and Humanities*, *4*(4), 47–51. https://doi.org/10.55544/ijrah.4.4.8**

आध्यात्मिक परंपराओं और ऋषियों की शिक्षाओं में निहित भारतीय ज्ञान प्रणाली, साहित्य से लेकर गणित तक, विभिन्न क्षेत्रों की व्यापक समझ पर जोर देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 का उद्देश्य इस समृद्ध ज्ञान विरासत को आधुनिक शिक्षा के साथ एकीकृत करना, मूल्यों और मानवता को बढ़ावा देना है। विश्वविद्यालयों को ज्ञान के मंदिरों के रूप में मान्यता देकर, NEP 2020 भारत को विश्वगुरु के रूप में स्थान देने, रचनात्मकता को बढ़ावा देने और एक एकीकृत शैक्षिक ढांचे के माध्यम से मानव आत्मा का उत्थान करने की आकांक्षा रखता है, जो भारत की शानदार बौद्धिक विरासत का सम्मान करता है।

(4) Gupta, A. (2024). A study of the scientific approach inherited in the Indian knowledge system (IKS). *The Scientific Temper*, *15*(02), 2385–2389. https://doi.org/10.58414/scientific-temper.2024.15.2.55

भारतीय ज्ञान प्रणाली (IKS) को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 में एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया है, जो प्राचीन भारतीय दर्शन और ज्ञान के महत्व पर जोर देता है। IKS में स्वदेशी तरीकों से अर्जित ज्ञान

का एक विशाल हिस्सा शामिल है, जो वैज्ञानिक जांच को दर्शन और आध्यात्मिकता के साथ एकीकृत करता है। NEP 2020 का उद्देश्य इस समृद्ध विरासत को आधुनिक शिक्षा में शामिल करना, विविध ज्ञान प्रणालियों की समझ को बढ़ावा देना और सीखने और पूछताछ के लिए समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से मानव कल्याण को बढ़ाना है।

(5) Amani, S. (2024). Integrating Indian Knowledge System: Revitalizing India's Educational Landscape. *International Journal For Multidisciplinary Research*, *6*(3). https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i03.23666

भारतीय ज्ञान प्रणाली नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 का अभिन्न अंग है, विशेष रूप से इनग्रेन्ड इन इंडिया की अवधारणा के माध्यम से। यह विचार भारत की समृद्ध बौद्धिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत में निहित व्यापक शैक्षिक अनुभव पर जोर देता है। NEP 2020 का उद्देश्य सांस्कृतिक विविधता, ऐतिहासिक निरंतरता और नैतिक मूल्यों के महत्व की समझ को बढ़ावा देना है, यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षा में समावेशिता और सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ावा देते हुए आने वाली पीढ़ियां अपनी गहरी परंपराओं से जुड़ी हों।

(6) Sardar, S., Saha, S., & Akhand, M. H. (2024). The Challenges and Opportunities of NEP-2020 in the Reference of Inclusive Education in India: An Overview. *International Journal for Multidimensional Research Perspective (IJMRP)*, *2*(10), 45–56. https://doi.org/10.61877/ijmrp.v2i10.207

यह पेपर विशेष रूप से NEP 2020 के संबंध में भारतीय ज्ञान प्रणाली को संबोधित नहीं करता है। हालांकि, यह समावेशी शिक्षा के लिए NEP 2020 के परिवर्तनकारी दृष्टिकोण पर जोर देता है, जिसमें विविध पृष्ठभूमियों के लिए समान सीखने के अवसरों को बढ़ावा देकर भारतीय ज्ञान प्रणाली के तत्वों को शामिल किया जा सकता है। मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे की कमियों और सामाजिक पूर्वाग्रहों जैसी चुनौतियों के साथ-साथ नीति-संचालित परिवर्तन और तकनीकी एकीकरण जैसे अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो भारत में एक समावेशी शैक्षिक वातावरण को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हैं।

शोध प्राविधि

अध्ययन में पूर्व प्रकाशित आलेखों शोध पत्रों जर्नल के अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त किया गया हैं।

निष्कर्ष

भारतीय ज्ञान परम्परा एक समृद्ध, बहुआयामी और प्राचीन परंपरा है, जिसमें वेद, उपनिषद, दर्शन, आयुर्वेद, ज्योतिष, योग, कला, साहित्य, गणित और विज्ञान जैसे अनेक विषय शामिल हैं। यह परंपरा न केवल आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों पर आधारित है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और व्यावहारिक ज्ञान से भी परिपूर्ण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) इस ज्ञान परम्परा को पुनर्जीवित करने और आधुनिक शिक्षा प्रणाली में एकी.त करने का प्रयास करती है। इस नीति का उद्देश्य शिक्षार्थियों को समग्र विकास की ओर प्रेरित करना, जड़ों से जुड़े रहकर वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है।

NEP 2020 भारतीय भाषाओं के अध्ययन, पारंपरिक और समकालीन ज्ञान प्रणालियों के समावेशन, और शिक्षा में बहु-विषयक .ष्टिकोण को बढ़ावा देती है। इसमें वेद, योग, आयुर्वेद, भारतीय गणित प्रणाली, तर्कशास्त्र, शास्त्रीय संगीत और भारतीय कला रूपों को शिक्षा प्रणाली में समाहित करने का प्रावधान किया गया है। नीति में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में प्रारंभिक शिक्षा देने पर बल दिया गया है, जिससे ज्ञान को आत्मसात करना सरल हो सके। इसके साथ ही, पारंपरिक गुरुकुल पद्धति और आधुनिक टेक्नोलॉजी आधारित शिक्षा के संतुलन पर भी जोर दिया गया है।

इस नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू नैतिकता, मूल्यों और संवेदनशीलता को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाना है, ताकि विद्यार्थी केवल जानकारी अर्जित न करें, बल्कि समाज के प्रति जागरूक और उत्तरदायी नागरिक भी बनें। समग्र और बहु-विषयक दृष्टिकोण अपनाते हुए, NEP 2020 भारत की प्राचीन विद्या और आधुनिक विज्ञान के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास करती है, जिससे शिक्षा प्रणाली अधिक समावेशी, नवीन और आत्मनिर्भर बन सके।

भारतीय ज्ञान परम्परा अत्यंत प्राचीन, समृद्ध और विविधतापूर्ण रही है, जिसमें वेद, उपनिषद, पुराण, ज्योतिष, गणित, चिकित्सा, कला, साहित्य और दर्शन जैसे विषयों का समावेश रहा है। ऋग्वेद से लेकर आधुनिक विज्ञान तक, भारतीय शिक्षा प्रणाली ने मौलिक चिंतन, आत्मज्ञान, तथा सार्वभौमिक सत्य की खोज को प्राथमिकता दी है। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविख्यात विश्वविद्यालयों ने भारतीय ज्ञान परम्परा को वैश्विक पहचान दिलाई थी, जहाँ देश-विदेश से छात्र अध्ययन के लिए आते थे। भारतीय शिक्षा का मूल उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्ति न होकर नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति भी था। गुरुकुल

प्रणाली में शिक्षकों और शिष्यों के बीच आत्मीय संबंध पर बल दिया जाता था, जिससे विद्या केवल एक पाठ्यक्रम न रहकर एक जीवनशैली बन जाती थी। औपनिवेशिक शासन के दौरान पारंपरिक भारतीय शिक्षा व्यवस्था को गहरी क्षति पहुँची और इसे पश्चिमी ढांचे में ढाल दिया गया। आधुनिक भारत में नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत पारंपरिक भारतीय ज्ञान परम्परा और समकालीन वैज्ञानिक सोच के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। योग, आयुर्वेद, संस्कृत, तथा भारतीय गणितीय पद्धतियों को पुनः शिक्षा प्रणाली में स्थान दिया जा रहा है, जिससे भारत की प्राचीन बौद्धिक धरोहर को पुनर्जीवित किया जा सके। डिजिटल युग में भारतीय शिक्षा प्रणाली नवाचार, अनुसंधान और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप ढल रही है, जिससे भारत पुनः एक ज्ञान आधारित समाज के रूप में उभर सके।

प्रभावों पर विचार करने की आवश्यकता है, जिसमें औपनिवेशिक और स्वदेशी योगदान शामिल हैं। यह व्यापक परिप्रेक्ष्य एक अधिक समावेशी और व्यापक शैक्षिक ढांचा तैयार करने में मदद कर सकता है, जो भारत की समृद्ध विरासत के सभी पहलुओं का सम्मान करता है और उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) भारतीय ज्ञान प्रणाली (IKS) को पाठ्यक्रम में एकीकृत करके भारत के शैक्षिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। इस एकीकरण का उद्देश्य देश की समृद्ध बौद्धिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का चित्रण करके भारत के शैक्षिक ढांचे को पुनर्जीवित करना है। NEP 2020 एक समग्र शैक्षिक दृष्टिकोण के महत्व पर जोर देता है जिसमें पारंपरिक भारतीय ज्ञान शामिल है, जिससे छात्रों में सांस्कृतिक पहचान और निरंतरता की भावना को बढ़ावा मिलता है। यह नीति भारत की प्राचीन बुद्धि और प्रथाओं के संरक्षण और प्रचार के साथ आधुनिक शैक्षिक आवश्यकताओं को संतुलित करने का प्रयास करती है।

भारतीय ज्ञान प्रणाली का एकीकरण

- NEP 2020 में IKS को एक मूलभूत घटक के रूप में शामिल किया गया है, जो विविध दृष्टिकोण और अंतर्दृष्टि प्रदान करके समकालीन शिक्षा को बढ़ाने की इसकी क्षमता को पहचानता है।
- नीति का उद्देश्य प्राचीन भारत के ज्ञान को आधुनिक शैक्षिक ढांचे में दर्शनशास्त्र, विज्ञान और कला जैसे क्षेत्रों में योगदान सहित एकीकृत करना है।

- IKS को ज्ञान प्रसारण की एक व्यवस्थित पद्धति के रूप में देखा जाता है, जिसका वैज्ञानिक जांच और विभिन्न विषयों में खोजों का लंबा इतिहास है (Gupta, 2024)

सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयाम

- NEP 2020 के भीतर इनग्रेन्ड इन इंडिया की अवधारणा सांस्.तिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक शिक्षा के महत्व पर जोर देती है, जिसका उद्देश्य छात्रों में नैतिक और नैतिक मूल्यों को स्थापित करना है (Sudhakar, 2024)।
- नीति भारतीय ऋषियों की आध्यात्मिक और दार्शनिक शिक्षाओं को स्वीकार करती है, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया है और मानव कल्याण में योगदान दिया है (Das, 2024)।

चुनौतियां और विचार

- जबकि NEP 2020 प्राचीन भारतीय ज्ञान पर केंद्रित है, लेकिन विभिन्न ऐतिहासिक अवधियों, जैसे कि भारत में मुस्लिम शासन के दौरान प्रचलित स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को पूरी तरह से शामिल नहीं करने के लिए इसकी आलोचना की गई है।
- नीति की सफलता आधुनिक शैक्षिक मांगों के साथ पारंपरिक ज्ञान को प्रभावी ढंग से संतुलित करने और इसके कार्यान्वयन में समावेशिता सुनिश्चित करने पर निर्भर करती है (Sethi, 2024)।

प्राचीन भारतीय ज्ञान पर ध्यान देने के विपरीत, भारत की शैक्षिक प्रणाली पर विविध ऐतिहासिक एकीकृत करता है।

सन्दर्भ

1. भारतीय शिक्षा प्रणाली और NEP 2020 पर एक व्यवस्थित समीक्षा (/papers/a-systematic-review-on-indian-education-system-nep-2020-4m3n8a9ns6) 2024, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ रिसर्च पब्लिकेशन एंड रिव्यूज़ 1 उद्धरण
2. शिक्षा में एक नई सुबह: छात्रों और शिक्षकों के लिए NEP 2020 का वादा और क्षमता (/papers/a-new-dawn-in-education-the-promise-and-potential-of-nep-7dkv4c48i9rr) 2024, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ साइंस एंड रिसर्च आर्काइव

3. भारतीय ज्ञान प्रणाली को एकीकृत करना: भारत के शैक्षिक परिदृश्य को पुनर्जीवित करना (/पेपर/इंटीग्रेटिंग-इंडियन-नॉलेज-सिस्टम-रिवाइटलाइजिंग-इंडियास-5dxxpvjhrj) 2024, इंटरनेशनल जर्नल फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च 1 उद्धरण
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 का वर्तमान परिदृश्य (/पेपर/राष्ट्रीय-शिक्षा-नीति-nep-2020-2liz2rrdc7wg) का वर्तमान-परिदृश्य/राष्ट्रीय-शिक्षा-नीति-nep-2020-2liz2rrdc7wg) 2024
5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) और पुस्तकालयों पर एक साहित्य सर्वेक्षण (/papers/a-literature-survey-on-national-education-policy 2020-nep-325igqpr) क्रिस्टोफ़ मेगेन 2023
6. Qasim, S. H. (2024). Indian Knowledge System: Reconfiguring Education in Present Scenario. International Journal For Multidisciplinary Research, 6(1). https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i01.13644
7. Gupta, R., & Portia, Ms. (2024). Reconciling Traditional Indian Knowledge with Technological -dvancements. Deleted Journal, 2(09), 2816-2821. https://doi.org/10.47392/irjaem.2024.0411
8. Das, R. K. (2024). Indian Knowledge System and National Education Policy (Nep) 2020. Integrated Journal for Research in Arts and Humanities, 4(4), 47-51. https://doi.org/10.55544/ijrah.4.4.8
9. Amani, S. (2024). Integrating Indian Knowledge System: Revitalizing India's Educational Landscape. International Journal For Multidisciplinary Research, 6(3). https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i03.23666
10. Khan, S. A., Sharma, M. (2024). An Overview on Indian Knowledge System. Integrated Journal for Research in Arts and Humanities, 4(4), 42-46. https://doi.org/10.55544/ijrah.4.4.7

राजेन्द्र गुप्ता
शोधार्थी वर्धमान महावीर खुला विश्विद्यालय, कोटा

डॉ. कीर्ति सिंह
निदेशक व सहआचाय
शिक्षा विद्यापीठ वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

❑❑❑

छत्तीसगढ़ के राजनैतिक इतिहास में कंवर जनजाति समाज का योगदान

हरवंश सिंह मिरी • प्रो. आभा रूपेन्द पाल

शोधार्थी द्वारा इस शोध पत्र में छत्तीसगढ़ के कंवर जनजाति समाज के प्रमुख व्यक्तित्व का संक्षिप्त अध्ययन किया गया है। इन प्रमुख व्यक्तित्वों ने राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश कर अपना सम्पूर्ण जीवन राष्ट्र एवं जनसेवा में लगा दिये। ऐसे प्रमुख नेताओं में बुद्धनाथ साय, नरहरि प्रसाद साय, प्यारेलाल कंवर, काका लरंग साय, बोधराम कंवर, चनेश राम राठिया, ननकी राम कंवर, नंदकुमार साय, सत्यानंद राठिया, सुनीति राठिया, गोमती साय और छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय।

शब्द कुंजी : राष्ट्रीय, समाज, राजनीति, राजनेता, सांसद, कंवर, विधायक, समिति, कार्य, क्षेत्र।

अध्ययन का उद्देश्य : छत्तीसगढ़ के कंवर समाज के राजनैतिक व्यक्तित्व को जिन्होंने छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भागीदारी निभाई और समाज तथा राष्ट्र के हित में कार्य कर कंवर समाज को गौरवान्वित किया। अतः प्रस्तुत शोध पत्र में इन्हीं पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अध्ययन किया गया है।

शोध प्रविधि : प्रस्तुत शोध पत्र के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोतों का सहारा लिया गया है। जिसके अतंर्गत प्रकाशित डिबेट्स रिपोर्ट, अखबार व समाजशास्त्रीय साक्षात्कार विधि से तथ्यों का संकलन व अध्ययन किया गया है।

भूमिका : कंवर जनजाति छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति है। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में 8,87,477 जनसंख्या है। राजनीतिक ऐतिहासिकता की बात करें तो कंवर जनजाति समाज की भागीदारी बहुत पहले से रही है। स्वतंत्रता के पश्चात् सन् 1947 से 1952 तक बुद्धनाथ

साय विधायक मनोनीत किए गए। इस जनजाति समाज से सन् 1962 में प्यारेलाल कंवर विधायक बने और सन् 1993 में अविभाजित मध्यप्रदेश के उपमुख्यमंत्री बने। नरहरि प्रसाद साय सन् 1977 में केन्द्र सरकार में संचार मंत्री रहे। जिला-कोरबा के ग्राम-हरदी बाजार में जन्में बोधराम कंवर सन् 1972 में निर्दलीय चुनाव जीतकर कर विधायक बने और सन् 2009 में प्रोटेम स्पीकर का भागीदारी भी निभाई। लरंग साय जिन्हें काका और विकास पुरुष की उपाधि से लोग सम्मानित करते थे। वे अनेक बार लोकसभा सदस्य और केन्द्र में केन्द्रीय मंत्री के रूप में कार्य किये। अविभाजित मध्यप्रदेश समय से ननकी राम कंवर विधायक निर्वाचित होने के उपरांत संसदीय सचिव के रूप में कार्य किए एवं छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद कृषि, राजस्व, सहकारिता, पशुपालन, खाद्य, गृह जेल एवं सहकारिता आदि विभाग के मंत्री के रूप में कमान संभाली। नंदकुमार साय नायब तहसीलदार के पद पर प्रशासनिक सेवा में चयनित हुए लेकिन उनकी रुचि राजनीति में होने की वजह से उन्होंने राजनीति में प्रवेश कर समाज हित में कार्य करते हुए लोगों को शराब के व्यसन से मुक्ति दिलाने के लिए सन् 1970 में आम लोगों के यह कहने से कि क्या आप अपने भोजन में से नमक छोड़ सकते हो? तो इस पर उन्होंने उसी समय से नमक का जीवन भर के त्याग कर दिया, नंदकुमार साय छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष एवं सांसद के साथ केन्द्रीय अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष थे। छत्तीसगढ़ सरकार में सत्यानंद राठिया सन् 2003 में लैलूंगा विधानसभा से विधायक निर्वाचित होकर सन् 2004 में वन, अवास एवं पर्यावरण राज्यमंत्री बने। सुनीति सत्यानंद राठिया तमनार जनपद पंचायत सदस्य के पद से आगे बढ़ते हुए सन् 2013 में लैलूंगा विधानसभा से विधायक चुनकर महिला एवं बाल कल्याण संबंधी समिति में कार्य किया। श्रीमती गोमती साय जिला पंचायत के अध्यक्ष रही एवं सन् 2017 में रायगढ़ से सांसद चुनी गई तथा वर्तमान में पत्थलगांव विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। वे अपनी क्षेत्र के मुद्दों को सदन में बखूबी रखती है। उनके प्रयासों से जशपुर में क्रिटिकल केयर सेंटर की स्थापना हुई। विष्णुदेव साय ग्राम पंचायत पंच पद से राजनीति में प्रवेश कर अपने कार्य और अच्छी छवि के चलते सांसद, केन्द्रीय इस्पात राज्य मंत्री और अपने दल के प्रदेश अध्यक्ष हुए एवं आज छत्तीसगढ़ राज्य के एवं कंवर जनजाति समाज से प्रथम मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हैं।

छत्तीसगढ़ के कंवर जनजाति समाज की प्रमुख व्यक्तित्व जिनका महत्वपूर्ण राजनीति क्षेत्र में योगदान है, उनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :

नरहरि प्रसाद साय

नरहरि प्रसाद साय का जन्म सन् 1929 को जिला–जशपुर के ग्राम-बंदरचुआ में हुआ। उनके पिता का नाम श्री सुखदेव साय है।[1] नरहरि प्रसाद साय संचार मंत्री रहते हुए अनेक स्थलों में टेलीफोन की सुविधा के लिए कार्य किये। 7 नवंबर 1977 में लोकसभा सत्र के दौरान श्री राघव जी द्वारा किए गए प्रश्न के नरहरि प्रसाद साय द्वारा दिये गये उत्तर से यह जानकारी प्राप्त होती है।[2]

प्यारेलाल कंवर

जनजाति समुदाय के प्रखर व्यक्तित्व के धनी प्यारेलाल कंवर का जन्म 19 मार्च 1933 को जिला–बिलासपुर (वर्तमान जिला-कोरबा), तहसील-कटघोरा के ग्राम भैसमा में हुआ। प्यारेलाल कंवर जी विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति में रुचि रखते थे। लोगों की समस्या को लेकर जागरूक रहते थे और उसका समाधान किया करते थे।[3]

वे सन् 1962 के आम चुनाव में रामपुर विधानसभा से विधायक निर्वाचित हुए और सन् 1967, 1972 व 1980 के आम चुनाव में भी विजयी रहे। अप्रैल 1984 से मार्च 1985 तक मध्य प्रदेश विधानसभा में उपाध्यक्ष के पद पर कार्य किया। प्यारेलाल कंवर पुनः सन् 1985 में विधानसभा चुनाव जीतकर राज्य वित्त एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के मंत्री के रूप में कार्य करना, लोगों में उनकी लोकप्रियता को बताती है।[4] सन् 1993 के आम चुनाव में लोगों का स्नेह उन्हें फिर से प्राप्त हुई, वे 28 दिसंबर, 1995 से 19 मई 1998 तक मध्य प्रदेश शासन में उपमुख्यमंत्री रहे।[5]

काका लरंग साय

राष्ट्रीय नेता काका लरंग साय का जन्म ब्रिटिश कालीन भारत में 20 अक्टूबर 1935 को जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज, तहसील-शंकरगढ़ के ग्राम चिरई (यशवंतपुर) में हुआ। उन्होंने प्राथमिक तक शिक्षा प्राप्त किया। उनका वास्तविक नाम लरंग साय था, लोगों ने अपने प्रति लरंग साय का स्नेह एक काका के भांति महसूस कर उन्हें काका की उपाधि से सम्मानित किया करते थे, इसलिए वे काका लरंग साय के नाम से मशहूर हुए।[6] ''काका'' के साथ-साथ उन्हें ''विकास पुरुष''[7] और ''जीन'' (''जीन=जादुई चिराग'' नाम से उनके घर वाले पुकारते थे) के नाम से संबोधित करते थे।[8]

लोगों का सहयोग करते हुए राजनीति में प्रवेश कर सन् 1967 से 1977 मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे एवं 1968 में राज्य सरकार में राज्य मंत्री रहे।[9] छठीं लोकसभा में 4 अगस्त 1977 से 28 जुलाई 1979 तक श्रम एवं संसदीय मामले के राज्य मंत्री रहे[10] तथा 1989 से 1991 और 1998 से 1999 तक क्रमशः नवीं और बारहवीं लोकसभा में सरगुजा क्षेत्र से सदस्य रहे। ऊर्जा मंत्रालय के सलाहकार समिति की सदस्य के रूप में सन् 1990 से 91 तक व अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण और विद्युत मंत्रालय के सलाहकार समिति का भी सदस्य रहे।[11]

उनके प्रयासों से अंबिकापुर रेल्वे लाइन का विस्तार संभव हुआ। यही वजह है, अंबिकापुर से दिल्ली तक चलने वाली ट्रेन में एक स्पेशल बोगी का नाम लरंग साय बोगी है।[12] उन्होंने छत्तीसगढ़ व झारखण्ड दोनों राज्यों को जोड़ने के लिए कन्हार नदी पर पुल का निर्माण करवाने के लिए अथक प्रयास किया, जो सफल हुआ। उनका देहावसान 6 जनवरी 2004 को हुआ।[13]

बोधराम कंवर

बोधराम कंवर का जन्म 28 जनवरी, 1938 को जिला–कोरबा, तहसील–पाली के ग्राम हरदी बाजार में हुआ। उनके पिता का नाम मुरित राम कंवर है। उन्होंने एम.एस.सी. रसायन शास्त्र, एम.ए., राजनीति शास्त्र का परीक्षा उत्तीर्ण किया।[14]

शासकीय हाई स्कूल, प्राचार्य पद से इस्तीफा देकर[15] सन् 1972 में पहली बार कटघोरा विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ा और विधायक चुने गए। वह कटघोरा विधानसभा से 6 बार क्रमशः 1977, 1980, 1985, 1993, 2003 एवं सातवीं बार 2008 में विधायक बने। सन् 1993 के चुनाव में तानाखार विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया।[16]

बोधराम कंवर सन् 2000 में सभापति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश शासन में कार्य किया।[17] वे विभिन्न पदों के जिम्मेदारी बखूबी से निभाते हुए सन् 2009 में प्रोटेम स्पीकर छत्तीसगढ़ विधानसभा एवं सन् 2011 में सदस्य लोक लेखा समिति, प्रत्यायुक्त विधानसभा समिति छत्तीसगढ़ विधान सभा।[18] बोधराम कंवर ने अपने अथक प्रयास से हरदी बाजार में महाविद्यालय खुलवाया जो एक रिकॉर्ड भी है, यह पहले महाविद्यालय है जो 14 विषयों के साथ प्रारंभ हुआ।[19]

चनेश राम राठिया

चनेश राम राठिया का जन्म 15 दिसंबर सन् 1942 को जिला-रायगढ़, तहसील-खरसिया के गांव नांदगांव में हुआ। उनके पिता का नाम मायाराम राठिया है। उन्होंने मैट्रिक व बी.टी.आई. की परीक्षा उत्तीर्ण की।[20] सन् 1971 में शिक्षक के शासकीय सेवा से त्याग कर राजनीति में प्रवेश किया।[21] सन् 1972 में पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़े लेकिन उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा।[22] सन् 1974 में कृषि उपज मंडी खरसिया के सदस्य व सन् 1975 में अध्यक्ष जोबी न्याय पंचायत जिला-रायगढ़ बने।

सन् 1977 के विधानसभा चुनाव में प्रथम बार विधायक निर्वाचित हुए। फिर क्रमशः सन् 1980, 1985, 1990, 1993 एवं 1998 इस प्रकार चनेश राम राठिया छः बार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। इस दौरान वे अविभाजित मध्य प्रदेश शासन में सन् 1993 से 1998 तक राज्य मंत्री लोक निर्माण, धर्मस्व तथा पुनर्वास विभाग तथा मंत्री पशुपालन विभाग और सदस्य लोक लेखा, याचिका, प्राक्कलन एवं पुस्तकालय समिति के रहे। सन् 2000 में छत्तीसगढ़ शासन में मंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का कार्यभार संभाला।[23]

कोरोना काल में कोरोना संक्रमण होने की वजह से 13 सितंबर (रविवार) सन् 2020 को रायगढ़ की निजी अस्पताल ओपी जिंदल में निधन हुआ।[24]

ननकी राम कंवर

ननकी राम कंवर का जन्म 21 जुलाई, 1943 जिला-कोरबा के ग्राम-बंधवाभाटा में हुआ। उनके पिता का नाम पंतराम कंवर है। उन्होंने एमए एलएलबी की शिक्षा प्राप्त किया। सन् 1969 में राजनीति में जन संघ के सदस्यता लेकर प्रवेश किया।[25] वे प्रथम बार सन् 1972 में चुनाव लड़ा किंतु वे विजयी नहीं हुआ।[26] सन् 1977 में रामपुर विधानसभा से विधायक निर्वाचित हुए और मध्य प्रदेश शासन में संसदीय सचिव राजस्व विभाग, सन् 1979 में राजस्व विभाग राज्य मंत्री रहे। क्रमशः सन् 1990, 1998, 2003, 2005 और 2018 में छठवीं बार चुनाव जीता। इस दौरान ननकी राम कंवर मध्य प्रदेश शासन में वन एवं कृषि विभाग का मंत्री, सदस्य अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण संबंधी समिति आदि जिम्मेदारी का निर्वाहन किया।[27]

ननकी राम कंवर जी 9 मार्च 1990 से 11 जून 1990 तक वन मंत्री और 12 जून 1990 से 8 फरवरी 1992 तक कृषि बायो गैस विकास मंत्री रहे। 28 सन् 2008 में उनके अच्छे कार्यों को देखते हुए पार्टी ने गृह, जेल एवं सहकारिता मंत्री का कार्य सौंपा।[29] ननकी राम कंवर ने नेशनल लेजिसलेटिव कॉन्फ्रेंस के साक्षात्कार में बताया की सिंचाई के क्षेत्र में उन्होंने अच्छा कार्य किया है, उनके क्षेत्र में जितनी सरकारी सिंचाई नहीं होती उससे अधिक निजी सिंचाई की जाती है विधायक मद् से इस कार्य के लिए उन्होंने भरपूर सहयोग दिया है।[30]

नंदकुमार साय

नंदकुमार साय का जन्म 1 जनवरी 1946 को ग्राम भगोरा में हुआ। उन्होंने स्नाकोत्तर तक की शिक्षा प्राप्त किया। सन् 1973 में राज्यसभा परीक्षा उत्तीर्ण कर नायब तहसीलदार का पद प्राप्त किया लेकिन नौकरी में नहीं गया। क्योंकि छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे।

उन्होंने सन् 1969 में प्रथम बार रायगढ़ के लोकसभा सदस्य का चुनाव जीता। तत्पश्चात् सन् 1996 में लोकसभा सदस्य बने। वे सन् 1980 में भारतीय जनता पार्टी के जिला का अध्यक्ष, सन् 1993-96 में प्रदेश के महामंत्री, सन् 1996-97 में अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं सन् 1997 से 2000 तक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य रहे।[31]

उनके राजनीतिक जीवन में यह भी मोड़ आया जब सन् 1970 में वे आदिवासी समाज को शराब छोड़ने के लिए आह्वान कर रहे थे तो लोगों ने तर्क दिया जिस तरह खाने में नमक है, उसी तरह उनके लिए शराब है, उन्होंने उसी समय प्रण लिया कि जीवन पर्यंत नमक का सेवन नहीं करूंगा फिर नंद जी ने तर्क दिया जो व्यक्ति नमक छोड़ सकता है उसके लिए शराब क्या है। उस वचन का अब भी पालन कर रहे है।[32] नंदकुमार साय राजनेता के साथ एक कृषक भी है, राजनेता बनने के बाद भी अपने खेतों में बैल के साथ हल से जुताई का कार्य करते है। आज भी आप नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के साइड में साय जी को बैल-हल से खेत की जुताई करते हुए छायाचित्र देख सकते हैं।[33]

सत्यानंद राठिया

सत्यानंद राठिया का जन्म 1 जुलाई, 1963 को जिला-रायगढ़, तहसील-तमनार के रोड़ोपाली गांव में हुआ। उनके पिता का नाम भोजराम राठिया है। उन्होंने हिंदी विषय से स्नाकोत्तर की शिक्षा प्राप्त किया।

सन् 2000 में सत्यानंद राठिया जिला वनोपज सहकारी संघ, रायगढ़ व प्रांतीय सदस्य छत्तीसगढ़ लघु वनोपज सहकारी संघ और सन् 2001 से 2003 तक छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति के सदस्य रहे। वे सर्वप्रथम सन् 2003 में लैलूंगा विधानसभा से विधायक बने और सन् 2004 में छत्तीसगढ़ शासन में वन, आवास एवं पर्यावरण विभाग राज्य मंत्री का दायित्व निभाया।[34]

विष्णुदेव साय

विष्णुदेव साय का जन्म 21 फरवरी, 1964 को जिला जशपुर तहसील-कांसाबेल, ग्राम बगिया में हुआ। उनके पिता का नाम श्री रामप्रसाद साय व उनके माता का नाम जशमनी देवी है। उन्होंने प्राथमिक तक शिक्षा अपने गांव बगिया में, हायर सेकेंडरी कुनकुरी के लोयोला मिशनरी स्कूल में किया। आगे की शिक्षा के लिए अंबिकापुर के महाविद्यालय में प्रवेश लिया।

राष्ट्रीय नेता नरहरि प्रसाद विष्णुदेव साय के बड़े पापा थे। केदारनाथ साय जो सन् 1967 से 1972 तक जनसंघ से तपकरा विधानसभा के विधायक रहे। ये भी विष्णुदेव साय के बड़े पिताजी थे। उनके दादा सरदार बुधनाथ साय को सन् 1947 से 1952 के समय तक क्षेत्र के विधायक मनोनीत किया गया था।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की परिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति से जुड़ी हुई है। यही राष्ट्र सेवा की भावना उन पर पड़ा और वे ग्राम पंचायती राजनीति में पंच की उम्मीदवार से विजयी होकर अपनी राजनीति सफर की शुरूआत किया। सन् 1990 में अपने ग्राम बगिया के निर्विरोध सरपंच चुने गये। सन् 1990 से 1998 तक अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा तपकरा के विधायक चुने गये। 13वीं, 14वीं व 15वीं लोकसभा में क्रमशः सन् 1999, 2004 व 2005 में रायगढ़ लोकसभा से सांसद चुने गये। राजनीति में उनकी जिम्मेदारी बढ़ती गई। सन् 2006 व 2014 में भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया।

16वीं लोकसभा 2014 में लोकसभा सांसद निर्वाचित होकर सन्

2014 से 2019 तक केंद्रीय राज्य मंत्री इस्पात खान, श्रम और रोजगार मंत्रालय में कार्य किया। विष्णुदेव साय पुनः सन् 2020 से 2022 तक भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष रहे। सन् 2023 की विधानसभा चुनाव में कुनकुरी विधानसभा से विधायक निर्वाचित हुए और 10 दिसंबर 2023 को भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के विधायक दल ने उन्हें अपना नेता चुनकर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुना।[35]

सुनीति सत्यानंद राठिया

सुनीति सत्यानंद राठिया का जन्म 11 अप्रैल 1975 को जिला-रायगढ़ के देवगढ़ गांव में हुआ। उनके पिता का नाम कार्तिक राम राठिया है। उन्होंने हायर सेकेंडरी तक की शिक्षा प्राप्त किया। सन् 1995 से 2000 तक सदस्य जनपद पंचायत तमनार और सन् 2000 से 2010 तक अध्यक्ष भी इसी जनपद पंचायत में रही। सन् 2010 से 2013 तक सदस्य जिला पंचायत रायगढ़ चुनीं गयी।

सन् 2013 में प्रथम बार लैलूंगा विधानसभा से विधायक निर्वाचित हुई। सन् 2014-15 में छत्तीसगढ़ विधानसभा के शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति और महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति में सदस्य के रूप में कार्य किया।[36]

गोमती साय

गोमती साय का जन्म 25 मई 1978 को जिला जशपुर के ग्राम कोकीखार में हुआ। उनके पिता का नाम शुभसरण सिंह एवं माता का नाम बसंती बाई है। उन्होंने 12वीं तक शिक्षा प्राप्त किया।[37] गोमती साय राजनीतिक जीवन की शुरूआत ग्राम पंचायत सरपंच से किया। पहली बार सन् 2005 में जिला पंचायत सदस्य चुनी गयी फिर सन् 2015 में जिला पंचायत सदस्य रही।[38]

17वीं लोकसभा सन् 2019 में पहली बार वे रायगढ़ से सांसद चुनी गई। उन्हें जनजाति कार्य मंत्रालय की परामर्शदात्री एवं महिला अधिकारिता संबंधी समिति की सदस्य बनायी गयीं। उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए सदैव कार्य किया। सदन की सभा में उनकी उपस्थिति लगभग 100% रही है और वे अपने क्षेत्र की मुद्दों को मुखर होकर उठाती है।

गोमती साय अपनी संसदीय कार्यकाल में सदन में जशपुर क्षेत्र में

क्रिटिकल केयर सेंटर नहीं होने की वजह से लोगों को होने वाली परेशानियों को इतनी शालीनता से रखी कि सरकार ने 24 करोड़ के लागत से वहां पर क्रिटिकल केयर सेंटर की स्थापना करवायी।[39]

3 जुलाई, 2019 को लोकसभा में आलू, मिर्ची तथा टमाटर की खेती का उदाहरण देते हुए जशपुर क्षेत्र में रेल लाइन की कमी को बताते हुए रायगढ़ एवं जशपुर में कोरबा से लोहार तक रेल लाइन देने की मांग किया।[40] उन्होंने सदन में यह भी मांग रखी–रायगढ़ में रेलवे लाइन तो है, लेकिन ट्रेन की स्टॉपेज कम है, जिससे लोगों को आवागमन की सुविधा में समस्या होती है, उनकी इस मांग पर यहां ट्रेन की स्टॉपेज की संख्या 4 कर दीं गयी।[41]

निष्कर्ष कंवर जनजाति समाज का राजनैतिक इतिहास में छत्तीसगढ़ के परिपेक्ष्य में अध्ययन करने से यह निष्कर्षत: यह जानकारी प्राप्त होती है कि कंवर जनजाति समाज के जो भी राजनेता हुए उन्होंने समाज के प्रत्येक क्षेत्र जैसे-सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक में नि:स्वार्थ योगदान दिया है। यह प्रभाव जनजाति समाज में एक प्रेरणा स्रोत के रूप में काम किया, जिससे खासकर युवा वर्ग उच्च शिक्षा प्राप्त कर अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ राजनीति के क्षेत्र को भी जनसेवा, समाजसेवा एवं रोजगार के रुप अपना रहे है। अत: कंवर जनजाति समाज के इन व्यक्तित्वों के राजनैतिक योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता।

1. साक्षात्कार, श्री टीकाराम कंवर, पिता–स्व. पतिराम कंवर, उम्र- 65 वर्ष, ग्राम–परसवानी (कुरुद) जिला–धमतरी, से.नि. उप-पुलिस अधीक्षक दिनांक–10/03/2024
2. https://eparlib.nic.in/handle/123456789/2603884? view_ type= browse
3. साक्षात्कार, श्री संदीप कुमार कंवर, पिता–श्री ननकी राम कंवर, उम्र–54 वर्ष, ग्राम–बंधुवाभाठा, जिला–कोरबा, सदस्य जिला पंचायत-कोरबा, एवं कृषक, दिनांक–06/02/2024
4. https://mpvidhansabha.nic.in/dpsp-PyarelalKanwar.htm
5. मंडवी, वेदमती, जनजाति राजनीति और नेतृत्व, मानसी पब्लिकेशन्स, कश्मीरी गेट दिल्ली, प्रथम संस्करण–2011, पृ. 355
6. साक्षात्कार, उपेन्द्र सिंह पैकरा पिता स्व. श्री कलमू पैकरा, उम्र-44 वर्ष, ग्राम–डूमरभावना (बालमपुर), ग्राम पंचायत सचिव संघ प्रदेश अध्यक्ष एवं सामाजिक कार्यकर्ता, दिनांक–14/02/2024

7. 12 वर्षों नगर पालिका के सामने रखी है काका लरंग साय की प्रतिमा, अनावरण का इंतजार

https://www.naidunia.com/chhattisgarh/ambikapur-ambikapur-news-statue-of-kaka-larang-sai-has-been-kept-in-front-of-the-municipality-for-12-years- awaiting-unveiling-6441084

8. साक्षात्कार, रामलखन पैकरा (संबंध-नाती) उम्र-54 वर्ष, ग्राम-जारगीम (मनोहरपुर), कृषक एवं राजनीति क्षेत्र, दिनांक 07/01/2024

9. Lok Sabha Debates, Lok Sabha, Wednesday, February 4, 2004/ Megha 15, 1925(Saka) https:/ /web.archive.org/web/ 20150118142846/ http://164.100.47.132/LssNew/psearch/Result 13.aspx?dbsl=7691

10. Parliament_of_India_6th_LokSabha_ Report English.pdf

11. Lok Sabha Debates, Lok Sabha, Wednesday, February 4, 2004/ Megha 15, 1925 (Saka)https://web.archive.org/web/ 20150118142846/ http://164.100.47.132/LssNew/psearch/Result13. aspx? dbsl=7691

12. https://www.naidunia.com/chhattisgarh/ambikapur-bjp-remembered-kaka-larang-sai-at-the-launch-of-delhi-train-7679821

13. https://www.naidunia.com/chhattisgarh/raipur-larang-say-statue-was-installed-during-life-now-his-village-will-become-an-ideal-village-3251358

14. https://cgvidhansabha.gov.in/hindi_new/mla_ex/3rdass/22.pdf पृ. 31

15. https://cgvidhansabha.gov.in/hindi_new/mla_ex/3rdass/22.pdf

पृ. 32

16. Interview- Sajag Nigahein) 7 बार विधायक रहे छत्तीसगढ़ के गांधी बाबा बोधराम कंवर, किया जीवन शिक्षा के लिए

https://youtu.be/PVO_YazsC9E?si=lyzu2khhPWy3zw43

17. मंडवी, वेदमती, पूर्वोक्त पृ. 371

18. https://cgvidhansabha.gov.in/hindi_new/mla_ex/3rdass/22.pdf पृ. 33

19. (Interview- Sajag Nigahein) 7 बार विधायक रहे छत्तीसगढ़ के गांधी बबा बोधराम कंवर, किया जीवन शिक्षा के लिए

https://youtu.be/PVO_YazsC9E?si=lyzu2khhPWy3zw43

20. https://cgvidhansabha.gov.in/hindi_new/mla_ex/MLA_first.htm

21. https://mpvidhansabha.nic.in/house%20proceedings/hp 230221.htm.

22. कोरोना में मौत: पूर्व मंत्री और आदिवासी नेता चनेश राम राठिया का निधन, कई दिनों से बीमार चल रहे थे https://dainik-b.in/cf1bZ5NNL9

23. https://cgvidhansabha.gov.in/hindi_new/mla_ex/MLA_first.htm

24. https://hindi.news18.com/news/chhattisgarh/raigarh-chhattisgarh-congress-leader-former-minister-chanesh-ram-rathia-dies-corona-virus-cgnt-

25. https://cgvidhansabha.gov.in/hindi_new/sadasy_parichay/20.pdfi पृ. 32

26. https://npg.news/diverse/nankiram-knwar-biograpgy-in-hindi-age-biography-education-wife-cast-net-worth-contact-adress-height-bio-birthday-wiki-1239517

27. https://cgvidhansabha.gov.in/hindi_new/sadasy_parichay/20.pdf पृ. 47-48

28. मंडवी, वेदमती, पूर्वोक्त पृ. 311

29. https://cgvidhansabha.gov.in/hindi_new/sadasy_parichay/20.pdf पृ. 49

30. National Legislative Conference Interview https://youtube.com/watch?v=mldP5J9Voho&feature=shared

31. मंडवी, वेदमती, पूर्वोक्त पृ. 311

32. साक्षात्कार, श्री नंद कुमार साय (स्वयं) पिता-लेखन साय, ग्राम-भगोरा (कुनकुरी) जिला-जशपुर, कार्य क्षेत्र-कृषि एवं राजनीति क्षेत्र, पूर्व सांसद एवं पूर्व अध्यक्ष केन्द्रीय अनुसूचित जाति आयोग, दिनांक-28/01/2024

33. National Commission for Schedule Tribes - https://g.co/kgs/tx46JEc

34. https://cgvidhansabha.gov.in/hindi_new/mla_ex/2ndass/16.pdf पृ. 118

35. Anmol News 24] CM Sai Birthday Special: CM साय पंच से की थी राजनीति की शुरुआत ऐसे बने मुख्यमंत्री https://www.anmolnews24.com/cm-sai-birthday-special-cm-sai-started-politics-from-punch/

36. https://cgvidhansabha.gov.in/hindi_new/mla_biodata_4th/15.pdf पृ.155-56
37. Digital Sansad – the house of the people-https://sansad.in/ls/hi/members/biography/5013?from=members
38. https://youtu.be/XeGVPho48kE?si=mdYX-562WPjCBL8G
39. DD News Safarnama Interview with MP, Raigarh Loksabha (Chhattisgarh) Gomati Sai-https://youtu.be/CmcUKAW-Kt8?si=cbkY topgM3wxZ0DV
40. Sansad TV Live – The Lawmakers : xkserh lk;] lkaln&jk;x<+] NRrhlx<+https://youtu.be/cS4-Ip68Kxk?si=t7hzWrR4g8XJIfma
41. LSTV (Lok Sabha TV Live) Smt. Gomati Sai raising 'Matters of Urgent Public Importance' in Lok Sabha https://youtu.be/XeGVPho48kE?si=plctpOLJtBxkph9Z

हरवंश सिंह मिरी
शोधार्थी, इतिहास अध्यनशाल
पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि.,
रायपुर (छ.ग.)

प्रो. आभा रुपेन्द पाल
शोध निर्देशक
से.नि. विभागाध्यक्ष, इतिहास अध्यनशाला
पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर (छ.ग.)

❑❑❑

महात्मा गांधी : परिवार में संवाद और सामंजस्य के प्रोत्साहक

• पूर्वा भारद्वाज

अपने मूल रूप में गांधीजी एक औसत पारिवारिक व्यक्ति थे। पुत्र, पति, पिता आदि अनेक रूपों में वे सदैव चिंतन-जिज्ञासा के केन्द्र में बने रहे। गत दिनों एक महत्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित हुई है– ''स्कोर्चिंग लव'' (Scorching Love) *जिसका संपादन मोहनदास के पौत्र, देवदास के पुत्र गोपालकृष्ण गांधी तथा त्रिदिप सुहृद ने किया है। इस पुस्तक में मोहनदास के अपने सबसे छोटे पुत्र देवदास गांधी (द हिंदुस्तान टाइम्स के यशस्वी संपादक) के नाम लिखे लगभग 600 पत्रों की व्याख्या है। इस महत्वपूर्ण कृति का मूल संदेश यह है कि एक राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय व्यक्तित्व होने के बावजूद महात्मा गांधी अपने परिवार की समस्याओं के प्रति पूर्ण सचेत है। वह जितनी शिद्दत से राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय मसलों में हस्तक्षेप करते हैं, उतनी ही तीव्रता से अपने परिवार की समस्याओं में भी हस्तक्षेप करते हैं। ये परिवार में कहीं भी उदासीन दिखाई नहीं देते। वह अपनी पत्नी को वह सब करने के लिए सहमत करने (बाध्य करने में नहीं) में सफल होते हैं, जो वह करना नहीं चाहती। ज्येष्ठ पुत्र हरिलाल से उनकी असहमति बहुत मुखर है। हरिलाल उनके कटु आलोचक हैं। पर गांधीजी न हरिलाल से दूर भागते हैं, न उनका निषेधात्मक तिरस्कार करते हैं बल्कि हरिलाल से बराबर विमर्श करते हैं। वे अपने तर्कों से हरिलाल को सहमत करने का प्रयास करते हैं।*

महात्मा गांधी अपने परिवार के हर सदस्य से संवाद करते हैं। हर सदस्य को समझाने की ही नहीं, उससे स्वयं सीखने हेतु निरंतर तत्पर रहते हैं। उनकी परिवार के सदस्यों से यह संवाद प्रक्रिया इकहरी न होकर द्विआयामी या बहुआयामी है। परिवार में वे सर्वाधिक संवाद अपने कनिष्ठतम पुत्र देवदास गांधी से करते हैं। इस कृति में जिन पत्रों का

उल्लेख है, उनसे स्पष्ट है कि गांधीजी अपने परिवार की समस्याओं के प्रति पूर्ण सचेत है। परिवार के मुखिया होने के कारण परिवार की अनेक समस्याओं के लिए स्वयं को उत्तरदायी समझते हैं। उनकी सारी सहमतियाँ असहमतियाँ परिवार के स्तर पर पूरी तरह से मुखर हैं, इतना कि ये अपने परिवारजनों की गतिविधियों के दायित्व से स्वयं को अलग नहीं कर पाते। 30 जनवरी, 1948 को गोली लगने से पूर्व गांधीजी ने 29 जनवरी, 1948 को रात 9.00 बजे के करीब देवदास गांधी से बातचीत की थी, हालांकि अगली रात वैसी नहीं थी, क्योंकि दूसरे दिन गांधीजी को गोली मार दी गयी थी।[1]

यहां हम पाते हैं कि राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय स्तर का दार्शनिक अपने परिवार के प्रति उतना ही सचेत है जितना राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय मुद्दों के प्रति। वह एक पारिवारिक आदमी है तथा अपने परिवार को लेकर पूर्णतः जागरूक है; परिवार की हर छोटी-बड़ी घटना पर पूरी तरह नजर रखता है। इसी की चर्चा इस शोध पत्र में की जानी अपेक्षित है।

मूल शब्द : *औसत पारिवारिक व्यक्ति, राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय व्यक्ति, उदासीन विमर्श, संवाद, परिवार नायक संस्था, मूल्यहीनता, ममतालु।*

मूल आलेख :

एक व्यक्ति का किसी मानव कल्याणकारी विचार या जीवन मूल्य में रूपांतरण कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। महात्मा गांधी का जीवन साधारण से असाधारण में तथा व्यक्ति से जीवन आदर्श में रूपांतरण एक बहुत जटिल यात्रा और साधनायुक्त कर्म पथ है। यदि गांधी व्यक्ति से जीवन मूल्य या जीवन आदर्श में रूपांतरित हुए तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उनके व्यक्ति होने का महत्व कम हो गया। व्यक्ति अपने आप में एक ठोस तथा जीवन हकीकत होता है, और अमूर्त विचार में परिणम होने पर भी उसका मूल व्यक्तित्व कहीं नहीं खोता। एक दर्शन, एक विचार, एक जीवन-मूल्य में परिणत होने के बावजूद व्यक्ति गांधी को पूरी तरह से पढ़ना, समझना चिंतकों तथा विचारकों के लिए सदैव चुनौती बना रहा है।

क्या यह विचित्र नहीं लगता कि महात्मा गांधी अपने सबसे छोटे पुत्र देवदास गांधी को 5 जनवरी, 1914 को कस्तूरबा की कमजोर हालत तथा बीमारी का विवरण देते हैं, किन्तु इस पत्र का आरम्भ इस वाक्य के साथ करते हैं—''अपना लेख सुधारो'' (Improve your handwriting)[2] इसी प्रकार 15 दिसम्बर, 1921 के आसपास देवदास ने इलाहाबाद से गांधीजी को दो पत्र

लिखे, जिनके उत्तर में गांधीजी साबरमती से लिखते हैं—''पत्र की सामग्री जितनी खूबसूरत है तुम्हारा लेख उतना ही खराब है।'' (your handwriting is as bad as the contents are beautiful)[3] वही 1917 के अंत में एक पत्र में गांधीजी लिखते हैं—मैं तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तुम अपनी दिनचर्या का विवरण मुझे दो। (Let me know your daily programme)[4]

आज हम जिस भयावह दौर से गुजर रहे हैं, उसमें परिवार नामक संस्था लगभग टूट गई है। हम देख रहे हैं कि जो लोग समाज में राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक हैसियत प्राप्त कर लेते हैं, उनके परिवार भी टूट-फूट के शिकार हैं। परिवारों में अराजकता हावी है। बड़ी-बड़ी हैसियत वाले लोगों की संतानें मूल्यहीनता का शिकार हैं। वे खुलेआम अपराधों में शामिल हैं। फिर भी उनके परिवारों के मुखिया अपने दायित्वों के प्रति सचेत नहीं हैं। इतना ही नहीं वर्चस्वशाली लोग अपनी संतानों के अपराधों को ढकने का काम करते हैं। हर हाल में इन लोगों की संतानें स्वेच्छाचरण में लिप्त हैं, नशे की लत उनके लिए सामान्य सी बात है। वे जानते हैं कि उनके वर्चस्वशाली माँ-बाप उनके हर स्वेच्छाचरण को जायज बना सकते हैं।

राजा का बेटा राजा ही होगा—यह परंपरा आज भी अक्षुण्ण है। गांधीजी वर्चस्वशाली जगत में अपवाद हैं। वे यही तो चाहते हैं कि उनके परिवार में लोगों को उनके होने का कोई लाभ ना मिले। यदि वे गांधी परिवार से हैं तो औरों से अलग नहीं है; जो भी उन्हें मिले उनके अपने बल पर मिले, अनुग्रह या वर्चस्व के प्रभाव से नहीं।

यों तो सारा संसार ही गांधीजी का परिवार था, फिर भी व्यक्तिगत स्तर पर उनका भरापूरा परिवार था। उनकी पत्नी कस्तूरबा, चार बेटे, उनकी पत्नियां और उनके बच्चे। जब वे जेल में होते और बा उनके साथ न होती तो उन्हें बा की बहुत चिन्ता रहती। वे किसी न किसी से बा की देखभाल करने का अनुरोध करते। अपने परिवारजनों के प्रति वे कितने संवेदनशील हैं, इसे एक घटना से समझा जा सकता है—23 अप्रैल, 1928 को गांधीजी को अपने भतीजे और दशकों के साथ मगनलाल के देहान्त का समाचार मिलता है तो वे अत्यंत दुखी होते हैं। तथापि पटना में मगनलाल के आतिथेय को लिखते हैं—''दाह कर्म अत्यंत साधारण होना चाहिए।'' साथ ही वे मगनलाल की पुत्री राधा, जो मृत्यु के समय मगनलाल के साथ थी, को आरम लाने की व्यवस्था करने में लग जाते हैं। वे मगनलाल के पिता खुशालचंद को लिखते हैं—''तुम जानते हो कि मगनलाल मेरे लिए तुमसे भी अधिक प्रिय और जरूरी था।'' दिल्ली में रह रहे

देवदास को मगनलाल के देहान्त की सूचना देते हुए मार भेजते हैं— ''तुम पटना मत जाना बल्कि पटना से अहमदाबाद जाते समय दिल्ली में राधा के साथ हो जाना और उसे लेकर आश्रम आ जाना।'' वे जानते थे कि मगनलाल के प्रति देवदास का गहरा लगाव था, इसलिए गांधीजी उन्हें सांत्वना भी दे रहे थे।[5]

गांधीजी का अपने परिवारजनों से गहरा लगाव था। उनके ज्येष्ठ पुत्र हरिलाल से उनके मतभेद रहे। वे अपने प्रथम जीवनीकार जे.जे. डोम को 11 अगस्त 1928 को लिखते हैं—'ज्येष्ठ पुत्र हरिलाल विद्रोही हो गया है। वह शराब पीता है और मस्ती करता है। उसकी दृष्टि में मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सब व्यर्थ और पथभ्रष्टता है।'[6] हरिलाल के साथ गांधीजी के मतभेद काफी मुखर थे। इसका कारण शायद यह भी था कि हरिलाल की गांधीजी से जो अपेक्षाएँ थीं, वे उन्होंने पूर्ण नहीं की। हरिलाल की पत्नी की मृत्यु भी बहुत शीघ्र हो गयी थी, हो सकता है उसका विद्रोह पत्नी की मृत्यु से आये खालीपन के कारण भी रहा हो। जो भी हो गांधीजी और हरिलाल के बीच संवाद बराबर बना रहा। भले वे सहमत न हो पाये हो पर गांधीजी हरिलाल को बराबर पत्र लिखकर समझाते रहे। इतना ही नहीं हरिलाल के पुत्र रसिक तथा नवीन देवदास को बहुत प्रिय थे। यह विचित्र है कि देवदास, रसिक तथा नवीन तीनों शुद्ध शाकाहारी और राष्ट्रभक्त बनकर जामिया मिलिया के मांसाहारी राष्ट्रभक्त वातावरण में संगठित परिवार के रूप में रहे। इस बारे में गांधीजी ने अपने अलग-अलग रह रहे परिवारजनों को मणिलाल और सुशीला को, एन्ड्रूज, एच.एस.एल. पोलम, श्री रामचन्द्रन आदि को लिखा कि 'जामिया हमारे मुस्लिम भाईयों का विद्यापीठ है तथा देवदास जामिया में पढ़ा रहा है और हिन्दू-मुस्लिम सहकार का प्रयास कर रहा है। रसिक तथा नवीन इस काम में उसकी सहायता कर रहे हैं।'

इतना ही नहीं गांधीजी रसिक तथा नवीन की पूरी देखभाल करने को देवदास को निर्देश देते हैं। गांधीजी ने मीराबेन को लिखा था कि खादी के प्रचार के लिए वे देवदास, रसिक तथा नवीन को मेरठ स्थित खादी आश्रम में काम करने के लिए भेजें। दिसम्बर, 1928 में देवदास रसिक तथा नवीन को मेरठ भेजते हैं। जब गांधीजी को यह सूचना मिलती है तो 16 दिसम्बर को गांधीजी देवदास को लिखते हैं—'रसिक और नवीन को मेरठ भेजकर तुमने अच्छा किया। उनसे कहो कि वे अपने अनुभवों को लिखें।'[7]

इससे यह स्पष्ट होता है कि गांधीजी अपनी राजनीतिक गतिविधियों को जारी रखते हुए भी अपने परिवारजनों का पूरा ध्यान रखते थे। इसी बीच

राजनीतिक कार्य के लिए गांधीजी का सिंध यात्रा का कार्यक्रम बन गया। बा उनके साथ थी। मेरठ से दिल्ली आने पर रसिक बीमार हो गया—वह टॉयफाइड का शिकार हुआ। देवदास ने उसे हर सम्भव उपचार दिलाया। उस समय सारे हालात के विषय में देवदास गांधीजी को बराबर अवगत कराते रहे। जब रसिक की दशा चिन्ताजनक हुई तो अपनी यात्रा बीच में छोड़ बा दिल्ली आ गयी ताकि वे रसिक की परिचर्या करा सकें। रसिक की दशा काफी खराब थी। बा और कांति वहाँ पहुँच गये। रसिक बेहोश था। देवदास ने तार द्वारा गांधीजी को रसिक की नाजुक हालत की सूचना दी।

9 फरवरी 1929 को गांधीजी लरकाना में थे जब उन्हें देवदास से रसिक के निधन का समाचार मिला। गांधीजी ने देवदास को लिखा, 'मैं रसिक को बहुत प्यार करता था तथा उससे मुझे काफी उम्मीदें थीं। रसिक की मौत ने मुझे जिन्दगी की हकीकत को समझाया है।'[8] मार्च में ब्रजकिशोर चांदीवाला से मिलने गांधीजी को दिल्ली आना था। वे आये तथा चांदीवाला के अतिथि बने ताकि देवदास पर कोई आर्थिक भार न आये, पर वे देवदास से मिले तथा उन्हें सांत्वना दी। स्पष्ट है गांधी जहां विश्वस्तर के नेता के रूप में अपने दायित्वों का निर्वाह करते थे, वहीं वे भावनात्मक स्तर पर एक सामान्य पिता की तरह अपने परिवारजनों की संवेदनाओं की रक्षा करते थे।

गांधी साहित्य का गहन अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि गांधीजी जितने विराट व्यक्तित्व वाले थे, उतने ही सामान्य व्यक्ति थे। वे अपने परिवार से गहराई से जुड़े थे तथा परिवार के हर सदस्य के दुख-सुख का ख्याल रखते थे। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि अत्यंत साधारण क्रियाशीलनों में ही असाधारण महानता छिपी होती है जिसे निभाना हरेक के बस का नहीं है।

गांधीजी की सामाजिक तथा राजनीतिक प्राथमिकताएं थीं किन्तु कोई भी प्राथमिकता उनके साधनों की पवित्रता में उनके अडिग विश्वास से बड़ी नहीं थी और इनमें भी अहिंसा उनके लिए सबसे श्रेयस्कर थी। वे अहिंसा पर कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। 1940 में देवदास ने वायसराय लिंलिथगो, जिनका वे सम्मान करते थे, के साथ गांधीजी की मुलाकात की व्यवस्था की। के.एम. मुंशी जैसे वकील अपना पक्ष रखने के लिए गांधीजी के साथ थे। किन्तु मैत्रीपूर्ण बहस में भी गांधीजी ने स्पष्ट कह दिया, 'हम लोगों के बीच मतभेद इतने व्यापक है कि आगे भी बातचीत करने का कोई लाभ नहीं है।' और गांधीजी ने अचानक बातचीत समाप्त कर दी।[9]

जब गांधीजी सेवाग्राम लौटे तो देवदास ने गांधीजी को लिखा कि वायसराय के साथ बैठक गांधीजी के कारण असफल हुई। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि गांधीजी हर मामले को तीन कोणों से देखते थे—राजनीतिक कोण, आश्रम कोण तथा पारिवारिक कोण। उनके व्यवहार में कभी-कभी तीनों साथ-साथ चलते थे। इसी मामले में गांधी ने अपने परिवार को पूरी तवज्जो दी। उन्हें पता चला कि देवदास ने अपना आवास किंग्जबे कैम्प की हरिजन बस्ती से 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के कनॉट प्लेस स्थित नये परिसर को एक क्वार्टर में बदल लिया है। बा परिवार से मिलने देवदास के नये परिसर में गयीं। सभी बहुत प्रसन्न हुए, किन्तु बा ने पाया कि अखबार के काम की अधिकता के कारण देवदास काफी दिनों से बीमार है। जब यह समाचार गांधीजी को मिला तो[10] जनवरी, 1940 को उन्होंने बा को लिखा—'वह जब तक जरूरी समझे देवदास के पास तब तक दिल्ली में रुक सकती है। उन्होंने बा को लिखा कि देवदास से कहना कि उसका बार-बार बीमार पड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता। वह अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं करता इसलिए वह काम के दबाव में वक्त पर भोजन भी नहीं करता यदि वह नियमित रूप से समय पर भोजन नहीं करेगा तो बीमार पड़ेगा ही।'[10] यह परिवार के प्रति उनकी गहरी निष्ठा का प्रमाण है।

इतना ही नहीं गांधीजी ने वायसराय को लिखा, 'मैंने पहले भी आपको बताया है कि मेरे पुत्र देवदास के मन में आपके प्रति गहरा सम्मान भाव है तथा आपके साथ अनायास बैठक समाप्त करने का मुझे दोषी मानता है।' दरअसल बैठक के इस तरह खत्म होने से कांग्रेस के नेता भी प्रसन्न नहीं थे क्योंकि लड़ाई अनिवार्य होती जा रही थी। किन्तु गांधीजी अहिंसा को त्यागने की सोच भी नहीं सकते थे। 3 जुलाई, 1940 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में हुए निम्नलिखित संवाद से स्थिति स्पष्ट हो सकती है—

गांधी—मैं कांग्रेस कार्य समिति से बिलकुल भिन्न मानसिकता को स्वीकार करता हूँ।

राजाजी—यह संगठन हमारा राजनीतिक संगठन है तथा हम अहिंसा के लिए नहीं राजनीतिक समझौते के लिए काम कर रहे हैं।

नेहरू—मैं राजाजी की राय से सहमत हूँ।

जिन्ना भी इस राय से सहमत थे। किन्तु गांधीजी अपने विचार पर सुदृढ़ थे। इसका एक प्रमाण और मिलता है कि मणिलाल गांधी ने जिन्ना पर

आक्रमण करते हुए 14 मई, 1940 को 'इंडियन ओपीनियन' में जिन्ना की निंदा की तो गांधीजी ने अपने पुत्र को लिखा, 'जिन्ना पर तुम्हारा आक्रमण उचित नहीं है। हमें अपने मदभेद इस तरह सार्वजनिक रूप से व्यक्त नहीं करने चाहिए।' जाहिर है गांधीजी हर हाल में हिन्दू-मुस्लिम एकता को कायम रखना चाहते थे।' जून में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई जिसमें गांधीजी ने अहिंसा द्वारा अपनी आजादी की रक्षा करने पर बल दिया, कार्यसमिति उनके विरुद्ध निर्णय न ले सकी।[11]

इसी दौरान मणिलाल गांधी की पत्नी सुशीला ने एक पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने इला रखा। 19 जुलाई, 1940 को गांधीजी ने मणिलाल और सुशीला को पत्र लिखा, 'अच्छा है कि प्रसव बिना किसी कष्ट के हो गया। तुमने पुत्री को नाम भी ठीक दिया है। फिर भी गांधीजी मणिलाल और सुशीला से 'इला' का स्रोत पूछते हैं। अन्त में वे एक पंक्ति लिखते हैं, 'इला के कानों में मेरे आशीर्वाद के साथ कहना—वह अपने परिवार के लिए शुभ साबित हो।'[12]

स्पष्ट है कि राजनीतिक घटनाओं की गम्भीरता के बीच भी गांधीजी परिवार के प्रति अपने दायित्व को भूलते नहीं थे। उनका परिवार बहुत बड़ा था। जमनालाल बजाज तो उनके पुत्र ही बन गये थे। फरवरी, 1942 में जमनालाल बजाज की मृत्यु पर गांधीजी स्मरण करते हैं, 'बाईस साल पहले तीस वर्ष का युवक पहली बार मुझसे मिला और कहने लगा—'मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ।' 'यदि मेरी क्षमता में होगा तो जरूर दूंगा', मैंने कहा था। उसने कहा 'मुझे देवदास की तरह अपना पुत्र बना लो।' आज जमनालाल बजाज को खोकर उसकी निष्ठा और उसके समर्पण को भारी मन से याद करता हूँ। उन्हें लगा कि वे इतने धन्य तो अपने जीवित पुत्रों से भी नहीं हुए जितने जमनालाल बजाज से।'[13]

जवाहरलाल नेहरू तो उनके लिए पुत्रवत ही रहे तथा मोतीलाल नेहरू उनके अपने परिवार के सदस्य की तरह थे। जब इंदिरा गांधी ने फिरोज गांधी से विवाह कर लिया तो गांधी ने 'हरिजन' में लिखा, 'इस सम्बन्ध के खिलाफ मुझे क्रोध भरे तथा गालियों भरे अनेक पत्र प्राप्त हुए। किन्तु आश्चर्य है कि किसी ने भी व्यक्ति फिरोज गांधी के विरुद्ध कुछ नहीं लिखा। मुझे लगता है कि उस प्रसंग में फिरोज गांधी का इतना सा अपराध था कि वह पारसी था।'[14] जवाहर लाल नेहरू से उनका प्रेम जगजाहिर था। 15 जनवरी, 1942 को वर्धा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को सम्बोधित करते हुए गांधीजी ने कहा था, 'मैं स्वयं

नहीं जानता कि स्वराज मिलने के बाद मैं क्या करूंगा? पर आज आप लोग मुझसे स्वराज के बदले अहिंसा मांग रहे हो। मेरी भावना को सच्चे अर्थों में हृदय और मस्तिष्क से केवल जवाहरलाल नेहरू समझता है। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि मैं जवाहरलाल के प्रति अधिक ममतालु हूँ। यह आधारहीन बात है पर जब से जवाहरलाल मेरे जाल में फंसा है, तबसे ही उसने मुझे मेरे मार्ग पर सुदृढ़ रहने का सम्बल दिया है। इसलिए मैं जाहिरातौर पर घोषणा करता हूँ कि मेरा वारिस जवाहरलाल ही है न राजाजी, न वल्लभभाई पटेल।' इससे यह स्पष्ट होता है कि नेहरूजी पर उनका कितना विश्वास था।

परिवार की छोटी से छोटी घटना पर वे कितने उत्साहित या निराश होते थे, इसका पता एक घटना से चलता है—देवदास की पत्नी लक्ष्मी ने अपने इण्टर की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर एक दावत दी। गांधीजी ने राजाजी को लिखा, 'वो, लक्ष्मी ने प्रथम श्रेणी में इण्टर उत्तीर्ण कर ली।' तो राजाजी ने गांधी को उत्तर दिया 'लक्ष्मी का प्रथम श्रेणी में इण्टर उत्तीर्ण करना इसलिए महत्वपूर्ण है कि इससे आपको अनिवार्य सुख और उदीप्त स्पंदन मिला है।' चकित करने वाली बात यह है कि देवदास द्वारा सहेजे दस्तावेजों में एक पत्र ऐसा भी मिला है जिसमें हरिलाल ने भी लक्ष्मी को इस अवसर पर बधाई दी है।'[15] यह है बापू का पारिवारिक आत्मीयता का सागर।

1940 के पश्चात् गांधीजी का जीवन राजनीतिक तथा व्यक्तिगत स्तर पर बहुत सक्रियता भरा रहा। इसी काल में 'भारत छोड़ो आन्दोलन' का उन्मेश हुआ तो हिन्दू-मुस्लिम विभाजन की प्रक्रिया भी तीव्र हुई। जिन्ना ने जैसे उन्हें चुनौती दी, 'गांधीजी एक हिन्दू नेता के रूप में प्रस्तुत हो तो मैं मुसलमानों के प्रतिनिधि के रूप में उनका स्वागत करूंगा।' लेकिन गांधीजी का स्पष्ट उत्तर था, 'मुझे गर्व है कि मैं हिन्दू हूँ पर हिन्दू के रूप में मैं किसी के समक्ष नहीं जाऊंगा। कांग्रेस कोई हिन्दू संगठन नहीं है। यदि कांग्रेस हिन्दू संगठन होता तो क्या उसका अध्यक्ष कोई मुसलमान हो सकता था या कार्य समिति में 15 में से 4 सदस्य मुसलमान हो सकते थे?'[16] गांधीजी हर हाल में हिन्दू-मुस्लिम एकता चाहते थे।

अगस्त में वर्धा में 4 से 8 तक कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हुई जिसमें छठे दिन गांधीजी द्वारा वायसराय को एक पत्र लिखा गया, जो धमकी न होकर परस्पर भिडंत को रोकने का प्रयास था। सातवें दिन कांग्रेस कार्य समिति की गोवालिया टैंक मैदान में हुई विशाल सभा में गांधीजी ने साफ-साफ कहा, 'हाँ, मैं आजादी चाहता हूं, तुरंत, सुबह होने से पूर्व इसी रात, यदि यह सम्भव हो।' 8 अगस्त को गांधीजी ने एक ऐतिहासिक वक्तव्य दिया- 'करो या मरो।' या तो

हम भारत को आजादी दिलाएंगे या मर जाएंगे। तभी 'भारत छोड़ो' आन्दोलन का आगाज हुआ।

इसकी प्रतिक्रिया में कांग्रेस के सभी बड़े-बड़े नेता बंदी बना लिये गये तथा उन्हें अलग-अलग जेलों में भेज दिया गया। जब गांधी और बा जेल में दिन काट रहे थे तभी एक वज्रपात हुआ— 15 अगस्त को अचानक महादेव देसाई गिर पड़े और उनके प्राण पखेरू उड़ गये। महादेव देसाई तो गांधीजी के दोनों हाथ थे। उन्होंने महादेव-महादेव की आवाज लगायी पर कोई उत्तर नहीं। बाद में गांधीजी ने लिखा कि यदि महादेव जिन्दा होते तो जरूर उतर देते। महादेव देसाई के आकस्मिक निधन से गांधी तथा कस्तूरबा स्तम्भित रह गये। दूसरे दिन महादेव का विधिवत दाह-संस्कार हुआ और गांधीजी ने उनकी अस्थियों को अपने मस्तक से लगाया। मौलाना आजाद को अहमदनगर जेल में रखा गया था जहां उन्हें सूचना मिली कि 9 मई को उसकी पत्नी जुलेखा बेगम का निधन हो गया। इस समाचार से गांधीजी बहुत आहत हुए।

स्पष्ट है कि गांधीजी एक ओर स्वतंत्रता आंदोलन का संचालन कर रहे थे, तो व्यक्तिगत स्तर पर अनेक आघातों को झेल रहे थे। उधर पूना जेल में कस्तूरबा की हालत भी खराब हो रही थी तथा उनके रिहा होने की सम्भावनाएं भी नहीं थीं। बा को तीन बार हृदयाघात पड़ चुके थे। एक जेल अधिकारी ने देवदास से कहा, 'यदि बा गांधीजी के साथ जेल में मर गयीं तो हम जैसा हृदयहीन (क्रूर) कौन होगा?'[17]

6 जनवरी, 1944 को जब देवदास जेल पहुँचे तो बा की दशा बेहद चिन्ताजनक थी। गांधीजी ने तभी कटेली के खान बहादुर को बा की इच्छा बताते हुए लम्बा पत्र लिखा। उसमें लिखा कि बा से मिलने की आज्ञा कनु गांधी, जयाबेन तथा धर्मेन्द्र गांधी को मिले ताकि वे बा को भजन सुना सकें। उन्होंने यह भी लिखा कि बा के लिए आया की उपस्थिति बेकार है क्योंकि जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती ने उनकी बहुत सेवा की है। प्रभावती बा के लिए पुत्री की तरह है। प्रभावती के पिता ने ही उन्हें आश्रम में सेवा के लिए भेजा था। यदि प्रभावती आ सकें तो श्रेयस्कर होगा। देवदास ने बा को आयुर्वेद के वैद्यों को भी दिखाया क्योंकि बा का आयुर्वेद पर अधिक भरोसा था।[18] स्पष्ट है गांधीजी व्यक्तिगत और पारिवारिक दायित्वों के प्रति उतने ही सजग थे जितने राजनीतिक दायित्वों के प्रति।

यहाँ एक मार्मिक प्रसंग का उल्लेख समीचीन होगा—पास बैठे गांधीजी से

कस्तूरबा ने पूछा, 'हमारी शादी हुए कितने साल हो गये?' गांधीजी ने बा की ओर देखकर कहा, 'क्या शादी की बरसी का समारोह करने का इरादा है?' 'सभी को हंसी आ गयी यहाँ तक कि 74 वर्षीय कस्तूरबा को भी।'[19] जिन लोगों ने इस दृश्य को देखा होगा वे कितने सौभाग्यशाली रहे होंगे क्योंकि विकट घड़ी में इस तरह का विनोद गांधी जैसा महान व्यक्ति ही उत्पन्न कर सकता है। उतना ही नहीं 17 फरवरी, 1944 को गांधीजी नये वायसराय बावेल का स्वागत करते हुए लिखते हैं, 'भारत की आत्मा सभी विदेशी शासनों से मुक्ति चाहती है। कांग्रेस उस आत्मा की प्रतिनिधि है।'[20] इस पत्र में गांधी बा की अचानक बीमारी का कोई उल्लेख नहीं करते, यद्यपि वे जानते थे कि बा के बचने की कोई उम्मीद नहीं है।

23 फरवरी, 1944 को अपने पति के हाथ में अपना हाथ रखे, कस्तूरबा प्राण त्याग देती है। यह शिवरात्रि का दिन है। हरिलाल, रामदास और देवदास तीनों उनके पास बैठे हैं। देवदास बच्चों की तरह बिलखने लगते हैं। दूसरे दिन बा का दाह संस्कार विधि विधान से होता है। 24 फरवरी को एक अत्यंत दुर्लभ क्षण आता है, जब गांधीजी अपने तीन पुत्रों के साथ भोजन करते हैं। मणिलाल तब अफ्रीका में थे। जेल के एक फोटोग्राफर ने इस दुर्लभ किन्तु नितान्त पारिवारिक क्षण को फोटो में कैद कर लिया था।

इन कोमल क्षणों में गांधी की स्थितप्रज्ञता निश्चय ही असाधारण थी। सामान्य व्यक्ति के लिए इस तरह सहनशीलता दिखाना सम्भव नहीं है। यही गांधी के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी शक्ति थी जिसने उन्हें 'महात्मा' बनाया और सारे विश्व में पूजनीय दर्जा प्रदान किया।

निश्चय ही गांधी जी जीवन के हर फ्रेम में महान थे। निडर, साहसी और तेजस्वी स्वतंत्रता सेनानी साथ ही एक परिवार के संवेदनशील मुखिया जो अपने परिवार की हर गतिविधि पर निगाह रखता है और हर समस्या का हल खोजता है। बिना विचलित या शंकित हुए। किन्तु यहाँ एक सवाल जरूर उठता है कि क्या उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र हरिलाल के साथ न्याय किया, जिसके अपने पिता से गहरे मतभेद रहे। हरिलाल ने गांधीजी के सिद्धान्तों के विपरीत आचरण किया। गांधीजी का हरिलाल से नाराज होना स्वाभाविक था। किन्तु क्या पुत्र के नाते हरिलाल की अपने पिता से कुछ अपेक्षाएँ गलत थीं?

जो गांधीजी न किसी के साथ अन्याय करते हैं न किसी के साथ अन्याय होना सहन कर पाते हैं, वे हरिलाल के प्रति इतने निस्पृह कैसे हो गये?

उपसंहार

गांधीजी का व्यक्तित्व बहुआयामी था। वे अपने जीवन में छोटी से छोटी समस्या के प्रति उतने ही सजगह, सक्रिय और संवेदनशील हैं, जितने राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय समस्याओं के प्रति। एक मुखिया की हैसियत से वे अपने पारिवारिक दायित्वों से कभी विमुख नहीं होते। परिवार के हर सदस्य की गतिविधियों पर नजर रखते हैं और यथा समय हस्तक्षेप करते हैं। इसलिए गांधीजी एक अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति होते हुए भी एक औसत पारिवारिक व्यक्ति हैं और पारिवारिक मूल्यों की रक्षार्थ सदा तत्पर रहते हैं।

इसका केवल यही निष्कर्ष निकलता है कि जो वृक्ष अपनी जड़ों को जितनी मजबूती से पकड़े रहता है, वह उतना ही मजबूत होता है और उतना ही छायादार होता है। जड़ों से मिली ऊर्जा उसकी व्यक्तिगत क्षमता उसकी परिधि का निरंतर विस्तार करती है, तो उसकी छाया दूसरों को जीवन के प्रति उदार, सचेत और संवेदनशील बनाती है। प्रकारान्तर से गांधीजी का अपने परिवार के प्रति गहरा लगाव उस दायित्व बोध की पुष्टि करता है, जो उन्हें 'स्व' से जोड़े रखता है और 'पर' में निरंतर परिवर्तित करता रहता है। गांधीजी का यह प्रसंग हमारे, आपके एवं वर्चस्वशाली लोगों के लिए यह संदेश है कि उन्हें अपने परिवार के दायित्वों को भूलकर उसे कभी भी बिखरने नहीं देना चाहिए। गांधीजी के जीवन का भारतीय परिवारों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण संदेश है।

संदर्भ :

1. वाजपेयी, अनन्या (2022 अगस्त 28). ऑफ फादर्स एंड सन्स. ''**द हिंदू मैगजीन**'', नई दिल्ली, पृ. 05
2. गांधी, गोपालकृष्ण एवं सुहृद, त्रिदिप (2022). ''**स्कोर्चिंग लव**'', ओक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, यूनाइटेड किंगडम, पृ. 50
3. वही, पृ. 68
4. वही, पृ. 51
5. वही, पृ. 104
6. वही, पृ. 105
7. वही, पृ. 108
8. वही, पृ. 110
9. वही, पृ. 384
10. वही, पृ. 385

11. वही, पृ. 387
12. वही, पृ. 388
13. वही, पृ. 193
14. वही, पृ. 194
15. वही, पृ. 193
16. वही, पृ. 385
17. वही, पृ. 399
18. वही, पृ. 400
19. वही, पृ. 401
20. वही, पृ. 402

पूर्वा भारद्वाज
एसि. प्रोफेसर
राजनीति विज्ञान विभाग
कानोड़िया पी.जी. महाविद्यालय,
जयपुर (राज.) 302004
मो. 7073637673
punpunbhardwaj@gmail.com.

❑❑❑

आधुनिक जीवन दर्शन और जम्भ वाणी

• डॉ. श्यामा पुरोहित

भारतीय दर्शन में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द ये चार प्रमाण प्रमुख रूप से स्वीकार किये गए हैं। इन प्रमाणों से ही साध्य की सिद्धि होती है। 'आप्त वाक्यं शब्द', 'आप्रस्तु यथार्थ वक्ता' अर्थात् आप्त पुरुष के द्वारा कहा गया वाक्य ही शब्द प्रमाण है और आप्त वही है जो यथार्थ वक्ता हो। ऐसे महापुरुषों की वाणी ही शब्दवाणी कहलाती है। शब्दवाणी का अर्थ ऐसे महापुरुष द्वारा उच्चारण किया गया शब्द जो वाणी अर्थात् पद्य रूप में है, जिन्हें गाया जा सकता है।

शब्दवाणी स्वयं में एक विशिष्ट दर्शन शास्त्र है। शब्दवाणी द्वारा परमात्मा का स्वरूप, जीव की गति और जगत की चकाचौंध, मानव का स्वरूप, गति, कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य को बताकर सचेत किया गया है। महापुरुषों के जीवनानुभवों का 'सार' सूत्र रूप में सबद वाणियों में समाहित होता है। 'सबद' शब्द का कोषगत अर्थ 'वेद' अर्थात् 'ज्ञान' भी बताया गया है। मनुष्य को जीवन-यापन हेतु व्यावहारिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। आदिकालीन साहित्य में सिद्धों की रचनाओं एवं नाथ साहित्य को इसी कारण अत्यधिक महत्त्व दिया गया है। नाथपंथ का प्रभाव गोरखनाथ, कबीर, जाम्भोजी आदि के अनुयायियों में देखा जा सकता है। ये वाणियाँ जहाँ हमें आध्यात्मिक उन्नयन हेतु उत्प्रेरित करती है, वहीं लोक व्यवहार तथा आदर्श जीवन-पद्धति के अनुपालन का मार्ग भी प्रशस्त करती है।

वाणियों, सबदों, परिचय ग्रंथों में संचित ज्ञानकोष मानवमात्र को सदाचार पूर्वक जीवन जीने का मार्ग तो दिखाता ही है। जीवन के चार पुरुषार्थों-धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति में भी सहायक बनता है। मनुष्य के मन में सहज रूप से उठने वाले प्रश्नों एवं जिज्ञासाओं का समाधान इन सबद-वाणियों के स्वाध्याय चिंतन एवं मनन से सहज ही हो जाता है। इनके अनुशीलन से

जीवन में उत्साह उमंग एवं सहजता का प्रादुर्भाव होता है एवं आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। साहित्य वस्तुतः समाज को मानवता का संदेश प्रदान करता है। 15वीं शताब्दी के राजनैतिक उथल-पुथल के समय में भारतीय इतिहास में भक्ति आंदोलन का विशिष्ट महत्त्व है। पश्चिमी राजस्थान में इस आंदोलन का सूत्रपात करने वाले गुरू जाम्भोजी रहे। जिन्होंने एक साधारण किसान से लेकर राजा-महाराजा तक अपने उपदेशों से धार्मिक, सामाजिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में क्रांति पैदा कर दी थी। गुरू जाम्भोजी का कार्यक्षेत्र विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के मारवाड़, बीकानेर एवं जैसलमेर राज्यों में था।

उस समय मरूप्रदेश में शिक्षा, दीक्षा और नैतिकता के स्थान पर नैराश्य, जड़ता और संस्कार हीनता पनप रही थी। आचार, विचार, पवित्रता, शीलता, दया, क्षमा, अहिंसा आदि नैतिक आचरण के गुण समाप्त हो गये थे। लोग अमल, तम्बाखू, भांग, मद्य, मांस आदि का प्रयोग करते थे। ऐसे आचरणों को देखकर ही गुरू जाम्भोजी ने 29 धर्म नियमों का संदेश दिया था।[1]

गुरू जाम्भोजी के सभी कार्य एवं उपदेश जनकल्याण हेतु थे अतः लोगों ने उनको जाना, अनुसरण किया। राजस्थान के मध्यकालीन संत साहित्य में उनका नाम सर्वोपरि लिया जाता है। इनका जन्म प्रसिद्ध क्षत्रिय कुल के पंवार वंश में हुआ। वि.सं. 1508 (1451 ई.) की भाद्रपद कृष्णा अष्टमी, सोमवार कृतिका नक्षत्र में नागौर परगने के पीपासर गांव में हुआ था।[2] गुरू जाम्भोजी के जन्म, नामकरण, शैशव काल के संबंध में अनेक लोककथन हैं। जिनमें जाम्भोजी को जन्म से ही एकांतप्रिय सहज-समाधि में ध्यान लगाने वाले योगी पुरुष के रूप में ही बताया गया है। इस अवस्था को देखकर पीपासर के लोग उन्हें 'गूंगिया' कहते थे। स्वामी ब्रह्मानंद ने जाम्भोजी के बारह वर्ष तक मौन रहने को बताया है।[3] कार्य आचार-व्यवहार आदि में वे अन्य समव्यस्क बालकों से भिन्न तथा अलौकिक शक्ति से युक्त माने जाते थे।[4] उनका बाल्यकाल पशुपालन में बीता, आजीवन ब्रह्मचारी रहे जाम्भोजी अपना घर तथा सारी संपत्ति का परित्याग करके समराथल नामक स्थान पर रहकर सत्संग तथा हरिचर्चा में अपना समय बिताने लगे। वि.सं. 1542 (1485 ई.) कार्तिक कृष्णा अष्टमी को इसी धोरे पर स्नान करके जप करते हुए उन्होंने कलश स्थापना करके बिश्नोई पंथ की स्थापना की थी।[5] इसी पंथ को सुचारू चलाने के लिए इसकी एक आचार-संहिता स्थापित की। पंथ में बीस और नौ (29) धर्म नियम तथा विष्णु की उपासना का विधान होने के कारण बिश्नोई कहे जाने लगे। बिश्नोई धर्म विवेक के अनुसार बिश्नोई शब्द एक मत का ही वाचक है

परन्तु मत के संबंध से यह बिश्नोई शब्द जाति परक हो गया। इस समुदाय में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और जाट, चौहान जाति के मनुष्य हैं।[6] मुख्यत: जाम्भोजी ने अपने संपर्क में आए सभी मनुष्य के जीवन से अंधविश्वास, आडंबर, अनैतिकता को त्याग कर जीवन के व्यावहारिक पक्ष और आचार-विचार को शुद्ध करने की प्रेरणा ही दी है। गुरू जांभोजी के अनुयायियों ने उनकी वाणी के आधार पर उनतीस धार्मिक नियमों को क्रमबद्ध किया, उसका मूल छंद दृष्टव्य है–

तीस दिन सूतक, पांच ऋतुवन्ती न्यारो।
सेरो करो स्नान, शील-संतोष सुचि प्यारो।
द्विकाल संध्या करो, सांझ आरती गुण गावो।
होम हित चित प्रीत सूं होय, वास बैकुण्ठे पावो।
पाणी, बाणी, इन्धणी, दूश इतना लीजें छाण।
क्षमा, दया हिरदै धरो गुरू बतायो जाण।
चोरी, निन्दा, झूठ बरजियो, वाद न करणो कोय।
अमावस्या व्रत राखणो, भजन विष्णु बतायो जोय।
जीव दया पालणी, रूख लीलो नहीं घावै।
अजर जरै जीवत मरै बै मास बैकुण्ठा पावै।
करे रसोई हाथ सूं, आन सूं पलो न लावै।
अमर रखावै थाट, बैल बधिया न करावै।
अमल तमाखू भांग मांस मद सू दूर ही भागै।
लील न लावै अंग, देखत दूर ही त्यागै।
उणतीस धर्म की आखडी, हिरदे धरियो जोय।
जाम्भैजी किरपा करी, नाम बिश्नोई होय।[7]

इस छंद के आधार पर बिश्नोई पंथ के नियम इस प्रकार है–

(1) तीस दिन तक सूतक रखना (संतान उत्पन्न होने पर)

(2) पांच दिन तक रजस्वला स्त्री को गृहकार्यों से अलग रखना

(3) प्रात:काल स्नान करना

(4) शील, संतोष एवं शुद्धि रखना

(5) द्विकाल (प्रातः - सांय) संध्या करना

(6) सांय को आरती करना

(7) प्रातःकाल हवन करना

(8) पानी, दूध, इंधन को छान-बीन कर प्रयोग में लेना

(9) वाणी सोच-विचार कर शुद्ध बोलें

(10) क्षमा रखें

(11) दया से रहें

(12) चोरी नहीं करना

(13) निंदा नहीं करना

(14) झूठ नहीं बोलना

(15) वाद-विवाद नहीं करना

(16) अमावस्या का व्रत करना

(17) विष्णु का भजन करना

(18) जीवों पर दया करना

(19) हरे वृक्ष नहीं काटना

(20) काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं अहंकार को वश में करना

(21) अपने हाथ से रसोई बनाना

(22) थाट अमर रखना (पशुओं बकरी, भेड़, गाय-बछड़ा, बैल आदि को कसाई को न बेचना)

(23) बैल की बधिया न करना

(24) अमल (अफीम) नहीं खाना

(25) तम्बाखू खाना-पीना नहीं

(26) भांग नहीं खाना

(27) मद्यपान न करना

(28) मांस भक्षण न करना

(29) नीले वस्त्र नहीं पहनना

गुरू जाम्भोजी द्वारा बताए इन 29 नियमों को अपनाने वाले बिश्नोई लोगों की अपनी विशिष्ट जीवन पद्धति है। जहाँ लोग गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपने 29 धर्म नियमों के आधार पर जीवन यापन करते हैं। मनुष्य की मुक्ति कहीं जंगल में जाकर कठोर तप करने से संभव नहीं होती, यह तो सहज रूप से इस जीवन में रहकर ही प्राप्त की जा सकती है। इन नियमों का समय-समय पर अनेक विद्वानों द्वारा वर्गीकरण भी किया गया है–(नैतिक, सात्विक, आध्यात्मिक, अंहिसात्मक, पर्यावरणीय) 15वीं शताब्दी में गुरू जांभोजी ने विष्णु की उपासना पर बल देकर धर्म का जयघोष किया। उन्होंने कहा 'गंदे मत रहो, नहावो, धोवो, सदाचार संयम से रहो।[8] जाम्भोजी के ये नियम आज के वैज्ञानिक युग में भी प्रासंगिक है तथा लोग इन नियमों तथा इनके परिणामों से संतुष्ट हैं तथा इन्हें अपनाने में लगे हैं।

बिश्नोई लोक कथाओं के द्वारा इन नियमों का प्रचार-प्रसार हुआ है। ये लोक कथाएँ केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं है, बल्कि इनमें नैतिक नियमों की अभिव्यक्ति भी देखने को मिलती है। प्रत्येक नियम के पीछे नैतिक आचरण की कई कथाएँ प्रचलित है। लोक कथाएँ बनाने एवं सुनाने वाले का यही उद्देश्य रहा था कि इनके माध्यम से लोगों को नैतिक दायित्वों की जानकारी मिले।[9] बिश्नोई धर्म नियमों में स्वच्छ, स्वस्थ, सादगी, नैतिकता, सदाचार, संयम के साथ जीवनयापन करते हुए जीव दया एवं पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया गया है जो आज के भौतिक युग की महती आवश्यकता है। गुरू जाम्भोजी ने पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का क्रांतिकारी कदम उठाया फलस्वरूप बिश्नोई पर्यावरण के प्रहरी कहलाए। हरे वृक्ष न काटना, सब प्राणियों पर दया करना, मांस न खाना, बैल-बधिय न करना, अमर थाट रखना आदि नियमों के प्रचार-प्रसार से जहाँ एक ओर पशुओं को संरक्षण मिला है वहीं दूसरी ओर लोगों में अहिंसा की प्रवृत्ति बढ़ी है। विशेषकर बिश्नोई आज भी शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं। गुरू जांभोजी की वाणी एवं 29 धार्मिक नियमों के आचरण से बिश्नोई समाज का संगठन कुछ इस प्रकार बन गया है कि उसकी अलग पहचान बनी है। समाज के संस्कारों पर भी गुरू जाम्भोजी की वाणी एवं उनकी आचार-संहिता का प्रभाव झलकता है। इसकी संपूर्ण प्रणीती हमें बिश्नोइयों के मेलों, त्यौहारों एवं लोक तीर्थों में देखने को मिलती है।

मध्यकालीन संतों तथा भक्तों के समान गुरू जांभोजी ने अपनी वाणी में गुरू महिमा, नामस्मरण, बाह्यआडंबरों का विरोध किया है। पाखंड और कर्मकांड को नकारते हुए वहाँ खान-पान एवं रहन-सहन में शुद्धता एवं स्वच्छता

पर ध्यान देते हुए पर्यावरण संरक्षण एवं पशुपालन पर बल दिया गया है। जो मूलतः एक व्यावहारिक जीवन पद्धति है।

गुरू जाम्भोजी की वाणी तथा नियमों में किसी प्रकार का आडंबर एवं दिखावा नहीं है। पर्यावरण संरक्षण को जीवन के प्रत्येक संस्कार एवं कार्यकलाप में महत्त्व प्रदान किया गया है। बिश्नोई समाज में सतीप्रथा का कोई प्रचलन नहीं था। चूड़ी पहराना एवं नाता प्रथा द्वारा विधवा-विवाह को प्रोत्साहन दिया गया है। विवाह के आर्थिक महत्त्व को समझते हुए समाज में विनिमय विवाह को प्रोत्साहन दिया गया था। इसके अंतर्गत स्त्री के अधिकारों को समान माना गया है। इससे तलाक जैसी समस्या पर भी नियंत्रण हुआ है।[10] इन नियमों से समाज में स्त्री की स्थिति में निश्चित रूप से सुधार हुआ है। अहिंसा का सिद्धांत भी भारतीय धर्मसाधना का सनातन सिद्धांत है। बिश्नोई पंथ के उनतीस नियमों में पर्यावरण संबंधी दो प्रकार के नियम हैं पर्यावरणीय मूल्यात्मक एवं अहिंसा मूल्यात्मक। यदि मनुष्य हिंसा नहीं करेगा तो वह मांस भक्षण नहीं करेगा जिससे शाकाहार को बढ़ावा मिलेगा वहीं दूसरी ओर मनुष्य में सात्विकता बढेगी, वन्य प्राणियों के संरक्षण से प्रवृति के घटकों में संतुलन होगा यही मूलतः पर्यावरण शुद्धि है। पेड़ों एवं वन्य प्राणियों को बचाने में बिश्नोई पंथ के लोग पर्यावरणीय इतिहास का प्रमुख अध्याय माने जाते हैं।

संसार में रहने वाले सभी जीवन अपनी-अपनी मार्यादाओं से नियमों से बंधे हैं–नेम तलाई, नेम जळ, नेम का जीमो (पीवो) पाहळ[11] आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी इन पांच तत्त्वों के संतुलन से ही धरती पर प्राणी मात्र का विकास जाम्भोजी ने भी स्वीकार किया है। इन तत्त्वों में संतुलन आवश्यक है। इनमें असंतुलन के कारण विश्व के सामने जल, वायु, आकाश, अग्नि एवं मिट्टी के प्रदूषण की गंभीर समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। मानव के शुद्ध सात्विक विकास एवं प्रकृति के तत्त्वों को हानि न पहुँचे, इस हेतु ही समयानुसार महापुरुषों ने विभिन्न नियम बनाए हैं। मरूस्थल के संरक्षक जाम्भोजी ने भी प्राकृतिक संतुलन की आवश्यकता को अनुभव करते हुए इसका मूल मंत्र अपने शिष्यों को दिया। 15वीं शताब्दी में पर्यावरण प्रदूषण जैसी कोई समस्या नहीं थी परन्तु मानव जाति के अस्तित्व को बनाए रखने हेतु प्रकृति के विविध आयामों के संतुलन को आवश्यक समझकर जांभोजी ने जो जीवन दर्शन प्रदान किया वह आज अधिक प्रासंगिक है। इन नियमों एवं पंथ का प्रभाव 15वीं शताब्दी से लेकर आज तक हमें दिर्खा देता है। 1730 ई. में खेजड़ली में आत्म बलिदान की महान घटना में 60 गांवों के, 64 गोत्रों के, 217 परिवारों के, 363

लोगों ने हरे पेड़ों की रक्षार्थ बलिदान दिया। तत्कालीन शासकों तथा महाराजाओं ने इन नियमों के संबंध में समय-समय पर पट्टे-परवाने जारी कर इन नियमों को संरक्षण प्रदान किया।

गुरू जाम्भोजी ने अपनी सबद वाणी में कबीर आदि संत कवियों के समान मूर्ति पूजा, बदुदेववाद का विरोध किया। समाधि, भूत-प्रेत तथा यक्ष योनि वालों की पूजा को पाखंड माना तथा समाधि आदि धोकने हेतु भी मना किया। बाह्यचारों में अनास्था एवं सत्कर्म को महत्त्व दिया।

थे नाथ कहावो नर मर जावो, सो क्यूं नाथ कहावो।
पढ़ि कागल वेदू शास्त्र सबदूं, भूला भूल झंख्यो आलूं।
इह निस आव घटती जाय दै, तेरा सांस सही कसवारूं।
जां जां दया न धरम्‌ं तां तां विक्रमै करम्‌ं।
जां पाळ्यां न सीलूं, तां तां क्रमै कुचीलूं।
जां जां जीव न जोति, तां तां मोख न मुक्ति।[12]

सैद्धांतिक रूप से जंभवाणी में निर्गुण-निराकार ब्रह्म की उपासना पर बल दिया गया है जो संपूर्ण सृष्टि के कण-कण में व्याप्त है। संसार नश्वर है तथा जीव अपने अहं को समाप्त कर ही ईश्वर से आत्म साक्षात्कार द्वारा मिल सकता है। यही ज्ञान योग है। गुरू जांभोजी की वाणी भक्ति-परक रचना है जिसमें विष्णु के सामिप्य लाभ और आत्म-तर्पण की भावना है। उनकी वाणी में विष्णु ही स्वयंभू और तत्त्व स्वरूप है। उनकी भक्ति एक साधारण गृहस्थ की भक्ति है। इसको प्राप्त करने के लिए कहीं जंगल में जाकर घोर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, न ही संन्यास धारण करने की आवश्यकता है। मनुष्य अपने दैनिक कार्यक्रम में ही भक्ति कर सकता है। उनकी भक्ति के मुख्य अंग है– विष्णु नाम का स्मरण, दान की महिमा, जीव दया की प्रधानता, नम्रता, क्षमा और सहनशीलता। गुरू जांभोजी ने विष्णु-विष्णु का जप करते रहने को तथा काम, क्रोधादि को वश में करने को ही जीवन का मूल तत्व माना है। उन्होंने हिन्दु-मुसलमानों को समान रूप से ही अपरम्पर का जप करने का संदेश दिया है। उनके विष्णु शेषनाग की शैय्या पर विराजमान विष्णु नहीं है बल्कि यह तो निराकार, निर्गुण परमतत्व है। जिसका वर्णन ऋग्वेद में भी हुआ है।[13]

जाम्भोजी ने कर्म को सफलता का मूल मंत्र माना। दुविधावृत्ति को त्यागकर, एकाग्रचित होकर यदि मनुष्य कर्म करेगा तभी उसे कार्य में सिद्धी प्राप्त होगी।

दोय मर दोय दिल सींवी न कंथा।

दोय मन दोय दिल पुनी न पंथा।[14]

दुविधावृति का त्यागकर, एकाग्रचित्त होकर गुरमुखी सद्कर्म ही मोक्ष प्राप्ति में सहायक है।

पहलूं किरिया आप कुमाइयै, तो अवरा न फुरमाइए।

गुरू जाम्भोजी की वाणी 'नैतिक वाणी है।' यह जनसामान्य की भावना को समझते हुए कही गई है। जो समस्त मानव-कल्याण के लिए उपयोगी है। उनकी वाणी के आधार पर ही बिश्नोई पंथ की आचार-संहिता निर्मित हुई थी। जिसमें सत्य, अहिंसा, शील, क्षमा, दया, संतोष, दान और परहित को महत्त्व दिया गया है वहीं परनिंदा एवं वाद-विवाद को त्यागने की बात कही गई है। जांभोजी का जीवन जन सेवा में ही व्यतीत हुआ। सन् 1483 के आस-पास संमराथल धोरे पर बैठने पर जांभोजी ने मरूस्थल में पड़े भीषण अकाल से लोगों की स्वयं रक्षा की थी। वे समन्वयवादी विचारधारा के प्रवर्तक थे। उन्होंने हिन्दू-मुसलमान, ब्राह्मण-क्षत्रिय, वैश्य-शूद्र, स्त्री-पुरुष, जाट-भाट, जोगी-दरवेश में कोई भेद नहीं किया और इसी पंथ पर चलने का संदेश दिया। गुरू जाम्भोजी ने कहा था 'उत्तम, मध्यम क्यूं जाणीजै, विवरस देखो लोई।'

मनुष्य की मुक्ति इसी जीवन में ही संभव है। उसे सिर्फ अपने जीवन की विधि को समझना एवं सही बनाना है, उसी व्यक्ति का जीवन सफल हो सकता है। गृहस्थाश्रम में रहकर ही एक साधारण मनुष्य उत्तम जीवन जी सकता है। जांभोजी का जीवन लोकोपकारी कार्यों में ही व्यतीत हुआ। बिश्नोई पंथ की स्थापना के पश्चात् जांभोजी ने संपूर्ण देश की यात्रा करते हुए अपने कार्यों को व्यावहारिक रूप प्रदान किया। अन्नदान, तालाबों-कुओं का निर्माण, अनाथों की सहायता, वन्य प्राणियों एवं पक्षियों को संरक्षण, पेड़ लगाना एवं पशुओं का संरक्षण उनके प्रमुख कार्य थे, जिन्हें उनके अनुयायियों ने भी स्वीकार किया। वे एक महान समाज सुधारक एवं महान क्रांतिकारी थे। उन्होंने व्यापक भ्रमण किया था। इसी भ्रमण के दौरान उनके अनेक शिष्य बने और अनेक व्यक्ति उनके संपर्क में आए। उनका पंथ केवल साधु-समुदाय का प्रतीक ही नहीं था, बल्कि गृहस्थ समाज का नियामक था। इसीलिए उनके संपर्क में गृहस्थ और विरक्त दोनों ही आए थे। बिश्नोई समाज में प्रचलित अनेक लोक-कथाओं में से व्यक्तियों एवं जातियों के मुखियों का, इस पंथ में दीक्षित होने का उल्लेख मिलता है। यह उनकी वाणी एवं उनके आचार संबंधी नियमों का चमत्कार था।

उनकी वाणी से समाज में जड़ता नष्ट हुई ओर उनके नियमों से हरे पेड़ों एवं वन्य प्राणियों को संरक्षण मिला। यह उस समय की ही नहीं आज की भी प्रमुख आवश्यकता है। जाम्भोजी ने पश्चिमी राजस्थान के घोर मरूस्थल में अभावग्रस्त लोगों को स्थानांतरण से रोका। अच्छे बीजों का ज्ञान, कृषि की तकनीकों का विकास, अकाल राहत कार्य, 'काम के बदले अनाज' जैसी योजनाओं का बीजारोपण मरूस्थल में सर्वप्रथम जाम्भोजी द्वारा ही किया गया। जिसे एक नवीन युग का सूत्रधार कहा जाए तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी।

आधुनिक युग की भौतिकवादी संस्कृति, मूल्यहीनता में जहाँ मानव समुदाय दिशाविहीन दौड़ लगा रहा है। तथाकथित प्रगति की होड़ में संपूर्ण विश्व में ही मानवीय मूल्यों का हनन हुआ है। जीवन की सरलता का स्थान मानसिक तनाव, अवसाद एवं कुण्ठाओं ने ले लिया है। धोखाधड़ी-अविश्वास के इस युग में जीव मात्र के प्रति दया, परोपकार, क्षमा का भाव लोगों में विश्वास एवं प्रेम का जागरण करने का मूल मंत्र है। पशुपालन, जीव संरक्षण, पेड़-पौधो का संवर्धन, स्वालंबन, स्वच्छता, परहित को महत्त्व देने जैसे नियम सहज, सरल एवं सुखी जीवन के मंत्र सिद्ध हो सकते हैं। स्त्रियों को समाज में बराबरी का स्थान देना तथा उनके स्वास्थ्य एवं खान-पान पर विशेष ध्यान देना सशक्त समाज की नींव ही है जहाँ महिला सशक्तिकरण की शुरूआत प्रतीत होती है। अनियमित दिनचर्या ही आज अधिकांश बिमारियों का मूल कारण है। प्रात:काल स्नान, द्विकाल संध्या, शील संतोष एवं शुद्धि, शुद्ध खान पान, नियमित दिनचर्या ही इसका सही उपचार है जिसे आज भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व भी स्वीकार कर रहा है।

जीव हत्या और हरे वृक्षों का संरक्षण, पशुओं का संरक्षण आज के पर्यावरणीय असंतुलन में अतिआवश्यक है। पर्यावरण प्रदूषण की विकट समस्या का प्रभावी समाधान वृक्षारोपण एवं वृक्षों का संरक्षण ही है। साथ ही समाज में बढ़ रही नशाखोरी की वृति से युवा वर्ग भ्रमित हो रहा है। समाज के जिस युवा वर्ग की ऊर्जा का उपयोग राष्ट्र एवं संपूर्ण विश्व के कल्याण में होना चाहिए वह दिग्भ्रमित हो रही है। जाम्भोजी के धर्म नियमों को अपनाकर नशामुक्त, सात्विक, धर्मपरायण, स्वस्थ, सशक्त, शुद्धपर्यावरण युक्त समाज का निर्माण किया जा सकता है। सादगी एवं स्वालंबन युक्त जीवन जीने की प्रवृति में आडंबर, दिखावे और थोथे प्रदर्शन को स्थान नहीं होता। जाम्भोजी ने अपने सबदों में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, नैतिक, पर्यावरणीय चेतना को जगाते हुए एक ऐसे मानव समाज की न केवल कल्पना की अपितु उसे वृहद् स्तर पर

निर्मित किया जहाँ जीवन का प्रत्येक पक्ष स्वच्छ, स्वस्थ, सादा, सरल एवं हितकारी है। वह स्वयं में एक अनूठा उदाहरण है जिसे आधार बनाकर तथा सामयिक परिस्थितियों के साथ इन नियमों को अपनाकर नवजीवन का प्रादुर्भाव किया जा सकता है।

सन्दर्भ :

1. गुरू जाम्भोजी एवं बिश्नोई पंथ का इतिहास–डॉ. कृष्ण लाल बिश्नोई–पृ. 45
2. जाम्भोजी महाराज का जीवन चरित्र भूमिका–स्वामी श्री रामदास
3. स्वामी ब्रह्मानंद–श्री जम्भचरित्र भानु–जन्म प्रंसग
4. कल्याण–वर्ष 10 पृ. 817 गीताप्रेस गोरखपुर (उ.प्र.)
5. जम्भसार–नंवा प्रकरण - पृ. 264
6. बिश्नोई धर्म विवेक–स्वामी ब्रह्मानंद - पृ. 5-6
7. गिरि ईश्वरानंद–जम्भचागर पृ. 439-40
8. परमानंद बणियाल का पोथा ग्रंथज्ञान सबदवाणी पत्र 21
9. गुरू जाम्भोजी एवं बिश्नोई पंथ का इतिहास–डॉ. कृष्णलाल बिश्नोई
10. गुरू जाम्भोजी एवं बिश्नोई पंथ का इतिहास–डॉ. कृष्णलाल बिश्नोई, पृ. 112
11. पाहळ मंत्र
12. जंभगीता–सबद
13. ऋग्वेद–मंडल-1 सूक्त 154
14. जंभगीता–सबद

डॉ. श्यामा पुरोहित

व्याख्याता

सिस्टर निवेदिता कन्या महाविद्यालय

बीकानेर

❑❑❑

ढूंढाड़ की लोक-संस्कृति

डॉ. महेश कुमार मीना

किसी भी क्षेत्र के इतिहास को जानने से पहले उसकी भौगोलिक स्थिति को जानना अत्यन्त आवश्यक होता है। इतिहास के भौगोलिक आधारों को समझने के बाद हम उस क्षेत्र से सम्बन्धित बहुत से जटिल प्रश्नों पर अनायास ही प्रकाश डाल सकते हैं और उसकी गुत्थियाँ सुलझा सकते हैं। भौगोलिक दृष्टि से ढूंढाड़ क्षेत्र जिसे सामान्यत: जयपुर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, इसमें वर्तमान जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, कोटपुतली का दक्षिणी भाग, नीम का थाना, सीकर जिले का दांतारामगढ़, अलवर जिले का दक्षिण-पश्चिमी भाग तथा करौली जिले का उत्तरी भाग शामिल है। यह क्षेत्र अरावली पर्वतमाला के आस-पास स्थित है। यह क्षेत्र एक तरफ अरावली की हरी-भरी पहाड़ियों से आच्छादित है तो दूसरी तरफ दौसा एवं जयपुर का विशाल मैदान है। इस क्षेत्र में ढूंढ, बनास, बाणगंगा, रूपारेल आदि बरसाती नदियाँ हैं। ढूंढ नदी की ऐतिसिकता की वजह से ही यह क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता है। इन नदियों एवं अरावली पर्वतमाला की विशेष स्थिति के कारण इस क्षेत्र में प्राचीनकाल से ही मानव बसावट राजस्थान के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक हुई है। इसकी भौगोलिक स्थिति इससे जुड़े मिथक और इसकी संस्थाओं, किलों, महलों, भवनों और धार्मिक स्थलों आदि से जुड़ा इतिहास इसे और भी दिलचस्प बना देता है। संक्षेप में इस क्षेत्र के इतिहास और भूगोल का अन्तर्सम्बन्ध अनूठा है।

ढूंढाड़ की समृद्ध विरासत को समझने के क्रम में यहाँ की लोक संस्कृति को समझना अत्यंत आवश्यक है। ढूंढाड़ की लोक संस्कृति शायद उतनी ही पुरानी है जितनी मानव सभ्यता। विशेष रूप से ढूंढाड़ क्षेत्र में लोक संस्कृति अपनी नैतिक आध्यात्मिक और मूल संवेदनाओं को अभिव्यक्त करती है। सामाजिक जीवन और सम्बन्धित संस्थाओं में लोक-जीवन का महत्वपूर्ण स्थान है। स्थानीय संस्कृति की अभिव्यक्ति लोक जीवन के विभिन्न स्वरूपों-लोक-कला, लोकगीत, लोक-नृत्य, लोक-नाट्य, लोकोत्सवों एवं मेलों में स्पष्ट रूप

से देखी जा सकती है क्योंकि इनके साथ प्राचीन परम्पराएँ एवं विचारधाराएँ जुड़ी रहती है। ये विचारधाराएँ और परम्पराएँ धार्मिक, ऐतिहासिक अथवा सामाजिक होती हैं। ढूंढाड़ के समाज में लोक-जीवन की एक समृद्ध परम्परा विद्यमान रही है जो यहाँ की लोक संस्कृति को जीवन्त बनाती है। प्रत्येक लोकगीत, लोक-नाट्य, लोक-कला, लोकोत्सव एवं मेला यहाँ के लोक जीवन की किसी किंवदन्ती अथवा किसी ऐतिहासिक कथानक से जुड़ा हुआ है। समाज के सांस्कृतिक पहलू की अभिव्यक्ति लोक-जीवन के इन्हीं स्वरूपों में होती है जिनमें प्रत्येक तबके का व्यक्ति सम्मिलित ढंग से बड़े उत्साह से भाग लेता है। ढूंढाड़ क्षेत्र के प्राकृतिक वातावरण में विभिन्नता होने से लोक-कलाओं एवं लोकोत्सवों का भी एक विशिष्ट स्वरूप बन गया है। अलग-अलग मौसम में अलग-अलग स्थानों में वेश-भूषा, नाच-गान या प्रदर्शन आदि विभिन्न विशेषताओं को समेटे हुए ढूंढाड़ भारतवर्ष में अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान रखता है। राजस्थान का ढूंढाड़ क्षेत्र अपनी रंग-बिरंगी संस्कृति हेतु विश्व प्रसिद्ध है।

लोक संस्कृति की समस्त विधाओं में लोकगीत, लोक-नृत्य एवं लोक-नाट्यों का महत्वपूर्ण स्थान है। इन विधाओं में लोकजीवन, मनोरंजन और संस्कृति के विविध रूप देखने को मिलते हैं। इन विधाओं के लिए न कोई ग्रन्थ लिखा गया और न ही इनका प्रणेता कोई आदिपुरुष है। ये विधाएँ सामान्य लोक-जीवन से जुड़ी हुई हैं। सामुदायिक वातावरण और परम्परागत अभ्यास ने इन कलाओं को जीवित रखा है। मौखिक स्मृतियों और लौकिक रूढ़ियों में ढली यह कला आज भी जीवित है। प्राचीनकाल से पनपी यह परम्परा ढूंढाड़ की संस्कृति की प्राण बनी हुई है। ये विधाएँ धर्म, समाज और परम्पराओं से जुड़ी हुई है जो आज भी जनसामान्य में लोकप्रिय है। इन विधाओं को लोक जीवन से इसीलिए जोड़ा गया क्योंकि चाहे गाँव हो या शहर सभी स्थानों में लोकगीतों, लोक-नृत्यों, लोक-नाट्यों का प्रमुख स्थान है। लोक का व्यक्त रूप मानव है, अतएव लोक-संस्कृति व्यवहारिक जीवन का परिष्कृत रूप है। लोक-संस्कृति के तीन मुख्य स्तम्भ लोकगीत, लोक-नृत्य तथा लोक-नाट्य है।

ढूंढाड़ क्षेत्र में लोक-नाट्य की परम्परा बड़ी प्राचीन है, जिसको हम ख्याल, रम्मत, लीलाएँ, नौटंकी, तमाशा और स्वांग के रूप में प्रचलित पाते हैं। लोक-नाट्य किसी के द्वारा रचित नहीं है, उससे सम्बन्धित गीत और संवाद भी किसी ने नहीं बनाये। वास्तविकता तो यह है कि इनकी परम्परागत कथाएँ, संवाद या गीत सम्भागियों को कण्ठस्थ रहते हैं। विशेष प्रकार के आयोजन तथा

धुनों से सम्बद्ध ख्याल, लीलाएँ और स्वांग सार्वजनिक रूप में आयोजित किये जाते हैं जिनमें पात्र और दर्शक भली प्रकार परिचित रहते हैं। एक समूह में प्रस्तुत होने वाले लोक-नाट्यों में वेशभूषा, ढाल, नृत्य, संवाद आदि में बड़ी समानता रहती है। हर गाँव में इसके कोई न कोई पात्र रहते हैं जो इसको व्यवसाय के रूप में नहीं अपनाते अपितु इसके प्रसंगों को रूचि से याद रखते हैं और जिन्हें बड़े सम्मान की दृष्टि से खेला और देखा जाता है। सभी प्रदर्शन साधारण जीवन के अंग होते हैं और अपने आप में लोक-कला के उत्कृष्ट नमूने होते हैं। प्रदर्शनों में नाई, कुम्हार, बैरागी, सरगडे, ब्राह्मण आदि सम्मिलित होते हैं।

ढूंढाड़ लोक-नाट्य की ख्याल शैली के लिए विख्यात है। ख्याल ढूंढाड़ के लोक-नाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा है। ढूंढाड़ क्षेत्र के दौसा, लालसोट, गंगापुर, सवाई माधोपुर आदि क्षेत्रों में 'हैला ख्याल' प्रसिद्ध है जो विशेष रूप से मीणा समुदाय में प्रचलित है। 'हैला ख्याल' में विशेष रूप से पुरुष ऐतिहासिक व सामाजिक विषयों पर गीत गाते हुए नृत्य भी करते हैं। इन ख्यालों ने अपनी प्रसिद्धी राजस्थान से बाहर भी ख्याति प्राप्त की। धर्म और वीर रस प्रधान ख्यालों में एकरूपता दिखाई देने के बावजूद ये अपने-अपने क्षेत्र में ध्येय की दृष्टि से विविधता लिए हुए है। इन ख्यालों की अपनी भाषाएँ तथा स्थानीय परिवेश है, ये ख्याल के अंग है। लीलाओं के माध्यम से धार्मिक एवं सामाजिक जीवन के पक्ष उजागर होते हैं। रामलीला और रासलीला ढूंढाड़ क्षेत्र में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। रामायण और भागवत पर आधारित कथाओं के साथ लोक जीवन को इस तरह प्रदर्शित किया जाता है कि राम, सीता, कृष्ण और राधा एक साधारण व्यक्ति के रूप में आते हैं और उनकी पोशाकें भी लोक-परिपाटी के अनुकूल होती है।

ढूंढाड़ी लोकगीत संगीत के क्षेत्र में अनमोल है। ढूंढाड़ी लोकगीतों में विशेष रूप से मीणावाटी लोकगीतों की प्रधानता है, जो जीवन के प्रत्येक अवसर से जुड़े हुए है। लोकजीवन की जीवन्तता को बखूबी प्रकट करने के कारण मीणावाटी लोकगीत ढूंढाड़ के लोकजीवन की प्राणवायु है जो आज भी ढूंढाड़ी लोकजीवन को जीवंत बनाये हुए है। इनको न तो किसी ने लिखा है और न ही इनका कोई रचयिता है। इनका प्रादुर्भाव मानस और वाणी से सम्बन्धित है। ये मौखिक परम्परा और अनुश्रुति पर आधारित है। इनमें मानव समाज की विशुद्ध मनोवृत्तियाँ और भावनाएँ समायोचित प्रसंगों पर हर्ष-विषाद, प्रेम-ईर्ष्या, उल्लास-भक्ति आदि प्रकट होती है। मौखिक होने से एकल और बहुधा सामूहिक रूप में इन्हें गाया जाता है। युग-युगान्तर से चली आ रही लोकगीत की यह विधा ढूंढाड़ क्षेत्र की संस्कृति के प्राण है। लोकगीतों के माध्यम से बुद्धि,

सौन्दर्य, सुख, भक्ति तथा आनन्द का अनुभव होता है। लोकगीत विभिन्न अवसरों पर सामूहिक रूप से गाये जाते हैं। लोक वाद्यों का प्रयोग इनकी मधुरता में वृद्धि करता है और कभी गीत के भावों को नृत्य द्वारा साकार किया जाता है, जिसे लोक नृत्य कहा जाता है। विवाह और बच्चे के जन्म के अवसर पर गाये जाने वाले गीतों में उल्लास होता है तो पुत्री की विदाई वाले गीतों में लौकिक दुःख का प्राबल्य है। तीज के त्यौहार के गीतों में प्राकृतिक छटा और पति-पत्नी संयोग या वियोग के भावों का अच्छा संयोग दिखाई देता है। जन-जीवन में व्याप्त हर्ष, कामनाओं और अभिलाषाओं का यदि अविरल स्रोत प्राप्त करना है तो वह लोकगीतों में मिलेगा।

लोकगीतों में सर्वाधिक गीत ऐसे हैं, जो संस्कारों, त्यौहारों तथा पर्वों के अवसरों पर परिवार की स्त्रियों द्वारा गाये जाते हैं। इनमें जन्म से लेकर विवाह तक गाये जाने वाले गीतों की संख्या सर्वाधिक है। परिवार में बच्चे के जन्म के अवसर पर गाये जाने वाले गीत को 'जच्चा' कहते हैं। बच्चे के जन्म के कुछ दिन बाद ढूंढाड़ क्षेत्र में 'कुआं पूजन' संस्कार होता है, इस संस्कार पर जो जच्चा गाया जाता है, वो इस प्रकार से है—

जच्चा नाह् लै, नाह्-रै सिंजो लै
परसाया तैल रमा लै यै, म्हारी घणी मंगैजण जच्चा
जच्चा एक कह्यो री, म्हारी सुण लै
सुसरा जी नै आदर कर लै, म्हारी घणी मंगेजण जच्चा।

विवाह के अवसर पर वर की निकासी के समय घुड़-चढ़ी की रस्म होती है। इस अवसर पर 'घोड़ी' गाई जाती है, जो इस प्रकार है—

थै ल्या द्यो नै बना का दादाजी, ऊँची सी घोड़ी
थै ल्या द्यो नै बना का बाबाजी, ऊँची सी घोड़ी
म्हारी घोड़्या कै घुँघर माळ, बरख्या कै फूँदा
वाह चमकैली चन्द्रवळ घोड़ी, भळकला भाला।

विवाह के अगले दिन सुबह जयपुर शहर एवं आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी विशेष रूप से मीणा समुदाय में दूल्हे को 'कँवर कलेवा' देने का रिवाज है जिसमें हँसी-ठिठोली के साथ-साथ स्त्रियों द्वारा गीत गाये जाते हैं। इन्हीं गीतों के माध्यम से वधू पक्ष व दूल्हे के बीच गीतों के माध्यम से ही संवाद होता है जिसका रोचक उदाहरण निम्न गीत के माध्यम से प्रस्तुत है—

धौया-धौया थाळ, परोस दिया भात जी
आवौ कँवरों बैठो म्हाकै साथ जी
बैठो म्हाकै साथ, बताओ थाकी जात जी
बाप म्हारो डेड छै, माई उद्धाळ जी
बुआ म्हारी भगतण, डेडा कै साथ जी
या ल्यो साला जी म्हारा माई-बाप रो गौत जी।

धौया-धौया थाळ, परोस दिया भात जी
आऔ साला जी, बैठो म्हाकै साथ जी
बैठो म्हाकै साथ, बताओ थाकी जात जी
बाप म्हारो चौधरी, माई पटराणी जी
बुआ सौदरा, रसोइयाँ कै माय जी
या ल्यो जीजाजी म्हारा माई-बाप रो गौत जी।।

विवाह के पश्चात दुल्हन की विदाई के समय बिछोह के दुःख को बेटी द्वारा रूंधे हुए गले से निम्न प्रकार से प्रकट किया जाता है—

हैलौ कुण नै दै ली जीजी, थारी लाडी सासरै चाली
जाग-बरण्डो खाली कर चाली
जीजी म्हारी-म्हारी करती, कांकड़ बारह काडै छै
बिदा करैड़ा पावणा नै भायो डांटै छै।

ढूंढाड़ क्षेत्र में अनेक उत्सवों, त्यौहारों, मेलों के दौरान भी अनेक लोकगीत गाये जाते हैं। जिनमें गणगौर, तीज, शीतला माता के मेलों के दौरान गाये जाने वाले गीत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

लोक-नृत्य ढूंढाड़ क्षेत्र के जन-जीवन की संजीवनी बूटी है। अपनी वैविध्ययुक्त पहचान के कारण ही ढूंढाड़ के जन-जीवन ने मस्ती से जीना सीखा। यहाँ के लोक-नृत्यों को तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है- क्षेत्रीय लोक-नृत्य, जातीय लोक-नृत्य एवं व्यवसायिक नृत्य। ढूंढाड़ क्षेत्र के प्रमुख लोक-नृत्यों में कठपुतली नृत्य प्रमुख हैं। कालबेलिया एक प्रमुख नृत्य पारंगत जाति मानी जाती है। यह जाति ढूंढाड़ में सभी जगह पाई जाती हैं। होली, दीपावली व तीज-त्यौहारों पर इस जाति के लोग बड़ी मस्ती के साथ नृत्य करते हैं, जिसमें शरीर

की लोच का प्रदर्शन देखते ही बनता है। कालबेलियों के प्रमुख नृत्य इंडोणी, शंकरिया तथा पणिहारी है। लोक-नृत्यों का सीधा सह-संबंध लोकगीतों से रहा है। लोकगीतों के बिना लोक-नृत्य अधूरे हैं फिर चाहे लोक-नृत्यों का संबंध तीज-त्यौहार, उत्सव मेले, धार्मिक संस्कार किसी भी अवसर से हो।

ढूंढाड़ क्षेत्र में कन्हैया-दंगल और हैला ख्याल की अगर हम बात करें तो ये बड़ी ही समृद्ध लोक कलाएँ हैं जिनमें लोक-संस्कृति की तीनों विधाएँ उपस्थित रहती हैं। इन दोनों ही कलाओं में लोक-नाट्य, लोकगीत तथा लोक-नृत्य तीनों ही विधाओं का अद्‌भुत सम्मिश्रण देखने को मिलता है। यह विधा ढूंढाड़ के दौसा, लालसोट, गंगापुर सिटी, करौली, सवाई माधोपुर क्षेत्र में मीणा समाज की एक समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर है। इस क्षेत्र के ये हैला ख्याल तथा कन्हैया दंगल ऐतिहासिक कथानकों पर आधारित है जो कि सामाजिक जीवन की जीवन्तता को प्रस्तुत करते हैं।

लोक-कलाएँ ढूंढाड़ क्षेत्र के जन-जीवन का अभिन्न अंग है तथा वे ग्रामीणों के आन्तरिक सौन्दर्य, कलात्मक अभिव्यक्ति, लोक रंजकता आदि की परिचायक है। साथ ही ये कलाएँ उनके सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन से जुड़ी विभिन्न परम्पराओं, विश्वासों, अंध-विश्वासों की सरल स्वभाविक अभिव्यक्ति है। इस लोक-कला का दर्शन हम लोग मांडणा, गोदना, थापा, मेहंदी-महावर, सांझी, कठपुतली कला तथा लोक अलंकरण के कुछ अन्य रूपों में करते हैं। मांडणा ढूंढाड़ के लोक-कला का सबसे अधिक विकसित और प्रचलित रूप है। ढूंढाड़ का मांडणा गुजरात की रंगोली, महाराष्ट्र की रंगावली तथा बिहार की अरीपना से केवल आंचलिक रूप से ही भिन्न है। ढूंढाड़ में मीणा समुदाय में मांडणा अलंकरण की परम्परा अधिक प्रचलित रही है। मीणा जाति का राष्ट्रीय पक्षी मोर से अधिक लगाव रहा है इसलिए मोरड़ी (मोरनी) मांडणा उनकी परम्परा का अंग है। सांझी भी ढूंढाड़ के लोक जीवन का अभिन्न हिस्सा है सांझी अश्विन माह की प्रतिपदा से लेकर दशहरा तक सांझी बनाई जाती है। सांझी ढूंढाड़ क्षेत्र की कुमारियों का कलापूर्ण रंग बिरंगा उत्सव माना जाता है। कुँवारी लड़कियाँ सफेदी से पुती हुई दीवारों पर गोबर से आकार उकेरती हैं तथा सांझी को माता मानकर अच्छे घर, वर के लिए कामना करती है। यह कला केवल कलात्मक भावनाओं की अभिव्यक्ति मात्र नहीं है अपितु इसमें प्राचीन, पौराणिक, पारम्परिक, धार्मिक, आध्यात्मिक एवं प्रचलित सामाजिक कथाओं का आलेख भी किया जाता है।

गोदना ढूंढाड़ के लोक अलंकरण की एक विशिष्ट परम्परा है। यह

परम्परागत रूप से प्राचीनकाल से चली आ रही है। किसी तीखे औजार से शरीर की ऊपरी चमड़ी खोदकर उसमें काला रंग भरने से चमड़ी में पक्का निशान बन जाता है, जिसे गोदना कहते हैं। अहीर, गूजर, सांसी, बनजारा, खटीक, कालबेलिया आदि जातियों की महिलाएं गोदना गुदवाने में अधिक रूचि रखती हैं। गोदना सौन्दर्य व अन्धविश्वास का प्रतीक माना जाता है गोदना गुदवाने में प्रकृति की झलक भी देखने को मिलती है। पिछड़ी एवं आदिम जातियों के प्रकृति के करीब होने के कारण गोदना गुदवाने में पशु-पक्षी जैसे–गाय, ऊँट, घोड़ा, मोर-मोरनी, चिड़ियाँ, तोता, सांप, बिच्छू आदि का चित्रांकन फूल पत्तियों व वृक्षों के साथ-साथ किया जाता है। पुरुषों के द्वारा भी गोदना गुदवाया जाता है। गोदना समस्त ढूंढाड़ की पिछड़ी व आदिम जातियों में महिलाओं एवं पुरुषों का विशिष्ट लोक श्रृंगार है जो अब धीरे-धीरे विलुप्त होने की कगार पर है।

लोक-कला के रूप में ढूंढाड़ की कठपुतली कला विश्व भर में प्रसिद्ध है। किलों, महलों एवं प्रमुख पर्यटन स्थलों पर देशी एवं विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केन्द्र यह कला है। वर्तमान में कठपुतली संचार व प्रचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुकी है। जब ग्रामीण लोक-कलाओं की बात आती है तो कठपुतली का उनमें विशिष्ट स्थान होता है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में इन कठपुतलियों का महत्वपूर्ण स्थान है। शहरों में भी विशेष अवसरों पर इनका आयोजन होता था परन्तु समय के साथ बदलाव स्वभाविक है जैसा कि इस कला के साथ भी हुआ और रेडियो, दूरदर्शन एवं सिनेमा के इस दौर में यह कला अब अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है।

ढूंढाड़ में विवाह, होली, दीपावली, अक्षय तृतीया एवं गणगौर के अवसर पर आपस में रंग लगाने और पीठ पर पूरे हाथ की छाप लगाने की परम्परा रही है इसे ही थापा कहा जाता है। मेंहदी-महावर सदियों से चली आ रही मांगलिक लोक-कला है जिसे नारी के सौन्दर्य प्रसाधनों में मेंहदी या महावर रचाना कहा जाता है। कन्याएँ एवं वधुएँ अनेक मांगलिक अवसरों पर मेंहदी एवं महावर अनुरागपूर्वक रचाती हैं। मेंहदी महावर की परम्परा सम्पूर्ण ढूंढाड़ में है जो कि सौभाग्यसूचक मांगलिक अलंकरण है। ढूंढाड़ की एक और लोक-कला है पाना अथवा पाने का निर्माण जिसके अन्तर्गत कागज पर विभिन्न देवी-देवताओं का अंकन किया जाता है तथा त्यौहारों पर इन्हें दीवार पर चिपकाकर पूजन किया जाता है जैसे कि दीपावली पर समस्त ढूंढाड़ में लक्ष्मीजी के पाने की पूजा की जाती है जिसमें लक्ष्मीजी के साथ-साथ गणेश जी एवं सरस्वती जी का भी अंकन होता है।

ढूंढाड़ के जनजीवन में रची-बसी यह लोक-संस्कृति ही समस्त भारतवर्ष में इसकी विशिष्ट पहचान का द्योतक है। इस लोक-संस्कृति की वजह से ही आधुनिकता के इस दौर में भी ढूंढाड़ आज भी अपनी ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत को एक धरोहर के रूप में संजोये हुए हैं। इन लोक-कलाओं की वजह से ही ढूंढाड़ अपनी रंग-बिरंगी सांस्कृतिक पहचान दुनिया भर के सामने प्रस्तुत करता है जिससे दुनिया भर के पर्यटकों के लिए ढूंढाड़ आज भी आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है। आवश्यकता इस बात की है कि हमें हमारी इस अमिट पहचान को संरक्षित एवं संवर्धित करना है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी इससे रूबरू हो सके।

संदर्भ :

1. बांकीदास री ख्यात, पत्र 361, हकीकत बही, वि.सं. 1833
2. श्यामलदास, वीर विनोद, भाग 1
3. जी. एन. शर्मा, सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा, 1968
4. दस्तूर कौमवार, 1757 ई., हकीकत बही, वि. सं. 1833
5. एस. एल. नागौरी, राजस्थान का सांस्कृतिक इतिहास, मलिक एण्ड कम्पनी, जयपुर, 2010
6. दस्तूर कौमवार, भाग 25, पत्र 701 य हकीकत बही, 1766, 1767, 1774 ई.
7. जी. एन. शर्मा, राजस्थान का सांस्कृतिक इतिहास, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2010
8. प्रकाश व्यास, राजस्थान का सामाजिक इतिहास, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 2001
9. पी. डब्ल्यू., पाऊलेट, गजेटियर ऑफ अलवर, 1988
10. जी. एन. शर्मा, आधुनिक राजस्थान का इतिहास, ग्रंथ भारती, जयपुर, 1994
11. देवस्थान फाइल, 18वीं सदी
12. ए हैण्डबुक ऑफ फॉकलोर, लोक संस्कृति विशेष, 2010
13. जवाहरलाल हन्डू, फॉकलोर ऑफ राजस्थान, सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, मैसूर, 1985
14. जयसिंह नीरज, राजस्थान की सांस्कृतिक परम्परा, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2007
15. लक्ष्मी कुमारी चूंडावत, सांस्कृतिक राजस्थान, राजस्थानी ग्रंथागार, जोधपुर, 2022

16. 'हैला ख्याल' में पुरुष चंग की थाप पर सामूहिक गायन एवं नृत्य करते हैं। हैला से अभिप्राय है 'आवाज देते हुए' अर्थात् एक स्वर में हैला देते हुए सामूहिक गायन एवं नृत्य।
17. बच्चे के जन्म के कुछ दिनों बाद जच्चा अपने परिवार से आये कपड़े पहनकर जिसमें 'पीला' अर्थात पीले रंग की ओढ़नी तथा 'चूड़ा' पहनकर परिवार की अन्य स्त्रियों के साथ कुआं पूजती है। इस संस्कार के दौरान गाये जाने वाले गीत को 'जच्चा' कहा जाता है।
18. 'कंवर कलेवा' दामाद को विवाह के अगले दिन जिसे 'बढ़हार' कहा जाता है कलेवा दिया जाता है। इस संस्कार में दामाद के साथ कलेवा में उसके बहनोई भी होते हैं। इस कलेवा के दौरान वधू पक्ष की महिलाएँ 'गाळ गीत' अर्थात् लोकगीतों में गालियां गाते हुए इनके साथ हँसी ठिठोली करती हैं। दोनों पक्ष गीतों के माध्यम से हंसी-मजाक करते हैं।
19. विदाई के समय बेटी अपनी जीजी (माँ) से बेहद दु:खी मन से कह रही है कि वह अब किसे 'हैलो' अर्थात आवाज देगी, उसकी लाडी अर्थात लाडली बेटी तो अब घर खाली कर चली।

20. बी. पी. शर्मा का आलेख 'लोकगीत', राजस्थान की सांस्कृतिक परम्परा, संपादक जय सिंह नीरज
21. एम. एल. गुप्ता, जयपुर संभाग का जिलेवार सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक अध्ययन, नवभारत प्रकाशन, जोधपुर, 2008
22. वाय. आर. यादव, पूर्वी राजस्थान का सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक वैभव, जवाहर कला केंद्र एवं राष्ट्रीय साहित्य संस्थान, जयपुर
23. प्रेमचन्द गोस्वामी, राजस्थान-संस्कृति, कला एवं साहित्य, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2016
24. हुकुमचन्द जैन, नारायणलाल माली, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, पररम्परा एवं विरासत, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2017

डॉ. महेश कुमार मीना

सहायक प्रोफेसर, इतिहास विभाग

वसंत महिला महाविद्यालय, बी.एच.यू.

वाराणसी-221001

email:mkmeena85bhu@gmail.com

मोबाइल : 9451863220

❑❑❑

मारवाड़ के दशनाम मठों के अभिलेखों व ताम्रपत्रों का सर्वेक्षण : एक अध्ययन

डॉ. दिनेश राठी • हुमा गोस्वामी

राजस्थान की विभिन्न रियासतों का इतिहास त्याग, बलिदान उदारता, प्रजा वात्सल्य जैसे मानवीय मूल्यों के साथ गौरवमय रहा है। जोधपुर के शासकों का राजनीतिक प्रभाव भी सम्पूर्ण भारत वर्ष में देखने को मिला है। मारवाड़ के प्रशासन में जहां राजपूतों द्वारा अविस्मर्णिय योगदान रहा है, वही समाज का प्रत्येक तबका भी उससे जुड़ा हुआ था। जोधपुर राज्य जो उस समय अनेक परगनो में बंटा हुआ था जैसे प्रमुख गढ़ जोधपुर, सीवणा, मेहवा, फलोधी, सोजत, जैतारण, सीव (शिव), मेडता इत्यादि।[1] मारवाड़ रियासत जो अपनी भव्यता के साथ स्वामी भक्ति के लिये भी जानी जाती है। भारत वर्ष की विशाल क्षेत्रफल वाली रियासतों में हैदराबाद व कश्मीर के बाद मारवाड़ का नाम आता है। मारवाड़ के परगनों में जो भी दशनाम मठ थे, उनका जोधपुर दरबार के साथ घनिष्ठ संबंध था।[2] ये दशनामी सामी प्रशासनिक, सैनिक व धार्मिक सभी क्षेत्रों में अपनी श्रेष्ठ सेवाओं के साथ इतिहास में महत्व रखते थे।

मारवाड़ के समाज संस्कृति विषयक इतिहास लेखन में स्तम्भ लेख, शिलालेख व अन्य अभिलेखीय सामग्री का विशिष्ट स्थान है। अनेक स्तम्भलेख समसामयिक होने के फलस्वरूप उनमें उत्कीर्ण वृत्तान्त प्रामाणिक माना जाता है। ऐसे स्तम्भ लेख जिन घटनाओं और परिस्थितियों का विवरण प्रस्तुत करता है इतिहास उसे देशकाल की कड़ी में व्यवस्थित करता है।

इस प्रकार के स्तम्भ लेख मारवाड़ रियासत में अनेक स्थानों पर बिखरे मिलते है। यथा भवनों, दीवारों, मंदिरों, मठों स्तुपों, जलाशयों, बावड़ियो और खेतों के बीच गढ़ी हुई शिलाओं पर उत्कीर्ण शब्द हमारे इतिहास और राष्ट्र की बड़ी सम्पदा है। यथार्थ को परिलक्षित करते, सत्य और तथ्यपरक इतिहास लेखन के लिये कच्ची सामग्री के रूप में प्राथमिक स्त्रोतों का सर्वाधिक महत्व

होता है। प्राथमिक स्त्रोत चूंकि समसामयिक होते है अतः उनकी प्रमाणिकता सर्वाधिक मानी जाती है।

ऐसे ही प्राथमिक स्त्रोत के पर्याय है दशनाम मठों में मिलने वाले अभिलेख।[3] दशनाम मठों के इन अभिलेखों द्वारा मठ के महंत की समसायिकता, उनके दरबार से सम्बन्ध, उनको दी जाने वाली जागीर या सासण भूमि, गांव का उल्लेख मिलता है। अपनी शोध यात्रा के दौरान जिन मठो में किसी न किसी स्थान पर अभिलेख उत्कीर्ण पाये गये वे प्रमुख रूप से निम्न है—

1. सर मठ, जोधपुर
2. खरंटिया मठ, बाडमेर।
3. कंवला मठ, जालोर।
4. भावंरी मठ, पाली।
5. परालिया मठ, बाड़मेर।
6. सामी जी की ढाणी, आसियां।

1. सर मठ, जोधपुर

जोधपुर जिले की लुणी तहसील में स्थित सर मठ अपनी विशाल एतिहासिक धरोहर को संभाले है।[4] जिनमें अभिलेखिय सामग्री के साथ अनेक पुरातात्विक वस्तुये भी उपलब्ध हैं जिनमें तलवार जिसकी धार में विष लगा, कटार, ढाल, पौराणिक ताला आदि।[5]

(सर मठः तलवार, कटार, ढाल)

इसमें अतिरिक्त कोठार बहियों में महतो द्वारा लिख रोजनामचा बही, धान के कोठार की हिसाब बही आदि शामिल है। मठ के द्वारा इन सभी पुरातात्विक वस्तुओं का संधारण बहुत ही अच्छे तरिके से किया गया है। यहां पर एक स्तम्भ लेख मिला है। जो मठ के मंदिर प्रांगण में नंदी की छतरी के चार खम्बों में से एक खम्बे पर उत्कीर्णित है।[6]

(सर मठः मंदिर प्रांगण में नंदी के पास लगा अभिलेख)

यह स्तम्भ लेख 17 पंक्तियों से बना है। इसमें इस मठ के संस्थापक महंत लिलकंठ भारती का नाम का उल्लेख मिलता है चूंकि यह स्तम्भ अभिलेख बहुत पुराना है अतः इसे पूरा नहीं पढ़ा जा सका है।

मठ प्रांगण में मुख्य भोजनशाला के आगे की ओर एक प्रस्तर अभिलेख मिला है। यह अभिलेख 12 पक्तियों का है।[7] महंत दयाराम भारती द्वारा पोल निर्माण का कार्य करवाया का उल्लेख मिलता है। इन्हें साजी गांव का पट्टा देने का प्रसंग भी मिलता है। जिसकी पुष्टी महाराजा मानसिंह क समय की मारवाड़

रा पट्टेदारां री विगत के अन्तर्गत गांव साजी (साली) का पट्टा सामी दयाल भारथी तथा इस समय महंत लखा भारती को इनायत हुआ मिलता है।[8] महाराजा मानसिंह के काल में इस मठ के महंतों की कुर्सीनामा में महंत लखा भारती का नाम मिलता है। अत: इस अभिलेख का समसामयिक होने की पुष्टी होती है।[9]

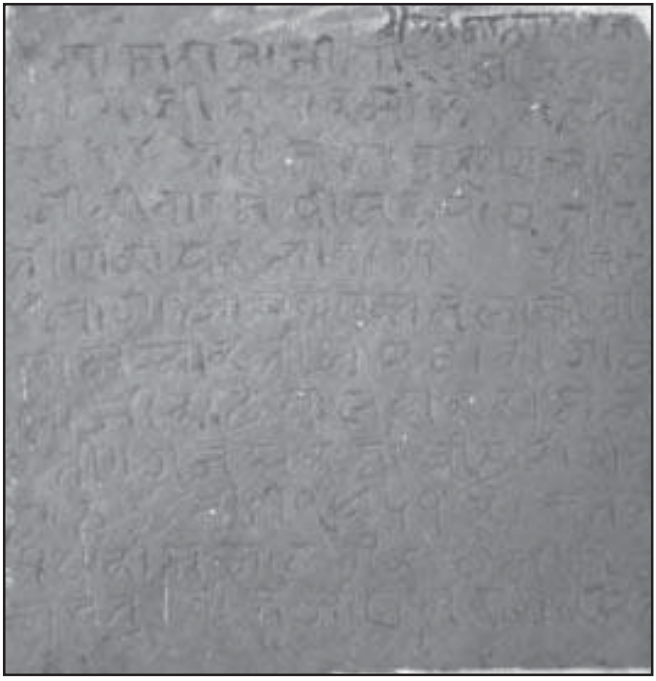

(सर मठ : भोजनशाला के बाहर लगा प्रस्तर अभिलेख)

इस प्रस्तर अभिलेख का अविकल रूप जो स्पष्ट हो पाया है निम्न प्रकार है।

श्रीमाता ध्वज
म्हाराजा जी व द 16 श्री
छी गश्रीदी वा रमा हैं महंत जे
..... ली ज मनई न हाण ज
जीरो वा क न पोल ने पो... सहि
तीण रा प र सा न... प. वी. जमने
इ जा गा व वाण अ ने ला को ग
..... अ भा र ती ने पटा रो गांव

साजी रा टे वा ल दा र राहो वे
तेग गज भार हा जी ..री राम
हुई मि.....लो चौत
दराम भारथी रा ...भी
भक्तुग च जीणरा मठ है

सर मठ से प्रापत अभिलेख में एक फारसी भाषा में लिखा नो मौहर लगा पत्र भी मिलता है जो निम्न चित्र में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है।[10]

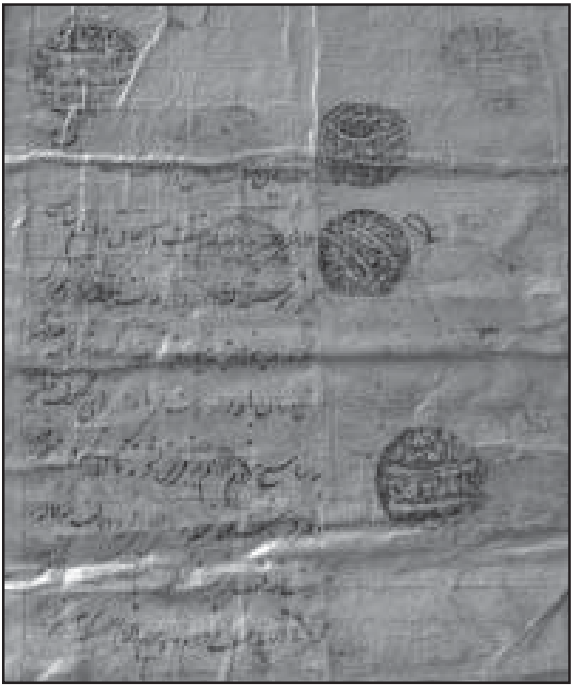

(सर मठ नौ मोहर वाला फारसी पत्र)

विस्तृत सांस्कृतिक विरासत लिये मारवाड़ के मठ अपने इतिहास को संजोकर संभाले हुये है। इसी शृंखला में सर मठ से एक ताम्र पत्र मिला है। इस ताम्र पत्र में महंत दयाराम भारती व उनके गुरू महंत देवाराम भारती के नाम का उल्लेख मिलता है। दस पंक्तियों का यह अभिलेख तलवार का चिह्न लिये हुये है, जिसके ऊपर परमेश्वर जी सहाय छै लिखा है। इस ताम्र पत्र के अंतिम पक्तियों में मारवाड़ के ख्याति प्राप्त इतिहास पुरुष वीर दुर्गादास का नाम भी मिलता है। महंत दयाराम भारती

को जागीर में इनायत पटै का गांव साजी का जिक्र भी इस ताम्र पत्र में मिलता है।[11] इस ताम्र पत्र का अविकल रूप इस प्रकार है।

।। श्री परमेश्वर जी राम छै
।। श्री कृष्ण जी ।। सही
।। सिद्धि जी महाराजधिराज महाराज श्री अजीत
सिंह जी व चनात तथा महंत दयाराम भार
श्री देवानंद भारती रासीष नै मया करनै परम
नै जोधपुर रो गांव 9 साजी तफै रोहीठ री धरम अ
रथ सासण कर नै दी यो छै सो पावसी कोई
थापल न पा व सालोक ।। आपदत परदत जै लो
पंत व संधरा ते मरा नरक जायंत जावत चंदु
दीवाकंर। संवत 1745 रा आसाड सुद 2 भु...
गुसर द दुवो श्री मुख पर वांनगी रा दुर गदास .
रा। उ दै सिंघजी

(सर मठः प्राप्त पुरातात्विक वस्तुओ में ताम्र पत्र)

2. खरंटिया मठ, बाड़मेर

खरंटिया मठ बाड़मेर जिले में स्थित एक प्राचीन मठ है। इसमें दो प्रकार के निर्माण कार्य देखने को मिलते है प्राचीन व आधुनिक। इसमें भी एक जमीन के अंदर धंसा हुआ स्तम्भ अभिलेख मिला है।[12] इस स्तम्भ के दो फलकों पर लेख उत्कीर्ण किया हुआ है। यह अभिलेख बहुत प्राचीन होने के कारण अपठनीय हो गया है। गहनता से देखने पर पीर शब्द को पढ़ा जा सका है। इस मठ के संस्थापक महंत जोगेन्द्र भारती को भी श्पीरों के पीरष के रूप में दन्त कथाओं में याद किया जाता है। इस अभिलेख का अविकल रूप जो स्पष्ट हो पाया है वो इस प्रकार है-

पैन्द पीरसा
ताम्र पतर श्री अकबर पाद साम
पीरा .... श्री
.....
.....
.....
.....

अभिलेख के नीचे का भाग जमीन में गढ़ा होने के कारण अस्पष्ट हो गया है।

इस अभिलेख की नकल जो इस प्रकार है-[13]

श्री पीर महमद सहाय छै, सईद पीर सहाय,

ताबां पतर श्री अकबरशा बादशा खरन्टिया मठ आयकर दिल खुशी होकर दिया अपनी बादशाही के भीतर दस्तुर एह है कि अवलशाजादा की नकल दुसरी उजीर की नाव चौथा कोटवाल का नाव पांचमा परगना का हाकिम का नाम छठा सायर का दरोगा नाव तथा ये हि मठ हिन्दु मुसलमान का ईसट की तकिया है, अवल सकाम में शाहेबंकु याद करणा और मरजाद रखी गउ कटती ही सा हम बन्द करके शरण पीर का बंधा ए ही तांबापतर कर दिया हम राजी होकर कर दिया है, सो फेर आशू कोई खटका करे, कोई गणती करे खेर।[14]

अभिलेखिय साक्ष्य से ताम्र पत्र की नकल को स्तम्भ पर उत्कीर्ण करना प्रतित होता है। शोध यात्रा के दौरान ताम्र पत्र उपलब्ध नहीं हो सका।

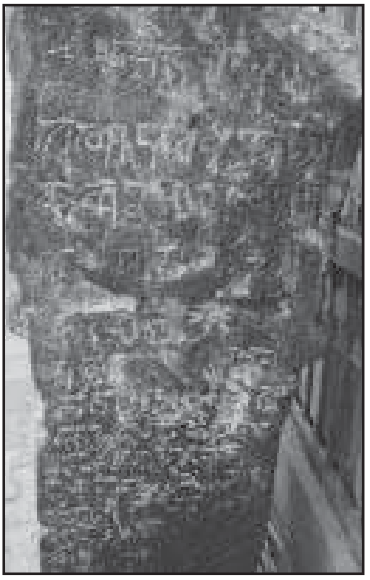

(खरंटिया मठः मठ के प्रांगण से प्राप्त स्तम्भ अभिलेख)

उपरोक्त स्तम्भ अभिलेख के अलावा अन्य पुरातात्विक वस्तुओं में शेर के मुख् वाला भाला, पीर जोगेन्द्र भारती की एक दंत कथा के अनुसार गांय का मास पकाने पर दण्ड स्वरूप मुस्लिम आक्रमणकारियों के कढालिये फोड़ दिये गये, उनकी बाटियां पत्थर की कर दी गई तथा ये पत्थर की बाटियां और फूटे हुये बड़े कढालिये आज भी मठ परिसर में उपलब्ध है।[15]

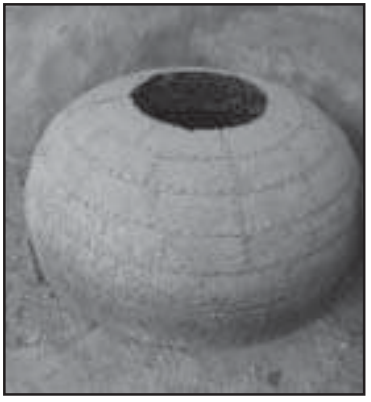

(खरंटिया मठः पत्थर की बाटियां और फूटी हुई कढाई)

3. भावंरी मठ, पाली

अभिलेखीय साक्ष्य में पाली जिले की पाली तहसील में स्थित भांवरी मठ का संवत 1761 का स्तम्भ अभिलेख है। यह पांच पक्तियों में लिखा गया है। इस मठ के संस्थापक महंत गंगापुरी जी का नाम इसमें श्री गगपुरी के रूप में प्रदर्शित होता है जिसमें नाथ नाम अन्य व्यक्ति का उल्लेख मिलता है।[16] इस अभिलेख का अविकल रूप इस प्रकार है।

संवत् 1761 वेर षे वेद
तसर 14 स च द ल स में
श्री गगपुरी जी....
रा र क गर फ या नाथ
वा रे म फे क ।

(भांवरी मठः मठ प्रांगण में पाया गया स्तम्भ अभिलेख)

4. कंवला मठ, जालोर

मारवाड़ और मेवाड़ दोनो साम्राज्यों से जुडा यह एक हेमशाही मठ है। जिसका बहुत ही विस्तृत सैन्य इतिहास रहा है। यह मठ अपनी जमात तैयार करता था। उन्हें सैन्य प्रशिक्षण मिलता था। आज भी इस मठ में बड़ी संख्या में हथियार उपलब्ध है।[17] समय के साथ काफी तो नष्ट प्रायः स्थित में है और कुछ गुम हो गये। इस मठ को न्यायिक अधिकार प्राप्त थे। जिसका साक्षी वहां पर पायी पुरानी हथकड़ी है।

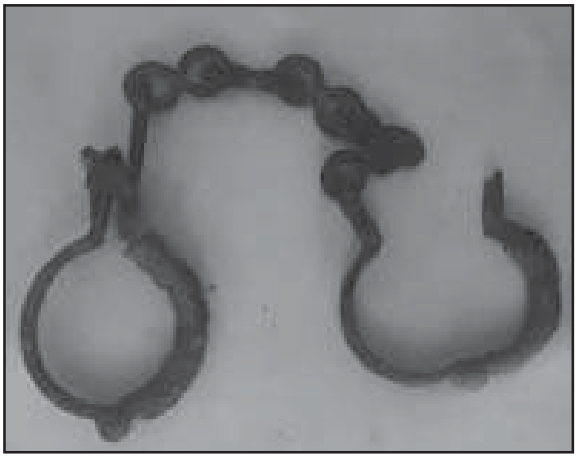

(कवला मठः मठ परिसर में उपलब्ध हथकड़ी)

(कवला मठः मठ परिसर में उपलब्ध अन्य हथियार कटार, बंदुक, तलवार इत्यादी)

इस मठ परिसर में भी दो प्रस्तर अभिलेख मिलते है।[18] प्राचीन अभिलेख महंत हेमपुरी जी की जीवित समाधि के द्वारा के उपर की ओर गजानंद की मूर्ति के साथ लगा हुआ है। इसमें महंत हेम पुरी जी नाम स्पष्ट रूप से दिख रहा है। यह चार पक्तियों का अभिलेख है। जिसका अविकल रूप इस प्रकार है-

श्री मत हेम पुरे जी वेच नता त
प 200) 25 ली गी त णा... ध... न परे जी
.....।। व कलणादुजो ज गर तफै ता
....जी.... सी कव...

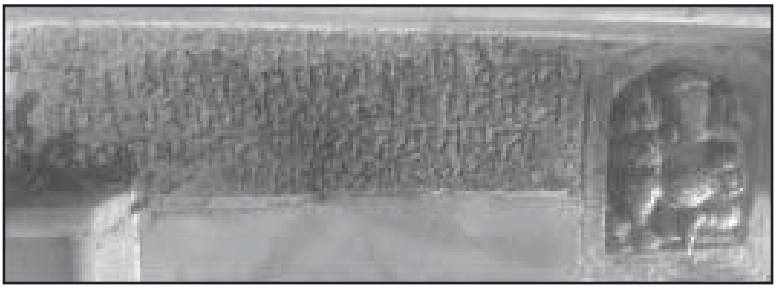

(कवला मठः महंत हेमपुरी की जीवित समाधि पर लगा अभिलेख)

कवंला मठ के पुराने परिसर की पोल पर भी एक स्तम्भ लेख लगा हुआ है। यह मेवाड महाराणा मोकलसिंह जी द्वारा दी गई जागीर का वर्णन करता है। इस अभिलेख में बछड़े को दुध पिलाती गांय का चित्र है। जिसके एक और चन्द्रमा बना है तथा दूसरी ओर सूर्य बना हुआ है। ये सभी पशुधन सरक्षण व पर्यावरण चेतना की ओर संकेत करते है। सात पक्तियों में उत्कीर्ण किया यह अभिलेख मारवाड़ तथा मेवाड़ राज्य के दानशीलता का प्रतिक है।19 इसमें मेवाड़ महाराणा मोकल सिंह द्वारा सासण भूमि का वर्णन मिलता है। आज भी इस मठ में भव्य कार्यक्रमों के आयोजन पर मेवाड महाराणा के वंशज अपनी उपस्थिति दर्ज कराते है। इस अभिलेख का अविकल रूप जो स्पष्ट हो पाया वह कुछ प्रकार है।

श्री महारांणा श्री मोकल सीग जी
रो..... सुरज री परबणी मे
जमीन बीका 1021 के करू जा . के
बीस बीगा दी नी सा श्री हेमपुरी जी
ने गांम कवला संवत 1432 रा
वेसाग वद 13.... झोली भरी
नाज

(कवंला मठः भीतरी मठ की दीवार पर उत्कीर्ण अभिलेख)

कंवला मठ की जागीर में हेमशाही कवलेश्वर एकलिंग नाथ महादेव का मंदिर भी शामिल है। जो मुख्य मठ से 8 किमी दूरी पर स्थित है इस मठ के दोनों ओर पर्वतों का रमणिक स्थल है, तथा तीसरी ओर कंवलेश्वर तालाब स्थित है। प्राचीन वैभवपूर्ण सांस्.तिक इतिहास इस मठ की विशेषता है। इस मठ में एक ताम्र पत्र भी प्राप्त हुआ है, जिसमें मंहत लक्ष्मणपुरी के नाम का वर्णन किया गया है।[20] यह मठ को इनायत जागीर, सिरैपाव व न्यायिक अधिकार का वर्णन करती है। इस मठ को 6 माह कारावास की सजा सुनाने तक का अधिकार जोधपुर दरबार की ओर से प्राप्त हुआ था। यहां कचौड़ी भी लगती थी। और अंदर कारावास भी था। ताम्र पत्र का अविकल रूप जो स्पष्ट हो पाया वह इस प्रकार है। इसमें पक्तियां है।

सही .....

.....

.....

.....

लक्ष्मण पुरी

.....

(कवला मठ से प्राप्त ताम्रपत्र)

5. परालिया मठ, बाड़मेर

जोधपुर से 50 किमी दुरी पर बाड़मेर जिले के कल्याणपुर तहसील में स्थित परालिया मठ अपने वैभवपूर्ण अतित कै साथ विद्यमान है।[21] यहां प्रथम मंहत मदरूपपुरी जी को बालाजी के दर्शन दिये तथा आज भी वे प्रकट रूप में विद्यमान है। इस मठ के अंदर मुख्य सभा कक्षा की दिवार पर एक अभिलेख उत्कीर्ण है। यह आठ पक्तियो का एक अभिलेख है जिसमें संवत 1968 में महंत जोगपुरी द्वारा किसी निर्माण कार्य का जिक्र होता है।[22] इसमें रूपये देने की बात भी लिखी है। अभिलेख पर पेन्ट कर देने के कारण यह अस्पष्ट हो गया है। इसका अविकल रूप जो स्पष्ट हो पाया वह निम्न प्रकार है।

श्री हनुमान जय श्री गणेशायनमः श्री गुरवेनम

।। सं 1968 रा मीती

..... माहाराज श्री श्री 105 श्री नोमपुरी जी महाराज.

श्री श्री 108 सोमपुरी जी..... श्री घजी री वारमडइती

...ल

.....सुथार

.... आ ज की वीवा सुणी मतु जे सर

.....र अतु कल्याण अस्तु .... ।। ।

श्री खराड्पीयादी ना छै

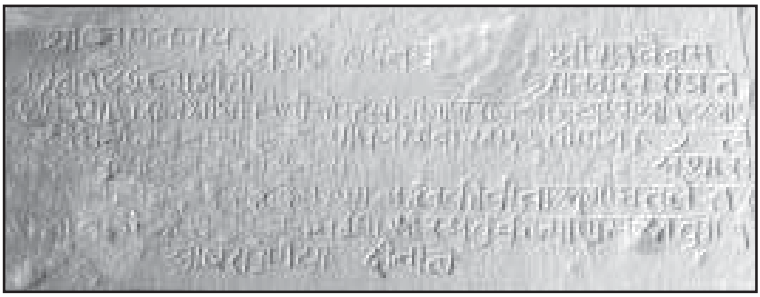

(परालिया मठः मुख्य सभा भवन में लगा अभिलेख)

इसके अतिरिक्त इस मठ के मंदिर प्रागंण में जहां बालाजी का प्रकट मंदिर है, महंत मदरूपपुरी जी की जीवित समाधि है, वहीं पाच अन्य महंतो की

समाधियां बनी हुयी है। इन पांच में से एक समाधि जो महंत जोगपुरी की है. पर भी अभिलेख उत्कीर्ण है। इस स्तम्भ अभिलेख में 15 पक्तियां है। जो केसरियां रंग से रंग दी गई है।[23] इसमें महंत जोगपुरी के शिष्य महंत सोमपुरी द्वारा छतरी निर्माण का समय स. 2035 व कारिगर का नाम राणसिंह मिलता है। इस स्तम्भ अभिलेख का अविकल रूप इस प्रकार है।

श्री श्री 108

मेहन्त

साहब

जोगपुरी जी

चवी कराई

श्री चेला

सोमपुरी जी

कराई संवत

2035 भाद

वा सूदी तेरस

ने कराई

कारीगर

राणसि

ह द्वारा

कोरन

(परालिया मठः महंत जोगपुरी की समाधि पर स्तम्भ अभिलेख)

6 सामी जी की ढाणी, ओसियां

यह सामी संन्यासियों की तपो भूमि है। यहां पर आज भी बढी संख्या में श्रद्धालुओं का तातां लगा रहता है। यहां पर लकवा ग्रस्त लोगों का झाड़ा लगाकर इलाज करते है। सच्ची आस्था के प्रतीक इस स्थान पर लोग ठीक होकर जाते है इस मंदिर के प्रांगण में पुराने परिसर के अंदर की ओर एक स्तम्भ लेख लगा हुआ है।[25] यह गहरा जमीन में धसा हुआ है। उपर कलश रूप में गोल पत्थर बना है, उसके नीचे चौकोर स्तंभ पर शिवलिंग उत्कीर्ण है। तथा नीचे की ओर लेख लिखा हुआ है। यह 19 पंक्तियों का एक लेख है जिसमें सामी जी के नाम का जिक्र मिलता है।[26] मेवासा से इस स्थान का सम्बन्ध स्पष्ट होता है। जिस समय इस लेख को लिखा गया तब का समय स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। अभिलेख का उपर का हिस्सा जो थोड़ा स्पष्ट हो पाया है वह अविकल रूप से इस प्रकार है।

... व च
सी ... ती...
क... वे व ण सुद
12 सो मे वास
रे थ भरत ग्र
साइजी श्री णे
म गी व जीरो
मिद दरी वेरा
हुकम प्रा...
....
....

(सांमी जी की ढाणी : जमीन में धंसा अभिलेख)

राजस्थान में एतिहासिक इमारते प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। यहां पर गांवो में भी बड़ी संख्या में अभिलेखीय सामग्री उपलब्ध हो जाती है। मारवाड़ के दशनाम मठों में भी कई एतिहासिक इमारतें मिलती है। इन मठों के स्थापत्य में उनके अन्दर निर्मित विशेष गर्भ गृह मनोहारी है। जहा शिव की उपासना की जाती है। प्रत्येक मठ में पूर्व महतो द्वारा स्थापित धूणा मिलता है। ये धूणा अग्नि को जीवंत रखने का कार्य करते थे। दशनाम मठ में स्तम्भ लेख भी मिले है। ये स्तम्भ लेख मुडिया लिपि में लिपिबद्ध किये गये थे। जो समय के साथ काफी प्राचीन भी हो गये है। शोध यात्रा के दौरान लिये गये मठो के चित्रों द्वारा उस समय के निर्माण कार्य के समझने का प्रयास किया गया है। मठों के प्रांगण में बनी जीवित समाधियां, उनके उपर की छतरी तथा चौकी पर विराजमान शिवलिंग व नंदी खास आकर्षण का केन्द्र है। प्राचीन सामग्रियों का भी वृहत पेमाने पर भण्डार मिलते है। इस प्रकार प्रचुर सांस्.तिक विरासत लिये अपनी प्राचीन धरोहर को समेटे दशनाम मठ विशाल इतिहास का वर्णन करता है।

सन्दर्भ

1. महाराजा मानसिंह मारवाड़ रा पट्टेदारां री विगत सम्पा: डॉ. विक्रम सिंह भाटी पृ.9
2. राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर, जोधपुर रियासत, हकीकत खाता बही संख्या 10 व 12 से।
3. दशनाम मठों की शोध यात्रा से प्राप्त अभिलेखों की जानकारी।
4. सर मठ की शोध यात्रा से प्राप्त अभिलेखों की जानकारी।
5. मठ के वर्तमान महंत देवेन्द्र भारती द्वारा दी सूचना के आधार पर।
6. यह जानकारी मठ प्रांगण का सर्वेक्षण करने पर मिला।
7. सर मठ के भोजनशाला के सर्वे से प्राप्त सूचना।
8. महाराजा मानसिंह मारवाड रा पट्टेदारां री विगत सम्पा डॉ. विक्रम सिंह भाटी पृ. 62
9. नेहरू लाल राव की बही के अनुसार प्राप्त कुर्सीनामा से।
10. मठ के पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त जानकारी ।
11. मठ से प्राप्त ताम्रपत्र का सर्वे करने पर।
12. खरटिया मठ की शोध यात्रा से प्राप्त अभिलेख साक्ष्य।
13. गिरि महादेव, राजस्थानांक गोस्वामी भाग 1, पृ. 75
14. मठ के आसपास निवास करने वालो से प्राप्त सूचना के आधार पर।
15. शोध यात्रा के दौरान मठ प्रागण से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर।
16. भावरी मठ की शोध यात्रा में प्राप्त अभिलेख की जानकारी।

17. कंवला मठ में उपलब्ध साक्ष्यों का निरिक्षण करने पर।
18. मठ प्रागण के सर्वे से प्राप्त अभिलेख।
19. मठ परिसर में गौशाला के पासउत्र्किण अभिलेख का सर्वे करने पर।
20. कवला मठ के पुरातात्कि साक्ष्यों को देखने पर।
21. परालिया मठ की शोध यात्रा से प्राप्त तथ्य।
22. मठ प्रांगण के सर्वे द्वारा प्राप्त अभिलेख।
23. मठ के मंदिर भाग में स्थित समाधियों के सर्वेक्षण से प्राप्त सूचना।
24. सांमीजी की ढाणी की शोध यात्रा से प्राप्त सूचना।
25. मंदिर परिसर का निरिक्षण करने पर प्राप्त अभिलेख।
26. अभिलेख को देखने से प्राप्त जानकारी के आधार पर।

डॉ. दिनेश राठी
सहायक आचार्य, इतिहास विभाग
जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर

हुमा गोस्वामी
शोधार्थी, इतिहास विभाग
जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर

❑❑❑

दशरथ लाल चौबे : एक क्रांतिकारी एवं पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम संस्थागत प्रयास के जनक

• ज्ञानेश शुक्ला

राजनांदगांव की धरती अपने सांस्कृतिक गौरव के कारण छत्तीसगढ़ की संस्कारधानी कहलाती है क्योंकि यहां उपजे अनेक महापुरुषों ने संस्कारों में परिवर्धन किया तथा नये संस्कारों को जन्म दिया। ऐसे ही एक महापुरुष दशरथ लाल चौबे ने नांदगांव की माटी को नयी सुगंध प्रदान की। दशरथ लाल चौबे एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और प्रखर क्रांतिकारी थे साथ ही राज्य निर्माण आंदोलन में भी उनकी अग्रणी भूमिका थी। वे पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए समर्पित प्रथम संस्था छत्तीसगढ़ महासभा के मुख्य प्रेरणा स्रोत थे।

शब्दावली : *छत्तीसगढ़ के क्रांतिकारी, रायपुर षड़यंत्र केस, छत्तीसगढ़ महासभा, मध्यप्रदेश योग विद्यालय, स्वामी साधनानन्द सरस्वती, परसराम सोनी, कुंज बिहारी चौबे, डॉ. खूबचन्द बघेल।*

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के संस्कारधानी राजनांदगांव में जन्मे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के आधार स्तंभ दशरथ लाल चौबे की भूमिका को उजागर करना है।

1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व ही छत्तीसगढ़ में एक क्रांतिकारी संगठन अंग्रेजों से लड़ने के लिए तत्पर था, इस संगठन में दशरथ लाल चौबे की भूमिका का अध्ययन एवं राज्य निर्माण में उनकी महती भूमिका पर प्रकाश डाला गया है।

मेथडोलाजी :

शोधकर्ता ने अध्ययन के लिए ऐतिहासिक शोध पद्धति का उपयोग किया है। अध्ययन के प्रासंगिक डेटा एकत्र करने के लिए प्राथमिक और द्वितीयक दोनों स्रोतों का उपयोग किया है। परिवार के सदस्यों से साक्षात्कार व मुलाक़ात की गई है, उनसे प्राप्त डेटा को एतिहासिक पद्धति से प्रामाणिकता और वैधता स्थापित की गई है। सिद्धांतों को स्थापित करने में डेटा की वैज्ञानिकता के आधार पर व्याख्या भी की गई है।

जन्म व परिवार

वर्तमान छत्तीसगढ़ (तत्कालीन सी. पी. एवं बरार) प्रांत के राजनांदगांव जिले के नवागांव जो वर्तमान में राजनांदगांव नगर निगम के अंतर्गत वार्ड नंबर 1 है, जिसे बजरंगपुर नवागांव भी कहते हैं, में 20/02/1922 को महान समाज सुधारक छबिराम चौबे व बती बाई के तीसरे सुपुत्र के रूप में दशरथ लाल चौबे का जन्म हुआ। छबि राम चौबे राजनांदगांव क्षेत्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। अस्पृश्यता विरोध के संदर्भ में छबिराम चौबे पं. सुन्दरलाल शर्मा के सहयोगी थे। राजनांदगाँव में वे छुआछूत निरोध कार्यक्रम में उत्साह से लगे हुए थे। उन्होने अस्पृश्य जतियों को जनेऊ धारण कराने का कार्य किया। राजनांदगांव जिले में पं. छबिलाल चौबे ने अस्पृश्यता के विरोध में 21 दिन का उपवास किया एवं अछूतोद्धार कार्यक्रम में तत्समय अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया था। पं. सुन्दरलाल शर्मा एवं पं. छबिराम चौबे ने मुसलमानों एवं ईसाइयों को शुद्ध कर हिन्दू धर्म में पुनः सम्मिलित करने के भी अनेक प्रयास किये वे आर्य समाज के सिद्धांतों से प्रभावित थे।[1]

दशरथ लाल चौबे के बड़े भाई कुंज बिहारी चौबे राजनांदगांव के स्टेट हाई स्कूल के भवन से यूनियन जैक (अंग्रेजी झण्डा) उतारकर स्कूल से बेदखली व अंग्रेजों से बेतों की सजा पाकर राजनांदगांव को आजादी के आंदोलन में पहचान दिला चुके थे, तत्समय यह राजनांदगांव क्षेत्र की अंग्रेज विरोधी सबसे बड़ी घटना थी। दशरथ लाल चौबे के अग्रज कुंज बिहारी चौबे छत्तीसगढ़ के प्रथम क्रांतिकारी व राष्ट्रवादी कवि माने जाते हैं।

प्रारंभिक जीवन

प्राथमिक शिक्षा समाप्त करने के बाद दशरथ लाल चौबे गवर्नमेंट स्टेट हाई स्कूल, राजनांदगांव में भर्ती हो गये। वे एक मेघावी छात्र थे। छात्र जीवन से ही देश सेवा के कार्य में जुड़े रहे। देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता की भावनाये परिवार से ही

मिला था। उन्होने सागर विश्वविद्यालय से विधि विषय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की तथा कुछ समय तक राजनांदगांव में वकालत भी की। दशरथ लाल चौबे के सुपुत्र निशीथ चौबे बताते हैं कि जब कोई गरीब व्यक्ति किसी केस के सिलसिले में उनसे मिलने आते थे, तब वे केस की फीस ना लेकर मुफ्त में ही केस लड़ते थे साथ ही अपनी ओर से भोजन और धन की सुविधा गरीब व्यक्ति को प्रदान करते थे। दशरथ लाल चौबे का विवाह कंकाली पारा, रायपुर के प्रसिद्ध स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी परिवार (रामलाल पांडे) की पुत्री रमा देवी से हुआ था।

क्रांतिकारी जीवन

दशरथ लाल चौबे के जीवन के 18 वर्ष पूरे भी नहीं हुये थे, उन्होंने अपने बड़े भाई कुंज बिहारी चौबे से प्रेरित होकर क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ गए। कुंज बिहारी चौबे परसराम सोनी के भी प्रेरणा स्रोत थे। 1939 में परसराम सोनी की मुलाकात कुंज बिहारी चौबे व दशरथ लाल चौबे से होने के पश्चात् ही छत्तीसगढ़ में क्रांतिकारी आंदोलन के लिए संगठन तैयार किया गया।

भगतसिंह और चन्द्रशेखर आजाद के बाद क्रांतिकारी आंदोलन समाप्त प्राय हो गया। पर चिंगारी राख के नीचे थी, बुझी नहीं थी। आवश्यकता सिर्फ अनुकूल समय की थी। स्वतन्त्रता संघर्ष के दौरान छत्तीसगढ़ के युवकों के एक दल ने सशस्त्र क्रांति का प्रयास किया था। यह घटना रायपुर षड़यंत्र केस या सूरबंधु केस के रूप में जानी जाती है।[2]

कांग्रेस द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन व भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व ही छत्तीसगढ़ में कुछ क्रांतिकारियों द्वारा सशस्त्र विद्रोह की योजनाएं बनाई गई। भगत सिंह, चन्द्रशेखर के शहादत को पढ़कर एवं इन वीर योद्धाओं के किस्से सुनकर इस क्षेत्र के युवा भी गरम पंथियों की ओर आकृष्ट हुए एवं क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया।[3]

छत्तीसगढ़ के इन युवकों में परसराम सोनी, कुंजबिहारी चौबे, दशरथ लाल चौबे, गोवर्धन राम, समर सिंह, सुधीर मुखर्जी, बिहारीलाल, क्रान्ति कुमार भारतीय आदि शामिल थे। ये क्रांतिकारी असेम्बली बमकाण्ड या काकोरी केस जैसी घटना करना चाहते थे। यदि ये अपने प्रयास में सफल हो जाते, तो भारत के क्रान्तिकारी इतिहास में रायपुर नगर का नाम भी जुड़ जाता। वे ऊँचे आदर्शों और आकांक्षाओं से भरे हुए थे।[4]

इस संगठन में कुंजबिहारी चौबे, दशरथलाल चौबे, निखिल भूषण सूर,

सुधीर मुखर्जी के अलावा लाल समर सिंह, प्रेम वासनिक, रणवीरसिंह शास्त्री, क्रांतिकुमार भारतीय आदि शामिल थे। दल की शक्ति बढ़ाने और परिचय बढ़ाने में यह सावधानी बरती गई कि अन्य साथियों का नाम, पता हर एक को मालूम न हो सके। इसका कारण था कि यदि गिरफ्तारी हो जाए तो दूसरों का नाम नहीं बता सकेंगे, ऐसा ही हुआ। संगठन के सदस्य तमाम विस्फोटक पदार्थ अपने पास एक ही दिन रखते थे, मध्य रात्रि के उपरांत दूसरे मित्र के यहां पहुंचा दिया करते थे। सरकार को इस प्रतिक्रियावादी संगठन का हल्का-सा आभास था, यह सन् 1940 के अंत की बात है। 1941 के आरंभ में सेंट्रल इन्टेलिजेन्स का एक अधिकारी भी आया, पर वह असफल ही रहा। वह एक अन्दाजी रिपोर्ट देकर चला गया।[5]

संगठन के क्रांतिकारी लम्बे प्रयासों के बाद निपुण रिवाल्वर निर्माता बन गए। उन्होंने टाईम बम, क्लोरोफार्म बम, फायरिंग बम आदि बनाना सीख लिया। इस संगठन के इस कार्य में गिरीलाल लोहार ने अच्छा सहयोग दिया। मालवीय रोड रायपुर में स्थित ओरिएन्टल होटल का एक कमरा क्रांतिकारियों के विचार-विमर्श का केंद्र बिन्दु था। कुंजबिहारी चौबे, दशरथलाल चौबे, सुधीर मुखर्जी, डॉ. निलिख भूषण सूर, रणवीर शास्त्री, क्रान्तिकुमार भारतीय होटल के उक्त कमरे में विचार-विमर्श के लिये आते रहते थे। संगठन द्वारा निर्मित बमों और रिवाल्वर आदि का प्रयोग इदगाहभाठा और रावणभाठा में करते थे। ये सभी कार्य सतर्कता से किये जाते थे।[6]

तमाम सावधानी के बाद भी शिवनंदन की गद्दारी की वजह से संगठन के क्रांतिकारी असमय ही गिरफ्तार हो गए। शिवनंदन की सूचना पर परसराम सोनी के घर की तालाशी ली गई। 4-5 घंटे तलाशी चलती रही।[7] शिव के अलावा समरसिंह भी पुलिस का गवाह बन गया। तलाशी में कुछ हासिल न हुआ किन्तु कुछ पत्रों के आधार पर गिरीलाल, कुंजबिहारी चौबे, दशरथलाल चौबे, सुधीर मुखर्जी, देवीकांत झा, होरीलाल, सुरेन्द्रनाथ दास, क्रांतिकुमार भारतीय, कृष्णराव थिटे, सीताराम मिस्त्री, भूपेन्द्रनाथ मुखर्जी और प्रेम वासनिक भी गिरफ्तार किए गए। इन क्रांतिकारियों को ए.डी.एम. की अदालत में पेश किया गया।[8]

कथित रायपुर षडयंत्र केस की खुली पेशी 11 जनवरी, 1943 से प्रारम्भ हुई। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की अदालत में अभियुक्तों पर मुकदमे की सुनवाई आरम्भ हुई। ठाकुर एडवोकेट नागपुर ने सरकार की ओर से पैरवी की तथा अभियुक्तों की तरफ से सर्वश्री एम. भादूरी, पी. भादूरी, श्री वी.पी. तिवारी,

अहमद अली आदि नामी-गिरामी वकीलों ने पैरवी की। इस षडयंत्र केस में कुल 15 अभियुक्त बनाये गए थे तथा सरकारी गवाहों की कुल संख्या 71 थी जिसमें कवर्धा, नांदगाँव, सरगुजा स्टेट के पुलिस कप्तान, श्री जे. योगानन्दम, प्रिन्सिपल छत्तीसगढ़ कॉलेज आदि प्रमुख रूप से थे। अभियुक्तों पर पुलिस द्वारा 120, 302, 395, ताजी-रात-ए-हिन्द और आर्म्स एक्ट की धारा 20 भारत रक्षा कानून 35 और 38 धारा मय 34 एवं ओ.पी. लागू की थी।[9]

नौ माह तक मुकदमे का नाटक चलता रहा। यह मुकदमा ए.डी.एम. केरावाला की अदालत में चला अभियुक्तों के विरुद्ध सरकार को रायपुर में वकील ही न मिल सका। फलतः बाहर से वकील लाकर सरकार ने मुकदमा लड़ा। कुल 171 गवाह और 130 डाकूमेंट्स पुलिस पेश किया। आर्म्स एक्सपर्ट ने संगठन के द्वारा बनी रिवाल्वर की भूरि-भूरि प्रशंसा की।[10] 28 अप्रैल 1943 को खचाखच भरी अदालत में रायपुर षडयंत्र केस के अभियुक्तों का फैसला सुनाया गया।[11]

इस मुकदमे के बाद परस राम सोनी को 7 वर्ष, गिरिलाल को 8 वर्ष की कड़ी सजा, सुधीर मुखर्जी को 2 वर्ष, देवीकान्त झा, सुरेंद्र नाथ दास और दशरथ चौबे को 1-1 वर्ष की सख्त कैद की सजा दी गयी।[12]

सन् 1857 की सशस्त्र कांति से लेकर सन् 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति तक छत्तीसगढ़ की जनता ने स्वराज्य प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय धारा के समानान्तर महत्त्वपूर्ण कार्य किया। रायपुर, उदयपुर संबलपुर, सोनाखान व बस्तर में हुई अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति से यही ज्ञात होता है कि यहाँ के रण बांकुरे किसी भी दृष्टि से कम नहीं थे। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर इनका मूल्यांकन अद्यतन प्रतीक्षित है। सरगुजा से लेकर बस्तर तक छत्तीसगढ़ के एक बड़े भूभाग में जनता भी अपने अधिकारों के लिए जागृत थी। ब्रिटिश अभिलेख प्रायः तत्कालीन ब्रिटिश शासकों के दृष्टिकोण से लिखा गया प्रतीत होता है, इसलिए छत्तीसगढ़ क्रांतिकारियों के संबंध में विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाती है।[13]

पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम संस्थागत प्रयास के जनक

वाचिक व साहित्यिक परंपरा में इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ के नाम से 14वीं शताब्दी से जाना जाता था किन्तु प्रथम बार किसी सरकारी रिपोर्ट में वर्ष 1910 ई. में बिलासपुर गज़ट में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग हुआ। वर्ष 1918 ई. में पं. सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट रेखाचित्र खींचा। उन्होंने छत्तीसगढ़ प्रांत की भौगोलिक सीमा को विशेष ढंग से रेखांकित किया।[14] ''जो

भाग उत्तर में विंध्य श्रेणी व नर्मदा से दक्षिण की ओर इंद्रावती नदी से ब्राह्मणी नदी तक है, जो पश्चिम में वेनगंगा के मध्य में अवस्थित है, जहाँ गढ़ नामवाची ग्राम संज्ञा है, जहाँ सिंग बाजा का प्रचार है, जहाँ स्त्रियों का पहनावा व वस्त्र प्रणाली प्रायः एक है, जहाँ कृषि में धान प्रधान उपज है।''[15]

राज्य निर्माण की अवधारणा के पीछे हम यह तथ्यगत बातें पाते हैं कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ऋषि संस्कृति, कृषि संस्कृति और वन संस्कृति से संस्कारित हैं। साधुता, सरतला, भोलापन से जीवन यापन करने वाले स्वस्थ और शांत स्वभाव के लोग हैं। यहां के लोगों में आपसी सहयोग, सद्भावना और सामाजिक समरसता की भावना भी सांसों में कूट-कूट कर भरी हुई थी। इसलिये अमीरी और गरीबी में भी समभाव मानकर संतोष करते हुए जीवन जीते थे। गांव के किसी भी परिवार के सुख और दुःख को अपना सुख और दुःख मानकर चलते थे। आपसी तौर पर समस्या को सुलझा लेते थे।[16]

छत्तीसगढ़ की इस सुव्यवस्था को देख कर विदेशी भी प्रभावित हुए और अनेक संस्मरणों, यात्रा वृतांतों में छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी समाज की संस्कारों और व्यवस्थाओं की अच्छाई को रेखांकित भी किए। उसके बाद छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी समाज में मुगल बादशाह, मराठा शासक एवं अंग्रेजों ने एक-एक करके इस सुव्यवस्था को तोड़ने एवं सामाजिक समरसता की भावना में जहर घोलने का कार्य किया।[17]

जब हिन्दुस्तान 15 अगस्त, 1947 को आजाद हो गया, उसके बाद देशीय राजनैतिक शासकों एवं नेताओं ने अंग्रेजों द्वारा फूट डालो और राज करो की नीति को ही अपनाकर उसको और अधिक हवा देने लगे। छत्तीसगढ़ी समाज के भोले-भाले सरल स्वभाव के लोग शासकों, राजनेताओं की चालाकी, चुस्ती और षड्यंत्र के शिकार होते गए। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दशा और दिशा बिगड़ती चली गयी। यहां के लोग अपने ही जल, जंगल और जमीन से शरणार्थी हो गए। और जो शरणार्थी थे, वे यहां के राजनेता, अधिकारी, व्यापारी, धार्मिक स्थलों के मठाधीश बन गए। इन तीनों की तिकड़ी ने मिलकर छत्तीसगढ़ के संसाधनों, उत्पादन, वनोपज, जल, जंगल और जमीन का अंधाधुंध लूटने का एक चक्र चलाया। यहां के प्रतिभाओं को बौना बनाने और उपेक्षा का शिकार बनाने का घिनौना खेल खेला। यहां के पढ़े-लिखे लोगों को रोजगार से वंचित किया।[18]

स्वतन्त्रता मिलने के कुछ समय के उपरांत ही रायपुर के तत्कालीन

विधायक और ठाकुर प्यारेलाल सिंह के पुत्र ठाकुर रामकृष्ण ने पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत किया। तत्कालीन मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के पं. रविशंकर शुक्ल की उदासीनता इस संदर्भ में आंदोलन के लिए शुभकर साबित नही हुआ। यह ऐतिहासिक सच्चाई है कि यदि समकालीन राजनेता पुरजोर प्रयास करते तो 1956 में ही पृथक छत्तीसगढ राज्य बन गया होता, किन्तु विधायक ठाकुर रामकृष्ण अकेले पड़ गये और आयोग ने उनकी मांग को महत्व नही दिया।[19]

मध्यप्रदेश के नव निर्माण के समय आयोग के अध्यक्ष मो. हिदायतुल्लाह थे वे छत्तीसगढ़ संबंधी अवधारणा से सहमत थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस तथ्य का उल्लेख भी किया था कि नये मध्यप्रदेश की आबादी एक करोड़ 37 लाख लोगों में से 75 लाख अकेले छत्तीसगढ़ के हैं यानी कि जनसंख्या के आधार पर भी छत्तीसगढ़ राज्य बनने की योग्यता रखता है।[20]

इन्ही परिस्थितियों में दशरथ लाल चौबे ने वकालत छोड़ दी और छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण आंदोलन से जुड़ गए। 1956 में डॉ. खूबचन्द बघेल के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के प्रयास को आगे बढ़ाने हेतु प्रथम संस्था का गठन किया। इसके पूर्व छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा हेतु अनेक संस्थाओं का गठन हुआ था किन्तु दशरथ लाल चौबे व डॉ. खूबचन्द बघेल के सम्मिलित प्रयासों से राज्य निर्माण की गति जोर पकड़ी। दशरथ लाल चौबे के प्रभावों के कारण ही छत्तीसगढ़ महासभा की स्थापना बैठक राजनांदगाँव में हुई। वे छत्तीसगढ़ महासभा के संस्थापक महासचिव थे, वे राज्य निर्माण आंदोलन के आधार स्तंभ थे।

राजनांदगांव में 26 से 29 जनवरी 1956 को द्वितीय छत्तीसगढ़ी निर्दलीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के कोने-कोने से कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। दशरथ लाल चौबे इस संबंध में लिखते हैं— छत्तीसगढ़ की जनता इस सम्मेलन की ओर बड़ी आशाएं लिये देख रही है। यह निश्चित है कि इस संस्था द्वारा छत्तीसगढ़ में स्वस्थ, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण होगा और छत्तीसगढ़ प्रगति के क्षेत्र में देश के किसी भी हिस्से से पीछे नहीं रहेगा।[21]

सन् 1956 में छत्तीसगढ़ राज्य की कल्पना को साकार रुप देने जुझारु एवं कर्मठ कार्यकर्ताओं का एक वृहद सम्मेलन राजनांदगाँव में आयोजित किया गया। इसके पहले सत्र की अध्यक्षता बैरिस्टर मोरध्वजलाल श्रीवास्तव एवं दूसरे

सत्र की अध्यक्षता बाबू पदुमलाल पन्नालाल बक्शी ने की। सम्मेलन में 'छत्तीसगढ़ी महासभा'' का गठन हुआ। सर्वसम्मति से इस महासभा के अध्यक्ष डॉ. खूबचन्द बघेल व महासचिव दशरथलाल चौबे निर्वाचित हुये। महासचिव दशरथलाल चौबे ने अपने भाषण में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के माँग के औचित्य पर व्यापक प्रकाश डाला फलस्वरुप सर्वसम्मति से ''छत्तीसगढ़ राज्य'' निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया। इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना के संघर्ष की नींव डल गई।[22]

इसी समय राज्य निर्माण से संबंधित एक बैठक बुलायी गई जिसमें दशरथ लाल चौबे, खूबचंद बघेल, घनश्याम सिंह गुप्त, मोरध्वज श्रीवास्तव, क्रांति कुमार भारतीय, रत्नाकर झा, अंबिकाचरण चौबे, खेमचंद जंघेल, बृजलाल वर्मा, (तत्कालीन विधायक), नंदूलाल चोटिया, बुधराम डडसेना, हरि ठाकुर, केयूर भूषण, कमल नारायण शर्मा आदि प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अधिवेशन में लगभग 15,000 लोगों को दशरथ लाल चौबे व खूबचन्द बघेल ने उद्बोधित किया।[23]

राजनांदगांव में आहूत इस राजनीतिक सम्मेलन के अंत में अर्थात 29 जनवरी को खूबचंद बघेल के प्रस्ताव पर छत्तीसगढ़ महासभा का गठन हुआ। इसके महासचिव दशरथलाल चौबे, अध्यक्ष डॉ. खूबचंद बघेल एवं संयुक्त सचिव हरि ठाकुर और केयूर भूषण बने। महासभा में संस्कृति इतिहास और साहित्य को प्रकाश में लाने के लिए उप समितियां का गठन किया गया जिसमें नारायण लाल परमार, जगन्नाथ बघेल आदि को सम्मिलित किया गया। समिति के संयोजक हरि ठाकुर मनोनीत किए गए। दाऊ रामचंद्र देशमुख ने कला संस्कृति की जिम्मेदारी ली साहित्य व इतिहास पक्ष का दायित्व हरि ठाकुर ने संभाला। पृथक छत्तीसगढ़ प्रांत की मांग का प्रस्ताव महासचिव दशरथलाल चौबे ने तैयार किया जिसे शासन को भेजा गया।[24]

उस समय पं. रविशंकर शुक्ल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। वे नही चाहते थे कि छत्तीसगढ को पृथक प्रदेश का दर्जा दिया जाए। उस समय छत्तीसगढ़ की राजनीति पर उनका अच्छा प्रभाव था। उन्होंने छत्तीसगढ़ के विधायकों में फूट डालकर इस मांग को उभरने नही दिया, उन्होने पृथक छत्तीसगढ़ प्रांत की मांग का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। इससे छत्तीसगढ़ की जनभावना को जबरदस्त आघात पहुँचा।[25]

दशरथ लाल चौबे व खूबचन्द बघेल छत्तीसगढ़ महासभा के माध्यम से

किसान आंदोलन से भी प्रत्यक्ष जुड़े हुये थे। छत्तीसगढ़ के किसानों की दयनीय स्थिति से इनके मन में सरकारी तंत्र के प्रति विरोध भर गया था। छत्तीसगढ़ महासभा के अंतर्गत ही इनके द्वारा ही प्रथम बार किसानों से उत्पादित संपूर्ण धान खरीदी व धान की उचित मूल्य की मांग की गई। छत्तीसगढ़ महासभा का पत्र जो तत्कालीन मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन को लिखी गई, का अंश उद्धृत है। प्रायः तीन माह से छत्तीसगढ़ी महासभा इस बात का लगातार प्रयत्न कर रही है कि छत्तीसगढ़ के किसानों को धान का भाव उचित मिले। आपसे दिनांक 15-11-1958, 30-11-1958 और 24-12-1958 के पत्रों द्वारा एवं दिनांक 24-11-1958 को इन्दौर में तथा दिनांक 24 और 26 दिसम्बर 1958 को रायपुर में प्रत्यक्ष भेंट में सब बातें स्पष्ट कर दी गयीं। चर्चा के बाद आपने धान का उचित भाव देने में असमर्थता प्रकट की और आपने यह आश्वासन दिया कि किसानों के सभी प्रकार के धानों की पूरी-पूरी खरीदी अधिक व्यापक और संतोषजनक रुप में करें। परन्तु दुख है कि धान की खरीदी की व्यवस्था आज तक किसी भी रेवेन्यु सर्किल में नहीं की गई और जो पुराने गंज (अनाज मंडियां) हैं वहां पर भी समूचे धान की पूरी खरीदी नहीं हो रही है। किसानों को अभी भी अपना धान माटी- मोल बेचने के लिये विवश होना पड़ रहा है। दूसरी ओर सरकारी कर्जों की वसूली कुछ स्थानों में बड़ी सख्ती के साथ हो रही है। गेहूं और चावल के बाबत एक ही प्रांत के अंदर आपकी अलग-अलग नीति है जिससे एक को लाभ और दूसरे को हानि उठानी पड़ रही है। किसानों के हर दैनिक आवश्यक उपयोग की चीजों का भाव आसमान छू रहा है। इन सब कारणों ने अब हमारी सहनशक्ति की सीमा का अन्त कर दिया है। अतएव हमने इस परिस्थिति का अहिंसात्मक ढंग से मुकाबला करने का निर्णय ले लिया है। विदित हो कि छत्तीसगढ़ महासभा छत्तीसगढ़ के तमाम जिला और तहसील दफ्तरों में पिकेटिंग कर प्रांतीय सरकार द्वारा लगायी गयी इस किसान-घातक निर्यात पाबंदी को तोड़ने का रास्ता अपने हाथ में लेगी।[26]

1967 में डॉ. खूबचंद बघेल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन हुआ था उसके संयोजक भी दशरथ लाल चौबे थे। दशरथ लाल चौबे ने छत्तीसगढ़ के हित चिंतन में अपना समय लगा दिया। वे छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के प्रथम संस्थागत प्रयास के आधार स्तंभ थे। छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन को गति देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान को जगाने और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले वे अग्रणी नेता थे।

योग गुरु व सन्यासी जीवन

स्वतन्त्रता के उपरांत के राजनीतिक दुश्चक्रो से उनके मन में विरक्ति की भावना बैठने लगी। केवल 40 वर्ष की उम्र में वर्ष 1962 में वे सांसारिक मोह माया, सक्रिय राजनीति व परिवार से दूर हो गए। इस समय उनके परिवार को उनकी महती आवश्यकता थी, किन्तु एक और बुद्ध को ज्ञान मार्ग की खोज में निकालना था, उन्होने सन्यास मार्ग ग्रहण कर लिया। संन्यासी जीवन व योग के क्षेत्र में वे महान योग गुरु स्वामी साधनानन्द सरस्वती के नाम से जाने गए। इनका एक पृथक आश्रम भूपदेवपुर, जिला रायगढ़ में था। इनके शिष्य देश-विदेश में फैले हुये थे। इनके एक प्रसिद्ध शिष्या स्वामी (मां) अद्वैतानन्द सरस्वती थी। स्वामी (मां) अद्वैतानन्द सरस्वती ने 1965 में 'मध्यप्रदेश योग विद्यालय', रायगढ़ में प्रवेश लिया, जहाँ इन्हें स्वामी साधनानंद सरस्वती का सान्निध्य प्राप्त हुआ। इस योग विद्यालय की स्थापना दशरथ लाल चौबे ने की थी। 1977 में स्वामी साधनानंद सरस्वती ने रामझरना, भूपदेवपुर में योग के प्रचार हेतु स्वतंत्र आश्रम खोला। इस योग आश्रम का प्रभाव छत्तीसगढ़ के अलावा ओड़ीसा के राऊरकेला तक था।[27]

जापान के प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी शिगेरू भी इनके शिष्य रहे। शिगेरू 1956 में कुमामोटो प्रान्त में पैदा हुए। जापान में जूनियर हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और संयुक्त राज्य अमेरिका में इज़राइल यूनिवर्सिटी ऑफ़ कैलिफ़ोर्निया से अपना अध्यापन पूरा किया था। इनको योग की पूरी शिक्षा स्वामी साधनानंद सरस्वती (दशरथ लाल चौबे) से मिला। इन्हे स्वामी सिगेल का नाम दशरथ लाल चौबे ने ही दिया था। शिगेरू ने अपनी किताब स्वामी साधनानंद सरस्वती (दशरथ लाल चौबे) को ही समर्पित किया है। इस किताब में रायगढ़ आश्रम व दशरथ लाल चौबे के साथ शिगेरू के अनेक फोटो भी है।[28]

निष्कर्ष

1942 के रायपुर षड्यंत्र केस के माध्यम से भारत के स्वतन्त्रता आंदोलन तत्पश्चात पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए संचालित आंदोलन में दशरथ लाल चौबे का योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने अन्य लोगों को भी राज्य निर्माण आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। दशरथ लाल चौबे ने छत्तीसगढ़ की जनता को शोषण और अन्याय से मुक्ति दिलाने के लिए पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के लिए संस्थागत प्रयास का शुभारंभ किया। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के वे नीव के पत्थर के रूप मे स्थापित होकर सक्रिय

राजनीति से दूर हो गए किन्तु उनके द्वारा जलायी गयी मशाल की चमक से आगे चलकर 1 नवंबर 2000 को नए छत्तीसगढ़ का उदय हुआ।

संदर्भ ग्रंथ

1. डॉ. साहू, सरिता, मौखिक स्रोतों पर आधारित छत्तीसगढ़ का राजनीतिक इतिहास, 2021, पृष्ठ 119
2. सामाजिक विज्ञान, कक्षा 8, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् छत्तीसगढ़, रायपुर
3. डॉ. साहू, सरिता, मौखिक स्रोतों पर आधारित छत्तीसगढ़ का राजनीतिक इतिहास, 2021, पृष्ठ 251
4. शुक्ला, सुरेश चंद्र, छत्तीसगढ़ का इतिहास, पृष्ठ 148
5. सिंह, आशीष, जज्बा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संस्मरणों का संकलन, पृष्ठ 69
6. शुक्ला, सुरेश चंद्र, छत्तीसगढ़ का इतिहास, पृष्ठ 148
7. परसराम सोनी-रायपुर षडयंत्र केस हस्तलिखित प्रतिलिपि के आधार पर
8. सिंह, आशीष, जज्बा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संस्मरणों का संकलन, पृष्ठ 69
9. शुक्ला, सुरेश चंद्र, छत्तीसगढ़ का इतिहास, पृष्ठ 148
10. सिंह, आशीष, जज्बा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संस्मरणों का संकलन, पृष्ठ 70
11. शुक्ला, सुरेश चंद्र, छत्तीसगढ़ का इतिहास, पृष्ठ. 149
12. Garg, Apoorva- lalluram.com/article-dont-forget-this-is-the-city-of-revolutionaries-fighters
13. डॉ. साहू, सरिता, मौखिक स्रोतों पर आधारित छत्तीसगढ़ का राजनीतिक इतिहास, 2021, पृष्ठ 254
14. Shukla, Gyanesh, Pt. Sundarlal Sharma: Pioneer of national movement and social reforms in Chhattisgarh, IJCRT.Org, Journal, ISSN No: 2320-2882
15. गुप्त, प्यारेलाल 'प्राचीन छत्तीसगढ़' 1973
16. जागेश्वर प्रसाद, चंद्राकार जी. पी. छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन का इतिहास, पृष्ठ 34
17. जागेश्वर प्रसाद, चंद्राकार जी. पी. छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन का इतिहास, पृष्ठ 34

18. जागेश्वर प्रसाद, चंद्राकार जी. पी. छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन का इतिहास, पृष्ठ 34
19. सुरेश चंद्र शुक्ला, अर्चना छत्तीसगढ़ का समग्र इतिहास, पृष्ठ 319
20. बिहारी लाल उपाध्याय, लेख, छत्तीसगढ़ राज्य का सपना जो सच हुआ राज्य स्थापना विशेषांक, नवभारत, 1 नवम्बर, 2001, पृष्ठ 45
21. छत्तीसगढ़ी महासभा का अधिवेशन, राजनादगांव, 1956, पृष्ठ 7
22. छत्तीसगढ़ी महासभा का अधिवेशन, राजनादगांव, 1956, प्रस्ताव क्र. 2
23. छत्तीसगढ़ी महासभा का अधिवेशन, राजनादगांव, 1956, प्रस्ताव क्र. 2
24. सुरेश चंद्र शुक्ला, छत्तीसगढ़ का इतिहास, पृष्ठ 326
25. मदनलाल गुप्ता, छत्तीसगढ़ दिग्दर्शन, पृष्ठ 40
26. वर्मा, डॉ. परदेशीराम, डॉ. खूबचंद बघेल: व्यक्तित्त्व एवं विचार (48), छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी
27. योग थेरेपी, स्वास्थ्य लाभ और दिव्य जीवन संस्करण 2006, प्रकाशक गुरुकुल वृन्दावन स्नातक शोध संस्थान, नई दिल्ली, अंतिम कवर पृष्ठ से
28. सिगेल स्वामी, ओवर द बार्डर, 2002, वंडर बुक कं. लिमिटेड, डौबत्सु पब्लिशिंग कं, टोक्यो, ISBN 4-924603-77-5

ज्ञानेश शुक्ला
सहायक प्राध्यापक
बद्री प्रसाद लोधी स्नातकोत्तर शासकीय महाविद्यालय
आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)

❑❑❑

प्रधानाचार्यों की विद्यालय प्रशासन की समस्याओं का अध्ययन

नीलम गोपीलाल परिहार • डॉ. विनीता एस.आडवाणी

शिक्षा ही समाज की प्रगति का प्रभावी बल हैं। सरकार, विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक चारो को जोड़कर निश्चित दिशा में गति प्रधान करने वाले विद्यालय रूपी जहाज का नाविक प्रधानाचार्य होता हैं। प्रधानाचार्य अनेक समस्याओं का सामना करते हुए, अपने नेतृत्व के बल शिक्षा की स्थाई बुनियाद डालता हैं। इस अध्ययन का उद्देश्य गुजरात राज्य के भावनगर जिले के माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की भौतिक और मानवीय समस्याओं का अध्ययन करना था। जिसके लिए 100 माध्यमिक विद्यालयों के प्रचानाचार्यों का या.च्छिकरूप से चयन किया गया। संशोधक द्वारा निर्मित प्रश्नावली के प्रत्युत्तरों के प्रतिशत के आधार पर समस्याओं की पहचान की गई। उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला गया जिसमे अनेक भौतिक और मानवीय समस्या समस्याए ध्यान में आई। सरकार को इन समस्याओ का जल्दी उपाय कर प्रधानाचार्यो में प्रबंधन कौशल्य का अधिक विकास हो एसा प्रभावी प्रशिक्षण देकर विद्यालयों को अधिक उत्तम बनाने की दिशा में कदम उठाने चाहिए।

प्रस्तावना

विद्यालय समाज का दर्पण है। विद्यालय के प्रधानाचार्य अपने साथी शिक्षकों के साथ मिलकर मनुष्य निर्माण की प्रक्रिया करते ह। किसी विद्यालय की गुणवत्ता उसके नेतृत्व पर निर्भर करती है। प्रधानाचार्यों का अधिकांश समय फाइलें, सरकारी परिपत्र, कार्यक्रमों की तस्वीरें और रिपोर्टे तैयार करने में खर्च हो जाता हैं। शिक्षा सरकार, समाज और शिक्षक का संयुक्त प्रयास है। पूरी व्यवस्था का नेतृत्व विद्यालय के प्रधानाचार्यों को करना होता हैं। उत्कृष्ट प्रशिक्षण के प्रावधान के लिए प्रधानाध्यापकों के सामने आनेवाली कठिनाइयों का एक खोजपूर्ण अध्ययन जरूरी हैं। शोध द्वारा समस्याओं के नये रूपों की

खोज होती हैं, तो उनका समाधान खोजना संभव हो जाता है। प्रधानाचार्यों के कार्य केवल प्रशासनिक ही नहीं बल्कि प्रबंधकीय भी हैं। उसे भौतिक सुविधाओं के प्रावधान, वित्तीय मामले, शैक्षिक उपकरण और शिक्षा प्रक्रिया, शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों, शिक्षा विभाग के अधिकारियों और ऐसे अन्य क्षेत्रों के लोगों जैसे मामलों की देखभाल करनी होती है। इन मामलों की देखभाल करते समय, उन्हें मानवीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा शिक्षण अधिगम कार्य, खेल-कूद, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, विद्यालयी परीक्षाएँ एवं परिणाम आदि से संबंधित अन्य समस्याएँ भी हैं जो विभिन्न प्रकार की समस्याओं को जन्म देती हैं। इसके कई कारण हैं, जैसे वित्त की कमी, अपर्याप्त भौतिक सुविधाएँ, ग्रामीण क्षेत्रों का पिछड़ापन, प्रबंधन संस्था की सीमाएँ, सरकारी नियम, परीक्षा प्रणाली, माता-पिता की सीमाएँ आदि। शोधकर्ता ने यह अध्ययन कुछ सवालों के जवाब ढूंढने के इरादे से किया है, जैसे एक स्कूल प्रिंसिपल को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इन समस्याओं के कारण क्या हैं और इन समस्याओं को हल करने में क्या कठिनाइयाँ आती हैं।

3. पृष्ठभूमि

सरकार द्वारा प्रधानाचार्यों को सक्षम बनाने और उनकी समस्याओं को कम करने के लिए यथा संभव प्रयास किया गया हैं। शैक्षिक प्रशासन को योजना, संगठन, प्रबंधन, प्रेरणा, नियंत्रण, समन्वय, निर्णय लेने, मूल्यांकन, पंजीकरण और रिपोर्टिंग इत्यादि जैसे कार्यों की एक शृंखला निष्पादित करनी होती हैं। शैक्षिक प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रशासनिक प्रशासन एक महत्वपूर्ण कार्य है।

4. अध्ययन के उद्देश्य :

1. विद्यालय प्रशासन में प्रधानाचार्यों को होने वाली भौतिक समस्याओं का अध्ययन करना।
2. विद्यालय प्रशासन में प्रधानाचार्यों को होने वाली मानवीय समस्याओं का अध्ययन करना।

5. तकनीकी शब्दों की व्याख्या :

1. **स्कूल :** गुजरात राज्य सरकार द्वारा मान्यता या सहायता प्राप्त कक्षा 9 और 10 स्कूल

2. **प्रधानाचार्य :** भगवद्गोमंडल के अनुसार आचार्य (प्रधानाचार्य)। आचार्य का अर्थ है गुजरात राज्य में सरकार या किसी माध्यमिक विद्यालय के ट्रस्ट द्वारा विद्यालय प्रशासन के लिए नियुक्त मुख्य शिक्षक।
3. **प्रशासन :** स्कूल प्रशासन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकारी नियमों के अनुसार शैक्षिक कार्य को उचित तरीके से पूरा करने के लिए स्कूलों के भौतिक और मानव संसाधनों का पर्याप्त उपयोग किया जा सकता है। जिसका नेतृत्व विद्यालय के आचार्य करते हैं।
4. **समस्याएँ :** यहाँ समस्या का अर्थ है विद्यालय प्रशासन के भौतिक, प्रशासनिक, शैक्षणिक, वित्तीय, मानवीय संबंधों और प्रशिक्षण पहलुओं के संदर्भ में स्कूल के आचार्य होने वाली समस्याएं।

6. शोध का महत्व

इस शोध की मदद से माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के सामने आने वाली विभिन्न प्रबंधन समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की गई है और इस खोज की मदद से इन समस्याओं के समाधान के लिए कार्य किया जा सकता है। प्रधानाध्यापकों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा और स्कूलों में शिक्षा प्रक्रिया में गुणवत्ता में सुधार किया जा सकेगा। स्कूलों के प्रधानाचार्यों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनमें अपर्याप्त भौतिक सुविधाएं और शिक्षा प्रक्रिया, आर्थिक प्रथाओं में कठिनाइयां, पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों और सरकारी प्रशासन के साथ संबंधों, स्कूल परीक्षाओं और परिणामों आदि से संबंधित समस्याएं शामिल हैं। इन समस्याओं को उचित और उचित माध्यम से हल किया जा सकता है और शोधकर्ता की ओर से यह छोटा सा प्रयास पूरा हो जाएगा।

7. अभ्यास के प्रश्न

विद्यालय प्रशासन के भौतिक, प्रशासनिक, शैक्षिक, आर्थिक, मानवीय संबंध, प्रशिक्षण संबंधी क्षेत्रों में विद्यालय प्राचार्यों की समस्याओं का गहराई से अध्ययन करने के लिए शोधकर्ता ने निम्नलिखित प्रश्न तैयार किये।

1. विद्यालय प्रशासन में स्कूल प्रधानाचार्यों को कौनसी भौतिक समस्याओं का सामना करना पड़ता हैं?
2. विद्यालय प्रशासन में स्कूल प्रधानाचार्यों को कौनसी मानवीय समस्याओं का सामना करना पड़ता हैं?

8. उपकरण

प्रस्तुत अध्ययन के लिए स्वनिर्मित प्रश्नावली का उपयोग एक उपकरण के रूप में किया गया है।

9. शोध पद्धति :

प्रस्तुत अभ्यास सर्वेक्षण प्रकार का हैं।

10. अध्ययन की परिसीमन

1. अध्ययन केवल गुजरात प्रदेश द्वारा संलग्न गुजराती माध्यम के भावनगर जिला के विद्यालयों तक ही सीमित है।
2. अध्ययन माध्यमिक विद्यालयों तक ही सीमित है।

11. न्यादर्श

प्रस्तुत शोध में उद्देश्यपूर्ण और या.च्छिक नमूनाकरण विधि का उपयोग किया गया जिसमें गुजरात राज्य में भावनगर के कुल माध्यमिक विद्यालयों में से 100 विद्यालयों के प्रधानाचार्यों का चयन यादृच्छिक रूप से किया गया।

12. प्रदत्त एकत्रीकरण और पृथक्करण

प्रस्तुत अध्ययन के लिए गूगल फॉर्म द्वारा जानकारी एकत्रित की गई। उनको सारणी बद्ध किया गया। सारणी क्रमांक-1 पेज 00 देखें

उपरोक्त सारणी क्रमांक 1 भौतिक समस्याओं के सन्दर्भ में माध्यमिक विद्यालयों की समस्याओ के विधान हा या ना के प्रत्युत्तर और प्रतिशत और उनके काई वर्ग दर्शाया गया हैं।

प्रत्येक समस्या के अनुसार वर्णन निम्नलिखित प्रकार से है—

1. लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय हैं समस्या के संदर्भ में कुल 80 में से 64 प्रधानाचार्यो ने 'हाँ' एवं 16 ने 'ना' प्रत्युत्तर दिया हैं अर्थात् 80 प्रतिशत विद्यालयों में लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय हैं परन्तु 20 विद्यालयों में अभी भी यह व्यवस्था नहीं हैं।
2. महिला विश्राम कक्ष (गर्ल्स रूम) हैं समस्या के संदर्भ में कुल 80 में से 24 प्रधानाचार्यो ने 'हाँ' एवं 56 ने 'ना' प्रत्युत्तर दिया हैं अर्थात अर्थात 30 प्रतिशत विद्यालयों में महिला विश्राम कक्ष (गर्ल्स रूम) हैं परन्तु 70 प्रतिशत विद्यालयों में अभी भी यह व्यवस्था नहीं हैं।

सारणी क्रमांक-1

भौतिक समस्याओं के प्रत्युत्तर, प्रतिशत और काईमूल्य

क्र.	विधान	हा	प्रतिशत	ना	प्रतिशत	कुल	काई वर्ग
1	लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय हैं।	64	80.00	16	20.00	80	28.8
2	महिला विश्राम कक्ष (गर्ल्स रूम) हैं।	24	30.00	56	70.00	80	12.8
3	खेल के मैदान हैं।	54	67.50	26	32.50	80	9.8
4	पेयजल सुविधाएं हैं।	44	55.00	36	45.00	80	0.8
5	प्रशासनिक कार्यों के लिए पर्याप्त सुविधाएँ हैं।	68	85.00	12	15.00	80	3.2
6	कम्प्यूटर लैब का अभाव है।	68	85.00	12	15.00	80	39.2
7	शिक्षण के लिए पर्याप्त कक्षाएँ हैं।	72	90.00	8	10.00	80	51.2
8	ऑडियो-वीडियो जैसे उपकरणों की कमी है।	66	82.50	14	17.50	80	33.8
9	पुस्तकालय में पर्याप्त पुस्तकें हैं।	74	92.50	6	7.50	80	57.8
10	सामूहिक प्रार्थना कक्ष हैं।	58	72.50	22	27.50	80	16.2
11	इंटरनेट सुविधा पर्याप्त है।	55	68.75	25	31.25	80	11.25

(नोट : उपरोक्त सारणी में सार्थकता मूल्य 0.05 स्तर पर 9.488 और 0.01 स्तर पर 13.277 है।

3. खेल के मैदान हैं समस्या के संदर्भ में कुल 80 में से 54 प्रधानाचार्यो ने 'हाँ' एवं 26 ने 'ना' प्रत्युत्तर दिया हैं अर्थात 67.50 प्रतिशत विद्यालयों में खेल के मैदान हैं और 32.50 प्रतिशत विद्यालयों में अभी भी खेल के मैदान नहीं हैं।
4. पेयजल सुविधाएं हैं के संदर्भ में कुल 80 में से 44 प्रधानाचार्यो ने 'हाँ' एवं 36 ने 'ना' प्रत्युत्तर दिया हैं अर्थात 55 प्रतिशत विद्यालयों में पेयजल सुविधाएं हैं और 45 प्रतिशत विद्यालयों में अभी भी पेयजल सुविधाएं नहीं हैं।
5. प्रशासनिक कार्यों के लिए पर्याप्त सुविधाएँ हैं समस्या के संदर्भ में कुल 80 में से 68 प्रधानाचार्यो ने 'हाँ' एवं 12 ने 'ना' प्रत्युत्तर दिया हैं अर्थात 85 प्रतिशत विद्यालयों में प्रशासनिक कार्यों के लिए पर्याप्त सुविधाएँ हैं और 15 प्रतिशत विद्यालयों में अभी भी प्रशासनिक कार्यों के लिए पर्याप्त सुविधाएँ नहीं हैं।
6. 6-कम्प्यूटर लैब का अभाव है समस्या के संदर्भ में कुल 80 में से 68 प्रधानाचार्यो ने 'हाँ' एवं 12 ने 'ना' प्रत्युत्तर दिया हैं अर्थात 85 प्रतिशत विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब का अभाव है और 15 प्रतिशत विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब हैं।
7. शिक्षण के लिए पर्याप्त कक्षाएँ हैं समस्या के संदर्भ में कुल 80 में से 72 प्रधानाचार्यो ने 'हाँ' एवं 8 ने 'ना' प्रत्युत्तर दिया हैं अर्थात 90 प्रतिशत विद्यालयों में शिक्षण के लिए पर्याप्त कक्षाएँ हैं और 10 प्रतिशत विद्यालयों में अभी भी पर्याप्त कक्षाएँ नहीं हैं।
8. ऑडियो-वीडियो जैसे उपकरणों की कमी है समस्या के संदर्भ में कुल 80 में से 66 प्रधानाचार्यो ने 'हाँ' एवं 14 ने 'ना' प्रत्युत्तर दिया हैं अर्थात 82.50 प्रतिशत विद्यालयों में ऑडियो-वीडियो जैसे उपकरणों की कमी है और 17.50 प्रतिशत विद्यालयों में ऑडियो-वीडियो जैसे उपकरणों की कमी नहीं हैं।
9. पुस्तकालय में पर्याप्त पुस्तकें हैं समस्या के संदर्भ में कुल 80 में से 74 प्रधानाचार्यो ने 'हाँ' एवं 6 ने 'ना' प्रत्युत्तर दिया हैं अर्थात 92.50 प्रतिशत विद्यालयों में पुस्तकालय में पर्याप्त पुस्तकें हैं और 7.50 प्रतिशत विद्यालयों में अभी भी पुस्तकालय में पर्याप्त पुस्तकें नहीं हैं।
10. सामूहिक प्रार्थना कक्ष हैं समस्या के संदर्भ में कुल 80 में से 58

प्रधानाचार्यो ने 'हाँ' एवं 22 ने 'ना' प्रत्युत्तर दिया हैं अर्थात 72.50 प्रतिशत विद्यालयों में सामूहिक प्रार्थना कक्ष हैं और 27.50 प्रतिशत विद्यालयों में अभी भी सामूहिक प्रार्थना कक्ष नहीं हैं।

11. इंटरनेट सुविधा पर्याप्त है समस्या के संदर्भ में कुल 80 में से 55 प्रधानाचार्यो ने 'हाँ' एवं 25 ने 'ना' प्रत्युत्तर दिया हैं अर्थात 68.75 प्रतिशत विद्यालयों में इंटरनेट सुविधा पर्याप्त है और 31.25 प्रतिशत विद्यालयों में अभी भी इंटरनेट सुविधा पर्याप्त नहीं हैं।

आलेख क्रमांक-1

भौतिक समस्याओ के प्रत्युत्तर

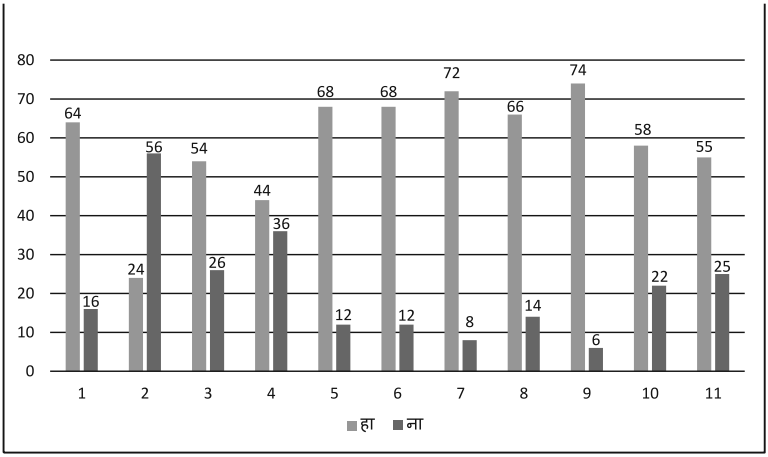

सारणी क्रमांक-2 पेज 00 देखें

उपरोक्त सारणी क्रमांक 2 मानवीय समस्याओं के सन्दर्भ में माध्यमिक विद्यालयों की समस्याओं के विधान हा या ना के प्रत्युत्तर और प्रतिशत और उनके काई वर्ग दर्शाया गया हैं—

प्रत्येक समस्या के अनुसार निम्नलिखित प्रकार से है—

1. संचालक मंडल के सदस्य विद्यालय विकास में का रुचि लेते हैं समस्या के संदर्भ में कुल 80 में से 22 प्रधानाचार्यो ने 'हाँ' एवं 58 ने 'ना' प्रत्युत्तर दिया हैं अर्थात 27.50 प्रतिशत विद्यालयों में संचालक मंडल के

सारणी क्रमांक-2

मानवीय समस्याओं के प्रत्युत्तर, प्रतिशत और काईमूल्य

क्र.	विधान	हा	प्रतिशत	ना	प्रतिशत	कुल	काई वर्ग
1	संचालक मंडल के सदस्य विद्यालय विकास में कम रुचि लेते हैं।	22	27.50	58	72.50	80	16.2
2	बच्चों की पढ़ाई में माता-पिता का सहयोग कम मिलता है।	64	80.00	16	20.00	80	28.8
3	अभिभावक सम्मेलन में अभिभावकों की उपस्थिति कम रहती है।	62	77.50	18	22.50	80	24.2
4	राजनीतिक हस्तियाँ स्कूल में हस्तक्षेप करती हैं।	56	70.00	24	30.00	80	12.8
5	राजनीतिक एवं सामाजिक वातावरण शैक्षणिक कार्य में बाधक बनता है।	48	60.00	32	40.00	80	3.2
6	अविश्वास और नकारात्मक वातावरण प्रबंधन में बाधा डालते हैं।	62	77.50	18	22.50	80	24.2
7	विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण स्कूल प्रबंधन में कठिनाइयाँ पैदा करता है ।	48	60.00	32	40.00	80	3.2
8	शिक्षक संघों के काम में परेशानी होती है।	42	52.50	38	47.50	80	0.2
9	मानवीय दृष्टिकोण अपनाने से नियम तटस्थ हो जाते हैं।	63	78.75	17	21.25	80	26.45

(नोट : प्रतिशत उपरोक्त सारणी में सार्थकता मूल्य 0.05 स्तर पर 9.488 और 0.01 स्तर पर 13.277 है।)

सदस्य विद्यालय विकास में का रूचि लेते हैं परन्तु 72.50 प्रतिशत विद्यालयों में ऐसा नहीं हैं।

2. बच्चों की पढ़ाई में माता-पिता का सहयोग कम मिलता है समस्या के संदर्भ में कुल 80 में से 64 प्रधानाचार्यो ने 'हाँ' एवं 16 ने 'ना' प्रत्युत्तर दिया हैं अर्थात 80 प्रतिशत विद्यालयों में बच्चों की पढ़ाई में माता-पिता का सहयोग कम मिलता है परन्तु 20 प्रतिशत विद्यालयों में ऐसा नहीं हैं।
3. अभिभावक सम्मेलन में अभिभावकों की उपस्थिति कम रहती है समस्या के संदर्भ में कुल 80 में से 62 प्रधानाचार्यो ने 'हाँ' एवं 18 ने 'ना' प्रत्युत्तर दिया हैं अर्थात 77.50 प्रतिशत विद्यालयों में अभिभावक सम्मेलन में अभिभावकों की उपस्थिति कम रहती है परन्तु 22.50 प्रतिशत विद्यालयों में ऐसा नहीं हैं।
4. राजनीतिक हस्तियाँ स्कूल में हस्तक्षेप करती हैं समस्या के संदर्भ में कुल 80 में से 56 प्रधानाचार्यो ने 'हाँ' एवं 24 ने 'ना' प्रत्युत्तर दिया हैं अर्थात 70 प्रतिशत विद्यालयों में राजनीतिक हस्तियाँ स्कूल में हस्तक्षेप करती हैं परन्तु 30 प्रतिशत विद्यालयों में ऐसा नहीं हैं।
5. राजनीतिक एवं सामाजिक वातावरण शैक्षणिक कार्य में बाधक बनता है समस्या के संदर्भ में कुल 80 में से 48 प्रधानाचार्यो ने 'हाँ' एवं 32 ने 'ना' प्रत्युत्तर दिया हैं अर्थात 60 प्रतिशत विद्यालयों में राजनीतिक एवं सामाजिक वातावरण शैक्षणिक कार्य में बाधक बनता है परन्तु 40 प्रतिशत विद्यालयों में ऐसा नहीं हैं।
6. अविश्वास और नकारात्मक वातावरण प्रबंधन में बाधा डालते हैं समस्या के संदर्भ में कुल 80 में से 62 प्रधानाचार्यो ने 'हाँ' एवं 18 ने 'ना' प्रत्युत्तर दिया हैं अर्थात 77.50 प्रतिशत विद्यालयों में अविश्वास और नकारात्मक वातावरण प्रबंधन में बाधा डालते हैं परन्तु 22.50 प्रतिशत विद्यालयों में ऐसा नहीं हैं।
7. विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण स्कूल प्रबंधन में कठिनाइयाँ पैदा करता है समस्या के संदर्भ में कुल 80 में से 48 प्रधानाचार्यो ने 'हाँ' एवं 32 ने 'ना' प्रत्युत्तर दिया हैं अर्थात 60 प्रतिशत विद्यालयों में विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण स्कूल प्रबंधन में कठिनाइयाँ पैदा करता है परन्तु 40 प्रतिशत विद्यालयों में ऐसा नहीं हैं।
8. शिक्षक संघों के काम में परेशानी होती है समस्या के संदर्भ में कुल 80 में से 42 प्रधानाचार्यो ने 'हाँ' एवं 38 ने 'ना' प्रत्युत्तर दिया हैं अर्थात

52.50 प्रतिशत विद्यालयों में शिक्षक संघों के काम में परेशानी होती है परन्तु 47.50 प्रतिशत विद्यालयों में ऐसा नहीं होता हैं।

9. मानवीय दृष्टिकोण अपनाने से नियम तटस्थ हो जाते हैं समस्या के संदर्भ में कुल 80 में से 63 प्रधानाचार्यों ने 'हाँ' एवं 17 ने 'ना' प्रत्युत्तर दिया हैं अर्थात् 78.75 प्रतिशत विद्यालयों मानवीय दृष्टिकोण अपनाने से नियम तटस्थ हो जाते हैं परन्तु 21.25 प्रतिशत विद्यालयों में ऐसा नहीं हैं।

आलेख क्रमांक-2

मानवीय समस्याओं के प्रत्युत्तर

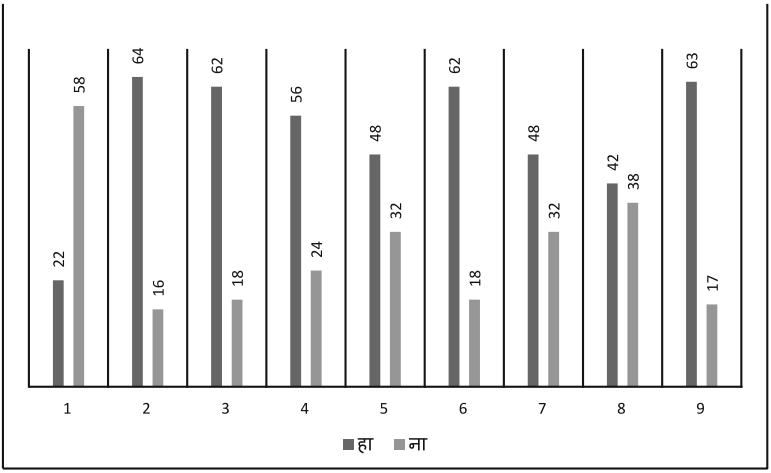

13. निष्कर्ष

भौतिक समस्याओ के सन्दर्भ में निष्कर्ष

1. बहुत कम विद्यालयों में महिला विश्राम कक्ष (गर्ल्स रूम) हैं।
2. अनेक विद्यालयों में खेल के मैदान नहीं हैं।
3. अनेक विद्यालयों में अभी भी पेय जल की पर्याप्त सुविधा नहीं हैं।
4. प्रशासनिक कार्यों के लिए पर्याप्त सुविधाएँ हैं पर अभी भी कुछ जगहों पर नहीं हैं।
5. विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब का अभाव अभी भी अभाव पाया गया हैं।
6. अधिकांश विद्यालयों में ऑडियो-वीडियो जैसे उपकरणों की कमी है।

7. कुछ विद्यालयों में सामूहिक प्रार्थना कक्ष की आवश्यकता हैं।
8. कुछ विद्यालयों मैं अभी भी इंटरनेट सुविधा पर्याप्त नहीं है।

मानवीय समस्याओ के निष्कर्ष

1. अधिकांश विद्यालयों में संचालक मंडल के सदस्य विद्यालय विकास में रुचि नहीं लेते हैं।
2. बहुत ही विद्यालयों में बच्चों की पढ़ाई में माता-पिता का सहयोग कम मिलता है।
3. अधिकांश विद्यालयों में अभिभावक सम्मेलन में अभिभावकों की उपस्थिति कम रहती है।
4. अधिकांश विद्यालयों में राजनीतिक हस्तियाँ स्कूल में हस्तक्षेप करती हैं।
5. अनेक विद्यालयों में राजनीतिक एवं सामाजिक वातावरण शैक्षणिक कार्य में बाधक बनता है।
6. अधिकांश विद्यालयों में अविश्वास और नकारात्मक वातावरण प्रबंधन में बाधा डालते हैं।
7. विद्यालयों में अविश्वास और नकारात्मक वातावरण प्रबंधन में बाधा डालता हैं।
8. विद्यालयों के प्रधानाचार्यों का विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण स्कूल प्रबंधन में कठिनाइयाँ पैदा करता है।
9. अधिकांश आचार्य मानते हैं कि मानवीय दृष्टिकोण अपनाने से नियम तटस्थ हो जाते हैं।

14. शैक्षणिक फलितार्थ

प्रधानाचार्यों को विद्यालय में उच्च शैक्षिक मानकों को बनाए रखने के लिए भौतिक सुविधाओं के आभाव में, मानवीय संशोधनों का महत्तम उपयोग कर, सरकार की नीतियों का व्यवहारिक क्रियान्वयन करते हुए पाठ्यक्रम विकास, शिक्षण पद्धतियों और छात्र मूल्यांकन की देखरेख करनी होती हैं। एक प्रधानाध्यापक भी सामुदायिक सहभागिता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एसे समय में उसे अनेक समस्याओं को एक साथ सुलझाने में मानसिक तनावों का सामना करना पड़ता हैं। छात्र, शिक्षक, अभिभावक और सरकार चारों के साथ समन्वय बना कर अपने विद्यालय की उत्तम व्यवस्थाओं का प्रस्थापित करने का कार्य एक उत्तम नेतृत्व शक्तिशाली व्यक्ति की आवश्यकता होती हैं। अनेक

विद्यालयों में जहाँ आज भी पर्याप्त मात्र में महिलाओं के लिए विश्राम कक्ष, बच्चों के लिए खेल के मैदान, शुद्ध पेय जल, कम्प्यूटर लेब, ऑडियो-वीडियो जैसे उपकरणों, सामुहिक प्रार्थना कक्ष, इन्टरनेट की सुविधा जैसी अनेक भौतिक सुविधाओं का अभाव पाया गया हैं। एसे विद्यालयों में सुविधाओं की उपलब्धि करवानी चाहिए।

References

1. Adams, K., & Turner, D. (2022). Leadership Challenges in Secondary Schools: Perspectives from Principals and Teachers. Journal of Educational Research, 40(2), 189-205.
2. Chen, H., & Wang, S. (2018). Balancing Act: Secondary School Principals' Struggles with Resource Allocation in Administration. International Journal of Educational Management, 32(1), 56-72.
3. Dinham, S. (2005), Principal leadership for outstanding educational outcomes. Journal of educational administration, 43(4), 338-356.
4. Forssten Seiser, A. (2019). Exploring enhanced pedagogical leadership: An action research study involving Swedish principals. Educational Action Research, 28(5), 791–806. https://doi.org/10.1080/09650792.2019.1656661
5. Garcia, M., & Lee, C. (2021). Coping with Burnout: A Study of Secondary School Principals' Experiences in Administration. Journal of School Leadership, 28(3), 215-230.
6. Håkansson, J., & Sundberg, D. (2018). Utmärkt ledarskap i skolan. Forskning om att leda för elevernas måluppfyllelse. [Excellent leadership i school. Research on leading for student success]. Natur & Kultur.
7. Jain, M., & Verma, P. (2017). Exploring the Administrative Issues Encountered by Secondary School Principals in Urban India. Educational Administration Quarterly, 43(1), 67-84.
8. Kumar, V., & Tiwari, S. (2018). A Study of Leadership Challenges Faced by Secondary School Principals in Rural Areas of India. Journal of School Leadership, 25(3), 278-295.
9. Marmar Mukhopadhyay and Trilok N Dhar (2001). Governance of Indian education – Proposed reforms. In Governance of School Education in India. Marmar Mukhopadhyay and R. S. Tyagi (Eds). NUEPA. New Delhi. p.316.

10. Mishra, R., & Choudhary, S. (2016). Challenges and Coping Strategies of Secondary School Principals in India: An Exploratory Study. International Journal of Educational Leadership and Management, 24(2), 189-206.

11. Mohnaty. B (1990), Educational administration. New Delhi. Publication Rajouri Garden

12. Rapp, S. (2021). Att leda elevers kunskapsutveckling. Styrkedjan och det pedagogiska ledarskapet [To lead students' knowledge development. Structural organisation and pedagogical leadership]. Gleerups.

13. Sharma, R., & Gupta, S. (2020). Challenges Faced by Secondary School Principals in India: A Qualitative Study. Journal of Educational Administration, 38(2), 123-140.

14. Singh, A., & Mishra, S. (2019). Administrative Challenges Confronting Secondary School Principals in India: A Case Study Approach. International Journal of Educational Management, 35(4), 456-472.

15. Verma, Rohit, et al. (2005), "Operations Management in Not For Profit, Public and Government Services: Charting a New Research Frontier.

15. Verma, Rohit, et al. (2005), Operations Management in Not Public and Government Services: Charting a New Research Frontier.

शोधकर्ता

नीलम गोपीलाल परिहार

रिसर्च स्कॉलर

कड़ी सर्व विद्यालय

गांधीनगर, गुजरात

मार्गदर्शक

डॉ. विनीता एस. आडवाणी

सहायक प्रोफेसर

एस.एस.पटेल कॉलेज ऑफ

एजुकेशन, गांधीनगर, गुजरात

❑❑❑

सावधान

जूनी ख्यात (अर्द्ध वार्षिक) दिसम्बर 1994 ई. से नियमित Print Form में प्रकाशित हो रही है। जून 2019 में 'UGC Care List' (S.N. 220) में सामाजिक-विज्ञान की श्रेणी में सम्मिलित करली गई है। हमारी पत्रिका Online प्रकाशित नहीं होती है।

जूनी ख्यात नाम से ही एक फर्जी पत्रिका (Cloned Journal) ऑन लाइन निकाली जा रही है जो हमारे ही ISSN एवं यू.जी.सी. केयर लिस्ट की संख्या को उपयोग में ले रही है। इस सम्बन्ध में **यू.जी.सी.** ने 23-7-2020 को 'Cloned Journal' की एक सूची जारी की है उसमें अन्य पत्रिकाओं के साथ **जूनी ख्यात** का भी नाम है। यह पत्रिका निम्न वेबसाइट पर प्रत्येक विषय के शोध पत्र आमंत्रित करती है।

Juni khyat Journal

Language	:	English & Hindi
Publisher		NA
ISSNo.		2278-4632
URL http	:	www.junikhyat.com

हमारी पत्रिका **मरुभूमि शोध संस्थान, श्रीडूँगरगढ़** द्वारा प्रकाशित की जाती है। अब 'नकली पत्रिका' बी.एल. भादानी, संपादक के नाम का भी उपयोग कर रही है जो एक आपराधिक कृत्य है।

इसमें तथाकथित रूप से प्रकाशित आलेख का कोई महत्त्व भी नहीं है। इसलिए शोधार्थियों से सावधान रहने की अपील की जाती है।

बी.एल. भादानी
संपादक

Sl.No.	Journal No.	Title	Publisher	ISSN
220		JUNI KHYAT		2278-4632

UGC Journal Details

Name of the Journal : **JUNI KHYAT (Print Form)**
ISSN Number : 2278-4632
e-ISSN Number : NA
Source : **UGC**
Discipline : **Social Science**
Subject : **Social Sciences (all)**
Focus Subject : Cultural Studies
Publisher : Marubhumi Shodh Sansthan, Sri Dungargarh (Bikaner)

जूनी ख्यात जुलाई–दिसम्बर, 2024 (Vol-II) वर्ष : 14, अंक :1 ISSN : 2278-4632

राष्ट्र भाषा हिन्दी प्रचार समिति, श्रीडूंगरगढ़ द्वारा राजस्थान स्थापना दिवस–2025 के अवसर पर आयोजित समारोह 'विरासत और संस्कृति का पर्व : राजस्थान दिवस' विषयक संगोष्ठी में उद्बोधन देते हुए साहित्यकार डॉ. चेतन स्वामी और शिक्षाविद् कवि डॉ. सुरेन्द्र सोनी

महावीर प्रसाद माली मरुभूमि शोध संस्थान,
श्रीडूँगरगढ़ के लिए मुद्रित एवं प्रकाशित।

मुद्रक : महर्षि प्रिंटर्स, श्रीडूँगरगढ़ (बीकानेर) राज.

जूनी ख्यात बैंक विवरण :
Account Name : Marubhumi Shodh Sansthan
Bank : Punjab National Bank, Sridungargarh
Account No. : 3604000100174114
IFSC : PUNB0360400

Website : http://rbhpsdungargarh.com